Punjab Legislative Assembly Debates

9th March, 1954.

VOL. I—NO. I.

OFFICIAL REPORT

CONTENTS.

Tuesday, the 9th March, 1954

CHANDIGARH :

Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab

1954

Price : -/9/-

PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY

Tuesday, the 9th March, 1954.

The Assembly met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh at 2 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Dr. Satyapal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

DEMAND OF THE RESIDENTS OF TEHSIL GARHSHANKER.

***1979. Sardar Chanan Singh Dhut** : Will the Chief Minister be pleased to state whether the residents of Tehsil Garhshankar, District Hoshiarpur, presented any demands on March 27, 1953, to him at Mahalpur; if so, a copy of the same be laid on the Table?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : The hon. Member has not given the subject matter of the demands presented by the residents of Tehsil Garhshankar, District Hoshiarpur. Such representations or applications received by the Chief Minister, are, however, invariably passed on to the Administrative Department concerned for proper action.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ: ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿਚ ਜੇਹੜਾ representation ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ........

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਜਦੋਂ ਕੋਈ representation ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ representation ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਦਸ ਦੇਵੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ representation ਸੀ ? ਅਸੀਂ ਪੁਛ ਕੇ ਦਸ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

अध्यक्ष महोदय: सवाल में बता दिया गया है कि वह कौन से representation के बारे में पूछ रहे हैं। २७ मार्च को चीफ़ मनिस्टर साहिब को एक representation दिया गया था उस के बारे में information मांगी जा रही है।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ ਬਲਕਿ representation ਦੀ nature ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ।

पंडित श्री राम शर्मा: २७ मार्च को माहलपुर में जो representations दिये गये थे क्या वह इतने ज्यादा थे कि उन की nature मालूम करने की ज़रूरत पड़ रही है ? क्या सिरफ़ एक representation था या बहुत सारे थे ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਆਪ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹੋ। ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਕਾਰਡ (Record) ਤਰੀਕਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਰਖੀਆ ਜਾਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ nature ਉਤੇ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा: मैं वज़ीर रह चुका हूं इसलिये मुझे मालूम है कि जब कोई representation आता है तो वज़ीर या उस का प्राईवेट सेक्रेटरी एक नोट उस पर दे देता है कि एक representation आया है। अब मैं पूछता हूं कि माहलपुर में कितने मिले थे। एक या बहुत सारे ?

अध्यक्ष महोदय: आप representation का subject matter बता दें।

पंडित श्री राम शर्मा: क्या इतने ज्यादा representation मिले थे कि इस बारे में मुशिकल पेश आ रही है ? अगर सिर्फ़ एक representation थी फिर तो यह सवाल ही पैदा नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय: फिर भी आप उसकी nature बता दें।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਇਕ ਸਾਂਝਾ representation ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा : Representation ज्यादा न थे फिर भी हम ने उन्हें याद ताजा करने में मदद दे दी है।

Mr. Speaker : The Chief Minister wants that you should tell him the subject matter of the representation.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜੇਹੜਾ representation ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ? ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ?

INCLUSION OF VILLAGES IN GRAM PANCHAYAT AREA IN THE STATE.

*2003. **Sardar Harkishan Singh Surjit :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a number of villages in the State have not been included in any Gram Panchayat Area; if so, their number together with their names;

(b) whether it is also a fact that village Buter, District Jullundur has not been included in any Gram Panchayat Area; if so, the steps Government proposes to take in the matter?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) All the villages in the State have been included in the Gram Panchayat Areas except certain suburbs of Ferozepore, Abohar and Gohana towns and some villages of Ferozepore District situated on the Pakistan side of the River Sutlej. Steps are being taken for the formation of Panchayats for the suburbs of Ferozepore, Abohar and Gohana Cities. As regards the villages situated on the Pakistan side of River Sutlej, the question of forming Panchayats in their case does not arise as they are not inhabited by Indian Nationals.

(b) There is no village known as 'Buter' in the Jullundur District. A village named as 'Butran' is, however, situated in the Jullundur tehsil of Jullundur District but it has already got a Gram Panchayat.

पंडित श्री राम शर्मा: क्या मैं पूछ सकता हूं कि जो गांव पंचायत Areas में शामिल होने से रह गये, उन के लिये कौन जिम्मेदार है और वह किस वजह से रह गये ?

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी: आप गांव का नाम बता कर सवाल का नोटिस दें तो जवाब दिया जा सकता है।

पंडित श्री राम शर्मा: पहले जवाब में कहा गया है कि सब गांव शामिल कर लिये गये हैं। फिर कहा गया है कि कुछ नहीं भी लिये गये। अब सवाल यह है कि जो नहीं लिये गये वह क्यों नहीं लिये गये और इस बात के लिये कौन ज़िम्मेदार है ?

अध्यक्ष महोदय: सवाल देखिये। उस में आपने वजह नहीं पूछी, number (गिनती) पूछा है।

पंडित श्री राम शर्मा: पहले कहा गया कि सब के लिये है फिर कहा गया, कि कुछ नहीं लिये। इस बिना पर मैंने यह सवाल किया है कि वजह बताई जाए।

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी: जो गांव Area से बाहर रह गये हैं उन के बारे में अभी आख़री फ़ैसला नहीं हुआ कि उन्हें rural area में रखा जाए या urban ही समझा जाए। यह फ़ैसला हो जाने पर उन के बारे में भी कार्यवाई ठीक हो जाएगी।

पंडित श्री राम शर्मा: क्या रह जाने वाले सब गांव ऐसे थे जिन के बारे में अभी यह फ़ैसला नहीं हुआ ?

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी: इस सवाल का नोटिस दीजिये ।

एक माननीय सदस्य: सवालों के जवाब हिंदी या पंजाबी में पढ़े जायें ।

अध्यक्ष महोदय: यह बात चीफ़ मिनिस्टर साहिब के ज़ेरे ग़ौर है और इस पर काफ़ी सोच विचार हो रहा है । लेकिन जब तक विधान में यह है कि record अंग्रेज़ी में हो, ऐसा करना कठिन है । मैं माननीय सदस्यों को यह भी बता देना चाहता हूं कि मंत्री साहिबान केवल अंग्रेज़ी में दिये हुए उत्तर का ज़िम्मा ले सकते हैं । हां, अगर अंग्रेज़ी में उत्तर सुनने के बाद माननीय सदस्य चाहेंगे तो उत्तर का खुलासा हिंदी या पंजाबी में भी बता दिया जायेगा ।

पंडित श्री राम शर्मा: जहां तक मेरा ख़्याल है आप ने ruling दिया था कि अंग्रेज़ी के उत्तर के बाद ही हिंदी या पंजाबी में तरजमा करके बता दिया जायेगा । अब आप फरमा रहे हैं कि यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो ऐसा किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय: पंडित जी ने मेरी गुज़ारिश ठीक तौर पर नहीं सुनी । मेरा कहने का मतलब यह है कि जब सवाल अंग्रेज़ी में होता है तो जवाब भी अंग्रेज़ी में सुन लिया जाये । अगर ज़रूरत होगी तो हिंदी और पंजाबी में भी खुलासा बता दिया जायेगा । यदि माननीय सदस्य कई बार तरजमे की ज़रूरत ही न समझें तो वक्त ज़ाया करने का क्या लाभ है ? आप जानते हैं सारे काम को overhaul करना है और यह कोई आसान बात नहीं है ।

श्री तेग राम: इस काम को overhaul करने में कितना समय लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय: यह कौन से सवाल का Supplementary है ?

पंडित श्री राम शर्मा: मैं आप के द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब Constitution में इस काम के लिये १५ साल का समय रखा गया है तो इस बारे में क्या कुछ किया भी है ?

अध्यक्ष महोदय: ऐसी बातों का ज़िक्र बजट की बहस में किया जाये तो अच्छा होगा ।

ARREST OF TENANTS AND KISAN SABHA WORKERS IN THE STATE.

*2033. **Shri Wadhawa Ram**: Will the Chief Minister be pleased to state the total number of prosecutions started against tenants and Kisan Sabha Workers, district-wise in the State during the years 1952, and 1953 respectively together with the number of cases in which convictions were secured?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): Information in respect of this question is being collected and will be supplied to the member shortly.

पंडित श्री राम शर्मा: मेरे विचार में सरकार को और आप के दफ़तर को भी इस बात का ख़्याल रखना चाहिये कि ऐसे सवालों पर जल्द से जल्द गौर हो ।

सिंचाई मंत्री (चौधरी लैहरी सिंह): माननीय सदस्यों को भी चाहिये कि सवाल ठीक प्रकार से लिख कर भेजा करें ।

ELECTION OF PANCHES AND SARPANCHES IN THE STATE.

*2154. **Sardar Darshan Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Panchayats recently constituted in the State district-wise;

(b) the total number of Gram Panchayat Areas in the State district-wise;

(c) the number of Sarpanches and panches belonging to Scheduled Castes elected to the Panchayats together with the number of such Panchayats district-wise in the State?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): A statement embodying the requisite information is given below. Information asked for in part (c) of the question cannot be supplied in respect of Kangra district, as elections of Panchayats in that district are still in progress.

STATEMENT.

Serial No.	Name of district.	Total No. of Panchayats recently constituted.	Total No. of Panhcayat areas in the State.	No. of scheduled castes Sarpanches.	No. of scheduled castes Panches.	No. of Panchayats from which these Sarpanches and Panches have been elected.
1	Hissar ..	97	682	13	674	587
2	Gurgaon ..	210	810	6	654	620
3	Rohtak ..	218	637	11	722	585
4	Karnal ..	65	719	6	687	709
5	Ambala ..	206	778	29	811	709
6	Hoshiarpur ..	271	1,035	81	1,258	895
7	Jullundur ..	65	781	78	1,265	774
8	Ludhiana ..	38	561	26	669	536
9	Ferozepore ..	164	1,012	17	701	586
10	Amritsar ..	200	30	17	739	694
11	Gurdaspur ..	135	714	21	502	423
12	Kangra ..	112	602	..	..	..

सरदार दर्शन सिंह: कई देहात में हरिजनों की आबादी १० फ़ी सदी से ज्यादा है परन्तु वहां कोई हरिजन पंच नहीं चुना गया। सरकार ऐसे देहात के बारे में क्या कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय: जब इस बारे में सवाल का जवाब ही नहीं दिया गया तो Supplementary कैसे पूछा जा सकता है ?

PUNITIVE POLICE POSTS IN DISTRICT FEROZEPORE.

***2261. Sardar Nidhan Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of punitive police posts set up in district Ferozepore during the years 1952 and 1953 together with the total amount of fine imposed in each case and the reasons for posting them;

(b) the basis of assessment of the fine imposed in each case;

(c) whether it is a fact that two police posts have been posted in village Lehra Mohabbatwala, Police Station Nathana, District Ferozepore; if so, the reasons therefor;

(d) whether it is a fact that the residents of village Lehra Mohabbatwala have also to undertake 'Thikri Pehra'; if so, the reasons therefor?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) A statement is given below—

(b) The cost in each case has been apportioned among the inhabitants according to the District Magistrate's judgement of their respective means within the area concerned.

(c) No.

(d) No.

STATEMENT.

Total number of Punitive Police Posts set up in District Ferozepore during the years 1952 and 1953.	Name of the Post.	Amount imposed. Rs A. P.	Reasons for posting.
12 ..	1. Mari Mustafa for villages Mari Mustafa and Chaudhriwala.	29,464 8 0	Disturbed condition of the villages and the conduct of their inhabitants.
	2. Badhni Kalan for villages Badhni Kalan, Lopon, Raoke Kalan and Badhni Khurd.	65,647 0 0	Ditto ditto
	3. Mudki for villages Mudki, Kot Karor Kalan, Phidde and Loham.	10,609 0 0	Ditto ditto
	4. Raunta for villages Raunta and Khote ..	23,020 8 0	Ditto ditto
	5. Chibranwali ..	10,706 6 0	Disturbed condition of the village and the conduct of its inhabitants.
	6. Thandewala ..	14,583 0 0	Ditto ditto
	7. Rupana for villages Rupana and Chak Duhewala. ..	17,181 3 0	Disturbed condition of the villages and the conduct of their inhabitants.
	8. Dona Jalloke for villages Dona Jalloke, Jalloke and Betu Jagir.	17,000 0 0	Ditto ditto
	9. Lakhewali ..	12,270 0 0	Disturbed condition of the village and conduct of its inhabitants.
	10. Tungwali ..	29,640 0 0	Ditto ditto
	11. Kandhwala Hazar Khan for villages Khandhwala Hazar Khan, Kamalwala and Mamukhera.	15,600 0 0	Disturbed condition of the villages and the conduct of their inhabitants.
	12. Fatehpur Manhian for villages Fatehpur Manhian, Dewan Khera and Tappakhera.	15,451 0 0	Ditto ditto

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ : ਇਕ ਪਿੰਡ ਪਿਰਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਥੇ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਬਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਚੌਕੀ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?

चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : माननीय सदस्य इस स्वाल का नोटिस दें ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ : ਇਕ ਪਿੰਡ ਚੰਧਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਚੌਕੀ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਚੌਕੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ?

अध्यक्ष महोदय : इस स्वाल के पूछने की आज्ञा नहीं ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं पूछना चाहता हूं कि जिन देहात में ताज़ीरी चौकियां बिठाई जाती हैं वहां assessment का क्या basis होता है ? क्या इस बात का ख्याल रखा जाता है कि गांव का कौनसा हिस्सा जुरम के लिये ज़्यादा ज़िम्मेदार है ?

मुख्य मंत्री : जब Punitive Police लगाई जाती है तो assessment के समय इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कोई आदमी इस काबिल है या नहीं कि उस से रकम वसूल की जा सके ।

पंडित श्री राम शर्मा : आम तौर पर जब Punitive Posts के लिये assessment की जाती है तो तमाम ज़मींदारों की ज़मीन देख कर और दूसरे लोगों की हैसीयत देख कर की जाती है । Chief Minister साहिब ने कहा है कि इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कौन से Section ने जुरम में ज़्यादा हिस्सा लिया है ।

मुख्य मंत्री : मैंने ऐसा नहीं कहा ।

पंडित श्री राम शर्मा : तो आपने क्या कहा है ?

मुख्य मंत्री : जो कुछ मैंने कहा है record हो चुका है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह ठीक नहीं कि आम तौर पर सरकार की तर्फ से हिदायत होती है कि ज़मीनें और हैसीयत देख कर नंबरदार वगैरा बना दिये जायें और इस बात का बिल्कुल ख्याल न रखा जाये कि वे अच्छे आदमी हैं या नहीं ?

मुख्य मंत्री : यदि स्पीकर साहब आज्ञा दें तो मैं इस स्वाल का जवाब देने को तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल के उत्तर देने की आज्ञा नहीं ।

PUNITIVE POLICE POSTS IN THE STATE.

***2544. Sardar Partap Singh Kairon** (Ratta Khera) : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of punitive police posts in the State as on 1st January, 1953 and on 1st January, 1954 respectively;

(b) the total amount of expenses incurred on these posts and borne by the people of the areas concerned in the year 1953;

(c) the total number of proclaimed offenders in the State, as on 1st January, 1953 and on 1st January, 1954 respectively;

(d) the total number of proclaimed offenders, in the State killed in police encounter in the year 1953?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): (a) 17 and 18 respectively.

(b) A total expenditure of Rs. 4,53,180-7-9 was incurred on these posts and a sum of Rs. 1,72,668-12-3 was realized from the people of the areas concerned, in the year 1953. The balance will be realized in subsequent years.

(c) 521 and 498 respectively.

(d) 18.

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ: ਮਾਨਯੋਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ।

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी: अगर माननीय मैम्बर को प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आता तो मैं इस का कोई इलाज नहीं कर सकता ।

पंडित श्री राम शर्मा: मैं गुज़ारिश करना चाहता हूं कि Treasury Benches पर बैठे हुए माननीय मैम्बर की तरफ़ से प्रश्नों का जवाब ironical तौर पर दिया जाता है जिस से हाऊस की dignity कायम नहीं रह सकती । अगर हम भी इस तरह करना शुरु करदें तो यह एक नाखुशगवार सिलसिला शुरु हो जायेगा । इसलिये मैं आप से गुज़ारिश करूंगा कि आप इन्हें कहें कि वह इस तरह के ironical remarks न करें ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ: ਇਹ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਾਗ ਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ?

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी: अगर माननीय मैम्बर अलहृदा नोटिस दें तो उन्हें इस बारे में सूचना दी जा सकती है ।

ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਇ: ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ?

CHALLANS MADE BY THE POLICE.

*2554. **Sardar Partap Singh** (Ratta Khera): Will the Chief Minister be pleased to state the number of persons in the State who were challaned by the Police under sections 107/151 and 109/151, Criminal Procedure Code, respectively, in each of the years 1951, 1952 and 1953?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : The required information is given as under—

Year.	No. of persons challaned by the Police under section 107/151, Cr. P. C.	No. of persons challaned by the Police under section 109, Cr. P. C. (*Note*. Section 151, Cr. P. C., is never combined with Section 109, Cr. P. C.)
1951	19,684	4,572
1952	16,572	3,365
1953	17,437	3,499

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਲਾਨ ਦਫਾ ੧੦੭/੧੫੧ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं दी जा सकती ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ੧੯੫੩ ਵਿਚ ਚਾਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ?

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : तादाद बढ़ी नहीं बल्कि कम हो गई है ।

DISMISSAL OF CORRUPT OFFICIALS IN THE STATE.

***2567. Shri Rala Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state the number, department-wise, of corrupt officials who have been dismissed as a result of the enquiries of the Anti-Corruption Committee in the State during the period from April, 1953 to January, 1954?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : The Anti-Corruption Committee itself makes no enquiries.

CORRUPT PANCHES AND SARPANCHES.

***2568. Shri Rala Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state the number of corrupt panches and sarpanches punished by the Government during the year 1953-54 in the State?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : The required information is being collected and will be supplied to the member when ready.

JUVENILE REFORMATORY SCHOOLS IN THE STATE.

*2569. **Shri Rala Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Juvenile Reformatory Schools in the State being run at present by the Government, the total number on their rolls at present, and the total cost incurred by the Government on them;

(b) the percentage of the students in these schools belonging to the erstwhile criminal tribes;

(c) the criteria for admission to these schools and at whose suggestion or recommendation these admissions are made?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : It is regretted that the answer to the question is not ready. The information is being collected and will be supplied as soon as it is ready.

HOLDING OF COURTS BY MAGISTRATES OF SUB-DIVISION FAZILKA.

*2653. **Shri Teg Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of days during which the Magistrate, Thana Khuian Sarwar and Ilaqa Magistrate, Thana Abohar, Sub-Division Fazilka held their courts during the months of October and November, 1953;

(b) the total number of days during which they held their courts at their headquarters;

(c) the total number of days during which the Court was held at Abohar and at the rest houses in the areas concerned;

(d) the total expenditure incurred by the Government in connection with T.A. and Daily Allowance of the Reader, Prosecuting Sub-Inspector and other members of the staff attached to the said Magistrates during the period mentioned in part (a) above?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) :

	Magistrate, Thana Khuian Sarwar	*Ilaqa Magistrate, Thana Abohar*
(a)	41	38
(b)	32	30
(c)	9	8
(d)	Rs. 130 approximately	Rs. 145 approximately.

श्री तेग राम : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इतने दिन मैजिस्ट्रेटों को headquarters से बाहिर अदालत लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी ?

अध्यक्ष महोदय : This does not arise out of the main question.

DECENTRALIZATION OF ADMINISTRATION IN THE STATE.

*2654. **Shri Teg Ram**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Punjab Government intends to follow the policy of decentralisation of administration; if so, the steps so far taken by the Government in this connection;

(b) whether under the said policy, Government intends to appoint a Magistrate at Abohar, District Ferozepore; if so, the steps that are being taken by the Government in this connection and the time by which a magistrate is likely to be appointed at Abohar?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): (a) Yes. In pursuance of the policy of decentralisation of administration, Government have posted Resident Magistrates at a number of Tehsil headquarters. As a result of recommendations made by the Committee on reorganisation of District Administration, it is proposed to open new Sub-Divisions at Tehsil Headquarters generally in the Gurdaspur, Hissar, Rohtak, Gurgaon, Kangra, Hoshiarpur, Jullundur, Ferozepore and Amritsar districts. In the field of Local Government a Decentralisation Committee was appointed by Government last year to explore the possibilities of greater association of rural population with the adminstration. Village Panchayats have been set up, and they have been invested with administrative and judicial functions. The number of Panchayats has been considerably increased, and they have been given larger powers. Thana Panchayats Unions are expected to be set up soon. It is further proposed to rename the District Boards as District Panchayat Boards, and to have indirect elections for them through an electoral college each consisting of the Panchayats in the district. Some of the powers previously exercised by the Commissioner under various laws relating to local bodies have been delegated to the Deputy Commissioners. Under the scheme of reorganisation of District administration, it is now proposed to transfer work relating to local bodies to Sub-Divisions and to invest the Sub-Divisional Officers with necessary powers in that behalf.

(b) No. It is not proposed to appoint a whole-time Magistrate at Abohar.

पंडित श्री राम शर्मा: क्या मैं यह मालूम कर सकता हूं कि सरकार की जो decentralization की नीति है और क्या जिस की सब से बड़ी कड़ी सब-डिवीज़नल मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने की है इस के अनुसार क्या यह सब-डिवीज़नल मैजिस्ट्रेट तमाम तहसीलों में लगाए गए हैं या कहीं कहीं लगाए गए हैं ?

मुख्य मंत्री: कुछ सब-डिवीज़नल अफ़सर पहले ही मौजूद हैं और कुछ जगहों पर सब डिवीज़न कायम करने का फ़ैसला किया गया है । हर ज़िले में फौरन सब-डिवीज़न कायम नहीं हो जायेंगे । जिन ज़िलों का नाम लिया गया है उन में सब-डिवीज़न बना दिये जायेंगे । वैसे सरकार का इरादा यह है कि हरेक तहसील को आहिस्ता आहिस्ता सब-डिवीज़न बना दिया जाएगा । सब-डिवीज़न बनाने की ग़रज़ यह है कि लोगों को ज़्यादा सहूलत दी जाए और उन को अदालती काम के बारे में दूर न जाना पड़े । उस तरह से वह अपनी आमदनी भी बढ़ा सकेंगे ।

श्री तेग राम: इस सवाल के दूसरे भाग के उत्तर में यह बताया गया है कि अबोहर में Resident Magistrate रखने का कोई इरादा नहीं है। क्या इस बारे में कोई जांच पड़ताल हुई थी ?

मुख्य मंत्री: पहले हम ने यह कहा था कि हम जगह जगह पर Resident Magistrate नियुक्त कर देंगे। इस फ़ैसले की बुनियाद यह थी कि मैजिस्ट्रेट चूंकि headquarters में रहते हैं इसलिये लोगों को दूर दूर से उन के पास आना पड़ता है। इसलिये हमने सोचा था कि लोगों की सहूलत के लिये Magistrates को तहसीलों में भेज दिया जाये या दूसरी मुनासिब जगहों पर भेज दिया जाये। उस के बाद Reorganisation Committee ने रिपोर्ट दी कि बजाए मैजिस्ट्रेटों को तमाम तहसीलों में भेजने के हमें ऐसा करना चाहिये कि जिस से लोगों का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। हमने Resident Magistrate फ़ौरी तौर पर लोगों को सहूलत देने के लिये नियुक्त किये थे। अब हम देखते हैं कि Sub-Divisional Magistrate ज्यादा लाभ लोगों को देंगे। हम चाहते हैं कि यह काम जल्दी हो। परन्तु काम करने वालों की किल्लत रास्ते में हायल है।

पंडित श्री राम शर्मा: कितने Sub-Divisional Magistrate अब तक बाकायदा तौर पर काम करने लग गये हैं ?

मुख्य मंत्री: इस के लिये आप की मनजूरी का इन्तज़ार है। बजट पास होने के बाद पहली अप्रैल से यह काम शुरु हो जाएगा।

पंडित श्री राम शर्मा: क्या Resident Magistrate सब जगहों पर लगाए गए हैं ?

मुख्य मंत्री: वह सब जगहों पर नहीं लगाए गए हैं।

श्री रंजीत सिंह कैप्टन: यह Sub-Divisional Magistrate नियुक्त करने पर कितना खर्च होगा ?

मुख्य मंत्री: थोड़ा और इन्तज़ार कीजिये। अर्थ मंत्री महोदय इस का पूरा जवाब दे देंगे।

राय रघुबीर सिंह: Reorganisation Committee ने अपनी रिपोर्ट में कुछ जगहों पर Sub-Divisional Magistrate नियुक्त किये जाने के बारे में कहा है। क्या यह काम बाज़ दूसरी जगहों पर भी शुरु किया जाएगा ?

Mr. Speaker: This does not arise.

पंडित श्री राम शर्मा: चूंकि मैजिस्ट्रेटों को headquarters से तहसीलों में भेजा जाता है, वह आम तौर पर इस को पसंद नहीं करते। ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार के पास आई है या नहीं ?

Mr. Speaker: Disallowed.

ਸਰਦਾਰ ਅਛੱਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ: ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਜੋ ਕਿ ਦੂਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

मुख्य मंत्री: क्या आप को यकीन है कि आप की information ठीक है ?

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ?

मुख्य मंत्री: यह वक्त बताएगा ।

RAISING OF MEMORIAL AT THE BIRTH PLACE OF LALA LAJPAT RAI.

***2680. Shri Ram Kishan** : Will the Chief Minister be pleased to state whether he has received any resolution passed by the Punjab Pradesh Congress Committee for making a suitable memorial at the birth place of Punjab Kesri Lala Lajpat Rai; if so, the steps so far taken by the Government in this connection?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : Yes. The matter is under consideration.

पंडित श्री राम शर्मा: यह काम कितना समय लेगा ?

Chief Minister : That will be taken into consideration.

श्री राम किशन: स्पीकर साहिब ! पहले सवाल करने वाले को Supplementary पूछने की आज्ञा मिलनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय: यह जरूरी नहीं है । कोशिश यही होती है कि उसे पहला मौका दिया जाए ।

प्रोफैसर मोता सिंह (आनंदपुरी): इस सवाल में यह चीज understood रखी गई है कि किस का suitable memorial बनाया जाना है । मैं यह जानना चाहता हूं कि memorial किस का बनाया जाना है ? (*Laughter*) ।

अध्यक्ष महोदय: सवाल का मोहमल होना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है । बल्कि उन की है (*Laughter*) !

श्री राम किशन: क्या चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी साहिब बताने की कृपा करेंगे कि इस बारे में कब तक फैसला होगा ?

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी: जल्दी ही फ़ैसला होगा ।

पंडित श्री राम शर्मा: स्पीकर साहिब, इस प्रश्न में दिया हुआ है कि लाला लाजपत राय की बर्थ प्लेस (Birth place) में एक मैमोरियल (memorial) बनाया जायेगा तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि किस का मैमोरियल बनाया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने उत्तर में कहा है कि The matter is under consideration इस का अर्थ यह हुआ कि जगह, सूटेबिलेटी (suitability) और कब होगा आदि सब बातें cover हो जाती हैं ।

प्रोफ़ेसर मोता सिंह अनन्दपुरी: किस का मैमोरियल बनेगा यह नहीं बताया गया ।

मुख्य मंत्री: मैं यह बात वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि सरकार का इरादा किसी मैम्बर का मैमोरियल बनाने का नहीं है (*Laughter*) ।

पंडित श्री राम शर्मा: तो क्या किसी वकील का मैमोरियल बनाने का है ?

अध्यक्ष महोदय: यह शायद अंग्रेजी भाषा का दोष है या समझने वालों का कि अगर लाला लाजपत राये की बर्थ-प्लेस (Birth place) पर मैमोरियल बनेगा तो उन्हीं का ही बनेगा न कि किसी और का ।

LIQUIDATION OF PROCLAIMED OFFENDERS IN ROHTAK DISTRICT.

*2689. **Pandit Shri Ram Sharma**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total yearly expenditure incurred by the Government during the last 3 years on the special police operations to liquidate proclaimed offenders in Rohtak district;

(b) the names of Deputy Superintendents and Inspectors of Police put incharge of these operations;

(c) the reasons for such a long time being taken in liquidating most of the proclaimed offenders;

(d) whether the ring leader of these proclaimed offenders Hem Raj is still at large; if so, the reasons therefor?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): Information in respect of this question is being collected and will be supplied to the member shortly.

पंडित श्री राम शर्मा: स्पीकर साहिब, कहीं ऐसा न हो कि प्रश्न का उत्तर मेरे घर भेज दिया जाये और on the floor of the House मुझे जवाब न दिया जाए ।

Mr. Speaker: The Chief Parliamentary Secretary has already stated that the information in respect of this question is being collected and will be supplied to the hon. Member very shortly. He cannot go beyond that.

पंडित श्री राम शर्मा: इसे घर भेजने का मतलब यह है कि Starred question को unstarred कर दिया जायेगा । अगर यह ठीक है तो क्या मैं आज से ही उस का फ़िक्र करूं ? अगर यह बात है तो वह बुरी बात है ।

मुख्य मंत्री: स्पीकर साहिब, सवाल यह है कि जब कोई मैटीरीयल इकट्ठा हो जाता है तो वह फौरन मैम्बर साहिबान की खिदमत में पेश कर दिया जाता है । बाज़ वक्त यह होता है कि एक सवाल आ जाता है जिस के जवाब की सामग्री इकट्ठी नहीं होती तो हम कह दिया करते हैं कि समय को बढ़ा दिया जाये । इस तरह मैम्बर साहिबान को कई बार उत्तर नहीं मिलता था । अब यह लिख कर कि "सूचना इकट्ठी की जा रही है" हम ने अपने हाथों को बांध दिया है । जो सूचना हम देंगे उस सूचना के बिना पर माननीय मैम्बर बहस कर सकते हैं । उस की बिना पर कोई प्रश्न खड़ा कर सकते हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा: तो गोया हम को दुबारा नोटिस देना पड़ेगा । इस का तो यह मतलब हुआ कि हाथ तो हमारे बांधे गए हैं ।

Mr. Speaker: He has already replied that the information is being collected and will be placed before the House. He should not think that we are going to make a starred question an unstarred one.

पंडित श्री राम शर्मा: जनाब का यह मतलब है कि यदि सूचना अधिवेशन के दौरान में इकट्ठी हो गई तो सभा में ही दे दी जायगी।

अध्यक्ष महोदय: हां जी।

MURDERS COMMITTED BY THE PROCLAIMED OFFENDERS IN ROHTAK DISTRICT.

***2690. Pandit Shri Ram Sharma**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the persons together with the dates and their brief accounts, murdered and seriously wounded by the proclaimed offenders in Rohtak district during the last five years;

(b) the number of cases of police encounters with the proclaimed offenders during the period mentioned in part (a) above and with what results;

(c) the names of proclaimed offenders killed and arrested by the Police during the above-mentioned period;

(d) the names of police informers killed by the proclaimed offenders and the rewards, if any, given to their dependants by the Government?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): Information in respect of this question is being collected and will be supplied to the member shortly.

DETENTION OF PERSONS HARBOURING THE PROCLAIMED OFFENDERS IN ROHTAK DISTRICT.

***2691. Pandit Shri Ram Sharma**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names along with the addresses of the persons arrested and detained by the Police in Rohtak District for harbouring the proclaimed offenders since 1st January, 1951 together with the period for which each of such persons was kept in detention;

(b) whether the persons referred to in part (a) above after their release from detention gave up harbouring the proclaimed offenders and gave a good account of themselves; if not, the steps taken by the Government in the matter?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): Information in respect of this question is being collected and will be supplied to the member shortly.

पंडित श्री राम शर्मा: अध्यक्ष महोदय ! मुझे एक माननीय सदस्य ने अभी २ बताया है कि उन के प्रश्नों का उत्तर पिछले दो साल से नहीं दिया गया । मेरी अर्ज़ है कि आप मेरा गरीब का ख्याल रखें कि मेरे साथ ऐसा वर्ताव न किया जाये और ऐसी नौबत न आवे ।

ADDITIONAL POLICE POST IN LUDHIANA CITY.

*2780. **Shri Mani Ram**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) with reference to the reply to part (a) of starred Assembly question No. 975 printed in the list of Starred Assembly Questions, dated 27th October, 1952; a copy of the Government notification published in the *Government Gazette* in connection with the quartering of the Additional Police Post in Ludhiana City under section 15 of the Police Act be laid on the Table;

(b) whether any mohallas of the City were excluded from the operation of this notification; if so, their list;

(c) the list of the mohallas from which the cost of the Additional Police Post referred to in part (a) above was to be recovered;

(d) (i) the total cost of the Additional Police Post imposed on the inhabitants of the mohallas referred to in part (c) above;

(ii) the total amount recovered up to 31st December 1953, from the inhabitants of the mohallas referred to in part (c) above; if not, the reasons therefor?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): (a) A copy of *Punjab Government Gazette* notification regarding the quartering of this Additional Police Post is given below.

(b) No mohalla was originally excluded from the operation of this notification. Subsequently, however, on a representation being made by some inhabitants in February, 1951, Government decided to remit a sum of Rs. 49,038 being the assessment on the residents of unaffected mohallas. A list (marked 'H') of affected mohallas is given below. The rest were unaffected mohallas.

(c) The list marked 'H' given below contains this information.

(d) (i) Rs. 1,10,941. This includes an amount of Rs. 63,926 due from Muslims, since migrated to Pakistan. A claim for this amount has been made to the Custodian, Evacuee Property.

(ii) Rs. 6,669 have been recovered from non-Muslim inhabitants of these mohallas, up to 31st December 1953. A sum of Rs. 40,346 is still due from them. Efforts to recover the balance are being made.

PUNJAB GAZETTE
PART I
Home/Police.

No. 5529-C, dated Lahore, the 9th November 1946.

Under the provisions of section 15 of the Police Act V of 1861, the Governor of the Punjab is pleased to declare that the area comprising Ludhiana Town, in the Ludhiana District, is in a disturbed state and because of the misconduct of the inhabitants of the aforesaid area, it is expedient to increase the number of Police.

The proclamation shall remain in force for a period of one year from the date the extra Police are actually entertained and shall be further notified by being posted on the :—

Court-house at Ludhiana.

Post Office at Ludhiana.

Police Station at City Ludhiana.

Patwar Khana at Ludhiana.

The extra Police will be quartered at Ludhiana Town.

LIST 'H'.

1. Shiwala Sanglawala.
2. Mahian.
3. Bangruan.
4. Wait Ganj.
5. Hazuri Road.
6. Rupa Mistri.
7. Meleri Mal.
8. Iqbal Ganj.
9. Ghas Mandi.
10. Gulchaman Gali.
11. Saban Bazar.
12. Ganji Chapri.
13. Madho Puri.
14. Lal Masjid.
15. Khud Mohalla.
16. Chowk Gujran.
17. Wakefield Ganj.
18. Gopal Road.
19. Choongaran.
20. Chowk Nimwala.
21. Lakkar Bazar.
22. Chaura Bazar.
23. Pul Kutchry.
24. Chowk Government School.
25. Chowk Kothi Sherawala.
26. Chowk Bijlighar.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं गवर्नमेंट से पूछ सकता हूं कि किस जुर्म की पैदायश में शहर में ऐडीशनल पुलिस बिठाई गई है । और जिन मुहल्लों में नहीं बिठाई गई उन्होंने कौनसा नेकी का काम किया है ?

पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : वह गज़ट हर एक माननीय मैम्बर साहिब को भेज दी जाती है। इस के साथ ही मैं यह भी कह दूं कि गज़ट की कापियां उन्हें इस तवक्कुह से भेजी जाती हैं कि वे उन्हें पढ़ेंगे।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि जो चीज़ उस गज़ट में होती है उस की कापियां फिर दोबारह इस हाउस के मम्बरान को नहीं बांटी जायेंगी ?

मंत्री : जी नहीं।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं मुख्य मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि प्रश्न करने वाले माननीय मैम्बर को कब रिहा किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप यह सवाल किसी और ढंग से पूछ सकते हैं। Supplementary (सप्लीमैंट्री) के ज़रिये नहीं।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਆਲ ਸਨ ੧੯੫੦-੫੧ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ (information) ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ?

पंडित श्री राम शर्मा : यह सवाल भी floods में बह गया मालूम होता है।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

PAYMENT OF BASTA ALLOWANCE TO REVENUE AND CANAL PATWARIS IN THE STATE.

*1954. **Sardar Sarup Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether any Basta Allowance (Conveyance Allowance) is being paid to the Revenue Patwaris in the State; if so, its rate per mensem;

(b) whether any Conveyance (Bast) Allowance is being paid to the Canal Patwaris; if so, at what rate per mensem;

(c) whether there is any difference between the allwances referred to in parts (a) and (b) above; if so, to what extent and the reasons therefor?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Rs. 4 per mensem.

(b) Rs. 6 per mensem.

(c) Yes. The difference is of Rs. 2 per mensem. Canal Patwaris have probably to do more touring and moving about.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं विकास मंत्री साहिब से पूछ सकता हूं कि नहरी पटवारियों को माल के पटवारियों के मुकाबले में दो रुपये ज़्यादा क्यों दिये जाते हैं ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਸ ਜੁਵਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ "Canal Patwaris have probably to do more touring and moving about".

पंडित श्री राम शर्मा: यह कैसे पता चल गया कि नहरी पटवारियों को माल के पटवारियों की निस्बत ज्यादा टूर (tour) करना पड़ता है ?

सिंचाई मंत्री: यह तो आप खुद अपने तजुरबे से भी अन्दाज़ा लगा सकते हैं ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਜ਼ੇਲਦਾਰ ਨੂੰ 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 6 ਜਾਂ 8 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੀ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੁਪਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੀੜਾ ਲੱਤਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

RECTIFICATION OF GIRDAWARIS.

*2253. **Shri Babu Dayal Sharma** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of applications received by each Collector in the State for rectification of previous Girdawaris since the Punjab Security of Land Tenures Act, 1953, was passed; together with the number of Girdawaris so corrected district-wise in the State;

(b) the number of applications for correcting previous Girdwaris that are pending in each district of the State;

(c) the total number of applications for correcting previous Girdawaris that were rejected?

Sardar Partap Singh Kairon : The statement is given below.

Name of district.	*Part* (*a*)		(*b*)	(*c*)
	(i) Applications received.	(ii) Girdawaris corrected.	Applications pending.	Applications rejected.
1. Hissar ..	553	425	11	117
2. Rohtak ..	14	2	7	5
3. Gurgaon ..	84	21	21	42
4. Karnal ..	6	..	2	4
5. Ambala ..	14	..	14	..
6. Simla ..	..	..	..	..
7. Kangra ..	20	..	15	5
8. Hoshiarpur ..	135	85	37	13
9. Jullundur ..	..	..	..	..
10. Ludhiana ..	..	..	..	..
11. Ferozepore ..	563*	102	312	32
12. Gurdaspur ..	79	18	9	52
13. Amritsar ..	..	..	..	..
Total ..	1,468	653	428	270

*The remaining 117 applications were either withdrawn by the applicants or compromises were effected.

श्री बाबू दयाल : क्या मैं पूछ सकता हूं कि जिला गुड़गांवां में गिरदावरियों को ठीक करने के लिए दी गई दरख्वास्तों में से जो 42 दरख्वास्तें नामंजूर की गईं उन में रघुनाथ दास नामक मुजारे की भी कोई दरख्वास्त थी ?

मंत्री: इस के लिये मुझे नोटिस चाहिये ।

COWS AND STUD BULLS IN THE STATE.

*2594. **Shri Jagat Ram Bhardwaj:** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the number of cows and stud bulls in each district of the State at the time of the last census;

(b) whether the Government has under consideration any proposal to assign to the Veterinary Department the work of evolving a breed of cows capable of yielding a larger quantity of milk and of giving a better quality of draught oxen;

(c) the steps, if any, so far taken by the Government to popularise artificial insemination to ensure good quality breeding?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) Cow bulls at stud and cows over three years of age kept for breeding and milk as per Livestock Census, 1951.

Name of district.	Number of cows bulls at stud in various districts in the Punjab.	Number of cows over three years of age kept for breeding or milk.
Hissar ..	1,400	155.542
Rohtak ..	913	91,222
Gurgaon ..	569	115,041
Karnal ..	546	150,634
Ambala ..	204	85,052
Simla ..	1	453
Kangra ..	185	161,406
Hoshiarpur ..	79	68,427
Jullundur ..	90	52,264
Ludhiana ..	345	58,127
Ferozepore ..	715	114,676
Amritsar ..	122	75,106
Gurdaspur ..	68	86,393

(b) A scheme to supplement Livestock Investigation work at the Government Livestock Farm, Hissar, whose sole object is to develop the milking capacity of Hariana breed of cattle without affecting their draught ability is already in progress. It is jointly financed by the Punjab Government and the Indian Council of Agricultural Research on 50 : 50 basis and the investigations are carried out in accordance with the detailed breeding programme laid down by the Council. As a result of the investigation carried on under this scheme, only those bulls are being used at the Government Livestock Farm, Hissar which have a greater pre-potency for milk and capable of infusing milk strain, in the progeny. Besides the Punjab Government have sanctioned a scheme for the starting of a cross breeding station at Palampur for upgrading the Kangra District cattle from 1st April 1954. The scheme is financed jointly by the Indian Council of Agricultural Research and the Punjab State on 50 : 50 basis.

(c) One Artificial Insemination Centre was started at the Government Livestock Farm, Hissar in December, 1951. During the current financial year (1953-54) 5 new Artificial Insemination Centres with 20

Key villages have been opened under the Key Village Scheme at the following places:

1. Government Dairy Farm, Chandigarh.
2. Gaushala Rewari (District Gurgaon).
3. Veterinary Hospital, Ludhiana.
4. Veterinary Hospital, Banga (District Jullundur).
5. Khalsa College, Amritsar.

In addition to the above, the Agricultural Marketing Committee in the State have also decided to start Artificial Insemination Centres at the following places:—

1. Moga.
2. Jagraon.
3. Sanehwal.
4. Rohtak.

The Community Project authorities are also starting an Artificial Insemination Centre in each Project area from the next year.

TEST FOR THE RECRUITMENT OF ASSISTANTS IN FINANCIAL COMMISSIONER'S OFFICE.

*2687. **Shrimati Sita Devi** : Will the Minister for Development be pleased to state whether it is a fact that the qualifying test for the recruitment of Assistants in the Financial Commissioner's Office, Simla, was scheduled to be held on the 19th December, 1953; if so, the total number of candidates who appeared in the said test?

Sardar Partap Singh Kairon : *First part.* Yes.
Second part. None.

ESTABLISHMENT OFFICER, FINANCIAL COMMISSIONER'S OFFICE.

*2688. **Shrimati Sita Devi** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the date of superannuation of the Establishment Officer, Financial Commissioner's Office;
(b) whether there is any proposal under the consideration of the Government to re-employ the said establishment officer or to give him an extension in service; if so, the reasons therefor?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) 4th September 1954 (Forenoon).
(b) *First part.* No.
Second part. Does not arise.

EMPLOYMENT OF WORKERS OF BHAKRA NANGAL PROJECT.

*2230. **Sardar Darshan Singh** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total number of workers employed on the Bhakra Nangal Project during the years 1950, 1951, 1952 and 1953, respectively;
(b) the system according to which requirement of these is made together with the rates paid to the different categories of workers during the period mentioned in part (a) above.

Chaudhri Lahri Singh : (a) The total number of workers employed on the Bhakra Nangal Project (Bhakra Dam Administration) during the years 1950, 1951 1952, and 1953 is as below:—

1950	52,676	1952	96,864
1951	89,469	1953	1,37,664

(b) The recruitment is made on monthly wage basis according to previous experience, qualification and suitability of the individuals for particular categories of posts. The monthly wages for different categories of workers are shown in a statement given below.

Monthly Wage exclusive of D. A. and Ty. Allowance.

Category	Before 1st January, 1953.
GROUP I	
A—MECHANICAL	Rs.
1. Foreman ..	150—5—200
2. Assistant Foreman ..	120—4—160
3. Chargeman ..	100—3—130
4. Supervisor ..	80—3—110
5. Superintendent, Water Works ..	80—3—110/4—130
B—ELECTRICAL	
6. Foreman ..	150—5—200
7. Assistant ..	120—4—160
8. Chargeman ..	110—3—130
C—CIVIL ENGINEERING	
9. Road Inspector ..	50—3—80/4—100
10. Works Mistri ..	50—3—80/4—88
11. Darogah (Boat Bridges) ..	50—3—80/4—88
GROUP II	
A—MECHANICAL	
1. Mechanical Tool Operator ..	50—2—60/3—90
2. Fitter ..	50—2—60/3—90

Category	On and after 1st January, 1953.	
	Min.	Max.
GROUP A		
1. *Foreman, Special* ..	300	500
Structural Shop Processing Plant. Batching and Mixing Plant. Placement Plant. Erection of Trestles. Maintenance of Special Plant. Repair of Special Plant at Bhakra Site. Welding Machinery. Earthmoving. Drilling.		
2. *Foreman, (Electrical)* ..	210	300
Heavy Plant overhaul.		
3. *Foreman Miscellaneous* ..	150	225
Automobile. Machine Shop. Foundry. Carpentry.		
ELECTRICAL		
4. *Assistant Foreman (Special)* ..	210	300
For jobs given under Foreman (Special)		
5. *Assistant Foreman* ..	150	225
For jobs against Foreman.		
ELECTRICAL (HEAVY WORK)		
6. *Assistant Foreman Miscellaneous* ..	120	150

		Rs.
3.	Pattern Maker ..	50—2—60/3—90
4.	Black Smith ..	50—2—60/3—90
5.	Copper and Tin Smith ..	50—2—60/3—90
6.	Moulder ..	50—2—60/3—90
7.	Turner ..	50—2—60/3—90
8.	Pipe Jointer ..	50—2—60/3—90
9.	Instrument Mechanic.Including Meter Mechanic	50—2—60/3—90
10.	Welder ..	50—2—60/3—90
11.	Tradesman's Mate to all above trades ..	25—1—30
12.	Hammerman ..	25—1—30
	B—ELECTRICAL	
13.	Fitter ..	50—2—60/3—90
14.	Electrician ..	50—2—60/3—90
15.	Lineman ..	40—2—60/3—90
16.	Wireman ..	40—2—60/3—90
17.	Switchboard Attendant ..	50—2—60/3—90
18.	Cable Jointer ..	90—5—140/6—170
19.	Armature Winder ..	50—2—60/3—90

		Min.	Max.
	For jobs given under Foreman Miscellaneous		
	ELECTRICAL (LIGHT PLANT)		
7.	*Chargeman, Special* ..	150	225
	For jobs given against Foreman (Special)		
8.	*Chargeman* ..	130	150
	For jobs given against Foreman.		
9.	*Chargeman Miscellaneous* ..	100	130
	For jobs against Foreman Miscellaneous Boiler.		
10.	Power House Superintendent ..	400	600
11.	Shift Engineer ..	250	400
	GROUP B		
1.	Template Maker of Steel Structural. Fitter Steel Structure. Errector Steel Structure	100	150
2.	*Journeyman, Special* ..	60	100
	Pattern Maker Moulder. Turner. Welder Electric and Gas. Instrument Mechanic (including Telephone and Refrigerator Mechanic)		
3.	*Journeyman, Mechanical* ..	60	90
	Tool Operator (Mechanic) Fitter heavy machine. Blacksmith. Copper and Tin Switch. Pipe Jointer. Diesel Mechanic. Carpenter. Motor Mechanic.		

Category	Before 1st January 1953
	Rs.
20. Instrument Mechanic (Including Telephone and Refrigeration Mechanic)	50—2—60/3—90
21. Trademan's Mate to all above trades ..	25—1—30
C—CIVIL ENGINEERING	
22. Surveyer ..	75—5—140
23. Plumber ..	40—2—60/3—90
24. Mason ..	40—2—60/3—90
25. Carpenter ..	40—2—60/3—90
26. Painter ..	40—2—60/3—90
27. Bricklayer ..	40—2—60/3—90
28. Sanitary and Gas Fitter ..	40—2—60/3—90
29. Platelayer ..	40—2—60/3—90
30. Well borer on rock driller. ..	90—5—140
31. Driller Foreman ..	150—8—190—10—240
32. Tradesman's Mate to all above trades ..	25—1—30
33. Meter Reader ..	50—2—70
GROUP III	
1. Driver (Locomotive) ..	60—3—90
2. Driver (Road Roller) ..	60—3—90 (to be paid during idle days according to P.W.D., Buildings and Roads Branch Manual)

Category	On and after 1st January 1953	
	Min.	Max
4. *Journeyman, Electrical* ..	60	90
Fitter. Electrician (Ordinary). Wireman-Lineman. Switch Board Attendant. Armature Winder. Driller Jack Hammer. Blastman.		
GROUP C.		
OPERATORS AND DRIVERS		
1. *Shovels, Dragglinge and cranes (diesel)*—		
Up to 1½ cyds size light ..	125	125
2 cyd. to 5 cyd Heavy ..	125	225
2. *Shovels Electrical* ..	125	225
2½ cyd to 5 cyd Whirly Crane, Truck Crane, Hammer Head Crane and Derrick Crane.	185	325
3. *Drivers of Carriers*—		
(Light vehicles)		
Cars, petrol Trucks 2½ tons, etc. ..	60	90
(Heavy vehicles)		
Diamond tees, macks, dumpers, etc. ..	60	90
Euclids ..	90	125
Dinkey Loco Driver, Main Line Loco Driver	60	90

3.	Driver (Motor Lorry and Tractor) ..	60—3—90
4.	Operator (Mechanical) Special ..	60—4—100/5—150
5.	Operator (Excavator) ..	60—4—100/5—150
6.	Driver (Crane, winch and Haulage) ..	60—3—90
7.	Driver (Stationary and Marine Steam Plant including steam power plant as well as ship and launch propulsion engines)	60—3—90
8.	Driver (Stationary Marine internal combustion plant including stationary as well as ship and launch propulsion engines)	60—3—90
9.	Driver Stationary (electrically operated plant)	60—3—90
10.	Driver (Stationary hydraulically operated plant)	60—3—90
11.	Operator (Gas producer plant) ..	35—1—45
12.	Cleaner (all classes of plant) ..	25—1—30
13.	Greaser oilman (all classes of plant) ..	25—1—30
14.	Fireman or stoker ..	25—1—30
15.	Boilder Attendant ..	25—1—30
16.	Condenser Attendant ..	25—1—30
17.	Coalman ..	25—1—30
18.	Attendants concrete mixers ..	25—1—30

	Min.	Max.
4. *Tractor Operators* (Light Tractors) D/4, Fowler, Marshal, etc. ..	60	90
D/6, D/7, D/8 Road Craders, T. D. 24, H. D. 20, etc.	100	130
5. *Operators Stationary Plant*—		
(Mechanical or Electrical) ..	60	90
Air Compressors, Pump, Pumpcrete, Welding sets, concrete mixers, small Generating sets		
GROUP D		
Aggregate Plant Control Batching and Mixing Plant Hoisting double drums. Plumbers.	150	200
GROUP E		
(*Transportation*)		
Station Master ..	75	100
Train Examiner Railway Guard ..	75	100
Shunter ..	50	60
Gangman, Trolleyman, Keyman ..	35	45
Gangmate, Trolley Jamadar, Bre ..	40	50

	Category	Before 1st January, 1953.	Category	On and after 1st January, 1953. Min.	Max.
	GROUP III—*contd*				
19.	Attendants Pumps ..	25—1—30			
20.	Workshops Gangman ..	25—1—30	GROUP		
	GROUP IV		(*Semi skilled*)		
1.	Work Mistri ..	50—3—80/4—88	Cleaners ..		
2.	Earthwork Mistry ..	35—1½—50	Greasers ..		
3.	Works Munshi ..	35—1½—50	Fireman ..		
4.	Gang Mate ..	25—1—30	Boiler Attendants ..		
5.	Darogha (Arboricultural or Head Mali) ..	35—1—50	Attendants Concrete ..		
6.	Reservoir Keeper ..	30—1—45	Mixer ..		
7.	Tar Sprayer ..	20—½—25	Attendants ..	30	40
8.	Keyman or Turn Cock (water-supply works)	20—½—25	Workshop Gangmen ..		
9.	Petrolman ..	20—½—25	Hammerman ..		
10.	Road Beldars ..	20—½—25	T. M. Mate ..		
11.	Pipe Lines man ..	20—½—25	Gangmates ..		
12.	Sewer Man ..	20—½—25	Coalman ..		
13.	Regulation Jamadar	The pay of these classes of establishment has been fixed separately.	Condenser Attendants ..		
14.	Assistant Regulation Jamadar ..		Muckers ..	30	40
15.	Gauge Reader ..		Mucker Jamadars ..	35	45

16. Discharge or sounding attendant ..	25—2—35			
17. Bhishties or Waterman ..	The rates of pay of these posts should be regulated by the pays fixed for similar posts by the Deputy Commissioners for their respective districts.	Slingers ..	40	60
18. Chowkidars ..		Barryman (Crowharman) ...	35	50
19. Coolies (Hospital) ..				
20. Coolies (Pankha) ..				
21. Sweeper Jamadars or Sanitary Jamadars ..				
22. Boarman or Ferryman ..	20—½—25			
23. Dak Cyclist ..	20—½—25			
24. Dak Runners (Foot) ..	20—½—25			
25. Farashes ..	20—½—25			
26. Khalasis ..	20—½—25			
27. Malis (Road Mates) ..	20—½—25			
28. Peons ..	20—½—25			
29. Sowars Camel ..	20—½—25 *plus* Rs. 8 Camel Allowance			
30. Beldars Regulation (at Head Works) ..	20—½—25			
31. Beldars Regulation (elsewhere than Head Works)	20—½—25			
32. Boatman Head or Jamadar or Daffadar ..	20—½—25			
33. Boatman Naib-Jamadar ..	20—½—25			
34. Deraiman ..	20—½—25			
35. Bullockman and Cartman without Bullock ..	20—½—25			

	Category		Before 1st January, 1953.
			Rs.
36.	Bullockman with one Bullock.	..	20—½—25 *plus* Rs. 30
37.	Bullockman with two Bullocks	..	20—½—25 *plus* Rs. 60
38.	Gate-keeper	..	20—½—25
39.	Khalasis Survey Head	..	20—½—25
40.	Mali Chowkidar at Rest-houses	..	20—½—25
41.	Forest Guard	..	20—½—25
42.	Khansama	..	20—½—25
	(b) TRANSPORTATION		
43.	Station Master	..	60—3—90
44.	Train Examiner	..	50—2—70
45.	Railway Guard	..	50—2—70
46.	Head Shunter	..	30—1—40
47.	Shunter	..	25—1—35
48.	Keyman Railway	..	25—1—30
49.	Breakesman	..	30—1—40
50.	Trollyman Jamadar	..	25—1—30
51.	Trollyman	..	20—½—25
	(c) GENERAL		
52.	Store-keeper	..	50—3—80/4—100
53.	Store Clerk, Store Munshi and Time Clerk		50—2—70
54.	Store Attendant	..	25—1—30

DAILY WAGES

		Rs. A. P.
Coolies ordinary	..	2 0 0
Coolies employed through contractors in emergent cases	..	2 2 0
Coolies skilled	..	2 8 0
Carpenters, Masons, Masons Store, Blacksmith, Turner and Fitter, Trailor, Driver and Lineman	..	3 0 0 to 4 0 0
Painter	..	2 8 0 to 4 0 0
Pair of Bullocks including attendant	..	4 8 0
Bullocks cart including attendant	..	4 8 0
Driver for electric driven machinery	..	3 0 0 to 4 8 0
Hammer man	..	2 8 0 to 5 0 0
Hire of boat with boat man	..	2 8 0
Greaser	..	2 0 0 to 2 8 0
Camel excluding camel man	..	3 0 0
Camel man	..	2 8 0
Local donkey excluding donkey man	..	1 0 0
Donkey man	..	2 0 0
Fitter cooly	..	2 8 0
Dresser	..	3 0 0 to 3 8 0
Dresser through contractor	..	3 5 0
Mates earthwork	..	2 2 0
Mochi	..	3 0 0
Erector	..	2 8 0 to 3 8 0

The Dearness allowance is being paid as below :—

For basic salaries up to Rs. 50	..	30
For basic salaries Rs. 51 to 100	..	40
For basic salaries Rs. 101 to 150	..	40
For basic salaries Rs. 151 to 200	..	45
For basic salaries Rs. 201 to 250	..	50
For basic salaries Rs. 250 to 300	..	60
For basic salaries Rs. 300 to 500	..	70
For basic salaries Rs. 500 to 750	..	85

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 25 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਮਕਿਣ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

ACQUISITION OF LAND FOR DIGGING BHAKRA CANAL AND ITS DISTRIBUTARIES

*2242. **Sardar Achhar Singh Chhina**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total extent of land acquired by the Government for digging the Bhakra Canal and its distributaries, for the distributaries etc. of the Bist Doab Canal, the Upper Bari Doab Canal and the Sidhwan Branch (Sirhind Canal Extension), respectively;

(b) whether the necessary notices for the acquisition of lend referred to in part (a) above were served by the Government on the owner; if not the reasons therefor;

(c) the total amount of compensation paid so far to the owners of land referred to above and the amount yet to be paid on this account;

(d) the total amount of compensation paid for the standing crops destroyed as a result of digging of the said canal and distributaries;

(e) whether the owners of the land which has been acquired for purposes mentioned in Part (a) above are still required to pay land revenue to the Government; if so, the reasons therefor and the total amount of land revenue realised in respect of such land;

(f) whether it is a fact that in respect of the land acquired for which land revenue is still being realised, no compensation is being paid for the crops which the owners could raise on such lands; if so, the reasons therefor?

Chaudhri Lahri Singh : A statement is given below:—

Name of Circle.	Total extent of land acquired by Government for digging the Bhakra Canal and its distributaries etc., of the Bist Doab Canal, U.B. D.C., Sidhwan Branch, S.C. Extension. (a)	Whether the necessary notices for the acquisition of land referred to part (a) above were served by the Government on the owners, if not, reasons therefor. (b)	Total amount of compensation paid so far to owners of land referred to above and the amount yet to be paid on this account. (c)	Total amount of compensation paid for the standing crops destroyed as a result of digging of the said canal and Distributaries. (d)	whether the owners of land which had been acquired for purposes mentioned in column (a) are still required to pay land revenue to the Government, if so, the reasons therefor and the total amount of land revenue realized in respect of such lands. (e)	Whether it is a fact that in respect of the land acquired for which land revenue is still being realized no compensation being paid for the crops which the owners could raise on such land, if so, the reasons therefor. (f)
1	2	3	4	5	6	7
1. Narwana Circle.	763·30 acres ..	Necessary notices were duly served to owners and interested persons.	Rs. 65,346 ..	Rs. 489 ..	The owners of the land are not required to pay land revenue. Necessary statements of land revenue reduction have already been sent to the Collectors of the Districts.	The question does not arise after the announcement of awards.
2. Sirhind Canal Circle.	Total land acquired for the construction of Mudki-Golewala Distributary System Punjab—515.86 acres. Pepsu—664.56 Acres.	Notifications under section 4 of the Land Acquisition Act of 1894 were published in the Government Gazette concerned.	(i) (1) Punjab Rs. 55,951 2. Pepsu Rs. 82,128 (ii) (1) Punjab-Rs. 2,58,950 (2) Pepsu-Rs. 2,97,874	No compensations due for payment on this account.	Land Revenue is being collected by the Civil Departments and as such this information cannot be supplied by the Irrigation Branch.	Land revenue is being collected by the Civil Departments, and as such this information cannot be supplied by the Irrigation Branch.

Name of Circle	Total extent of Land acquired by Government for digging the Bhakra Canal and its distributaries etc., of the Bist Doab Canal, U. B. D. C., Sidhwan Branch S. C. Extension. (a)	Whether the necessary notices for the acquisition of land referred to part (a) above were served by the Government on the oweners; if not, reasons therefor. (b)	Total amount of compensation paid so far to owners of lands referred to above and the amount yet to be paid on this account. (c)	Total amount of compensation paid for the standing crops destroyed as a result of digging of the said canal and Distributaries. (d)	Whether the owners of land which had been acquired for purposes mentioned in column (a) are still required to pay land revenue to the Government, if so, the reasons therefor and the total amount of land revenue realized in respect of such lands. (e)	Whether it is a fact that in respect of the land acquired for which land revenue is still being realized, no compensation is being paid for the crops which the owners could raise on such lands, if so, the reasons therefor. (f)
1	2	3	4	5	6	7
3. Bist Doab Circle	Total land acquired for Sidhwan Branch and its distributaries is 3,000 acres.	Necessary notifications under the provision of section 4 were issued, but due to the urgency of the work the channels were dug before declaration under section 6 as the alignment of almost all the channels were finalized with the consent of the Zamindars. The necessary notification under section 6 for about 70 per cent channel have since been issued andthe documents for the remainig are bing sent up.	The total amount of compensation paid so far is Rs. 13,240-10-0 and the balance to be paid is Rs. 9,00,000.	Rs. 5653 which is being paid to the owners.	The land has been acquired. The question of realization of land revenue does not arise.	Does not arise.
4. Upper Bari Doab Circle	2,160 acres	Yes	Awards have not yet been announced	Nil.	Yes. Because of reasons mentioned in Col. (c).	No. The owners will get interest on the amount paid under the Act.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ, ਸਵਾਲ ਦੇ (ਬੀ) ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੰਪੇਨਸੇਸ਼ਨ (Compensation) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਿਕਨ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ "Awards have not been announced."

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ? ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤਿਕਨ ਇਹ Awards announce ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ?

मंत्री : इस काम में देर हो जाने की एक खास वजह यह है कि गवर्नमेंट को और भी बहुत से काम हैं (हंसी)। आखिर एवार्ड्ज़ Announce करने से पहले उन के मुतल्लिक फ़ैसला भी तो करना है। इस के लिए तो वक्त लगेगा।

REALIZATION OF ABIANA IN ILAQA BET, DISTRICT FEROZEPORE.

*2492. **Sardar Bachan Singh** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total amount of 'Abiana' realized from ilaqa Bet, Tehsil Zira, District Ferozepore during the period 1947 to 1952 each year;

(b) the total number of persons in the ilaqa who were arrested or whose properties were confiscated for failure to pay Abiana or to pay back *Taccavi Loans* to the Government?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Total amount of Abiana realized is as follows—

	Rs.
1950-51	1,97,407
1951-52	1,26,537
1952-53	1,91,007

Prior to 1st May 1950 this ilaqa was under the control of Civil Department.

(b) 24 persons were arrested for failure to pay back Taccavi Loans to the Government from 1947 to 1952.

CULTURABLE EVACUEE AREA AT VILLAGE DHARAR, DISTRICT AMRITSAR

*1959. **Sardar Sarup Singh** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the total culturable evacuee area at Village Dhorar, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar as on 1st April 1950;

[Sardar Sarup Singh]

(b) the total culturable evacuee area which was allotted to displaced persons up to 31st December 1950;

(c) the total evacuee area which was not allotted to any persons up to 31st May, 1953, and the reasons for not allotting the same to the displaced persons;

(d) (i) whether any ousted temporary allottees had filed their review applications before 30th September, 1950, with the Additional District Magistrate, Amritsar, and the Director-General, Rehabilitation; if so, their list;

(ii) whether any of persons referred to in part (d) (i) above were ordered to be restored in this Village by the Director-General, Rehabilitation, Jullundur,—*vide* his orders, dated the 10th August, 1950; if so their list;

(e) (i) whether the orders of the Director-General, Rehabilitation referred to in part (d) (ii) above were implemented up to 15th June 1953; if not, the reasons therefor;

(ii) the person responsible for failure to implement these orders and the action, if any, taken by the Government in the matter;

(f) (i) whether the authorised Deputy Custodian, Amritsar, passed any orders on 22nd May, 1953, for the implementation of the Director-General, Rehabilitation's orders, dated 10th August, 1950, referred to in part (d) (ii) above; if so, whether the same were implemented up to 15th July, 1953; if not, the reasons, therefor;

(ii) the person responsible for delay and the action proposed to be taken against him by the Government?

Sardar Ujjal Singh :

	S. A.	Units.
(a)	1,355	12¾
(b)	1,292	½
(c)	63	12

(d) (i) Yes. Sh. Puran Singh son of Sh. Khazan Singh filed a review application before 30th September 1950.

(ii) Yes. The above-named allottee was ordered to be restored in this village.

(e) (i) These orders could not be implemented because by another order of the Director-General, Rehabilitation, 49 smaller sitting allottees with an area of 167 S.A. 11¼ units had to be allotted land in this village. Sh. Puran Singh himself was a bigger allottee as compared with the other applicants who in addition to being sitting allottees formed a group of blood relations and had, therefore, to be given preference.

(ii) The reasons have been explained in e(i) above.

(f) (i) Yes. The Additional Deputy Commissioner ordered that Puran Singh should be fitted in this village if the area was available.

(ii) There has been no delay in this case.

CANCELLATION OF THE ALLOTMENT OF LAND AT VILLAGE JODHSINGHWALA

***1960. Sardar Sarup Singh**: Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) (i) whether allotments of land of any displaced persons were cancelled under orders of the authorised Deputy Custodian, Amritsar, from Village Jodhsinghwala, Tehsil Patti, District Amritsar,—*vide* this order, dated 25th June 1953; if so, the list and the grade of land to which this had been put;
(ii) the reasons for the cancellation of allotments;
(iii) the provision of law under which these allotments were cancelled;

(b) whether the land made available by the cancellation of allotments referred to above has been allotted or is proposed to be allotted to any other displaced persons;

(c) whether any of the persons referred to in part (a) (ii) above have been allotted land at Village Rasulpur, Tehsil Patti; if so, their list and the area allotted to each one of them;

(d) the grades in which the lands of Village Jodhsingwala and Village Rasulpur referred to above have been placed for allotment purposes;

(e) (i) whether any applications, dated 26th May, 1953, from Sardar Dharam Singh, son of Ajit Singh, and other displaced persons of Village Rasulpur refrered to above, were received by the Deputy Commissioner, Amritsar, to the effect that available area at Village Rasulpur be allotted to them;
(ii) whether any enquiry on the spot was made by the Revenue or the Rehabilitation Authorities, Amritsar, from any of the persons referred to in part (e) above; if so, with what result;

(f) (i) whether any applications were received by the Rehabilitation Authorities, Amritsar, from any of the persons referred to in part (a) (i) above; if so, their list;
(ii) the date of the receipt of each application;

(g) (i) whether the persons referred to in part (a) (i) above were given preference over the persons referred to in part (e) above; if so, the reason therefor;
(ii) whether the area allotted to any of the persons referred in part (e) (i) above has been found unculturable on local enquiry by the Tehsildar, Patti; if so, the list of such persons and the area found unculturable on local enquiry by the Tehsildar, Patti; if so, the list of such persons and the area found unculturable in each case;
(iii) whether any applications for the allotment of the available area referred to above at Village Rasulpur were invited by the Tehsildar, Patti, before or after the 20th June 1953, in light of the Government instructions, dated 24th July, 1952, for the allotment of the available area; if not, the reasons thereof?

Sardar Ujjal Singh : (a) (i) the allotment of land to one Shri Piara Singh, son of Bahal Singh, deceased, to the extent of 31 SA 1¼ Units was cancelled under orders of the Authorised Deputy Custodian, Amritsar, from Village Jodhsinghwala, Tehsil Patti, on 25th June 1953. The land of this village is of 3rd grade.

(ii) The allotment was cancelled for exchange with unallotted area in Village Rasulpur, Tehsil Patti.

(iii) The Authorised Deputy Custodian can cancel the allotment for exchange to another village where evacuee area is available for allotment in accordance with the conditions on which quasi-permanent allotment has been made.

(b) No.

(c) Shri Piara Singh referred to in part (a) (i) above has been allotted 31 SA and 2 Units land in Village Rasulpur, Tehsil Patti. ;

(d) Both the Villages Jodhsinghwala and Rasulpur are of 3rd grade for the purpose of allotment.

(e) (i) An application, dated 26th May 1953, from Shri Dharam Singh, son of Ajit Singh, for the exchange of his inferior land with that of the above available area of Village Rasulpur was received on 30th May 1953.

(ii) An enquiry was made by the fiield staff about the application referred to in part (e) (i) above and proposal for the exchange in lieu of inferior land allotted to Dharam Singh with unallotted area in the same Village was sent to the Deputy Commissioner, Amritsar.

(f) (i) An application from Sardar Piara Singh, son of Bahal Singh, deceased, referred to in part (a) (i) above, was received by the Rehabilitation Authorities.

(ii) The application was received on 20th June 1953.

(g) (i) Sardar Piara Singh referred to in part (a) (i) above was given preference over Dharam Singh referred to in part (e) (i) above, as an orphan has a preferential claim over all the other claimants.

Moreover, Piara Singh was a smaller allottee than Dharam Singh. Dharam Singh was allotted land in this village only a few days before on his own request and as such his request for exchange was not proper.

(ii) out of the allotted area to Dharam Singh referred to in part (e) (i) above 55 SA 1½ Units was found inferior and 4SA good land on local enquiry by the Tehsildar, Patti.

(iii) No application for the allotment of the available area referred to above at Village Rasulpur were invited by the Tehsildar on the application of Sardar Dharam Singh.

ALLOTMENT OF HOUSES IN VILLAGE KALA AFGHANA, DISTRICT GURDASPUR.

*1993. **Sardar Achhar Singh Chhina** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the first allotment of houses in Village Kala Afghana, Tehsil Batala, District Gurdaspur; was done in the year 1950 but was subsequently cancelled; if so, the reasons thereof;

(b) whether it is a fact that in November, 1950, a fresh allotment was made but the allottees were not given possession of the houses so allotted, if so, the reasons for the failure to give possession of the houses to the allottees and the action taken by the Government for recovering the record which was lost;

(c) whether it is a fact that the allotment ordered in the year 1952 by the Deputy Commissioner was set aside on 18th November, 1952; if so, the reasons therefor;

(d) whether it is a fact that the houses still remain unallotted; if so, the action Government proposes to take in the matter?

Sardar Ujjal Singh : (a) Yes. Because it was against the rules of allotment.

(b) Yes. But again the allotment was found to be defective and was not carried through. Action is being taken to fix responsibility for the loss of record.

(c) No.

(d) Only three houses are at present unallotted. Action for the allotment of these three houses is being taken by the Deputy Commissioner, Gurdaspur.

REPRESENTATION FROM ALA MALIKS OF SALIH NAGAR, DISTRICT JULLUNDUR.

***2001. Sardar Harkishan Singh Surjit : Will the Minister for** Finance be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that land belonging to Ala Maliks of Salih Nagar, Tehsil Nakodar, District Jullundur, the possession of which was taken over by the Custodian of Evacuee Property has been given for cultivation on "Chakota" since the year 1948;

(b) whether it is also a fact that the said Ala Maliks have not been paid any part of the rent of their land since 1948;

(c) whether it is a fact that the Government has been receiving land revenue from the said Ala Maliks in respect of this land during all these years;

(d) whether the Government has received any representations from the Ala Maliks referred to in part (a) above in the month of April, 1953, regarding the matters set out in part (a), (b) and (c) above;

(e) if the answers to part (a), (b), (c) and (d) above be in affirmative, the action, if any, Government proposes to take in the matter?

Sardar Ujjal Singh : (a) There is no such area in Village Salih Nagar, Tehsil Nakodar, District Jullundur and there are no Ala Maliks in that Village.

(b) and (c) In view of the reply at (a) the question does not arise.

(d) No such representation has been received.

(e) The question does not arise.

REVISION PETITIONS REGARDING ALLOTMENTS.

***2040. Sardar Achhar Singh Chhina** : Will the Minister for Finance be pleased to state:—

(a) the total number of revision petitions so far received by the Land Claims Organisation, Rehabilitation Department, together with the number of those disposed of and of those pending separately;

(b) whether it is a fact that a date was fixed after which applications were not to be entertained; if so, what and the number of applications received thereafter;

(c) whether he has received any demand from displaced persons regarding the extension of the date referred to in part (a) above; fi so, the action, if any, taken thereon?

Sardar Ujjal Singh : (a) Total number of revision petitions filed in the Rehabilitation Department (Land Claims Organisation) up to 7th September, 1953, amounts to 5,979 out of which 5,702 have been disposed of leaving a balance of 277 applications still pending on the 7th September, 1953.

(b) Yes. 31st May, 1953, was fixed as the last date after which no applications had to be taken. 2899 applications have been received after 31st May, 1953, up to 19th September, 1953.

(c) No written request for the extension of time has been received so far, although some verbal demands have been made.

NUMBER OF DISPLACED PERSONS IN THE STATE.

***2250. Shri Babu Dayal** : Will the Minister for Finance be pleased to state the total number of displaced persons living in the State at present, district-wise, together with number of those who have taken loans from the Government and the amount of loan in each case ?

Sardar Ujjal Singh : A statement giving, district-wise, the numbers of displaced persons living in the State, the amounts of various Urban and Rural Rehabilitation loans advanced and the number of loanees under each category separately, is given below. In addition, the following loans were also advanced:—

Kind of loan	Amount advanced	No. of loanees
	Rs.	
1. Educational loans ..	25,25,545	4,666
2. Loans to Punjab University Solan ..	2,19,000	
3. Loans to Electric Supply Companies ..	1,10,000	

District-wise information in respect of Educational loans is neither available nor can it be readily collected, and it is not possible to indicate the amount of an given in each individual case as the number of loanees runs into thousands

STATEMENT

Name of District	Displaced Persons' population according to 1951 Census	Urban Rehabilitation Loans: Small Urban Loans for industry, business, etc.			Urban Rehabilitation Loans: House Building Loans		Rural Rehabilitation Loans: Food		Rural Rehabilitation Loans: Rural Artisans		Rural Rehabilitation Loans: Fodder	
		Number of individual borrowers	Number of Societies (Borrowers	Amount advanced	Number of individual borrowers	Amount advanced	Number of loanees	Amount advanced	Number of loanees	Amount advanced	Number of loanees	Amount advanced
				Rs.		Rs.		Rs.		Rs.		Rs.
Jullundur	273,625	3,238	124	33,45,272	471	18,76,925	25,474	2,59,908	285	45,890	2,358	94,761
Ludhiana	169,267	2,400	65	21,38,325	296	16,82,476	6,470	4,84,582	85	12,850	1,254	49,440
Hoshiarpu	146,935	1,120	32	13,67,800	116	4,27,500	71,253	3,99,320	400	90,800	3,038	83,540
Ferozepore	358,341	2,945	64	21,88,035	..	..	38,651	5,54,304	176	35,660	1,992	1,72,160
Amritsar	332,260	1,950	91	18,48,605	..	..	261,711	8,42,513	419	98,250	2,912	1,17,000
Gurdaspur	297,581	2,083	42	15,16,260	..	..	65,348	6,63,545	527	97,395	6,499	1,39,260
Ambala	188,892	2,310	81	28,58,640	686	21,56,376	45,788	8,73,245	72	20,880	3,401	1,17,000
Karnal	250,471	2,982	80	22,18,040	374	11,79,422	97,474	14,20,065	1	400	..	..
Hissar	127,657	1,190	73	14,76,983	219	9,39,600	201,995	15,19,705	444	95,300	316	18,620
Rohtak	123,646	2,087	79	19,08,800	369	13,18,670	48,465	7,05,543	588	145,800	2,501	58,770
Gurgaon	84,587	1,536	41	11,20,415	179	7,46,250	9,019	5,62,940	67	17,950	73	2,580
Kangra	8,434	376	4	2,12,350	..	..	..	..	..	..	..	..
Simla	14,281	515	..	7,82,350	..	..	..	..	..	..	..	..
Total	2,375,977	24,732	776	,29,81,875	2,910	1,03,27,219	871,648	82,85,670	3,064	6,61,175	24,344	8,53,131

STATEMENT—*contd*

RURAL REHABILITATION LOANS

District	*Seed*		*Bullocks*		*Implements*		*Repair of Wells*		*Persian Wheels and Water Pumps*		*Tube-wells*	
	Number of Loanees	Amount	Number of loanees	Amount	Number of loanees	Amount	Number of loanees	Amount	Number of loanees	Amount	Number of loanees	Amount
		Rs.		Rs.		Rs		Rs.		Rs.		Rs.
Jullundur ..	268,354	7,02,544	2,968	9,11,800	3,927	1,09,674	353	35,800	1,294	11,73,446	5	32,500
Ludhiana ..	14,997	5,53,727	1,935	7,43,307	2,492	1,25,861	191	19,550	399	6,75,322	4	32,500
Hoshiarpur	27,243	6,40,761	3,565	11,10,950	3,824	98,845	62	7,365	231	4,74,213	6	45,000
Ferozepore	62,703	15,58,713	7,745	22,71,822	9,629	1,82,575	..	..	510	4,64,176	2	15,000
Amritsar ..	57,218	6,36,949	3,021	7,89,450	6,332	1,32,475	114	11,390	729	4,10,841	1	10,000
Gurdaspur	26,982	8,06,056	5,364	9,96,894	4,760	1,34,975	314	31,300	468	4,05,285	4	30,000
Ambala ..	14,757	4,01,865	4,501	9,97,060	2,840	91,320	27	2,592	60	2,86,221	63	60,000
Karnal ..	27,491	7,05,301	3,838	12,37,230	6,785	1,72,975	211	21,030	654	8,75,622	9	60,000
Hissar ..	20,120	5,42,030	5,199	12,77,043	5,583	1,84,416	40	4,080	69	2,16,695	5	47,500
Rohtak ..	7,665	1,67,382	1,285	5,55,958	2,357	99,673	37	3,700	73	94,000	2	15,000
Gurgaon ..	6,256	1,94,726	2,717	5,56,350	1,914	69,680	..	..	110	94,882	..	..
Kangra ..	90	3,075	10	5,000	2	2,750	..	..	..	..	..	..
Simla ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Total ..	291,147	69,13,129	42,148	1,14,52,864	50,445	14,05,219	1,349	1,36,807	4,597	51,70,703	101	3,47,500

STATEMENT—*contd*

RURAL REHABILITATION LOANS

District	*Boring of wells*		*Tractors*		*Repair of houses*		*Construction of houses*	
	No. of loanees	Amount	No. of loanees	Amount	No. of loanees	Amount	No. of loanees	Amount
		Rs.		Rs.		Rs.		Rs.
Jullundur ..	80	4,14,560	3	3,52,000	..	..	883	85,150
Ludhiana ..	19	1,87,855	1	5,24,000	..	..	147	31,055
Hoshiarpur ..	28	2,03,000	3	2,64,000	276	33,940	176	70,500
Ferozepur ..	9	71,800	11	2,72,000	..	..	718	1,63,305
Amritsar ..	7	44,300	3	70,000	711	16,396	42	1,70,000
Gurdaspur ..	16	1,27,390	2	46,000	10	10,500	85	27,050
Ambala ..	11	1,47,000	5	1,08,000	501	22,000	290	1,16,200
Karnal ..	68	6,39,400	12	12,70,000	213	24,000	123	49,300
Hissar ..	1	1,250	11	1,88,000	278	5,130	105	42,150
Rohtak ..	1	2,500	2	48,000	99	9,991	23	21,370
Gurgaon ..	2	10,550	3	49,200	780	44,895	14	24,440
Kangra ..	..	..	..	..	..	..	..	..
Simla ..	..	..	..	..	..	..	..	..
Total ..	242	18,49,605	56	32,01,200	2,868	66,852	2,606	6,47,520

District	*Repair of houses and flood effected villages*		*Tube-wells in garden colonies*		*Agricultural machinery in garden colonies*	
	No. of loanees	Amount	No. of loanees	Amount	No. of loanees	Amount
		Rs.		Rs.		Rs.
Jullundur ..	5,047	8,74,480	150	1,50,000	5	38,000
Ludhiana ..	921	2,30,450	150	1,50,000	3	26,500
Hoshiarpur ..	2,567	6,80,510	75	75,000	2	11,000
Ferozepur ..	4,068	5,62,200	25	25,000	3	26,000
Amritsar ..	5,116	8,71,869	..	..	3	20,500
Gurdaspur ..	2,285	4,71,090	50	50,000	2	13,500
Ambala ..	..	..	100	1,00,000	4	28,500
Karnal ..	..	..	100	1,00,000	5	42,500
Hissar ..	..	..	..	..	2	18,000
Rohtak ..	..	..	100	1,00,000	3	22,000
Gurgaon ..	..	..	..	..	1	3,500
Kangra ..	..	..	..	..	..	..
Simla ..	..	..	..	..	..	..
Total ..	20,004	36,90,599	750	7,50,000	33	2,50,000

APPLICATION FOR REVISION OF LAND ALLOTMENT.

***2462. Sardar Nidhan Singh** : Will the Finance Minister be pleased to state:—

(a) the total number of applications for revision of land allotment filed by displaced persons in the State before the 31st March, 1952, and after 31st March, 1952, together with the number of such applications disposed of;

(b) whether the Government fixed any date after which revision petition were not to be entertained, if so, what and the number of petitions received after such date together with the action taken by the Government on them?

Sardar Ujjal Singh :

The information is detailed below:—

(a)	Applications for revision of land allotment filed by displaced persons.	*Number of applications received before 31st March* 1952 2,938	*Disposed of* 2,925
	Applications for revision of land allotment filed by displaced persons.	*Number of applications received after 31st Mach* 1952 3,087	*Dsiposed of* 2,799

(b) The limitation period for filing a revision petition is fixed under the Evacuee Property Act, 1950, and is thirty days for revision before the Custodian and sixty days before the Custodian-General from the date of the passing of the order sought to be revised.

ALLOTMENT OF MACHINERY TO THE INDUSTRIES DEPARTMENT.

***2557 Shri Dev Raj Sethi** : Will the Minister for Finance be pleased to state:—

(a) whether any valuable machinery was allotted to the Department of Industries, Punjab, by the Government of India out of the quota of reparations realised from German Government; if so, the details thereof;

(b) the manner in which it was disposed of by the said department?

Sardar Ujjal Singh : (a) Yes. 182 German Reparations Machines, as per list given below, were purchased by the Industries Department from the Reparations Directorate in 1950-51.

(b) Out of these 182 machines, 69 were installed in various Work Centres set up by the Industries Department for the rehabilitation of displaced persons, 37 were utilised in various Government Industrial Schools, Institutes and Vocational Training Centres, 22 were transferred to the Executive Engineer, Capital Project, Chandigarh and the Executive Engineer, Bhakra Division, Main Line, Patiala and 54 which became surplus due to closing down of certain Work Centres are proposed to be sold.

LIST OF GERMAN REPARATIONS MACHINERY

Serial No.	Plant No.	Item No.	Description of machinery.	REMARKS.
1	2	3	4	5
1	1126	6-211-1/1	Surface plate 3½" x2½" ..	Transferred by the Sonepat Centre to Technical Manager, Agricultural Implements Work Centre, Rohtak.
2	2034	30/1/1	Column type drilling machine	Ditto
3	1009	15/32/87	Horizontal milling machine	Ditto
4	—	EW-1832	Double Head Grinder	Ditto
5	1072	1-56/1/1	Plain & screw cutting lathe	Ditto
6	1126	6-78/1/1	Engine Lathe	Ditto
7	—	EW/1121	Spindle vertical drilling machine ..	Ditto
8	1015	45	Eccentric Press ..	Ditto
9	1692	4-9/1/1	Power Hacksaw ..	Ditto
10	1706p	2·334	Engine lathe SS& SC 8' bed	Ditto
11	Dr	576	Shaper 18" stroke	Ditto
12	FW	479	Double Head Grinder ..	Ditto
13	1072	1-49/1/1	One grinding machine ..	Ditto
14	352 P	42	Double Head Grinder ..	Transferred to Button Making Work Centre, Panipat.
15	ER	11	Engine & SC Lathe	Ditto
16	80	221	Sewing machine ..	Transferred to Shoe and Leather Goods Work Centre, Jullundur.
17	FEDS	EW/400	Double Head Grinder ..	Ditto
18	FEDS	1078/1/1	Small spindle lathe	Ditto
19	1052	5-23	Engine Lathe ..	Transferred to Utensil Making Work Centre. Abdullapur.
20	80	943	Punching Machine ..	Transferred from Sonepat to Metallic Fitting Work Centre, Abdullapur.
21	80	91	Bench Drilling Machine	Ditto
22	FEDS	CR-300	Reveting machine	Ditto
23	FEDS	CB-112	Pendulum Press ..	Ditto

[Minister for Finance]

Serial No.	Plant No.	Item No.	Description of machinery	REMARKS
1	2	3	4	6
24	FEDS	352/S	Double Grinding Head	Transferred from Sonepat to Metallic Fitting Work-Centre, Abdullapur.
25	1004	624	Transportable Rottary shed	Ditto
26	..	EB-643	Pendulum Press ..	Ditto
27	..	EW-1033	Bench Drilling machine ..	Ditto
28	..	1044	Bench Drilling machine ..	Ditto
29	..	281	Friction Press ..	Ditto
30	..	EW-1603	Reveting machine ..	Ditto
31	..	EW-357	Turret Lathe ..	Ditto
32	1048	3-175	Engine Lathe ..	Ditto
33	1004	305	Eccentric Press ..	Ditto
34	1004	1345	Cold sawing machine ..	Ditto
35	1639	2-134	SS & SC Lathe 8' bed ..	Ditto
36	CB	170	Horizontal Milling machine	Ditto
37	CR	580	Vertical Milling machine	Ditto
38	CR	504	Vertical Drill Cone Pulley	Ditto
39	1048	2-135	Short Shaper 18" stroke	Ditto
40	DR	754	Engine & screw entling Lathe	Ditto
41	89	6	Heavy Duty Drill ..	Ditto
42	1048	7-76	Eccentric Press ..	Ditto
43	1072	1-154/1/1	Hardening Furnace ..	Transferred to Pottery Work Centre, Sonepat.
44	1323P	S-2	Wood Planner ..	Transferred to Wood-Work Centre, Panipat.
45	333	53	Eccentric Press ..	Installed at Panipat.
46	EB	891	Turret Lathe ..	Ditto
47	FB	278	Saw Cutting Metal	Ditto
48	EW	702	Engine Lathe SS & SC	Ditto
49	DR	95	Thread cutting machine	Ditto
50	1076	266	SS & SC Lathe ..	Ditto
51	CB	670	Double End Grinder ..	Ditto
52	EW	526	SS & SC Lathe ..	Ditto

Serial No.	Plant No.	Item No.	Description of machinery	REMARKS.
1	2	3	4	5
53	EB	442	Bench Drill 3/8"	Installed at Panipat.
54	.. .	DR 626	Grinding & Polishing Machine	Ditto
55	EB	294	SS & SC Lathe 6" Bed	Ditto
56	FW	118	Vertical Drill Machine ..	Ditto
57	CW	17	Engine Lathe SS & Sc	Ditto
58	EW	192	Eccentric Press ..	Ditto
59	20	200	Travelling Head planner typeshapper	Ditto
60	1297	14/111/1/1	Horizontal milling machine	Transferred to Govt. Indl. School, Ferozepur.
61	EW	EW1007	Bench Drilling machine ..	Ditto
62	..	EW/436	Scan Automatic Lathe ..	Ditto
63	1048 P	2-137	Precision Engine Lathe	Ditto
64	CR	581	Vertical Milling machine	Ditto
65	CR	152	SS & SC Lathe 6' Bed	Ditto
66	1015	123	Grinding Head	Ditto
67	1126	10-8	Lathe	Transferred to Vocational Training Centre, Pathankote.
68	1048	3-198/1/1	Column Type Drill Machine	Ditto
69	1381	8-1	Band Saw	Ditto
70	1082	566	Bench Lathe	Ditto
71	DR	976	Grinding machine	Reserved for Kasauli.
72	252	64	Engine Lathe SS & SC 8' Bed	Ditto
73	EW	1268	Tool Grinding direct drive	Ditto
74	1126	6-177	Hand spindle 3" dia. screw press ..	Transferred to the Executive Engineer, Capital Project, Chandigarh.
75	2034	42-1-1	Bar straight machine	Ditto
76	1	ISCH	Bench drilling machine	Ditto
77	1268	1-6	Hand Lever shear	Ditto
78	1381	8-1	Band-saw	Ditto
79	1015	14	Upright drilling machine	Ditto

[Minister for Finance]

Serial No.	Plant No.	Item No.	Description of machine	REMARKS
1	2	3	4	5
80	1048	2—125	Bench drill machine	Transferred to Executive Engineer Capital Project, Chandigarh.
81	CR	259	Turning lathe	Ditto
82	1126	10-3	Single space high speed lathe	Ditto
83	1381	3—5	Mechanical lathe	Ditto
84	1126	10-7	Engine Lathe	Ditto
85	2034	62—1—1	Circle saw with motor and table	Ditto
86	1015	14	Upright drilling machine	Ditto
87	1323	75/1	Universal tool grinding machine	Ditto
88	1126	6—74	Engine Lathe	Ditto
89	50	..	Generating set	Transferred to the Executive Engineer, II Bhakra Division Patiala
90	333	52	Eccentric press table size 420/600	Surplus G. R. machinery at Panipat.
91	306	396	High speed drill table size	Installed in workcentre.
92	333	8	Shapper 18" stroke table 20"x12"	Ditto
93	1052	4—3	Automatic Drill machine	Ditto
94	1048	2—55	Hydraulic Press	Surplus at Panipat.
95	EB	772	Tool Grinder ..	Installed in workcentre.
96	1004	587	Power Hack Saw	Ditto
97	EW	1135	Spring rolling machine	Surplus at Panipat.
98	1004	1093	Drill High Speed	Ditto
99	EB	301	Bench Drill 3/8"	Installed in workcentre.
100	1126	6—50	Horizontal surface, Grinding machine	Surplus at Panipat.
101	80	904	Engine Lathe	Ditto
102	1004	268	Grinding Buffing Head	Ditto
103	80	908	Heavy Duty Drilling Machine	Installed in workcentre.
104	1015	6	Grinding Head	Ditto
105	1	2MH	Perforating Machine	Surplus at Panipat.
106	1	7MH	Wire staping machine	Ditto
107	1015	115	Wood Band Saw	Installed in workcentre.

Serial No.	Plant No.	Item No.	Description of machinery	REMARKS
1	2	3	4	5
108	CR	568	Eccentric Press	Surplus at Panipat.
109	CR	656	Ditto	Ditto
110	..	EW-1844	Turret Lathe	Surplus G. R. machinery at Sonepat.
111	FEDS	1805/1/1	Bench Drilling Machine	Installed in work centre.
112	1126	6-104	Tool Grinding Machine	Surplus at Sonepat.
113	FEDS	EW-1839	Sawing Machine	Ditto
114	1639	1-491/1/1	Column type drilling machine	Ditto
115	1126	6-80	Centring machine	Ditto
116	1072	1-70/1/1	Saw cutting lathe	Ditto
117	1126	10-26	Universal Cylinder Grinding Machine	Ditto
118	FEDS	287/1/1	Grinding Machine	Ditto
119	1639	2-148/1/1	Upright drilling machine	Ditto
120	1646	1-78/1/1	Threading milling machine	Ditto
121	FEDS	EW-1079	Small Spindle Lathe	Sarplus G. R. machinery at Sonepat.
122	1126	10-66	Surface plate with support	Ditto
123	1838	1-32	Double wheel grinder	Ditto
124	1838	1-40	Threading machine	Ditto
125	1692	4-4/22	Eccentric Press	Ditto
126	..	1643/1/1	Horizental milling machine	Ditto
127	1838	1-35	Double wheel grinder	Ditto
128	..	1313	Bend drilling machine	Ditto
129	1015	1-35	Double wheel grinder	Ditto
130	1	34	Electric shed	Ditto
131	1	R.P. 251	Hand spindle press	Ditto
132	1015	87	Grinding head	Ditto
133	1169	1-86	Multiple Punch Head	Ditto
134	80	911	Double Head Grinder	Ditto
135	90	913	Grinder Head	Ditto
136	1126	10-34	Grinding Machine	Ditto

[Minister for Finance]

Serial No.	Plant No	Item No.	Description of machinery	REMARKS
1	2	3	4	5
137	FEDS	EB 149	Tool Press Pendle	Surplus G. R. machinery at Sonepat:
138	Do	CB 276	Vertical Drilling Machine	Ditto
139	Do	277	Ditto	Ditto
140	Do	283	Multiple spindle bench drilling machine	Ditto
141	FEDS	286	Vertical Drilling machine	Ditto
142	Do	363	Spindle vertical drilling machine	Ditto
143	80	428	Screw press	Ditto
144	1297	2—71	Grooming machine	Installed in workcentre.
145	FEDS	282	Friction Press	Surplus at Sonepat
146	..	ER 22	Polishing machine	Ditto
147	1004	142	Grinding and Polishing Head	Ditto
148	..	705	Horizontal Milling machine	Ditto
149	40/G-107-45	..	Grinder	Installed in work centre.
150	FEDS	357	Bench Drilling Machine	Surplus at Sonepat.
151	1126	3—55/1/1	Grinding Head	Ditto
152	Do	3—60/1/1/	Ditto	Ditto
153	FEDS	CR 559	Special Stitching machine	Ditto
154	Do	EW 174	Turret Lathe	Ditto
155	1048	7-36/1/1	Crank Press	Ditto
156	..	..	Press Drill Candian	Installed at work centre.

NATIONALISATION OF BOOKS.

*2558. **Shri Dev Raj Sethi**: Will the Minister for Education be pleased to state:—

(a) the particulars of books so far nationalised by the Government and the details of the scheme for the future;

(b) the causes of delay in printing the publication of such books;

(c) the total saving made by the Government up to date on this account?

Shri Jagat Narain : (a) The lists of books so far nationalised are given below. Text-books for class VIII are to be published and introduced by the Government this year whereas books for classes I, II, III, V, VI and VII (English only) will be published and introduced next year.

(b) The delay in the publication of books has been caused by—

(i) long time taken by referees in giving their reports,

(ii) delay by the printing presses. The Punjab Government Printing Press is at present not in a position to undertake the printing work itself.

(c) The net amount of income will be Rs. 4,51,000.

LIST OF TEXT-BOOKS

CLASS I

		Rs.	A	P	
1. Health and Social Activities (Nirog Nagrik)	.. Hindi ..	0	3	6	
2. Ditto	.. Punjabi ..	0	3	6	
3. Basic Craft (Agriculture)* Arambhik Shilp Vigyan (Krishi)	.. Hindi ..	0	6	3	(*for class I and II)
4. Basic Craft (Agriculture) Buniadi Dastkari	.. Punjabi ..	0	6	3	
5. Recreational Activities*—Chitra Lekh	.. Hindi ..	0	4	6	(*for Class I and II)
6. Ditto	.. Punjabi ..	0	4	6	

CLASS II

1. Health and Social Activities (Nirog Nagrik)	.. Hindi ..	0	4	0
2. Ditto	.. Punjabi ..	0	4	0

CLASS III

1. Basic Craft (Agriculture)—Buniyadi Dastkari (Kheti Bari)	.. Hindi ..	0	5	0
2. Ditto	.. Punjabi ..	0	5	0
3. Recreational Activities—Chitra Lekh (for III and IV Classes)	.. Hindi ..	0	7	6
4. Ditto	.. Punjabi ..	0	7	6
5. Social Studies	.. Hindi ..	0	9	6
6. Ditto	.. Punjabi ..	0	9	6

CLASS IV

1. Basic Craft (Agriculture) Arambhik Shilp Vigyan	.. Hindi ..	0	9	6
2. Basic Craft (Agriculture) Buniadi Dastkari (Kheti Bari)	.. Punjabi ..	0	9	6
3. Sadharan Vigyan	.. Hindi ..	0	9	6

[Minister for Education]

LIST OF TEXT BOOKS—CONTD

CLASS IV—concld

			Rs.	A.	P.	
4.	Dainik Vigyan	Punjabi	0	9	6	
5.	Hindi Reader	Hindi	0	11	0	
6.	Hindi Supplementary Reader No. 1	Hindi	0	8	0	
7.	Ditto No. 2	Hindi	0	5	6	
8.	Ditto No. 3	Hindi	0	5	6	
9.	Punjabi Di Chauthi Pothi	Punjabi	1	2	0	
10.	Punjabi Supplementary Reader No. 1	Punjabi	0	6	0	
11.	Ditto No. 2	Punjabi	0	6	0	
12.	Ditto No. 3	Punjabi	0	5	0	
13.	Ganit Ki Pustak	Hindi	0	13	0	
14.	Ganit Ki Pustak	Punjabi	0	13	0	
15.	Social Studies	Hindi	0	13	0	
16.	Ditto	Punjabi	0	13	0	
	CLASS V					
1.	Basic Craft (Agriculture) Arambhik Shilp Vigyan	Hindi	0	10	0	
2.	Basic Craft (Agriculture) Arambhik Shilp Vigyan [Buniyadi Dastkari (Kheti Bari)]	Punjabi	0	10	0	
3.	Recreational Activities—Chitra Lekh	Hindi	0	6	0	
4.	Ditto	Punjabi	0	6	0	
5.	Social Studies	Hindi	0	15	0	
6.	Ditto	Punjabi	0	15	0	
	CLASS VI					
1.	Agriculture (Krishi Vigyan)	Hindi	0	11	6	
2.	Ditto (Kheti Bari)	Punjabi	0	11	6	
3.	Tailoring—"Seena Pirona" *	Hindi	2	0	0	*Meant for classes VI, VII and VIII.
4.	Ditto	Punjabi	2	0	0	
5.	Drawing	Hindi	1	2	0	
6.	Ditto	Punjabi	1	2	0	
7.	Sangeetalok	Hindi	0	5	0	
8.	Ditto	Punjabi	0	5	0	
9.	Hindi Grammar	Hindi	0	5	3	
10.	Punjabi Grammar	Punjabi	0	4	3	

LIST OF TEXT BOOKS—CONCLD

CLASS VII

				Rs.	A.	P.
1.	Krishi Vigyan (Agriculture)	..	Hindi	0	12	0
2.	Kheti Bari (Agriculture)	..	Punjabi	0	12	0
3.	Drawing	..	Hindi	0	15	0
4.	Drawing	..	Punjabi	0	15	0
5.	Hindi Regional Reader	..	Hindi	0	11	0
6.	Hindi Grammar	..	Hindi	0	8	0
7.	Sanskrit	..	Hindi	0	8	0
8.	Bhugol	..	Hindi	1	5	0
9.	Bhugol	..	Punjabi	1	5	0
10.	Ganit Ki Pustak	..	Hindi	1	1	0
11.	Ganit Ki Pustak	..	Punjabi	1	1	0
12.	Punjabi Grammar	..	Punjabi	0	10	0
13.	Punjabi Reader	..	Punjabi	1	0	0
14.	Punjabi Regional Reader	..	Punjabi	0	12	0
15.	Sangeetalok	..	Hindi	0	5	0
16.	Sangeetalok	..	Punjabi	0	5	0
17.	Sadharan Vigyan	..	Hindi	1	1	0
18.	Ditto	..	Punjabi	1	1	0
19.	Hindi Reader	..	Hindi	1	2	3
20.	English Grammar	..	English	0	7	6

CLASS VIII

				Rs.	A.	P.
1.	Agriculture—Krishi Vigyan	..	Hindi	1	2	0
2.	Ditto Kheti Bari	..	Punjabi	1	2	0
3.	English Reader	..	English	1	0	0
4.	Supplementary English Reader	No. 1	English	0	4	0
5.	Drawing	..	Hindi	1	1	0
6.	Do	..	Punjabi	1	1	0
7.	Sangeetalok	..	Hindi	0	6	6
8.	Sangeetalok	..	Punjabi	0	7	6
9.	Supplementary English Reader No. 2		English	0	5	6
10.	English Grammar (Hindi)	..	English	0	10	0
11.	English Grammar (Punjabi)	..	English	0	8	6

REALIZATION OF ROYALTY FROM AUTHORISED PUBLISHERS.

*2559. **Shri Dev Raj Sethi** : Will the Minister for Education be pleased to state:—

(a) the total amount realized by the Government as royalty from authorised publishers of text books in the State up to 31st December, 1953;

(b) the balance due from such publishers, the reasons for non-realization, and the steps, if any, taken by the Government to get the arrears cleared?

Shri Jagat Narain : (a) and (b) The statement showing the amount of royalty realized by Government from publishers for the period ending 31st December, 1952, is given below. The total amount of royalty realized up to this date is Rs. 1,07,496-2-0. All publishers have not supplied the statements of accounts duly audited by chartered accountants along with the treasury receipts of the royalty accruing thereon for the period ending the 31st December, 1953. The publishers have been served with notices asking them to supply this information without any further delay.

Statement showing the amount of royalty realized from Publishers on the sale of books for classes I, II, V and VI (English only)

Serial No.	Name of the firm.	Amount realized. Rs.	A.	P.
1	M/s Gurdas Kapur and Sons, Delhi ..	8,018	8	9
2	M/s Lahore Book Shop, Ludhiana ..	1,874	4	0
3	M/s Amarjit Printing Press, Jullundur ..	2,148	4	0
4	M/s Orient Longmans, Bombay ..	806	4	0
5	M/s Rajpal and Sons, Delhi ..	3,664	10	9
6	M/s Uttar Chand Kapur and Sons, Delhi ..	11,438	1	3
7	M/s Gulab Singh and Sons, Delhi ..	7,664	8	9
8	M/s Indian Press Ltd., Ambala ..	2,415	6	3
9	M/s New Educational Book Depot, Jullundur ..	908	6	3
10	M/s Sewadheen Sahitya Ltd., Jullundur ..	68	4	3
	Total ..	39,004	12	9

Statement showing the amount of royalty realized from Publishers on the sale of books for classes III, VI (Except English) and VII (English only)

Serial No.	Name of the firm.		Amount realized. Rs	A.	P.
1	M/s Gulab Singh and Sons, Delhi	..	4,735	3	6
2	M/s Uttar Chand Kapur and Sons, Delhi	..	15,303	0	0
3	M/s Gurdas Kapur and Sons, Delhi	..	4,957	11	0
4	M/s Rajpal and Sons, Delhi	..	2,649	11	6
5	M/s Madan Gopal Ram Sarup, Ambala	..	364	1	0
6	M/s East Punjab Publishing Company , Ludhiana	..	1,010	9	9
7	M/s Dass Brothers, Ambala	..	1,491	8	0
8	M/s Mool Raj and Sons, Delhi	..	2,343	10	0
9	M/s Amarjit Printing Press, Delhi	..	2,087	0	6
10	M/s Indian Press Ltd., Ambala	..	5,045	6	0
11	M/s University Publishers, Delhi	..	3,661	13	6
12	M/s Oriental Book Depot, Delhi	..	2,392	0	0
13	M/s Macmillan and Co., Bombay	..	1,151	12	3
14	M/s Ram Lal Suri and Sons, Delhi	..	2,995	14	0
15	M/s Blackie and Sons, Delhi	..	968	3	9
16	M/s Sushil Pustak Bhandar, Delhi	..	2,433	3	3
17	M/s Lahore Book Shop, Ludhiana	..	2,494	11	0
18	M/s Sunshine Publishers, Delhi	..	2,871	2	0
19	M/s Gulab Chand Kapur and Sons, Delhi	..	5,272	3	0
20	M/s Punjab Kitab Ghar, Jullundur	..	3,084	13	9
21	M/s Swadheen Sahitya Ltd., Jullundur	..	177	11	0
	Total	..	68,491	5	3
	Grand total	..	1,07,496	2	0

NATIONALISATION OF BOOKS.

*2513. **Shri Abdul Ghani Dar** : Will the Minister for Education be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that the Government nationalised certain books on Social Studies in History during the year 1950;

(b) whether it is a fact that the books on Special Studies for the first to the fourth classes were published after about a lapse of 2½ years; if so, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that since the year 1950, the Government has not been able to publish the History of India for the middle classes;

(d) if the answer to the part (c) above be in the affirmative whether he is aware of the hardship thereby caused to the students; if so, the steps that Government intends to take in this connection?

Shri Jagat Narain : (a) Yes and authors were commissioned by the Government to write books in Social Studies in October, 1950.

(b) The books in Health and Social Activities for classes I, II were made available for sale in September, 1952, whereas books for classes III and IV were put in the market in 1953.

(c) and (d) Yes, but the students have not suffered in any way as institutions were allowed to use text-books approved prior to the introduction of the new Scheme of Studies in the subjects in which books were not printed by the Government. The books in all the subjects have now been printed and placed in the market except Social Studies for Classes VI, VII and VIII which are in the press and will be available for sale from April next.

MEMORIALS OF THE PUNJAB PUBLISHERS ASSOCIATION.

*2644. **Shri Abdul Ghani Dar** : Will the Minister for Education be pleased to state whether any memorials from the Punjab Publishers Association to the effect that they were prepared to sell text-books at prices ten per cent cheaper than the Government was received by him; if so, the action, if any, taken by the Government thereon?

Shri Jagat Narain : Yes. The matter was given due consideration by the Government, but it was decided not to abandon the Scheme of Nationalisation of Books which had already been put into operation before the memorials from publishers were received, as the purpose of nationalisation is not only to bring down the prices of books but also to remove the corrupt practices which are found in the book trade.

HISTORY OF THE STRUGGLE FOR FREEDOM.

***2679. Shri Ram Kishan.** Will the Minister for Education be pleased to state:—

(a) whether he is aware of the fact that the Union Government has appointed a Central Board of Editors for writing the history of the struggle for the freedom of India from 1857 to 1947;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether the State Government has taken any steps to assist the Cenral Board in collecting and compiling the material regarding the State contribution to the said movement; if so, what?

Shri Jagat Narain. (a) Yes.

(b) The Committee has been constituted. The requisite financial provision has also been made during the next year's budget for the compilation of the history of the freedom movement in the Punjab.

LEVY OF PROFESSIONAL TAX IN THE STATE.

***2232. Sardar Darshan Singh:** Will the Minister for Public Works be pleased to state:—

(a) the total amount of professional tax levied on Harijans during the years 1951, 1952 and 1953, district-wise in the State;

(b) whether any arrears of professional tax have to be realised from the Harijans; if so, the total amount to be realised district-wise in the State;

(c) the steps that are being taken to realise the arrears;

(d) whether he is aware of the fact that Harijans have demanded that the said arrears be wiped off; if so, the action, if any, taken by the Government in the matter?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa: The required information is being collected and will be supplied to the member when ready.

MEETINGS HELD IN THE TOWN HALL, JULLUNDUR.

***2463. Sardar Nidhan Singh:** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the total number of meetings held in the Town Hall, Jullundur and the names of organizations under whose auspices the meetings were held in each case during the period from January, 1953, till today;

[Sardar Nidhan Singh]

(b) whether it is a fact that the Punjab Peace Committee was refused permission to hold an Indo-Pak. Friendship meeting in the said Hall in the month of September, 1953; if so, the reasons therefor?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : The information is being collected and it will be supplied to the member shortly.

LABOUR CO-OPERATIVE AND CONSTRUCTION SOCIETY, BHIWANI.

***2648. Shri Ram Kumar Bidhat** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the details of works so far entrusted to the Labour Co-operative and Construction Society, Bhiwani, by the Public Works Department;

(b) whether any work on the Bhiwani-Loharu Road has been given to the above-named Society?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) (i) Filling up depression in New Colony at Bhiwani.

(ii) Earthwork on Hansi-Jind Road.

(b) The work of collection of metal and bajri on Loharu-Bhiwani Road was offered to the Society but there is no response as yet and the work has not so far been allotted to any contractor. The Society is again being requested to take up the work in hand at estimated rates.

BHIWANI MUNICIPALITY.

***2649. Shri Ram Kumar Bidhat** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the total cost incurred on the repair of roads or pavement or newly constructed roads in each ward of Bhiwani Municipality, since the present committee took charge of the municipal administration;

(b) the total cost of the new Public Water Stand Posts provided in each ward by the present Municipal Committee?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) A sum of Rs. 74-4-0, Rs. 790-6-0 and Rs. 14-2-0 was incurred on the construction of new roads and repairs in Wards Nos. 2, 11 and 12 respectively and a sum of Rs. 255, Rs. 540-5-0, Rs. 532-5-3, Rs. 246-11-9, and Rs. 1,301-13-9 and Rs. 169-6-0 was incurred on the construction of new pavements and repairs in Wards Nos. 6, 7, 8, 9, 11, and 12 respectively.

(b) None, as the expenditure on installation of two stand post—one in Ward No. 7 and another in Ward Nos. 9 and 10 was incurred by the inhabitants of the ilaqa.

APPOINTMENT OF HARIJANS IN THE MUNICIPAL COMMITTEE, BHIWANI.

*2650. **Shri Ram Kumar Bidhat** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the number of Harijans appointed by the Municipal Committee, Bhiwani, in its various departments since the issue of the instructions by the Government to reserve 19 per cent posts for Harijans;

(b) whether he is aware of the fact that the said Municipal Committee did not invite any applications for its newly created post of Tax Superintendent; if so, the reason therefor?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : The information is being collected and it will be supplied to the member shortly.

REMOVAL OF EXECUTIVE OFFICER, PATTI.

*2781. **Shri Mani Ram** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) (i) whether any resolution of the Municipal Committee, Patti, District Amritsar, on 16th November, 1953, for the removal of its Executive Officer has come to his notice; if so, the charges, if any, levelled against him;

(ii) the number of the members who voted in favour of this resolution;

(iii) the number of members who voted against this resolution;

(b) whether the condition laid down in subsection (7) of section 3 of the Punjab Municipal (Executive Officer) Act, 1931, for the removal of an Executive Officer was fulfilled; if so, to what extent;

(c) whether this resolution was forwarded by the Municipal Commitee, Patti, to the Deputy Commissioner, Amritsar; if so, the date when it was received in his office;

(d) (i) whether the said resolution was sent to the Government by the Deputy Commissioner, Amritsar; if so, when;

(ii) the period for which it remained with the Deputy Commissioner, Amritsar;

(e) (i) the date on which the resolution referred to in part (d) (i) above was received by the Government;

(ii) the action, if any, taken by the Government in the matter up to 12th February 1954; if not, the reasons therefor?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) (i) Yes. The main charges levelled against the Executive Officer, Municipal Committee, Patti, are that in giving tenders for municipal work, he had contravened the provisions of the Municipal Account Code, that he has got bad reputation, is incompetent and has created party factions in the town.

(ii) Six.

(iii) Three.

(b) Yes. Resolution was passed by 5/8th of the total number of the members constituting the committee for the time being.

(c) Yes. It was received by the Deputy Commissioner, Amritsar, on the 23rd November, 1953.

(d) (i) Yes, by the Deputy Commissioner, Amritsar, on the 18th January, 1954.

(ii) It remained with the Deputy Commissioner, Amritsar, from 23rd November, 1953, to 18th January, 1954.

(e) (i) It was received by Government on the 20th January, 1954.

(ii) The matter is under the consideration of Government and certain papers have been called for from the office of Deputy Commissioner, Amritsar.

TAXATION ENQUIRY JULLUNDUR.

***2681, Shri Ram Kishan :** Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) whether the Government has submitted any memorandum in reply to the questionnaire issued through Taxation Enquiry Commission appointed by the Union Government;
(b) whether any suggestions were given to the said Commission during the recent visit of the Commission to Chandigarh;
(c) if the answer to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the gist of the proposals sent or suggestions made before the said commission?

Sardar Ujjal Singh : (a) Yes;

(b) Discussions were held with the representatives of the State Government at Chandigarh and information on various points raised by the Commission was supplied.

(c) It is not in the public interest to give the gist of the proposals sent to or suggestions made before the Commission.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

BARANI CULTURABLE AREA IN VILLAGE VIRAM, DISTRICT AMRITSAR.

514. **Sardar Sarup Singh**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether there is any Barani Culturable area in Village Viram, Tahsil Patti, District Amritsar situated just by the side of Basarke Distributary, if so, its total;

(b) whether any representation has been received by the Government from Sardar Chanan Singh and several other zamindars of Village Viram referred to in part (a) above for the supply of canal water through Jhalar; if so, the decision if any, arrived at by the canal authorities in the matter?

Chaudhri Lahri Singh: (a) Yes, the area in question is 100 acres.

(b) Yes. No perennial supply is available on U B D.C. for extension of irrigation to new areas. The question of sanction of Jhallars does not arise.

JUDICIAL LOCK-UPS IN THE STATE.

516. **Sardar Sarup Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the list of the Judicial Lock-ups in the State at present together with the names of each of the Darbans of these Judicial Lock-ups;

(b) the monthly pay including allowances of each of the Darbans;

(c) the minimum academic qualifications fixed for Darbans of these Judicial Lock-ups by the Government along with the academic qualifications of each of the Darbans referred to in part (a) above?

Shri Bhim Sen Sachar: It is regretted that the answer to the question is not yet ready. The information is being collected and will be supplied as soon as it is ready.

ALLOTMENT OF LANDS.

517. **Sardar Sarup Singh**: Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any representation of certain displaced persons of Village Rai Kalan, Tehsil Kasur, District Lahore, forwarded by Sardar Sajjan Singh, ex-M.L.A., to the Director,

[Sardar Sarup Singh]

Rehabilitation, Rural, Jullundur, under his office No. 132, dated 3rd May 1953 (Registered) complaining therein that in certain cases displaced persons bearing the same names and parentage have been allotted more lands than they were entitled to was received by him together with the date on which it was received by him and the action if any taken thereon;

(b) whether the applicants were informed of the action taken by the Government up to 24th September, 1953; if so, when, if not, the reasons therefor?

Sardar Ujjal Singh : (a) Yes. A representation made by one Niranjan Singh, son of Lal Singh, was received in this office on 7th May 1953. Allotment had already been corrected under Deputy Commissioner, Amritsar's order, dated 11th June 1951.

(b) As the representation was forwarded by Shri Sajjan Singh Margindpuri, he was informed of the action taken—*vide* post card No. 6150, dated 5th October, 1953, which has been acknowledged.

MORTGAGE SANADS.

520. Sardar Sarup Singh : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any applications from certain displaced persons were received by the Director, Rehabilitation Rural, Jullundur, between 30th May 1953 and 1st June 1953 and on 18th May 1953 for preparing the mortgage sanads to which they were entitled but which had not been previously handed over to them if so, the list of such persons along with their full addresses;

(b) the action, if any, taken by the Director Rehabilitation Rural, in each case up to 15th September, 1953;

(c) the dates of sending the required sanads of mortgage land in each case;

(d) whether the applicants referred to in part (a) above were informed of the action taken up to 24th September, 1953, in each case; if not, the reasons therefor?

Sardar Ujjal Singh : A number of applications were received from the applicants on 18th May, 1953 and from 3rd May, 1953 to 1st June 1953. In order to sort out the applications regarding the preparation of mortgages sanads it requires a great labour and time which will not be commensurate with the labour involved.

RETIREMENT OF REVENUE PATWARIS.

521. Sardar Sarup Singh : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) (i) whether any Revenue Patwaris of Tehsil Tarn Taran, District Amritsar, were retired from service in the month of September, 1952; if so, their list and the names of the circle in which they were posted prior to their retirement;

(ii) the date of retirement in each case;

(b) whether any arrears of pay, allowances and gratuity was due to them; if so, the amount to which each one of them was entitled as pay and gratuity respectively on the day of retirement;

(c) whether the amount referred to in part (b) above was paid to the persons concerned at the time of their retirement; if not, the reasons therefor;

(d) whether any representations were received by the Deputy Commissioner, Amritsar, from any of the persons referred to in part (a) above for the payment of their dues referred to in part (b) above; if so, the dates when these representations were received from each of the persons concerned: along with the action, if any, taken by the Deputy Commissioner in the matter;

(e) (i) whether any amount referred to in part (b) above was paid to any one of them before 13th September 1953; if not, the reasons for delay;

(ii) the person responsible for this delay and the action, if any, taken against him;

(f) whether any instructions have been issued by the Government for the payment of all the dues to the Revenue Field Staff on the day of their retirement; if not, the reasons therefor;

(g) the steps, if any, taken for the early payment of the amount referred to in part (b) above?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) (i) No.

(ii) Does not arise.

(b) to (g) Do not arise.

MOTOR FARE BETWEEN PATTI TOWN AND BHIKHIWIND, DISTRICT AMRITSAR.

522. **Sardar Sarup Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the actual distance between the motor stand of Patti Town and Bhikhiwind, District Amritsar;

(b) the motor bus fare charged per passenger by the Omnibus Service and the Majha Transport Co-operative Society, Ltd., respectively for the distance referred to in part (a) above;

(c) whether there is any difference between the fares charged; if so, what, together with the reasons therefor?

Shri Jagat Narain : (a) 13.0 miles.

(b) The fare charged by the Amritsar Omni Bus Service for the distance mentioned at (a) above is Rs. 0-7-6 inclusive of passengers tax, whereas the Majha Transport Co operative Society Ltd., charge for the same distance the fare of Rs. 0-8-9 inclusive of passengers tax.

(c) The Majha Transport Co-operative Society Ltd., charges anna 0-1-3 more than the State owned Amritsar Omni Bus Service. The maximum or minimum fares per passenger per mile for stage carriages are fixed by the Punjab Government in exercise of the powers conferred under section 43 of the Motor Vehicles Act, 1939. Within these limits the passenger transport companies are competent to fix fares within their operational area. The Amritsar Omni Bus Service is charging fare at the minimum rate of pies 6 per passenger per mile whereas the Majha Transport Co-operative Society Ltd., is charging fare at the maximum rate of pies 7 per passenger per mile.

COPYING AGENCY TEHSIL HEADQUARTERS PATTI, DISTRICT AMRITSAR.

523. **Sardar Sarup Singh** : Will the Minister for Development be pleased to state:—

(a) whether any Copying Agency has been established at Tehsil Headquarters, Patti, District Amritsar, if so, since when;

(b) (i) whether all the seals required under the rules have been supplied to the said Agency, if so, since when; if not, the reasons therefor;

(ii) the number of seals with the aforesaid agency as on 25th September 1953;

(c) (i) whether any representations were made by the person incharge of the Copying Agency referred to above asking for seals and a copy of the Manual of rules Governing the Copying departments to be supplied to the District Authorities, Amritsar, between 1st January, 1951 and 31st August 1953; if so, the date of each representation;

(ii) the action taken by the District Authorities in the matter up to 25th September, 1953;

(iii) the person responsible for the failure to supply the said seals and the Manual upto 25th September 1953; together with the action, if any, taken by the Government against him?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes. Since 24th June, 1949.

(b) (i) In the past no seals were supplied as no requisition in this respect was made to the Deputy Commissioner, Amritsar.

(ii) None.

(c) (i) and (ii) No.

(iii) Registration Clerk working under the Tehsildar, Patti, who failed to ask for the required seals is responsible for this. No action against that official has been taken so far.

JAMABANDI RECORDS OF CHAK NO. 109/15 L TEHSIL KHANEWAL, DISTRICT MULTAN.

*524. **Sardar Sarup Singh**: Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether Jamabandi Records of Village Chak No. 109/15L Tehsil Khanewal, District Multan, have been received from Punjab (Pakistan) authorities;

(b) whether there are any entries in the Jamabandi Records referred to in part (a) above regarding the cultivation of Killa No. 4 to 8/1 in Rectangle No. 75; if so, a copy of the same be laid on the table;

(c) whether the area referred to in part (b) above was sold by the Government to Sardar Sohan Singh and others—*vide* sale deed, dated 5th April, 1944, registered in the office of the Sub-Registrar, Khanewal; if so, the price thereof;

(d) whether the record of Khasra Girdwari of this village for the year 1946-47 has also been received by the Government; if so, a copy of the entry of Khasra girdwari for the year 1946-47 regarding the area referred to in part (b) above be laid on the table;

(e) whether any area has been allotted to persons referred to in part (c) above in lieu of the area referred to in part (b) above; if so, at what place; if not, the reasons therefor?

Sardar Ujjal Singh: (a) Yes.

(b) Yes. A copy of the *Jamabandi in respect of Killa Nos. 4 to 8/1 is laid on the table;

(c) There is no entry in the Jamabandi with regard to the sale of the area referred to in part (b);

(d) No.

(e) Yes. Allotment was made in Village Chur, H. B. No. 149, Tehsil Nakodar, District Jullundur.

*Kept in the Library.

ALLOTMENT OF LAND TO CERTAIN TENANTS IN VILLAGE KALSIAN KALAN.

525. Sardar Sarup Singh : Will the Minister for Finance be pleased to state:—

(a) whether Bachan Singh, Achhar Singh, sons of Lakh Singh, Boor Singh, son of Gurdit Singh. Bagga Singh. Tahal Singh, sons of Deva Singh and Kundan Singh and Inder Singh, sons of Sadha Singh, were holding any area as occupancy tenants in the "Shamlat turf Buryar" at Village, Badarpur, Tehsil Kasur, District Lahore, according to the Jamabandi record received from Pakistan; if so, the area held by each of them in standard acres;

(b) whether the persons referred to in part (a) above were owning any land in the village referred to in part (a) above; if so, the total area held by each of them in standard acres;

(c) whether at the time of allotment the areas to be allotted to each of them were consolidated; if so, the total area to which each of them is entitled according to the consolidated parcha claims;

(d) (i) whether they have been allotted any area in lieu of the areas referred to in parts (a) and (b) above at Village Kalsian Kalan and Kals of Tehsil Patti, District Amritsar, and at Village Tarmala, District Ferozepore; if so, the total area allotted to each of them in these villages;

(ii) whether there has been any difference between the area to which each of them is entitled according to the consolidated parcha claims referred to in part (c) above and the area actually allotted to each of them; if so, to what extent and the reasons therefor?

Sardar Ujjal Singh : (a) Yes. They owned land in the Shamlat turf Buryar of Village Badarpur, Tehsil Kasur, District Lahore, under occupancy rights as well.

Name of the person.	*Area in St. acres.* S.A.	U.
1. Bachan Singh, son of Labh Singh	5	11
2. Achhar Singh, son of Labh Singh	5	11
3. Buta Singh, son of Gurdit Singh	17	7
4. Bagga Singh, son of Deva Singh	4	8½
5. Tehal Singh, son of Deva Singh	5	7
6. Kundan Singh, son of Sadha Singh	2	11½
7. Inder Singh, son of Sadha Singh	2	11½

(b) Yes. As under—

	Name of the person.	*Area in St. acres* S.R.	U.
1.	Bachan Singh, son of Labh Singh	14	9
2.	Achhar Singh, son of Labh Singh	14	8
3.	Buta Singh, son of Gurdit Singh	19	1
4.	Bagga Singh, son of Deva Singh	5	8
5.	Tehal Singh, son of Deva Singh	11	2
6.	Kundan Singh, son of Sadha Singh	5	9
7.	Inder Singh, son of Sadha Singh	5	9

(c) Chhant jamabandi in respect of the shamlat area possessed by the occupancy tenants was prepared afterwards and as such this area was not taken into account at the time of general allotment.

(d) (i) In lieu of part (a) the parcha claims of Bachan Singh, Achhar Singh, sons of Labh Singh, Buta Singh, son of Gurdit Singh, and Bagga Singh, Tehal Singh, sons of Deva Singh have been consolidated with their previous parcha claims and according to that each of them is entitled to the net allotable area which is as under—

	Name of the person.	*Area allotted.* S.A.	U.
1.	Achhar Singh, son of Labh Singh	14	10
2.	Bachan Singh, son of Labh Singh	14	10¾
3.	Buta Singh, son of Gurdit Singh	25	6¼
4.	Bagga Singh, son of Deva Singh	7	8¾
5.	Tehal Singh, son of Deva Singh	12	2

Deputy Commissioner, Amritsar, has been directed to make adjustments in their accounts.

As in the chhant jamabandi the area under occupancy rights (prepared in the names of Inder Singh and Kundan Singh, their) parentage was written as Bahadur Singh instead of Sadha Singh their parcha claims could not be consolidated with the parcha claims previously prepared in their names.

In lieu of the area entered at (b) above they have been allotted land in Village Kalsian Kalan, Tehsil Patti, District Amritsar. No allotment has been made in Village Kals, Tehsil Patti; District

[Minister for Finance]
Amritsar or in Village Tarmala, Tehsil Fazilka, District Ferozepore. Each has been allotted as under—

Name of the person.	*Area allotted.* S.A.	U.
1. Bachan Singh, son of Labh Singh	10	11
2. Achhar Singh, son of Labh Singh	10	10¼
3. Buta Singh, son of Gurdit Singh	13	13½
4. Bagga Singh, son of Deva Singh	4	2
5. Tehal Singh, son of Deva Singh	8	4¾
6. Kundan Singh, son of Sadha Singh	4	2¾
7. Inder Singh, son of Sadha Singh	4	2¾

(ii) Yes. The details are as under—

Serial No.	Name of the perso.	Area actually allotted.		Net allotable area.		Additional area to be given.	
1	Bachan Singh, son of Labh Singh	10	11	14	10¾	3	15¾
2	Achhar Singh, son of Labh Singh	10	10¼	14	10	3	15¾
3	Buta Singh. son of Gurdit Singh.	13	13½	25	6¼	11	8¾
4	Bagga Singh, son of Deva Singh	4	2	7	8¾	3	6¾
5	Tehal Singh, son of Deva Singh	8	4¾	12	2	3	13¼
6	Kundan Singh, son of Sadha Singh.	4	2¾	5	7½	1	4¾
7	Inder Singh, son of Sadha Singh	4	2¾	5	7½	1	4¾

DEARNESS ALLOWANCE TO WORK-CHARGED ESTABLISHMENT (BUILDINGS AND ROADS BRANCH).

526. Sardar Sarup Singh : Will the **Minister** for Public Works be pleased to state—

(a) (i) whether any increment either in the pay or dearness allowance of the work-charged establishment, (Roads and Buildings Branch) was sanctioned by the Government during the year 1953; if so, at what rate per mensem;
(ii) the date from which this increment was sanctioned;

(b) whether the work-charged establishment employed over the Harike-Khalra Road and Amritsar-Khemkaran Road, respectively, were allowed to avail themselves of this increment up to 31st December, 1953, if not the reasons therefor;

(c) the total amount to which each member of Harika-Khalra and Amritsar-Khemkaran Roads work-charged establishment was entitled from the date referred to in part (a) (ii) above up to 31st December 1953;

(d) (i) whether the amount referred to in para (c) above was paid to them up to 10th January, 1954, if so, when, if not the reasons for delay;

(ii) the person responsible for this delay and the action, if any, taken or proposed to be taken by the Government against him?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) (i) Yes. Rs. 5 per mensem at both the initial and final stages for posts where the basic scales of pay start at less than Rs. 30 per mensem, i.e., up to and including Rs. 29-15-0 per mensem.

Rs. 7-8-0 per mensem at both ends, i.e., the minimum and the maximum in the case of posts, where the minimum pay is Rs. 30 per mensem, but less than Rs. 50 per mensem.

This increase was, however, not to be applied in the case of work-charged establishment recruited on *ad hoc* rate of pay taking into account the increase cost of living.

(ii) 1st April, 1953.

(b) Since the admissibility of this increase to all low-paid work-charged establishment was not clear, the matter referred to the Finance Department and it is at present under consideration of Government.

(c) Does not arise till (b) is decided .

(d) (i) Does not arise till (b) is decided.

(ii) Does not arise.

RETIREMENT OF THE OFFICE ESTABLISHMENT OF THE UPPER BARI DOAB CANAL CIRCLE.

527. Sardar Sarup Singh : Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

(a) whether any signallers, other officers and members of office establishment of the Upper Bari Doab Canal Circle are to be retired from service during the year 1954; if so, their list and their ranks;

(b) whether their service books have been completed; if not, the reasons therefor;

(c) whether any instructions have been issued by the Government that at the time of their retirement all their dues be paid on retirement and their pension papers be prepared and delivered within a month after retirement; if so, copy of these instructions be laid on the Table?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Statement showing names and ranks of persons due to retire during 1954 is enclosed herewith.

(b) (i) Service books of all the officials mentioned in the statement are complete except of items (1), (2), (7) and (24).

(ii) Item (1) Service Book is with Hissar Division, Western Jumna Canal Circle.

[Minister for Irrigation]

Item (2) Service Book is with Accountant-General, Punjab, Simla.

Item (7) Service Book is awaited from West Punjab.

Item (24) Service Book is with Rehabilitation Department.

(iii) Steps are being taken to obtain the Service Books back from the offices concerned. As regards Item 7, new Service Book has to be opened by getting particulars from the official or from information available in his personal files.

(c) No such separate instructions have been issued nor is there any necessity as the rules on this very subject in para 5.1 of P.F.R. Volume I, and Rule 9.14(2) of C.S.R., Volume II as amended by A and C No. 79 are quite clear and fulfil the conditions put forth by the hon. Member. The question of supplying copy thereof does not arise.

STATEMENT SHOWING NAMES OF ESTABLISHMENT ATTACHED TO UPPER BARI DOAB CIRCLE DUE TO RETIRE DURING 1954.

Serial No.	Name of person due to retire.	Rank.	Date of birth.	Date of retirement.
1	Shri Thakar Singh ..	Deputy Collector	28-8-1899	28-8-54
2	" Bishan Singh ..	Zilladar ..	23-3-1899	23-3-54
3	" Udham Singh ..	Do ..	20-4-1899	20-4-54
4	" Ram Narain ..	Overseer ..	25-11-1899	25-11-54
5	" Manohar Lal ..	Head Vernacular Clerk	2-5-1899	2-5-54
6	" Teja Singh ..	Officiating Head Vernacular Clerk	25-10-1899	25-10-54
7	" Inder Singh ..	Vernacular Clerk	1-10-1899	1-10-54
8	" Puran Singh ..	Ditto	1-2-1899	1-2-54
9	" Gian Chand ..	Ditto	1-4-1899	1-4-54
10	" Mela Ram ..	Signaller ..	7/1899	16-7-54
11	" Ramji Dass ..	Do ..	8-8-1899	8-8-54
12	" Chaman Lal ..	Do ..	1-9-1899	1-9-54
13	" Gurmukh Singh ..	Do ..	25-12-1899	25-12-54
14	" Som Nath ..	Do ..	1-1-1900	1-1-55
15	" Ram Lal ..	Assistant Clerk ..	12/1899	16-12-54
16	" Mathra Dass ..	Revenue Peon ..	7/1894	16-7-54

Serial No.	Name of person due to retire.	Rank.	Date of birth.	Date of retirement.
17	Shri Ram Piara ..	Telegraph Peon	7/1894	16-7-54
18	" Dewan Chand, son of Ganga Ram	Gauge Reader	1894	1-7-54
19	" Labhu Ram ..	Patwari ..	15-3-99	15-3-54
20	" Ram Chand, son of Ushamaki Ram	Do ..	18-4-99	18-4-54
21	" Sunder Dass ..	Do ..	8/1899	16-8-54
22	" Pindi Dass ..	Do ..	18-4-99	18-5-54
23	" Ram Lok ..	Do ..	28-3-99	28-3-54
24	" Kartar Nath ..	Do ..	28-8-99	28-8-54
25	" Kartar Singh, son of Sant Singh	Do ..	18-10-99	18-10-54
26	" Chandu Ram ..	Do ..	21-11-99	21-11-54
27	" Bhan Singh ..	Do ..	8-12-99	8-12-54
28	" Sardar Singh ..	Do ..	10-3-99	10-3-54
29	" Barkat Ram ..	Do ..	14-6-99	14-6-54
30	" Sadhu Ram ..	Do ..	18-5-99	18-5-54
31	" Dewan Chand ..	Do ..	12-6-99	12-6-54
32	" Kartar Singh, son of Sunder Singh	Do ..	7-5-99	7-5-54

COURT BUILDING AT SIRSA.

528. Shri Ram Dayal Vaid : Will the Minister for Public Works be pleased to state:—

(a) the amounts, if any, spent year-wise on the repairs of the court building at Sirsa, District Hissar from the year 1948-49 to 1952-53;

(b) whether any repairs, beyond white-washing and yellow-washing were done to the said building; if so, what and the total expenditure incurred thereon;

(c) whether he is aware of the fact that the Eastern Wall of the court building badly stands in need of repairs and at places reconstruction;

(d) whether this need of repair and reconstruction came to the notice of the Executive Engineer, Public Works Department through the Sub-Divisional Magistrate, Sirsa or the Deputy Commissioner, Hissar; if so, when for the first time;

[Shri Ram Dayal Vaid]

(e) whether he had a personal look at the court building in December, 1953; if so, the action, if any, taken or proposed to be taken by the Government in this connection?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) The building was previously maintained by the District Board and no repairs were done during the years 1948-49 to 1951-52. It was taken over by Government during 1952-53 and a sum of Rs. 150 spent on the repairs thereof during that year.

(b) No special repairs to the building have been done so far.

(c) Yes, an estimate for special repairs was prepared.

(d) The need for repairs was brought to the notice of the local P.W.D. authorities by the Superintendent of Police, Hissar in February, 1954.

(e) Yes, the building was inspected by me in the company of the Executive Engineer, Gurgaon Provincial Division. The building was found to be in such a condition that it had to be condemned as the special repairs estimate required was out of all proportion and it was proposed that a new building for Sub-Divisional Officer's Court be constructed as soon as funds are available.

TOURS BY THE MINISTER FOR DEVELOPMENT IN 1952.

531. Sardar Sarup Singh : Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) the list of the places visited by the Minister for Development during the year 1952 in the Tehsils of Patti and Tarn Taran, District Amritsar, respectively, along with the dates of each visit;

(b) the list of the Rest Houses in each of the Tehsils referred to in part (a) above;

(c) the list of halting places (Tehsil-wise) along with the dates of halts of the said Minister during the tour mentioned in part (a) above;

(d) the total amount of Daily Allowance charged by him in connection with these visits?

Shri Bhim Sen Sachar : The requisite information is contained in the statement given below.

Part (a)		*Part (b)*	*Part (c)*	*Part (d)*	
Dates.	Places visited in Patti and Tarn Taran Tehsils.	Rest Houses in the two Tehsils.	Halting places.	Dates.	Amount of Daily Allowance charged.
		Tarn Taran Tehsil			Rs.
27-4-52 / 28-4-52	Kairon	Khwaspur Rasulpur Dilawarpur	Kairon ..	27-4-52 / 28-4-52	15
29-6-52 / 30-6-52	Kairon	Nowshera	Kairon	29-6-52 / 30-6-52	15
5-7-52 / 6-7-52	Kairon	Bhuchar Kasel Lalu Ghuman Museh	Kairon	5-7-52 / 6-7-52	15
25-8-52	Kairon	Tarn Taran	Kairon	25-8-52	
26-8-52	Patti	Attari	Kairon	26-8-52	75
27-8-52	Valtoha Batala		Amritsar	27-8-52	
		Patti			
28-8-52	Kairon	Khara	Kairon	28-8-52	
29-8-52	Kairon	Jaura Valtoha	Jullundur	29-8-52	
16-11-52 / 17-11-52	Kairon	Minhala Khem Karan	Karion	16-11-52 / 17-11-52	15
22-11-52	Thatta	Pahuwind	Thatta	22-11-52	15
23-11-52	Kairon	Khalra		23-11-52	
20-12-52 / 21-12-52	Kairon Jaura and Patti	Patti Harike	Kairon Karion	20-12-52 / 21-12-52	45
22-12-52	Patti		Kairon	22-12-52	

TOURS BY THE MINISTER FOR DEVELOPMENT IN 1953.

532. Sardar Sarup Singh: Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) the list of the places visited by the Minister for Development during the year 1953 in the Tehsils of Patti and Tarn Taran, District Amritsar, respectively, along with the dates of each visit;

[Sardar Sarup Singh]

(b) the list of the halting places along with the dates of halts of the said Minister during the tours mentioned in part (a) above;

(c) the total amount of Daily Allowance charged by him in connection with the visits referred to in part (a) above?

Shri Bhim Sen Sachar: The requisite information is contained in the statement given below.

Part (a)		Part (b)		Part (c)
25-1-53	Taran Taran	25-1-53	Taran Taran	Rs. 240 only
26-1-53	Harike and Kairon	26-1-53	Kairon	
		27-1-53	Kairon	
27-1-53	Valtoha and Toot	28-1-53	Kairon	
		29-1-53	Tarn Taran	
28-1-53	Patti	3-4-53	Kairon	
29-1-53	Tarn Taran	23-4-53	Kairon	
	Viring	1-6-53	Kairon	
	Ekalgada	16-6-53	Kairon	
	Moghal Chak, &	17-6-53	Dubli	
	Tarn Taran	18-6-53	Dibipura	
3-4-53	Kairon	19-6-53	Dasuwal	
23-4-53	Kairon	20-6-53	Kairon	
1-6-53	Kairon	27-6-53	Kairon	
16-6-53	Kairon	18-7-53	Kairon	
17-6-53	Dubli	29-10-53	Amritsar	
18-6-53	Dibipura			
19-6-53	Dasuwal			
20-6-53	Kairon			
27-6-53	Kairon			
18-7-53	Rasulpur & Kairon			
29-10-53	Khalra			

OWNERS OF LAND OF KHATA NO. 68 OF VILLAGE NURPUR TEHSIL AND DISTRICT LAHORE.

533. Sardar Sarup Singh: Will the Minister for Finance be pleased to state:—

(a) the list of the owners of Khata No. 68 (sixty-eight) entered in Jamabandi of 1946-47 of Village Nurpur, Tehsil and District Lahore;

(b) the area owned by each one of them in this village;

(c) the valuation of the area in standard acres owned by each one of them in Village Nurpur;

(d) (i) whether any of them has been allotted any culturable area in this state in lieu of the area held in the village referred to above; if so, the localities in which each of them has been allotted any area;

(ii) whether any information regarding the allotment referred to in part (d) (i) above was sent to them; if so, when and by what means;

(e) whether any of the persons referred to above was owning any culturable area at Village Ghowind, Tehsil Lahore; if so, their list and the area owned by each one of them;

(f) whether any representation from Tek Singh, Rattan Singh and others was received by the Director Rehabilitation Rural, Jullundur for the consolidation of their area at Village Algon, Tehsil Patti; if so, the action, if any, taken by the authorities in the matter?

Sardar Ujjal Singh : The reply is detailed below.

(a) Wassan Singh, Dara Singh, sons of Bogh Singh, and Tek Singh, Rattan Singh, sons of Bur Singh.

(b)

	Name of the person.	*Area owned.* A.	K.	M.
1.	Wassan Singh, s/o Bogh Singh	1	6	12
2.	Dara Singh, s/o Bogh Singh	1	6	12
3.	Tek Singh s/o Bur Singh	1	6	12
4.	Rattan Singh, s/o Bur Singh	1	6	13

(c)

	Name of the person.	*Valuation* S.	A. U.
1.	Wassan Singh, s/o Bogh Singh	1	15
2.	Dara Singh, s/o Bogh Singh	1	15
3.	Tek Singh, s/o Bur Singh	1	15
4.	Rattan Singh, s/o Bur Singh	1	15

(d) (i)

	Name of the person.	*Place of allotment*
1.	Dara Singh, s/o Bogh Singh	Allotment not traceable.
2.	Wassan Singh, s/o Bogh Singh	Allotment not traceable.
3.	Tek Singh, s/o Bur Singh	Village Algon, Tehsil Patti, District Amritsar.
4.	Rattan Singh, s/o Bur Singh	Village Algon, Tehsil Patti, District Amritsar.

[Minister for Finance]

(ii) Intimation cards were issued by post to all the allottees at the time of quasi-permanent allotment.

(e) Yes. As under—

Name of the person.	*Area owned.* A. K. M.
1. Tek Singh, s/o Bur Singh	7 4 10
2. Rattan Singh, s/o Bur Singh,	7 4 10
3. Wassan Singh, s/o Bogh Singh	3 7 19
4. Dara Singh (Didar Singh), s/o Bogh Singh	3 7 19

(f) No representation was received for consolidation of area from any of them.

OWNERS OF KHATAS NOS. 427 AND 430.

534. Sardar Sarup Singh: Will the Minister for Finance be pleased to state:—

(a) the names of the owners of Khatas No. 427 (Four hundred and Twenty Seven) and No. 430 (Four Hundred and thirty) entered in Jamabandi Records for the year 1946-47 of Village Hudiara Hud Bast No. 279, Tehsil Lahore;

(b) the total area owned by each of the owners referred to in part (a) above;

(c) the total value fixed by the Rehabilitation Department for the area owned by each of the owners referred to in part (b) above;

(d) the area to which each one of them was entitled after the application of the general cut;

(e) the area allotted to each one of them and the place of allotement in each case;

(f) whether each of the allottees referred to in part (b) above has been put into possession of the area so allotted, if not, the reasons therefor;

(g) whether any of the persons referred to in part (b) above has not been put into possession of the area so allotted, if so, their list?

Sardar Ujjal Singh: (a) Shri Kundan Singh, Pritam Singh sons of Gujjar Singh.

(b)—

Name of the person.	*Area owned.* A. K. M.
1. Pritam Singh, s/o Gujjar Singh	**8 5 4**
2. Kundan Singh, s/o Gujjar Singh	**9 5 4**

(c)—

Name of the person.	*Value fixed* SA.	U.
1. Pritam Singh, s/o Gujjar Singh	**8**	**4¾**
2. Kundan Singh, s/o Gujjar Singh	**8**	**15**

(d)—

Name of the person.	*after cut* SA.	U.
1. Pritam Singh, s/o Gujjar Singh	**6**	**3¾**
2. Kundan Singh, s/o Gujjar Singh	**6**	**11¼**

(e) Kundan Singh was allotted 6 St. acres 11¼ units area in Village Badian H.B. 24, Tehsil Muktsar, District Ferozepore, but under the orders of D.P.R., dated 25th April 1953, his allotment to the extent of 4 St. acres was cancelled on account of his claim being false. The place of allotment of Pritam Singh is not traceable.

(f) Allotment of Kundan Singh stands in Village Badian and he is in possession thereof.

(g) Question does not arise.

REGISTRATION OF CASES AT POLICE STATION, DHARIWAL

538. **Sardar Shib Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of cases registered, challaned and convicted separately while Shri Sunder Dass was incharge of P.S. Dhariwal, District Gurdaspur;

(b) the number of cases of encounters with the police that were registered during the period referred to in part(a) above?

Shri Bhim Sen Sachar : (a) Cases registered 280, challaned 189, and convicted 127, at P.S. Dhariwal, District Gurdaspur, from 9th April, 1951 to 4th May, 1952, while S.I. Sunder Dass was incharge of the Police Station.

(b) One case.

REGISTRATION OF CASES IN GURDASPUR DISTRICT.

539. **Sardar Shib Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of cases that were registered in Gurdaspur District when Shri A.S. Midha was Superintendent of Police during the year 1951-52;

(b) the number of cases registered after the said Superintendent relinquished charge of the district up to now;

(c) whether there was any increase or decrease in crime; if so, to what extent together with the reasons therefor?

Shri Bhim Sen Sachar : (a) 5,087 cases were registered during the period 18th July, 1951 to 19th April, 1953, when Shri A. S. Midha I.P.S., was Superintendent of Police, Gurdaspur.

(b) 1954 cases were registered from 20th April, 1953 to 25th February, 1954 after Shri Midha relinquished charge of this district.

(c) There was a decrease of 543 (mainly in Excise and Arms Act cases and in Burgalries) cases from 20th April, 1953 to 25th Febraury, 1954 as compared with the Crime Return of corresponding period of preceding year and this decrease is in consonance with the general downward trend of crime in the State.

DAMAGE DONE TO CANAL OUTLET R.P. 122,495—R.

541. **Shri Mani Ram** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:—

(a) with referrence to the reply to unstarred Assembly Question No. 143 printed in the list of unstarred questions, dated 20th October, 1952, whether any damage was done to canal outlet R. D. 122,495—R; if so, the nature of the damage done;

(b) the estimated cost sanctioned for the repair of the canal outlet referred to in part (a) above;

(c) the total amount actually paid in connection with the repairs of this outlet together with the number of the bill and the date of its payment;

(d) the total amount actually spent on the repairs of the canal outlet R.D. 119,975—R together with the number of the bill and the date of its payment?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes. Outlet at R.D. 122 495—R Patti Distributary was damaged. The sanctioned size of a 6″ pipe outlet was replaced by a 8″ dia. pipe and a barrel was also made in the masonry of the outlet.

(b) No special estimate for the repair of this outlet was sanctioned. The repairs were carried out under M and R. (c) and (d). The information is being collected which will take some time as the matter pertains to the year 1947-48.

DISPLACED LAND OWNERS OF VILLAGE CHATHIANWALA, DISTRICT LAHORE.

542. Shri Mani Ram: Will the Minister for Finance be pleased to state:—

(a) (i) whether there are any displaced land owners of Village Chathianwal, Tehsil Kasur, District Lahore, who have not been allotted any culturable land in the State in respect of the land they held in Pakistan; if so, their list together with their father's names and castes;

(ii) the area which each one of them held in Pakistan;

(iii) the area to which each one of them was entitled;

(b) the reasons for not allotting them any area so far in each case?

Sardar Ujjal Singh: (a) (i) All the displaced land owners of Village Cathianwala, Tehsil Kasur, District Lahore, were allotted land and there is no unsatisfied claimant of this village.

(ii) Does not arise in view of the reply to (a) (i).

(iii) Does not arise in view of the reply to (a) (i).

(b) Does not arise.

DISPLACED LAND OWNERS OF VILLAGE THIH JHAROLIAN, DISTRICT LAHORE

543. Shri Mani Ram: Will the Minister for Finance be pleased to state:—

(a) whether there are any displaced land owners of Village Thih Jharolian, Tehsil Kasur, District Lahore, who have not been allotted any culturable evacuee area up to 31st January, 1954, if so, their list together with their father's names and reasons for not allotting them any area of land in each case;

(b) the area of land which each one of them held in the Village referred to in part (a) above;

(c) the culturable area to which each one of them was entitled after the general cut;

(d) (i) the number of the displaced persons who owned lands in Village Thih Jharolian referred to above;
(ii) the number of displaced persons from this Village who have been allotted lands up to now?

Sardar Ujjal Singh: (a) All the displaced land owners of Village Thih Jharolian, Tehsil Kasur, District Lahore, were allotted land and there is no unsatisfied claimant of this village.

(b) Does not arise in view of reply to (a).

(c) Does not arise in view of reply to (a).

(d) (i) 154.

(ii) 154.

FRESH WARABANDIS IN VILLAGE RANIWALAH, DISTRICT AMRITSAR.

*550. **Shri Mani Ram** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether the consolidation of the canal irrigated culturable area has been completed in Village Raniwalah, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar; if so, since when;

(b) whether any duly stamped representations by Sardar Sajjan Singh and others of this village were received by the Executive Engineer, Canals, Jandiala Division at Amritsar on 1st February, 1954 (vide Registered postal acknowledgement) for preparing the warabandi of canal outlets R.D. 23,825 and R.D. 18,472 of Jamaria Distributary according to the new allotments under the Consolidation Act; if so, the action taken in the matter;

(c) whether any steps have been taken by the Canal authorities to make temporary arrangements for the warabandi of canal water pending the final decision under section 68 of the Canal Act; if so, with what results; if not, the reasons therefor?

Chaudhri Lahri Singh : (a) It is not definitely known whether consolidation of Village Raniwalah has been completed. The information is being collected and it will be supplied to the member.

(b) Yes. Duly stamped applications were received and in reply the applicants were informed that as the areas which rank for water according to the sanctioned chakbandi were not discernible after consolidation, warabandi under section 68 of the Canal Act could not be framed.

(c) General instructions have already been issued to all Canal Zilladars that wherever possible temporary warabandi should be framed with the consent of the shareholders.

PAYMENT OF CYCLE ALLOWANCE TO TAIL GAUGE READERS IN UPPER BARI DOAB CANAL CIRCLE, AMRITSAR.

552. **Shri Mani Ram** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

(a) whether the tail gauge readers in the Upper Bari Doab Canal Circle Amritsar were entitled to any cycle allowance under the rules, if so, at what rates per mensem between 1st June, 1950 and 31st March, 1953;

(b) the list of the tail gauge readers referred to in part (a) above;

(c) the total amount to which each of the persons referred to in part (b) above was entitled cycle allowance for the period referred to in part (a) above;

(d) the total amount actually paid to each one of them up to 30th April, 1953;

(e) (i) the arrears due to each one of them up to 31st March, 1953, for the period referred to in part (a) above;

(ii) the reasons for the non-payment of the arrears up to 31st January, 1954;

(f) the persons responsible for this delay and the action, if any, taken by the Government against him for this delay?

Chaudhri Lahri Singh : The hon. members may please refer to the enclosed statement which indicates the whole position.

STATEMENT

(a) Whether the tail gauge readers in the U.B.D. C.C. Amritsar were entitled to any cycle allowance under the rules ; if so, at what rate per memsem between 1st June, 1950 to 31st March, 1953.	(b) The list of the tail gauge readers referred to in part (a).	(c) The total amount to which each of the persons referred to in part (b) was entitled cycle allowance for the period referred to in part (a).	(d) The total amount actually paid to each of them up to 30th April, 1953.	(e) (i) The arrears due to each one of them up to 31st March, 1953 for the period referred to in part (a)	(e) (ii) The reasons for the non-payment of the arrears up to 31st January, 1954.	(f) The person responsible for this delay and the action, if any, taken by the Government against him for this delay
		Rs. A. P.	Rs. A. P.	Rs. A. P.		
Majitha Division Yes, at Rs 4-8-0 per month.	1. G. R. Kathunangal	54 0 0 each.	4 8 0 each.	54 0 0 each.	Deterioration in efficiency of Administration at the time.	This calls for disciplinary action to be taken against the official of Majitha and Jandiala Division. Action against the Divisional Accountant of Jandiala and two accounts clerks is already being taken for the delay.
	2. G. R. Lalughuman					
	3. G. R. Khalra					
	4. G. R. Ranewali					
Jandiala Division Yes, at Rs 4-8-0 per month.	5. G. R. Khara	153 0 0	49 8 0	103 8 0		
	6. G. R. Nowshehra	153 0 0	49 8 0	103 8 0		
	7. G. R. Khawaspur	153 0 0	49 8 0	103 8 0		
	8. G. R. Manhala	153 0 0	36 0 0	117 0 0		
	9. G. R. Manihala	153 0 0	36 0 0	117 0 0		
	10. G. R. Valtoha	153 0 0	36 0 0	117 0 0		
	11. G. R. Rasulpur	149 10 0	36 0 0	113 10 0		
Gurdaspur Division Yes, at Rs 4-8-0 per month.	12. G. R. Sewa Singh	112 6 0	112 6 0	does not arise		
	13. G. R. Santokh Singh	111 15 0	111 15 0			
	14. G. R. Sain Dass	116 4 0	116 4 0			

COMPLAINT OF SHRI PALL SINGH OF VILLAGE SAIDO, DISTRICT AMRITSAR

554. Shri Mani Ram: Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) whether any complaint by Shri Pall Singh, son of Bishan Singh, Member, Gram Panchayat of Village Saido, Tehsil Patti, District Amritsar under sections 342, 323 and 504 I.P.C. was filed in the court of the Additional District Magistrate, Amritsar on or about 11th November, 1953 against Shri Hans Raj, Head Constable and Sardar Gurdial Singh and Mehr Singh, Constables of Patti Police; if so, the exact date thereof;

(b) whether the complaint under reference was sent to the Resident Magistrate, Patti for enquiry;

(c) (i) whether any summons were issued by the Resident Magistrate referred to in part (b) above to be served on Mehar Singh accused between 13th January, 1954 and 2nd February, 1954; if so, on what date;

(ii) the number and dates of the despatch register of the said Resident Magistrate's Court, under which the summons were sent to the Senior Superintendent of Police, Amritsar, for compliance between 13th January, 1954, and 12th February, 1954;

(iii) the dates and the numbers of the receipt register of the office of the Senior Superintendent of Police, Amritsar, against which the summons referred to in part (c)(ii) above were received;

(iv) the dates and the numbers of despatch register of the office of the said Senior Superintendent of Police, under which the summons under reference were sent to the Station House Officer, Patti Police Station or Officer Incharge, C.I.A., Patti, for compliance;

(v) the dates and numbers of the receipt register of Station House Officer, Patti Police, or Officer Incharge, C.I.A., Police Patti, against which these summons were received;

(d) (i) whether the summons referred to above were served on the accused referred to in part (c)(i) above up to 12th February, 1954; if so, when; if not, the reasons therefor;

(ii) the dates and numbers of despatch register under which these summons were sent back by the Patti Police to the Office of the Senior Superintendent of Police, Amritsar, after compliance or with report;

(iii) the dates and numbers against which these summons were sent by the Senior Superintendent of Police, Amritsar, too the Resident Magistrate, Patti;

(iv) whether any of the summons referred to in part (c) (ii) above were not sent back to the said court; if so, the reason therefor ?

Shri Bhim Sen Sachar : Information in respect of this question is being collected and will be supplied to the hon. member shortly.

DISPLACED PERSONS OF VILLAGE HUDIARA, DISTRIST LAHORE

556. **Shri Mani Ram** : Will the Minister for Finance be pleased to state:—

(a) the list of the displaced persons together with the names of their fathers and castes of Village Hudiara, Tehsil and District Lahore, who were allotted no culturable area up to 31st January, 1954, for the lands they owned in the said village ;

(b) the total area which was held by each one of them as full owner and as an occupancy tenant in the village referred to in part (a) above ;

(c) the area to which each one of them was entitled after the general cut ;

(d) the reasons for not allotting them any area in each case up to 31st December, 1953?

Sardar Ujjal Singh : (a) All the displaced land-owners of Village Hudiara, Tehsil and District Lahore, were allotted land and there is no unsatisfied claimant of this village.

(b) Does not arise in view of reply to (a).

(c) Ditto ditto

(d) Ditto ditto

REPRESENTATION FROM SARDAR SURAT SINGH AND OTHER LAND-OWNERS OF VILLAGE NARLI, DISTRICT AMRITSAR.

557. **Shri Mani Ram** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state the decision; if any, arrived at by the Canal authorities in the case referred to in Unstarred Assembly Question No. 329, printed in the list of Unstarred Questions, dated 11th March, 1953?

Chaudhri Lahri Singh : Request of Shri Surat Singh and others for transfer of 80 acres of area from outlet R.D. 15044-L to 18866-L of Sukharchak Distributary has since been accepted by Government. The transfer of the area was approved on 29th October, 1953.

JAMABANDI RECORDS OF VILLAGE KHERA.

558. **Shri Mani Ram**: Will the Minister for Finance be pleased to state:—

(a) with reference to the reply to Unstarred Assembly Question No. 493, printed in the list of Unstarred Questions, dated 8th October, 1953; whether any corrections were made in the jamabandi records of Village Khera, referred to therein on a comparison; if so, the list of the Khatas in which corrections were made;

(b) whether in the light of the corrections referred to in part (a) above any changes were made in the parchas of chhant jamabandi; if so, their nature and the list of the persons concerned; if not, the other purpose for which the comparison was made;

(c) whether Khatas No. 13 (thirteen) was compared at Wagha Border; if so, with what results;

(d) the total area owned by each of the shareholders of the Khata referred to in part (c), above before comparison and after the comparison;

(e) whether any difference was found on comparison in the shares of the area of ownership of any shareholder of the Khata referred to in part (c) above; if so, to what extent?

Sardar Ujjal Singh: (a) The entries of the Jamabandi of Village Khara, Tehsil Kasur, were compared with the original record at Wagha and the entries of Khatas No. 6, 10, 13, 23, 30 and 48/512—515—533—548, were corrected.

(b) The comparison has been conducted very recently, and no corrections in the chhant jamabandi have so far been made.

(c) Yes. In the copy of the jamabandi previously received the names of Gurbux Singh, Sucha Singh, sons of Ajaib Singh; Inder Singh, son of Dhayan Singh; Sunder Singh, Sham Singh, sons of Jaimal Singh; Sunder Singh, Isher Singh, sons of Jawala Singh and Wassan Singh, Surain Singh, sons of Hakam Singh were entered as share-holders in Khata No. 13. In the Jamabandi now received after comparison only Inder Singh, son of Dhayan Singh, Sham Singh, Sunder Singh, sons of Jaimal Singh and Surain Singh, Wassan Singh, sons of Hakam Singh, are shown as owners in this Khata.

(d) The details are as under:—

S. No.	*Name of the person.*	*Area before comparison.*	*Area after comparison.*
		A.K.M.	A.K.M.
1.	Inder Singh, son of Dhayan Singh	8 5 7	34 5 10
2.	Sham Singh, son of Jaimal Singh	8 5 8	34 5 10

S. No.	Name of the person.	Area before comparison.	Area after comparison.
		A.K.M.	A.K.M.
3.	Sunder Singh, son of Jaimal Singh	8 5 7	34 5 10
4.	Surain Singh, son of Hakam Singh	2 7 3	11 4 10
5.	Wassan Singh, son of Hakam Singh	5 6 5	23 1 0
6.	Gurbux Singh, son of Ajaib Singh	5 6 5	(No land found)
7.	Sucha Singh, son of Ajaib Singh	5 6 5	Ditto
8.	Sunder Singh, son of Jawala Singh	24-1-14	Ditto
9.	Isher Singh, son of Jawala Singh	46-1-19	Ditto

(e) The details of the shares under ownership rights are as under :—

S. No.	Name of the person.	Share before comparison.	Share after comparison,	Difference of area.
				A.K.M.
1.	Inder Singh, son of Dhayan Singh	1/16	1/4	26 0 3
2.	Sham Singh, son of Jaimal Singh	1/16	1/4	26 0 2
3.	Sunder Singh, son of Jaimal Singh	1/16	1/4	26 0 3
4.	Surain Singh, son of Hakam Singh	1/48	1/12	8 5 7
5.	Wassan Singh, son of Hakam Singh	1/24	1/6	17 2 15
6.	Gurbux Singh, son of Ajaib Singh	1/24	..	5 6 5
7.	Sucha Singh, son of Ajaib Singh	1/24	..	5 6 5
8.	Sunder Singh, son of Jawala Singh	1/3	..	24 1 14
9.	Isher Singh, son of Jawala Singh	1/3	..	46 1 19

REPRESENTATION FROM SARDAR KHEM SINGH AND OTHERS OF VILLAGE NARLA AND MARI MEGH, DIETRICT AMRITSAR.

560. Shri Mani Ram : Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

(a) with reference to the reply to part (c) of Unstarred Assembly Question, printed in the list of Unstarred Assembly Questions, dated 28th September, 1953, whether the local canal officers had submitted any report to the higher authorities before 31st January, 1954; if so, when;

(b) to what extent the complaint under reference was found to be correct;

(c) whether any action has so far been taken by the canal authorities of Majitha Division to get rid of the silt; if so, the nature of the action taken and the result thereof;

(d) whether a duly stamped application sent by Sardar Khem Singh of Village Narla on 10th February, 1954 (Registered Post) was received by the Executive Engineer, Majitha Division, on or about 12th February, 1954?

Chaudhri Lahri Singh : (a) No, because the fresh properly stamped application was not received up till 31st January, 1954.

(b) Does not arise in view of (a) above.

(c) No.

(d) Yes, but the same had also to be returned to the applicant for resubmission after giving full particulars of the outlet.

BASIC SALARY OF MAIL RUNNERS IN CANAL DEPARTMENT.

561. Shri Mani Ram : Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

(a) the basic salary per mensem of the mail runner in the Canal Department in the various canal circles;

(b) the date when the present scale of their pay was revised;

(c) whether this scale of pay has even been revised by the Government during the last 6 years; if so, when and with what results; if not, the reasons therefor;

(d) whether the mail runners referred to in part (a) above are considered Government servants; if so, of which class?

Chaudhri Lahri Singh : (a) The basic salary of Mail Runners is fixed by the Deputy Commissioners of the district concerned, annually and varies from district to district.

(b) In Simla, the present basic salary is Rs. 30 per mensem, in Simla proper and Rs. 25 per mensem in places other than Simla, with effect from 1st March, 1953.

(c) The information relating to Simla District is as under :—

The scale of Mail Runners was revised on 1st March, 1953, from Rs. 25 and 20 per mensem to Rs. 30 and 25 per mensem in respect of Simla proper and places other than Simla, respectively.

(d) Yes, Contingent Establishment.

BARRANI CULTURABLE AREA OF VILLAGE VEERAM, DISTRICT AMRITSAR.

562. **Shri Mani Ram** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total barrani culturable area of Village Veeram, Tehsil Patti, District Amritsar, which lies close to the Bassarke Distributary ;

(b) whether any representation sent by Sardar Chanan Singh and other land-owners of the village referred to in part (a) above through Sardar Sajjan Singh, Margindpuri, under his office No. 302, dated 15th September, 1953, (Registered Post A.D.), was received by the Executive Engineer, Majitha Division, Amritsar; if so, when ;

(c) whether any action was taken by the Canal authorities in the matter up to 12th February, 1954; if so, the nature of the action taken in the matter ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Total barrani culturable uncommanded area of Village Veeram is 21 acres.

(b) Yes, on 17th September, 1953.

(c) The request could not be acceded to as the area is uncommanded.

GRANT OF NEW ARMS LICENCES IN DISTRICT AMRITSAR.

563. **Shri Mani Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the list of the applicants together with their full home addresses whose applications duly recommended by the police for new arms licences were pending on the 1st January, 1953, with the District Magistrate, Amritsar ;

[Shri Mani Ram]

(b) whether any of the applications referred to in part (a) above were rejected during the year 1953; if so, the reasons therefor in each case;

(c) whether any of the applications referred to in part (a) above were accepted; if so, the date of acceptance in each case;

(d) the kind of weapon allowed to each applicant;

(e) the qualifications which enabled each of the applicants referred to in part (c) above to get the arm licence asked for ?

Shri Bhim Sen Sachar : (a—e) It is not in the public interest to disclose the information asked for. However, any specific case needing Government's attention may be brought to its notice, when it will be duly looked into.

REJECTION OF APPLICATIONS RECOMMENDED BY POLICE FOR ARMS LICENCES IN AMRITSAR DISTRICT.

564. Shri Mani Ram : Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) the Tehsil-wise list of persons together with their full home addresses who applied to the District Magistrate, Amritsar, for the grant of arms licences during the year 1953;

(b) the date when each of the applications referred to in part (a) above was received by the District Magistrate with a recommendation from the Senior Superintendent of Police of the said District;

(c) the kind of the weapon asked for in each case;

(d) whether any of the applications were accepted and the licences asked for issued by the District Magistrate, Amritsar, during the year 1953; if so, the date when such applications were accepted;

(e) whether any of the applications rejected were such as had been duly recommended by the police; if so, the date of rejection in each case together with the reasons therefor;

(f) whether any of the applications referred to in part (a) above were not dispossed of during the said year; if so, their number and the reasons therefor ?

Shri Bhim Sen Sachar : Information in respect of this question is being collected and will be supplied to the member shortly.

Mr. Speaker : The Question Hour is over. Now the Chief Minister will make a Statement.

मुख्य मंत्री श्री भीम सेन सच्चर: माननीय स्पीकर साहिब ! मैं आप का मशकूर हूं जो आप ने मुझे मौका दिया है कि मैं उस मामले की तरफ आप की वसातत से हाऊस की तवज्जुह दिला सकूं जो कि मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है और वह मामला उस कार्यवाही से सम्बन्ध रखता है जो कल यहां हुई। आप जानते हैं, स्पीकर साहिब, कि कायदे और कानून के मुताबिक कल एक इकट्ठी बैठक थी इस असैम्बली की और कौंसिल की और वह बैठक बुलाई गई थी गवर्नर साहिब के हुक्म से। वह एक आइनी बैठक होती है और आइनी बैठक के सिवाए इस का और कोई मतलब नहीं होता है। इस मौके पर गवर्नर साहिब ने अपना अड्रैस (address) पढ़ना होता है; और कुछ नहीं होना होता। आप जानते हैं कि इस मौके को एक खास अहमियत दी गई है। इस मौके पर साधारण तौर पर मैम्बर अपनी निश्चित जगह पर नहीं बैठते बल्कि जहां चाहें वहां बैठ सकते हैं। फिर आम तौर पर जब असैम्बली की बैठक होती है तो बाकायदा तौर पर इत्तलाह कर दी जाती है कि स्पीकर साहिब तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन जब गवर्नर साहिब ने दोनों सदनों को इकट्ठा address करना होता है तो यह तरीका इख्तियार नहीं किया जाता। इस दिन गवर्नर साहिब को एक procession की शक्ल में यहां लाया जाता है। इस मौके पर उन्हें खास मान दिया जाता है जिसे खास तौर से कबूल किया जाता है। यहां पर, स्पीकर साहिब! आप खुद होते हैं, चेयरमैन (Chairman) साहिब होते हैं और कुछ दूसरे लोग होते हैं जिन को साधारण तौर पर इस हाऊस में आने की इजाजत नहीं होती, जैसे गवर्नर साहिब के ए. डी. सी. और उन के सैक्रेटरी। मैं आप की तवज्जुह इन तफ़सीलात की तरफ इस लिये दिलाता हूं कि अगर हाऊस का कोई माननीय मैम्बर ऐसा हो जो इन चीजों को न जानता हो तो वह समझ सके कि कल की जो बैठक थी वह असाधारण तौर पर एक बैठक थी। वह बैठक ऐसी नहीं थी जिस पर वह सभी कायदे और कानून हावी हो सकें जो आपने हमारे लिये बनाए हैं और जो आईन में दिये गये हैं। इसलिये जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं इस मौका की खास अहमियत है। इस की जो खसूसीयत है उस की भी एक खास नोयत है इसलिये इस बैठक को आम बैठकों की निसबत एक विशेष स्थान दिया जाता है। स्पीकर साहिब! कल जो कुछ हुआ है इस का मतलब तो सिवाए इस के और कुछ नहीं है कि जो मैम्बर साहिबान कांग्रेस पार्टी के हैं उन के इलावा और कोई भी दूसरी पार्टी का मैम्बर इस मौके की अहमियत को महसूस न करे और यह समझे कि यह एक असाधारण बैठक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिये। आज कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट है तो कल दूसरी पार्टी की भी हो सकती है। Democracy का यह नियम ही है कि राज्य का जो ऊंचे से ऊंचा अधिकारी है यानी जो स्टेट हैड (Head) है, वह इस मौके पर उन के सामने आता है और उन्हें अड्रैस करता है। आप जानते हैं, स्पीकर साहिब, कि यह जो रूलज़ हैं उन में, और विधान (Constitution) में भी जो स्टेट का हैड है उस को एक खास जगह दी गई है। जितनी इज्जत एक स्टेट के हैड (Head) की हो सकती है वह हमारे विधान (Constitution) में और रूलज़ में है। इस बारे में जोर दिया गया है कि जो Head of the State है वह तमाम ताकत को represent करता है और यही वजह है कि State का जो हैड (Head) होता है उस को राज्य का प्रतीक समझा जाता है और उस का आदर करना राज्य का आदर करना है और इस ताकत का symbol समझते हुए भी हम उस की इज्जत करते हैं। इसी वजह से हम बड़े तरीका से और जाब्ता से बैठते उठते और बोलते हैं। बल्कि बोलते नहीं; खामोश ही रहते हैं क्योंकि उस वक्त बोलने की गुंजाइश ही नहीं होती। माननीय स्पीकर साहिब ! आम तौर के हालात में हम यहां के कवायद के मुताबिक चलते हैं लेकिन जब हमें कई हालात में कोई कायदा नहीं मिलता तो उस सूरत में हम Mother of Parliaments यानी British Parliament के कवायद को देखते हैं और उन के मुताबिक चलते हैं। वह हम इस लिये नहीं देखते कि वह इंगलिस्तान की चीजें हैं बल्कि इस लिये के इंगलिस्तान ने यह चीजें कायम करने में बहुत भारी हिस्सा लिया है। वहां हम देखते हैं कि यह Address from the Throne होता है। जिसे बड़ी इज्जत

[मुख्य मंत्री]

श्रौर सम्मान से सुना जाता है । मैं अर्ज करता हूं कि यहां ऐसी भावना पैदा करने में शायद वक्त लगेगा । हम देखते हैं कि उन आज़ाद मुल्कों में जब National Anthem गया जाता है तो हर शख्स, हर आदमी जिस जगह पर होता है वहीं खड़ा हो जाता है जैसे कि उस जगह पर जम गया हो । लेकिन अभी तक यहां पर हम वह भी नहीं कर पाये हैं कि जब हमारा National Anthem गाया जा रहा हो हम उस के आदर में खड़े हो जायें ।

फिर मैं अर्ज करता हूं कि हमारे देश का culture बड़ा शानदार है और हिंदुस्तान का culture में तो एक अतिथि का बड़ा आदर किया जाता है—अतिथि का मान किया जाता है । आप उस का मान करते हैं, उस को ऊंची जगह देते हैं और आप उस के सामने नीची जगह रखते हैं । फिर यह जानते हुए कि कोई मैम्बर बोल नहीं सकता है और यह जानते हुए कि कोई मैम्बर कोई Point of Order उठा नहीं सकता, कल जो कुछ आप की आंखों के सामने इस हाऊस में हुआ उस के लिये हमें शर्मिंदा होना पड़ता है । इस का मतलब यह है कि हम नहीं जानते कि democracy भी कोई चीज़ होती है, Democracy में लोगों की ताकत होती है और जो Head of the State होता है वह लोगों की ताकत का प्रतीक होता है और उस का हमें हमेशा आदर करना चाहिये । इस बात का ख्याल नहीं करना चाहिये कि वह गवर्नमेंट किसी खास पार्टी की है और वह Head of the State उसी पार्टी का Head है क्योंकि अगर आज एक पार्टी की गवर्नमेंट है तो कल दूसरी की भी हो सकती है ।

फिर, स्पीकर साहिब, अगर कोई माननीय मैम्बर हाऊस से उठ कर चला जाता है और इस की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेता या Address के समय शामिल नहीं होता तो वह भी सही चीज़ नहीं करता । लेकिन, स्पीकर साहिब, यह तो कभी नहीं हुआ कि हाऊस के अन्दर इस तरह के नारे लगाए गए हों । मैं मानता हूं, स्पीकर साहिब, कि आज कोई आदमी उस तरह के नारे नहीं लगा सकता क्योंकि सब जानते हैं कि वह हाऊस से निकाला जा सकता है । कल इसलिये नारे लगाए गए थे क्योंकि वे जानते थे कि स्पीकर उस वक्त functions नहीं कर सकता था, चेयरमैन functions नहीं कर सकता था । इस लिये मैं आप की वसातत से हाऊस के तमाम मैम्बरों से दरख्वास्त करता हूं कि वह इन सभी बातों को महसूस करें क्योंकि इन से सारे हाऊस की बदनामी हुई है ।

मैं आप की खिदमत में यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप इस हाऊस की डिग्निटी (dignity) और प्रैस्टिज (prestige) के कस्टोडियन (custodian) हैं । मैं हाऊस के लीडर (Leader of the House) की हैसियत में यह पब्लिक (public) तौर पर कहना चाहता हूं और आप की सहायता मांगता हूं कि आप इस हाऊस की डिग्निटी (dignity) को कायम रखने के लिये जो कदम उठाना चाहें कृपा करके उठायें और शिकायतों को दूर करने के सिलसिले में जो कुछ भी हो सकता है करें । इस हाऊस की डिग्निटी (dignity) को, जो कि हमने कल की घटना से खो दी है, वापिस लाने के लिये आप और आप की वसातत से मैं मेंबरान से प्रार्थना करता हूं कि वह भी मुनासिब कदम उठायें । हम बहस करें, हम सवाल करें, सप्लीमेंट्री (supplementary) करें, मगर (courtesy) को क्यों हाथ से छोड़ें ? गालियां निकालना कोई अच्छी बात नहीं है । गड़बड़ मचाना कोई बड़ी हिम्मत की बात नहीं है कीचड़ उछालना कोई हिम्मत की बात नहीं होती । हिम्मत तो इस बात में है कि आदमी बोले तो एक समझदार आदमी की तरह से जिस से वह कोई बेहतरी कर सके । मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस सिलसिले में हमारी मदद करेंगे कि ऐसा शर्मनाक वाक्या जैसा कि कल हुआ इस असैम्बली में फिर कभी न होगा । (तालियां) ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात पर माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने निहायत मुनासिब अलफ़ाज़ में कल के वाक्या की मुज़म्मत की है। यह सारा वाक्या न सिर्फ़ बड़ा शर्मनाक ही है बल्कि परेशानकुन भी है। इस हाऊस में ऐसे नारे लगाए गए जो एक मुमताज़ ऐवान की शान के शायां नहीं हैं। मेरी हमेशा यह ख्वाहिश रही है कि हर किस्म के ख्यालात को यहां पर पेश किये जाने का मौका मिले। लेकिन हाऊस की डिग्निटी (dignity) और प्रैस्टिज (prestige) को संभालना न सिर्फ़ मेजौरिटी पार्टी (majority party) का ही काम है बल्कि हर उस शख्स का भी है जो इस हाऊस का मैंबर है। हो सकता है कि कुछ मैम्बरान के दिलों में रंजिश या परेशानी हो। लेकिन जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने फ़रमाया इस हाऊस के वकार का अदब बराबर किया जाना चाहिए। आप को कड़ी से कड़ी नुक्ताचीनी करने का पूरा २ हक है, लेकिन गवर्नर साहिब के आने पर, जो, जैसा कि सारी दुनिया जानती है, सिर्फ़ एक कान्स्टीटयूशनल हैड (Const tutional Head) हैं और उन का पालिसी (policy) बनाने से कोई सम्बन्ध नहीं है और जो फैसले खुद नहीं करते, उन के विरुद्ध ऐसा करना निहायत परेशानकुन है। गवर्नर साहिब जब यहां आए तो उन को दोनों हाऊसों के मैम्बरान से मिल कर बड़ी खुशी हुई। लेकिन उन से जो सलूक हुआ उस से उन के चेहरे से ऐसा मालूम हुआ कि उन्हें निहायत रंज हुआ। उस से मुझे भी बहुत दुःख हुआ है और मेरे ख्याल में आप सब को भी रंज हुआ होगा।

अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं पूरा यकीन रखता हूं कि माइनौरिटी पार्टी (minority party) यानी औपोज़ीशन (Opposition) को हकूमत से कितनी ही नाराज़गी क्यों न हो और वह उस पर कड़ी से कड़ी नुक्ताचीनी भी क्यों न करे—इस का उन्हें हक है, पूरी आज़ादी है—लेकिन वह ऐसी कोई हरकत न करें कि जिस से गवर्नर साहिब को क्या किसी मैम्बर की शान पर भी कोई हरफ़ आए। अगर ऐसा न हुआ तो यह बड़ा नामुनासिब होगा।

मैं उम्मीद करता हूं कि यह अफसोसनाक वाक्या यहीं पर खत्म कर दिया जायगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है मैं चीफ मिनिस्टर साहिब का मशकूर हूं कि उन्होंने पहले ही मौके पर इस वाक्या की मुज़म्मत की है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि हम में से कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिस से इस हाऊस की बेअदबी और बेइज्ज़ती हो।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ !

अध्यक्ष महोदय : यह मिनिस्टरज़ (ministers) का privilege है कि वह किसी मामले पर जब भी चाहे स्टेटमैंट (statement) दे सकते हैं और वह स्टेटमैंट बहस का मूजब नहीं बन सकती। उस स्टेटमैंट के बारे में कोई सवाल जवाब भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं सरदार साहिब से जिन के लिए मेरे दिल में बड़ा इहतराम है, गुज़ारिश करूंगा कि वह इस पर बहस न करें। लीडर आफ दी हाऊस (Leader of the House) ने इस घटना की मुज़म्मत बिना तानो तशनीह और निहायत ही मौज़ूं इलफ़ाज़ में की है और इस पर बहस से इस की सारी ग्रेस (grace) मारी जाएगी।

अब बाकी रहा सरदार साहिब और दूसरे मैम्बरान का इस से इख्तिलाफ़। यह इस वक्त बहस का कारण नहीं बन सकता। इस के लिये उन्हें बजट पर और गवर्नज़ ऐड्रैस पर डिस्कशन (discussion) के वक्त काफ़ी मौके मिलेंगे। उस वक्त वह जो फ़रमाना चाहें फ़रमा सकेंगे। इसलिये यह बहस यहीं खत्म कर दी जाए।

पंडित श्री राम शर्मा : आन ए पुआंएंट आफ आर्डर सर (On a point of order, Sir,) क्या मैं पूछ सकता हूं कि जब चीफ मिनिस्टर साहिब कोई ब्यान दें तो उस पर किसी मैम्बर को ताईद या तरदीद करने का अख्तियार नहीं है ? बाअज़ दफ़ा जो कुछ लीडर आफ दी हाऊस (Leader of the House) कहते हैं, लीडर आफ दी औपोज़ीशन (Leader of Opposition) उस की ताईद कर देते हैं। तो आप की रूलिंग (Ruling) का यह मतलब हुआ कि मिनिस्टर साहिब की न कोई ताईद कर सकता है और न ही तरदीद ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ (On a point of order, Sir) ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤੱਲਕ ਜੋ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਫਰਮਾਂ ਸਕਣਗੇ ।

ADJOURNMENT MOTIONS

पंडित श्री राम शर्मा : मैंने एक ऐडजर्नमैंट मोशन (adjournment motion) का नोटिस दिया था । अगर इजाज़त हो तो उसे पढ़ दूं !

अध्यक्ष महोदय : गुज़ारिश है कि मेरे पास इस वक्त तक ऐडजर्नमैंट मोशनज़ (adjournment motions) के नौ नोटिस आये हैं। चूंकि सरकार ने अपनी पालिसी (Policy) वाज़े तौर पर बयान करनी है इसलिये पेशतर इस के कि मैं ऐडजर्नमैंट मोशनज़ के मुतअल्लिक कोई डिसीज़न (decision) दूं मैं चीफ मिनिस्ट्र साहिब से दरखास्त करूंगा कि वह बताएं कि क्या उन में से किसी मामले में या मामलों में वह ऐसा करने के लिए तैयार है ? मेरा ख्याल है कि इन ऐडजर्नमैंट मोशनज़ के नोटिस उन्हें पहले ही मिल चुके होंगे ।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. अगर आप इजाज़त दें तो मैं जो रूल है वह गुज़ारिश करना चाहता हूं। पहले आप मुझे rule पढ़ लेने दें और बाद में अगर आप मुनासिब समझें तो Adjournment motion को किसी भी ground पर रद्द कर सकते हैं। मुझे Adjournment Motion का नोटिस तो पढ़ लेने दें ।

अध्यक्ष महोदय : रूल यह है कि अगर मैं किसी नोटिस को in order (नियमानुकूल) करार दूं तो मैं खुद उस Adjournment Motion को पढ़ कर आप के सामने पेश करूंगा और अगर समझूं तो राय लूंगा। जब तक मैं कोई decision न दूं कि वह in order है या नहीं तब तक adjournment motion को या उस के नोटिस को पढ़ने का अधिकार नहीं है। दर असल यह अकल की बात है कि adjournment motion इसलिए पेश किया जाता है कि जो majority party हो या जो शासन कर रही हो उस पर नुक्ताचीनी की जाए। और अगर adjournment motion पढ़ ही दिया गया और पब्लिक (public) कर दिया गया तो इस के disallow करने या allow करने का advantage ही क्या है ? इसलिये सब से पहले यह स्पीकर का discretion है कि वह Adjournment motion को पढ़ कर सुनाए या महसूस करे कि वह कायदा और शरायत के मुताबिक है या नहीं। मेरे पास जितनी Adjournment Motions पहुंची हैं उन के मुतअल्लिक भी यही procedure adopt किया जाएगा । अभी मैंने अपना फ़ैसला सुनाया ही नहीं। इस लिये पंडित श्री राम शर्मा को adjournment motion पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकता ।

पंडित श्री राम शर्मा : श्रीमान् जी क्या मैं एक गुज़ारिश कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : आप गुज़ारिश कर सकते हैं। मानना न मानना मेरा काम है। मगर procedure यह है कि अगर मुझे यकीन हो जाए कि motion in order है तो मैं खुद ही उस को पढ़ दूंगा।

पंडित श्री राम शर्मा : अगर आप मेरी adjournment motion को in order नहीं समझते तो मैं बैठ जाता हूं और किस्सा खत्म हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : तो यही समझ लीजिए क्योंकि मैं आप को बहिस नहीं करने देना चाहता।

पंडित श्री राम शर्मा : इस का मतलब यह हुआ कि आप ने मेरी adjournment motion in order नहीं समझी : और अगर ऐसा है तो मामला खत्म हो जाता है। आप ने यह भी गौर करने की तकलीफ गवारा नहीं की कि मुद्दई कौन है और मुद्दालय कौन है.।

अध्यक्ष महोदय : Order, Order मुझे मैम्बर साहिब के व्याख्यान की ज़रूरत नहीं।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. मैं अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि 'व्याख्यान' जो लफ्ज़ है उस को मैम्बर साहिबान ने भी इस लाईट (light) में लिया है जिस में कि कोई Ironical बात होती है। आप की बहुत बड़ी dignity है।

अध्यक्ष महोदय : Motion के in order होने का फ़ैसला करना मेरी ज़ात तक महदूद है। इस का procedure यह है कि इस का फ़ैसला देना मेरा काम है कि adjournment motion in order है या नहीं। अगर यह motion in order है तो वह आप की वोट (vote) के लिए रखी जाएगी। इसलिये मैं पंडित जी से कहूंगा कि वह इस मामले को यहां पर खत्म कर दें। अगर Chief Minister साहिब कुछ इस बारे में फ़रमाना चाहें तो कह सकते हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. मैं यह गुज़ारिश करना चाहता हूं कि Chief Minister साहिब को यह तो पता ही नहीं कि हालात क्या हैं, क्या वजूहात हैं और जब यह बात उन पर ज़ाहिर ही नहीं तो वह किस और कौन सी adjournment motion पर बोलेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : Chief Minister साहिब के पास सब Adjournment motions मौजूद हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : लेकिन मैं तो अपनी Adjournment motion के मुतअल्लिक कह रहा हूं। यह नौ हैं। मुझे मालूम नहीं कि किस पर Chief Minister साहिब बोलेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपने जिन adjournment motions का नोटिस दिया है वह मेरे पास मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो नंबर बता सकते हैं। मैं Chief Minister साहिब को नं. १ की Adjournment motion पर जो चाहें कहने की दरखास्त करता हूं।

पंडित श्री राम शर्मा: मैं अदब के साथ जानना चाहता हूं कि मुझे ऐसा मालम होता है कि मुझे इजाज़त नहीं कि मैं इस Adjournment motion के बारे में कुछ कह सुन सकूं। इस लिये मैं बाहर जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठहरिये। आप रूल quote कीजिये।

पंडित श्री राम शर्मा: रूल मैं खाक quote करूं जब आप बोलने ही नहीं देते।

अध्य महोदय: आप रूल Quote करें। खाक वगैरा का लफज़ इस्तेमाल करने से क्या फायदा।

पंडित श्री राम शर्मा: मैं गुज़ारिश करना चाहता हूं कि रूल यह है:—

If the Speaker is of the opinion that the matter proposed to he discussed is in order he shall read the statement to the Assembly and ask whether the member has the leave to move the adjournment?

If objection is taken, the speaker shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places and if not.........

मेरी गुज़ारिश यह है कि अगर आप नोटिस के बगैर यह समझ लें कि मेरी Adjournment motion in order नहीं है तो नोटिस की क्या ज़रूरत है?

अध्यक्ष महोदय: अगर आप की इस तरह से ही तसल्ली होती है तो यह समझ लेना चाहिये कि motion in order नहीं है।

पंडित श्री राम शर्मा: I am very thankful to you, Sir,

श्री सिरी चन्द: On a point of order, Sir. बाकी की Adjournment motions के बारे में आप का क्या फैसला है?

अध्यक्ष महोदय: बाकी की adjournment motions भी आ जाएंगी।

पंडित श्री राम शर्मा: तो क्या बाकी की सारी adjournment motions out of order ही होंगी?

अध्यक्ष महोदय: यह फ़ैसला सिर्फ पहली adjournment motion के बारे में है।

पंडित श्री राम शर्मा: अगर आप मुझे वह order बता दें जिस में कि मेरी adjournment motions रखी गई हैं तो मुझे आसानी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय: उन का वही order है जिस में कि उन के नोटिस मिले हैं। I would like the Chief Minister make to some observations on Adjournment motion No. 2.

गुज़ारिश यह है कि हमारी असैम्बली का procedure बराबर यही रहा है और जिस के लिये हमारे पास अथारिटी (authority) है कि बजट सैशन में कोई Adjournment Motion ज़ेर बहस नहीं लाई जा सकती। *(Interruptions)* Order, Order इस लिये कि यह जो बजट सैशन है इस में मैम्बर साहिबान को किसी भी मज़मून पर किसी भी दिन ख्यालात के इज़हार करने की इजाज़त दी जाती है। मौका भी होता है और वक्त भी होता है।

मैं Adjournment motions के मुतअल्लिक एक ruling पढ़ कर सुनाता हूं:—

Here is a ruling given by the Speaker of the United Punjab Assembly in regard to the admissibility of the Adjournment Motions.

"I have received notices for about thirty adjournment motions. Following the past practice, I do not consider them to be in order because the general discussion of the Budget and the voting of the demands for grants will take place all these days, all matters on which discussion is sought to be raised by these adjournment motions can be discussed in the Budget Session. Therefore, I can't allow any discussion on these motions". (*Cheers*)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : On a point of order, Sir, ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ adjournment motions ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਰੂਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। Adjournment motions ਬਾਰੇ provision ਹੀ ਨਾ ਰਖੋ।

ਸਰਦਾਰ ਅਛੱਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਕ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker : The whole of this Session is called the Budget Session. Strictly speaking, the hon. Member is correct, but the Budget Session is coming and notice to that effect has been circulated and the matter shall have to wait till then. These adjournment motions are, therefore, at this stage anticipatory.

Besides, this has been our practice and it was followed last year and the year before and a convention has been established that no adjournment motions are taken up during the Budget Session. I propose to follow the same procedure this year too. The subject matter of these motions will either be discussed during the general discussion of the Budget or when demands for grants are considered.

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ यही एक वजह नहीं। सब motions में या तो किसी की गिरफतारी का जिकर है या किसी कत्ल का या ऐसी ही किसी और बात का। यह सब के सब *Subjudice* हैं। मुकदमे चल रहे हैं और वह लोग अदालतों में इनसाफ हासिल कर सकते हैं। फिर यह बात भी नहीं कि इन बातों पर बोलने का आप को मौका नहीं मिलेगा। अभी तो गवर्नर साहिब का ऐड्रेस है, बजट है। इन सब पर बहस होगी और आप को हर मामले पर बोलने का मौका मिलेगा। पर यह सब adjournment motions out of order हैं।

लेकिन एक बात है। इन में से बाअज मामले ऐसे हैं जिन के बारे में पब्लिक में बहुत काफी तशवीश है। इस लिये मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से अर्ज करता हूं कि अगर वह मुनासिब समझें तो किसी मुनासिब दिन दो तीन घंटे थोड़ी बहुत बहस के लिये रख दें ताकि मेम्बर साहिबान अपनी बात कह लें और वज़ीर जवाब दे दें।

मुख्य मंत्री : अर्ज है कि जो मामले disorders के मुताल्लिक हैं उन पर गवर्नर के Address पर बहस में अगर यह पेश किये गये तो मैं जरूर जवाब दूंगा और मैं उमीद रखता हूं कि उस जवाब से आप की तसल्ली हो जायगी। अगर कोई और बात हो तो....

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब आप से एक दरखास्त की है। उन्हें उस का जवाब देना चाहिये। हम इन की तरफ से सफाई सुनने के लिये तैयार नहीं।

मुख्य मंत्री : अर्ज यह है कि मैं आप के इरशाद की इज्जत की जगह दे कर अर्ज करता हूं कि कल बहस हो रही है । यह अपनी बातें कर लें और मैं जवाब दे दूंगा । मैं बहस को prejudice नहीं करना चाहता । मैं चाहता हूं कि वाकियात मालूम हो जायें । फिर हम कार्यवाही जरूर करेंगे ।

सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत : जनाब आप की तजवीज के बारे में इन का क्या जवाब है ?

मुख्य मंत्री : जनाब जवाब यह है कि कल परसों और General Budget पर बहसों के बाद भी आप यह कहें कि काफी बहस नहीं हुई तो हमें आप की तजवीज के मुताबिक समय देने पर कोई एतराज न होगा ।

सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत : Address पर तो हम बहस करेंगे ही । मगर आपने दो घंटे की खास बहस की तजवीज की थी । उस पर इनका जवाब क्या है ?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब अगर आप आज्ञा दें तो कल साढे छः की बजाए साढे आठ बजे तक बैठ सकते हैं । ताकि मैंबर साहिबान जितना समय चाहें ले लें और सब कुछ कह सकें ।

अध्यक्ष महोदय : Chief Minister साहिब का ख्याल यह है कि कल बहस होगी । मेम्बर साहिबान अपनी बातें कह लेंगे । Chief Minister साहिब उन का जवाब दे देंगे । और अगर इस के बाद भी मेम्बर साहिबान की तसल्ली न हुई तो दो घंटे खास तौर पर इस बहस के लिये मुकर्रर कर दिये जायेंगे । मेरे विचार में यह बहुत मुनासिब है ।

Pandit Shri Ram Sharma, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a matter of urgent public importance, namely, the police excesses up to the limit to committing rape on innocent women during the course of the anti-dacoity operations in Rohtak District in the last week of January last.

Pandit Shri Ram Sharma, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss an urgent matter of public importance, namely, the whole-sale arrests of the tenants in Hissar District, who were coming to Chandigarh to represent their case before the Government.

Pandit Shri Ram Sharma, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss an urgent matter of public importance, namely, the murder of one Gugan, son of Hans Ram, Jat of Village Khorra, District Rohtak, in the unlawful custody of the police and the cremation of his dead body without handing it over to his family.

Sardar Har Kishan Singh Surjit, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the atrocities perpetrated by the Police including indiscriminate beating, rape and dishonouring of women, loot and destruction of property in Village Jagsi, Rabhran and others in District Rohtak in the last week of January, 1954, and the regime of terror that has been now established in District Rohtak to suppress and gag the people.

Sardar Chanan Singh Dhut, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent, public importance, namely, the arrest of the two newly-elected members of Punjab Legislative Assembly, Shri Mani Ram Bagri and Shri Balu Ram and others, imposition of Section 144 in District Hissar and Ferozepore and the terror spread by the police in the month of February, 1954, to suppress the voicing of legitimate demand of the tenants for security of tenure and facilitate the evictions of tenants from land.

Announcement by the Speaker.

Mr. Speaker: I will now make a few announcements.

GOVERNOR'S ADDRESS TO BOTH HOUSES OF THE LEGISLATURE

Mr. Speaker: In pursuance of Rule 13(i) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I have to report that the Governor was pleased to address both Houses of the Legislature assembled together on the 8th March, 1954, under Article 176 (1) of the Constitution.

A copy of the Address is laid on the Table of the House.

ADDRESS

Mr. Chairman, Mr. Speaker and Members of the Legislative Council and Legislative Assembly:

I welcome this opportunity of greeting you all collectively for the first time since my arrival in the Punjab. I have met most of you individually and I am glad to say how much I have appreciated the warmth of your feeling towards me. You have the honour and the privilege to represent a people who have distinguished themselves in all walks of life and have left the impress of their courage and endurance all over the world. A less hardy and steadfast people than the Punjabis would perhaps have succumbed to the heavy pressure of calamities following the Partition, but with your resilience and fortitude you have not only survived but have resurrected your past glory. Through you, ladies and gentlemen, I wish to convey my sincere tribute to the brave and hard-working Punjabis. I consider it an honour and a privilege to be associated with their representatives in this august House in running their Government and to be of service to them. I assure you and, through you, your constituents that my one purpose and desire is to be of help and service in the making of the new Punjab that is now emerging before our eyes.

Sardar Achhar Singh Chhina, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the arrest of JOURNALISTS including the Editor of Partap, Prabhat, Akali Patrika, Ajit, Akali, Shri Chanan Singh Dhut, M.L.A., and Shri Jagjit Singh Anand, under section 124-A, in the month of November, 1953, and the arrest of General Manager "Naya Zamana" on February 13, 1954, without consulting the Press Advisory Committee, and thereby suppressing and gagging democratic and opposition Press in the State.

Sardar Darshan Singh, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of public importance, namely; the repression let loose against the HARIJANS of Village ROPANA, Bhangjari, Mahanbadar, Mooth, Roharianwala, Phulweri in Tehsil MUKTSAR, District Ferozepore, in the month of February, 1954, and keeping dozens of them in custody by the Police in a small room in Village ROPANA for a number of days and their indiscriminate beating.

Shri Wadhawa Ram, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely; the Begar taken from hundreds of villagers between February 6th and February 11th, 1954, for the repair and decoration of Roads in Tehsil Fazilka, for the visit of the Governor on February, 12, 1954, to Fazilka and the harassment of people at the time of the visit of the Governor, when they were not allowed to move about and do their normal work within 3 miles on either side of the Road on which the Governor was to pass.

Sardar Chanan Singh Dhut, M.L.A., to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the Lathi-charge on workers in Nangal and arrest of their leaders on January 12, 1953, and imposition of Section 144, when the workers demanded HOLIDAY on the Festival of 'Lohri'.

2. With the dawn of independence, the emphasis in the activity of Government has shifted from merely the maintenance of law and order and collection of revenue to the development and advancement of the people in all possible directions. Law and order have, however, to be maintained to enable the citizens to work in an atmosphere of peace, and I am glad to say that our position in this respect is on the whole satisfactory and hopeful. The total crime figure during 1953 have shown a decrease of about 4,000 cases as compared to 1952 and of about 8.000 as compared to 1951. Serious crime like murder, dacoity and robbery has declined to a level that compares favourably with the pre-partition figures. The main achievement of the year has been the liquidation of gangs of desperate outlaws operating in the Punjab as well as the neighbouring States. Thirty-six outlaws were shot dead in encounters with the Police and 42 arrested.

3. Apart from individual crime, the peace and tranquillity of the land can be threatened by the subversive, anti-social and anti-national activities of groups of self-seeking and misguided elements in the society. Unfortunately, in spite of the terrible lessons taught by the partition of the country and its aftermath, there are still some amongst us who seek to create differences and estrangement among the people and claim rights and privileges for a section thereof on wholly unacceptable and narrow considerations. Their activities have to be kept in check in the interests of the healthy growth of the nation. You, ladies and gentlemen, are aware of the several agitations started during the last year by such people. My Government kept unceasing vigil and took strong action without hesitation where necessary. In spite of the fact that the people of the Punjab have suffered heavily and are, therefore, prone to be easy victims of false promises and malicious attacks on the Government established by law, they have, generally speaking, refused to be misled by interested parties and the major share of the credit for the maintenance of public peace should go to them. An average Punjabi is a good worker, a good family man and attached to land. These characteristics of his are a good guarantee for the safe and healthy development of democracy in the Punjab, provided the required leadership is available to keep the people on the right track. This can be ensured through a stable Government and I hope you will agree with me that, since Partition, we have now as stable a Government as one could have. My Government is determined that no subversive or anti-social activities will be allowed to go unchecked.

4. Mere maintenance of law and order is, however, only a negative achievement and has to be accompanied by a complete confidence in the administration, the public services and the judiciary. The system that we inherited from the British created the impression in the public of government and its machinery being something awful, terrible and distant. This might have suited their purpose, but the average citizen could not have any faith in it, because whatever justice and redress he could secure from it was very costly and he never had the feeling of being associated with its working. All

this my Government have sought to remove by progressive, important steps in the direction of decentralization of the administrative machinery. As you all know, over 9,000 panchayats were elected to office during 1953 and have been entrusted with wide powers. As these institutions grow and take root in the soil, it is the intention of my Government to transfer more and more power to them, to extend their jurisdiction and to strengthen their hands. Our people will now have the chance to work out their own salvation in their own way by applying their own mind and their own hands to the tasks ahead. Some cynics might laugh at these experiments. Obviously such people have no faith in man. For centuries they have got used to the conception that a few selected people alone are capable of managing the affairs for the rest of the society. Such a view is erroneous. We have faith in our people and have hope in them. Let them have a hand in shaping their own destiny and we will see millions of them here in this State and elsewhere in India raising themselves to a pitch of activity to achieve an acme of progress unparalleled in history.

5. The decentralisation of administration is also being extended in another direction. It is proposed to raise every tahsil in the State to the status of a Sub-Division and to enhance the powers of the Sub-Divisional Officer to approximate those of the Deputy Commissioner. This is a step which I and my Government would have very much liked to implement at once throughout the State, but financial limitations stand in our way. We require more buildings and equipment at the tahsil headquarters for housing the officers to be located there and for their offices. These are not available everywhere, but in the coming year, thirteen tahsils in various districts will be converted into Sub-Divisions and the process of conversion will be completed as soon as possible. Side by side with this reform, we are about to introduce another, i.e., the separation of the executive and the judiciary in accordance with the Directive Principles of our Constitution. In the six districts of Gurgaon, Ambala, Jullundur, Hoshiarpur, Kangra and Simla, it is proposed to entrust criminal judicial work practically wholly to the Additional District Magistrate and some other Magistrates under him, who will perform only judicial duties. For the present, this decision is being implemented only under executive orders, but the ultimate aim is to separate all judicial work, take it out of executive control and place it directly under the High Court. In mentioning this reform, I do not for a moment suggest that our Magistrates have up to now been amenable to executive considerations necessarily at the expense of justice, or that there has been, in the recent past, any executive interference with judicial work. I should like to mention that in spite of the absence of separation of the judiciary from the executive, our Magistracy has remained as fairly independent as one could wish and our executive has continued to evolve the sound democratic tradition of non-interference in judicial matters. This is another matter to be greatly appreciated. I have been proud of the fact that my Chief Minister and his colleagues have repeatedly emphasised this aspect of non-interference in judicial matters. However, the system had to be changed, but it has been a case not so much of the need as of the principle involved. Justice must be free from even a suggestion of

being influenced by power and while the executive should be as strong as possible, the common citizen should have full faith in the judiciary of the State. My Government, I am assured, are, therefore, keen not to strengthen their own hands, but the hands of their masters, the people.

6. Administrative reform during the past year has not confined itself to the broader aspect of change in systems. It has also concerned itself with the more immediate and mechanical aspects of administration by securing that the personnel entrusted with the task of serving the people are efficient and honest. You are already aware of the existence of an independent Public Service Commission dealing with the cases of the higher Government officials. During the last year the Commission dealt with the recruitment of over 300 persons and cases of promotion of about the same number of officers. Although Government have the right—a very special right—to disagree with the decisions of the Commission, I am happy to announce that the advice of the Public Service Commission in regard to all these cases was invariably accepted. Let me also congratulate you on our State having the singular distinction of placing recruitment to lower category posts also in the charge of an independent body, the Subordinate Services Recruitment Board. This is a welcome step to secure efficient and honest officials at lower levels. The race for recommendations is now abating and a cleaner, healthier atmosphere is already discernible. Once more it is a question of faith. That faith in the essential justice of democratic government will grow from such small steps, because in their implication these steps are not small. While ensuring justice, these steps also ensure the appearance of justice and are most welcome to the common man. It is up to you and the people, in power or otherwise, to make these experiments a real success. Recommendations to these Commissions should be considered undignified, low, immoral and dangerous.

7. The reforms that we have introduced, and will continue to introduce, must aim also at the removal of corruption. The chief instrument of corruption is exploitation. A person in power, or wanting power, exploits either his own position or the weakness of his fellow men. As our people emerge from one shackle after another, as they find expression and fulfilment of themselves in shaping and developing their own destiny, corruption will disappear, because corruption is a peculiar characteristic and manifestation of slaves and slave-drivers. Although Government alone, in the context of the present circumstances, cannot eradicate corruption altogether, it must, of necessity, keep a vigilant check. Our Anti-Corruption Committee at Headquarters and similar committees at the district level have remained active and busy through the year. No less than 86 Government servants received punishment during 1953-54 in one form or the other, including imprisonment in two cases, dismissal in 8, termination of services in 15 and compulsory

retirement in 6 cases. The term of the Bhrashtachar Nashak Committee, which was constituted in the beginning of 1953, has been extended from time to time and it has proved a source of confidence to the people. You, ladies and gentlemen, can play an important role in rousing public opinion to a pitch where persons shy of committing other crimes, should also become naturally afraid of committing the crime of corruption. You can ensure that Government work is carried out on principles rather than on the basis of persons and personalities. While exposing corrupt officials mercilessly, your task and the task of the people, who have chosen you as their representatives, is to encourage and appreciate the independent, unprejudiced and fair work done by our officers. In the meantime, my Government have decided to examine all Rules of Conduct and Business in the various Departments and offices to ensure removal of oppressive, unnessary and useless rules and precedents. In many cases, delay, is the greatest weapon in the hands of the corrupt officials. On the other hand, since the Administration is responsible to you, ladies and gentlemen, ultimately nothing can be done which has not been tested in all its aspects as correct and accurate. Passage of time is necessary and inevitable in Government work, but passage of time is one thing and avoidable delays quite another. My Government, after examination of all the rules, will see whether a modification or change of these rules can by itself eliminate avoidable delays and chances of corruption in various directions.

8. Before passing on to other topics, I would like to place on record my general and sincere appreciation of the Services in this State. You are lucky, ladies and gentlemen, that you have a large number of officers who are honest, efficient, hard-working and painstaking. These officers were the people who, by their unremitting labour, honesty and devotion to duty, piloted this young State through the worst period of its earliest history and I have no doubt that they will carry on the task of building up of this State with the same zeal and interest. All those of the services who have done good work deserve my thanks, the thanks of my Government and, I am sure, of the Members of this House who represent the people of the State.

9. And now I must turn to Development and the State Five-year-Plan. The State Plan was formulated in 1950, and, as was inevitable, most of the Post-War Reconstruction Schemes were icorporated in it. The original Plan, including an estimate of Rs. 10 crores for the new Capital, was just a little over Rs. 20 crores for the State. By raising the estimates on the Capital Project, the introduction of Community Projects and Schemes in the scheduled areas and, last of all, the introduction of the National Extension Service, the total State Plan has now come to about Rs. 31 crores. During the Plan period the maximum expenditure will be on the Capital, amounting to Rs. 12·8 crores. The Community Projects will take Rs. 3.244 crores, agricultural and rural development Rs. 2.625 crores, Irrigation and Power Projects Rs. 3.644 crores and the National Extension Service Rs. 1.53 crores. These schemes are of course, exclusive of the Central Schemes of Bhakra Nangal and Harike Projects. With a view to increasing immediate opportunities of employment, the State Plan is proposed

to be strengthened further to the extent of Rs. 4.49 crores, comprising expenditure on small scale and cottage industries, road development, education and minor irrigation.

10. Our achievements under the State Five-Year-Plan, in the context of the original schemes, have been more than satisfactory. Out of a total proposed outlay of over Rs. 20 crores, we have already spent about Rs. 16 crores in three years, leaving a balance of about Rs. 4 crores for the remaining two years. It was on the basis of this that we were able to secure further promises of help from the Planning Commission in regard to the additional expenditure of Rs. 4.49 crores. Some schemes involving this additional expenditure have already been sanctioned.

In regard to physical targets of achievement, you see the results all round. From a deficit State we have now positively emerged as a surplus State in foodgrains and are fast assuming our old position of being the granary of India. The latest declaration by Government de-controlling and derationing rice, I am sure, was welcomed in all quarters. There is no control at all on the movement of coarse grains. A levy on the export of gram was being made since April, 1953 but that too stands abolished with effect from the middle of December, 1953. Foodgrains are now freely available throughout the State. We have managed not only to meet all our requirements of food from within the State, but also to export as much as 74,000 tons of rice, 28,000 tons of wheat and 11,000 tons of coarse grains. The drive for growing more food, however, continues. Our target of production during the five years was 16,444.53 thousand tons and during the past three years of the Plan we have achieved more than the average increase. During the year 1953-54 an expenditure of over Rs. 44 lakhs is expected to be incurred on grant-in-aid schemes and a sum of over Rs. 266 lakhs on loan schemes for Grow-More-Food Campaign. On the side of irrigation it would be sufficient to state that 206 tube-wells were sunk during the year by the Agricultural Department. Over 400 tube-wells have been sunk or are being sunk by the Irrigation Branch. 522 percolation wells have also been dug. Considerable progress was made under the East Punjab Utilization of Lands Act by bringing waste land under cultivation. Over 7 lakhs of acres of waste land are estimated to be fit for cultivation. Out of it, over 1,20,000 acres have been actually brought under the plough. Consolidation of holdings throughout the State is another measure designed to increase the production of food and confer material prosperity on the agriculturist. The total area for consolidation is about 155 lakhs of acres. Till the end of December, 1953, a total of 3,179 villages with an area of over 26,37,000 acres had been repartitioned into consolidated holdings. It is expected that by the end of March, 1954, work will have been completed altogether in 10 tehsils, and in another 3 tehsils a litle later. An important policy decision which may be touched upon in this connection relates to reservation of land out of the common pool for the village panchayats. This land will be managed and utilised for common needs and benefits of the villagers. There has been considerable progress in various schemes which aim at supplying cheap power and adequate water for purposes of irrigation. Under the minor irrigation

schemes an area of over 3 lakh acres was brought under non-perennial irrigation. The Jagadhri tube-well scheme is awaiting completion. 500 tube-wells are in hand under the T.C.A. programme.

11. The Chief Irrigation and Power Project to benefit the State is the Bhakra-Nangal Project which is making steady progress. The two diversion tunnels have been completed. Nangal Dam has also been completed. The excavation of the canal leading from it is practically complete and it will be completely lined by the end of April 1954, The canal will be ready by May, 1954, and Kharif supplies will be run this year. During last year four distributaries of Sirhind Canal were completed and opened to irrigation with effect from Kharif, 1953. Most of the work on the Bhakra Main Line is also done and it will be fully completed by April. It is a matter of pride for me to announce that the work will be comleted two years ahead of the porgramme in the case of Narwana Branch, and one year ahead of the progrmme for other branches.

12. On the Hydro-Electric side, power house No. 1 at Ganguwal is likely to be commissioned by the target date of July-August, 1954. The second power house at Kotla will be commissioned by November, 1955. 417 miles of high tension line out of a total of 1,734 miles have been completed. For the present these lines have been energised from thermal or Uhl river schemes. It is expected that the whole work will be completed by the end of 1954-55. Steps for increasing supply of power were taken in various other directions also. During 1953-54, Capital works costing approximately Rs. 79 lakhs were scheduled to be executed for extension of electric supply from the Uhl system to urban and rural areas in the districts of Kangra, Gurdaspur, Amritsar, Jullundur, Ludhiana and Ferozepore. Since partition, 118 private tube-wells have been connected to this scheme. Also, the Electricity Branch have undertaken to supply power to 355 tube-wells which are to be sunk under the T.C.A. programme.

13. Originally the road development programme of my Government under the Five-Year-Plan was rather weak. It has now been expanded by Rs. 90.5 lakhs. Also the road programme for Bhakra area with a total expenditure of over Rs. 2 crores has recently been submitted to the Planning Commission for approval.

So far as the Education Department are concerned, their achievements, particularly in regard to non-basic primary schools, are considerable. Ultimately it is intended to convert all these schools to the basic pattern. Under the additional programme of the Education Department for relieving unemployment, it is intended to open 2,300 single teacher schools and 80 social education centres, besides the provision of additional teachers to 700 schools during the remaining Plan period. The Co-operative Department have a fairly ambitions programme during the plan period. With a target of over 3,500 new Co-operative Societies of various types, such as multi-purpose societies, credit societies, sale and marketing societies, co-operative farming societies, industrial societies and others, the yearly figure has exceeded the average. It is expected that the work in

connection with the development of co-operative farming societies, as also in connection with the formation of labour co-operatives, will be considerably augmented during the remaining years of the Plan. Labour co-operatives have been introduced with two objectives. One is to interest the local people in the execution of the projects passing through their areas. The second is to eliminate the huge profits of the contractor, and to distribute these among the rural population, incidentally providing them with work to remove under-employment, which is a feature of our rural economy.

14. The work of rehabilitation is gradually coming to a close. Allotment of land has reached its final stages. Payment of compensation to displaced persons in respect of their properties abandoned in Pakistan has begun and steps are now being taken to accelerate the pace. About 20,000 mud huts which were occupied by displaced persons, have been transferred to them at a concessional rate. To meet the acute shortage of housing accommodation, Government have constructed more than 2,000 cheap tenements at different places. Along with the rehabilitation of the people, Government, as you all can see, have taken a major step to rehabilitate themselves. In pursuance of their resolve to be amidst the people whom they have to serve, Government decided, in spite of many obstacles, to move down from Simla last year. Since then several offices have shifted to Chandigarh and the town is now humming with official activity. The number of residential sites so far sold now exceeds 7,000. Sixty-seven industrial sites and 148 commercial sites have also been sold. Practically all the official houses to be built under the Project have been completed or will be completed in the next two or three months. Private construction has begun, although on a small scale. My Government are considering ways and means to accelerate it. The High Court building is expected to be completed by the beginning of October next. It will then be possible for the High Court also to shift from Simla to Chandigarh. This is expected to give impetus to private construction.

15. By far the greatest feature of any Plan under a democratic Government is the development of the community. Government can never have enough resources to make direct investment in development commensurate with the needs of the people. The greatest feature, therefore, in the Five-Year-Plan is the energising of the people themselves. In pursuit of this objective were launched the Community Projects which were inaugurated in October, 1952. Four Community Projects were sanctioned for our State, involving 1,500 villages and a population of one million, and about 7,50,000 acres of cultivated land. During 1953, four more community blocks were added at Kulu, Tarn Taran, Thanesar and Naraingarh, and now has come the wider programme of the National Extension Service. Technical aid and Government help in almost all directions has to be extended to blocks of 100 villages all over the country. For the Plan period, 30 bloks were sanctioned for this State. It is intended to cover the whole State with these blocks by the end of the second Five-Year Plan. Another side of community development programmes are the Local Development Works Schemes. These are chiefly introduced in areas which are either backward or have not received, so far any attention under the Community Projects

or the National Extension Service programmes. For the year 1953-54 the Government of India sanctioned Rs. 9.8 lakhs for these programmes. With 50 per cent contribution by the people of the areas selected, schemes costing about Rs. 19 lakhs have been worked out and will shortly be initiated all over the State. The Deputy Commissioners have been directed to go ahead with the schemes and with the preparation of more schemes for the coming year.

Community Projects, National Extension Service, Local Development Works Schemes—all these are primarily the same thing. Ultimately, all Community Development Work will be consolidated into National Extension Service Blocks. The expenditure therein will be gradually raised to the standard of Community Projects as investment in this direction begins to show results. Government loans, fertilisers, implements, seeds, co-operative guidance, help in marketing, aid in small scale and cottage industries—all these will flow through the headquarters of the Extension Block, which is now the new real unit of administration. This corresponds exactly with our schemes for decentralisation of administration otherwise. You will see that this will provide intensification of effort in all directions in these small manageable units and Government departments will now function essentially as veins supplying blood to feed these practically autonomous development cells in the country.

16. Ladies and gentlemen, you are on the threshold of a new era, but the maximum achievement, again, depends entirely on you. I and my Government are devoting ourselves to the task of building the new State of Punjab and to energising the people and securing their effective partnership in the task of administration. In this direction we have not ignored another vital aspect, that is, of helping up such sections of society which have sunk lower than the rest. No community can function homogeneously without all its sections being brought forward in one single line to contribute their best constructive effort. In accordance with the directives of our Constitution my Government have gone ahead with helping various categories of backward classes to come forward and to develop themselves. Schemes worth about Rs. 75 lakhs have been specially introduced for the Scheduled tribes and the Scheduled areas. Other backward classes have been provided facilities in education entailing commitment by Government to expenditure of lacs of rupees every year. The work of enumerating backward classes is still not complete but it has been decided to extend to the backward classes all the concessions which are at present available to Scheduled castes, except, of course, those relating to reservation of seats in the Legislature, which are governed by the Constitution. The Harijan Welfare Scheme for the promotion of education amongst backward classes continues to function and vacancies in Government departments have been reserved for them, as you all know. Another proposal about to mature is that seats in technical institutions should also be reserved for these classes of people. For the purpose of looking after the interests of backward classes better, it has now been decided to create a separate department. Reservation in services, seats in educational and technical institutions, drive against untouchability, reservations in Panchayats and Lambardaris, such measures and many others are designed to ensure effective equality between all sections of society. Slavery, mental, social and political, creates, among other things, poverty, and poverty, again, leads to

some kind of slavery. It is up to all of us to break this vicious circle and to recognise our backward brothers and sisters as such. May I ask you, Ladies and Gentlemen, to base your entire life, its various phases of activity, on dreams and hopes that will ensure opportunities for all and that will banish ignorance and poverty from this country for ever.

17. There is another class of depressed people who require our help. This class is not a backward class. In fact, it is a class of heroes, national heroes who suffered untold miseries in the struggle for freedom. National pride can hardly survive if national heroes are left to rot after a lifetime of poverty, oppression and imprisonment. My Government have continuously applied themselves to the task of rehabilitating our heroes as the honoured soldiers of the fight for freedom, to the task of helping their widows and minor children to face the struggle for existence with a measure of dignity. The Government contribution to the National Workers' Relief Fund stands at about Rs. 3 lakhs. Other concessions which have been extended to political sufferers relate to grants in the form of land, relaxation of age-limit for entry into Government service, restoration of pensions, refund of fines, restoration of confiscated properties, etc. Private contributions to this Fund, however, still remain negligible. It is hoped that, with your help, the people will come forward with all they can do by way of partly paying the debt which we owe to these warriors.

18. Ladies and Gentlemen, you will shortly be considering the Government proposals for the budget for the new year. You will recall that last year we were compelled to present a deficit budget. Our lean resources will not, however, deter us in the coming year from increasing the pace of economic development and spreading of educational, medical and other facilities both in the rural and urban areas of the State, particularly in the backward areas and tracts. Every effort has been made to make the budget proposals consistent with our avowed policies of building up the State and its people in all directions. There are one or two major policy decisions of my Government which I have to announce. Under the Directive Principles of the Constitution, Government stand committed to the policy of prohibition. In pursuance of this policy they have decided that public drinking should be effectively discouraged. No new bar licences will, accordingly, be granted and the bar licences surrendered will not be renewed. Drinking in civilian clubs will be banned *in toto* with effect from the 1st of April. Government have also taken another important decision, that is to nationalise the road transport. The process of nationalisation will be begun next year but completed over a period of some years.

19. Your programme is fairly heavy because in addition to the budget you have several legislative measures to consider. Before I leave you to your deliberations, let me express the hope that you will continue to remain conscious of your heavy and important responsibilities. The effort to be made is very vast indeed. The United States Military Aid to Pakistan is now no longer a matter of conjecture and surmise. Military aid is being offered to a country that is

not involved in any immediate or future threat of war. Even the sponsors of the aid have been hard put to it to give any justification except the one of a sovereign nation being free to cut its own throat. It is only recently that many oppressed and down-trodden nations of Asia have begun to breathe freely. However, Asia is still in the grip of poverty, ignorance and disease. In such circumstances to sow the seeds of infection, once more, of foreign domination and to regard the process as if the military aid was not a military expedition, would be ridiculous and dangerous. In such circumstances there is only one defence, one precaution, one protection. We must remove all weaknesses, all discords, all disparities from amongst us because, ultimately, it is a strong, united, peaceful and determined people that constitute a target that even the deadliest weapons find difficult to destroy. Everything else can be destroyed but not a consciously determined and united people. In a way, on your shoulders falls the mantle for the defence of the country and, in fact, of Asia. We are dedicated to the cause of Peace and goodwill among nations—the more so to our neighbour across the border. We have no aggressive intentions or designs towards anybody. But we must jealously guard the Freedom we have won after a long struggle full of suffering and sacrifice. We must resist all attempts to reverse or retard the course of recent history in Asia. Obviously it is the proud privilege of our generation to work harder and make greater sacrifices to ensure our own freedom and enable our erstwhile associates to regain theirs. I will expect you to bear this in your mind when we come up to you to demand help for a concerted action towards making our country internally sound and strong in every possible manner. May God bless you!

JAI HIND.

ARREST OF SHRI MANI RAM AND SHRI BALU RAM, M.L.A.s.

Mr. Speaker: I have to inform the House that Shri Mani Ram and Shri Balu Ram, Members of the Punjab Legislative Assembly were arrested at Hissar on 1st March, 1954, under section 145/188 of the Indian Penal Code.

ABSENCE OF SARDAR NIDHAN SINGH, M.L.A. FROM THE BUDGET SESSION ON ACCOUNT OF ILLNESS.

Mr. Speaker: I have received the following application from Sardar Nidhan Singh, M.L.A.

> "I have been ill for the last four months. Even though the crisis has passed, it is still not possible for me to attend the next Budget Session of the Punjab Legislative Assembly and I require regular treatment and complete rest. I am at present admitted in the V.J. Hospital, Amritsar, and am under treatment. I, therefore, request you to grant me leave of absence from the Budget Session of the Punjab Legislative Assembly......"

Has the hon. Member the leave of absence asked for?

The leave was granted.

PANEL OF CHAIRMEN.

Mr. Speaker: Under Rule 11(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, I have nominated the following four Members as Members of the Panel of Chairmen:—

1. Shrimati Shanno Devi.
2. Sardar Harkishan Singh Surjit.
3. Rao Gajraj Singh.
4. Shri D. D. Puri.

COMMITTEE ON PETITIONS

Mr. Speaker: Under Rule 177 of the Rules of Procedure of the Punjab Legislative Assembly, I have nominated the following Members as members of the Committee on Petitions:—

1. Sardar Gurdial Singh Dhillon (Deputy Speaker) .. *Chairman.*
2. Sardar Wazir Singh.
3. Shri Rizaq Ram.
4. Rao Gajraj Singh.
5. Shrimati Dr. Parkash Kaur.

LIBRARY COMMITTEE.

Mr. Speaker: Under Rule 172-A of the Rules of Procedure of the Punjab Legislative Assembly, I have nominated the following Members as Members of the Library Committee to advise upon matters connected with the Members' Library:—

1. Dewan Jagdish Chandra, ... *Chairman.*
2. Shri Rala Ram.
3. Shri Mool Chand Jain.
4. Sardar Ajmer Singh.
5. Thakore Balwant Singh.
6. Shrimati Shanno Devi.

HOUSE COMMITTEE

Mr. Speaker: Under Rule 173 of the Rules of Procedure of the Punjab Legislative Assembly, I have nominated the following Members as Members of the House Committee to consider and advise upon matters connected with the comfort and convenience of Members of the Assembly:—

1. Sardar Gurdial Singh Dhillon, ...*Ex-Officio Chairman*.
2. Shri Kedar Nath Saigal.
3. Sardar Achhar Singh Chhina.
4. Khan Abdul Ghaffar Khan.
5. Shrimati Shanno Devi.

Now the Secretary will place some papers on the table of the House.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Secretary: Sir, I beg to lay on the Table a statement showing the Bills which were passed by the Punjab State Legislature during its Autumn Session and assented to by the Governor or the President.

Statement showing the Bills which were passed by the Punjab State Legislature during its autumn session, 1953, and assented to by the Governor or the President.

(1) The Sikh Gurdwaras (Third Amendment) Bill, 1953.

(2) The Punjab Village Common Lands (Regulation) Bill, 1953.

(3) The Punjab Livestock Improvement Bill, 1953.

(4) The Sikh Gurdwaras (4th Amendment) Bill, 1953.

(5) The Land Acquisition (Punjab Amendment) Bill, 1953.

(6) The East Punjab Urban Rent Restriction (Amendment) Bill, 1953.

(7) The Punjab Agricultural Produce Markets (Validation) Bill, 1953.

(8) The East Punjab Refugees Rehabilitation (House Building Loans) (Amendment) Bill, 1953.

(9) The Punjab State Aid to Industries (Amendment) Bill, 1953.

(10) The Punjab Minor Canals (Amendment) Bill, 1953.

(11) The Punjab Local Authorities Laws (Exercise of Powers) Bill, 1953.

(12) The Punjab Municipal (Amendment) Bill, 1953.

(13) The Punjab District Boards (Second Amendment) Bill, 1953.

(14) The Punjab Small Towns (Second Amendment) Bill, 1953.

(15) The Punjab Maternity Benefit (Amendment) Bill, 1953.

(16) The Punjab Vaccination Bill, 1953.

[Secretary]

(17) The Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, 1953.

(18) The Sikh Gurdwaras (5th Amendment) Bill, 1953.

(19) The Punjab Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Bill, 1953.

(20) The Punjab Legislative Council Chairman's and Deputy Chairman's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1953.

(21) The East Punjab Ministers' Salaries (Second Amendment) Bill, 1953.

(22) The Punjab Security of Land Tenures (Amendment) Bill, 1953.

(23) The Punjab University (Amendment) Bill, 1953.

(24) The Punjab Land Revenues (Amendment) Bill, 1953.

(25) The Punjab Appropriation (No. 3) Bill, 1953.

(26) The Punjab Sugarcane (Regulation of Purchase and Supply) Bill, 1953.

Chief Minister (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I beg to lay on the Table the additions made by the Governor to Schedules 'B' and 'C' referred to in regulations 5 and 6 respectively of the Punjab and North West Frontier Province, Joint Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, as required by clause (5) of Article 320 of the Constitution.

Sir, I also beg to lay on the Table Ordinances 1 and 2 of 1954, promulgated since the prorogation of the last Session of the Assembly, as required by clause 2(a) of Article 213 of the Constitution.

THE SIKH GURDWARAS (SECOND AMENDMENT) BILL, 1954

Chief Minister (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I introduce the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill.

Chief Minister : Sir, I beg to move—

That the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 1

Sub-Clause (2)

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause (2), of Clause 1, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1
Sub-Clause (1)

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause (1) of Clause 1, stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Chief Minister (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I beg to move—

That the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill, be passed.

The motion was carried.

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों की सेवा में अर्ज़ करना चाहता हूं कि कल, बुद्धवार है और बुद्धवार को ज़ाबते के अनुसार छुट्टी होनी चाहिये परन्तु कल छुट्टी नहीं होगी ; काम किया जायेगा ।

The Assembly then adjourned till 2 p.m. on Wednesday, the 10th March, 1954.

59PSLA—283—15-9-54—CP&S, Pb. Chandigarh.

Punjab Legislative Assembly Debates

10th March, 1954.

16.9.54

VOL. I—NO. 2

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, 10th March, 1954

CHANDIGARH :

Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab

1954

Price : -/7/-

PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY

Wednesday, 10th March 1954.

The Assembly met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital, at 2 p. m. of the clock. Mr. Speaker (Dr. Satyapal) in the chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

BOYCOTT OF PANCHAYAT ELECTIONS IN THE STATE.

*2005. **Sardar Harkishan Singh Surjit :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there have been any cases of complete boycott of Panchayat Elections by the public in the State; if so, in how many cases, where and for what reasons;

(b) whether there have been any cases of boycott of the Panchayat Elections by a section of the candidates; if so, in how many cases, where and for what reasons;

(c) the number of candidates whose nomination papers were rejected due to non-payment of 'Chulha' Tax together with their number and names, district-wise in the State ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) Panchayat Elections were boycotted completely in the following cases :—

	Name of Panchayat		*District*
1.	Fatehpur	..	Hoshiarpur.
2.	Sasoli	..	Do.
3.	Sarchur	..	Gurdaspur.
4.	Rupowali	..	Do.
5.	Wariah	..	Amritsar.
6.	Fakharpur	..	Do.
7.	Mahman	..	Do.
8.	Basti Baba-Khel	..	Jullundur.
9.	Kote Grewal	..	Do.
10.	Harse Manser	..	Hoshiarpur.
11.	Dhun	..	Amritsar.
12.	Gilpan	..	Do.
13.	Narla	..	Do.
14.	Kals'an Khurd	..	Do.
15.	Dalīri	..	Do.
16.	Dal	..	Do.
17.	Wan	..	Do.
18.	Innowal	..	Hoshiarpur.

[Chief Parliamentary Secretary]

In cases of Panchayats from Serial Nos. 1—9, the Panchayats were boycotted for the reason that the voters of certain villages were not satisfied over the grouping of their villages with Panchayats concerned while at Gram Panchayat Harse Manser mentioned at Serial No. 10, no nomination papers are reported to have been received during the time prescribed and no cause of boy cott was reported to the Returning Officer. The village Lambardars are also reported not to have co-operated at all in completing this election. In Panchayat areas mentioned against Serial Nos. 11—17, the residents of the village did not file nomination papers as they did not agree to pay the tax on hearths imposed in the Gram Panchayat areas. In case of Panchyat at Serial No. 18, some persons who were not likely to be elected, dissuaded the voters not to take part in the election, thinking that they might succeed in getting themselves nominated with personal influence. The Deputy Commissioner has, however, ordered re-election in this case.

(b) Panchayat Elections were boycotted by a section of people in the following cases :—

(1) Wariam Khera, District Jullundur.

(2) Nurpur, District Jullundur.

(3) Dhudike, District Ferozepore.

(4) Atta, District Karnal.

In the first two cases the agriculturists who are in a minority boycotted the Panchayat election on finding that their success in the election was uncertain, while in the third case certain section of candidates accused a Polling Officer of propagating in favour of a candidate and left the polling station. In the fourth case three candidates left the polling station as Polling Officer did not concede some of their requests.

(c) This information cannot be supplied as nomination papers were received from the Returning Officers in sealed envelopes by the District Panchayat Officers and the same cannot be opened by the Panchayat Staff under the Gram Panchayat Election Rules, 1953.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤ੍ਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਦ ਬੰਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ?

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : अगर माननीय मैम्बर नोटिस दें तो यह सूचना उन्हें दी जा सकती है ।

RULING OF THE SPEAKER REGARDING STARRED QUESTIONS LEFT OVER ON A PARTICULAR DAY.

Pandit Shri Ram Sharma : On a point of order, Sir. मैं गुज़ारिश करना चाहता हूं कि इस असैम्बली में 16,17 साल से यह तरीका चला आ रहा है कि एक दिन में जितने सवाल ख़त्म हो जायें तो उस दिन की लिस्ट के बाकी के सवालों का जवाब दूसरे रोज़ हाउस में दिया जाता था । मैं आप से पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में नियम कब तबदील किये गये हैं क्योंकि यह मामला हाउस के सामने पेश नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी 15,16 साल से यह देख रहा हूं कि माननीय मैम्बर कभी कांग्रेस के बैंचों पर विराजमान होते हैं और कभी दूसरी तरफ़ । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि

हम ने पार्लियामेंट के नियमों के मुताबिक अपना तर्जे अमल बदल लिया है । अब हमने मेम्बर साहिबान को discretionary powers दे दी हैं कि जिन सवालों का जवाब Floor of the House पर दिया जाना जरूरी समझते हैं उन्हें mark कर दें । इस वक्त हमारे पास दो हजार से ज्यादा सवालों के नोटिस पहुंच चुके हैं । इस लिये अगर हम पुराने तरीके के मुताबिक काम करें तो इन सवालों को खत्म करने में लग भग एक साल लग जायेगा । इन हालात में बाकी के सवालों को लाज़मी तौर पर postpone करना पड़ेगा । ऐसी postponement कोई नई बात नहीं । पहले भी सवाल postpone किये जाते थे ताकि बाकी के मेम्बरों को सवाल पूछने का मौका मिल सके । स्पीकर को यह अधिकार है कि नियमों में तबदीली कर सके । मैंने House of the People के Secretariat से राये ली है और जो दस्तूर वहां रायज है वह यहां भी जारी कर दिया गया है । इसलिये मौजूदा तरीके में कोई तबदीली नहीं की जा सकती ।"

पंडित श्री राम शर्मा—मेरे ख्याल में Rules of Business को हाउस ही पास कर सकता है और इन में अगर कोई तबदीली करनी जरूरी हो तो वह हाउस ही कर सकता है ।

Mr. Speaker : May I ask the Hon. Member to quote the rule according to which the House is only competent to change the Rules? Rules of Business को तबदील करने के सम्बन्ध में जो अधिकार मुझे प्राप्त हैं उन पर माननीय मेम्बर ने नुक्ताचीनी की है । मैं इस सम्बन्ध में Constitution of India के Article 208(2) को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ।

"Until rules are made under Clause (1) the rules of procedure and standing orders in force immediately before the commencement of this Constitution with respect to the Legislature for the corresponding Province shall have effect in relation to the Legislature of the State, subject to such modifications and adaptations as may be made therein by the Speaker of the Legislative Assembly."

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

HUSKING OF PADDY IN THE ZAIL OF NAUSHERA PANUAN, DISTRICT AMRITSAR

***2166. Sardar Sarup Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the list of persons having the necessary machinery to husk paddy in the zail of Naushera Panuan (Kairon), Tehsil Patti, District Amritsar, before 31st August 1950 and between 1st September 1950 and 31st January 1953, respectively;

(b) whether any date was fixed by the Government after which permission for husking paddy on private account could not be granted during the year 1950; if so, what;

(c) (i) whether any applications from any of the persons referred to in part (a) above were received by the Civil Supplies authorities between 1st September 1950 and 31st May 1953 asking for permission to husk paddy on private account ; if so, their list together with their full addresses;

[Sardar Sarup Singh]

(ii) whether any of the applications were rejected; if so, their list and the reasons therefor;

(d) the distance in miles between the villages Keharka and Kairon;

(e) whether any complaint forwarded by Sardar Sujjan Singh Margindpuri, ex-M.L.A., Patti—*vide* his letter No. 254, dated 16th August 1953 (Registered A.D.). was received by him stating that the Civil Supplies authorities had allowed a person to husk the paddy even after the fixed date and had rejected the applications of certain owners of such machines which had been received within the time fixed; if so, whether any enquiry was made in the matter, together with the result of the enquiry so made;

(f) whether during the enquiry, the ex-M.L.A. referred to in part (e) above was called upon to substantiate his complaint; if not, the reasons therefor;

(g) if he would lay a copy of the complaint referred to in part (e) above on the Table?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): (a) The list of persons having machinery to husk paddy in the zail of Naushera Panuan (Kairon), Tehsil Patti, District Amritsar, before 31st August 1950 is given below:—

(i) Shri Babu Ram of Kairon.

(ii) Shri Bay Ram, son of Kirpa Ram of Lauka.

(iii) Shri Pritam Singh for M/s Nathu Ram-Beli Ram of Naushera Panuan.

(iv) Shri Tek Singh of Naushera Punuan.

The list of persons having paddy husking machines in the zail of Naushera Panuan between 1st September 1950 and 31st January 1953 is as under:—

(i) Shri Babu Ram, Village Kairon.

(ii) Shri Atma Singh, son of S. Labh Singh, C/o Harnihal Bhagwan, Kairon.

(iii) Shri Tek Singh of Naushera Panuan.

(iv) M/s Nathu Ram-Beli Ram of Naushera Panuan.

(v) Shri Bay Ram, son of Kirpa Ram, Village Lauka.

(vi) Shri Gurbax Singh, Village Doburji, Tehsil Tarn Taran.

(vii) Shri Inder Singh, son of Bir Singh, Ramgarhia, Village Vijaypur, Post Office Kairon.

(vii) Shri Hazara Singh, son of Khan Singh, Ramgaria, Village Sheron, Tehsil Tarn Taran.

(b) Yes. Instructions were issued in 1950 to the effect that authorisation to husk paddy whether on Government or private account should not be issued to huller type rice machines installed after 31st August 1950.

(c) (i) S. Gurbux Singh of Doburji. S. Inder Singh of Vijayapur and S. Atma Singh of Kairon applied for permission to dehusk paddy on private account.

(i) The applications of S. Gurbux Singh and Inder Singh were rejected on the following grounds:—

(1) The rice husking machines were installed by them after 31st August 1950;

(2) The policy of Government was to allow husking of paddy on private account throughout the year at those centres only which were the headquarters of the food officials. Doburji and Bijaypur were not the headquarters of any food official.

(d) The distance between Kairon and Koharka is only 3½ miles.

(e) Yes. The milling authorisation granted to the person in question was cancelled.

(f) No. The question does not arise.

(g) A *copy of the complaint referred to in part (c) above is enclosed.

It may, however, be stated in this connection that restrictions on the husking of paddy in rural areas have since been removed and the rice *chakkis* in villages can now husk paddy for private consumption of the rural population without any quantitative restriction.

Copy of letter No. 2958-MP-53/5162, dated the 14th June 1953, from D.G.F.S., to (1) S. Pritam Singh, Village and Post Office Kairon, Tehsil Patti, District Amritsar, and (2) S. Balwant Singh, Village Koharka, Post Office Kairon, Tehsil Patti, District Amritsar.

Subject.—**Husking of paddy on private account.**

Reference your letter No. Nil, dated Nil, on the subject noted above.

2. It is regretted that authorisation for private husking of paddy cannot be allowed in respect of hullers set up after 31st August 1950.

No. 2958-MP-53/5162-A, dated the 14th June 1953

A copy is forwarded, for information, to the D.O.C.S. and R., Amritsar.

By order,

MPO/DGFS

*Kept in the Library.

[Chief Parliamentary Secretary]

Copy of Memo. No. 171-MP-53/909, dated the 10th January 1953, from DGFS to the DOCS and R, Amritsar.

Subject.—Installation of a new huller for husking of paddy on private account

Reference enclosed copy of a letter No. Nil, dated 18th December 1952, from S. Atma Singh of Kairon, on the subject noted above.

2. S. Atma Singh should be permitted to instal a new huller at Kairon for husking paddy of paddy growing cultivators on private account.

No. 171-MP-53/910, dated Simla, the 10th January 1953.

A copy is forwarded, for information and necessary action, to S. Amta Singh, son of Sobha Singh, c/o Harmhal Bhawan, Kairon, Tehsil Patti, District Amritsar.

By order,

MPO/DGFS

OBSERVATIONS MADE BY THE SPEAKER

अध्यक्ष महोदय : मैं आप की थोड़ें समय के लिये indulgence चाहता हूं। यहां पर यह प्रश्न किया गया है कि यह rule हाउस की मनज़ूरी के बगैर क्यों बदला गया है। मैंने इस बारे मे गुज़ारिश की है कि मैंने यह rule पार्लियामेंट के इस सम्बन्ध में rule के अनुसार बनाया है। अब सवाल यह है कि rule बनाने का इख्तियार किस को है? पंडित श्री राम शर्मा ने एतराज़ किया है कि हाउस के सामने यह तबदीली नहीं लाई गई। इस सम्बन्ध में मैंने Constitution का provision पढ़ कर सुनाया है। उस provision के अनुसार जब तक हाउस तमाम rules को नये सिरे से बनाने पर आमादा न हो तब तक जो मौजूदा rules हैं उन पर ही कारबंद होना होगा और उनमें जो तबदीली स्पीकर वक्तन फवक्तन करना चाहे, वह कर सकता है। हमारे rules में भी यह Provision है "All matters not specifically provided shall be regulated in such manner as the Speaker may from time to time direct." यानी अगर कोई ऐसा मौका आए तो जो फ़ैसला स्पीकर दे उस पर कारबंद होना चाहिये। इसलिये मैंने यह rules बदलने में अपने हकूक से तजावज़ नहीं किया है। इस के अलावा यह rules वैसे भी काबलेकदर हैं क्योंकि हमारी पार्लिआमेंट में इस पर अमल किया जाता है।

पंडित श्री राम शर्मा : आपने मुझ से rule पूछा था। वह rule यह है—

"A House of the Legislature of a State may make rules for regulating, subject to the provisions of the Constitution, its procedure and the conduct of its business."

Mr. Speaker : I will be very happy if the hon. Member or the Leader of the House brings forward a Bill in the House for modifying the existing Rules or for framing new Rules of Procedure. But as long as such a Bill is not introduced in and accepted by the House, I am fully competent to frame the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly.

पंडित श्री राम शर्मा : मैंने एतराज नहीं किया था। मैंने तो केवल दरियाफ्त किया था।

अध्यक्ष महोदय : अगर माननीय मेम्बर की तसल्ली नहीं हुई तो और पूछ लें ।

मुख्य मंत्री : On a point of order, Sir, यह एक साफ़ चीज़ है कि जब स्पीकर साहिब एक ruling दे दें तो उस पर discussion नहीं होती । तरीका यह है कि यदि किसी मेम्बर को कोई मज़ीद रौशनी की ज़रूरत हो तो वह स्पीकर साहिब के कमरे में जा कर वह रौशनी हासिल कर सकता है बजाए इस के कि सारे House का समय इस तरह से लिया जाए ।

पंडित श्री राम शर्मा : श्रीमान् जी, मैं protest करता हूं.......

अध्यक्ष महोदय : Order, order हमने Gazette में भी यह change publish कर दी है । 28 अक्तूबर 1952 के बाद से इस rule को बदला गया है । यह Gazette में publish हो चुका है । इस के अलावा मैं इस बारे में House of the People के Rules of Procedure में से भी पढ़ कर सुना देता हूं । वहां लिखा है—

> "If any question placed on the list of questions for oral answers on any day is not called for answer within the time available for answering questions on that day, the Minister to whom the question is addressed shall forthwith lay upon the Table a written reply to the question and no oral reply shall be required to such question and no supplementary questions shall be asked in respect thereof".

पंडित श्री राम शर्मा : मुख्य मंत्री के कहने का यह मतलब है कि मैं ने आप की ruling को question किया है । मैं ने यह नहीं कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो अभी तक नहीं कहा है । Next question please.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

PANCHAYAT OF VILLAGE BHONDSI, DISTRICT GURGAON.

*2420. **Shri Babu Dayal** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether he is aware of the fact that the Harijans of Village Bhondsi, Tehsil and District Gurgaon, were deprived of their reservation in the Panchayat ;

(b) whether he is also aware that the Harijans referred to in part (a) above informed the District Magistrate in this connection ;

(c) if the answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the action, if any, taken in the matter ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : The required information is being collected and will be supplied to the hon. Member when ready.

श्री बाबू दयाल : क्या चीफ़ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बतायेंगे कि जो enquiry डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने इस बारे में की है, उस पर कोई action लिया गया है ?

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : सरकार election petitions के बारे में कोई action नहीं लेती । इस case में election petition दायर कर दी गई है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह अमर वाक्या नहीं है कि कानून में यह amendment कर दी गई है कि अगर सब हरिजन उम्मीदवारों की दरखास्तें रद्द हो जाएं तो उन की जगह सरकार नामजदगी कर सकती है ?

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : अगर माननीय सदस्य नोटिस दें तो बता सकता हूं ।

सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत : क्या वह दो सीटें जिन के लिये कागज़ रद्द हो गये थे, पुर कर दी गई हैं ?

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : इस के लिये नोटिस की ज़रूरत है ।

श्री चांद राम ग्राहलावत : क्या उस गांव की आबादी इतनी थी कि हरिजनों के लिये seats reserve हो सकती थीं ?

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : इस के लिये नोटिस चाहिये ।

पंडित श्री राम शर्मा : श्रीमान् जी, क्या इस बात के लिये भी नोटिस की ज़रूरत है कि आया law में इस बात की provision है या नहीं ?

Chief Parliamentary Secretary : I am not expected to remember rules and regulations.

DRAMATIC PERFORMANCES.

*2464. **Sardar Nidhan Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state the number of times, for which dramatic performances were prohibited in each district of the State under Section 3 of Dramatic Performance Act, IX of 1876, between the period January 1952 to September 1953, together with the reasons therefor in each case ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : The Statement below gives the names of districts, the number of performances banned from January 1952 to September 1953 and the reasons thereof :—

District	Number of performances banned	Reasons
Hoshiarpur ..	6 ..	The dramas were reported to be of scandalous and defamatory nature.
Jullundur ..	29 ..	The dramas were reported to be of a scandalous and defamatory nature likely to excite feelings of disaffection towards Government and were also likely to deprave and corrupt the audience.

District	Number of performances banned	Reasons
Ferozepore ..	6 ..	Performances were likely to incite the unsophisticated villagers attending the performance to imbibe feelings of disaffection towards Government and to have recourse to violence.
Amritsar ..	19 ..	Dramas were likely to be of scandalous and defamatory nature and likely to excite feelings of disaffection towards Government and were also likely to deprave and corrupt the audience and to excite them to commit breach of peace.

ਸਰਦਾਰ ਚਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀ ਹੈ?

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : जिन ड्रामों पर डिप्टी कमिशनर ने पाबन्दी लगाई है उन को देखा नहीं बल्कि पढ़ा गया था ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि कुछ राजनैतिक कारणों से इन ड्रामों को बन्द किया गया है या कि क्राइम (crime) की बढ़ौती को रोकने के लिये इन को बन्द किया जाता है ?

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : यह जवाब में बता दिया गया है कि किन वजूहात के कारण इन को बंद किया गया है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या इन्हीं वजूहात पर इन ड्रामों को रोका गया है या कि कुछ और भी हैं ?

ਸਰਦਾਰ ਚਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੇਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਸਕੈਂਡਲ' ਵਰਤਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਦਸੀਆਂ ਜਾਣ ।

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : यह तो पहले ही उत्तर में बता दिया गया है ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ban ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਹਨ ?

चीफ़ पार्लीमेंट्री सैक्रेटरी : मैंने अर्ज़ की है कि वे ड्रामे पढ़े गये थे और देखे नहीं गये थे। पढ़ कर उन को बैन (ban) किया गया है। अगर माननीय सदस्य और नोटिस दें तो वे तमाम वजूहात भी बताई जा सकती हैं।

ਸਰਦਾਰ ਚਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਛੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿਓ।

चीफ़ पार्लीमेंट्री सैक्रेटरी : छः ड्रामों पर बैन (ban) नहीं लगा बल्कि छः बार बैन (ban) लगाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उन ड्रामों को ज़िला के डिप्टी कमिश्नर ने बैन (ban) किया है। इन्होंने नहीं किया।

पंडित श्री राम शर्मा : आपने फ़रमाया है कि डिप्टी कमिश्नर ने बैन (ban) किया है तो क्या इस का अर्थ यह है कि जो कुछ डिप्टी कमिश्नर करता है उस की ज़िम्मेदारी सरकार पर नहीं आती ?

DEMANDS OF PANCHES AND SARPANCHES OF DISTRICT AMRITSAR.

*2486. **Sardar Darshan Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the elected Panches and Sarpanches of District Amritsar submitted any signed memorandum to him at the time of their oath taking ceremony; if so, the number of signatories to the aforesaid memorandum together with the demands put forward in the memorandum ;

(b) a copy of the aforesaid memorandum be laid on the Table ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) and (b) Yes. The number of alleged signatories to the memorandum is 652. A copy of the memorandum which contains the demands put forward by the panches is laid on the Table of the House.

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭੀਮ ਸੈਨ ਜੀ ਸੱਚਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,

ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਬਨਾਣ ਤੇ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ:—

ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹਨ

(੧) ਮਾਮਲੇ ਦਾ ੨੫% ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

(੨) ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੇ ਬਗੈਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।

(੩) ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਰਨ ।

(੪) ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ।

HABITUAL CRIMINALS IN THE STATE

***2570. Shri Rala Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of adults of the erstwhile criminal tribes who have been registered as habitual criminals during the year 1953-54 in the State ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : It is regretted that the answer to the question is not ready. The information is being collected and will be supplied as soon as it is ready.

CASES OF MURDER IN THE STATE.

***2666. Shri Teg Ram** : Will the Chief Minister be pleased to State —

(a) the total number of cases of murder registered in the State during the years 1952 and 1953, respectively ;

(b) the total number of tenants in the State who were murdered during the period mentioned in part (a) above together with the total number of persons who were arrested in this connection, the number of those who were found guilty and the punishments awarded to each one of them ;

(c) the total number of cases referred to in part (b) above in which the guilt of the accused could not be established and the accused were acquitted ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : Information in respect of this question is being collected and will be supplied to the hon. Member shortly.

ADMINISTRATIVE STATUS OF CHANDIGARH

***2684. Shri Ram Kishan** : Will the Minister for Public Works be pleased to state :—

(a) the administrative status of Simla and Chandigarh Capital respectively after the Government has shifted to the Chandigarh Capital;

(b) whether any Municipality or Municipal Corporation is intended to be constituted at Chandigarh ; if so, when, together with its status and the mode in which it will be constituted ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) It is not understood as to what is the administrative status of a town.

(b) The matter has not yet been considered.

श्री राम किशन : प्रश्न यह है कि—

Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the administrative status of Simla and Chandigarh Capital, respectively, after the Government has shifted to the Chandigarh Capital.

मंत्री : यह समझ नहीं आई कि administrative से क्या मुराद है ।

पंडित श्री राम शर्मा : इस से मुराद यह है कि क्या चंडीगढ़ ज़िले का या कि तहसील का Headquarter है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे कि चंडीगढ़ के ज़िले का या किसी पंचायत का Headquarter बनाया जायगा ?

मुख्य मंत्री : इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि चंडीगढ़ नक्शे के हिसाब से अम्बाला ज़िला और खरड़ तहसील में वाक्या है । शिमला एक ज़िला है । चंडीगढ शिमला ज़िला में नहीं आता ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह शिमला ज़िला का भी हैडक्वार्टर था और सरकार का भी उसी लिहाज़ से चंडीगढ़ का क्या status होगा ? क्या यह ज़िला का या तहसील का या गवर्नमेंट का हैडक्वार्टर होगा ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲਾ ਦਾ ਹੈਡਕਵਾਰਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ।

पंडित श्री राम शर्मा : मेरी अर्ज़ यह है कि क्या इस का status म्युनिसिपल कमेटी का होगा या notified area का ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੇਰੇ ਗ਼ੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस मामले का निर्णय कितने समय में होगा ?

ANTI-DACOIT OPERATIONS IN ROHTAK DISTRICT.

***2692. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the names of the Villages in Rohtak District where anti-dacoit operations were conducted by the police during the months of January and February 1954;

(b) the method adopted by the Police to collect the villagers at one place, make house searches, administer public beating to badmashes suspected of harbouring the proclaimed offenders and others for teaching lessons to whole villages together with the names and number of Lambardars; Panches and others given public beating by the police in this connection ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : The required information is given below —

(a) Chhara, Dhekora, Rewari Khera, Mandothi, Matan, Kharar Bhaproda, Asodha, Bhupania, Sohity, Baliana, Kehrawar, Chuliana

Garhi Sampla, Papli, Dataur, Pakasman, Mor-Kheri, Barota, Chhachhrana, Mundlana, Garhwal, Bhawar, Randhana, Lath, Bhainswal Kalan. Kahni, Anwali, Rabra, Jagsi, Dhamar, Kaloi,Jassia, Bhagotipur, Khadwali,Makroli Kalan, Makroli Khurd, Chamarian,Dobh, Goddi-Kheri, Balamba,Girawar, Nidhana, Mokhra, Kansala, Pipli, Roorki, Sehri, Ridhau,Goohna, Jharot, Pinana, Bohla, Katwal, Gehwana, Rehmand, Juan, Kaloi, Kheri Daiya, Bhatgaon, Salimsar-Majra, Gohna, Tihar, Rattan-Garh, Garhi Haqiqat Jaji, Moohana, Rohat, Badhana, Kakroi, Jharot, Jharoti, Mehlana Lohrara, Mehipur, Bayanpur, Murthal, Machri, Khizarpur Jat, Barwasn, Shahzadpur, Klorad, Tharu, Jwahri, Hassanpur, Deolu, Reoli, Shahjahanpur, Narthan, Nakloi, Garhi Brahminan, Raipur, Shadipur, Fazalpur, Kalupur, Bhagan, Rajpura, Sheikupura, Purkhas Ganaur, Juan, Rehmana, Butana, Jafarabad, Pinana, Garhi Rajlu, Sandal Kalan, Chutia Auliya, Bajana, Dudna, Boohla, Pugthala, Chulkana, Kami Khizarpur, Ahir, Bhagan, Bindruli, Kanwali, Nahra, Nahari, Nathupur, Shafiabad, Rai. Kheora, Jhundpur, Desawarpur, Sehali Aurangabad, Jatheri, Akharpur, Barota, Jatauli, Thana Khurd, Kelon and Jagdishpur.

(b) The method adopted by the Police was to conduct searches in the houses of suspected harbourers and then to collect all the villagers and advise them not to harbour proclaimed offenders but to give information about their presence to the Police. No public or private beatings were given to anyone, badmashes or others.

पंडित श्री राम शर्मा : ज़िला रोहतक के गांवों की फहरिस्त जो कि पालियामेंट्री सैक्रेटरी ने पढ़ कर सुनाई है और जिन में पुलिस ने यह कार्रवाई की है, उन के ख्याल के मुताबिक वहां absconder छुपे हुए थे या कि उन का कुछ और भी विचार था ?

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : उन का यह विचार था और उन को शक था कि वहां पर डाकू आते जाते थे। इस विचार से कि वहां पर डाकू और उन के साथी मिल सकेंगे पुलिस ने यह कार्रवाई की थी।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं दर्याफत कर सकता हूं कि जिस विचार से पुलिस ने घेरा डाला था उस में उन को कोई कामयाबी हुई ?

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे फ़ाज़िल दोस्त को इस बात का इल्म है कि इस सिलसिला में हमें जो इत्तलाह मिली है और उस इत्तलाह के मुताबिक हमने जो कार्रवाई की उस में हमें काफ़ी कामयाबी हासिल हुई जिस के नतीजे के तौर पर काफ़ी आदमी पकड़े गये और उन्हें मारा भी गया। फिर उस के बाद जो harbourers थे वे भी निकले। ये तभी बरामद हुए जब हम ने उस सूचना के मुताबिक कार्रवाई की।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि जिन गांवों के नाम सूची में दिये गये हैं और जहां पर कि बदमाशों को पकड़ा गया है, वहां पर ऐसी सरकारी कार्रवाई के नतीजे के तौर पर कोई माल भी बरामद हुआ या नहीं ? अगर हुआ तो कहां कहां ?

मुख्य मंत्री : मेरे फ़ाजिल दोस्त अच्छी तरह जानते हैं कि जो जवाब यहां पर दिये जाते हैं वह केवल उन्हीं सवालों के मुतअल्लिक होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। वैसे तो हमारे पास हर ज़िला की हर जगह की एक एक दिन की पूरी रिपोर्ट होती है। अगर मेरे फ़ाजिल दोस्त

[मुख्य मंत्री]

इस के मुतअल्लिक कोई सवाल पूछें तो उस का जवाब दिया जा सकता है। वैसे जो सवाल उन्होंने पूछा है उस का उन के असली सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं—यह उस में से arise ही नहीं होता।

ORNAMENTS AND CASH TAKEN FROM RABRAN, POLICE STATION GOHANA.

*2693. **Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) the details of ornaments and cash taken possession of by the Police from Village Rabran, Police Station Gohana, District Rohtak ;

(b) whether he is aware of the fact that the police forcibly snatched some ornaments from the persons of women folk of the said village ; and also got removed some ornaments from their persons with the help of goldsmiths ;

(c) the name of the Subedar pensioner publicly beaten by the police and the reasons therefor ;

(d) the provision of law and the rules under which all this was done by the Police ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : Information in respect of this question is being collected and will be supplied to the member shortly.

पंडित श्री राम शर्मा : कब तक यह जवाब मिल जाएगा ?

पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : जलदी ही।

RECOVERY OF UNLICENSED FIRE-ARMS IN ROHTAK DISTRICT.

*2694. **Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of unlicensed fire-arms (i) revolvers. (ii) guns and (iii) others recovered by the police since 1st January 1954 in Rohtak District ;

(b) the number of persons arrested for possessing the said unlicensed fire-arms ;

(c) the number of fire-arms recovered without effecting any arrest by asking the villagers to give up arms without disclosing their identity since 1st January 1954 ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a)(i) 9 foreign-made revolvers.

(ii) 39 guns out of which 3 are foreign-made.

(iii) 7 foreign-made rifles, 2 F. M. Pistols, 43 country-made pistols, 4 barrels of guns and one C.M. cannon were recovered from 1st January 1954.

(b) 93 persons.

(c) 297 fire-arms were recovered by the 'Bran-pie' method. Of these 280 were country-made and 17 foreign-made.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन लोगों के पास unlicensed arms थे उन्हें यह यकीन नहीं दिलाया गया था कि अगर वे हथियार वापिस कर देंगे तो उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ? क्या यह सच नहीं कि रोहतक ज़िले में जिन ऐसे लोगों ने हथियार इकट्ठे कर के गवर्नमेंट को दे दिये थे उनके अब नाम वगैरा मुकदमा चलाने के लिये पूछे जा रहे हैं ?

मुख्य मंत्री : मैं अपने काबिल दोसत को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस सिलसिला में हमने ठीक वही तरीका इख्तियार किया है जो कि कोई advocate किया करता है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं गवर्नमेंट से पूछ सकता हूं कि क्या इस मौके पर ऐसा तरीका इख्तियार नहीं किया गया जो कि अभी तक किसी ने भी न किया हो ?

मुख्य मंत्री : जी नहीं ।

APPLICATION OF SARDAR GURCHARAN SINGH SENSRA OF VILLAGE SENSRA, DISTRICT AMRITSAR FOR RESTORATION OF HIS PROPERTY

*2705. **Sardar Harkishan Singh Surjit :** Will the Chief Minister be pleased to state whether he is aware of the fact that S. Gurcharan Singh Sensra of Village Sensra, Police Station Majitha, District Amritsar applied in the month of June 1952, for the restoration of his property confiscated by the British Government for political reasons ; if so, the action, if any, taken by the Government on the said application ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : Yes. He applied in June 1952. The matter is under consideration.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਦੇਰ ਲਗ ਜਾਏਗੀ ।

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : उम्मीद है कि उसके कलेम पर जल्दी ही फ़ैसला हो जाएगा । चूंकि इस सिलसिला में सभी कागज़ात वगैरा मंगवाने हैं इसलिये कुछ देर तो ज़रूर ही लग जाएगी ।

RESTORATION OF CONFISCATED PROPERTIES IN THE STATE.

*2706. **Sardar Harkishan Singh Surjit :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government has restored the properties confiscated by the British Government for political reasons to persons concerned or their heirs; if so, the number of persons together with their names whose properties have so far been restored by the Government ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : Yes. Two—Pt. Munshi Ram, son of Pt. Paras Ram, of District Ferozepore and S. Ram Singh, son of S. Hakim Singh of District Hoshiarpur.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਬਾਕੀ ਦਿਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਫ਼ਰਰਜ਼ (political sufferers) ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਬਤੀ ਕੀ ਹੈ ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

चीफ़ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी : जब आप बाकियों के बारे में सवाल पूछेंगे तो आप को मुनासिब जवाब दे दिया जाएगा ।

मुख्य मंत्री : नहीं, नहीं । मेरे फ़ाजिल दोस्त ने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है । यह सवाल जो पूछा गया था इस में तो पंजाब के सभी ज़िलों के विषय में पूछा गया है केवल होशियारपुर के ज़िला के मुतअल्लिक नहीं । मैं अपने काबिल दोस्त को यकीन दिलाता हूं कि इस का पूरा जवाब आप को दे दिया जाएगा ।

RESTORATION OF CONFISCATED IMMOVABLE PROPERTIES.

*2784. **Shri Mani Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the policy that has been laid down by the State Government regarding the restoration of the immovable properties which had been confiscated by the British Government for political activities of the displaced persons ;

(b) whether any representation from Sardar Kartar Singh, son of Sardar Arjan Singh of Village Mari Kambo Ki, Tehsil Patti, District Amritsar for the restoration of his deceased father's land forwarded by Sardar Sajjan Singh Margindpuri, Ex M.L.A., Patti, under his office letter No. 15, dated 25th January 1954 was received by the Chief Secretaty to Government, Punjab, Chandigarh on 27th January 1954 (*vide* postal acknowledgement receipt) ; if so, the diary No. of the receipt register wherein the said representation was entered ;

(c) whether any verification has been made or is proposed to be made from the Pakistan Government regarding the circumstances which led to the confiscation of the property under reference ; if made, with what results ;

(d) the decision, if any, arrived at by the Government in the matter ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) The question of actual restoration of lands or properties, situated in Panjab (Pakistan), which were confiscated under the British regime, on account of the national activities of the owners, who are now displaced persons, does not arise. But any person from Punjab (Pakistan), who suffered confiscation of property or other losses during recognised national movements, could put up his claim to Government for considration up to 31st December 1953.

(b) Yes ; the diary number in the receipt register is 1624-WG-54./973(c).

(c) Yes. A report from the Punjab (Pakistan) Government is awaited.

(d) Does not arise.

पंडित श्री राम शर्मा : जिन पोलिटीकल सफरर्ज़ (political sufferers) की अचल सम्पत्ति जो कि गवरनमेंट ने confiscate कर ली थी और जो अब पाकिस्तान में रह गई है—उस के वापस देने या उन के बदले उन्हे कोई मुआवज़ा देने के बारे में सरकार ने कोई नीति बनाई है या नहीं ?

मुख्य मंत्री : यह सवाल कैसे पैदा होता है ?

पंडित श्री राम शर्मा : मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों की ज़मीनें पूर्वी पंजाब में confiscate की गई थीं, उन को वापस करने के बारे में तो विचार हो रहा है लेकिन उन लोगों को जिन की ज़मीनें पश्चिमी पंजाब में confiscate की गई थीं और वे लोग अब पार्टीशन के बाद हिन्दोस्तान में आ गये हैं उन्हें compensate करने के बारे में क्या नीति इख्तियार की है ?

मुख्य मंत्री : इस के लिये आप नोटिस दे दें, जवाब दिया जायेगा ।

RELIEF TO POLITICAL SUFFERERS.

*2785. **Shri Mani Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the decision, if any, arrived at by the Government regarding the giving of relief to the political sufferers in ;

(1) case referred to in letter No. 4806-WG-51/2382, dated 20th June 1951, Letter No. 6198-WG-52/6175, dated 10th September 1952; Letter No. 6092-WG-53/9-ASR, dated 14th August 1953, No. 1515-WG-52/673, dated 26th March 1952, from the Chief Secretary to Government, Punjab, to Shri Daulat Ram and Sardar Sajjan Singh Margindpuri of Patti, District Amritsar ;

(2) case referred to in Chief Secretary to Government, Punjab's letter No. 6092-WG-53/97-ASR, dated 21st September 1953 ;

(3) case referred to in part (d) (ii) of Starred Assembly Question No. 963 printed in the list of questions dated 21st October 1952; in Starred Assembly Question No. 974 printed in the list of questions dated 25th October 1952, in Unstarred Assembly Question No. 245 printed in the list of questions dated 25th November 1952 and Starred Assembly Question No. 2165 printed in the list dated 10th October 1953 ;

(b) the date since when each of the cases referred to above has been pending ;

(c) the steps, that are being taken by Government for the early disposal of the cases referred to above ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) :

(a) (1), (2), and (3) and (c) } The cases are under consideration and the decision will be communicated as soon as possible.

[Chief Parliamentry Secretary]

(b) (1) 16th May 1951.. Sathi Daulat Ram.

(2) 9th August 1953.. S. Sajjan Singh Margindpuri.

(3) 11th August 1952.. S. Baghel Singh.

(4) 16th January 1953.. Shri Salig Ram.

FILING OF APPEAL IN WRIT NO. 75/1952 IN THE SUPREME COURT OF INDIA.

***2802. Sardar Achhar Singh Chhina :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Punjab Government filed any appeal in the Supreme Court of India against the High Court judgement delivered in Civil Writ No. 75 of 1952 in the case of Sardar Gurmukh Singh Chawla, Pleader, Ambala City versus Shri R. P. Kapur, I.C.S., if not, the action, if any, Government now proposed to take in the matter.

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : No. It is not intended to take any action.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या कारण है कि सरकार इस पर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती ?

Chief Minister : Because the Government does not consider it worth while taking any action in that particular case.

पंडित श्री राम शर्मा : किंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि किन कारणों या किन बातों की बिना पर गवर्नमेंट इस को नज़रअंदाज़ करना चाहती है ?

Mr. Speaker : The Government is not expected to give explanation for filing or not filing an appeal. This is its own affair.

पंडित श्री राम शर्मा : यह तो ठीक है। लेकिन स्पीकर साहिब, मैं यह दरियाफ़त करना चाहता हूं कि किन वजूहात की बिना पर सरकार इस मामले पर कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझती ?

Mr. Speaker : This question does not arise out of the main question.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਬਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ (action) ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ? ਜਦ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗ਼ਲਤ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ (action) ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ?

मुख्य मंत्री : अगर आप इस केस में interested हैं तो मैं आप की इत्तलाह के लिये एक दो बातें कह देता हूं। यह जो केस ज़ेरेबहस है इस पर जो judgement हाईकोर्ट (High Court) ने दी उस सिलसिले में गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया था कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को move किया जाए। इस बारे में उसे

इजाज़त दे दी गई थी। लेकिन कुछ वक्त की वजह से या कुछ दूसरी बातों की वजह से उस वक्त के अन्दर अन्दर ऐसा न किया जा सका ((*interruptions*)।

सिंचाई मंत्री : हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को move करने की इजाज़त नहीं दी थी।

मुख्य मंत्री—हां, नहीं दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को move करने का ज़रूर ख्याल था। लेकिन यह कुछ टाईम बार्ड (time barred) सा हो गया। फिर उस सिलसिले में Solicitor General की राए ली गई। लेकिन उस राए के नतीजे के तौर पर क्या हुआ ? यह मैं इस वक्त नहीं बता सकता क्योंकि यहां ऐसा करने से contempt of court का इलज़ाम लगाया जा सकता है। तो भी गवर्नमेंण्ट ने पहले अपनी पूरी तरह से यह तसल्ली की कि उन remarks की बिना पर कहां तक और क्या कार्रवाई हो सकती है। तब कहीं जाकर जो मुनासिब कार्रवाई थी, वह की गई।

ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜੇਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ action ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ High Court ਦੇ remarks ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मुख्य मंत्री फरमाते हैं कि High Court के खिलाफ़ कुछ कहा नहीं जा सकता और इस केस में गवर्नमेंट ने Legal Opinion, Solicitor-General से हासिल की है।

श्री देव राज सेठी : हकूमत High Court की finding को नज़रअन्दाज़ करने में कहां तक हकबजानब है ?

Mr. Speaker : I do not think it is a relevant question, Government has not ignored the decision of the High Court. But it is not prepared to take any action as it does not consider this matter urgent.

श्री देव राज सेठी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस फ़ैसले के पेशेनज़र कि High Court ने उस वकील साहिब को बिल्कुल बेकसूर माना है और कि अफ़सर मुतअल्लिका का फ़ैसला बेबुनियाद था और कि अफ़सर मुतअल्लिका के खिलाफ High Court का फैसला आखरी और कतई होना चाहिए, क्या हकूमत उस अफ़सर मुतअलिका के खिलाफ़ कोई action ले चुकी है या लेना चाहती है ?

मुख्य मंत्री : जहां तक हाई कोर्ट (High Court) के फ़ैसले का ताल्लुक है हकूमत उस को इज़्ज़त और एहत्राम की निगाह से देखती है। इस सारे केस का फैसला करते वक्त तमाम मुतअल्लिका अमूर को सामने रख कर ही जो गवर्नमेंट की अन्दरूनी बातें हैं उस के मुतअल्लिक फैसला किया है।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि इस मामले में गवर्नमेंट की considered policy क्या है कि जब कभी गवर्नमेंट के बड़े या छोटे अफ़सरों के खिलाफ़....,...

Mr. Speaker : It does not follow.

Pandit Shri Ram Sharma : Sir, it does follow,

Mr. Speaker : No. It does not. This is my ruling. (Pandit Shri Ram Sharma then collected his papers and rose to leave the House).

Pandit Shri Ram Sharma : You are treating us like children.

Mr. Speaker : Unless you withdraw these words now, you will have to withdraw them when you come back. I don't claim you as a child.

Pandit Shri Ram Sharma : I withdraw the words but I want to submit....

Mr. Speaker : I hope you are now a sober man.

पंडित श्री राम शर्मा : मैंने इसी लिये considered policy का word इस्तेमाल किया है कि क्या गवर्नमेंट ऐसे मामलों के मुतअल्लिक कोई considered policy तय कर चुकी है कि नहीं कि ऐसे फ़ैसलों की सूरत में गवर्नमेंट ने अफ़सर मुतअल्लिका के खिलाफ़ क्या action लेना है क्योंकि यह देखा गया है कि गवर्नमेंट ऐसे मामलों में कोई परवाह नहीं करती ?

Mr. Speaker : I again rule it out of order. It is not a supplementary arising out of the main question. You can ask any supplementary question provided it is a reasonable one.

श्री देव राज सेठी : क्या यह बात ठीक है कि हकूमत ने हाई कोर्ट के फ़ैसला के मुकाबला में Solicitor-General की राये को फ़ौक़ीयत दी और उस के अनुसार अपना फ़ैसला किया है ?

मुख्य मंत्री : यह किस ने कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है that it is for them to take executive action in the matter.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या इस केस का फ़ैसला, हाईकोर्ट के फैसले में दिये गये adverse remarks को मद्दे नज़र रखते हुए किया गया है या नहीं। क्या आप बतायेंगे कि वह remarks क्या हैं ?

Chief Minister : The judgement of a Court is a public property जो public property हो वह लाज़मी तौर पर गवर्नमेंट के नोटिस में आई होगी और उसे देख कर ही उस ने वह फैसला किया होगा जो उस की समझ में आया होगा ।

ਸਰਦਾਰ ਚਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ findings ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ action ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ enquiry ਕੀਤੀ ਹੈ ?

मुख्य मंत्री : इस का जवाब वही है जो मैंने पहले दिया है कि ऐसे जो remarks होते हैं उन पर गवर्नमेंट पूरे तौर पर विचार करती है । दर असल सारे हालात पर गौर करने के बाद ही उसे कोई action लेना होता है ।

पंडित श्री राम शर्मा : इस मामले में वह कौनसी बातें थीं जिन का गवर्नमेंट ने नोटिस लिया है ? हम देखते हैं कि हाई कोर्ट के adverse remarks के बावजूद भी इस मामले के बारे में कुछ नहीं किया गया । मैं पूछता हूं कि वह कौन सी other considerations थीं जिन की बिना पर गवर्नमेंट ने कोई action नहीं लिया ?

मुख्य मंत्री : केस (case) की तमाम मुतग्रल्लिका considerations और जुमला हालात को मद्देनजर रखते हुए उस के मुतग्रल्लिक अच्छी तरह गौर किया जाता है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या इस केस के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में उन considerations का कोई भी हिस्सा है ? Even one hundredth or one-tenth part जो........

Mr. Speaker : No please. Disallowed.

'CHOS' IN DISTRICT HOSHIARPUR.

***2301. Sardar Chanan Singh Dhut** : Will the Minister for Development be pleased to state :—

(a) the total area of cultivable land rendered unfit for cultivation by 'chos' in Hoshiarpur District during the year 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 and 1953, respectively ;

(b) the total area of land under cultivation in Hoshiarpur District during the years 1952 and 1953 ;

(c) the total crops destroyed by Chos in Hoshiarpur District during the years 1952 and 1953 ;

(d) the action, if any, taken by the Government to control the Chos ;

(e) whether it is a fact the Government is collecting land revenue even for those lands which have been rendered unfit for cultivation by the 'Chos' ; if so, the amount recoverable and the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon :

(a)

Year.	*Area rendered unfit.*
1948-49	Nil.
1949-50	Nil.
1950-51	Nil.
1951-52	95 acres.
1952-53	20 acres.

(b)

	Area under cultivation.
1951-52	710,250 acres.
1952-53	761,214 acres.

[Minister for Development]

(c)

		Area destroyed.
1952	..	7 acres.
1953	..	226 acres.

(d) (1) 2,49,893 acres were closed under sections 4 and 5 of the Land Preservation Act while 76,958 acres were closed under section 38 of the Indian Forest Act.

(2) Sowing and plantings have been carried over 31,336 acres up to the 31st March 1953.

(3) Check dams, contour trenching and gully plugging works have been carried over in an area of 5,118 acres.

(4) An area of 11,823 acres has been terraced and watted and contour ridged.

(5) Actual cho training work has been carried out over a length of 643 miles.

(e) *First Part.* No.

Second part. Does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ । ਕੀ ਨਸਰਾਲਾ ਚੋ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁਟਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ?

मंत्री—226 एकड़ बताई थी ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 42,300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

मंत्री : कोई मालिया नहीं लिया जाता । जमीन का रकबा जानने के लिये फ्रैश (fresh) नोटिस दें ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ (action) ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । (ਹਾਸਾ)

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 226 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨੀ ਘਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਕਿਉਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ?

मंत्री—226 एकड़ ज़मीन पर फ़सल खराब हुई है। आप का सवाल................

अध्यक्ष महोदय : There is legal distinction between the land which has been rendered unfit for cultivation and that of which the crops have been damaged.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਠੀਕ ਹੈ, ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਡ ਗਈ !

मंत्री : ज़मीन तो कभी भी उड़ती नहीं ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਉਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਚੋ ਵੇਖਆ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਇਹ ਦਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਚੋ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

मंत्री : बात यूं है कि होशियारपुर में चोओं की वजह से लोगों को तकलीफ़ हुई है। सरकार इस बारे में अपनी पालिसी का सर्वे (survey) कर रही है। उसने वहां पर इसी काम के लिये २० ओवरसीयर और ६ ऐस. डी. ओ. लगा रखे हैं.............

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਨਣਾਂ ਚਾਂਹੁੰਦੇ ।

मंत्री : सरकार इस तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश कर रही है।

DESTRUCTION OF CROPS IN DISTRICT GURGAON BY WILD COWS.

***2324. Shri Babu Dayal** : Will the Mintster for Development be pleased to state whether he is aware of the fact that thousands of wild cows are destroying the crops in villages in District Gurgaon ; if so, the action, if any, Government intends proposing for its prevention ?

Sardar Pratap Singh Kairon : Yes. There are about 100 wi'd cows near the villages of Dharuhera, Chelar and Jhabwa in Rewari Tehsil and 125 wild cows in Bhora Kalan, Bhondsi and Sohna Circles in Gurgaon Tehsil. An effort to domesticate these wild cows was made in the past, but the scheme proved failure as it was found very difficult to catch them and tame them.

श्री बाबू दयाल : मंत्री महोदय ने ग़लत नम्बर दिया है। गौओं की गिनती का अनुमान 200 और 250 का है ।

मंत्री : इस की पड़ताल की जायेगी। अगर ऐसा हुआ तो इस संख्या को ठीक कर लिया जाएगा ।

श्री बाबू दयाल : क्या सरकार ने इन की रोक थाम के लिये कोई यत्न किया है ?

मंत्री : जी हां, कर रही है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यत्न किये जा रहे हैं ?

मंत्री : सरकार उन को पकड़ने की कोशिश कर रही है जिस के बाद उन को डोमैस्टीकेट (domesticate) किया जायगा ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पहली स्कीम क्यों असफल हुई थी और अब दूसरी स्कीम को सफल बनाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

मुख्य मंत्री : मेरे फाज़िल दोस्त जानते हैं कि प्रोबलम (Problem) क्या है । स्थिति यह है कि बहुत सी नाकारा गाएं जंगली हो गई हैं और काबू में नहीं रहतीं । इन को काबू करने का तरीका यही है कि एक तारों से घिरा हुआ हलका बनाया जाय और इन जंगली गौओं को उस के अन्दर रखा जाए । वरना यह गौएं तब तक काबू में नहीं रहेंगी जब तक यह पूरी तरह domesticate नहीं कर ली जातीं । कुछ लोग यह कहते हैं कि इन गौओं का दूसरे जंगली जानवरों की तरह खातमा कर दिया जाए लेकिन ऐसा काम मैम्बरान पसन्द नहीं करते । इसलिये यही किया जा सकता है कि इन गौओं को तारों के हलके में बन्द रखा जाए ।

DISPARITY IN LAND REVENUE.

*2428. **Shri Babu Dayal** : Will the Minister for Development be pleased to state whether the disparity in land revenue in villages of Bawal Sub-Tehsil was brought to his notice when he paid a visit to Gurgaon, if so, the action, if any, that has been taken in the matter ?

Sardar Partap Singh Kairon :

First part. Yes.

Second part. The matter is receiving the attention of Government.

ANIMALS KILLED BY LEOPARDS.

*2599. **Shri Jagat Ram Bhardwaj** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that during the last six months, 12 heads of cattle in Village Dandoh, 8 in Rehmanpur 2 in Takhni and 4 in Patiari, Thana Hariana, District Hoshiarpur were killed by the leopards;

(b) whether he is further aware of the fact that many more heads of cattle have been killed in other villages in the Kandi illaqa;

(c) the steps, so far taken by the Government to save the cattle from the growing menace of leopards in the said District ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : The requisite information is being collected and will be supplied to the member when ready.

NOMINATIONS TO THE NEW MARKET COMMITTEE, BHIWANI.

***2651. Shri Ram Kumar Bidhat** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the caste and place of residence of each of the nine members (excluding the Tehsildar) recently nominated by the Government to the New Market Committee of Bhiwani to represent the agriculturists;

(b) the total number of villages which are to have their representatives on the said Market Committee ?

Sardar Partap Singh Kairon:

	Name of member	*Profession*	*Name of village*
(a) 1.	Shri Ranjit Singh	Agriculture	Village Bhiwani.
2.	Shri Jai Lal	Do	Village Miran.
3.	Shri Jug Lal	Do	Village Rodhan.
4.	Shri Sagar Singh	Do.	Village Deosar.
5.	Shri Randhir Singh	Do	Village Kherkhari Makhwan.
6.	Shri Nanu Singh	Do	Village Kherkhari Sohan.
7.	Shri Akhe Ram	Do	Village Kherkhari Makhwan
8.	Shri Darya Singh	Do	Village Deva Bas.
9.	Shri Arjun Singh	Do	Kharkheri.

(b) 74 Villages.

REPRESENTATION OF HARIJANS AND DISPLACED PERSONS ON THE MARKET COMMITTEE, BHIWANI.

***2652. Shri Ram Kumar Bidhat** : Will the Minister for Development be pleased to state whether he is aware of the fact that the District Board of Hissar did not recommend any person from among Harijans or displaced persons to represent the agriculturists on the Market Committee of Bhiwani if so the steps, if any, proposed to be taken by the Government to safeguard the interests of these sections of the rural population of Bhiwani Tehsil ?

Sardar Partap Singh Kairon : Government is considering to revise Market Committee rules and this thing will be given due consideration then.

MARCH OF RAJASTHAN DESERT INTO THIS STATE

***2683. Shri Ram Kishan** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the steps, if any taken or intended to be taken by the Government to check the march of the Rajasthan Desert into this State :

(b) the area of culturable and unculturable land of this State that has so far come within the grip of the desert since 15th August 1947 ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) A scheme for Rs. 1,02,700 has been submitted to Government of India. As soon as this scheme is sanctioned the work will be undertaken.

(b) Not known.

APPOINTMENT OF HARIJAN LAMBARDARS IN THE STATE.

***2881. Shri Mool Chand Jain** : Will the Minister for Development be pleased to State whether the Government has postponed their decision to appoint Harijan Lambardars; if not, whether any Harijan Lambardar has been appointed so far in the State and if none, the reason for the delay and the time likely to be taken for implementing this decision ?

Sardar Partap Singh Kairon : *First Part.* No.

Second Part. No, No Harijan Lambardar has been appointed so far.

Third Part II. Rules are being amended and the decision will be implemented shortly.

EXPENDITURE ON THE RESIDENCES OF AMERICAN EXPERTS.

***2308. Sardar Achhar Singh Chhina** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state the total expenditure incurred by the Government on the furnishing and fitting of the residences of American Experts employed on the Bhakra and Nangal Projects ?

Chaudhri Lahri Singh : The total expenditure incurred up-to-date is Rs. 1,44,413.

CLEARANCE OF SILT FROM A MOGA.

***2485. Sardar Darshan Singh** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state —

(a) whether it is a fact that Executive Engineer, Majitha Division (Canals), Amritsar, engaged local peasants for the clearance of silt from a moga from R.D.O. 4858 to R.D. 10 during the year 1952 ; if so the total payments made by the Government to the peasants for this work ;

(b) whether it is a fact that silt from the above moga was again cleared during the same year through two contractors; if so, the time which elapsed between the two clearances, together with the payment made to the contractors ?

Chaudhari Lahri Singh : (a) The question does not specify even the name of the Distributary. Silt clearance of mogas is never done at Government expense.

(b) Does not arise.

TUBE-WELLS FOR JAGADHRI-KARNAL PROJECT AREA.

*2560. **Shri Dev Raj Sethi** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total number of Tube-wells, sanctioned by the Government for the Jagadhri-Karnal Project area and the date of their sanction ;

(b) the total number of tubewells which began functioning as on 31st December 1953 ;

(c) the total cost involved and the estimate of their working expenses ;

(d) the total quantity in cusecs of water being pumped by these tube-wells ;

(e) the manner in which the water thus pumped is being used ;

(f) whether Garden Colonies in Rohtak District will also get some quantity of water out of this project ; if so when and its quantity ?

Chaudhri Lahri Singh—

(a) 256. The estimate was sanctioned on 26th September 1949.

(b) 100.

(c) The estimate of cost amounts to Rs. 1,41,79,200. The annual working expenses will be :—

(i) Rs. 26,84,000 with electricity from Thermal Plant.

(ii) Rs. 20,79,000 with electricity from Nangal Project.

(d) Up to 31st December 1953, about 200 cusecs discharge was being pumped.

(e) It is being used to supplement supplies of Western Jumna Canal for extension of Irrigation and thereby converting Bhalaut Branch into a perennial channel. It is also proposed to convert Sundar Branch into perennial channel with effect from 1st April 1954.

(f) Gardens on Sundar and Bhalaut Branches will get supplies according to rules in force on Western Jumna Canal.

INSTALLATION OF TRIAL BORING TUBE-WELLS IN THE STATE.

*2562. **Shri Dev Raj Sethi** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state —

(a) the total number of trial boring tube-wells sanctioned for this State by the Government of India ;

(b) the list of places selected for such trial borings ;

(c) the names of stations where such trial boring operations have been carried out together with the results thereof ;

(d) the dates when the said schemes were sanctioned and the dates when they were implemented ?

Chaudhri Lahri Singh :

(a) 46 exploratory tube-wells have been allotted to this state by Goverement of India.

(b) A list showing the proposed sites for these 46 exploratory tube-wells is given below. But it is being revised further.

(c) The work has not yet been started, therefore, the quesion of reporting results does no arise.

(d) Proposal was made by the Government of India during 1952 and Punjab Government agreed to pay the cost of successfully developed and equipped exploratory tube-wells. These tube-wells will be installed after the sites have been inspected by the Technical working Party of Government of India.

List showing exploratory tube-wells to be installed in Punjab State—

Name of District	Name of Tehsil	Name of Village for which tube-wells are proposed	No. of Tube-wells	REMARKS
Gurdaspur ..	Batala ..	Dera Baba Nanak, Kalanaur, Aliwal	3	
Hoshiarpur ..	Garhshankar..	Samundra		
	Dasuya ..	Miani	3	
	Hoshiarpur ..	Bassi Daulat Khan		
Jullundur ..	Nakodar ..	Shahkot, Balanda 2		
	Phillaur ..	Talwan, Lisara 2	5	
	Nawashar ..	Rahon 1		
Ludhiana ..	Ludhiana ..	Nurpur 1	2	
	Jagraon ..	Aliwal 1		
Ambala ..	Ambala ..	Shahpur, Kesri, Dhun Barara 4	6	
		Kharar, Majri 2		

Name of District	Name of Tehsil	Name of Village for which tube-wells are proposed	No. of Tube-wells	REMARKS
PEPSU ..		Banur ..	1	
Karnal ..	Thanesar ..	Thel, Shahbad ..	2	
Hissar ..	Hansi ..	Hansi 1	7	
	Bhiwani ..	Sungarpur, Thunpa, Bhiwani Pahari, Siwani, Loharu 6		
Rohtak ..	Rohtak ..	Rohtak 1	5	
	Gohana ..	Gohana 1		
	Jhajjar ..	Nahar, Bahadurgarh Salahwas 3		
Gurgaon ..	Rewari ..	Jhabwa 1	3	
		Rajpur 1		
		Nangal Pathani 1		
	Nuh ..	Jaurasi 1	2	
		Rehna 1		
	Ferozepore Jhirka	Merora 1	2	
		Ghagas 1		
	Gurgaon ..	Shamaspur 1 Between Chandu and Bhurara 1	2	
	Ballabgarh ..	Manjhauli 1	3	
		Dhoj 1		
	Palwal ..	Amarpur 1		
		Grand Total ..	46	

PAYMENT OF COMPENSATION TO THE OWNERS OF SHAH NAHAR.

***2571. Shri Rala Ram :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether he is aware of the fact that more than half the compensation due from the Government to the erstwhile owners of Shah Nahar remains unpaid in spite of their persistent demand for payment ; if so, the reasons therefor ?

Chaudhri Lahri Singh: Major part of the compensation due to owners on account of Shah Nahar Canal has been paid ; but some of it is still

[Minister for Irrigation]
outstanding as the rates have not been accepted by some owners who have gone to the court for settlement. The cases have not yet been decided by the court.

CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETIES IN HOSHIARPUR DISTRICT.

*2572. **Shri Rala Ram** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether it is a fact that a number of Co-operative Credit societies in Hoshiarpur district is dwindling for lack of credit facilities due to the blocking up of their deposits in the Central Co-operative Bank, Lahore ; if so, the steps Government proposes to take to salvage these Societies ?

Chaudhri Lahri Singh : No amount of any credit Society of Hoshiarpur district is blocked up in the Central Co-operative Bank, Lahore. The deposits of Co-operative Central institution of Hoshiarpur was blocked up in Provincial Co-operative Bank Ltd., Lahore but the Punjab Provincial Co-operative Bank Ltd., Jullundur, is giving relief to the affected Central institutions of their pool and the Government of India have also recently sanctioned a loan of Rs. 35 lacs for financial assistance to such institutions in the State.

CONSTRUCTION OF CANAL COLONY AT ABOHAR.

*2656. **Shri Teg Ram** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state —

(a) the total expenditure likely to be incurred by the Government on establishing the Headquarter of the Abohar Canal Division at Abohar ;

(b) the total area of land acquired by the Government and also the price paid for the construction of the Canal Colony at Abohar ;

(c) the total number of wagons of coal so far purchased for purposes of building the said Canal Colony and from whom these were purchased:

(d) the names of the kiln owners to whom the Coal referred to in part (c) has been supplied and the rate at which it had been supplied ;

(e) the total number of kiln owners from whom tenders for the supply of bricks were invited ;

(f) the total number of tenders received and the rates thereof together with the names of the kiln owners whose tenders were accepted and also the rates and the kinds of bricks that were agreed to be accepted ;

(g) the total number of timber merchants who submitted tenders for the supply of timber and the rates that were quoted by each one of them ;

(h) the date and the name of the officer who opened these tenders and the rate at which these tenders were accepted and also the kind of timbers agreed to be accepted from the contractors ;

(i) whether the timber merchant to whom the contract was given has supplied the kind of timber contracted to be supplied together with the name of the officer who is the final authority for determining whether the right kind of timber has been supplied ;

(j) the total weight of iron, the rate thereof and the name of the merchant from whom it has been purchased for the construction of said canal colony ;

(k) the names of the contractors to whom contracts for the construction of building in the said Canal Colony have been given ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Rs. 4,54,000

(b) 17.8 acres, at a cost of Rs. 13,306

This includes the cost of land compulsorily acquired, which is yet to be paid.

(c) Total quantity of slack coal received is 573 tons for purposes of buildings in Abohar Canal Colony. The coal received from M/s. Chawla and Co, and E.I.R. and B.N. Joint Colliery as allotted by the Procurement and Focal Officer, Punjab Irrigation Secretariat, on placing half yearly indent by the Superintending Engineer.

(d) The coal has been supplied to :—

Shri Nihal Chand Narang and Shri Murari Lal. The coal has been supplied at the rate of :—

Bricks	Tiles
22 tons per lac. bricks.	32 tons per lac

(e) The tenders for supply of bricks were invited by giving wide publicity through all the Executive Engineers and Sub-Divisional Officers of Sirhind Canal Circle.

(f) Three tenders were received. The names of tenderers and the rates offered by each are :—

Name of contractor	*Pacca bricks*	*III class bricks*	*Bats*	*Tiles*
Nihal Chand	Rs. 20 per thousand	Rs. 13 per thousand	Rs. 10 per cent cft	Rs. 43 per thousand
Murari Lal	Rs. 19 per thousand	Rs. 15 per thousand	Rs. 12 per cent cft	Rs. 42-8-0 per thousand
Bhup Chand	Rs. 22 per thousand	Rs 15 per thousand	Rs. 10 per cft	Rs. 50 per thousand

[Minister for Irrigation]

The tenders of Shri Nihal Chand and Shri Murari Lal were accepted at the following lowest rates.

Pacca Bricks	*III class bricks*	*Bats*	*Tiles*
Rs. 19 per thousand	Rs. 13 per thousand	10 per cent cft	42-8-0 per thousand

(g) The following timber merchants submitted tenders for the supply of timber at the rates noted against each:—

1. Kartar Chand Bhalla and Sons of Doraha .. Rs. 5-9-6 per cft.
2. Tara Chand for Nihal Chand and Tara Chand .. Rs. 7-6-0 per cft.
3. Nayar Brothers. .. Rs. 5-14-3 per cft.

(h) The tenders were opened on 13th December 1953 at 3 p.m. by the Executive Engineer, Abohar Division. The lowest tender of Kartar Chand Bhalla and Sons was accepted by the Superintending Engineer, Sirhind Canal Circle. The kind of timber is Deodar.

(i) The S.D.O., Gobindgarh is the final authority for determining whether the right kind of timber has been supplied. The S.D.O. went to Timber Depot for selecting the timber and marking it. The part supply has been received and part is yet awaited.

(j) The total weight of iron required for Canal Colony, Abohar, roughly works out to 125 tons. This is allotted by the Procurement and Focal Officer, Punjab Irrigation and purchased through the registered stockists. Part of the steel has arrived and part is yet to arrive. The steel of various categories is supplied by the Stockists at controlled rates fixed by the Government.

(k) The tenders for construction of buildings in the Canal Colony, Abohar, were invited. Six contractors tendered, the rates tendered were high and exorbitant, as compared with the sanctioned schedule of rates, so these tenders were rejected and the Sub-Divisional Officer, Gobindgarh, was asked to have the work done from any contractor, who may be willing to do this work, at sanctioned schedule of rates.

ALLOTMENT OF LAND IN VILLAGE GHARYALA—DISTRICT AMRITSAR.

***2167. Sardar Sarup Singh:** Will the Finance Minister be pleased to state —

(a) whether any area was made available for allotment in village Gharyala, Tehsil Patti, District Amritsar, as a result of a report by the rechecking staff during the year 1953, if so, its total :

(b) (i) whether there were any temporary allottees of the aforesaid village whose review applications during the year 1951 were accepted by D.G.R., Jullundur and who were ordered to be restored to this village but in respect of whom the orders of the D.G.R. were not impelmented upto 30th June 1953, if so, the list of such allottees ;

(ii) the date when these applications were accepted ;

(iii) the area to which each of them was entitled ;

(iv) the reasons, if any, for not implementing the orders of D.G.R., Jullundur ;

(c) whether any applications from any of the temporary allottees referred to in part (b) (i) above were received by the Revenue Officers of Patti Tehsil for the allotment of this available area if so, their list ;

(d) whether the persons referred to in part (c) above have been allotted or are proposed to be allotted any area out of the area referred to in part (a) above, if so, to what extent ; if not, the reasons therefor ;

(e) (i) the list of the persons to whom this area has been allotted or is proposed to be allotted ;

(ii) the area to which each of them is entitled;

(iii) the reasons for allotment in each case ;

(iv) the provision of law under which they have been given or are proposed to be given preference over the temporary allottees referred to in part (b) (i) above.

(f) whether the allotment of this area had been made under Section (9) (c) of Chapter IV, page 84 of the Land Resettlement Manual, if not the reasons therefor ?

Sardar Ujjal Singh :

(a) No area was made available for allotment in this village.

(b) (i) to (iv). It is not possible to collect this information without knowing the full particulars of the persons whose review-applications were accepted by D.G.R.

(c) The following persons submitted their applications for allotment of area alleged to have become available for allotment—

1. Kehar Singh, son of Mangal Singh,
2. Roor Singh, son of Bhola Singh,
3. Virsa Singh, son of Kundan Singh,
4. Amrao Singh, son of Sulakhan Singh,
5. Gurdip Singh, son of Dharam Singh,
6. Dharam Singh, son of Ajit Singh

(d) As stated in reply to part (a) above no area was found available and as such none of them has been allotted land in village Gharyala,

(e) (i) to (iv). In view of the reply to part (d) above the question does not arise.

(f) The question does not arise.

WORKING OF WEIGHTS AND MEASURES ACT

*2682. **Shri Ram Kishan**: Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) whether the Government is aware of the resentment amongst the traders and shopkeepers against the working of the Weights and Measures Act in the State ;

(b) whether the Government has received any resolution passed by the Executive of the Punjab Pradesh Congress Committee in this connection, if so, the action, if any, the Government intends to take in regard thereto ?

Sardar Ujjal Singh : (a) No. Individual complaints received from Associations, traders and shopkeepers are investigated and remedies made, where possible.

(b) No.

ALLOTMENT OF UPPER PORTION OF HOUSE NO. 6637 IN AMBALA CITY.

*2803. **Sardar Achhar Singh Chhina**. Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the date when the District Rent Officer. Ambala, allotted the upper portion of House No. 6637, Ambala City to Sardar Gurmukh Singh Chawla, Pleader, Ambala city;

(b) the date when Sardar Gurmukh Singh Chawla was put in possession of the portion of the said house;

(c) the name of the person who was occupying the upper portion of the house in the intervening period and with whose authority.

(d) the action taken by the authorities concerned after the High Court Judgment in Civil Writ No. 75 of 1952, to evict the person occupying the portion of the said house ?

Sardar Ujjal Singh: (a) 2nd April 1951.

(b) 6th February 1954.

(c) Shri Sri Ram Mago remained in illegal occupation of this portion till 29th December 1953 when it was sealed. During the intervening period Shri Mago twice secured the allotment of this portion from Deputy Custodian, Ambala, but the same was later on cancelled by higher authorities.

(d) There was no direction in the High Court judgment in Civil Writ Petition No. 75 of 1952 to evict the person occupying the upper portion of the house. The Hon'ble Judges only directed the Deputy Custodian, Ambala to deal with the question of the allotment of the upper portion to Shri Gurmukh Singh Chawla according to law.

ROAD PERMITS FOR BUSES

*2556. **Sardar Partap Singh** (Ratta Khera). Will the Minister for Education be pleased to state the total number of road permits for buses granted by the Government during the year 1953, together with the number of these permits granted to Harijans and to Harijan Co-operative Societies or Companies ?

Shri Jagat Narain: No fresh stage carriage permits were granted during the year 1953.

REPRESENTATION AGAINST IMPOSITION OF PROFESSIONAL TAX IN LUDHIANA DISTRICT.

*2487. **Sardar Darshan Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state (i) whether 2,500 residents of 80 villages of District Ludhiana in a signed petition to the Chief Minister sent on 18th April 1953 represented against the imposition of Professional Tax and (ii) if so, the action, if any, taken by the Government thereon.

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (i) No.

(ii) Does not arise.

RETRENCHMENT OF WORKERS IN AMRITSAR.

*2218. **Sardar Chanan Singh Dhut :** Will the Minister for Labour be pleased to state —

(a) whether he is aware of the fact that even after the Punjab High Court declared the appointment of the Industrial Tribunal as void, retrenchment of Industrial workers in Amritsar has taken place, if so —

(i) the number of workers retrenched so far,

(ii) the number of factories which as a result of retrenchment have closed down, and

(iii) the number of strikes of the workers,

b) whether it is a fact that the workers have demanded the restoration of the Industrial Tribunal, if so, the action, if any, taken by the Government in this behalf?

Chaudhri Sundar Singh: (a) Yes.

(i) Exact figures not available.

(ii) Nil. Two factories, however, closed down due to trade reasons.

(iii) 14.

(b) Yes. The Industrial Tribunal was restored by Government. Also a Second Tribunal has been set up at Amritsar to cope with increased work.

OBSERVATION MADE BY THE SPEAKER.

अध्यक्ष महोदय : इस से पहले कि आप राज्यपाल महोदय के भाषण पर बहस शुरु करें मेरी दो एक गुज़ारिशें हैं जिन को आप, उम्मीद है, ध्यान में रखेंगे।

एक तो यह है कि इस ऐड्रेस पर जो तक़ारीर आप फ़रमायें उनमें गवर्नर साहिब की personality का ज़िक्र न करें। उन्होंने जो ऐड्रेस दिया है वह निजी तौर पर नहीं दिया। इसलिये आप साहिबान में से जो भी तकारीर फ़रमाना चाहते हैं या जिन ख्यालात का इज़हार करना चाहते हैं, वह इस बात को सामने रख कर ऐसा कर सकते हैं।

दूसरी गुज़ारिश यह है कि कृपा करके अपनी तकरीर को शानदार अलफाज़ में बयान कीजिए। आप को अपनी ज़िम्मेदारी का ख्याल रखना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह छोटी छोटी बातें करना आप की शान के शायां नहीं।

तीसरी गुज़ारिश यह है कि आप सबर और शान्ति से मुकर्रिर की तकरीर को सुनें। उस को टोकना अच्छी बात नहीं। आप को भी मौका मिलेगा जबकि आप उस तकरीर की जो वह करें ज़ोरदार अलफ़ाज़ में तरदीद कर सकते हैं। इसलिये मुकर्रिर की तकरीर के दौरान में किसी तरह के remark करना या टोकना अच्छा नहीं होगा।

मैं उम्मीद करता हूं कि आप तकरीर करते समय इन बातों को ध्यान में रखेंगे।

TRANSACTION OF GOVERNMENT BUSINESS ON THURSDAY, THE 11TH MARCH 1954.

Chief Minister (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I beg to move :—

> That Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government Business transacted on Thursday, the 11th March 1954.

Mr. Speaker : Motion moved :

> That Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government Business transacted on Thursday, the 11th March 1954.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ (ਨਕੋਦਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ motion ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਕਿ Private Business ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਇਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਵੀਰਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਵੋ, ਬਾਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੇ ਪੈਣ। ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੁਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ rush through ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਏ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਕੱਰਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ।

ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਲਬੋਤੇ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਪੁਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ।

ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ (rules) ਵਿਚ ਅਤੇ (constitution) ਵਿਚ ਇਹ provide ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ Private Business ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਅਜੇਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਸੋ, ਜੇਕਰ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਨੀਯਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸਲਈ ਇਹ ਗਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ rush through ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ Leader of the House ਅਗੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ । ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖੱ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ motion ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ।

श्री श्री चंद (बहादुरगढ़)—स्पीकर साहिब ! मैं चीफ़ मनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उन्हें इस बात को मामूल नहीं बना लेना चाहिये कि हर बार प्रस्ताव पेश कर दिया जाये कि non-official day को सरकार लेना चाहती है । गवर्नमेंट को अपना काम किसी खास हद के अन्दर करना चाहियें । जैसा कि आम तौर पर दूसरी असैम्बलियों में होता है । यह बात सभी जानते हैं कि यहां पर opposition के मैंबरों की तादाद इतनी नहीं जिसे ज़्यादा कहा जा सके । दूसरे मायनों में हम इतनी गिनती में नहीं कि उन की मरज़ी के खिलाफ़ उन्हें कार्यवाही करने पर मजबूर कर सकें । लेकिन हरेक असैंबली, हरेक पार्लियामेंट का तरीका और दसतूर होता है कि वह opposition के साथ अच्छा treatment करें । कहीं भी ऐसा नहीं होता कि opposition की परवाह न की जाये । अगर हमारी कम गिनती को देख कर यह ख्याल कर लिया जाये कि opposition

[श्री श्री चन्द]

की परवाह कीये बग़ैर सब बातें की जा सकती हैं तो यह अलग बात है । मगर ऐसा करने से यह असैम्बली farce बन कर रह जायेगी। हां अगर rules की परवाह न करते हुए वीरवार को ज़रूर ही official day बनाना मकसूद है तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि सरकार को चाहिये कि वे opposition के मैंबरों से मिल कर सलाह कर लिया करें। ऐसा करने से मामला बखूबी सुलझ सकता है।

पिछले सैशन में पहले यह कहा गया कि आप को non-official day की बजाए कोई और दिन दिया जायेगा। मगर हुआ क्या? वीरवार का दिन ले लिया गया लेकिन ग़ैर-सरकारी काम के लिये कोई दिन निश्चित न किया गया और प्रोग्राम बदल दिया गया। मैं गुज़ारिश करूंगा कि non-official day मेम्बरों का right है।

फिर श्रीमान् जी! पहले हफ्ते में एक दिन ऐसा होता था जब कि असैंबली की बैठक नहीं हुआ करती थी। मगर अब वह छुट्टी भी उड़ा दी गई है।

(आवाजें—छुट्टी बहाल कर दी गई है)

फिर, श्रीमान् जी, वीरवार के दिन resolution और ग़ैर-सरकारी बिलों पर बहस होनी होती है। इस लिये मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि non-official day को सरकारी काम नहीं किया जाना चाहिये। और House के leader को यह motion वापस ले लेनी चाहिये।

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब ! यह तजवीज़ जो हमारे मुख्य मंत्री जी ने हाउस के सामने रखी है वह एक मामूल ही बन गया है। मैंने 17-18 वर्ष तक अपने सूबे में अंग्रेज़ों के वक्त की नकली Democracy को देखा है और आजकल की असली Democracy को भी देख रहा हूं। मैं महसूस करता हूं कि यह गवर्नमेंट 98 बल्कि 99 फी सदी rules पर पाबन्द नहीं रहती। और इस तरह दिन बदिन ग़ैर-ज़िम्मेदार होती जाती है। अगर rules में यह provision रखा गया है कि वीरवार को non-official business transact किया जायेगा तो सरकार या majority party यह क्यों समझती है कि इस उसूल की खिलाफ़वर्ज़ी की जाये शायद यह डरती है कि अगर non-official day रखा गया तो कहीं कोई मुसीबत न खड़ी हो जाये। श्रीमान् जी ! मैं समझता हूं कि opposition को confidence में ले कर ही real Democracy कायम की जा सकती है वरना यह धींगा मुश्ती और Dictatorship बन कर रह जाती है। मुझे अफ़सोस है कि इस सूबे में Democracy का मज़ाक हो रहा है। हमारी constitution तो दिल्ली में तैयार हो गई लेकिन यहां उस की spirit का भी गला दबाया जा रहा है। असैम्बली के Rules में तो रख दिया गया है कि हफ्ते में एक दिन मेम्बर साहिबान को बिल और resolutions सभा के सामने पेश करने का मौका दिया जाये। मगर हम क्या देखते हैं? सारे महीने में एक भी दिन ग़ैर-सरकारी काम के लिये नहीं रखा गया। इस तरह से non-official day को official day बना कर rules का मज़ाक (face) उड़ाया जा रहा है। हमारे मुलक की दूसरी स्टेट

असेम्बलियों के अन्दर ऐसा कहीं नहीं होता। और यह सरकार की शान के शायां नहीं कि वह ग़ैर-सरकारी दिन को सरकारी काम के लिये इस्तेमाल करे।

मैं गुज़ारिश करूंगा कि बार बार Rule 23 को suspend करके उस का फ़ायदा उठाना मुनासिब नहीं। यह तो rules की असली spirit को बिगाड़ना है। मगर यह अफ़सोस की बात है कि ऐसा करना सरकार का वतीरा ही बन गया है। मैं अर्ज़ करता हूं कि सरकार रूल्ज़ को काफ़ी रौंद चुकी है। अब वह इन को मुआफ़ कर दे या फिर जिस रूल के मातहत ग़ैर-सरकारी काम के लिये दिन रखा गया है उसे सिरे से ही उड़ा दे ताकि दुनिया को आप की डेमोक्रेसी की असलियत मालूम हो जाए। मैं इस रोज़ २ की धींगा मुश्ती के खिलाफ़ protest करता हूं।

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ (ਡੇਹਲੋਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ motion ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਰਜੰਟ ਮੈਟਰ (urgent matter) ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ opposition ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਖੋਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹੋ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਲੂਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ T. A. (ਭੱਤਾ) ਬਣਾ ਸਕਣ......

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ।

प्रोफ़ैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : स्पीकर साहिब। आज़ादी मिलने के बाद हमें बड़ी उम्मीद थी कि आपोज़ीशन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएंगी। डेमोक्रेसी (Democracy) चलाने का सब से पहला उसूल यह है कि आपोज़ीशन को confidence में लिया जाए। उसे disarm करने का यही एक तरीका है। लेकिन यहां उस को disarm करने की बजाए Rules को सस्पेंड (suspend) करके उसे और भी arm किया जा रहा है। मैं अर्ज़ करता हूं कि जिस डेमोक्रेसी (Democracy) में आपोज़ीशन की न सुनी जाए और जहां पूरी तवज्जुह से काम करने वाली आपोज़ीशन न हो उस body politic को सेहतमन्द नहीं कहा जा सकता। इसलिये यह ज़रूरी है कि आपोज़ीशन को अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाये, उस की बात को सुना जाए और प्राईवेट काम के लिये जो दिन निश्चित किया गया है उस को न छीना जाए।

मुख्य मंत्री (श्री भीम सेन सच्चर) : स्पीकर साहिब! मैं मानता हूं कि मैंने बड़ी ग़लती की जो अपनी यह मोशन (motion) पेश करते वक्त कोई तकरीर न की। मैं समझता था कि यह मामला इतना साफ़ और सीधा सादा है कि इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं। जो दोस्त यहां मौजूद हैं, मैं जानता था, कि वे सब रूल और क़ायदे जानते हैं। फिर उन को यह भी मालूम है कि बजट 31 मार्च से पहले पास हो जाना चाहिये। वे इस बात को भी जानते हैं कि बजट पर ग्राम बहस होगी, मांगें पेश होंगीं, फिर बिल ग्रायेगा और उस पर बहस होगी। यह सब कुछ 31 मार्च तक करना है।

मौलवी अब्दुल गनी दार : यह सब बातें सरकार को पहले ही मालूम थीं और इन को देखते हुए असैम्बली का इजलास पहले बुलाया जा सकता था।

मुख्य मंत्री : मेरे दोस्त मौलवी अब्दुल गनी का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि असैम्बली का इजलास पहले बुला कर फ़रवरी में शुरु किया जा सकता था। बेशक यही होना चाहिये था कि नार्मल तरीके में बजट 31 मार्च तक पास हो जाता और ग्रापोज़ीशन का दिन भी न लिया जाता। मगर मेरी अर्ज़ यह है कि 8 तारीख से पहिले हमारे पास इजलास करने के लिये जगह तैयार न थी। हमने पूरी कोशिश की लेकिन यह जगह इस से पहले तैयार न हो सकी। अगर हो जाती तो हमें यह दिन लेने की ज़रूरत न पड़ती। मुझे यह दिन ले कर कोई खुशी नहीं हुई। हमारी नेक नीयती का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 31 मार्च के बाद जो पहला वीरवार आता है वह ग़ैर-सरकारी काम के लिये रख दिया गया है। मैं कह सकता था कि गवर्नर के एड्रेस और बजट की बहस में मेंम्बर साहिबान को सब कुछ कहने का मौका मिल जायेगा। इसलिये ग़ैर-सरकारी दिन की क्या ज़रूरत है लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बस यह सिर्फ़ मजबूरी की बात है। अगर यह दिन न लिया जाए तो बजट का काम 31 मार्च से पहले खत्म न हो सकेगा।

पंडित श्री राम शर्मा : यह मजबूरी पहली बार आई है या पहले भी यही कुछ होता रहा है?

मुख्य मंत्री : आप खुद भी कई बार यह मजबूरी महसूस कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि मई, 1952 से जुलाई, 1953 तक हम ठीक काम करते रहे हैं (हंसी)।

फिर, मेरे दोस्त श्री सिरी चन्द जी ने कहा है कि हम लोग जल्दी जल्दी किस्सा खत्म करना चाहते हैं। मेरी अर्ज़ है कि आप इस इजलास को जितना चाहें लम्बा कर लें। मई के आखिर तक भी ले जायें तो हमें कोई एतराज़ नहीं। इसलिये मैंने यह फैसला किया है और स्पीकर साहिब से दरख्वास्त की है कि जहां तक हो सके शनिश्चर वार को off day रखा जाये। अक्सर वकील साहिबान को भी एक आध दिन अपने काम काज के लिये ज़रूर मिलना चाहिये।

सरदार वज़ीर सिंह : आखिर लोगों को टी. ए. भी तो दिलाना है।

मुख्य मंत्री : टी. ए. का सवाल नहीं। मैंने तो यह फ़ैसला इसलिये किया है कि तमाम लोग लुध्यिाना से अपना काम काज करके तो हर रोज़ आ नहीं सकते। कई वकील मित्र ऐसे हैं जो गुड़गावां, रोहतक और दूर दूर जगहों से आते हैं। हम चाहते हैं कि वे भी अपने काम कर लें। जब हम इस बात को मानते हैं कि एक आदमी वकील होते हुए भी इस सभा का

सदस्य हो सकता है तो हम पर लाज़म आता है कि उन के काम के लिये उन्हें कुछ सहूलतें भी दें। सरकार का यह मतलब नहीं और न ही इस का इरादा है कि सभा के जो इख्तियारात या हकूक हैं उन पर किसी तरह का छापा मारा जाये। और यह तो मैं ने अर्ज़ कर ही दिया है कि पहले हम Session कर ही न सकते थे क्योंकि जगह available न थी। यदि जगह available होती तो हम Session अवश्य पहले करते। मेरा विचार है कि माननीय सदस्य मेरी मारूज़ात को सुनने के बाद मुझ से इतिफ़ाक करेंगे कि वीरवार को official day करार दिया जाना उचित है।

अध्यक्ष महोदय : पेश्तर इस के कि मैं यह सवाल आप की राये के लिये रखूं मैं महसूस करता हूं कि non-official day जो मुकरर है उस की sacredness को कायम रखा जाये। मुख्य मंत्री साहिब ने फ़रमाया है कि अप्रैल में जो वीरवार आयेंगे वे non-official business के लिये ही इस्तेमाल होंगे।

पंडित श्री राम शर्मा : इस का मतलब यह है कि एक ही दिन non-official काम के लिये मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय : चार दिनों में तो एक ही non-official day आ सकता है। दो दिन तो किसी सूरत में नहीं आ सकते। हां इजलास लम्बा हो गया तो ज़्यादा दिन मिल जायेंगे। मैंने सच्चर साहिब से यह कहा है और उन्होंने इस बात को कबूल किया है। हो सकता है कि उन्होंने मेरे कहने पर ही यह शानदार तकरीर की है।

सरदार वज़ीर सिंह : हमारी बात तो वे कभी नहीं मानते।

अध्यक्ष महोदय : आप T. A. के बग़ैर कोई और बात करते भी तो नहीं।

Mr. Speaker : Question is—

That Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business transacted on Thursday, the 11th March 1954.

The Assembly then divided.

Ayes : 63

Noes : 23

The motion was declared carried.

AYES

1. Abhai Singh, Shri.
2. Badlu Ram, Shri.
3. Baloo Ram, Shri.
4. Benarsi Dass Gupta, Shri.
5. Bhim Sen Sachar, Shri.
6. Chand Ram Ahlawat, Shri.
7. Chuni Lal, Shri.
8. Darbara Singh, Sardar.
9. Daulat Ram, Shri.
10. Daulat Ram Sharma, Shri.
11. Devi Lal, Shri.
12. Dev Raj Sethi, Shri.
13. Dharam Vir Vasisht, Shri.

[Mr. Speaker]

14. Gajraj Singh, Rao.
15. Gopi Chand, Shri.
16. Guran Das Hans, Bhagat.
17. Gurbachan Singh, Sardar.
18. Gurbanta Singh, Sardar.
19. Gurdial Singh Dhillon, Sardar.
20. Gurdatt Singh, Shri.
21. Gurmej Singh, Sardar.
22. Hari Ram, Shri.
23. Hari Singh, Sardar.
24. Jagat Narain, Shri.
25. Jagat Ram Bhardwaj, Shri.
26. Jagdish Chander, Shri.
27. Jagdish Chandra, Dewan.
28. Joginder Singh, Sardar.
29. Kanhaya Lal Butail, Shri.
30. Kasturi Lal Goel, Shri.
31. Khem Singh, Sardar.
32. Khushi Ram Gupta, Shri.
33. Lahri Singh, Chaudhri.
34. Lajpat Rai, Shri.
35. Mam Raj, Shri.
36. Mehar Singh, Shri.
37. Mehar Singh, Thakur.
38. Mohan Singh Jathedar, Sardar.
39. Mool Chand Jain, Shri.
40. Nand Lal, Shri.
41. Naranjan Dass Dhiman, Shri.
42. Partap Singh, Bakhshi.
43. Phaggu Ram, Shri.
44. Prabodh Chandra, Shri.
45. Raghuvir Singh, Rai.
46. Rajinder Singh Gyani, Sardar.
47. Rala Ram, Shri.
48. Ram Chandra Comrade, Shri.
49. Ram Dayal Vaid, Shri.
50. Ram Kishan, Shri.
51. Ram Kumar Bidhat, Shri.
52. Ram Sarup, Shri.
53. Rizaq Ram, Shri.
54. Samar Singh, Shri.
55. Sant Ram, Shri.
56. Sarup Singh, Shri.
57. Sher Singh, Professor.
58. Shib Singh, Sardar.
59. Sohan Singh, Sardar.
60. Sundar Singh, Chaudhri.
61. Teg Ram, Shri.
62. Uttam Singh, Sardar.
63. Waryam Singh, Sardar.

NOES.

1. Abdul Ghani Dar, Maulvi.
2. Achhar Singh Chhina, Sardar.
3. Amir Chand Gupta, Shri.
4. Babu Dayal, Shri.

5. Bachan Singh, Sardar.
6. Bhag Singh, Sardar.
7. Chanan Singh Dhut, Sardar.
8. Darshan Singh, Sardar.
9. Gopal Singh, Sardar.
10. Harkishen Singh Surjit, Sardar.
11. Iqbal Singh, Principal.
12. Kedar Nath Saigal, Shri.
13. Mam Chand, Shri.
14. Maru Singh Malik, Shri.
15. Mota Singh Anandpuri, Professor.
16. Mukhtiar Singh, Sardar.
17. Naurang Singh, Sardar.
18. Partap Singh, Sardar (Ratta Khera).
19. Shamsher Singh, Sardar.
20. Shri Ram Sharma, Pandit.
21. Sri Chand, Shri.
22. Wadhawa Ram, Shri.
23. Wazir Singh, Sardar.

PRESENTATION OF SUPPLEMENTARY ESTIMATES (SECOND INSTALMENT), 1953-54.

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (Second Instalment), 1953-54.

PRESENTATION OF ESTIMATES COMMITTEE'S REPORT.

Shri Mool Chand Jain (Sambhalka) : Sir, on behalf of Shri Som Datt Bahri, I beg to present the report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment), 1953-54.

ANNOUNCEMENT BY SECRETARY RE. CERTAIN BILLS.

Secretary : In pursuance of Rule 2(ii) of the Punjab State Legislature (Communications) Rules, 1952, I have to inform the House that the Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill, 1954 (Bill No. 3), the Punjab State Legislature (Prevention of Disqualifications) Bill, 1954 (Bill No. 1) and the Punjab Security of the State (Amendment) Bill, 1954 (Bill No. 2), passed by the Punjab Legislative Council on the 9th of March 1954, have been received.

I also lay copies of the above Bills on the Table of the House.

DISCUSSION ON GOVERNOR'S ADDRESS.

Shri Ram Kishan (Jullundur City, North-West) : Sir, I beg to move—

> That the members of this House assembled in this session are deeply grateful to the Governor for the address he has been pleased to deliver to both the Houses assembled together.

स्पीकर साहिब ! गवर्नर महोदय ने जो भाषण इस हाउस के मेम्बरों के सामने ८ मार्च को दिया था वह पिछले एक साल के राज्य की कारगुजारी और इस राज्य की आयंदा

[श्री राम किशन]

पालीसी जिस की बिना पर हमारी सरकार मुसम्मम इरादे के साथ इस राज्य के कारोबार को चलाना चाहती है और इस राज्य में Economic और Social स्वराज्य की स्थापना करना चाहती है, की ज़िन्दा और जीती जागती तसवीर है। स्पीकर साहिब ! अगर इस ऐड्रैस को अच्छी तरह पढ़ा जाये तो इस से पता चलेगा कि किस तरह पंजाब की सरकार इस देश में आर्थिक स्वराज्य को लाने के लिये poverty, unemployment, under-employment, sickness, ignorance और illiteracy को दूर कर के एक नये राज्य की स्थापना कर के पंजाब के लोगों का standard of living (जीवन स्तर) ऊंचा करना चाहती है। स्पीकर साहिब ! अगर इस की एक एक चीज़ पर जिस की तरफ़ गवर्नर महोदय ने अपने ऐड्रैस में इशारा किया है, विस्तार से कहा जाये तो काफी वक्त लगेगा। इस लिये मैं केवल दो चार बातों की ओर ही हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

जर्मन फ़िलास्फ़र गैटे (Goette) ने एक बार कहा था, "The best Government is that which teaches people to govern themselves" इस असूल के अनुसार पंजाब की सरकार ने पिछले साल पंजाब के 16,455 देहातों में 9,177 village Panchayats कायम करके उन देहातों का प्रबन्ध लोगों के अपने हाथों में दे दिया था। ऐसा करके हमारी सरकार ने स्वतन्त्र भारत के भीतर देहातों में village republics कायम कर दी हैं। इन लोगों के बारे में अगरचे यह कहा जाता है कि वह तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। फिर भी सरकार ने इस बात को नजरन्दाज़ करते हुए और इस असूल को मद्देनज़र रखते हुए कि देहात के लोगों को भी देश के राज्य प्रबन्ध में हिस्सेदार बनना चाहिये, देहातों में पंचायत राज की स्थापना की। आज हम देखते हैं कि इन पंचायतों को गांओं की management करने के सिलसिले में पूरे इख़्तियारात हासल हैं। हिंदुस्तान की तारीख़ में यह पहला मौका नहीं है। अंग्रेज़ी राज से पहले भी यहां पर पंचायती राज मौजूद था और लोग अपने फ़ैसले पंचायती तरीकों से करते थे। पंजाब की सरकार ने अब भी उन्हीं लाइनों पर लोगों के हाथों में ताकत सौंप दी है। सिर्फ़ यही नहीं। परन्तु सारे देश की पंज-साला योजना के समाप्त होने पर जो दूसरी पंज-साला योजना बनाई जानी है, उस में planning का काम नीचे से शुरु किया जाना है। अर्थात् पंचायतों को और इख़्तियार दिये जायेंगे ताकि वे देश का नकशा बदलने में पूरी सहायता दें। देश का नकशा बदलने में पंचायतों ने बहुत बड़ा part play करना है। मुझे यकीन है कि जिस तरह से पंजाब सरकार उन की सहायता कर रही है, उस से वे पूरे तौर पर शासन में सरकार के हिस्सेदार बन रहे हैं। इस तरह से जो village leadership पैदा हो रही है वह नये पंजाब के बनाने में जो हम बनाना चाहते है, एक बहुत बड़ा part play करेगी जिस की तरफ़ गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में भी इशारा किया है। यह पंजाब वह होगा जिस में poverty नहीं होगी, जिस में ignorance नहीं होगी और जिस में standard of living इतना ऊंचा होगा जिस से कि यह सीमा प्रांत एक शानदार नाम पैदा करेगा।

दूसरी गुज़ारिश में सरकार की decentralisation of Administration की नीति के बारे में करना चाहता हूं। यूनान के फ़िलासफ़र थोरियो (Thoreau) ने

कहा है, " That Government is best which governs the least " इस असूल के अनुसार पंजाब की सरकार ने administration को decentralise करने का फ़ैसला किया था । चुनांचि इख़्तियार को अपने हाथ में रखने की बजाए इस सरकार ने उन को नीचे की तरफ मुन्तकिल करने की कोशिश की । पिछले साल इसी सदन में Judiciary को Executive से अलहदा करने के सिलसिले में प्रस्ताव पर बहस हुई थी जिस के द्वारा सारे हाउस ने मांग की थी कि शीघ्र ही भारत के विधान के अनुसार दोनों को अलग किया जाये । पिछले साल इस House में सरकार की तवज्जुह इस बात की ओर दिलाई गई थी कि इस सूबे की Administration में अब भी वह ख़ामियां मौजूद हैं जो अंग्रेज़ी राज में थीं । ब्रिटिश राज्य में एक police state थी जिस का काम Revenue इकट्ठा करना और Law and order कायम करना था । परन्तु आज हम एक welfare state बना रहे हैं । इस में जहां हम ने एक बड़ा part अदा करना है वहां administration ने भी एक ख़ास part अदा करना है । इस सिलसिले में पंजाब सरकार ने administration को decentralize करने का जो फ़ैसला किया है इस पर मैं इसे मुबारकबाद देता हूं । इस का नतीजा क्या होगा ? आज 13 तहसीलों के अन्दर सब-डिवीज़न बनाए जा रहे हैं और 8 सबडिवीज़न पहले मौजूद हैं । इस का नतीजा यह होगा कि लोगों को district headquarters पर आने में जो तकलीफ़ होती थी वह कम होगी और उन के cases पर sympathetic फ़ैसले हुआ करेंगे । पासपोर्ट तथा दूसरी चीज़ों के बारे में उन्हें ठीक इनसाफ़ उन के देहात के नज़दीक ही मिल जाएगा । हम बार बार इस बात पर एतराज़ करते हैं कि एक ही अफ़सर को Judiciary, Executive और Revenue के इख़्तियार क्यों दिये गये हैं । अब यह खामी दूर की जायगी । अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और ऐडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के इख़्तियारात में ज़रूर कुछ फ़र्क पड़ेगा । Sub-Divisional Magistrate केवल Administrative Officer के तौर पर ही काम नहीं करेगा बल्कि वह सही मायनों में Development Officer होगा । Head of the District Authorities भी अब एक Development Officer के तौर पर काम करेगा । आज जिस चीज़ की ज़रूरत है वह यह है कि rulers of the day और जनता के दरमियान एक ख़ास सहयोग होना चाहिये । आज इस Administrative तबदीली से लोगों के सामने यह चीज़ आयेगी कि Rulers govern करने के लिये नहीं बल्कि वह तो serve करने के लिये हैं। मेरा ख़्याल है कि services और लोगों के एक दूसरे के नज़दीक आने से इस सूबे को खुशहाल होने में भारी मदद मिलेगी । ज्यों ज्यों इस देश की development होती जाती है, त्यों त्यों administration में तबदीलियां करने की ज़रूरत अनुभव होती है । इसलिये यह ज़रूरी है कि administration की ख़ामियों को दूर किया जाये । पंजाब की सरकार ने इसलिये फ़ैसला किया है कि उन rules and conduct of business को बदल दिया जाये जो अंग्रेज़ के ज़माने के बने हुए हैं और जिन की वजह से red tapism चलता है तथा जिन के कारण justice न तो cheap है और न ही quick । इसलिये ऐसे rules बनायें जाने चाहियें

[श्री राम किशन]

जिन से लोगों को फ़ायदा पहुंचे । सो, हमारी सरकार ने जनता की ख़ाहश के मुताबिक इन rules को बदलने का फ़ैसला किया है । इस के साथ साथ लोगों की मांगों को भी पूरा किया जा रहा है ।

अगर हमने नया पंजाब बनाना है तो ज़रूरी है कि law and order कायम हो। इस मकसद के लिये देश में peaceful वातावरण की और अच्छे Administration की ज़रूरत है । हमारे प्रान्त में, जो एक सीमा प्रांत है, इस चीज़ की और भी अधिक ज़रूरत है । इसलिए जिस तरह से सरकार ने यहां law and order कायम कर रखा है उस के लिये वह मुबारकबाद की मुस्तहक है । यह एक शानदार काम है । स्पीकर साहिब! आप को मालूम है कि हमारे सूबे का border 300 मील zigzag तरीके से जाता है और उस की देखभाल की जिम्मेवारी हमारी P.A.P. पर है । इस border पर 1947 में जहां 264 incidents हुए थे वहां पंजाब की बहादुर P.A.P. की निगरानी की वजह से पिछले साल केवल दो incidents हुए थे । इस के लिये हम सरकार को मुबारकबाद देते हैं (*cheers*) । इस के अतिरिक्त पुलिस ने अपनी जान जोखों में डाल कर बाज़ जगहों पर डाकुओं को ख़त्म किया है। यह बहुत बहादुरी का काम है (*cheers*) ।

परसों जब यहां गवर्नर महोदय ने भाषण दिया था तो कुछ भाई वाक आऊट (walk out) कर गये थे । वह एक निहायत नाज़ेबा हरकत थी । इस के बारे में आप और मुख्य मंत्री महोदय पहले ही फरमा चुके हैं ।

अध्यक्ष महोदय ! अब मैं आप की तवज्जुह उस वाक्या की तरफ़ दिलाना चाहता हूं जो कि पंजाब के अन्दर ज़िला रोहतक के गांवों जागशी आदि में हुआ । इस सिलसिले में मेरी प्रार्थना है कि कोई भी सभ्य सरकार उस गड़बड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो कि पिछले कुछ वर्षों से वहां हो रही थी । कुछ पार्टियां जो कि अपने आप को राजनैतिक पार्टियां कहलाती हैं और जो कई विशेष कारणों से सूबे के अन्दर हकूमत भी करती थीं, उन्होंने रोहतक के ज़िला में reign of terror बरपा कर रखी थी और ऐसे प्रतीत होता था कि मानों भूपत पाकिस्तान से छूट कर आ गया हो या कहीं 'पीर पगाड़' के आदमियों ने अड्डा आ जमाया हुआ हो । यदि सारी हिस्टरी को देखा जाये तो पता चलेगा कि पिछले तीन चार वर्षों में इन तीन चार गांवों में ऐसी हालत हो गई थी कि वहां पर कोई भी पीस लविंग सिटीज़न (peaceloving citizen) रहना पसन्द नहीं करता था । वहां पर इतनी अराजकता फैली हुई थी कि खुले बन्दों वकीलों को गोलियों का निशाना बनाया जाता था । पुलिस के इनफ़ारमर्ज़ (informers) को मौत के घाट उतारा जाता था । नौबत यहां तक पहुंच चुकी थी कि लोगों के सिरों की कुछ रुपये कीमत रखी जाती थी और चंद चांदी के टुकड़ों के लालच में आदमी को कत्ल कर दिया जाता था ।

स्पीकर साहिब ! यह कौन नहीं जानता कि जब पिछले दिनों पंजाब पुलिस ने छापा मारा था तो हज़ारों रुपये का चोरी का माल बरामद हुआ था और इस के अतिरिक्त कितना ही

खतरनाक असलह जिसमें पिस्तौल और राइफलें भी शामिल हैं वहां से मिला था। जिस प्रकार की गड़बड़ वहां फैली हुई थी उसे कोई भी civilized या democratic सरकार सहन नहीं कर सकती थी। हमारी सरकार का यह कदम काबले तारीफ़ है कि उस ने देश में law and order, अमन और शान्ति को कायम रखने के लिये किसी ऐसे बड़े से बड़े आदमी को spare नहीं किया जिस ने मुल्क में व्यवस्था और शान्ति को भंग करने के लिये कोई हरकत की हो। स्पीकर साहिब! वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में यह अत्यावश्यक है कि हमारे पंजाब में law and order कायम रहे। परन्तु होता यह था कि उस जिला में डाके पड़ते थे कत्ल होते थे। पिछले चार वर्षों में वहां पर एम. एल. एज़. के भाइयों पर कातलाना हमले हुए, वकीलों के मुनशियों पर वार किये गये और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मैम्बरों पर गोलियां चलाई गईं। सरे बाज़ार भरे मजमों में मर्डर (murder) होते रहे। बावजूद इस के किसी को हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह इन वाक्यात की रोकथाम कर सके। अब अगर पंजाब की पुलिस अपनी जान जोखों में डाल कर इन डाकुओं, चोरों और गुण्डों को हिम्मत से दबाने की कोशिश करती है तो भवन में walk out होते हैं, agitations होते हैं। मुझे इन बातों पर बहुत हैरानी होती है कि जो लोग इतने हेनस क्राइम्ज़ (heinous crimes) करते हैं उन को प्रोटेकशन (protection) मिलती है ताकि उन का राज़ न खुले। लेकिन कौन नहीं जानता कि आख़िर उन का राज़ खुलेगा और पता चलेगा कि इन गुण्डों और डाकुओं की पीठ पर कौन लोग थे। किस तरह वे पिछले तीन चार साल से absconders को शरण देते रहे हैं। न केवल यही बल्कि पिछले दिनों जालन्धर में एक पोलिटिकल पार्टी ने एक murder के सम्बन्ध में कुछ इश्तहार भी शाए किये थे। murders को छिपाने के लिये राजनीतिक रंग दिया जाता है। मैं समझता हूं कि यह निहायत शर्मनाक बात है।

स्पीकर साहिब! मैं आप के द्वारा अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह ज़माना गया जब Unionist Party ऐसी बातों को सहन करती थी। अब पंजाब की वर्तमान कांग्रेस सरकार प्रान्त में एक peaceful and silent revolution लाना चाहती है। यह डाकुओं के लिये नहीं, offenders के लिये नहीं और harbourers के लिये नहीं, बल्कि उन लोगों के लिये लाना चाहती है जो कि पंजाब में 126 लाख की संख्या में सरकार पर यह उमीदें लगाए बैठे हैं कि सरकार उन के standard of living को ऊंचा करेगी और सारे प्रदेश में अमनो-अमान कायम रखेगी। इस सिलसिले में मैं अपने Communist भाइयों से केवल एक बात कहना चाहता हूं कि इस में कोई शक नहीं कि उन्होंने walk out किया—और भी बहुत कुछ किया लेकिन एक Chinese proverb के अनुसार मैं यही कहूंगा कि Clear the snow before your door and do not object to the frost on your neighbours' roof। उन को देखना चाहिये कि दुनिया के दूसरे देशों में क्या हो रहा है और फिर वह उस की तुलना हमारे देश के साथ करें। हमारे देश में freedom of speech है, freedom of expression है। लेकिन स्पीकर साहिब! इस freedom का मतलब यह नहीं लिया जा सकता कि कोई इस से अनुचित फ़ायदा उठाता हुआ दूसरों पर

[श्री राम किशन]

हमला कर दे। ऐसी freedom देने के लिये कोई भी सरकार तैयार न होगी। चुनांचि पुलिस ने वहां से offenders को पकड़ा और outlaws को गरिफ़तार किया। गर्ज़ेकि जगह जगह से उन के अड्डों को ख़त्म किया। कौन नहीं जानता कि Enquiry का क्या नतीजा निकला था और किस तरह से वहां पर एक reign of terrorism थी? डर के मारे कोई सामने नहीं आता था। लेकिन अब वहां पर अमनोअमान कायम किया गया है। पंजाब में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने के बाद पंजाब की सरकार आगे की तरफ़ बढ़ी है। पंजाब की पुलिस ने न सिर्फ़ पंजाब में ही बल्कि हैदराबाद, पैप्सू, राजस्थान, जम्मू और काश्मीर में भी अपनी बहादुरी और योग्यता के शानदार रिकार्ड (record) कायम कर दिये हैं जिस के लिये मैं पुलिस के सिपाहियों को मुबारिकबाद देता हूं (*cheers*) और आप की वसातत से उन को यकीन दिलाता हूं कि पंजाब का हर एक peace loving citizen उन की इन efforts में साथ देगा जो कि पंजाब में डाकुओं और हारबरर्ज़ (harbourers) को दबाने के लिये और अमनोअमान कायम रखने के लिये की जाएगी। हमारी पूरी हमदर्दी उन के साथ होगी (*cheers*)।

स्पीकर साहिब! Law and order को कायम करने पर ही मौकूफ नहीं बल्कि दूसरी बातों की तरफ़ भी दृष्टि डाली जाये तो मालूम होगा कि 1947 में हमारा प्रान्त एक deficit province था जो कि हमें एक उजड़े हुए प्रोविंस की शकल में मिला था। और कौन नहीं जानता कि संसार का कौन सा कहर है जो इस पर नाज़िल नहीं हुआ था? कहीं पर flood आये, कहीं पर अनावृष्टि हुई, कहीं टिड्डी दल के आक्रमण हुए इत्यादि कई एक मुसीबतें आईं। लेकिन आज हमारी हालत ऐसी है जिस पर पंजाब की सरकार गौरव से अपना सिर बुलन्द कर सकती है।

पिछले वर्ष हमने decontrol करने के बाद 113 हज़ार टन अनाज दूसरे प्रान्तों को भेजा। इस के अतिरिक्त हमारी सरकार की नीति यह रही है कि decontrol के बाद न तो अनाज की कीमतें बढ़ें और न ही वह कम हों ताकि ज़मींदारों पर बुरा असर न पड़े। लेकिन इस के बावजूद जब कीमतें बढ़ने लगीं तो सरकार ने cheap grain shops खोल कर लोगों की बहुत सहायता की जिस पर मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं (*cheers*)। यह मामला यहीं पर बस नहीं होता। हमारी सरकार ने पैप्सू, दिल्ली और राजस्थान को एक २ माह की आवश्यकता के बराबर चावल भेजा है जो कि बहुत ही शानदार काम है और इस के लिये मैं इसे बधाई देता हूं।

इस के उपरान्त, स्पीकर साहिब, मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल इतना ही नहीं, बल्कि पंजाब के sturdy किसानों ने, पंजाब के मेहनती किसानों ने, पंजाब के बहादुर किसानों ने जिस तन्देही से, जिस शान से और जिस लगन से सरकार की स्कीमों पर अमल किया और उन्हें कामयाब बनाने के लिये जो महत्त्वपूर्ण भाग लिया उस के लिये वह हमारी, हमारी सरकार की और सब से बढ़ कर इस हाउस के ज़रिये पंजाब की सारी जनता की तरफ़ से मुबारकबाद के मुस्तहक हैं (*cheers*)।

इस के अलावा, स्पीकर साहिब. मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारी सरकार की achievements यहीं खत्म नहीं हो जातीं। इस को छोड़ कर और भी कई आम मुफ़ाद के—रफ़ाए आमा के—काम हमारी सरकार ने किये हैं। आप भाखड़ा-नंगल को लीजिये। किस शानदार तरीके से इस काम को सरअन्जाम दिया जा रहा है। भाखड़ा और नंगल पर जिस तेज़ी से progress हो रही है, उस से हम आसानी से आइन्दा आने वाले पंजाब की तस्वीर देख सकते हैं। कौन नहीं जानता कि पिछले चालीस सालों से भाखड़ा और नंगल की स्कीमें केवल कागज़ी स्कीमें ही रहीं ? कौन नहीं जानता कि यूनियनिस्ट पार्टी की मनिस्ट्री भी इन कागज़ी स्कीमों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर सकी ? कौन नहीं जानता कि पहली आलमगीर जंग के खातमे के बाद सन 1919 में जब सर माईकल ओडवायर, जो पंजाब के गवर्नर थे, उस ने पंजाब के निवासियों से क्या वायदे नहीं किये ? लड़ाई के खातमे के बाद वह हिसार में भी गया और एक दरबार लगाया वहां पर यूनियनिस्ट पार्टी के मैम्बर और जमींदारा लीग के मैम्बर भी मौजूद थे। उन्होंने बड़े ज़ोर से यह फ़रमाया कि "ऐ हिसार के लोगो, ऐ हरियाना प्रान्त के निवासियो मैं तुम पर बहुत खुश हूं क्योंकि युद्ध जीतने में आप लोगों ने हमें बड़ा सहयोग दिया है और जल्दी ही तुम्हें भाखड़ा और नंगल से पानी मिलेगा जिस से तुम्हारे सब दुख दूर हो जायेंगे —यह जो छः सात सालों के बाद तुम्हें भयानक कहत का सामना करना पड़ता है, नहरी पानी आने से तुम इस कष्ट से छूट जाओगे। तुम्हारे इलाकों में नदियां बहेंगी तुम्हारी ज़मीनों को नहरी पानी सैराब करेगा"। लेकिन, स्पीकर साहिब, बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है कि वे सभी वायदे धरे के धरे रह गये और जो कुछ उस नहरी पानी के स्थान पर पंजाब के निवासियों को मिला, वह कौन नहीं जानता ? खैर, स्पीकर साहिब उन अंग्रेज़ों के वादों के मुताल्लिक मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूं कि किस को मालूम नहीं कि 15 अगस्त 1947 को जब कि हमारे प्रान्त का विभाजन हुआ तो भाखड़ा-नंगल पर construction का काम तो क्या, उस से सम्बन्धित कागज़ात भी हमें अंग्रेज़ी सरकार से नहीं मिले। लकिन मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूं कि जो काम पिछली सरकारें—यूनियनिस्ट पार्टी, जमींदारा लीग और अंग्रेजों की सरकारें—विभाजन से पहले चालीस वर्षों में भी न कर सकीं उसे हमारी अपनी सरकार ने—जनता की अपनी सरकार ने सात सालों के अन्दर कर दिखाया है। क्या यह इस सरकार के लिये credit का काम नहीं कि इसी साल मई के महीने से भाखड़ा नंगल से पानी मिलना शुरु हो जायेगा ? क्या ही अच्छा नज़ारा होगा जब हिसार के उन हिस्सों में जहां हर सात आठ साल के बाद अकाल पड़ जाता था सरसब्ज़ और लहलहाते हुए खेत नज़र आयेंगे। इस से हिसार का ज़िला केवल पंजाब की ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान की granary बन जायेगा। स्पीकर साहिब ! मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाखड़ा और नंगल के मुकम्मल हो जाने पर पंजाब सरकार न सिर्फ़ उस 1,08 करोड़ रुपये का भार अपने सिर से दो तीन सालों के अन्दर उतार देगी जो कि इस की construction के लिये भारत सरकार ने इसे दिया है, बल्कि सारे देश में खुशहाली का एक नया दौर शुरु होगा। भाखड़ा नंगल के बनने के पश्चात् जितना अनाज पैदा होने वाला है, वह सारे भारत के 90 करोड़ रुपये की currency को बचाने वाला होगा।

[श्री राम किशन]

इतना ही नहीं। स्पीकर साहब ! यहां से बिजली भी पैदा की जाने वाली है। वह कितनी ज्यादा बिजली की ताकत होगी? जनाबे वाला, उस की इतनी ताकत होगी कि हमारे हिन्दुस्तान में जितनी भी रेल गाड़ियां इस वक्त चलती हैं और उन पर जितना कोयला खर्च होता है उस की बजाए हमारे भारत की सारी गाड़ियों को 24 घंटे लगातार सारा वर्ष चलने के लिये जितनी बरकी ताकत की आवश्यकता है, इतनी केवल हमारा नंगल ही पैदा कर रहा है। जनाबे वाला, यह बिजली हमारे सूबे में एक नया ही रंग और रूप पैदा कर देगी। यह बिजली चीफ़ मिनिस्टर साहिब के बंगले में नही जायेगी। यह कोई Administrators के बंगलों में नहीं जायेगी। यह तो जनता के लाभ के लिये इस्तेमाल में लाई जायेगी। इस से न सिर्फ़ सूबे के हरेक गांव को, हरेक कसबे को और हरेक गली को रोशनी मिलेगी बल्कि यह हमारी माली हालत को भी पायेदार और बेहतर बनाने में काफ़ी मदद देगी।

स्पीकर साहिब! यह सब बातें कहने से मेरा यह मकसद है कि आज हमारा सूबा एक तरक्की के दौर से गुज़र रहा है जिस के पूरा होने पर हमारी और देश as a whole की खुशहाली यकीनी है। यह एक ऐसी stage है जब कि हमें सही सही और ठीक ठीक हालात अपनी जनता के सामने रखने चाहियें। इसलिये, स्पीकर साहिब, आप के ज़रिये मैं आपोज़ीशन के भाइयों से एक गुज़ारिश करना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि वे सरकार का, सरकार की नीतियों का या सरकार के कामों का criticism न करें। वे आलोचना करें क्योंकि यह प्रजातन्त्र में उन का मूल अधिकार है। लेकिन वह healthy criticism होना चाहिये जिस से मुलक को आगे बढ़ने में मदद मिले न कि उस में disorder पैदा हो या लोगों की ग़लतफ़हमियों में अज़ाफ़ा हो जाए। आज हमारे सामने सब से बड़ा सवाल देश से गरीबी को दूर करने का है। आज हमें देश से बेकारी को दूर करने की ज़रूरत है। यही नहीं, हमें देश से अविद्या को दूर करने की आवश्यकता है। आख़िर यह बीमारी, गरीबी लाइल्मी और बेरोज़गारी कैसे दूर हो सकती है? यह कोई बड़ी २ तकरीरें करने से तो दूर नहीं हो सकती। किसानों को बहकाने से या लोगों को गुमराह करने से तो दूर नहीं हो सकती! इन बुराइयों को जिन्होंने इतने वर्षों की गुलामी के कारण हमारे समाज की जड़ों को हिला दिया, मुख्तलिफ़ किसम के ख्यालात का इज़हार करने से दूर नहीं किया जा सकता। इन्हें दूर करने के लिये united efforts की ज़रूरत है—इकट्ठे मिल कर कोशिश करने की ज़रूरत है। जिस देश को आज़ाद कराने के लिये हमने मिल कर कोशिश की उसी पंजाब को हम मिली जुली ताकत से ही तरक्की के रास्ते पर आगे ले जा सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ़ एक चीज़ की है और वह है "हिम्मत"। आप कैनेडा (Canada) की मिसाल लें। उस की क्या हालत है? आबादी के लिहाज़ से उस की आबादी सारी दुनिया की आबादी का केवल ½ प्रतिशत है लेकिन बिजली की स्कीमों के इस्तेमाल से दुनिया की आबादी का ½ प्रतिशत आबादी वाला वह मुल्क आज संसार में तिजारत के लिहाज से तीसरे नम्बर पर है। इसलिये मैं पूरे यकीन के साथ यह कह सकता हूं कि अगर आप और हम मिल कर और हिम्मत बान्ध कर पंजाब को बनाने का काम करें तो कोई कारण नहीं कि यह सूबा हिन्दुस्तान का स्विटज़रलैंड न बन जाये।

स्पीकर साहिब ! यह सब कुछ कह चुकने के बाद मैं इस सदन का ध्यान सरकार द्वारा की गई दूसरी अच्छी बातों की तरफ़ भी दिलाना चाहता हूं। सरकार ने सूबे की law and order की स्थिति को सुधारते हुए अपनी administration की efficiency को या सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्तर को ऊंचा करने के सवालों को नजरअन्दाज़ नहीं किया। स्वतन्त्रता प्राप्त करने से पहले जो हमारा स्वराज्य आन्दोलन था उस में शराब बन्दी के सिलसिले में भी हम आन्दोलन किया करते थे। आज अगर हम माननीय राज्यपाल द्वारा दिये गये भाषण को पढ़ें तो हम देखते हैं कि हमारी सरकार ने उस मोहिम्म को जारी रखने का फ़ैसला किया है। स्पीकर साहिब ! काबले तारीफ बात तो यह है कि ऐसा कदम उठाने के लिये बावजूद आमदनी में खसारा होने के इस बात की प्रवाह नहीं की गई कि ऐसा करने से राज्य के revenue पर उलटा असर पड़ेगा। प्रवाह केवल एक बात की की गई है और वह यह है कि पंजाब निवासियों के moral को, उन की नैतिकता को ऊंचा किया जाये। इस लिये, पंजाब सरकार ने सिवल क्लबों में भी शराब-खोरी बन्द करने का जो फ़ैसला किया है क्या वह इस पर मुबारकबाद की मुस्तहक नहीं ? मैं समझता हूं कि उसे जरूर मुबारकबाद मिलनी चाहिये। मुझे यकीन है कि पंजाब निवासी हरेक भाई और बहन मेरे साथ इस मामले में सहमत होगा कि सरकार ने सोसाईटी (society) को रीफ़ार्म (reform) करने के लिये यह एक बड़ा भारी कदम उठाया है।

इस के बाद, स्पीकर साहिब, सरकार ने जो और important कदम उठाए हैं उन में से सब से ज़्यादा काबले तारीफ़ वह है जो इसने हरिजनों के सिलसिले में उठाया है। कौन नहीं जानता कि पिछले दिनों जनवरी, 1954 में रोहतक में एक हरिजनों की कान्फ्रेंस हुई। उस में यह मांग की गई थी कि हरिजन भाइयों के welfare के लिये एक Welfare Board बनाया जाए। पंजाब सरकार मुबारकबाद की मुस्तहक है कि उस ने उन की मांग को स्वीकार कर लिया है और अब एक हरिजन वैलफ़ेयर बोर्ड बनाने का फ़ैसला किया है। इसका क्या असर होगा ? बोर्ड देखेगा कि हरिजनों के साथ किसी किसम का भेद भाव न किया जाए। लेकिन इस में भी सरकारी कोशिशों के अलावा पब्लिक सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम सब मिल कर co-operative efforts नहीं करेंगे तब तक हमारे स्वप्नों की classless society बनना मुश्किल है। इस लिये मैं हाउस के सभी मेम्बरों से अपील करता हूं कि आप सब मिल कर इस काम को— इस उद्देश्य को पूरा करें।

अब, स्पीकर साहिब, अगर हम आगे चलें तो illiteracy यानी अविद्या की समस्या हमारे सामने आती है। हमारी सरकार इस दिशा में भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं। कौन नहीं जानता कि जब स्वतन्त्रता प्राप्त हुई तो उस समय हमारे देश के अन्दर केवल 6 साल से 11 साल तक की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों की 16 प्रतिशत आबादी को ही तालीम दी जाती थी ? लेकिन अगर हम तालीम के मैदान में भी अपनी सरकार की achievements का जाईज़ा लें तो हमें पता चलेगा कि पिछले छः सालों में और खास कर पिछले दो सालों में 16 प्रतिशत से उठा कर 42 प्रतिशत स्कूल जाने वाले बच्चों को तालीम की सहूलतें पहुंचाई जा रही हैं (*cheers*)। जहां पहले केवल 16 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे

[श्री राम किशन]

वहां अब पंजाब की सारी आबादी के 42 प्रतिशत बच्चे स्कूलों और कालेजों में तालीम पा रहे हैं। जहां सन् 1947 में केवल 2,500 स्कूल थे वहां अब 6,245 स्कूल खुले हुए हैं। कौन नहीं जानता, स्पीकर साहिब, कि इसी तरह का काम करते हुए रूस जैसे बड़े मुल्क ने जहां 18 साल लगाए, वही काम हमारी पंजाब सरकार ने पिछले 6 सालों के अन्दर कर दिखाया है।

इस के अलावा, स्पीकर साहिब, हमारे गवर्नर साहिब ने अपने भाषण में और भी कई बातों की तरफ़ ईशारा किया है। उन में से unemployment का—बेकारी का—भी एक सवाल है। बेकारी कोई छोटी मोटी समस्या नहीं। एक बड़े पैमाने का सवाल है। इस सिलसिले में भी, स्पीकर साहिब, मेरी ज़ाती राय यह है कि यह किसी तरह भी हल होने वाला नहीं। जब तक कि हम इस दिशा में united efforts न करें और सारे देश की समूचे तौर पर development न हो जब तक हमारे सूबे में बेकारी का मसला हल नहीं होगा। यही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी विकास होना मुमकिन नहीं। ऐसा करने के लिये हमें छोटी २ बातों को भूल जाना होगा। हमें भूल जाना होगा कि हम भोली भाली जनता को गुमराह करें। स्पीकर साहिब, गो मैं कहना तो नहीं चाहता था मगर एक खास बात आप के नोटिस में लाए बग़ैर रह नहीं सकता। पिछले दिनों ईलैकशन के मैदान में जब हमारे आपोज़ीशन के भाइयों को और कोई प्वाईट (point) न मिला तो आप यह सुन कर हैरान होंगे कि वह लोगों में तरह तरह की गलतबयानियां करते रहे और उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते रहे। मुझे याद है कि कम्यूनिस्ट पार्टी के मेरे दो दोस्तों ने अपने भाषणों के दौरान में लोगों से कहा कि भाखड़ा और नंगल से जो पानी आप को मिलेगा वह तो फोका होगा क्योंकि उस में से बिजली तो गवर्नमैंट ने निकाल लेनी है (हंसी)। कितनी खोखली और बोदी दलील है यह !

फिर, स्पीकर साहिब, इलैकशन के दिनों में हमारे कम्युनिस्ट साथियों ने बजाए इस के कि वह देश में हो रही developments के बारे में लोगों पर पूरी तरह से प्रकाश डालते उन्होंने यह कहा कि यह जो बिजली आप के यहां आ रही है वह आप के घरों में आग लगा देगी क्योंकि उस में से पानी निकाला गया है (हंसी)। सो बजाए इस के कि वह गवर्नमैंट को co-operation दें इस तरह का पर्रोपेगैंडा गवर्नमैंट के खिलाफ किया जाता है। पंजाब की सरकार को लोगों की co-operation की बड़ी जरूरत है और इसी से ही वह तरक्की की ओर आगे बढ़ सकती है।

जहां तक unemployment का ताल्लुक है, यह भी लोगों की co-operation से दूर हो सकती है। स्पीकर साहिब ! मैं आप की वसातत से हाउस से अर्ज करना चाहता हूं कि उन की co-operation के बिना यह इतना बड़ा मसला कैसे हल हो सकता है। जब 1950 में जनगणना हुई तो उस वक्त जो figures इकट्ठी की गई थीं उन से यह पता चलता था कि हमारे पंजाब के देहात में रहने वाले हर दस आदमियों में से सात आदमी agriculture पर गुज़ारा कर रहे हैं। जिस देश में हर दस आदमियों में से सात का सिर्फ़ agriculture पर ही गुज़ारा हो वहां की unemployment का मसला हल करना कोई आसान काम

नहीं । अगर पंजाब भर के ऐसे दस में से सात आदमियों की बजाये छ: को agriculture पर रहने दिया जाये और उन में से सिर्फ़ एक को agriculture से हटा कर दूसरे कामों पर लगा दिया जाये तो दो लाख आदमियों को और कामों पर लगाना होगा । मैं समझता हूं कि जब तक यहां cottage industries नहीं चलेंगी और देश के अन्दर बिजली नहीं आयेगी उस समय तक यह मसला हल होना संभव नहीं है । स्पीकर साहिब ! मैं आप की वसातत से इन दोस्तों से कहना चाहता हूं कि हमारे हां पंजाब में इस सिलसिला में एक Five-Year Plan चल रही है । कौन नहीं जानता है कि Five-Year Plan से हमारे राष्ट्र ने कितनी तरक्की की है । 1949-50 में हमारे देश की आमदनी 8,650 करोड़ रुपये थी लेकिन आज हमारी आमदनी 9,530 crores of rupees तक पहुंच गई है और इतने थोड़े अरसे में 900 करोड़ रुपये बढ़ गई है । हमने सारे देश की income को double कर देने का निश्चय कर रखा है । आखिर यह आमदनी किस तरह double होगी ? हम चार Five-Year Plans से अपनी आमदनी 85 प्रतिशत बढ़ा सका हैं । जब ऐसे दो तीन और पलैन बन कर मुकम्मल हो गये तो हमारे देश का नकशा बदल जायेगा । मैं इन दोस्तों से कह देना चाहता हूं कि ऐसा करने के लिये देश में अमनो अमान बनाए रखना चाहिये ।

स्पीकर साहिब ! इस ऐडरेस में एक खतरा की तरफ़ भी हमारी तवज्जुह दिलाई गई है । वह देश के अन्दर की स्थिति नहीं । वह है बाहर की । आज जो International हालात हो रहे हैं उन से जो खतरा हमारे देश के लिये पैदा हो गया है वह केवल हमारे देश के लिये ही नहीं बल्कि सारे ऐशिया के देशों के लिये भी है । अब जो पाक-अमरीकन (Pak-American) फ़ौजी मुआयदा हुआ है उस से हमारे पंजाब को ज़्यादा खतरा पैदा हो गया है । हम पंजाबी बार्डर (border) पर रहने वाले हैं हमें पंजाब को sword arm of India बनाना होगा । पंजाब ने सारे देश की रक्षा करनी होगी । स्पीकर साहिब ! मैं आप की वसातत से हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो गई तो पंजाब की सरकार, पंजाब में सब रहने वाले लोग बल्कि पंजाब का एक एक बच्चा अपने प्यारे देश हिंदुस्तान की रक्षा के लिये पूरी ताकत से लड़ेगा और हमारा यह नारा होगा कि हमने देश की रक्षा के लिये अपना सब कुछ कुर्बान कर देना है ।

स्पीकर साहिब मैं आप की वसातत से Opposition के चन्द मेम्बरों को छोड़ कर उन मेम्बरों से कहना चाहता हूं जिन्होंने पिछली बड़ी लड़ाई में अंग्रेज़ की मदद के लिये न केवल जंग में हिस्सा लिया था बल्कि victory को धयेय बना कर उसे जिताया भी था । मगर आज हमारे देश की हिफ़ाज़त का सवाल है । यह केवल इस मुल्क की ही नहीं बल्कि ऐशिया की भी problem है । जब एशिया (Asia) के लोग colonial domination से निकल कर अपनी भूख और गरीबी के मसले हल करने की कोशिश में हैं तो दुनिया की बड़ी ताकतें इन का ध्यान इस ओर से हटा कर जंग की तरफ़ लगा रही हैं और इन की तारीख़ बदलने की कोशिश हो रही है । आज सारी दुनिया एशिया का नक्शा बदलना चाहती है । पंडित जवाहर लाल नेहरू, हिंदुस्तान के प्राईम मिनिस्टर

[श्री राम किशन]

(Prime Minister) ने, इसी लिये यह कहा है कि पाक अमरीकन मुआयदा से सिर्फ़ भारत को ही नहीं बल्कि सारे एशिया को ख़तरा है। उन्होंने ठीक फरमाया है " If India dies who lives and if India lives who dies " मैं गुज़ारिश करूंगा कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपने Prime Minister के हाथ मज़बूत करें हमारा सब का जगह जगह पर यह एक नारा (slogan) होना चाहिये " Freedom is a pearl. Defend it with all your might." पंजाब को " sword arm of India " कहा जाता है। आज पंजाब हिंदुस्तान भर की administration में से best administrative unit बनने वाली है। पंजाब के तमाम लोग, पंजाब की तमाम बहनें और भाई Prime Minister को यकीन दिलायेंगे कि इस सीमा प्रान्त के लोग, जिन्होंने पहले ही बड़ी मुसीबतें उठाई हैं और बड़ी बड़ी तकालीफ़ें सही हैं, अपनी आज़ादी को बचाने के लिये किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत को बर्दाशत करने और उस का सामना करने से गुरेज़ नहीं करेंगे। मैं इन इलफ़ाज़ के साथ गवर्नर साहिब को मुबारकबाद देता हूं जो उन्होंने यहां तकरीर फ़रमा कर इस हाउस को मशकूर किया है।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ) : ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰਕੇ ਦੀ ਸਪੀਚ (speech) ਪਿਛੋਂ ਉਸੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਪੁਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ address ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸਦੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਆਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਦਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ Address ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਬਾਲਗੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਸਟੇਟਸ (States) ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ Address ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ Address ਇਕ ਨਿਹਾਇਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਡਰੈਸ (Address) ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ policy ਉਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਅਗੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਨੀਯਤ ਰਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਛੂਤ ਛਾਤ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ Labour Co-operatives ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ inferiority complex ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਪ੍ਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ services ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 ਫੀ ਸਦੀ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ posts ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਸਪੇਰਟੀ (disparity) ਹੁਣ ਤਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰੀਜ਼ਰਵ (reserve) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧ ਜਾਏਗੀ ਜੋਕਿ ਅਗੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਮਾਲੀ ਪਹਿਲੂ ਵਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਆਨੇ ਸਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਪਲਸ (surplus) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਆਬਾਦ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜ਼ੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ (under cultivation) ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਐਕਸਪੋਰਟ (export) ਕਰਨ ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ Community Project ਅਤੇ National extension ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚ 31 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇ।

ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੁਖਾਲਿਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਨ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰਜ਼ (political workers) ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ?

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ : ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਿਖ ਹੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਦਦ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਾ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (Transport Nationalisation) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਕਮਿਊਨਟੀ (Community) ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ (single out) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ

[ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ]

ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ (challenge) ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਉਸ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! sales tax ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀਂ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ (agitation) ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

अध्यक्ष महोदय : जो मोशन (motion) श्री राम किशन जी ने तजवीज़ की है उस की ताईद प्रिंसीपल हरभजन सिंह जी ने की है।

Motion moved—

> "That the members of this House assembled in this session are deeply grateful to the Governor for the Address he has been pleased to deliver to both the Houses assembled together."

इस मोशन के मुताल्लिक मेरे पास कुछ अमेंडमेंटस (amendments) आई हैं। यह अमेंडमेंटस आप के सामने हैं। तकरीर करते वक्त आप ओरिजीनल (original) मोशन और अमेंडमेंटस दोनों पर बहस कर सकेंगे।

So the following amendments would be deemed to have been moved—

1. **Shri Mool Chand Jain :**

That at the end of the motion, the following be added :—

" but regret that adequate consideration has not been given to—

(a) remove unemployment and under-employment in the State ;

(b) remove disparities between the rich and the poor ;

(c) provide cheap credit to the landless, the tenants and the labourers and cottage industry ;

(d) change the pro-rich mentality of the administration ;

(e) fulfil the assurance of appointing Harijan lambardars;

(f) fulfil the assurance of holding District Board elections ;

(g) provide technical and vocational educational in the State ;

(h) encourage the Bhoodan Sampatidan movement ;

(i) check the growing evil of Satta gambling ;

(j) make arrangements for settlement along with consolidation;

(k) change rules regarding the grant of Arms licenses ; and

(l) provide good publicity facilities for Government activities.

2. **By Sardar Wazir Singh :**

3. **By Sardar Ajmer Singh :**

4. **By Sardar Gopal Singh :**

5. **By Sardar Iqbal Singh :**

6. **By Sardar Shamsher Singh :**

That at the end of the motion, the following be added :—

"but regret that the Government had failed to administer even-handed justice to people of all shades of opinion in the province and ha ve pursued anti-national policies which harmed the just interests of the State."

7. **By Sardar Harkishan Singh Surjit :**

8. **By Sardar Achhar Singh Chhina :**

9. **By Shri Wadhawa Ram :**

10, **By Sardar Bachan Singh :**

11. **By Sardar Darshan Singh :**

12. **By Sardar Chanan Singh Dhut :**

That at the end of the motion, the following be added :—

"But regret that—

(i) the atrocities perpetrated by the Police on men, women and children in the villages of District Rohtak, the rape and dishonouring of women and looting and destruction of property have not been mentioned and insti-sitution of a JUDICIAL ENQUIRY into the Police excesses and punishment of those guilty have not been promised ;

(ii) the notices of eviction served on tens of thousands of tenants, encouragement given to the landlords by the Government and the colusion of certain Government officials with landlords have not been mentioned ;

(iii) the general repression launched against tenants arrests of hundreds of tenants and Kisan Sabha workers in all parts of Punjab and the arrest of two members of Punjab Legislative Assembly to suppress the tenants movement have not been mentioned ;

(iv) the repressive policy of Government, imposition of Section 144 and posting of Punitive Police Posts have not been mentioned ;

(v) the policy of Government to suppress and gag democratic and opposition PRESS and arrest of Journalists without even consulting PRESS ADVISORY COMMITTEE have not been mentioned ;

(vi) the increase in unemployment, retrenchment of workers and employees and wage-cuts have not been mentioned; and

(vii) the failure of the Government to protect and encourage INDUSTRY has not been mentioned."

13. **By Shri Maru Singh Malik :**

That at the end of the motion, the following be added :—

"But regret that nothing has been done to safeguard the civil liberty honour and property of the general public in the State."

14. By Shri Sri Chand :

That at the end of the motion the following be added—

"but regret that—

(a) nothing has been done to check the high handedness and wanton attack on the Civil Liberties of the Public, at the hands of the Police in the name of Law and Order;

(b) no mention has been made at the sensational abduction of the two sisters of Jamnanagar;

(c) nothing has been mentioned about the alleged atrocities perpetrated upon the residents of the various villages of the District of Rohtak under the garb of anti-dacoit operations."

15. By Pandit Shri Ram Sharma :

That at the end of the motion the following be added :—

"but regret that " the address of the Governor did not refer to the Police atrocities committed in Rohtak District in connection with the anti-dacoit operations in the last week of the January last."

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब ! गवर्नर साहिब ने बड़ी मेहरबानी फ़रमा कर परसों इस हाऊस और अपर हाऊस के मुशतरका इजलास में ऐड्रैस (Address) फ़र्माया और उस के लिये उन का शुक्रिया करने की तहरीक और उसकी ताईद हो चुकी है। मैं इस में एक तरमीम करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरी तरमीम यह है जो कि मोशन के आख़ीर में शामिल की जाए.—

"but regret that the address of the Governor did not refer to the Police atrocities committed in Rohtak District in connection with the anti-dacoit operations in the last week of the January last".

मुझे यह तरमीम करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि गवर्नर साहिब ने अपने ऐड्रैस में इस हकूमत का एक सुनहरी और रोशन पहलू पेश किया है जो उन्हें ज़ाबता के मुताबिक करना ही था। स्पीकर साहिब ! जो कुछ हमारी गवर्नमेंट ने ऐडरेस में ज़ाहिर किया है उस की कोई शिकायत नहीं करता क्योंकि ऐडरेस में बड़े बड़े कारनामों का ज़िकर किया जाता है और जो बड़े बड़े काम सरकार ने पिछले साल किये हैं उन्हें एडरेस में बयान किया जाता है। मगर यह कोई पूछता नहीं कि वह काम जिन का ऐडरेस के अन्दर ज़िकर किया गया है वैसे थे भी या नहीं।

इस में नुमायां तौर पर यह ज़िकर किया गया है कि "The main achievement of the year has been the liquidation of gangs of desperate outlaws operating in the Punjab as well as the neighbouring States." गोया पंजाब और इस की हकूमत के कारनामों पर रोशनी डालते हुए यह ज़ाहिर किया गया है कि Law and order के कायम रखने के लिये मारके का काम किया गया है। फिर आगे चल कर कहा गया है कि सूबे से सब डाकुओं, ख़ून करने वालों और मार धाड़ करने वालों का ख़ातमा कर दिया गया है।

जनाब स्पीकर साहिब ! जो ज़्यादतियां पुलिस ने ज़िला रोहतक के देहात के लोगों, जिन में औरतें भी शामिल हैं पर कीं और जो वहशयाना सलूक औरतों के साथ किया गया है वह बयान से बाहर है। (Cries of shame shame from opposition Benches) ।

जनाब स्पीकर साहिब! जहां तो सरकार की सरगर्मियों का सुनहरी और साफ़ नक्शा हमारे सामने रखा गया है वहां पर मुझे अफ़सोस यह है कि ऐडरेस में पुलिस की उन ज्यादतियों का जिक्र नहीं किया गया है जो उन्होंने जनवरी के आखरी हफ़्ते में dacoits को ठिकाने लगाने के बहाने से की हैं। मुझे जाती तौर पर उन जुल्मों का पता है जो पुलिस ने किये।

गवर्नर के ऐडरेस देने के वक्त इन ज्यादतियों के खिलाफ़ जो पुलिस ने कीं मेरे कुछ दोस्तों ने नाराजगी जाहिर करते हुए walk out किया। मेरे उन में शामल न होने का यह मतलब नहीं कि मुझे पुलिस के इस जुल्म पर कोई दुख नहीं। मैं तो उन सब से ज्यादा दुखी हूं। मैंने इसलिये walk out नहीं किया कि Constitution के मुताबक गवर्नर Head of the State होता है और वह Party Politics से ऊपर होता है। गवर्नर इन ज्यादतियों के लिये personally जिम्मेदार नहीं हैं। मैंने सोच समझ कर walk out में शामूलियत नहीं की। लेकिन इस का मतलब यह न लेना चाहिये कि मेरे दिल में इस बात का दुःख नहीं है। मैंने और मेरे साथियों ने Parliament की शानदार रवायतों का अनादर नहीं किया मगर मैं फिर कहे देता हूं कि जिन दोस्तों ने walk out किया है मैं उन से इस जुल्म के लिये कहीं ज्यादा दुख महसूस करता हूं।

स्पीकर साहिब! रोहतक में इतने खौफ़नाक वाक्यात हुए कि उन की मिसाल नहीं मिलती। मेरे काबिल दोस्त नुमाइन्दा जालन्धर और इस motion के मुहर्रिक ने तारीफों के पुल बांध दिये मगर साथ ही यह शिकायत भी की कि ज़िला रोहतक में Law and order की हालत पिछले दो या तीन वर्षों से बहुत खराब थी। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछले 2½, 3 साल से जो कुछ रोहतक में हो रहा था उस के लिये कौन जिम्मेदार है? यह कहा गया है कि रोहतक के अन्दर lawlessness थी। गुजरात का भूपत फिर रहा था और लोग घरों से बाहर न निकल सकते थे। यह बात मेरे दोस्त ने बड़े ज़ोर से कही है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में रोकथाम कर दी है। मगर मैं पूछता हूं कि इन दो 2½ सालों के अन्दर जो जुल्म पब्लिक पर ढाए गए उन का सरकार को कब पता चल गया? क्या यहां पर किसी ग़ैर की हकूमत थी या गुजरात वालों की थी जिन्होंने भूपत को भेजा था? अगर यहां पर किसी ग़ैर की हकूमत नहीं थी तो सरकार को 6 महीने, एक साल या 2, 3, साल पहले पता क्यों न चला कि रोहतक में Law and order की हालत बुरी है? और इतने लम्बे समय तक उस का इन्तज़ाम क्यों नहीं किया गया? जो डरावने नक्शे मुहर्रिक ने ज़िला रोहतक के खींचे हैं वह ज्यादा सही हैं मगर मैं पूछता हूं कि जब यह बुरी हालत 1 साल, 1½ साल, 2 साल से या 2½ साल से डरावनी शकल इख्तियार कर चुकी थी तो सरकार को अब Law and order का यकायक कैसे ख्याल आ गया? अगर सरकार ने ही हालात को इस तरह खराब होने दिया है तो क्या वह मुबारकबाद की मुस्तहक हो सकती है? हैरानी की बात है कि गवर्नर साहिब को मुबारकबाद दी जाती है ऐसे डरावने नक्शों को सामने रख कर और भूपत को याद करके!

मुझे एक ऐसे मुखबिर का जो सरकार को इत्तलाह देते हैं, पता है जिस को dacoits ने गोली मार दी मगर अभी तक इस सम्बन्ध में डाकुओं का सरदार गिरफ़्तार नहीं किया

[पंडित श्री राम शर्मा]

जा सका है। (एक आवाज़ : आप भी उस समय वज़ीर थे) सो, अगर रोहतक के अन्दर Law and arder की यह हालत हो तो इस के लिये शरमिन्दगी किस को है ? चीफ़ मनिस्टर साहिब को या श्री राम को ? (*Interruptions*)। इस तरीके से Lawlessness को खत्म नहीं किया जा सकता। मैंने मुख्य मंत्री को कई बार लिख कर और ज़बानी कहा है कि पुलिस को तबदील करते रहने से इस Lawlessness को खत्म नहीं किया जा सकता। मैंने यह कहा था कि अगर मुझे इस को खत्म करने के लिये इन्चार्ज मुकर्र कर दिया जाए तो मैं या तो lawlessness को खत्म कर दूंगा या खुद खत्म हो जाऊंगा। (*Cheers*)।

फिर जिस बात का ज़िक्र हमारे कामरेड राम किशन ने किया है कि रोहतक में दो साल से भूपत का राज चला आ रहा था तो मैं पूछता हूं कि इस बदअमनी को दूर करने की ज़िम्मेदारी किस की थी? 6 महीने हुए 1½ साल गुज़रा हत्तांकि दो साल गुज़र गये मगर इन हालात की रोक थाम का कोई इन्तज़ाम क्यों न किया गया ? और जिस गवर्नमेंट ने ऐसा होने दिया वह मुबारकबाद की मुस्तहक नहीं हो सकती। मैं यह कहता हूं कि इस बात पर जिस का कि इस प्रस्ताव (resolution) में ज़िक्र है और जिस के लिये गवर्नमेंट को मुबारकबाद का हकदार बनाया गया है उस पर कोई भी गवर्नमेंट फ़ख्र नहीं कर सकती खास तौर पर जब कि रोहतक में लोगों को इन डाकुओं ने ज़िन्दा जलाया और बेगुनाहों का खून किया।

जनाब स्पीकर साहिब! एक आदमी को पुलिस वालों ने दरखत पर चढ़ाया कि वह पता लगाये कि डाकू किस तरफ़ हैं। मगर पुलिस के देखते देखते उस आदमी को डाकुओं ने गोली का निशाना बनाया। पुलिस टस से मस नहीं हुई और कपड़े झाड़ कर वहां से चल दी। (Shame, shame from the Opposition Benches). इन मफ़रूरों को पकड़ने के नाम पर लाखों रुपये बरबाद किये जा रहे हैं। कहा जाता है कि घोड़स्वार नियत किये गये, Armoured Cars मंगाई गई। खास खास Deputy Superintendent Police और Superintendent Police लगाये गये हैं। यह सब बेकार साबत हुए। इस तरह सूबे का रुपया बरबाद किया गया है। मगर यहां पर प्रस्ताव यह किया जाता है कि गवर्नमेंट मुबारकबाद की हकदार है। मुझे अफ़सोस है कि रोहतक की सी Law and order की हालत के पेशेनज़र सरकार को मुबारकबाद दी जा रही है (*Interruptions*) अगर गवर्नमेंट की यह हालत हो तो उसे होश कब आएगी? यह कहते हुए मुझे दुख होता है कि कई बेगुनाह मारे जाते रहे हैं मगर गवर्नमेंट ने कभी महसूस नहीं किया और फिर किया तो यह किया कि लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर के उन्हें बुरी तरह पीटा गया और उनकी बेइज़्ज़ती की गई।

एक बार कोई दो हज़ार के करीब आदमी एक नाच को देख रहे थे तो डाकू आए और उन्होंने एक आदमी का नाम पूछा। जब वह आदमी खड़ा हुआ तो उन्होंने उसे वहीं मार दिया और लोगों का इतना बड़ा हजूम कुछ न कर सका क्योंकि वहां लोग बिल्कुल demoralise हो चुके थे। डाकू आराम से चले गये और धमकी दे गये कि अगर किसी ने आवाज़ उठाई

तो उस के साथ भी यही सलूक किया जाएगा। मैंने मामले का जिक्र इस लिये किया है कि यह Subjudice नहीं है।

Minister for Irrigation: It is subjudice. Even the accused have been arrested और court में चालान जा चुके हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो subjudice हो। मगर यह अमर वाक्या है कि कुछ मुलज़म मफ़रूर हैं और अभी तक गिरफ़्तार नहीं किये गये।

Chief Minister: On a point of order, Sir. It is obvious that murder has taken place and investigation is going on एक आदमी मारा गया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। आदमी पकड़े जा रहे हैं। अगर यह मामला भी subjudice नहीं है तो और क्या हो सकता है?

Minister for Irrigation : Sir, I have already pointed out that the case is pending in the Court. Inspite of that my hon. friend is trying to create difficulties for the prosecution.

अध्यक्ष महोदय : अगर यह मामला अदालत में पेश है तो इस के बारे में अगर कुछ कहा गया है तो उस का ज़रूर असर पड़ेगा। इसलिये मैं अर्ज़ करूंगा कि आप को इस बात से परहेज़ करना चाहिये।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं ज़रूर परहेज़ करूंगा, जनाब, मैं खुद ही कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। मैं अर्ज़ कर रहा था कि आखिर सरकार ने देखा कि यह मामला अब आम लोगों तक नहीं रहा। जब एक ऐसे वकील का मुन्शी मारा गया जो सरकार से बहुत करीब का मेल रखता है, और उस ने अपनी जान के खतरे का वावेला किया और जब एक वज़ीर को भी खतरा पैदा हुआ (Laughter) तो सरकार ने बजा तौर पर एकशन (action) लेने का फ़ैसला किया। मैं सरकार को इस फ़ैसले पर बुरा नहीं कहता। मामला सचमुच बहुत बिगड़ गया था। मगर अफ़सोस यह है कि बीमारी तो बेशक बहुत बुरी थी मगर जो इलाज किया गया वह उस से भी बुरा था। एकदम बौर्डर की पुलिस के बहुत से जवान वहां ले जाए गये। बड़े बड़े अफ़सर भी बुला लिये गये और हुकम दिया गया कि रोहतक में पुलिस आप्रेशन किया जाए। आज सवालों के वक्त मुझे पूछताछ करने का पूरा मौका न मिल सका। खैर, हुआ यह कि सौ २ सिपाहियों ने रोहतक के पन्द्रह बीस गांवों के गिर्द घेरा डाल लिया। फिर हौले २ यह सर्कल (circle) छोटा करते गये। फिर जो आदमी जहां कहीं मिला उस से कहा गया कि वह दो मिनट के अन्दर चौपाल में पहुंच जाए। पुलिस ने किसी को डंडा मारा, किसी की लातों की ठोकरों से मुरम्मत की और इस तरह सारा गांव इकट्ठा कर लिया। उस के बाद यह हुआ कि जिन लोगों पर शुबह था कि वह डाकुओं को पनाह देते हैं या जिन के साथ पुलिस की दुशमनी थी या जिन से डरा धमका कर मदद लेने की उम्मीद थी उन को ज़मीन पर उलटा लिटाया गया और सब कपड़े उतार कर नंगा कर दिया गया। फिर खुले चौपाल में सब के सामने उन के private parts पर लगातार जूते लगवाये गये। स्पीकर साहिब! अंग्रेज के ज़माने में जो बातें हवालात और जेलों के अन्दर हुआ करती थीं वह इस सच्चर-कैरों सरकार के ज़माने

[पंडित श्री राम शर्मा]

में खुले चौपाल में छोटे बड़ों और बहू बेटियों के सामने हुईं (shame, shame) रबड़ा गांव में फिर एक भंगी को हुकम दिया गया कि वह उन के private parts पर थूके (shame, shame) ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि आप जो कुछ कह रहे हैं उस की पूरी पूरी जिम्मेदारी भी लेते हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं एक एक बात की जिम्मेदारी लेता हूं । जिस का जी चाहे मेरे साथ चल कर देख ले अगर मेरी एक बात भी ग़लत साबित हो तो जो सज़ा हाऊस की तरफ़ से दी जाए वह मुझे मनज़ूर होगी । जनाब, मैं अर्ज करता हूं कि एक गाव में 6 लम्बरदारों को बुला कर सब के सामने उन के कान स्कूल के बच्चों की तरह पकड़वाये गये और उन के private parts पर जूते लगवाये गये । इस तरह सब के सामने उन को ज़लील किया गया ।

पंचायतों के बारे में यह सरकार बहुत शेखियां बघारती है लेकिन पंचों के साथ भी बुरा सलूक किया गया । मैंने सुना है कि कुछ पंचों ने ग़ैरत से काम ले कर इसतीफ़े भी दे दिये हैं । स्पीकर साहिब! जिन लोगों को पीटा और बेइज्ज़त किया गया उन में कुछ M.L.A. साहिबान के रिशतेदार भी हैं । जिस किसी का किसी बड़े आदमी से ताल्लुक था उस को भी पीटा और बेइज्ज़त किया गया । अगर किसी शामत के मारे ने कहा कि हमारा कसूर क्या है तो उसे ठोकरें मार कर कहा गया कि कसूर सच्चर और लहरी सिंह से जा कर पूछो ।

जनाब! आप को मालूम है कि जागसी गांव में गवर्नर साहिब दौरे पर तशरीफ़ ले गये थे । उन्होंने वहां के लोगों को सेवा भाव से सड़क बनाने पर मुबारकबाद दी थी और उन की बहुत तारीफ़ की थी । मगर हैरानी की बात है कि सरकार की नज़रों में दो ही दिन में वह सारा गांव बाग़ी हो गया और डाकुओं को पनाह देने वाला बन गया । रबड़ा और जागसी में पुलिस के सिपाहियों को हुकम दिया गया कि जाओ और लोगों को पकड़ कर इकट्ठा करो । वहां उस वक्त मर्द नहीं थे । घरों में सिर्फ़ औरतें ही थीं । यह जो कहा गया है कि तीस हज़ार का डाके का माल बरामद हुआ है वह माल स्त्रियों के शरीर पर से सुनारों द्वारा निकलवाया गया है । और यहां यह कहा गया है कि डाके का माल निकलवाया गया (shame) ।

सिंचाई मंत्री : यह मामला भी अदालत में है ।

पंडित श्री राम शर्मा : श्री राम किशन जी ने उस का ज़िक्र किया है । उस वक्त आप कहां थे ?

सिंचाई मंत्री : मैं तो सिर्फ यह कहता हूं कि जो चीज़ें subjudice हैं उन का यहां ज़िक्र न करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : जब यह मामला पहले पहल हाऊस के सामने आया और मोशन (motion) के मूवर (mover) साहिब ने इस का ज़िक्र किया था, तो किसी ने यह बता कर उन्हें टोका नहीं था कि मामला अदालत में है तो फिर मैं जवाब देने वाले को किस तरह मना कर सकता हूं (Hear, hear) फिर भी मैं मेम्बर साहिब की good sense को अपील करूंगा कि इस बात का ख्याल रखें ।

सिंचाई मंत्री : जहां तक ज़ेवरात का सम्बन्ध है उस बात पर तो बहस हो सकती है लेकिन यह कहना कि जेवर किस तरह recover हुए ठीक नहीं।

अध्यक्ष महोदय : तो माननीय सदस्य सुनारों का नाम न लें। वे केवल यही कह दें कि जेवरात को इकट्ठा करके लाया गया।

पंडित श्री राम शर्मा: स्पीकर साहिब! मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूं कि पुलिस ने क्या कुछ लोगों के साथ किया। मरदों को घरों से बाहिर रखा गया और औरतों के साथ शर्मनाक हरकतें भी की गईं। औरतों से बयान लिये गये हैं और इन के साथ ऐसी बातें की गई हैं जिनका ज़िक्र करना इस कदर शर्मनाक है कि सभा में मैं उनका बहुत एहत्यात के साथ ज़िक्र करने में भी हिचकिचाता हूं। मैं सच कहता हूं कि मैंने अंग्रेज़ के दिनों में भी ऐसी शर्मनाक हरकतें होती नहीं देखीं और कम सुनी हैं। यह ठीक है कि Martial law के दिनों में लोगों को पेट के बल चलाया गया और बहुत कुछ हुआ लेकिन औरतों की इतनी बेहुरमती उस समय भी न की गई थी।

स्पीकर साहिब! मेरे मित्र कहेंगे कि यदि इतना कुछ हुआ तो मैं खुद लोगों के बयानात लेने क्यों न चला गया। मैं जानता था कि यह लोग कई तरह की बातें करेंगे। यह ज़रूर motives impute करेंगे। किसी के बारे में तो कहा जा रहा है कि वह तो Communist हैं किसी को unionist पुकारा जाता है। मेरे खुद जाकर बयानात लेने पर कहा जाता है कि मैंने सरकार को बदनाम करने के लिये अपने असर से बयान प्राप्त कर लिये हैं। यह सब कुछ कहा जाता लेकिन मैं कहता हूं कि मैं खून के घूंट पीता रहा और लोगों के बयान लेने इस लिये न गया क्योंकि वज़ारत से मेरा ज़ाती झगड़ा था। यही वजह थी कि मैंने scrupulously यानी बड़ी एहतियात रख कर इस कार्य में दखल नहीं दिया।

स्पीकर साहिब! ज़िला रोहतक की Bar Association ने जो सरकार की हमेशा supporter रही है और जो किसी तरह भी political जमात करार नहीं दी जा सकती रवड़ा और जागसी गांवों के बारे एक जांच कमेटी मुकर्रर की थी। उस committee ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इन गांवों में पुलिस द्वारा ज़ना बिलजबर किये गये हैं। इस रिपोर्ट की सदाकत में शक नहीं किया जा सकता क्योंकि इस कमेटी के Chairman साहिब वे आदमी हैं जो 22 वर्ष सरकार के Public Prosecutor रहे हैं। इस कमेटी की रिपोर्ट में साफ़ लिखा है कि रवड़ा और जागसी गांवों में औरतों के साथ ज़ना बिलजबर किया गया। इन की बेहुरमती की गई। लूट मची, सामान और अनाज खराब किया गया और तरह तरह की शर्मनाक हरकतें की गई। मैं कहता हूं कि Bar Association के इन 6 मेंबरों का, जिन्होंने रिपोर्ट लिखी है, सरकार से कोई अनाद न था। इसी तरह स्वामी स्वतन्त्रानंद जी ने भी, जो किसी political जमात से सम्बन्ध नहीं रखते, यही कहा है। श्रीमती लक्षमी देवी ने भी, जिसे पिछले election में मेरे मित्रों ने कांग्रेस टिकट पर खड़ा किया था और जो कम वोटों के कारण कामयाब न हो सकी, यही बात कही है। यही नहीं तमाम वह लोग जो political जमातों से कोई सम्बन्ध नहीं रखते कह रहे हैं कि रवड़ा और जागसी में बहुत अत्याचार हुए हैं।

[पंडित श्री राम शर्मा]

लेकिन हमारे कुछ मित्र और वजीर साहिबान हैं जो कहे जाते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह Home Secretary साहिब हैं। उन्होंने बयान निकाल दिया है कि कोई बात ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप को अफ़सरों के बारे में कुछ न कहना चाहिये।

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब ! लोगों ने पंडित जवाहर लाल और श्री काटजू के पास जा कर चीखो पुकार की और कहा कि यहां पर अंधेर गर्दी हो रही है और इस प्रान्त की पुलिस तो कुछ मामलों में रोहतक के दिहात में जनरल डायर से भी बाजी ले गई है। परन्तु भारत सरकार के गृह मंत्री ने कहा कि वे इस मामले में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि Law and order तो प्रान्तीय सरकार के पास है। मैं कहता हूं कि यदि सरकार को non-political जमातों और लोगों पर एतबार न हो तो बेशक सरकारी तौर पर तहकीकात करवा ली जाये। लेकिन यह तफ़तीश हमारे Home Secretary जैसे अफ़सरों से न करवाई जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप अफ़सरों को बहस में न लायें।

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब ! मेरा Home Secretary का जिक्र करने से मतलब केवल इतना है कि उन अफ़सरों को जो इस बारे में राय दे चुके हैं, तहकीकात पर न लगाया जाये। बेशक यह काम किसी हाई कोर्ट के जज या बड़े सरकारी अफ़सर के सपुर्द कर दिया जाये। अंग्रेजों ने जनरल डायर जैसे जाबिर और ज़ालिम अफ़सर के खिलाफ action ले लिया था लेकिन मुझे अफ़सोस है कि हमारी सरकार और हमारे वज़ीर अपनी पुलिस के खिलाफ़ कुछ नहीं करना चाहते। मैं challenge करता हूं कि रोहतक के इस इलाके से जहां यह अत्याचार हुए. जो नुमाइंदा आया है यदि उसे अब चुनाव के लिये खड़ा कर दिया जाये तो उस की ज़मानत ज़ब्त हो जायगी। क्या अजीब बात है कि गवर्नर साहिब से गलत बातें कहलवा दी गई हैं। उन से कहलवाया गया है कि इस सरकार ने बड़े बड़े मारके मारे हैं। मेरे विचार में independence के बाद अगर इस सरकार ने कोई achievement हासिल की है तो वह रोहतक के देहातों में अत्याचार और स्त्री जाति की बेहुरमती का बड़ा ही शर्मनाक वाक्या है।

ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਨੂਰਮਹੱਲ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤਰ ਪੰਡਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ, ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੇ ਡੇੜ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਲੀਫੂਨ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਏ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾਏ?

पंडित श्री राम शर्मा : सरकारी बेंचों पर बैठे हुए मैम्बरों को यह ज़ेब नहीं देता कि वह बहस के दौरान में किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ़ ऐसे शब्द इस्तेमाल करें ।

श्री श्री चन्द : On a point of order, Sir मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि जहां तक हो सके बहस के दौरान में personal remarks करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिये । माननीय मेम्बरों को बहस का मियार ऊंचा करना चाहिये और असल हालात हाऊस के सामने पेश करने चाहिये और माननीय मेम्बरों पर ज़ाती हमला नहीं करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि जो दमाग़ की कैफीयत होती है वह ज़बान से खुद बखुद जाहिर हो जाती है चाहे कोई मेम्बर कांग्रेस पार्टी से सम्बन्ध रखता हो या किसी और पार्टी से ।

ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਪਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਪ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਇਥੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਰੌ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ independent enquiry ਕਰਾਈ ਜਾਏ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਹਕੀਕਾਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਨ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਹਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੈਂ ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਹਰ ਇਕ ਵਯਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਧੁਨ ਸਮਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ੨ ਜਤਨ ਕਰਨੇ ਹਨ । ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਕਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ democracy ਪਰਫੁਲਤ ਹੈ । ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ powers ਨੂੰ decentralize ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੱਚਰ ਤੇ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, democracy ਨੂੰ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਲਾਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੀ Gram Panchayat Bill ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ]
ਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ Community Projects ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਜਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਐਡਰੇਸ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਦਸ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਯਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬ ਕੁਝ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ (election) ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਣ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰ ਰਹਿਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ Narwana Circle ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਏਗਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਗ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁਕਾਂ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ motion of thanks ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਗਲ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂਕੁ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ Self-sufficient ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਡਰਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਐਡਰੇਸ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ actual facts ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ motion of thanks ਨੂੰ nullify ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ motion ਨੂੰ support ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ (ਡੇਲੋਂ): ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਸ motion of thanks ਤੇ ਮੈਂ ਇਕ amendment ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਥੇ ਸਰਕਾਰ even handed justice ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਥ ਹੀ ਇਹ anti national activities ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਅੱਡ ਅੱਡ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ motion of thanks ਦੇ proposer ਅਤੇ seconder ਦੋਹਵਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਕ ਰੁਖ ਇਓਂ depict ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਥੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਹਊਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਪੰਡਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ action ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਅਦ ਐਥੇ ਜਿੰਨਾ favouritism, nepotism ਅਤੇ corruption ਵਧੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤ੍ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ privately ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕੇ (ਹਾਸਾ)। ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੇਵਲ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ law and order ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਓਥੇ ਕੋਈ law and order ਨਹੀਂ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ cancel ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਇਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ law and order ਦੀ ਹਾਲਤ।

ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਕੀਹ opposition ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੀਹ ਦੂਸਰੇ, ਸਭ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਐਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ]

ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੋਚੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਾਂ opposition ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ law and order ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ administration ਵਿਚ ਆਪ ਬਹੁਤ interfere ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ demoralise ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ sense of justice ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ party in power ਦੇ ਪਰਵਰਦਾ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਨ ਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ demoralise ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਥੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ (Upper House) ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ (Chief Minister) ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚ ਸਭ ਆਦਮੀ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਡੇਪੂਟੇਸ਼ਨ (deputation) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ greivances ਦੱਸੀਆਂ। ਉਥੇ ਮੋਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ operators ਦੀ lead ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ strike ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ!

ਅਸਾਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ trial ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਛਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਾਕਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਵਜਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ

ਰਖਦੇ ਸਨ । ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਦਰ ਅਸਲ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ਼ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦਾ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ (opposition) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ ਉਹ demoralize ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬਨ੍ਹਾਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ protect ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਨ ਅਗੋਂ ਵੀ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ law and order ਤਦ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਮਕਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir, यदि किसी मर्द के स्थान पर कोई महिला हो तो उस के साथ तो रियायत की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : आप की बाधा डालने की आदत अभी तक नहीं गई । माननीय सदस्य को अपना भाषण जारी रखना चाहिये और बाधा की ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिये । १

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ National Government ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ Indian Penal Code ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਇਸ ਦੇ ਉਪ੍ਰਾਂਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਕਮਤ ਨੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ੨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹਾਂ, ਇਕ ਗਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ Divide and Rule ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ । ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਾਵਰ (power) ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ percentage of votes ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗਾਹ ਉਪਰ divide and rule ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਖੀ ਹੈ । ਮਸਲਨ tenants ਨੂੰ landlords ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਵੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ demoralization ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।

[ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ]

ਅਗਲੀ ਗਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ (judiciary) ਨੂੰ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ (executive) ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ judiciary ਵਿਚ Executive ਵਲੋਂ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ interference ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਬਿਲ (Bill) ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਜਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਹੀ ਘਟਾਂ ਵਧਾ ਸਕੇ ਬਲਿਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ judiciary ਅਤੇ Executive ਨੂੰ ਜੁਦਾ ੨ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ judiciary ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ appoint ਕਰਨ ਦਾ ਬਲਕਿ dismiss ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤੀਆਰ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਗਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ Transport ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ nationalization ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ nationalize ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਡੀ (body) ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ (support) ਤੇ finance ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ transport ਨੂੰ nationalize ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ transport ਨੂੰ nationalize ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ nationalize ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਲੋਕਾਂ ਤੇ effect ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਦਾਰਾ nationalize ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਜੇਕਰ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ transport ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ co-operative basis ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ੨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੌ ਸੌ ਹਿਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ families ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ transport ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਡੇ ੨ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੰਦ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ nationalize ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ effect ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ nationalize ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਪ੍ਰੰਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ੨ ਵੀ transport ਨੂੰ nationalize ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਫ਼ੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸਤਾਨ ਵਿਚ transport ਨੂੰ nationalize ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ incharge ਹਨ, ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ

ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਵਲ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Motion of Thanks ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧਨਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ।

श्री देवराज सेठी (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, परसों महामान्य राज्यपाल ने जो अभिभाषण पंजाब विधान मंडल के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में दिया था, उस में ज्यादा ज़ोर इस राज्य की अमन और कानून की स्थिति पर दिया गया था। मैं भी आप के द्वारा अपनी हकूमत की सूचना में इसी विषय से सम्बन्धित हालात लाना चाहता हूं और अपना भाषण अमन और कानून के विषय तक ही सीमित रखूंगा।

जहां तक ज़िला रोहतक का सम्बन्ध है; इस ज़िला की कुछ बातें तो ऐसी हैं जिन के बारे में हाऊस में अर्थात् मनिस्टीरियल पार्टी (Ministerial Party) और विरोधी पार्टी के दरमियान कोई इख्तलाफ़ राये नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पर जिस विषय पर इस सदन में दो राएं नहीं हो सकतीं, वह है वहां की अमन और कानून की स्थिति। इस से पहले कि इस सम्बन्ध में कोई भी बात कहूं, मैं खुले शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि इस हाऊस में अगर कोई ऐसी पार्टी हो जो अमन और कानून को बालाए ताक रख कर तखरीबी कार्यवाही द्वारा इस राज्य में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती हो तो उस के साथ हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता और न ही ऐसी पार्टी या विचारधारा को पनपने या बढ़ने की इजाज़त दी जा सकती है। इस बात से तो सब सहमत होंगे कि अमन और कानून को हर हालत में बनाए रखना हकूमत का पहला फ़र्ज़ है।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो सब से बड़ी और पवित्र हैं, वह है औरतों की इज्ज़त। औरतों की इज्ज़त की रक्षा करने के लिये सारी दुनियां में अनेकों कुर्बानियां हुई हैं और होती रहेंगी। मैं नहीं समझता कि आज अगर विरोधी पक्ष वाले माननीय मेम्बर या दूसरे लोग कोई हकीकी घटना इस प्रकार की सुनें तो चुप बैठे रहें या चैन से इसे बर्दाश्त करते रहें। क्या कोई इस बात का दावा कर सकता है कि हमारे लीडर श्री भीम सेन सच्चर जो कि हमारे सूबे के मुख्य मंत्री हैं, इस प्रकार की बेइज्ज़ती की वारदात को सुनकर बर्दाश्त कर लेंगे? मेरा ख्याल है, स्पीकर साहिब, कि यह एक ऐसा विषय है कि जिस में सब सहमत होंगे कि औरतों की इज्ज़त एक बहुत पवित्र चीज़ है और यदि कोई औरतों की इज्ज़त पर वार करता है तो उसे रोकने के लिये हर तरह की कुर्बानी दी जानी चाहिए।

तीसरी चीज़, अध्यक्ष महोदय, यह है कि काफी देर से रोहतक ज़िले के हालात ग़ैर-मामूली हो रहे थे और हैं। ये हालात ऐसे हुए हैं जिन से हमें बहुत भारी दुःख हुआ है। दर असल, श्रीमान् जी, मेरा ख्याल नहीं कि इस सदन में कोई ऐसा मेम्बर हो जिसे इन ग़ैर-मामूली हालात से और जो घटनाकांड वहां पर हुआ, उस से दुख न हुआ हो। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह से मैं कोई ग़ैर-ज़िम्मेदाराना बात कहूं। लेकिन जो हकीकत है उस से तो हम

[श्री देव राज सेठी]
आंख नहीं मूंद सकते ।

पार्टीशन (Partition) से पहले जो चीज़ें हम सुना करते थे, उन कातो ज़िक्र करना ही व्यर्थ है। लेकिन पिछले सात सालों से जब कि विभाजन के बाद में रोहतक में बसा और वहां का नागरिक बना, तब से मैं देख रहा हूं कि वहां के जो हालात हैं वे ग़ैर-मामूली से कम नहीं कहे जा सकते । मिसाल के तौर पर गांव "अ" में ६,७ या ८ कत्ल हो जाते हैं परन्तु हैरानगी यह है कि वहां पर कातलों पर हाथ उठाने वाला कोई नहीं। आई.जी. पुलिस, (I. G. Police) डी. आई.जी. पुलिस (D. I. G. Police) और सुप्रिंटैण्डैण्ट पुलिस (Superintendent Police) तहकीकात करने जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि कत्ल करने वाला कौन है। वहां दिन दिहाड़े लोगों को लूटा जाता है उन की बेइज्ज़ती की जाती है और आखिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है पर पता नहीं चलता कि लुटेरा कौन है—डाकू कौन है । ऐसी वारदातें होती रही हैं और होती रहेंगी। वहां पर लोगों को किसी प्रकार की कोई safety नहीं—कोई protection नहीं । यह हालात, स्पीकर साहिब, पिछले कई सालों से इतने बढ़ गए हैं कि उन्होंने एक खौफ़नाक सूरत इख्तियार कर ली है। जैसा कि मेरे माननीय दोस्त पंडित श्री राम शर्मा जी ने बताया कि दो अढ़ाई हज़ार के मजमें में से किसी को धकेल कर ले जाया जाता है, उसे दरख्त से लटका कर कत्ल कर दिया जाता है । अगर्चे उस के मुंह पर कोई mask नहीं, हरेक आदमी जानता है, जो मजमे में खड़ा है कि किसने यह हरकत की है लेकिन जब पुलिस जांच करती है तो हरेक के मुंह से यही लफ़्ज़ निकलते हैं कि "मेरे बेरा ना से" यानी मुझे कोई पता नहीं । इसी तरह से दो नाई बेचारों को जो बिलकुल बेकसूर हैं, मारा जाता है। स्पीकर साहिब ! इस ज़ुल्मोसितम की दर्दनाक कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती । बालेड़ एक गांव है । वहां पर एक गरीब शरणार्थी जाता है । उसे भी मार दिया जाता है। इसी तरह के कत्ल दिन रात बढ़ रहे हैं और यह खौफ़नाक तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों ? हो सकता है कि पुलिस के कुछ आदमी ऐसे हों जो ऐसे कातलों से भी ताल्लुक रखते हों और उधर अपनी ड्यूटी भी देते हों ताकि उन पर किसी प्रकार का शक भी न किया जा सके । इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि वहां की जो हालत है वह ग़ैर-मामूली शकल इख्तियार कर चुकी है और इस से इनकार नहीं किया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय ! इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं उस मुगालते को जो कि पिछले दो महीनों की अखबारों की चर्चा से पैदा हो सकता है, भी दूर करना चाहता हूं। वह यह है कि सारे का सारा ज़िला ही lawlessness का शिकार हो गया हो, सो ऐसी बात नहीं । आम जनता बड़ी law abiding है और विशेष कर हमारे पंजाब की जनता तो और भी ज़यादा शान्ति प्रिय है । सभी लोग डाकू हों, सभी लोग राहज़नी करते हों या कि मुख्तलिफ़ जातियों के लोगों—ब्राह्मण, हरिजन वग़ैरा में कोई दुश्मनी हो जिस के नतीजे के तौर पर ऐसी घटनाएं होती हों, ऐसी बात भी नहीं। बात, वास्तव में, यह है कि इस ज़िला के हरेक गांव में दो, चार या छः ऐसे मनचले आदमी हैं जो ऐसी हरकात करते हैं और जिन्होंने लोगों में ऐसा डर और भय फैला रखा है जिस से लोग खौफ़ज़दा रहते हैं । स्पीकर साहिब ! आप जानते हैं कि जो जो तरीके terrorists इस्तेमाल किया करते हैं, वैसे ही तरीके ये लोग वहां पर इस्तेमाल करते हैं।

आखिर वहां पर स्थिति क्या है ? यह कि डाकू वहां पर आते हैं । खेतों में रहते हैं । छः छः हफते वहां रहते हैं । वहां रहते हुए उन्हें सब कुछ मिलता है । एक बाकायदा organised तरीके से उन्हें खाने पीने को मिलता रहता है । खाना पकता है किंतु खाना पकाने वाले को पता नहीं कि वह खाना किस के लिये पका रहा है । उस को केवल इतना ही पता है कि खाना पकाना है । फिर खाना परोस कर गांव से गांव की हद तक ले जाने वाला व्यक्ति कोई और होता है जिसे केवल इतना ही पता होता है कि उसे खाना फुलां २ जगह पर पहुंचाना है । उस के बाद उस खाने को उठाकर उन डाकुओं के पास ले जाने वाला पुरुष या औरत और है । इस प्रकार पंजाब और पैप्सू से सैंकड़ों रुपया, मनों चांदी और सेरों सोना लूट लूट कर बाहर ले जाया जा रहा है । इस तरह, अध्यक्ष महोदय, यह सारे का सारा काला काम हो रहा है । वहां का हर कोई आदमी यह जानता है कि उसके साथ किस बद-इखलाकी का सा सलूक हो रहा है लेकिन उस पर डर की इतनी सख्त और ज़ालिम तलवार लटक रही है कि वह अपना मुंह खोल कर किसी के सामने अपना रोना तक भी नहीं रो सकता । Unlicensed arms जिन के मुताल्लिक आज भी पार्लीमैण्ट्री सैक्रेटरी महोदय ने एक सवाल का जबाव दिया है, का पेशा उसी तरह चल रहा है ।

यह थोड़ी सी बातें, अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सिलसिला में आप के सामने रखी हैं । यह अन्याचार यहीं पर समाप्त नहीं हो जाते । स्पीकर साहिब, यह एक दिल हिला देने वाली और नाकाबले तरदीद सच्चाई है कि वहां कई इतने ज़लील और नैतिकता से गिरे हुए लोग भी मौजूद हैं जो खुद अपनी अपनी बहू बेटियों, लड़कियों और औरतों को उन के पास भेजते थे ! कितनी शरम की बात है !!

अध्यक्ष महोदय ! इस परिस्थिति का जायज़ा लेने के लिये एक दो वकील वहां गए । जो खौफ़नाक हालात वहां पर बर्पा थे, वे उन्होंने मुझे बताया । स्पीकर साहिब, यकीन कीजिए कि मेरा खून खौलने लगा । मैंने फैसला कर लिया कि चाहे सच्चर साहिब से बग़ावत ही क्यों न करनी पड़े मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि लोगों की तकलीफों को दूर नहीं किया जाता और वहां पर अमन और कानून नहीं स्थापित किया जाता । चूनांचे हम पांच मेम्बर लैजिस्लेटिव असैम्बली के और एक दो वकील राबड़े और जागसी गांव में गये । दो तीन घंटे हम वहां रहे । हम चाहते थे कि पुलिस ने जो जो अत्याचार वहां किये थे हमें उनका सही पता लगे । हम यह चाहते हैं कि अगर पुलिस जो कि असली मानों में राज्य की रक्षक है. लोगों और सरकार से विश्वासघात करके खुद उन पर ही अत्याचार करती है तो पुलिस के ऐसे कर्मचारियों को फांसी पर लटका दिया जाये । हम चाहते हैं कि ऐसी विद्रोही कार्यवाहियों में हिस्सा लेने वाले पुलिस अफ़सर को ज़्यादा से ज़्यादा दंड दिया जाये । सो इस मुद्दे से हम वहां गये ताकि असली हालात का जाईज़ा लें और कोई आखिरी राए कायम कर सकें ताकि हम अगला कदम उठा सकें । खैर हम गांव में गये । जितने गांव वाले थे सब को बुलाया और उन से मिले । वहां पर कोई दो सौ आदमियों का मजमा हमारे पास जमा हो गया । हमने उनसे बात चीत की । लोगों को एक एक से अलहदा २ मिले । जब भरे मजमे में उन से कहा गया कि यह तो ठीक है कि पुलिस ने वहां पर काफी action लिया है लेकिन इस सिलसिले में अगर किसी औरत की बेइज्ज़ती की गई हो तो आप वह हमें बताएं ।

[श्री देव राज सेठी]
उन्होंने कहा पहले तो उन की बेइज्जती हो चुकी है और अब सब के सामने बताने पर उन की दुगनी बेइज्जती होती है। उन्होंने हमें कहा कि हम उन के घरों में जाकर सारा हाल खुद मालूम करलें। जब हम ने उन के घरों में जाकर उन की औरतों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन की बेइज्जती की गई है। लेकिन बाद में साफ़ कह दिया कि असल बात यह है कि उन लोगों के पास डाकुओं का आना जाना है और हम से यह बयान दिलाया गया कि हमारी बेइज्जती पुलिस ने की है।

जागसी गांव में हमारी बहन श्रीमती सीता देवी भी गई थीं। उन्होंने भी जा कर अपने तौर पर उन औरतों से enquiry की थी और उन्होंने भी असलियत का पता लगा लिया था। लेकिन, स्पीकर साहिब, मुझे हैरानी के साथ यह कहना पड़ता है कि जो हमारे साथी हमेशा इस काम में सरगरम हिस्सा लेते रहे हैं उन का इखलाकी मियार वहां के लोगों के इखलाक से बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। हमारे पुराने साथी सरदार सोहन सिंह ने भी वहां जा कर पड़ताल की और मैंने भी उन से बात चीत की। मैंने उन की खिदमत में अर्ज़ की कि अगर वह उन बहिनों से जा कर मिलें तो उन को हकीकत का पता लग जायेगा। जो बातें आम तौर पर मशहूर की गई हैं वह ठीक नहीं हैं। मैंने देखा कि जो लोग उन की इमदाद के लिये चले आते थे उन के वहां काफी अरसे से vested interests चले आते थे। सरमायादारों के vested interests होते हैं। वकीलों के होते हैं। उन की वकालत ही तब चल सकती है जब डाके पड़ें, कतल हों और फिर डाकुओं की जमानतें हों। फिर लीडरशिप (leadership) की दूकान भी तब चलती है जब देहात में डर और खौफ़ फैला रहे। लेकिन जब उन को कुछ झंझोड़ा जाए तो शोर किया जाता है।

माननीय स्पीकर साहिब ! जब हमने जांच पड़ताल कर ली तो चौधरी बदलू राम जी ने 250 आदमियों के मजमे में कहा कि वह वहां सारी बातों का पता लगाने आये थे, उन्होंने खुद जा कर औरतों से बातें की हैं और यह वाक्या ग़लत है कि औरतों की बेइज्जती की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि वह वहां सारी रात बैठने को तैयार हैं अगर कोई बेइज्जती वाली उस बात को सच्चा साबत कर सके। उन्हें किसी ने गुमराह किया है। फिर, स्पीकर साहिब, वहां एक refugee रहता था। मैंने उसे अलग ले जा कर पूछा कि असल बात क्या है। क्या पुलिस वालों ने औरतों की बेइज्जती की है ? तो उस ने कहा कि सच्ची बात तो यह है कि पुलिस वालों से मुमकिन है कि कुछ बेगुनाह आदमी मारे गये हों लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है कि औरतों की बेइज्जती की गई है।

स्पीकर साहिब ! मुझे इस चीज़ से दुख होता है कि हकूमत ने दो साल चार साल या पिछले 20 साल से इन हालात को बढ़ने दिया और मजबूती से काम नहीं लिया। गरीब लोग तो कहते हैं कि असल में राज तो आज आया है। उन की औरतों की इज्जत पहले महफूज़ न थी। आज जो कुछ वहां पर किया गया, हालात उस का तकाज़ा करते हैं कि drastic malady demands drastic remedy. हम जब रबड़ा में एक अपने कांग्रेसी साथी से मिले तो उस ने कहा कि वह बेगुनाह पुलिस के हाथों पिट गया है। मैंने उसे अलग ले

जा कर कहा कि उस के पीटे जाने के बारे में चारा जोई की जायेगी बशर्तेकि वह असल बात बताये कि क्या राबड़ा गांव में औरतों के साथ सचमुच कोई इस तरह की बात हुई है। उस ने साफ़ कह दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। फिर, स्पीकर साहिब, हमें रास्ते में रोहतक से आने वाले लम्बरदार और सरपंच मिले तो हमने उन से कहा कि अगर कोई इस तरह का वाक्या हुआ है तो वह हमें ज़रूर बतायें। उन्होंने भी यही बताया कि औरतों की कोई बेइज्ज़ती नहीं की गई। जो जेवर उन से उतारे गये वह ज़ेवर वही थे जो चोरी के थे।

फिर स्वामी जी का ज़िक्र किया गया है। स्पीकर साहिब ! मैंने स्वामी जी का बयान खुद पढ़ा है। उन्होंने यही लिखा है कि दो बहनों की बातों से मालूम होता है कि उन के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है। मगर उन्होंने अपनी कोई observation नहीं दी। मुझे हैरानी है और साथ ही परेशानी भी कि Law and Order के मामले में औरतों की इज्ज़त का सवाल खड़ा कर के किस तरह पालिटिक्स का सवाल बनाया जाता है। जन संघ के प्रधान दिल्ली से भागे आये ताकि जाटों से हमदर्दी दिखा कर उन के दिलों में जनसंघ के लिये कोई जगह बना सकें। हिंदू महासभा के प्रधान भी भागे आये और उन का तो महज़ काम ही यही है कि कांग्रेस को बदनाम किया जावे। उन का तो दृष्टिकोण ही to fish in troubled waters है। कम्युनिस्टों ने भी सोचा कि उन का वहां कोई strong field नहीं बना तो इस से बन जायगा—(*Interruptions*).

Mr. Speaker : The hon. Member need not care for these interruptions. He should go on with his speech.

श्री देव राज सेठी : मैं ने तो यह अर्ज़ करना है कि गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है उस से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। कहीं कहीं कुछ बेगुनाहों के साथ ज़्यादतियां हुई हैं और कहीं third degree methods भी बरते गए हैं लेकिन अगर कहीं ज़्यादती हो रही हो तो वह ज़रूर बन्द होनी चाहिये। इस से किसी को इनकार भी नहीं हो सकता। बाकी रही जुडीशल इनक्वारी (Judicial Enquiry) की बात। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस की कोई आवश्यकता नहीं है। There is no *prima facie* case for a judicial enquiry.

स्पीकर साहिब ! मैं जागसी के बारे में अर्ज़ कर दूं कि अधिकारियों, एम., एल. एज़ और दूसरे ज़िमेवार लोगों ने यही कहा है कि जो कुछ यहां पर हुआ वह बिल्कुल मुनासब था और कि औरतों की बेइज्ज़ती वगैरा की बातें सब बनावटी हैं।

हां, रोहतक में ज़रूर कुछ अफ़सोसनाक बातें हुई। इस का हमें दुख है और इस ओर हमें जल्दी से जल्दी मुनासिब कार्यवाही करनी चाहिये। हमें जज़बात को दूर रख कर मुनासिब तरीके से इसे कामन काज़ (Common Cause) बनाना चाहिये। यही नहीं बल्कि इस स्टेट में रूल आफ़ ला (Rule of Law) कायम करने और एक पायदार हकूमत बनाने के लिये हमें पूरी कोशिश करनी चाहिये (तालियां)।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : स्पीकर साहिब ! आज़ादी से हमने यह आशाएं बांध रखीं थीं कि इसे हासल करने के बाद हमारे मुल्क का मियार ऊंचा हो जायगा और यहां पर एक आज़ाद हकूमत कायम की जायगी जिस से हमारे वतन के लोगों की ज़िन्दगी में सुख आएगा, सब से इन्साफ होगा और सही तौर पर राम राज्य कायम होगा।

[प्रो० मोता सिंह आनन्दपुरी]
महात्मा गांधी की रहनुमाई में अंग्रेज़ों का ज़माना होते हुए भी बहुत कुछ अच्छी बातें हुईं। मिसाल के तौर पर untouchability जैसी anti socia चीज़ को खत्म कर के हरिजनों की regeneration की गई। और भी बहुत अच्छी २ बातें की गई। लेकिन इस आज़ादी के ज़माने में हमारी गर्दनें झुकी हुई हैं और हम अपना मुंह ऊपर नहीं उठा सकते, जैसा कि हमारा हक है। यह देख कर हमें और भी हैरानी होती है कि हकूमत अपनी administrative machinery के नकाइस को छिपाने की कोशिश कर रही है।

मुझे पता है कि हकूमत ने ऐसे भी काम किये हैं जिन पर इसे हम मुबारकबाद देते हैं। अब मैं opposition में हूं लेकिन मेरी नुक्ताचीनी में कोई फर्क नहीं। इसलिये मैं फिर उम्मीद करता हूं कि हम और आप मिल कर कोई सही कदम उठावें। स्पीकर साहिब ! पंजाब की पालिटिक्स में २,३ नकाइस हैं और वह हैं भ्रष्टाचार तथा इस हकूमत में चलने वाली सिफ़ारिशें। जहां हमें law and order की हालत को सुधारना है वहां हमें अपने इखलाक को भी ऊंचा बनाना है। खाह कोई वज़ीर सिफ़ारिश करे या कोई ऐम. ऐल. ए. सर्विसिज़ में इतनी हिम्मत होनी चाहिये कि वह इस सिफ़ारिश पर अमल करने से इनकार कर दें (तालियां)। यदि यह चीज़ हो जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं और मैं समझता हूं कि लोग इलैक्शनज़ (elections) के समय हमारी इन खिदमात की तारीफ़ करेंगे। इस लिये हमें अपनी कमज़ोरियों को छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये।

मुझे बड़ी हैरानी हुई जब एक माननीय मैंबर ने पुलिस की तारीफ़ शुरु कर दी। यदि मेरा कुछ इख्तियार होता तो मैं उसे बिठा देता (तालियां)।

Mr. Speaker: Please do not cast any reflections on any member.

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी: मेरा reflection करने का इरादा नहीं था। मैं आप को एक exceptional Speaker समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यह भी एक reflection ही है।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी: यह जो कांग्रेसमैन (Congressmen) पुलिस की तारीफ़ करते हैं मैं उन से कहता हूं के रोहतक तो क्या वह मेरे साथ जालन्धर चलें। मैं कई बार पुलिस की ऐसी बातें सरकार के नोटिस में ला चुका हूं कि यह फांसी का फंदा उस शख्स के गले में डालते हैं जिस को फिट (fit) बैठे। किसी का कसूर नहीं देखते। मेरे ज़िले में बेशुमार ज़ुल्म हुए, बाज़ीगर कत्ल किये गये लेकिन कोई मुनासिब कार्यवाही नहीं की गई। फर्ज़ी मुजरमों को अदालत में पेश किया गया और असली मुजरमों को छोड़ दिया गया। वह तो मजिस्ट्रेट अच्छा था कि उस ने उन्हें बरी कर दिया। लेकिन पुलिस अफ़सर का हौसला इतना बढ़ा हुआ था कि सब खराबियां उस में थीं। मैं सब कुछ कह सकता हूं लेकिन मेरी कुछ बहनें यहां बैठी हैं इस लिये कुछ न कहूंगा। एक बार मैंने चीफ़ मनिस्टर साहिब की खिदमत में चंद दरखास्तें पेश की थीं। आप वह सारी की सारी दरखास्तें पंडित मूलराज जी के घर छोड़ आए (हंसी) मैंने पूछा तो कहने लगे कि वह वहां रह गई हैं। यह हमारे चीफ़ मनिस्टर की हालत है जिन के लिये मेरे दिल में बहुत इज़्ज़त है। वह इतना काम कर रहे हैं कि उन को पता नहीं कि वह क्या कर रहे हैं और उन की डियूटी क्या है। ला ऐंड आर्डर

(Law and Order) की यह हालत है कि बेपनाह जुल्म हो रहे हैं, womanisation हो रही है। मुझे अफ़सोस होता है कि मैंने अपनी जिन्दगी का एक बड़ा हिस्सा ऐसी सरकार बनाने में लगाया। अगर कोई चीज़ unnoticed हो जाए तो दूसरी बात है, मगर यहां तो सब कुछ खुले बन्दों हो रहा है।

गवर्नर साहिब बड़े अच्छे आदमी हैं। काबिल भी हैं और उन के लिये मेरे दिल में बड़ी इज्ज़त है। उन के thanks सच्चे अलफ़ाज़ में किये जाने चाहियें न कि इन झूठे इलफ़ाज़ में। उन की सही तारीफ़ की जानी चाहिये लेकिन मुझे अफ़सोस है कि वह हो नहीं रही।

मुझे उम्मीद है कि आप सही तजवीज़ पेश करेंगे जिस में मेरी कोआप्रेशन (co-operation) आप के साथ होगी।

फिर, स्पीकर साहिब जहां तक Five-Year Plan का ताल्लुक है हम पर यह इलज़ाम लगाया जाता है कि हम इस की पूर्ती में सरकार को co-operation नहीं देते। यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जहां तक इस का हमारे साथ ताल्लुक है जो co-operation देने की बात है हम आप के साथ हैं। हम आप से जुदा नहीं हैं। हम आप को sincere co-operation देने को तैयार हैं अगर आप सही चीज़ पेश करें।

इस के उपरान्त मैं कुछ और बातें भी कहना चाहता हूं जिन की तरफ़ मेरे दोसतों ने तवज्जुह दिलाई है। ऐसी दो तीन जरूरी बातें हैं जिन का मैं ज़िक्र करूंगा। एक तो Executive को Judiciary से अलग करने का सवाल है। यह ख़याल हमारा बहुत देर से है। हम ने भी कई बार कहा है। कांग्रेस ने भी इस बात पर कई बार ज़ोर दिया है और प्लेटफार्म पर भी कई बार इस सम्बन्ध में कहा गया। मगर एडरेस में जिस तरीके से इस को लाया गया है वह खुशनुमा नहीं है। एडरेस में यह तजवीज पेश की गई है कि हरेक तहसील को सब डवीज़न बना दिया जाए और सब डवीज़नल अफ़सरों के इख्तियारात बढ़ा कर डिप्टी कमिश्नर के कर दिये जायें। इस का मतलब यह बताया गया है कि मुकदमों के फ़ैसला करने का सारा काम Executive के हाथों से निकाल कर Judiciary के सुपुर्द कर दिया जाएगा क्योंकि चीफ़ मनिस्टर साहिब और उन के साथियों ने Judiciary के काम में दखल न देने पर ज़ोर दिया है। मगर मैं तो यह कहता हूं कि कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर सिफारशें न चलती हों। अदालतों में भी सिफ़ारिशें चलती हैं। और यहां पर Public Service Commission कुछ नहीं कर सकता। अब जो Subordinate Services Selection Board बनाया गया है वहां पर भी मनिस्टरों की सिफ़ारिशों का सिलसिला जारी है। मुझे कोई भी ऐसा महकमा दिखाई नहीं देता जहां merit के आधार पर आदमी चुने जाते हों। ऐसे हालात में administration कैसे अच्छा हो सकता है? मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की administration और Judiciary का मियार तब ही ऊंचा हो सकता है जब कि कोई भी सिफ़ारश न की जाए और मैं भी इस पर खुशी का इज़हार करूंगा।

श्रीमान् जी, मुझे न केवल पता ही है बल्कि मेरे पास तहरीरी सबूत मौजूद हैं कि फलां मनिस्टर साहिब ने फलां केस में सिफ़ारिश की है। मैं जानता हूं कि मेरी इन बातों पर चीफ़ मनिस्टर साहिब को दुःख होगा मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह सदाकत पसन्दी की बात

[प्रो० मोता सिंह ग्रानन्दपुरी]
हैं और मेरे पास सबूत हैं। अगर आप कहेंगे तो हाऊस में उन का नाम ही बता दूं। कहो जी बता दूं ?

(आवाजें : जरूर जरूर)

प्रोफैसर मोता सिंह ग्रानन्दपुरी : Justice को कलंकित करने वाले एक Superintendent, Police की रिपोर्ट की गई जिस में एक केस जबर जना का था और दूसरा भी इस तरह के संगीन जुर्म का था। इन दो cases में हमारे मनिस्टर साहिबान ने सिफ़ारिश की। वह मनिस्टर हैं लाला जगत नारायण जी और चौधरी सुन्दर सिंह जी (Shame)। मेरे पास इस की कापी मौजूद है। अगर हमें कहें तो कापी लाकर दिखा दूं (interruptions)।

अध्यक्ष महोदय : (Order, order)

प्रोफैसर मोता सिंह ग्रानन्दपुरी: अगर आप चाहेंगे तो और ज्यादा भी कह सकता हूं। हमने कांग्रेस हाई कमांड के सामने इन की सियाहकारियों का पर्चा रखा था।

Mr. Speaker : What happened outside can not be discussed on the floor of the House.

प्रोफैसर मोता सिंह ग्रानन्दपुरी : श्रीमान् जी, इस बात को छुपा ही रहने देता हूं। यह कोई ऐसा कांड नहीं जिस की तशरीह की जरूरत हो।

फिर मेरे दोस्त ने प्रोजैक्टों का ज़िक्र किया और भाखड़ा का नाम फ़खर से लिया। और यहां पर जो दस मिनट का समय उन को बोलने के लिये दिया गया उस में उन्होंने इसी डैम के बारे में बड़े तमतराक से बताया कि इस से नहरें निकलेंगी और बिजली तैयार की जायगी। मगर मैं पूछता हूं कि इस में फ़खर करने की कौनसी बात है और इस में हमने क्या किया है ? यह तो वे चीजें जो अंग्रेज बना गए हैं और हम से तो इन स्कीमों को चलाया तक भी नहीं जा सकता। इस में हमने कोई नई चीज तैयार नहीं की। तो फिर यह फखर की कौनसी बात है ? (interruptions)

अध्यक्ष महोदय : पांच मिनट और हैं।

प्रोफैसर मोता सिंह ग्रानन्दपुरी: अब मैं उन लोगों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जिन पर सब से ज्यादा जुल्म किये गये हैं और वे हैं Political Sufferers। यह माना गया है कि यह शूरवीरों की जमात है जिस ने आज़ादी की जंग में अपनी जानें दी हैं। इन की विधवाओं और बच्चों के लिये सहायता फंड में सरकार ने तीन लाख रुपये की रकम दी है। और यह भी कहा गया है कि सरकार ने उन को ज़मीनें देने और पैनशनें देने का फ़ैसला भी किया है। यह सब कागज़ी कार्रवाई है और इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। सहायता सिर्फ़ चंद आदमियों को दी गई है और अभी तक उन की एक भारी तादाद ऐसी है जिन को कोई सहायता नहीं मिली।

श्रीमान् जी, जब कांग्रेस की एक sitting के अन्दर यह फ़ैसला किया जा रहा था कि किस किस political sufferers को माली इमदाद दी जाये तो

वहां पर पहले ही बता दिया गया कि देखना श्री राम ग्रुप के किसी ग्रादमी को सहायता न मिल जाए ।

श्रीमान जी, मैं उन विधवा ग्रौरतों के बारे में ग्रर्ज़ करनी चाहता हूं जिन के पास जूता तक नहीं । इन widows के पास एक पैसा तक नहीं । मैंने खुद उन्हें सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में 10-10 ग्रौर 20-20 Registered letters सरकार को भेजे हैं मगर इन की तरफ़ कोई भी ध्यान नहीं देता । क्यों कि They belong to the group of Prof. Mota Singh यह है गवर्नमेंट की narrow-mindedness की हद । मैं गवर्नर साहिब को यहां पर बतलाना चाहता हूं कि वज़ारती बेंचों पर बैठे मेरे दोस्तों ने उन के सामने इस सहायता की सही तसवीर पेश नहीं की है । इन के ग्रन्दर नारदिज़म (Naridism) इस हद तक ग्रा गया है कि बहुत से political sufferers के बच्चे ग्रौर widows ऐसे हैं जिन को ग्रभी तक कोई मदद नहीं दी गई ।

श्रीमान् जी, ग्रगर ग्राप चाहें तो मैं ऐसी मिसालें दे सकता हूं जिन को ग्रभी तक कोई सहायता नहीं मिली है । इन मिसालों में से बबर ग्रकाली लहर के बानी जनरल किशन सिंह को लें । उस ने ग्रपनी जान फांसी के तख्ते पर लटक कर दे दी मगर उस के वारसों को ग्रभी तक कुछ नहीं दिया गया ।

मैं कुछ widows को साथ लेकर लाला जगत नारायण जी के मकान पर गया तो ग्रापने उन की बेबसी को देख कर फ़रमाया कि मैं क्या कर सकता हूं । फार्म (form) नए बन गये हैं । मैं ने ग्रर्ज़ किया कि यह फ़ार्म कई बार तबदील किए जा चुके हैं ग्रौर इन बिचारी widows ने कई बार पुर कर के भेजे हैं मगर ग्रब तो इन के पास Registration fees तक के लिये भी पैसे नहीं रहे । एक तरफ़ तो widows के ऊपर यहां इतना जुल्म हो रहा है ग्रौर दूसरे तरफ़ वहां उन की life एक ideal life मानी जाती है । ऐसी हालत में तीन लाख रुपये की रकम रखने से उन का क्या बन सकता है । ऐसे लोगों का गुज़ारा तो सरकारी फंड से होता है । ग्रगर सरकार इस का इन्तज़ाम नहीं कर सकती तो यह हकूमत ग्रपने हाथ में रखने के काबल नहीं । इस हकूमत को तबदील कर देना चाहिये ।

ग्रध्यक्ष महोदय : ऐसी बातों के लिये ग्राप को ग्रभी बहुत वक्त मिलेगा । कुछ बातें उस समय के लिये रहने दें ।

प्रोफैसर मोता सिंह ग्रानन्दपुरी : ग्रगर ग्राप मुझे कल फिर बोलने का मौका दें तो मैं finish करता हूं ।

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप का समय खत्म हो चुका है ।

प्रो० मोता सिंह : ग्रगर ग्राप कुछ time ग्रौर दें तो मैं एक दो बातें ग्रौर कहनी चाहता हूं ।

Mr. Speaker: No please. The hon. Member's time is over.

श्री मूल चंद जैन (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, इस वक्त जो मोशन (motion) हमारे सामने पेश है इस पर मैंने कुछ तरामीम का नोटिस दे रखा है। उन के बारे में कुछ अर्ज़ करने से पहले मैं आपोज़ीशन (opposition) की कुछ बातों का जवाब देना जरूरी समझता हूं। खास कर जो कुछ पंडित श्री राम शर्मा ने रोहतक के बारे में कहा है। इस सिलसिले में अर्ज़ है कि मेरा गांव सिकन्दरपुर माजरा है जो रखड़ा से आध मील के फ़ासले पर है। मेरे भाई और उन की family सब वहीं रहते हैं। रखड़ा के बहुत से आदमी मुझे जानते हैं। अगर रखड़ा में वह सब कुछ हुआ होता जो उन्होंने कहा है तो वह लोग मुझे ज़रूर बुलाते या मेरे पास आते कि चल कर देखो वहां क्या हो रहा है। लेकिन कोई भी यह बताने नहीं आया कि वहां इतना जुल्म हो रहा है।

जागसी मेरे गांव से दस मील के फ़ासले पर है। मैं वहां जा चुका हूं। पंडित श्री राम शर्मा ने कहा है कि अगर उन लोगों के ख्यालात मालूम करने हैं तो वहां इलेकशन कराके देख लो। मैं अर्ज़ करता हूं कि जागसी के साथ ही सफ़ेदों के हलके से अभी अभी पैप्सू के इलेकशन हुए हैं और वहां हमारे उम्मीदवार ने चौधरी इन्द्र सिंह को सात हजार वोट ज्यादा ले कर हरा दिया है (सरकारी बंचों से तालियां) वहां भी यही औरतों पर जुल्म की दुहाई मचाई गई थी। पंडित श्री राम वहां बीस तीस गांव में गये और लोगों से कहा कि तुम्हारी बहू बेटियों के साथ यह सुलूक हुआ है जाओ पैपसू में जाकर कांग्रेस के खिलाफ काम करो। और जनाब उस का जो नतीजा हुआ वह आप के सामने है। मेरे दोस्त जिन्होंने floor cross किया यह फ़रमाते हैं कि इलेकशन कराके देखो। मैं अर्ज़ करता हूं कि जब floor cross किया जाये तो इसतीफ़ा दे देना चाहिये। आप इसतीफ़ा दे दीजिये। खुद ही इलैक्शन हो जायगी (तालियां) असल बात यह है कि जैसा कि मेरे दोस्त श्री देव राज सेठी जी ने कहा है अब ऐसी हालत सुधर गई है कि गरीबों ने सुख का सांस लिया है। पहले वह लोग हमें ताने देते थे कि तुम्हारी धोती पोशों की हकूमत में हमारा यह हाल हो रहा है। मगर अब उन्होंने सुख का सांस लिया है। खैर जनाब, सफ़ेदों के हलके का नतीजा सब के सामने है। और सफीदों का हल्का जागसी गांव से दो मील पर शुरु हो जाता है। और हम रोहतक जिले में भी चुनाव चलेंज कबूल करते हैं।

अब मैं अपनी तरामीम की तरफ़ आता हूं। लेकिन पहले यह अर्ज़ कर दूं कि हमारी सरकार ने कई ऐसे काम किये हैं जिन की हर तरफ़ बड़ी वाहवाह हो रही है। मिसाल के तौर पर इशतमाल अराज़ी के बारे में हमारे पंजाब का काम सारे मुल्क में बहुत ही शानदार है। इस काम के लिये और इस महकमे से corruption को दूर करने के लिये मैं सरदार प्रताप सिंह जी को मुबारकबाद देता हूं। दूसरा शानदार काम पंचायतों का कानून है। मैंने एक अखबार में बम्बई के पंचायत कानून का ज़िक्र देखा तो पहले यह ख्याल हुआ कि वह बड़ी progressive स्टेट है इसलिये उन का कानून बहुत अच्छा होगा। लेकिन ग़ौर से देखने पर मालूम हुआ कि हमारा पंचायती तरीका बहुत अच्छा है (Hear, hear)। वहां दो हज़ार की आबादी वाले गांव के लिये पंचायत है इस से कम के लिये नहीं। लेकिन हमारे यहां दो चार गांव के सिवा जिन के बारे में यह फ़ैसला करना है कि वहां पंचायत हो या टाऊन कमेटी बनानी चाहिये बाकी सब गांवों में पंचायत बन गई है। इस के

अलावा मालगुज़ारी का दसवां हिस्सा पंचायतों को दे दिया गया है और यह हमारी मौजूदा मनिस्टरी का बहुत बड़ा कारनामा है। इस सिलसिले में यह बात भी कह दूं कि पिछले कानून में हरिजनों को reservation के लिये कुछ कमी रह गई थी। मगर ज्यों ही उस का इल्म हुआ पिछले अक्तूबर सेशन (Session) में वह नुकस दूर कर दिया गया। आबादी में भी दस की जगह पांच फी सदी की शर्त कर के उन को मुनासिब रियायत दे दी गई है। फिर शामिलात ज़मीनों के बारे में जो कानून बनाया गया उस की सब तारीफ़ कर रहे हैं। पहले एक तबका दूसरे पर बहुत जुल्म और सख्ती किया करता था। हरिजनों और ग़रीब विसवेदारों का बाईकाट किया जाता था। मगर अब पंचायतें मालिक हो गई हैं। इस बारे में मैं अपनी तरमीमों पर बहस करते हुए कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन यह बात साफ़ है कि अब उन लोगों पर जुल्म न हो सकेगा। वह शामिलात में इतने ही हिस्सेदार हो गये हैं जितने कि और लोग।

इस के उपरान्त चीज है Subordinate Services Selection Board का कायम करना। सब जानते हैं कि पहले थोड़ी तनखाह वालों की भरती का इख्तियार महकमों के अफ़सरों और सेक्रेटरियों को होता था। इस में आम लोगों को कई किस्म की शिकायतें थीं। मसलन यह कि जिन लोगों की सिफ़ारिश वगैरा न हो उन को कोई मौका न मिलता था। अब बोर्ड बन गया है और एक मशहूर और ईमानदार सज्जन को उसका chairman लगाया गया है। यह बोर्ड सारे मुल्क में अपनी मिसाल आप है। भारत की किसी और स्टेट में ऐसा कदम नहीं उठाया गया।

और भी बहुत सी अच्छी बातें इस सरकार ने की हैं। लेकिन अब मैं अपनी तरमीम की तरफ़ आता हूं। आप जानते हैं कि सियासी आज़ादी के बाद मुल्क में आर्थिक और सामाजिक आज़ादी लाना कितना जरूरी है। इस के लिये हमारे मुल्क में एक peaceful revolution जारी है। सारी दुनियां की आंखें हिंदुस्तान की तरफ़ लगी हुई हैं कि इसे peaceful इनकिलाब में कामयाबी होनी है या खूनी इनकिलाब ही इस की आर्थिक और सामाजिक आज़ादी के लिये जरूरी होगा। आर्थिक आज़ादी आयेगी ज़रूर। मगर कैसे ? सवाल यह है !

मैं मंत्रियों और तमाम बड़े अफ़सरों को हमेशा कहता रहता हूं और उन्हें लिखता भी हूं कि जिस कदर हो सके पुर अमन आर्थिक और सामाजिक इनकिलाब लाने के लिये तेज़ से तेज कदम उठायें जायें। मेरी सब की सब 12 तरमीमों का मतलब यही है कि यह इनकिलाब लाया जाये। इस इनकिलाब के बगैर राम राज्य नहीं आ सकता। मैं तो कहूंगा कि सरकार के पास कोई गज या कसौटी होनी चाहिये जिस से पता चल सके कि हम राम राज्य के कितने नज़दीक आ चुके हैं। राम राज्य हमारा निशाना है और अगर हम इस के नज़दीक नहीं आ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि हम कुछ भी achieve नहीं कर रहे।

स्पीकर साहिब! मेरी एक तरमीम सरकार का ध्यान बेरोज़गारी और कम रोज़गारी की तरफ़ दिलाती है। इस सभा के तमाम सदस्य जानते हैं कि हमारे नौजवान यूनीवर्सिटी के इम्तहान पास करके बेकार फिरते हैं। उन्हें रोज़गार के लिये कोई काम नहीं मिलता। मैं जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार बेरोज़गारी दूर करने के लिये क्या कुछ कर रही है। अगर Chief

[श्री मूल चन्द जैन]

Minister साहिब अपने जवाब में इस बारे कुछ रोशनी डालें तो मैं बहुत मशकूर हूंगा। मुझे अफ़सोस है कि गो बेरोज़गारी दूर करने के लिये technical और training institutions में हर साल इज़ाफ़ा होना चाहिये, लेकिन पिछले साल एक भी ऐसी institution का इज़ाफ़ा तक नहीं किया गया।

मेरी एक तरमीम यह है कि गरीब मुज़ारों और मज़दूरों को ससता कर्ज़ा देना चाहिये। इन गरीबों को credit इस लिये नहीं दिया जाता क्योंकि यह security नहीं दे सकते। इन्हें कहा जाता है कि तुम co-operative societies बनाओ। लेकिन इन्हें ज्यादा credit नहीं दिया जाता क्योंकि security देने के लिये इन के पास जायदाद नहीं होती। हां हमारी constitution में तो लिख दिया गया है कि सब को equal opportunity दी जायेगी। परन्तु यह equal opportunity है कहां? किसी के पास दस दस मकान और हज़ारों बीघे ज़मीन है और किसी के पास कुछ भी नहीं और फिर वह गरीब कर्ज़ा मांगें तो कर्ज़ा भी नहीं मिलता।

एक और बात जिस पर मैंने बहुत ग़ौर किया है यह है कि हमारे अफ़सरान की mentality pro-rich है। मैं यह नहीं कहता कि उन में कोई भी pro-poor नहीं। नहीं, कई pro-poor भी हैं। इस में शक नहीं कि हमारी administration दूसरे सूबों की administration से मसलिन U.P., Delhi, Pepsu की administration से कहीं अच्छी है। हमारी पुलिस, Revenue Department और मजिस्ट्रेसी (Magistracy) वग़ैरा दूसरे सूबों से बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस का यह मतलब नहीं कि हम अपनी कमज़ोरियां दूर न करें। कई बार देखा गया है कि जब अमीर का गरीब से मुकाबला होता है तो अफ़सरान अमीर की हिमायत करते हैं। कोई यह कहे कि अमीर लोग जुर्म करते ही नहीं। यह कैसे हो सकता है। I refuse to admit this thing। मैं प्रार्थना करता हूं कि अफ़सरों की तवज्जुह इस बात की तरफ़ दिलाई जाये और उन्हें कहा जाये कि वे गरीबों से कुछ हमदर्दी किया करें। जब कभी गरीब मुज़ारों का ज़मींदारों से झगड़ा हो जाता है तो मुज़ारों की रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती। अगर लिखी जाती है तो दोनों फ़रीकों को 107/151 के अधीन गिरफ्तार कर लिया जाता है हालांकि गरीब मुज़ारे को जबरदस्ती बेदखल करने की मालिक कोशिश करता है। यह ठीक नहीं। पुलिस को तफ़तीश करनी चाहिये और जो शख्स aggressor हो केवल उसे ही गिरफ़्तार करना चाहिये।

मुझे एक बात और कहनी है। हमारी सरकार ने शामिलात का कानून तो पास कर दिया है। इस बात को दो महीने हो गये हैं। लेकिन इस पर अमल करने के लिये छोटे अफ़सरों को अभी तक हिदायतें जारी नहीं की गई हैं। इसी तरह कई कानून पास होते रहते हैं लेकिन कितनी कितनी देर instructions issue नहीं होतीं। जब हम जाकर ज़िला अफ़सरों से पूछते हैं कि उन कानूनों पर जो पास हो गये हैं अमल क्यों नहीं होता तो वे यही कहते हैं कि उनके पास बड़े अफ़सरों की तरफ से instructions नहीं पहुंची। ऐसा नहीं होना चाहिये। कानून के पास होते ही हिदायतें जारी हो जानी चाहिये!

स्पीकर साहिब ! मैं अपनी इन तजवीजों के साथ गवर्नर साहिब का उन के address के लिये शुकरिया अदा करता हूं ।

The Assembly then adjourned till 2 p.m. on Thursday, the 11th March **1954.**

85 PSLA—283—27-7-54—CP and S., Pb., Chandigarh

Spare Copies

Punjab Legislative Assembly Debates

11th March, 1954.

VOL. I—No. 3

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, 11th March, 1954.

CHANDIGARH

Printed by the Controller, Printing and Stationery, Punjab

1954

Price : -/7/-

PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY

Thursday, 11th March 1954.

The Assembly met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital, at 2 p. m. of the Clock.

Mr. Speaker (Dr. Satyapal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

ELECTIONS OF PANCHAYATS IN AMRITSAR DISTRICT.

*2488. **Sardar Darshan Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the elections of Panchayats in village Khara, Police Station Sarhali, District Amritsar, scheduled to be held on 9th and 10th August 1953, were held on the said dates; if not, the reasons therefor ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): The required information is being collected and will be supplied to the member when ready.

INQUIRY REGARDING THE FINANCIAL POSITION OF GOVERNMENT SERVANTS.

*2506. **Shri Babu Dayal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government has made any inquiry into the financial condition of Government servants at the time of their joining the services and now; if not, whether it intends doing so as a step towards eradicating corruption in the State ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : Government are not making any inquiry into the financial condition of Government servants at the time of joining the services, and do not propose to do so. It is, however, proposed to make provision in the draft Government Servants Conduct Rules, 1953, requiring the Government servants to make declaration of their movable property from time to time.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या गवर्नमेंट को इस बात का इल्म है कि रिश्वत को रोकने के लिये जिन दूसरी प्रान्तीय सरकारों ने कदम उठाये हैं उन्होंने यह प्रबन्ध किया है कि जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में लिया जाये तो उस वक्त उस की माली हालत का जायज़ा लिया जाये ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने भी इस तरफ़ ध्यान दिया है ?

चीफ़ पार्लीयामेंटरी सैक्रेटरी : हमें दूसरी प्रान्तीय सरकारों के नियमों का तो पता नहीं । लेकिन जहां तक हमारी सरकार का सम्बन्ध है हमने यह हिदायतें जारी की हैं कि सरकारी कर्मचारी की ग़ैर-मनकूला जायदाद का जायज़ा समय समय पर लिया जाये ताकि सरकार को पता लग सके कि किसी सरकारी कर्मचारी ने कितना रुपया इकट्ठा कर लिया है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या गवर्नमेण्ट सरकारी कर्मचारी की ग़ैर-मनकूला जायदाद का जायज़ा शुरू में न ले कर उस के सरकारी नौकरी में दाखिल होने के बाद लेना शुरू करती है ?

चीफ़ पार्लीयामेंटरी सैक्रेटरी : ऐसे कोई नियम नहीं कि उस की जायदाद का जायज़ा शुरू में ही लिया जाये और न ही ऐसे नियम बनाने का सरकार का कोई इरादा है । गवर्नमेंट पूरी इत्तलाह रखने के लिये यह ज़रूरी समझती है कि सरकारी कर्मचारी की जायदाद के बारे में जायज़ा कभी कभी ले लिया जाये ।

पंडित श्री राम शर्मा : चीफ़ पार्लीयामेंटरी सैक्रेटरी ने बताया है कि गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारियों की गैर-मनकूला जायदाद का जायज़ा समय समय पर लेती है । मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट किसी सरकारी कर्मचारी की जायदाद का जायज़ा उस के मुलाज़मत में दाखल होते वक्त क्यों नहीं लेती ?

Mr. Speaker : I do not think you can have any other answer. Government is not prepared to agree to make an enquiry into the financial condition of Government servants and it is up to it to decide whether it wants to hold an enquiry or not.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं पूछता हूं क्यों ?

POLICE EXCESSES IN DISTRICT ROHTAK.

***2616. Sardar Chanan Singh Dhut :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Special Police carried out 'Anti-Dacoit Operations' in certain villages of District Rohtak during the month of January 1954; if so, the names of the villages raided in this connection together with the number of dacoits arrested;

(b) whether he received any joint representation, dated 27th January 1954, from Babu Anand Swaroop and Shri Partap Singh Dolta, Advocates of Rohtak, in which they had brought to his notice the excesses committed by the Police against innocent people during the operations referred to in part (a) above; if so, the action, if any, taken by the Government thereon;

(c) whether the Government has decided to hold any enquiry into the police excesses referred to above ?

Shri Prabodh Chandra (Parliamentary Secretary) : (a) Operations for the arrest of dangerous out-laws were carried out in villages Kheri, Dehia, Bhatgaon, Salimsar, Majra, Gohna, Rattangarh, Tehiar, Ghari Haqiqat, Jaji, Mohana, Rohat Badhana Karaoi, Jharoti, Lehrana, Mahipur, Biarpur, Murthal Machri, Khazarpur, Barwasni Bhagon, Rajpur Juan, Pinan, Shikhupura, Shehtira Bahadarpur, Jetheri, Bhandrauli, Karwali, Khanda, Sehai, Roorki, Puloongi, Lath, Bhainswal, Barota, Chhachrana, Mundlana, Garhwal, Jagsi, Bhawar, Randhana, Kahni, Jauli, Rabra, Sohiti, Baliana, Kherawar Mandothi, Chuliana, Farmana, Bidhlan, Susana, Garhi, Kansala, Rédhan, Sehri Morkheri, Jasrana, Rana Kheri, Ismaila, Kharar, Chhara, Geharawar, Nidhana, Balamba, Mokhra, Chiri, Makrauli, Jassian, Jatauli, Daleh, Kaloi and Rabra in the Rohtak District during the month of January 1954. As a result of these nine dacoits or robbers were arrested and two were killed in encounters with the Police.

(b) Yes, Government had the allegations inquired into by Senior Officers, including the Deputy Inspector-General of Police, Ambala Range, Deputy Commissioner and Superintendent of Police, on the spot. These officers visited the villages concerned, held open and careful enquiry and found the allegations quite baseless and wrong.

(c) Does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਇਹ ਸਚ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਆਦਮੀ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ?

चीफ़ पार्लीयामेंटरी सैक्रेटरी : अगर आप नोटिस दें तो बता दिया जायेगा ।

सिंचाई मंत्री : जी हां । गिरफ्तार कर लिये गये हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : यह जो 'Anti-Dacoit Operations किये गये हैं उन का incharge कौन सा अफ़सर था ?

चीफ़ पार्लीयामेंटरी सैक्रेटरी : इन्स्पैक्टर से ऊपर की rank का अफ़सर इन operations का incharge था ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या माननीय चीफ़ पार्लीयामैंटरी सैक्रेटरी बतायेंगे कि इन operations का सब से बड़ा अफ़सर कौन था ?

Chief Parliamentary Secretaay : D. I. G., Ambala Range.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं माननीय चीफ़ पार्लीयामेंटरी सैक्रेटरी से पूछना चाहता हूं कि क्या डिप्टी कमिश्नर या दूसरे अफ़सरों ने मौका पर जाकर कोई तहकीकात की और जो representation बाबू आनन्द स्वरूप और श्री प्रताप सिंह ने दिया उस के पेशे नज़र सरकार ने कोई तहकीकात करवाई ?

चीफ़ पार्लीयामेंटरी सैक्रेटरी : गवर्नमेंट के पास जो representation आया उस के बारे में तहकीकात की गई लेकिन उस में जो allegations किये गये हैं वह बिल्कुल ग़लत और बेबुनयाद हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या इन दो आदमियों के अलावा किसी और व्यक्ति ने भी सरकार के पास कोई representation भेजा ?

Mr. Speaker : It does not arise.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं गुज़ारिश करना चाहता हूं कि चीफ़ पार्लीयामैंटरी सैक्रेटरी ने कहा कि न सिर्फ़ इन लोगों ने बल्कि और लोगों ने भी representation भेजे थे तो मैं पूछता हूं कि............

Mr. Speaker : It does not follow from the original question.

पंडित श्री राम शर्मा : चीफ़ पार्लीयामैंटरी सैक्रेटरी ने बताया है कि यह representation मौसूल होने पर डिप्टी कमिश्नर और दूसरे अफ़सर मौका पर तहकीकात करने गये और यह भी बताया कि इस representation के अलावा और भी representations गवर्नमेंट के पास पहुंचे । इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि इन के अलावा और किन लोगों ने representation भेजे ?

Mr. Speaker : I don't think he will repeat the mistake.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं पूछना चाहता हूं कि जब बाबू आनन्द स्वरूप और श्री प्रताप सिंह दोलता का representation गवर्नमेंट के पास पहुंचा तो क्या डिप्टी कमिश्नर ने मौके पर जा कर तहकीकात की ? जैसा कि आम कायदा है कि शिकायत करने वाले तहकीकात करने वाले अफ़सरों को पहले से आगाह कर देते हैं.........

Mr. Speaker : A supplementary question does not need a speech to support it.

Chief Parliamentry Secretary : What is his supplementary question, Sir.

Mr. Speaker : He only wants to know whether these gentlemen were informed that the Government was going to make an enquiry regarding the report submitted by them. He has not got the information whether these people were informed.

चीफ़ पार्लीयामेंटरी सैक्रेटरी : जो ज़ाबता के मुताबिक रिवाज है उन्हें ज़रूर बताया गया होगा ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ controversial ਬਣ ਚੁਕਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : यह बात आप की शान के शायां नहीं है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या चीफ़ पार्लीयामेंट्री सैक्रेटरी बतायेंगे कि गवर्नमेंट ने जो तहक़ीकात कराई उस में कितने आदमी बुलाए गये थे ?

Mr. Speaker : May I know how does this arise from the main question ? What is asked therein is whether the Government has decided to hold an enquiry ?

पंडित श्री राम शर्मा : In part (b) it has been asked whether the Chief Minister received any joint representation, dated the 27th January 1954; and if so, the action taken thereon ? इस के जवाब में उन्होंने बताया है कि डिप्टी कमिश्नर मौका पर गये और तहक़ीकात की । मैं पूछना चाहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर ने किस तरह तहक़ीकात की ? क्या गवर्नमेंट के पास इस बारे में कोई तफ़सीलात मौजूद हैं कि किस तारीख़ को उन्हें बुलाया गया और क्या मौका दिया गया ?

चीफ़ पार्लीयामेंटरी सैक्रेटरी : इस सम्बन्ध में अगर आप नोटिस दें तो तफ़सीलात बताई जा सकती हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि किस तारीख़ को और किन किन को पकड़ा गया था ?

चीफ़ पार्लीयामेंटरी सैक्रेटरी : आप नोटिस दें तो जवाब दे दिया जायेगा ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या हर सवाल का जवाब बस इन्हीं अलफ़ाज़ में दिया जायेगा ?

श्री वधावा राम : क्या उन दो आदमियों का जो गिरफ्तार किये गये हैं, यह कसूर है कि उन्होंने शिकायत की थी ?

पंडित श्री राम शर्मा : क्या उन दो आदमियों का जो पकड़े गये हैं यह कसूर था कि उन्होंने representation की थी ?

श्री सिरी चंद : प्रश्न में number of dacoits arrested पूछा गया है। इस का कोई जवाब नहीं दिया है ।

Chief Parliamentary Secretary : As a result of anti-dacoit operations, 9 dacoits and robbers were arrested and two were killed in encounters with the police.

ਸਰਦਾਰ ਰੰਗਨ ਸਿੰਘ ਪੁਤ : ਇਹਨਾਂ operatoin ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀ arrest ਹੋਏ ਸਨ?

चीफ़ पार्लीयामैंटरी सैक्रेटरी : इस के लिये नोटिस चाहिये ।

पंडित श्री राम शर्मा : इन 9 dacoits की arrest इन operations में हुई थी या उन से पहले और बाद में भी हुई थी ?

चीफ़ पार्लीयामैंटरी सैक्रेटरी : यह dacoit इन ही anti-dacoit-operations में पकड़े गये थे ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह 9 dacoits उन ५० गांवों में से पकड़े गये थे जो फ़हरिस्त में बताये गये हैं ?

चीफ़ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : यह डाकू किये गये operations में पकड़े गये थे ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या आप उन के नाम बतायेंगे ?

Minister for Irrigation : It is not in public interest to give this information.

CASES OF ABDUCTION AND KIDNAPPING IN THE STATE.

*2685. **Shri Ram Kishan** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of women and children abducted and kidnapped in the State during the years 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 and 1953, respectively, together with the reasons therefor in each case;

(b) the steps, if any, taken by the Government for the recovery of women and children referred to in part (a) above and the number so far recovered ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : The information in respect of this question is being collected and will be supplied to the member shortly.

PERSONS CALLED FOR INTEROGATION IN ROHTAK DISTRICT.

*2695. **Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that besides several arrests a very large number of suspected persons were called and kept at the police stations and police posts for purposes of interrogation during the recent Anti-dacoit Operations in Rohtak District;

(b) the approximate number of such persons and particularly women, Thana-wise;

[Pandit Shri Ram Sharma]

(c) whether the arrested persons so called and kept in police stations for interrogation were also given a beating;

(d) whether Chander, son of Harphool, Brahman of Ladhaut, Police Station Rohtak Sadr, Surat Singh Jat, Congress Worker of Chhara, Chandgi Ram Panch, Gopal Singh Ex-Sarpanch, Village Ladrawan, Police Station Bahadurgarh, were amongst the persons referred to in part (c) above ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : Information in respect of this question is being collected and will be supplied to the member shortly.

POLICE EXCESSES AT VILLAGE JAGSI, DISTRICT ROHTAK.

***2696. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of arrests made from Village Jagsi, Police Station Barauda, District Rohtak, of persons suspected of harbouring dacoits together with the steps taken by the Government to prevent proclaimed offenders being harboured in future;

(b) whether he is aware of the fact that persons suspected of harbouring proclaimed offenders in the village referred to in part (a) above were given a shoe-beating mercilessly on their naked buttocks by the Police during the recent Anti-Dacoity Operations; if so, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that after the people of the said village were gathered at one place, they were indiscriminatley slapped, kicked and caned by the Police; if so, why ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) 12 arrests were made in this connection. A Police Guard has been posted in the village to keep a watch on the activities of the harbourers. Special Mobile Squads have also been posted to patrol the areas and villages suspected of harbouring P.Os.

(b) This information is incorrect.

(c) This information is incorrect.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या में दरियाफ़्त कर सकता हूं कि यह जो (parts b) और (c) के जवाब में कहा गया है कि यह बातें incorrect हैं यह किस अफ़सर की इत्तला पर जवाब दिया गया है ?

चीफ़ पार्लीयामैंटरी सैक्रेटरी : यह सरकार की इत्तलाह है ।

Mr. Speaker : He is not bound to give that information. He cannot go beyond the answer already given.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह बात कि उन लोगों को बेपरदा करके पीटा गया ग़लत है या सब कुछ ग़लत है ?

ANTI-DACOIT OPERATIONS IN ROHTAK DISTRICT.

***2697. Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Deputy Inspector-General of Police, Ambala Range, himself directed on the spot Anti-Dacoit Operations in Rohtak District and prescribed to the police a uniform pattern to be adopted in these operations; if so, the nature of instructions given by him in the matter;

(b) whether it is also a fact that the services of hundreds of P.A.P. men were utilised in these operations; if so, the exact number of force so employed;

(c) what other forces besides the local police were utilised by the Government for these operations ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) Yes. The Deputy Inspector-General of Police, Ambala Range, did personally direct the anti-dacoity operations in the Rohtak District during december 1953 and January 1954. The affected areas of the district were divided into five sectors and each sector was placed under the supervision of a Gazetted Officer or an Inspector-Each. Sector Commander was also given additional police force for purposes of the operation. Each Sector Commander was directed to personally supervise the operations. The houses of harbourers were to be searched and raids to be carried out according to intelligence available regarding Hem Raj Gang. They were also directed to collect information regarding illicit weapons and recover the same as well as create reliable informers for the liquidation of Hem Raj Gang.

(b) The following Punjab Armed Police Reserves were utilised in connection with operations against Hem Raj Gang in Rohtak District :—

		S.I.s	A.S.I.s	H.C.s	F.C.s
(i) Foot Reserves	..	3	1	6	84
(ii) Mounted Reserves	..	..	1	2	26
Total	..	3	2	8	110

(c) Besides the above Punjab Armed Police Reserves and the Local Police, four Reserves each of 1 S.I., 2 H. C.s and 25 F. C.s of the Jullundur Range were utilised in these operations from 14th February to 9th March.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं यह दरियाफ़्त कर सकता हूं कि D. I. G. Police ने खुद इस operation को carry out करने के लिये direct किया था ? मेरा मतलब यह है कि इस सिलसिले में उन्होंने किसी खास किस्म की हिदायतें दी थीं या कि यह काम पुलिस वालों की मर्जी पर छोड़ दिया गया था ?

चीफ़ पार्लीयामेंटरी सैक्रेटरी : यह कारंवाई सारी D.I.G. Police के हुक्म के मातहत हुई है ।

पंडित श्री राम शर्मा : तो क्या यह सारी कारंवाई ऐन उन की हिदायत के अनुसार हुई हैं या कुछ कम या ज्यादा ?

चीफ़ पार्लीयामेंटरी सैक्रेटरी : महकमें का जो incharge officer होता है सब काम उस के हुक्म के ऐन मुताबिक होते हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਡਾਕੂ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ?

Chief Parliamentary Secretary : You know better.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

पंडित श्री राम शर्मा : जब सरकार की तरफ़ से यह उत्तर दिया गया है कि जो कुछ हुआ वह सब D.I.G. Police के हुक्म के मातहत हुआ तो क्या मैं जान सकता हूं कि उन का हुक्म किसी ख़ास तरीका का था या कि यही कि जा कर गांव को घेर लिया जाये और तलाशी ली जाए ? अगर कुछ और था तो वह क्या था ?

Chief Parliamentary Secretary : It is not in the public interest to divulge those instructions.

PROSECUTION OF SARDAR SADHU SINGH AND SARDAR PALLA SINGH, SUB-INSPECTORS OF POLICE.

***2707. Sardar Harkishan Singh Surjit** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Sub-Inspectors of Police Sadhu Singh and Palla Singh are being prosecuted under section 302/342, at Ambala;

(b) whether it is also a fact that the said Sardar Sadhu Singh was transferred from Police Station Mullana and ordered to remain in Police Lines till the decision of the case in the court;

(c) whether he is aware of the fact that the said Sadhu Singh has recently been posted as Sub-Inspector, C.I.A.;

(d) whether the Government has received any complaints to the effect that Sardar Sadhu Singh is using his position to interfere in the case referred to in part (a) above and harass the witnesses;

(e) if the replies to parts (a), (b), (c) and (d) above be in the affirmative, the action Government proposes to take in the matter ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) S.I. Palla Singh is being prosecuted u/s 302, I.P.C. and S.I. Sadhu Singh u/s 342, I.P.C., at Ambala Cantt. on the basis of a criminal complaint filed by Shri Ram Sarup, son of Nand Ram, Brahmin of Village Jaspur, Tehsil Naraingarh, District Ambala.

(b) S.I. Sadhu Singh was transferred from Police Station Mullana to Police Lines on 6th June 1953, but he was not ordered to remain there till the decision of the case in the court.

(c) S.I. Sadhu Singh was posted as Sub-Inspector, C.I.A. Headquarters, on 19th October 1953.

(d) Yes. Two applications, one addressed to the Chief Minister and the other to the District Magistrate, Ambala, were received. These were enquired into and the Enquiry Officer, after making sifting enquiries, came to the conclusion that the allegations made by the applicants were false, baseless and obviously levelled only to harass the Sub-Inspector in his defence.

(e) Does not arise.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि कोई केस इस पुलिस अफ़सर के विरुद्ध दर्ज किया गया था और अदालत में पेश हुआ था ? और अगर हुआ था तो उस का क्या परिणाम निकला था ?

Chief Parliamentary Secretary : They are being prosecuted and the case is before the court.

पंडित श्री राम शर्मा : जब किसी सरकारी मुलाज़म के खिलाफ़ अदालत में मुकद्दमा चल रहा हो तो उस के बारे में यह कह देना कि वह case baseless है तो क्या यह contempt of court नहीं है ?

Mr. Speaker : But why is the hon. Member so anxious to protect the Government from any action that the court might take against it ?

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब हम चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले । मैं पूछना चाहता हूं जब गवर्नमेंट मानती है कि इस के खिलाफ़ ३०२ दफ़ा के मातहत मुकदमा चल रहा है तो इस अफ़सर को जमानत पर रिहा किया गया है या बगैर जमानत के ?

चीफ़ पार्लीयामैंटरी सैक्रेटरी : यह अदालत का काम है । Government has nothing to do with it.

Mr. Speaker : If you have information, you may give it. If a man is being prosecuted, why should he be allowed to hold any office ? This is exactly what he wants to know.

चीफ़ पार्लीयामेंटरी सैक्रेटरी : सिर्फ़ मुकदमा चलने से ही तो कोई culprit नहीं बन जाता ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ C. I. A. ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕ Investigating Agency ਹੈ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਹ ਆਪ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਉਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ?

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬਰਾਂਚ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

पंडित श्री राम शर्मा : यह हमारी सरकार की आम प्रैकटिस है कि जिस के विरुद्ध कोई केस होता है उस को C.I.D. में भेज दिया जाता है।

Mr. Speaker : No, disallowed. The hon. Member should not make any insinuation.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है कि किस प्रकार की पालिसी इख्तियार की जा रही है इस का जवाब दे ?

Mr. Speaker : The hon. Member cannot ask through this question what the policy of the Government is.

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब मैं जानना चाहता हूं कि इस अफ़सर में क्या सिफ़त है कि उस को C.I.A. में लगाया गया है फिर उस को किस कानून के मातहत वहां लगाया गया है ?

चीफ़ पार्लीयामेंटरी सैक्रेटरी : उस को उसी कानून के मातहत लगाया गया है जो कि उन की अपनी सरकार के वक्त में लागू था।

Mr. Speaker : The Chief Parliamentary Secretary should not raise personal questions ?

पंडित श्री राम शर्मा : वह ऐसी बातें कहे बिना नहीं रह सकते।

Mr. Speaker : No please. I cannot allow this.

पंडित श्री राम शर्मा : C.I.A. का महकमा पुराने और संगीन मुकदमों की तहकीकात के लिये होता है। जिस अफ़सर के खिलाफ़ ऐसी शिकायत हो उस को वहां लगाने में क्या राज़ है ?

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਬ-ਇਨਸਪੈਕਟਰ suspend ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ reinstate ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ?

सिंचाई मंत्री : वह तो duty पर है, suspend कहां हुआ है ?

REPRESENTATION FROM MOTOR UNION, SAMALKHA, DISTRICT KARNAL.

***2708. Sardar Harkishan Singh Surjit** : Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government has received any representation, dated 6th December 1953, from the members of the Motor Union, Samalkha, District Karnal, complaining against the harassment by the police; if so, the action, if any, taken by the Government thereon ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : Yes. Careful enquiries made by a Gazetted Police Officer revealed that the allegations made by the members of the Motor Union, Samalkha, were baseless.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਉਹ baseless ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? (Laughter).

पंडित श्री राम शर्मा : सरकार के पास जो representation आई है उस में पुलिस के खिलाफ़ क्या क्या शिकायतें दी गई थीं ?

चीफ़ पार्लीयामेंटरी सेक्रेटरी : अगर आप नोटिस दें तो आप को बताया जा सकता है ।

Mr. Speaker : You may ask for a notice but the question is clear. It has been asked whether the Government has received any representation and the reply is in the affirmative. You are supposed to know what the representation is and what action has been taken on it. It is about harassment by the Police.

पंडित श्री राम शर्मा : स्वाल यह है कि क्या कोई representation पुलिस के खिलाफ़ मिला है और अगर मिला है तो क्या action किया गया है ?

Minister for Development : I am afraid the case is before the court.

Pandit Shri Ram Sharma : Sir, is this question then not a contempt of court ?

Minister for Development: When this question was sent, the case had not gone to the Court; but now it is in the Court.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੀਪਰੀਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇੰਜ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. गवर्नमैण्ट की तरफ़ से यह कहा जाता है कि यह केस sub-judice है और अपोज़ीशन (Opposition) की तरफ़ से कहा जाता है कि यह बात ऐसी नहीं । क्या आप इस का कोई नोटिस लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : पोज़ीशन (position) हाउस के सामने है ।

पंडित श्री राम शर्मा : फिर यह मान क्यों नहीं लेते कि यह केस sub-judice है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो यह मानना ही पड़ेगा । जो कुछ यह कहते हैं वह भी और जो कुछ आप कहते हैं वह भी ।

ABDUCTION OF THE DAUGHTER OF SHRI SHERO OF VILLAGE APRA, DISTRICT JULLUNDUR.

***2709. Sardar Harkishan Singh Surjit** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that the daughter of one Shri Shero, son of Maro, Adharmi of village Apra, Tehsil Phillaur, District Jullundur, was abducted on November 7/8, 1953;

(b) whether he is further aware of the fact that the said Shri Shero reported the matter to the Police Station, Phillaur; if so, the action taken by the Police Authorities in the matter;

(c) the date on which the place from where and the circumstances under which the girl referred to in part (a) above was recovered;

[Sardar Harkishan Singh Surjit]

(d) whether he is aware of the fact that the abducted girl has made a statement before the Police and the Court regarding her abduction and has named one Mulak Raj Dhiman as her abductor; if so, the action taken by the Police in the matter ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) Yes.

(b) Yes. The complainant lodged a report at P.S. Phillaur on 16th November 1953. Case F.I.R. No. 212, dated 16th November 1953, under section 363, I.P.C., was registered and investigation started.

(c) The girl was traced on 26th November, 1953, at Ladwar, District Bharatpur (Rajisthan). One Mul Chand of Ladwar (Rajisthan) saw the girl with one Bhagwat while they were standing at a shop. He suspected her to be an abducted girl and produced both of them at P.S. Ladwar where she was interrogated. On 1st December, 1953, the father of the girl received a telegram from P. S. Ladwar about his daughter having been traced. Shero (father of the girl) went to Ladwar and brought back the girl and produced her at P.S. Phillaur on 5th December, 1953, where her statement was recorded.

(d) In her statement at P.S. Ladwar the girl did not mention the name of Mulak Raj but in her statement at P.S. Phillaur she mentioned Mulak Raj as her abductor. In order to effect the arrest of Mulak Raj, action under sections 87/88, Cr.P.C., was taken against him and he was finally arrested on 4th January, 1954. The case is still under investigation.

ENFORCEMENT OF THE PUNJAB SECURITY OF THE STATE ACT, 1953, IN THE STATE.

***2716. Shri Ram Kishan :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of arrests, if any, made under the Punjab Security of the State Act, 1953, since 16th April 1953, to date;

(b) the number of public meetings and processions banned under the said Act since 16th April 1953 in the State to date;

(c) the number of persons, if any, who have been asked to furnish sureties under the provisions of the said Act since 16th April 1953 to date;

(d) the number of persons, if any, whose movements have been restricted by the Government in specified areas under the said Act since 16th April 1953 to date;

(e) the number of persons, if any, externed from their home districts under the provisions of the said Act since 16th April 1953 to date;

(f) the number of persons, if any, arrested by the Government under the provisions of said Act, for making speeches or writing articles since 16th April 1953, to date;

(g) whether any area was declared as dangerously disturbed area after the 16th April 1953 ; if so, the name of the area and the collective fine, if any, imposed on the inhabitants of that area;

(h) whether any search was made after the 16th April 1953, under the provisions of the said Act; if so, the details thereof;

(i) the number of security prisoners now restricted or detained in the State under the provisions of the said Act ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : Information in respect of this question is being collected and will be supplied to the member shortly.

VILLAGE RAINIAN LAND DISPUTE.

*2717. **Shri Ram Kishan** : Will the Chief Minister be pleased to state whether any settlement has been reached by the Government with the Punjab (Pakistan) Government regarding the land dispute of Village Rainian; if so, the details thereof; if not, the position as it is today?

Sardar Partap Singh Kairon : No settlement has yet been reached by this Government with the Punjab (Pakistan) Government regarding the land dispute of Village Rainian.

2. In the meeting between the two Financial Commissioners held at Simla on the 23rd and 24th October 1953, the Financial Commissioner, Revenue, Punjab (Pakistan), desired that a statement of the case should be submitted to him for consideration at the next meeting. This was done in November 1953. In the last meeting held at Chandigarh on the 29th and 30th January 1954, the Financial Commissioner, Revenue, Punjab (Pakistan), stated that he had asked for a report in the matter from his local officers, which was still awaited.

HARIJANS IN SERVICES.

*2757. **Sardar Darshan Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the percentage of Harijans employed in various departments of the Government district-wise during the years 1951, 1952 and 1953 ;

(b) the steps taken by the Government to raise the percentage of Harijans amongst its employees to 19 per cent ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) It is regretted that the information asked for is not readily available and the time and labour involved in collecting it will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

(b) A statement containing details is given below:—

Government have made every possible effort to ensure that the vacancies reserved for Scheduled Castes are filled by them. All departments have instructions to duly advertise, and to intimate to the Employment Exchange—who maintained a master register of all Scheduled Caste candidates available for employment—, their requirements of Scheduled Caste candidates for reserved posts. Even after this is done, no department is allowed to fill any vacancy reserved for members of the Scheduled Castes by appointing a member of another community without prior sanction of the Chief Secretary (in the Welfare and General Branch All departments have further been instructed that members of the Scheduled Castes and Tribes who are in service and are otherwise qualified and suitable should not ordinarily be brought under reduction or retrenchment, so long as their total strength does not exceed 19 per cent.

[Chief Parliamentary Secretary]

2. Government also obtain a half-yearly statement from all departments showing the progress in the employment of Scheduled Castes. These statements are examined carefully and action taken where necessary.

3. Further, in order to ensure to members of the Scheduled Castes their due share in Government services, Government have recently adopted a block system of recruitment based on a formula of rotation. According to this system, appointments are made on the basis of blocks of 5 vacancies, each,—the first vacancy in each block being reserved for members of Scheduled Castes and Tribes. If the reserved vacancy cannot be filled by a member of the Scheduled Castes and Tribes, the reservation is carried on from vacancy to vacancy in the block, and then on to the next block, so that the first two vacancies in the second block become reserved. But if in the second block also, no vacancy can be filled by appointment of a member of the Scheduled Castes and Tribes, then only one vacancy is carried forward to the next block, so that not more than two vacancies in a block will be reserved.

Government continue to devote thought and attention to this question and will take all feasible steps to see that as many reserved vacancies as possible are filled by members of the Scheduled Castes.

CASE UNDER SECTION 379, I.P.C., AT POLICE STATION SARHALI, DISTRICT AMRITSAR.

*2786. **Shri Mani Ram**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) (i) whether any case under section 379, I. P. C., was registered at the Police Station Sarhali, District Amritsar, on 22nd November 1952, against certain persons of Village Kamalpur; if so, their list;

(ii) the facts of the case in biref ;

(b) whether the above case was sent up for trial to any court of law by the Police ; if so, the date when the challan was put up in the court ;

(c) (i) whether the case under reference was transferred to any village Panchayat under the orders of the Additional District Magistrate, Amritsar ; if so, when ;

(ii) the date when the file of the case was received by the Panchayat concerned ;

(d) whether the case was ever taken up by the Gram Panchayat after the receipt of its file up to 31st December 1953 ; if so, when ; if not, the reasons therefor ;

(e) (i) whether the accused were summoned by the Panchayat up to 31st January 1954 ; if so, when; if not, the reasons therefor ;

(ii) whether the accused ever appeared before the Panchayat and were bailed out ; if so, when ;

(f) the steps that are being taken by the Government for the early disposal of such cases ;

(g) (i) if the answer to part (e) above be in the negative, the steps taken or proposed to be taken by the Government against the persons responsible for this delay ;

(ii) whether the Assistant Panchayat Officer concerned ever inspected the record of pending cases of this Gram Panchayat between 1st December 1952 and 31st January 1954 ; if so, when ;

(iii) whether he took notice of the case noted above ; if so, with what results ; if not, the reasons therefor ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : Information in respect of this question is being collected and will be supplied to the member shortly.

PANCHAYAT SECRETARIES IN THE STATE.

***2916. Sardar Partap Singh Rai :** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of Panchayat Secretaries in each district of the State whose educational qualifications are less than Matriculation ; together with their names and the places of their postings ?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : The required information is being collected and will be supplied to the member when ready.

SUGARCANE CROP IN HOSHIARPUR DISTRICT.

***2573. Shri Rala Ram:** Will the Minister for Development be pleased to state whether it is a fact that the sugarcane crop in Hoshiarpur District was most adversely affected by a pest during the year 1953-54 ; if so, the steps, if any, taken by the Agricultural Department to combat this pest, particularly the guidance given to the cultivators to fight this menace ?

Sardar Partap Singh Kairon : Yes, to some extent. The top borer and new pyrilloid borer appeared in the form of pest in Hoshiarpur Tehsil and Mukerian Sub-Tehsil of Hoshiarpur District. The Zamindars were advised to remove the affected shoots. This method was practically demonstrated in the villages and at rural gatherings.

At this stage to arrest the pest from further multiplication, during 1954 the cultivators were advised to crush their whole cane before 28th February. Where it was not possible to do so, the cultivators were advised to remove and crush the affected cane immediately.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਇਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਇਲਾਜ ਬਾਬਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਜੀ ਹਾਂ । ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੀਸਰਚ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

TRACTORS.

***2668. Shri Teg Ram:** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total number of tractors purchased by the Government during each year from 1948 to 1953 ;

[Shri Teg Ram]

(b) the total number of tractors purchased for the Fazilka Tehsil during each of the years mentioned in part (a) above ;

(c) whether the Government keeps any record of the area in acres ploughed each year with these tractors ; if so, the total acreage of land ploughed during each of the years mentioned in part (a) above in the State and in Fazilka Tehsil, respectively ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) A statement is given below :—

Year.		No. of tractors purchased by the Agriculture Department from 1948 to 1953.
1948	..	Nil
1949	..	124
1950	..	60
1951	..	5
1952	..	3
1953	..	Nil
Total	..	192

(b) The tractors mentioned at (a) above were purchased for use in the entire State and not for specific tehsils. Hence no tractors were purchased exclusively for the Fazilka Tehsil.

(c) (i) Yes. The area of land reclaimed and machanically cultivated with the help of Government tractors in the entire State is given below agricultural year-wise (July to June) :—

——	1948-49	1949-50	1950-51	1951-52	1952-53
(i) Reclamation (in acres) ..	6,459	13,362	11,333	6,879	..
(ii) Mechanical Cultivation in different operations (in acres)	35,184	77,383	90,980	72,862	52,536

(ii) No record of land operated by the Government tractors was maintained tehsil-wise and hence it is not possible to give information regarding acreage dealt with in the Fazilka Tehsil.

DISTRIBUTION OF THE AREA OF SHAMILAT DEH IN THE STATE.

*2885. **Shri Mool Chand Jain** : Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether any instructions have been sent to the Consolidation Officers regarding the exclusion of the area known as Shamilat Deh from the common pool to be distributed amongst the proprietors in view of or before the passing of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1953 ; if so, a copy of the instructions be laid on the Table ;

(b) whether the Government has issued any instructions to the Consolidation Officers regarding the lands to be reserved for (i) common purposes and (ii) the occupation and use by non-proprietors, especially the Harijans; if so, a copy of the instructions be laid on the Table ;

(c) whether in view of the vesting of Shamlat Deh in Panchayats the Government has issued any instructions to the Consolidation Officers to compulsorily include a representative of the Panchayats in the Advisory Body for each village ; if so, a copy of the instructions be laid on the Table ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes, Punjab Government memorandum No. 4900-D-52/4898, dated the 25th August 1953, a copy of which is given below.

(b) (i) (ii) Yes, attention is invited to Punjab Government memoranda No. 5944-D-53/3179, dated the 20th April 1953, No. 2568-D-52/2449, dated the 12th/14th June 1952 and Punjab Government letter No. 12669-D-53/9231, dated the 9th December 1953 (copies given below).

(c) Instructions already exist in rule 4 of the Act (copy given below).

Copy of memorandum No. 4900-D-52/4898, dated the 25th August, 1952, from the Deputy Secretary to Government, Punjab, Revenue Department, Simla-2, to all Deputy Commissioners in the Punjab (except Simla).

SUBJECT :—*Partition of Shamilats during Consolidation Operations.*

Government have had under consideration the question of partition of Shamilats during consolidation proceedings. After giving the matter a careful consideration it has been decided that where shamilat area of a village is already barely adequate for the requirements of the village, the consolidation staff should not effect any partition. In the case of those villages, however, in which shamilat area is in excess of requirements, the Consolidation staff may continue to do partition and consolidation work side by side, subject to the condition that the shamilat area should not be reduced below the reasonable needs of the village community.

2. The Settlement Officers (Consolidation) should ensure that Consolidation Officers do not exercise their discretion under section 112 of the Land Revenue Act to the detriment of the non-proprietors.

3. It is requested that these instructions may kindly be brought to the notice of all concerned and they should be asked to observe them carefully.

No. 4900-D-52/4899

A COPY is forwarded to the Director, Consolidation of Holdings, Punjab, Jullundur City, for information, with reference to his U. O. No. G/582, dated the 2nd August, 1952.

By order,
(Sd.)
Deputy Secretary, Revenue.

No. 4900-D-52/4900

A COPY is forwarded to the Commissioner, Ambala and Jullundur Divisions, for information.

(Sd.)
Deputy Secretary, Revenue.

[Minister for Development]

Copy of memorandum No. 5944-D-53/3179, *dated the* 20*th April* 1953, *from the Deputy Secretary to Government, Punjab, Revenue Department, Simla*-2, *to the Director, Consolidation of Holdings, Punjab, Jullundur.*

SUBJECT :—*Reservation of land from the area of common land for extension of abadis of Harijans.*

Reference :—Communication noted in the margin.

Your D.O. letter No. G/773, dated 6th September 1952.

Government observe that under section 3 of the Land Revenue Act, 1887, the *abadis* of villages have been declared "Estate" through Punjab Government notification No. 474-R-53/705, dated the 8th March 1953 and a s such the question of payment of compensation to any previous owner does not arise.

2. The Punjab Village Common Lands (Regulation) Bill, 1953, is before the Legislature. When it is passed and enforced it would provide for *Shamilat Deh* to vest in the Panchayat of the village without the payment of any compensation to any previous owner. The *Shamilat Deh* land would then be utilized or disposed of by the panchayat for the benefit of the inhabitants (both the proprietors and non-proprietors) of the village.

3. It may be pointed out that *Shamilat land* in some of the villages is already very small and in view of this fact Government approve your suggestion that the size of plots *for* building purposes should be 5 biswas kacha for *Harijans*. It has been noticed that usually area contiguous to the houses of Harijans is in many cases fertile 'niain' land and it would be a waste of such land if it is diverted from agricultural to house buildings. Similarly in some cases the land near their *abadi* is *barren* and *bunjar* and undoubtedly less fertile. Government consider that the question of the area to be earmarked for this purpose be left to the judgment of Settlement Officers. Government also realize your difficulty that reservation of land for the houses of Harijans in villages where Consolidation of Holdings work has been finalized is not possible at this stage but Government trust that if any thing could be done without re-opening the consolidation proceedings, it will be appreciated. For future, it should, however, be noted that land should be invariably reserved for the *abadis* of Harijans when *consolidation proceedings are in progress.*

Copy of memorandum No. 2568-D-52/2449, *dated the* 12*th*/14*th June*, 1952, *from the Deputy Secretary to Government, Punjab, Revenue Department, Simla*-2, *to all Deputy Commissioners in the Punjab* (*except Simla*).

SUBJECT:—*Division of* shamilats *during Consolidation proceeding—sreservation of lands for common purposes.*

The question of reserving land for various common puposes from the village Shamlat at the time of Consolidation operations has been engaging the attention of Government for some time past. While Government agree that the requirements in regard to the reservation of land for various common purposes from the village Shamilat vary from village to village and each case has to be decided by the Consolidation Officer on merits in consultation with the advisory body yet with a view to observe uniformity in procedure throughout the State, it has been decided to specify the compulsory and optional items for which lands ought to be reserved from the common pool in each village to the extent indicated below :—

COMPULSORY ITEMS.

1. Roads, village roads, field roads and arterial roads—

(a) Village to village and circular roads 4 to 6 karams wide.

(b) Roads to serve as communication to villages fields from village abadis 3 to 4 karams and those leading to individual plots 2 karams wide.

(c) To village drinking wells and ponds (for watering cattle) 1 to 2 karams wide.

(d) Other roads including that to be laid under the Development Scheme and to serve as link to existing pucca roads 6 to 8 karams wide.

2. Extension of abadi for proprietors and non-proprietors.

3. Tanks	..	According to the requirements of the villagers concerned.
4. Manure pits	..	
5. Hada Rori	..	
6. Public latrines		
7. Primary schools	..	One acre.
8. Play-grounds for children and adults	..	½ acre in the vicinity of the school

9. Fuel plantation (Optional in Jullundur District), elsewhere according to local requirements.

10. Cremation grounds .. According to local requirements.

11. *Watercourses*. As far as the changes in alignment of *Sarkari* watercourses are concerned or new *Sarkari* courses are concerned area to be covered by them but in the case of zamindari watercourses. it is understood that the Khal or watercourse of customary width will be made available through the lands of the zamindars concerned without payment of any compensation.

12. Grazing grounds	..	Area to be reserved according to local needs.
13. Tanning places	..	
14. Well for drinking purposes	..	

OPTIONAL ITEMS.

1. Road-side Ada .. One Kanal. (Only in villages through which or along which pucca roads pass).

2. Sewerage tank. (Only where the villages are large and it is regarded as essential).

3. Reservation of land for Middle and High Schools.

4. Markets.

5. Mela ground.

6. Rural dispensary.

7. Veterinary centre.

8. Village theatre.

9. Panchayat-ghar. Janjghar (½ Kanal to 1 Kanal) (Only where no common building in the form of Chopall or other bearing similar name exists).

10. Gurdwara, Temple, etc. (Only where villagers feel the necessity).

(In the case of items 2 to 8 and 10 area to be reserved will be according to the local needs).

It is requested that the Settlement Officer (Consolidation) and his staff may please be instructed to observe these instructions carefully in future.

No. 2568-D-52 /2450

A copy is forwarded to the Director, Consolidation of Holdings, Punjab, Jullundur City, for information, with reference to the correspondence resting with his communication noted in the margin.

D.O. No. 123-S/775, dated the 7th May, 1952.

Sd.

Deputy Secretary, Revenue.

No. 2568-D-52/2451

A copy is forwarded to the Commissioner, Ambala and Jullundur Divisions, for information.

Sd.

Deputy Secretary, Revenue

[Minister for Development]

Copy of letter No. 12669-D-53/9231, *dated the 9th December* 1953, *from the Deputy Secretary to Government, Punjab, Revenue Department, to all Deputy Commissioners in the Punjab (except Simla).*

SUBJECT :—*Reservation of land for various common purposes.*

Reference :—Punjab Government memorandum No. 2568-D-52/2449, dated the 12th/14th June 1952.

It has been decided in the 62nd meeting of the Committee of "Increased Food Production" held at Chandigarh on the 5th October, 1953, that compulsory reservation of land should be made in all estates for common purposes out of the common pool on the following scale irrespective of the fact whether Shamlat Deh exists or not :—

Serial No.	Area of the village	Area proposed for reservation
	Acres	Acres
1	500 ..	15
2	1,000 ..	20
3	2,000 ..	30
4	5,000 ..	50

This reservation should be exclusive of reservation already authorised in Punjab Government memorandum No. 2568-D-52/2449, dated the 12th/14th June 1952. The common land so reserved should be placed under the management of village Panchayats established under the Punjab Gram Panchayats Act, 1952, and the net income of the land should be utilized by the Panchayats for the common needs and benefits of the villagers. In this connection it may also be stated that the Legal Remembrancer who was consulted in the matter has advised that no compensation is required to be paid to the right-holders for making compulsory reservation of land out of the common pool during consolidation operation under Section 18(c) of the Consolidation Act, for being managed by the village Panchayats.

2. It has further been decided that new Abadis should be located on unfertile blocks of land within a radius of half mile from the existing Abadi sites. In such cases, the Abadi sites which are selected should be laid on the Model Village Scheme. Plan will be provided by the Development Department.

3. In the case of villages in which Shamlat land is available, and is fit for cultivation without incurring unduly high development costs, the reservation of land as stated in para 1 above may be made out of it. But if such area is not available out of Shamlat, then the reservation may be made out of average land of the village, provided that an area of equal value is added to the common pool out of the Shamlat for distribution to right-holders.

4. It has also been decided that alignment of the watercourses should be made before repartition and soon after Qilabandi is done. The Chief Engineer, Irrigation Branch, and the Director, Consolidation of Holdings, Punjab, are to evolve a procedure for carrying out the alignment of the watercourses so as not to delay the work of Consolidation of Holdings. This Scheme should be ready within a fortnight. Any delays in the execution of this Scheme should be brought to the notice of Government.

5. The layout of village roads should be completed before repartition. Road plans for the tahsils which are under consolidation should be prepared so that the village roads are integrated with the road plans of the Public Works Department.

6. The compulsory reservation now ordered should be made in all 'B' group tahsils, and the tahsils to be taken up for consolidation in future.

7. It is requested that the Settlement Officer (Consolidation) and his staff may please be instructed to observe these instructions carefully.

Copy of endorsement No. 12669-D-53/9232

A COPY is forwarded to the Director, Consolidation of Holdings, Punjab, for information and with the request that he should please take action accordingly.

Copy of Endorsement No. G/17547, dated the 18th December 1953, from the Director, Consolidation of Holdings, Punjab.

A COPY is forwarded to the Assistant Director, Consolidation of Holdings, Jullundur, for information.

No. G/18044-55

Office of the
Director, Consolidation of Holdings, Punjab,

Dated Jullundur City, the 30th December 1953.

A COPY is forwarded to all the Settlement Officers, Consolidation of Holdings, in the State, for information and communication to their subordinates for necessary compliance.

(Sd.) ——29-12-53

SUPERINTENDENT,

for Director, Consolidation of Holdings, Punjab.

DEVELOPMENT DEPARTMENT

(CONSOLIDATION OF HOLDINGS)

NOTIFICATION

The 8th December 1949.

No. 10954-D-49/7351.

RULES.

4. *Preparation of scheme of consolidation.* After the notification and publication under subsection (1) of section 14, the Consolidation Officer shall visit each of the estates concerned after giving reasonable notice of his visit to the land-owners thereof and shall in consultation either with the village Panchayat or, where no village Panchayat exists with a village committee specially chosen from among the land-owners for this purpose by him, put up a scheme, for the Consolidation of Holdings.

श्री मूल चंद जैन : क्या मैं पूछ सकता हूं कि शामिलात देह के कानून के पास हो जाने के बाद भी इस सिलसिला में कोई हिदायतें जारी की गई हैं ?

मंत्री : जी हां, की गई हैं ।

श्री मूल चंद जैन : उन हिदायात की कापी मुझे नहीं मिली ।

मंत्री : इस की वजह यह है कि ये हिदायतें अभी अभी जारी की गई हैं । उस की कापी आप को भी दे दी जायगी ।

पंडित श्री राम शर्मा : जो हिदायतें जारी की गई हैं, क्या वे यहां पर बताई जा सकती हैं ?

मंत्री : बताने में तो कोई हर्ज नहीं मगर वह बहुत लम्बी चौड़ी हैं । हां उन की कापी आप को दे दी जाएगी ।

पंडित श्री राम शर्मा : आप उस का खुलासा ही पढ़ कर सुना दें ।

मंत्री : वह लम्बी बहुत हैं । उन को पढ़ने में बहुत वक्त लगेगा ।

श्री मूल चंद जैन : क्या मनिस्टर साहिब बतायेंगे कि मेरे सवाल के पार्ट 'सी' (c) का जवाब टेबल (Table) पर क्यों नहीं रखा गया ?

Mr. Speaker : It has already been stated in reply that "instructions already exist in rule 4 of the Act (copy laid on the Table)".

श्री राम स्वरूप : जिन लोगों ने इस कानून के लागू होने से पहले शामिलात देह की जमीनों को तकसीम कर लिया था, उन के खिलाफ भी गवर्नमैंट कोई कार्यवाही करने का ख्याल करती है ? क्या उन जमीनों को वापिस ले लिया जायगा ?

ਮੰਤਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਸ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

श्री मूल चंद जैन : जो स्टेटमैण्ट टेबल पर रखी गई है उस में लिखा है कि २६ अगस्त १६५२ के बाद की शामिलात देह जो छूट गई हैं उन्हें पार्टीशन (partition) नहीं किया जायगा। लेकिन पिछले साल जो consolidation का काम—खास कर करनाल ज़िला में हुआ है—वहां पर जितनी शामिलातें थीं उन में से ५ प्रतिशत छोड़ी गई हैं। क्या सरकार यह समझती है कि जो ५ या १० प्रतिशत छोड़ी गई हैं वह काफ़ी हैं ? क्या कायदे के मुताबिक जितना रकबा छोड़ा जाना चाहिये था वह छोड़ा गया है, या नहीं ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ (partition) ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਏਰੀਏ (area) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਜ਼ਮੀਨ (reserve) ਕਰ ਲਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਤੁਅਲਕ ਹੈ ਉਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ evacuee lands ਸਨ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਦੀ Relief and Rehabilitation ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲ ਇਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪੁਰ ਪਾਬੰਦ ਰਹਾਂਗੇ।

श्री राम स्वरूप : बहुत से गांवों में शामिलातों पर हिंदुओं और मुसलमानों का मुश्तरका हिस्सा था। अब महकमा रीहैबीलीटेशन ने मुसलमानों के पाकिस्तान चले जाने के बाद वे ज़मीनें किन्हीं और हिंदुओं को अलाट कर दी हैं। वह शामिलातों की ज़मीन है। क्या सरकार उनको वापस करने के मामले पर सोच विचार कर रही है ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

COMPENSATION FOR LAND ACQUIRED FOR BHAKRA-NANGAL PROJECT, ETC.

***2304. Sardar Chanan Singh Dhut :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the area of land acquired by the Government respectively for the Nangal and Bhakra Projects, the Ganguwal Power House and for roads, railway tracks, houses, etc., in connection with the said projects and the said power house ;

(b) the total amount of compensation paid for the land acquired and the compensation yet to be paid by the Government together with the basis on which the compensation has been assessed ;

(c) whether it is a fact that the land revenue is still being collected for the land acquired by the Government for which compensation has been paid to the owners ; if so, the reasons therefor, together with the amount of land revenue collected from such owners so far ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) 3,635·46 acres.

(b) Rs 26,60,371.

No compensation remains yet to be paid.

The basis for the compensation are the usual standards laid by the Government for land acquisition.

(c) Yes. Land revenue was collected by the District Revenue authorities from the owners for several harvests after the land had been acquired by the Department. This was due to omission on the part of the Land Acquisition Officer in submitting a reduction in land revenue statement prescribed in para 79 of the Financial Commissioner's Standing Order No. 28 together with award statements received after pre-audit by the Accountant-General, Punjab. Land revenue amouning to Rs 2,603 has already been remitted,—*vide* Punjab Government Memorandum No. 6687-A-53/3255, dated 12th September 1953, and the balance of Rs. 13,603 recovered during the previous harvests will be refunded during the current financial year.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ compensation ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੀ basis ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਦਸਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨਗੇ ?

मंत्री : Compensation उसी standard पर दी जाती है जो गवर्नमेंट ने आम तौर पर उन जमीनों की compensation देने के सम्बन्ध में कायम कर रखा हुआ है जो वह acquire करती है। यह उस ज़मीन की पिछले पांच साल की Mutation value की औसत के बेसिस (basis) पर गिनी जाती है ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : Compensation ਦੇ ਗਿਣਨ ਲਈ ਉਹ ਰਕਮ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ Mutation ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

मंत्री : वह उस इलाके के पिछले पांच साल के दाख़ल ख़ारज से निकाली जाती है ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਕੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਕਦ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मेम्बर जरा इतना तो सोच लें कि क्या यह supplementary सवाल main question से पैदा होता है ?

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਇਹ compensation ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ supplementary question ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

मंत्री : यदि माननीय मेम्बर यह details में चाहते हैं तो वह नोटिस दे दें लेकिन मैं general information के लिए उन्हें बता देता हूं कि जो ज़मीनों के मालक नकद मुआवज़ा लेने से इनकार करते हैं और उनको ज़मीन देने के लिए सरकार के पास ज़मीन नहीं होती, तो वह common pool में से लेकर उसे दी जाती है और जो मुआवज़ा दिया जाना होता है वह सारे गांव को दिया जाता है ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣ ?

मंत्री : ज़मीन कहीं आसमान से तो नहीं आनी होती । जो वहां इन्हें दी जा सकती है वह वहीं दी जाती है । वरना मुआवज़ा दिया जाता है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह महकमा नहर का आम मामूल हो गया है कि जो ज़मीन acquire कर ली गई हो और उस का मुआवज़ा भी मालक ले चुके हों उस की मालगुज़ारी उन्हीं मालकों से ली जाती है ?

मंत्री : असल में बात यह है कि इस थोड़े अरसा में कई distributaries खोदी गई हैं और कदम २ पर नहरें ले जाई गई हैं । उनके लिये जगह जगह पर land acquire की गई है और यह सब काम इतना hurriedly चल रहा है कि इस के बारे में कर्मचारी इत्तलाह नहीं दे सकते । फिर यह कोई रकम भी बहुत नहीं होती । वक्त पर सब ठीक हो जायगा ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैंने सवाल कुछ पूछा था और माननीय वज़ीर साहिब ने जवाब कुछ दिया है । मैंने पूछा है कि क्या हमारे महकमा नहर का यह आम मामूल हो गया है कि ज़मीनें लेने के बाद भी उन की मालगुज़ारी उन के मालकों से ही वसूल की जाती है ?

मंत्री : मैं इस का जवाब दे चुका हूं । जो Land Acquisition Officer, land acquisition का काम करते हैं वही acquired ज़मीनों के बारे में statement तैयार करते हैं और वही Deputy Commissioners को इत्तलाह देते हैं । उन के पास और ज़रूरी काम इतना होता है कि यह जल्दी में नहीं कर सकते ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं यह दरियाफ़्त कर सकता हूं कि यह जो ज़मीनें गवर्नमैण्ट acquire कर लेती है और फिर उन की मालगुज़ारी भी लेती रहती है उन के बारे में ऐसा करना महकमा नहर का मामूल बन गया है ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਤਲਾਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੈਣੀ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह अमर वाक्या नहीं है कि यह महकमा नहर का मामूल बन गया है कि उन ज़मीनों की मालगुज़ारी भी सरकार वसूल करती रहती है ?

सिंचाई मंत्री : नहीं यह अमर वाक्या नहीं है ।

INQUIRY OF SABRAS BUND CASE OF TEHSIL NUH, DISTRICT GURGAON.

***2508. Shri Babu Dayal :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether the inquiry into the case of Sabras Bund of Tehsil Nuh, District Gurgaon, is over; if so, the report of the inquiry be laid on the Table.

Chaudhri Lahri Singh : Yes. A copy of the report is given below.

Copy of letter No. 0204-C/683-W., dated the 28th August 1952, from the Superintending Engineer, Western Jumna Canal, East Circle, to the Chief Engineer, Irrigation Works, Punjab, Simla.

SUBJECT :—*Reconditioning of Sabras Bund*
Reference :—Your letter No. 2573/RC/767/44, dated the 7th July, 1952.

Pt. Babu Dyal, M.L.A., Gurgaon, was contacted in connection with the complaint made by him. Copy of his reply is enclosed. According to the request, I fixed 3rd August, 1952, as the date of inspection at site and reached there by 10 o'clock. Pt. Babu Dayal was not there. However, some other congress men and zamindars of the neighbouring villages were present. The enquiry was held at site and a complete detail of it is enclosed herewith.

The following conclusions are drawn :—

None out of the responsible members of the Congress present at site had any first-hand knowledge of the complaint made. Their idea was all based on hearsay and what the zamindars of the neighbouring villages had told them. Their chief complaint was that no work was done by Mangtu, Contractor, on Sabras Bund in reach 4,000 to 6,000 while payment has been made to him. They further alleged that no work was done at all during March, April and May in this reach.

Incidently, a responsible member of the public one Dr. Amir Chand happened to come at the site and the Congress men present wanted me to take his statement as well. He stated that the work in this reach was being done during *Chet* and *Bisakh* and they were stopped from dismantling the tatties in the borrowpits because they were required for measurements. The inspection of the site also showed that the work for which payment was made has actually been executed.

However, during my investigation, it came to my notice that the payment for the part of the work, i.e., Pushta about which complaint has been made, was not based on borrowpit-measurements but measurements of the work as executed while measurement for other works in the same cross-section was based on borrowpits. As this could have led to over-payment, I deputed the Executive Engineer, Delhi Division, to verify the actual quantity of earthwork executed at site. Copy of his report made,—*vide* his D.O.No. 0173, dated 20th/23rd August 1952, is enclosed herewith. It shows that no overpayment has been made.

The Sub-Divisional Officer was explaining that the motive for their complaint is different. He is occupying a requisitioned house which belongs to an influential congress-man and he is being harassed so that he may vacate this house.

Encls :—
1. Copy of Pt. Babu Dayal's letter.
2. Copy of Xen's D.O.

PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY.
Simla, 22nd July 1952.

DEAR SIR,

Reference your C. letter No. 10082/683-W, dated 17th July 1952, regarding Sabras Bund, Tehsil Nuh, Thana Tauru, District Gurgaon, I have been informed by Sh. Shiam Sunder, General Secretary, Congress Committee, Taru, that the S.D.O., Bunds of Gurgaon, has embezzled Rs. 2,000 on behalf of the contractor named Mangtu. No earthwork has been done during the month of payment rather than that no work has been done during the last year.

The Vice-President, L. Bed Ram, Congress Committee, Tauru, has enquired the matter and he is convinced of the fact. I tried to see all the concerned during my vacation from Assembly Session but could not see all concerned except the S. D.O. Shri Shiam Sunder, Shri Ved Ram, the site and the villagers. They proved that no earthwork has been done on the site since the last year. They say that there was unused money of about Rs. 2,000 which has been consumed by such misappropriation.

I gathered the whole village on the 20th instant. All of the assembled people denied such earthwork.

As response to your letter to accompany you on the spot, I would try to spare my time on Sunday which falls on 3rd proximo but I would like to request you to please ask your following staff to be on the spot : The Overseer who supervised the work. S. Jagjit Singh, Overseer, should be present. The Mistree who supervised and measured the earth, the Jamadar, the S.D.O. and contractor Shri Mangtu Ram.

[Minister for Irrigation]

I have requested the General Secretary and Vice-President who made the initial enquiries should be on the site. I hope you would confirm the date and try to reach on the site by 10 o'clock on the appointed time 3rd August, 1952.

Yours sincerely,

(Sd) BABU DAYAL.

Proceedings of the enquiry held at site of Sabras Bund on 3rd August 1952, at 10 a.m. as per Chief Engineer's letter No. 2573/RC/767/44, dated the 7th July 1952.

Sabras Bund was inspected on 3rd August 1952, at 10 a.m. The following gentlemen were present at the site :—

(1) L. Kishan Datt, President, Congress Committee, Tauru.
(2) Sh. Shiam Sunder, Secretary, Congress Committee, Tauru.
(3) L. Ved Ram, Vice-President, Congress Committee, Tauru.
(4) L. Banwari Lal, Member, District Congress Committee, Gurgaon.
(5) L. Rudhar Datt, Member, Congress Committee, Tauru.
(6) Sh. Bhobla, Lambardar, Sabras.

These gentlemen stated that payment made to Mangtu, Contractor, during April 1952, is fictitious and that may be investigated. The gentlemen were requested to come to the site for necessary investigation.

These gentlemen stated when brought to the site of work that they have no personal knowledge of the fact whether any work was done or not. They have been told of this complaint by the people of Sabras but they have no personal knowledge. They further stated, "We made enquiries at site and came to know that the work being shown to us was done by one Pritam and Dwarka Parshad. This work was finished in June of last year and the payment made to Mangtu is for the same work, that is, the payment is being made twice". "We have seen the work. It has been done at site but our contention is that it was not done by Mangtu but somebody else and long before April 1952."

Statement of Mangtu, Contractor.

"The work in question shown to me was done by me during March 1952. My Labour strength was from 15 to 35 men and I took 2 to 2½ months to finish the work. I started the work in March 1952, and finished it some time in *Jeth*, i.e. May, 1952. I worked throughout the Sub-Division and I have got permanent labour and I do not depend on local labour. Nowhere has labour got ration card made for them and so I had none. I had come on the work and crops were sparcely standing here and there on either side of the berm. Excepting one or two zamindars nobody objected to the taking of earth from their fields. The crops of gram and barley".

Statement by Dr. Amir Chand and Shri Shib Dayal, Lambardar.

"We live in the village Sheikhpur adjoining the Sabras Bund between R. D. 4,000 and 6,000 . During *Chet* and *Baisakh* the work was going on this bund by labour not belonging to the adjoining villages. We were stopped from dismantling the cross tatties because we were told that they were required to be kept intact for measurement purposes".

श्री बाबू दयाल : क्या इस केस की enquiry हो चुकी है ?

मंत्री : जी हां, enquiry मुकम्मल हो चुकी है और रिपोर्ट मेज पर रख दी गई है । आप को नोटिस दिया गया था लेकिन आप दफ्तर में नहीं आए थे ।

श्री बाबू दयाल : क्या मैंने आप से यह शिकायत नहीं की थी कि यह रिपोर्ट ग़लत है ?

Mr. Speaker : Whatever has been done there, cannot be discussed on the floor of the House.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं वज़ीर साहिब से पूछ सकता हूं कि यह इस शिकायत पर जो माननीय मैम्बर की तरफ से की गई थी कि गवर्नमैंण्ट का हजारों रुपया .खुर्द बुर्द कर लिया गया है और जो एक एस. डी. ओ. के खिलाफ थी, enquiry माननीय मैम्बर की मौजूदगी में नहीं की गई ?

मंत्री : जब इस शिकायत पर enquiry की गई थी तो वहां कई कांग्रेसी सज्जन मौजूद थे। वहां की कांग्रेस कमेटी के President भी मौजूद थे। माननीय मैम्बर से दरखास्त की गई थी वह भी वहां हाजिर हों लेकिन यह वहां नहीं पहुंचे। शायद यह डर गए थे क्योंकि इन की शिकायत झूठी थी।

Mr. Speaker : The hon. Minister should not have said that.

Minister : I withdraw my words, Sir.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वजीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि enquiry के वक्त किन किन लोगों के बयानात दर्ज किये गये ?

Mr. Speaker : How does this supplementary question arise out of the main question?

पंडित श्री राम शर्मा : स्पीकर साहिब ! में यह दरयाफ़्त करना चाहता हूं कि enquiry किस तरीका से हुई ? जब पंडित बाबू दयाल की अदम मौजूदगी में जिन लोगों के बयानात लिये गये उन के नाम, और जो फ़ैसला हुआ वह बतला दिया जाये।

मंत्री : यह इत्तलाह इस statement में मौजूद है जो मेज़ पर रख दिया गया है।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वह फ़ैसला इसी बिना पर किया गया है कि यह शिकायत उस अफ़सर के खिलाफ़ सिर्फ़ इसलिये की गई है कि उस ने एक कांग्रेसी सज्जन का मकान requisition कर रखा है ?

मंत्री : ऐसा नहीं है। माननीय मैम्बर जवाब देख सकते हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह उस फ़ैसले में नहीं लिखा गया है कि चूंकि वह कांग्रेसी सज्जन उस S. D. O. को उस मकान से निकालना चाहते थे इसलिये उन्होंने उस के खिलाफ़ शिकायत की थी ?

Mr. Speaker : This does not arise.

श्रीमती शन्नो देवी : स्पीकर साहिब मैं एक बात पूछना चाहती हूं कि अगर पंडित श्री राम शर्मा और माननीय मंत्री ही आपस में हर वक्त झगड़ते रहें तो हाउस का काम कब होगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो प्वांयंट ग्राफ़ ग्रार्डर (Point of order) नहीं ।

श्री बाबू दयाल शर्मा : क्या ऐनक्वायरी (enquiry) में चीफ़ मनिस्टर साहिब के पास शिकायत की गई थी ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो ग्राप का सवाल समझ नहीं ग्राया ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Superintending Engineer की तहकीकात से मुतमय्यन न हो कर यह शिकायत वज़ीर साहिब ग्रौर चीफ़ मनिस्टर साहिब के पास की गई थी कि इनसाफ़ नहीं किया गया ?

मंत्री : मैंने चीफ़ मनिस्टर को यह भी लिखा था कि जो ऐम. ऐल. एज. झूटी दरखास्तें दिलाते हैं ग्रौर तहकीकात में शामिल नहीं होते, उन के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाए ?

पंडित श्री राम शर्मा : क्या Government ने तय कर लिया है कि जो शिकायत झूटी साबित हो उस में तो कार्यवाही की जाए ग्रौर जो सच्ची शिकायत हो उस पर कार्यवाही न की जाए ?

CO-OPERATIVE FARMING SOCIETIES IN THE STATE.

***2617. Sardar Chanan Singh Dhut :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total number of Co-operative Farming Societies formed in the State year-wise since August 1947 and the total number at present ;

(b) the number of land-owners district-wise owning less than 5 acres, between 5—10 acres, between 10—20 acres and above 20 acres of land who have joined the said Co-operative Farming Societies ;

(c) the total aid, monetary or otherwise given by the Government yearly to the above Co-operative Societies referred to above ;

(d) the aid given by the Government district-wise to those owning less than 5 acres, between 5—10 acres, between 10—20 acres and above 20 acres of land who have joined these Co-operative Societies ?

Chaudhri Lahri Singh : (a)—

Year	*Number of Co-operative Farming Societies.*
1947-48	..
1948-49	..
1949-50	2
1950-51	17

Year	*Number of Co-operative Farming Societies*
1951-52	40
1952-53	112
At present	180

(b) This information is not available with the Government. It can, however, be collected from the Co-operative Farming Societies concerned and it will take time.

(c) and (d) No aid has been given by the Government to any Co-operative Farming Society.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਭਾਗ (B) ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker : Not allowed.

CULTURABLE AREA UNDER THE COMMAND OF UPPER BARI DOAB CANAL, ETC.

***2804. Sardar Achhar Singh Chhina :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total culturable commanded area under the Upper Bari Doab, Bist Doab, Sirhind and Dipalpur Canals during the years 1950, 1952 and 1953 ;

(b) the total supply of water in the above canals during the years mentioned in part (a) above ;

(c) the total water rate collected by the Government during the period mentioned in part (a) above ?

Chaudhri Lahri Singh : (a), (b) and (c). A statement containing the required information in respect of Upper Bari Doab, Bist Doab and Sirhind Canals is given below.

2. Dipalpur Canal after partition is under the jurisdiction of Pakistan; hence necessary data is not available.

STATEMENT

Name of Canal	(a) Total culturable area commanded			(b) Total supply of water			(c) Total water rates collected		
	1950-51	1951-52	1952-53	1950-51	1951-52	1952-53	1950-51	1951-52	1952-53
	Acres	Acres	Acres	Cusecs	Cusecs	Cusecs	Rs	Rs	Rs
Upper Bari Doab ..	828,123	883,306	988,888	903,197	928,340	972,291	46,43,430	47,64,812	53,98,417
Shah Nahar ..	47,000	47,000	48,000	97,560	200,790	204,027	Nil	915	7,21,270
Bist Doab (Grey Canals) ..	289,795	289,663	219,573	560,706	366,462	576,653	2,26,646	4,23,443	..
Sirhind Canal ..	2,103,120	2,110,000	2,113,499	1,402,181	1,615,706	1,658,706	90,17,922	83,37,094	88,11,773

ALLOTMENT OF LAND AT VILLAGE BHAINI MASSA SINGH, DISTRICT AMRITSAR.

***2170. Sardar Sarup Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) (i) whether any evacuee culturable area was excluded from the pool of allotment at Village Bhaini Massa Singh, District Amritsar, under orders of the Additional Deputy Commissioner, Amritsar, dated 2nd February 1950 ; if so, the provision of law under which these orders were passed ;

(ii) the reasons for its exclusion from the allotment pool ;

(b) the list and the full address of the persons on whose request (representation) these orders were passed by the Additional Deputy Commissioner, Amritsar ;

(c) (i) whether any of the persons referred to in part (b) above were allowed by the Additional Deputy Commissioner, Amritsar, to file a suit for the cancellation of the sale deed in favour of the owners ; if so, their list along with their full addresses ;

(ii) whether any of the said persons had filed a suit before the Competent Authorities of the Rehabilitation Department for the cancellation of the sale deed; if so, the list of the petitioners, and the names of the authorities concerned ;

(d) (i) the decision, if any, arrived at by the Rehabilitation Authorities, referred to in part (c) (ii) above ;

(ii) the date of decision ;

(e)(i) the name of the persons or person to whom the possession of the area referred to above was delivered after its exclusion from the said allotment pool ;

(ii) the terms on which the possession was delivered ;

(f) (i) whether any rent has been realised from the persons referred to in part (e) (i) above; if the reply be in the negative, the reasons therefor ;

(ii) total rent due up to 15th June 1953 ;

(g) if the answer to part (f)(i) above be in the negative, the reasons therefor ;

(h) (i) the nature of the final decision arrived at in this case by the competent Rehabilitation authorities ;

(ii) whether the decision arrived at has been implemented by the Government; if not, the reasons therefor ?

Sardar Ujjal Singh: (a) (i) Yes. 30 acres of culturable area was excluded from evacuee area pool of Village Bhaini Massa Singh.

(ii) This area was excluded from the evacuee pool as a civil suit filed by one Shri Sardul Singh was pending for establishing his right on this land.

[Minister for Finance]

(b) Shri Sardul Singh, son of Shri Paul Singh, resident of Village Baini Massa Singh.

(c) (i) No. The suit for the cancellation of the sale had already been filed by Shri Sardul Singh referred to in (b) above, before the orders were passed by the Deputy Commissioner.

(ii) No.

(d) (i) Does not arise.

(ii) Does not arise.

(e) (i) This area is still in the illegal possession of Shri Paul Singh, son of Shri Ishar Singh.

(ii) In view of reply to (e)(i) no terms were fixed with Shri Paul Singh.

(f)(i) Yes. Rs 2,946 have been realised from the unauthorised cultivator at eight times the land revenue.

(ii) Total rent due up to 15th June 1953 amounts to Rs 2,946.

(g) In view of reply to f(i) it does not arise.

(h)(i) In view of reply to part (c)(ii) it does not arise.

(ii) No decision has so far been communicated to the district authorities and the question of its implementation does not therefore arise.

ALLOTMENT OF LAND IN TOWN PATTI.

***2511. Sardar Sarup Singh** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any orders were issued by the Director, Rehabilitation Rural, Jullundur, on 26th August 1953, for the delivery of possesion of a certain area at Town Patti, District Amritsar, to the allottees whose review applications had been accepted during the year 1951 ; if so, the total of this area together with the number of persons to whom possession was to be given ;

(b) whether under orders of Director, Rehabilitation Rural, referred to in part (a) above, any allottees were put into possession on 17th September 1953 ; if so, their number and the area given to each one of them ;

(c) whether compliance of the orders referred to in part (a) above was stopped by the Revenue Field Staff under orders of the Tehsildar, Patti; if so, the provision of law under which these orders were issued together with the reasons for doing so ;

(d) whether any complaint against the Tehsildar, Patti, was received by the Chief Administrator, Rehabilitation ; if so, the action, if any, taken against him; if not, the reasons therefor ?

Sardar Ujjal Singh : (a) No final orders were passed by the Director, Rehabilitation, Rural, Jullundur on 26th August 1953.

(b) The field staff of Patti Tehsil delivered the possession to the following allottees on 17th September 1953 due to misunderstanding and cleverness of the man who got a copy of Director, Rehabilitation, Rural's U. O. No. 5648/Reh(R), dated 26th August 1953 and brought the same to Tehsil office for compliance although no final orders had been passed.

	Name of allottee		*Area* K.	M.
1.	Puran Singh, son of Bagga Singh	..	36	0
2.	Karam Singh, son of Bagga Singh	..	36	0
3.	Chanan Singh, son of Gurmakh Singh	..	36	0
4.	Ralia Singh, son of Jota Singh	..	36	0
5.	Palla Singh, son of Dal Singh	..	12	8
6.	Chanda Singh, son of Basant Singh	..	50	17
7.	Ghasita Singh, son of Dal Singh	..	36	0
8.	Sajjan Singh, son of Sadha Singh	..	37	7
9.	Narinjan Singh, son of Sadha Singh	..	35	6
10.	Sohan Singh, son of Sardul Singh	..	36	0
11.	Hardyal Singh, son of Isher Singh	..	38	6
12.	Gurbachan Singh, son of Sewa Singh	..	9	12
13.	Lachhmi, widow of Thakar Singh	..	36	10

(c) The matter was brought to the notice of the Deputy Commissioner, Amritsar on 18th September 1953, who stopped further proceedings in the matter.

(d) A complaint from Shri Sajjan Singh Margindpuri was received in Deputy Commissioner's Office, Amritsar through the Development Commissioner, but it has been found to be incorrect as no orders were passed by the D. R. R., for the delivery of possession on 26th August 1953. The final orders for the delivery of the possession were communicated to the Deputy Commissioner, Amritsar on 17th Sepetmebr 1953 and action has accordingly been taken in the matter.

INDUSTRIAL POTENTIAL IN HOSHIARPUR AND KANGRA DISTRICTS.

***2602. Shri Jagat Ram Bhardwaj.** Will the Minister for Finance be pleased to state wheher he is aware of the existence of industrial potential in the Districts of Hoshiarpur and Kangra ; if so, the steps taken by the Government to utilise that potential for the industrial advancement of the State ?

Sardar Ujjal Singh : Information is being collected and will be supplied to the Member, when ready.

SALE OF STANDING TREES IN CULTURABLE EVACUEE AREA.

***2788. Shri Mani Ram** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

whether the allottees of the culturable allotted area in the State have been allowed by the Government to use or sell standing trees in the culturable evacuee area allotted to them ?

Sardar Ujjal Singh : Trees which interfere in cultivation of land are allowed to be cut on the condition that the allottees plant double the number of trees on the embankment of the fields within a year. Such permission is granted by Circle Revenue Officer on receiving an application from the allottee in which the number of trees to be cut are specified.

GOVERNMENT AND PRIVATELY-MANAGED COLLEGES IN THE STATE.

***2574. Shri Rala Ram** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of Government Colleges as well as privately-managed Colleges in the State at present ;

(b) whether it is a fact that the number of privately-managed Colleges has increased ;

(c) whether the amount sanctioned by the Government for financial help to these privately-managed institutions was cut down during the years 1952-53 and 1953-54 ; if so, the reasons therefor ?

Shri Jagat Narain : (a) Government Colleges .. 13

Other .. 37

(b) Yes.

(c) No.

BASIC SCHOOLS IN THE STATE.

***2575. Shri Rala Ram** : Will the Minister for Education be pleased to state the number district-wise of basic schools in the State existing as on 31st January 1954 ?

Shri Jagat Narain : A statement is given below—

Statement showing the number of basic shools in the State as it stood on 31st January 1954 district-wise.

1.	Amritsar	..	6
2.	Ferozepore	..	8
3.	Gurdaspur	..	30

4.	Hoshiarpur	..	9
5.	Jullundur	..	7
6.	Ludhiana	..	6
7.	Kangra	..	7
8.	Ambala	..	57
9.	Gurgaon	..	5
10.	Hissar	..	9
11.	Karnal	..	6
12.	Rohtak	..	4

SCHOOLS IN AMRITSAR DISTRICT.

***2756. Sardar Darshan Singh** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of schools in Amritsar District at present together with the number of schools opened by the Government, the District Board, the Municipality and the private Agencies, respectively, during the year 1953 ;

(b) the total number of teachers employed in these schools at present and the number of Harijans amongst them ;

(c) the number of teachers employed during the year 1953 in these schools and the number of Harijans amongst them ;

(d) the steps taken by the Government to bring the percentage of Harijans among teachers to 19 per cent ?

Shri Jagat Narain : The information is being collected and will be supplied to the member.

LAND LEASE IN CHANDIGARH CAPITAL.

***2507. Shri Babu Dayal** : Will the Minister for Public Works be pleased to state whether he is aware of the fact that there is a great resentment in the public against the high rate of land lease in Chandigarh Capital ; if so, the action Government intends taking in the matter ?

Sardar Gurbacahan Singh Bajwa : It is not corrrct to say that the rates of land lease in the Capital are high and that there is any resentment among the public on this account. Government, therefore, do not intend to take any action in the matter.

CATERING ARRANGEMENTS FOR 7TH OCTOBER 1953.

***2564. Shri Dev Raj Sethi** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether a tea party was arranged in honour of the President on 7th October 1953, at Chandigarh, in connection with the Inauguration ceremony of the New Capital ;

[Shri Dev Raj Sethi]

(b) the name of the caterer to whom the catering arrangements were given by the Government, together with the terms settled with him ;

(c) the total payment made to the said caterer by the Government in this connection ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) Yes.

(b) Catering arrangements for the tea were entrusted to Messrs Oberoi Hotels Limited at the rate of Rs 4 per guest. In addition, the Government were also to pay the caterers the cost of transport of foodstuffs, crockery, hostel-personnel, etc., from Delhi to Chandigarh.

(c) A sum of Rs 14,220 has already been paid and bills amounting to Rs 3,431 are still under investigation.

OFFICERS' HOSTEL CHANDIGARH.

***2565. Shri Dev Raj Sethi** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the total cost of the building used as Officer's Hostel at Chandigarh ;

(b) the total cost of the furniture provided by the Government in that Hostel ;

(c) the name of the firm to whom the said Hostel has been leased out, and the manner of leasing it out ;

(d) the terms on which it has been leased out by the Government ;

(e) the total number of suites in the said Hostel ;

(f) the details of facilities, if any, for extending the number of suites under canvas or otherwise ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) About Rs 4,90,000.

(b) About Rs 50,000.

(c) The Officers' Hostel has been leased out to M/s. Oberoi Hotels, Limited by private negotiations.

(d) The main terms of lease are as follows :—

(i) The building, along with its fittings and furniture has been leased out to Messers Oberoi Hotel Limited, for a period of 3 years in the first instance with an option to the lessee to extend the lease for a further period of 3 years. The rent payable by the lessee will be as follows :—

		Rs
1st year	..	19,200
2nd year	..	24,000
3rd year	..	28,800

		Rs
4th year	..	33,600
5th year	..	33,600
6th year	..	33,600

(ii) Out of the total accommodation of 24 single and 9 double suites, Government will be entitled always, to the use of 10 single and 3 double suites. Officers staying in these suites will pay at the rate of Rs 10-8-0 per day for single suites and Rs 19 per day for double suites.

(iii) The lessee will have the right to utilise the suites reserved for Government, when these are lying vacant. Government will exercise no control on the rates to be charged by the lessee from private guests.

(iv) Government will make certain alterations and additions to the building, the details of which are yet to be decided.

(v) Annual repairs to the building and the replacement of fittings and furniture, when necessary, will be the responsibility of the Government.

(vi) Government will grant to the lessee a bar license for the sale of foreign wines and spirits.

(e) Twenty-four single and nine double suites.

(f) None at present.

PRIVATE PLOTS AT CHANDIGARH CAPITAL.

***2600. Shri Jagat Ram Bhardwaj** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the total number of plots so far allotted by the Government to private persons in the Capital Area at Chandigarh ;

(b) the total number of private houses and business premises so far constructed upon such plots ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) and (b) The desired information is given below :—

——		Number of plots allotted to private persons	NUMBER OF BUILDINGS CONSTRUCTED THEREON	
			(a) Completed	(b) Under construction
Residential	..	7,021	..	6
Industrial	..	67	1	2
Commercial	..	154	2	55
Total	..	7,242	3	63

RESIDENTIAL QUARTERS AT CHANDIGARH.

*2601. **Shri Jagat Ram Bhardwaj** : Will the Minister for Public Works be pleased to state whether he is aware of the fact that the residential quarters built for clerks and peons and other Government Servants at Chandigarh Capital are unsafe from the point of view of security ; if so, the steps, if any, proposed to be taken by the Government in the matter ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa, : On receiving complaints from certain residents of type 10-F and 11-F houses, it was felt that these houses needed an extra door and iron bars to the windows. Orders have accordingly been issued to make necessary additions.

OBSERVATIONS-MADE BY THE SPEAKER.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। बहस शुरु होने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे चीफ़ मनिस्टर साहिब की Mother-in-law स्वर्गवास हो गई हैं इसलिये वह तशरीफ़ ले गए हैं। जैसा कि आम तौर पर ऐसे मौकों पर होता है, कोई और मंत्री उन का काम करेंगे। सरदार उज्जल सिंह जी को उत्तर देने के लिये एक घंटा चाहिये। इस वक्त तीन बजे हैं। और अब से 6-30 बजे तक तकरीरें करने के लिये हमारे पास वक्त है। 6-30 बजे हाऊस की बैठक उठ जायेगी। चूंकि ऐन मुमकिन है कि आप में से कोई साहिब Division कराना चाहें या Lobbies में जाना पसन्द करें तो इस के लिये आधे घंटे का वक्त रख लिया गया है। और कारंवाई छ: बजे तक चल सकती है। 5 से 6 बजे तक सरदार उज्जल सिंह इस बहस का जवाब देंगे। इसलिये हमारे पास ? घंटे बहस के लिये बाकी हैं।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਕੀ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੋ ।

अध्यक्ष महोदय : वह वक्त तो चीफ़ मनिस्टर साहिब ने खुद मन्ज़ूर किया है। इसलिये अगर वह मौजूद नहीं तो मैं उन के बग़ैर उस वक्त की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अब अर्ज़ यह है कि अब तक मेरे पास 10 Amendments के नोटिस आए हैं और अगर हरेक को 15 मिनट दिये जाएं तो 15 × 10 कितने होते हैं ?

श्रीमती शन्नो देवी सहगल : 150 मिनट ।

अध्यक्ष महोदय : इसलिये दोनों तरफ से जो साहिबान तकरीरें फ़रमाना चाहते हों वह आपस में फ़ैसला कर लें कि सारे मेम्बर साहिबान ही बोलेंगे या उन में से कुछ ?

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾ ਵਕਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤੇ ਅਧਾ ਵਕਤ opposition ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ।

अध्यक्ष महोदय : अगर वे सब साहिबान जिन के नाम मेरे पास हैं तकरीर करना चाहते हैं तो मैं यह कर सकता हूं कि वे बारीबारी खड़े हो जायें और मैं घंटी बजा दूंगा। मैं Time Limit दोनों तरफ के मशवरे से ही fix करना चाहता हूं। मैं पूछता हूं कि क्या पांच मिनट काफ़ी होंगे (आवाजें : नहीं जी दस मिनट) अच्छा तो यह फ़ैसला रहा कि एक घंटा आप को और एक घंटा उन को। अब मुझे यह बतायें कि आप में से कौन २ साहिबान बोलेंगे क्योंकि मेरे पास तीन चार लिस्टें हैं ?

श्री सिरी चन्द : हमारी तरफ़ से पांच आदमी बोलेंगे। २ आदमी 15—15 मिनट और तीन 10—10 मिन्ट।

अध्यक्ष महोदय : मैं Time के मुतअल्लिक पूछ रहा हूं कि जिन के नाम मेरे पास हैं उन को ही बोलने का वक्त दिया जाये या जो भी खड़ा हो और जिस का नाम मैं लूं। क्योंकि इस में भी तो Opposition में A. B. C. D. Divisions हैं और कई तरह की Problems हैं इसलिए मैं चाहूंगी कि सारी Opposition की तरफ़ से बता दिया जाये कि कौन कौन बोलेंगे ?

श्री बाबू दयाल : जिस की Amendments पहले है वह पहले बोलें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई एतराज़ नहीं अगर सब Agree करें तो।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰਿੲ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ (*Interruptions*).

Mr. Speaker : Order please.

RESUMPTION OF DISCUSSION ON GOVERNOR'S ADDRESS.

श्री सिरी चंद (बहादुरगढ़) : साहिबे सदर ! हमारे मुल्क के जो हालात हैं और जिन के मुतअल्लिक पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने भी कहा है कि आजकल हालात ऐसे हैं कि Nation के सब आदमियों को इकट्ठे हो कर पूरे इतहाद के साथ मुल्क के लिये काम करना चाहिये। हमारे गवर्नर साहब ने भी Address में यह बात कही है कि पंजाब में अगर कोई ताकत है तो वह है लोगों के इतहाद में। इन हालात के पेशे नज़र में अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि वह अपनी तकरीरों की Tone जो वह इस सदन में करते हैं, ज़रा संजीदा कर दें। आपस में एक दूसरे पर सख्त इलफाज़ में एतराज़ करने से क्या फ़ायदा ? हमें ऐसा Atmosphere पैदा करना चाहिये कि जिस से ऐसे हालात पैदा हो जायें कि हम सब मिल कर काम कर सकें। मेरा ख्याल है कि आपस में इतहाद करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती।

साहिबे सदर ! मैं अच्छी तरह जानता हूं कि चीफ़ मनिस्टर साहिब और डिप्टी चीफ़ मनिस्टर साहिब खुश नहीं होते जब लोगों पर जुल्म किया जाये। मगर पता नहीं क्या वजह है कि जब वह मनिस्टर बन जाते हैं तो लोगों से ऐसे Cut Off हो जाते हैं कि उन को और कोई बात सूझती ही नहीं। उनके सामने एक Smokescreen या Iron Curtain सा आ जाता है। इसी वजह से उन को सब बातें नहीं बताई जातीं। और उन के आस पास ऐसा Atmosphere बना दिया जाता है कि वे अपने Officials की रिपोर्ट पर ही रहते हैं। इन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। इसलिये आम लोगों को शिकायत होती है कि जो भी मनिस्टर बन जाता है वह बहकी बहकी बातें करने लग जाता है। उन का नज़रिया वह नहीं रहता जो कि हम बताना चाहते हैं।

साहिबे सदर ! मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि रोहतक के हालात के बारे में जो रिपोर्ट हमारे मनिस्टर साहिबान को दी जाती है वह दीदा दानिस्ता उन को Mislead करने की कोशिश से दी जाती है। साहिबे सदर ! मैं आप की वसातत से कैबिनट (Cabinet) से दरखास्त करना चाहता हूं कि ये ऐसे मामले हैं जिन पर उन्हें संजीदगी के साथ सोचना

[श्री सिरी चंद]
चाहिये। माना कि पुलिस अफ़सर बड़े हुशयार हैं और Expert हैं और इन को Expert भी होना चाहिये। मगर इस का यह मतलब नहीं कि दूसरी पार्टी पर इलज़ाम लगाया जाये कि वह मफ़रूरों की मदद करती है। मेरी गुज़ारिश यह है कि ऐसी बातों से मफ़रूरों को पकड़ने में मदद नहीं मिलती। इस का उल्टा Psychological Effect होता है। साहिबे सदर ! इस Motion के Proposer ने इशारा किया है कि हम मफरूरों की मदद करते हैं। यह बिल्कुल ग़लत बात है। साहिबे सदर, मैंने न सिर्फ इस असेम्बली में बल्कि दस २ हज़ार लोगों के मजमें में कहा है कि जो डाके डालते हैं, मार धाड़ करते हैं, और कत्ल करते हैं उन को गिरफ़तार करना चाहिये। मैंने और चौधरी सूरजमल जी ने एक मुकदमा में, जिस में कि मफरूरों और उन के साथियों ने बड़िबा गांव में कत्ल किया था, उन के खिलाफ़ शहादत दी और उन को फांसी की सज़ा दिलवाई। इन हालात में यह कहना किसी तरह भी ठीक नहीं कि दूसरी पार्टी उन की मदद करती है। वह कोई भगत सिंह नहीं और न ही उन्हें कोई देश भक्त समझता है। मैं ललकार कर कहता हूं कि कोई भी आदमी यह साबित नहीं कर सकता कि उन लोगों ने कोई Political कत्ल किया है या किसी वोटर पर किसी पार्टी की ख़ातिर दबाव डाला है। वह तो पैसे की ख़ातिर या दुशमनी की वजह से कत्ल करते थे। बस ऐसे ज़लील आदमियों की कौन शरीफ़ आदमी मदद कर सकता है ? लेकिन चूंकि पुलिस जब यह लिख देती है कि दूसरी पार्टी इन लोगों की मदद करती है तो सरकार इस बहाने को फ़ौरन कबूल कर लेती है। पुलिस वाले हमेशा ऐसी बात लिख देते हैं और उन की नालायकी पर पर्दा पड़ा रहता है।

साहिबे सदर ! मुझे कल दो तकरीरों पर बड़ा ताज्जुब हुआ। एक तो श्री राम किशन जी ने पुलिस वालों को देवता बना दिया। मेरा ख़्याल है कि उन को पुलिस के तौर तरीकों का बड़ा तजुरबा है, और वह अब तक पुलिस की मार न भूले होंगे। वह जानते हैं पुलिस क्या कुछ किया करती है मगर उन की तकरीर सुन कर यह मालूम होता था कि पुलिस दो ही साल में बिल्कुल देवता बन गई है।

दूसरी तकरीर श्री देवराज सेठी की थी। उन्होंने कहा वकील लोग डाकुओं के हमदर्द हैं। वह चाहते हैं कि डाके पड़ें ताकि उन का काम चलता रहे। मैं पूछता हूं कि क्या यह बात सचमुच संजीदगी से कही गई थी ? ऐसी लचर बात एक तालीमयाफ़ता आदमी को कहनी शोभा नहीं देती। गांधी जी वकील थे, जवाहर लाल जी वकील हैं, उन के पिता जी वकील थे। क्या इन लोगों के बारे में ऐसी बात कही जा सकती है ? वकीलों में एक आध बुरा आदमी भी हो तो सब के बारे में ऐसी बात क्यों कर कही जा सकती है ? फिर सब से बड़ी बात यह है कि वकीलों को इस से क्या फ़ायदा हो सकता है ? वह लोग तो मफ़रूर होते हैं, आप से पकड़े ही नहीं जाते। फिर मफ़रूरों के मुकदमे ले कर कौन आता या आ सकता है ?

साहिबे सदर ! डाकुओं ने जो कुछ रोहतक में किया उस की तसवीर आप के सामने आ चुकी है। उन्होंने गरीबों को मारा और कत्ल किया। इन ग़रीबों के साथ सब को हमदर्दी है मगर उन के दु:ख का इलाज यह नहीं जो आपने किया है। यह तो वही बात है कि एक बच्चा रो रहा था, बाप ने पूछा क्या बात है तो मां ने बताया कि बालाई मांग रहा है। यह

सुन कर बाप बोला इस से रोटी भी छीन लो (*Laughter*) जनाब, मैंने पुलिस वालों को यह जुल्म करने पर पूछा कि यह क्यों कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि यह लोग पुलिस को खबर नहीं देते। मैंने कहा कि वह बेचारे ग़रीब लोग तो डाकुओं से डरते हैं मगर वह अफ़सर कहने लगा कि अब हम इन को पुलिस से इतना डरायेंगे कि यह डाकुओं का डर भूल जायेंगे और अपने आप ही आ कर हमें सब कुछ बतायेंगे। यह थी जनाब हमारी पुलिस की मन्तक !

अब ज़रा पुलिस की इस शिकायत का हाल भी सुनिये कि लोग इत्तलाह नहीं देते। एक शख़्स ने इत्तलाह दी थी। उस को डाकुओं ने ज़िन्दा जला दिया और किसी से कुछ न बना, अमर सिंह सासाने वाले ने डाकुओं को आप पकड़ने की कोशिश की, उस को गोली लगी और मामला इसी पर खत्म हो गया। एक और शख़्स थानेदार को बताने गया कि डाकू बन्द कर दिये हैं चल कर पकड़ लीजिये तो थानेदार साहिब सो रहे और उस ग़रीब के दो भाई मारे गये।

विकास मंत्री : क्या यह ठीक वाकिया है ?

श्री सिरी चन्द : जी हां, आप के बड़े बड़े पुलिस अफ़सरों को इस का इल्म है। वह आदमी इत्तलाह करने गया कि डाकू बन्द हैं मगर थानेदार साहिब बोले कि बदमाश सोने भी नहीं देते 'भाग जाओ'। इस पर उस बेचारे ने अपना थाना बहादुरगढ़ छोड़ कर सांपला में रिपोर्ट की, तब वह डाकू पकड़ा गया। दूसरी तरफ़ यह बात भी काबले ज़िक्र है कि जिस आदमी ने काले मफ़रूर की मुखबरी की थी उस का बन्दूक का लाइसेंस मनसूख कर दिया गया। खैर जनाब, मैं यह पूछता हूं कि लोगों का तो डाकुओं के हाथों यह हाल हुआ मगर क्या पुलिस के किसी एक आदमी को डाकुओं के हाथ से एक रगड़ भी लगी है ? जिस ताज़ीरी पुलिस पर इतना खर्च किया गया, उस ने अपना पेट भरने के सिवा क्या काम किया ? क्या उस का यह जवाब काफ़ी है कि हम कुछ नहीं कर सके क्योंकि दूसरी पार्टी वाले डाकुओं की मदद करते थे ? डाकू पांच साल तक तबाही मचाते रहे और अब पुलिस की तरफ़ से यह जवाब दिया जा रहा है। कल एक दोस्त ने कहा था कि मार पीट तो बेशक हुई लेकिन पुलिस कहती है कि ऐसी मार पीट तो हुआ ही करती है। फिर कहा कि वहां लूट हुई थी और पुलिस ने तीस हजार का माल निकलवाया। जनाब ! मैं अर्ज़ करता हूं कि ख़ुद पुलिस ने तीन लाख रुपया लूटा। हमें यह भी सुनाया गया कि जम्मू से हमारी पुलिस की बड़ी तारीफ़ आई है मगर मैं यह कहता हूं कि पंजाब वाले जम्मू और हैदराबाद में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे।

अब मैं इन सब बातों को छोड़ कर आप के सामने एक सन्यासी का बयान पेश करता हूं। स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी का किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं ? उन का बयान सुनिये। मैं आप से पूछता हूं कि कौन सी ऐसी ज़लील पार्टी हो सकती है जो अपनी कंवारी लड़कियों से ऐसे बयान दिलाये। एक 14 साल की लड़की ने कहा कि मेरे मुंह को काटा गया और फिर मेरे साथ रेप (Rape) किया गया। एक 16 साल की कंवारी लड़की का बयान है कि मेरी चची को बाहर निकाल दिया गया और मेरे साथ रेप किया गया। एक और 16 साल की बच्ची ने भी ऐसा ही बयान दिया। कोई बताये कि कंवारी लड़कियां इस किस्म के बयान झूठ मूठ क्यों कर दे सकती हैं जिन के सामने अभी सारी उमर काटने को पड़ी है।

[श्री सिरी चंद]

खैर साहिब सदर ! स्वामी स्वतन्त्रानन्द कहते हैं कि चौधरी साधुराम हरिजन पंच और जेकरन हरिजन और चौधरी माम चन्द और दूसरे हरिजनों ने बयान किया जिस को चौधरी मामचन्द, एम. एल. ए. भी सुन रहे थे कि इस तरह की मार पीट और अन्याय हमने इस से पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने मिसाल दे कर कहा कि जिस तरह चक्की में डाला हुआ दाना शायद ही पिसने से बचे उसी तरह हमारे गांव में कोई किस्मत वाला ही पुलिस की मार से बचा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिस आदमी ने यह पूछा कि मेरा कसूर तो बताया जाये उस को सब से ज़्यादा मार पड़ी और पुलिस ने कहा कि कसूर तो सच्चर और लहरी सिंह से जा कर पूछो। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि मार पीट बिना पूछताछ और जातपात के भेदभाव के की गई थी। उन्होंने फिर कहा कि जब हम चौपाल में थे तो बहुत से लोगों को चौपाल में नंगा करके सब के सामने औंधा कर के उनके चूतड़ों को खूब पीटा गया। एक बार कहा गया कि फुलां तरफ़ के सब कोहलू वाले चौपाल के नीचे आ जायें। इस पर कोई 50 आदमी चौपाल के नीचे गये। पहले तो उन की धोतियों की लांगड़ खुलवाई गई, फिर उन को उल्टा लिटाया गया। इस के उपरान्त एक सिपाही ने उन की गर्दन की तरफ़ खड़े हो कर उन के चूतड़ों पर डंडों और जूतों से खूब मारा। इस के बाद लगभग 10 आदमियों का एक गिरोह और बुलाया गया। उसे भी इसी तरह पीटा गया। फिर शाम के साढ़े तीन बजे के लगभग सब को छोड़ दिया गया। गांव में किसी तरह की पूछताछ नहीं की गई।" साहिबे सदर ! हालात यह हैं कि D. I. G. को रिपोर्ट के लिये कहा जा रहा है। क्या उस D. I. G. से जिस ने खुद डाके मरवाये, लूट मचावाई और Rape करवाये सच्ची रिपोर्ट की उम्मीद की जा सकती है ? हरगिज़ नहीं। इस पुलिस के बारे में हम सब जानते हैं। दो साल हुए जमनानगर से दो लड़कियां निकाली गईं पर यह पुलिस अभी तक उन का कोई पता नहीं लगा सकी।

मेरे लायक दोस्त श्री देवराज सेठी ने माना है कि Police ने मार पीट ज़िला रोहतक में ज़रूर की है। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि लड़कियों को Rape भी किया गया है। मैं उन तीन लड़कियों के नाम जिन के साथ Rape किया गया, नहीं बताऊंगा लेकिन इतना कह देता हूं कि इन तीनों लड़कियों के बयान श्रीमती लक्ष्मी देवी जी ने लिखे हैं। यहां पर और भी बहुत कुछ हुआ। लोगों को शहर के बाहर बुलवा कर गोली से हलाक कर दिया गया और यह कहा गया कि Encounter हो गया था। लोगों का अनाज इकट्ठा करवा के उसमें पेशाव करवाया गया और उसे गोबर में मिला दिया गया। मैं पूछता हूं कि क्या ऐसी हरकतें करने से डाकू पकड़े जाते हैं ? वह भूपत जिस को पकड़ने के लिये Police गई थी, D. I. G. और I. G. के हाथों से भाग गया लेकिन उन से कोई पूछने वाला नहीं कि वह डाकू को क्यों न पकड़ सका। यदि फ़ौजी अफ़सरों से ऐसा हो गया होता तो नमालूम उन के साथ क्या सलूक किया जाता। यहां तमाम ज़िम्मेवारी लोगों पर फेंकी जा रही है। एक चमार के लड़के को कहा जाता है कि Police को डाकुओं की तरफ़ ले जाये। उस को आगे आगे चलने के लिये कहा जाता है और जब डाकू उस पर गोली चलाते हैं तो Police भाग जाती है। यह हैं कारनामे हमारी Police के !!

श्री बदलू राम (कलानौर) : प्रधान जी, मेरे साथियों ने रोहतक ज़िले का बहुत ज़िकर किया। उन्होंने पुलिस की बहुत बुराई की है। परन्तु बात बिल्कुल वैसी नहीं जैसी कही गई है। हमारे ज़िले को भूपत का ज़िला कहा गया है। यह भूपत तो चार या पांच साल से सुनने में आ रहा है। इस ज़िले में तो ३० साल से भूपत चले आते हैं और इस का कारण केवल पार्टीबाजी है। मैं इस बात को साबत कर सकता हूं। लोग ठाकुर, जाट, ब्राह्मण आदि बन कर हमारे ज़िले में छिपते रहे हैं और डाके मारते रहे हैं। यह ठीक है कि इन डाकुओं के पकड़ने में Police कामयाब नहीं हो सकती। Police वहां कामयाब हो सकती है जहां पार्टीबाज़ी न हो। जब तक पार्टीबाज़ी रहेगी डाकू अपनी मनमानी करते ही रहेंगे। मुझे याद है कि ज़मींदारा वज़ारत के दिनों में जब सर सिकन्दर हयात और हमारे ज़िले के वज़ीर साहिब रोहतक आये तो उन का जलूस निकाला गया। इस के बाद यह हुआ कि दुकानें लूटी गईं। और स्वयं पंडित श्री राम शर्मा को छिप कर अपनी जान बचानी पड़ी थी। अब कहा जा रहा है कि इस मामले का पार्टीबाज़ी से कोई सम्बन्ध नहीं और स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी का नाम लिया जा रहा है। मेरे मित्र कहते हैं कि उनका किसी पार्टी से सम्बन्ध नहीं। मैं कहता हूं कि यह कैसे नहीं। क्या उन्होंने 8 तारीख को एक विरोधी Political Party की मीटिंग (Meeting) की प्रधानगी नहीं की जहां यह सब तकरीरें हुईं।

अध्यक्ष महोदय : आप स्वामी जी को बहस में न लायें।

श्री बदलू राम : स्पीकर साहिब, रोहतक में 4 तारीख को स्वामी जी की प्रधानगी के अधीन Meeting हुई और एक गांव के लोगों ने 9 तारीख को Police का मुकाबला किया।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को रहने दें क्योंकि इस पर अदालत में कार्यवाही हो रही है।

श्री बदलू राम : मैं इस मामले के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो केवल पार्टीबाज़ी की बात करता हूं। मैं रत्नथयां के बारे सब कुछ जानता हूं। यह ठीक है कि मैं दूसरे गांव में नहीं गया। वहां हालत ऐसी हो गई थी कि यदि मैं वहां जाता तो ज़िन्दा वापिस न आता। श्रीमान् जी, कहा गया है कि रावड़ा गांव में एक आदमी की ३० मन खांड और उस का पांच मन घी उठा लिया गया। यह भी कहा गया है कि वहां औरतों की बहुत बेइज्ज़ती की गई। और जब गांव वालों से पूछा गया कि क्या क्या हुआ है तो लोगों ने कहा कि उन्हें पीटा गया है। इस से हम इन्कार नहीं करते कि लोगों को पीटा गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मैम्बर से कहूंगा कि वह अपना भाषण दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बदलू राम : श्रीमान् जी ! मुझे अफ़सोस है कि रोहतक ज़िला बहुत बदनाम किया गया है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि रोहतक ज़िले में क्या हुआ। राम सिंह काला मफ़रूर जागसी गांव का रहने वाला है और थोड़े दिन हुए मारा गया। राम किशन मफ़रूर भी उसी गांव का रहने वाला था। आस पास के इलाके में जो भैंसें चोरी हो जाती हैं वह जागसी जाती रही हैं। एक छुडवाली गांव है वहां मफ़रूरों ने एक नाई से मिल कर उस से झूठ बुलवाने की कोशिश की नाई को बुला कर मफरूरों ने उसे पीटा क्योंकि उस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था।

श्री सिरी चंद : The case is *sub judice*.

अध्यक्ष महोदय : मैं मेम्बर साहिबान से गुजारिश करूंगा कि वह इस बात का ख्याल रखें कि *Sub judice* cases को ज़ेरे बहस नहीं लाया जा सकता।

श्री बदलू राम : मैं पार्टी बाज़ी की बात बताता हूं कि वहां कितनी पार्टी बाज़ी है। नाइयों को बुलाया गया है और पीटा गया।

श्री सिरी चंद : यह ठीक है कि Lower Court ने इस मुकद्दमे का फैसला कर दिया है लेकिन हाई कोर्ट में इस की अपील Pending है।

सिंचाई मंत्री : नाई की मार पीट का कोई मुकद्दमा नहीं हुआ मुकद्दमा तो कत्ल का हुआ है।

श्री बदलू राम : मैं तो पार्टीबाज़ी का ज़िक्र कर रहा हूं। नाईयों को बुला कर पीटा गया। थाना में रिपोर्ट दी गई। दो आदमी रात के वक्त मारे गये। मैं पूछना चाहता हूं कि वह नाई किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे। नाईयों को इस लिये पीटा गया कि वह झूठ नहीं बोलना चाहते थे। बखतावरपुर में हमारे एक वज़ीर ने ६०० रुपये की थैली ली और हथियारों के लाईसेंस Cancel करवाए। दो आदमी वहां मारे गये जिन्होंने उन को वोट दिये। आज हम किसी पुलिस के अफसर को अपने ज़िले में दाखिल नहीं होने देते। हरफूल सिंह डाकू ब्राह्मणों के घर ठहरता रहा। उसने मुसलमानों को मारा। मुगला ने हिंदुओं को मारा। दीपा को ब्राह्मण ठहराते रहे और हेमा को जाट। यहां तो बिरादरियों और मज़हबों के नाम पर मफरूर होते रहे हैं। अब कुछ हकूमत ने किया तो लोग बुरी भली कहते हैं। रोहतक में एक बार अकालियों के लीडर ने कहानी सुनाई। रामचन्द्र के ज़माने में जब वे बनवास गये तब उन्होंने सब नर-नारियों को लौटने के लिये कहा। वहां के नर नारी चले आए। जब वे १४ वर्ष के बाद बनवास से लौटे तो हीजड़ों को वहीं बैठे देख कर पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें तो चले जाने के लिये नहीं कहा गया था। इस लिये वे वहीं १४ वर्ष रहे। राम चंद्र जी ने प्रसन्न हो कर कहा कि "जाओ तुम भी कलियुग में चार साल राज करोगे" कल इसी हीजड़ों के राज ने थोड़े से बुरे आदमियों पर हाथ उठाया है तो इसी से रो पड़े हैं (हंसी)। अगर कहीं मर्द करते तो पता नहीं क्या होता। हर गरीब आदमी इस वक्त यह कहता है कि अजीब है यह राज। हीजड़ों के राज में सुख है और हर आदमी आज़ादी से बाहर निकल सकता है!

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मेम्बर को 'हीजड़ा' का शब्द इस्तेमाल करने में खुशी होती है।

श्री बदलू राम : राज तो हीजड़े कर रहे हैं मगर मारे गये हैं वकील और मुनशी।

अध्यक्ष महोदय : आप कौन सी ज़बान बोल रहे हैं?

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਹੀਜੜਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ (ਹਾਸਾ)।

श्री बदलू राम : ७०० रुपये की थैली ले कर लाईसेंस Cancel करवा दिये और दो आदमी मरवा दिये।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of personal explanation, Sir......

अध्यक्ष महोदय : ज़रा उन को बोलने दीजिये! आप कृपा कर के बैठ जायें!

श्री बदलू राम : एक बात और सुन लें। मेरे अपने गांव के नज़दीक, पिछले साल की बात है, कि भावड़ गांव में एक आदमी को जिन्दा जलाया गया। यह लोग उस वक्त कहां थे। जब इतने जुल्म हुए तो किसी आदमी ने इस के खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाई लेकिन आज कहते हैं कि लड़कियों के साथ यह हुआ, वह हुआ। हरयाना प्रांत में और कोई आदमी किसी लड़की को बुरी नज़र से देख ले तो कत्ल हो जाते हैं। अगर कई साहिब मेरे साथ रबड़ा गांव में चलें तो वहां उन्हें एक आदमी भी नहीं मिलेगा जो यह कह दे कि वहां कभी औरतों की बेइज्ज़ती की गई है।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ Opposition ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਅਜ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਏਨਾ ਨੀਵਾਂ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮੈਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਕ ਆਊਟ ਨੂੰ Treasury Benches ਵਲੋਂ Misrepresent ਕਰਕੇ Opposition ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ Serious Allegations ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਕਿਆਤ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ Allegations ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ Allegations ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1/5 Population ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਕ Constitutional Head ਹਨ, Constitutional Monarch ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੂੰਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਤਹਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ Protest ਕੀਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਇਕ Constitutional Head ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ Central Government ਨੂੰ Represent ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਵਜੁਹ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਵਾਉਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਇਤਨੇ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗਲ ਕਰੇ ਅਤੇ Treasury Benches ਉਸ ਨੂੰ Defend ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ Concession ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਦੇ Debate ਦਾ Level ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Allegation ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਉ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ Disinterested Enquiry ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Impartial

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

Enquiry ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ਼ਾਲਿਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ Affairs ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ-ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ Opposition ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ Black ਤੋਂ Black Paint ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਉਹ Enquiry ਕਰਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ Allegations ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਵਾ ਦੇਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ Opposition ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ Enquiry ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਲ-ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ Protest ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ Cabinet ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ Border ਦੇ ਪਰਲੀ ਤਰਫ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖ਼ਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ Without Trial Detained ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਬਾਹੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ Defend ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਗਲ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਵਿਚ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟੋ ਘਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ Morale ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ਼ਾਲਿਫਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਕ ਪੁਚਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ Secure ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : On a point of personal explanation, Sir. मुझे अफ़सोस है कि सरकारी मेम्बर personal हमले करके इस House की Discussion का Level नीचा करना चाहते हैं। चौधरी बदलू राम ने एक आदमी के क़त्ल के बारे में मुझ पर आरोप लगाया है। यह चीज़ सरासर ग़लत और बेबुनियाद है। हक़ीक़त यह है कि एक वज़ीर ने कोशिश करके एक बेगुनाह आदमी को फंसाया था। मगर सैशन कोर्ट ने

उसे छोड़ दिया । इस मामले से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था ।

(At this stage Chaudhri Badlu Ram rose to speak again and again and there was a loud noise).

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये ! आपने पहले ही अपनी तकरीर में अपनी तहज़ीब का काफी सबूत दे दिया है । अब आप फिर खड़े होते हैं । (Loud cheers from the Opposition Benches)

विकास मंत्री : आप उस का भी Personal Explanation तो सुन लें !

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਸੁਝਾਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਥੇ 30, 35 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ Valuable Time ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ Constructive ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ Destructive ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਹਾਇਤ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ:—

"We must remove all weaknesses, all discords, all disparities from amongst us, because ultimately, it is a strong, united, peaceful and determined people that constitute a target that even the deadliest weapons find difficult to destroy."

ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਪਰ Question ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ Minority ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ Democracy ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ Dictatorship ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਬਦਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

श्रीमती सीता देवी (जालंधर शहर, दक्षिण पूर्व) : माननीय स्पीकर साहिब, बहुत अच्छा होता यदि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उचित रूप से भाषण किये जाते । तस्वीर का सही रुख पेश किया जाता । परन्तु कल से ले कर यह सदन रोहतक के Politics का अखाड़ा बना हुआ है । अभिभाषण को आदि से ले कर अन्त तक पढ़ा जाये तो जो काम उस में दर्ज हैं और जो हमारी सरकार ने एक वर्ष या दो वर्ष में करने हैं उन को जानकर कोई आदमी चाहे कितना ही anti-Government हो कितना ही anti-Congress हो कितना ही Prejudiced हो वह इस सचाई को झुटला नहीं सकता कि यह सब स्कीमें Paper पर ही नहीं है बल्कि इन पर अमल किया जा रहा है और यह साफ

[श्रीमती सीता देवी]

ज़ाहिर है कि हमारे सूबे ने इन के जरिये कितनी Development एक साल में की है। आप पैदल चलें, रेलगाड़ी में जायें या मोटर में जायें तो आप देखेंगे कि स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी नहरें बन रही हैं। स्थान २ पर Community Projects बन रहे हैं। यदि आप मेरे साथ Rupar से लेकर Bhakra तक जायें तो हर दो फर्लांग पर आप को नया Construction का काम दिखाई पड़ेगा। गंगोवाल का जो Power House बन रहा है वह देखने के योग्य है। मैंने तो मुख्य मंत्री साहिब से कई बार कहा है कि जो लोग जनता को Mislead करते हैं उन की तसल्ली करने का बेहतर तरीका यह है कि उन को ट्रेन में ले जाकर पावर हाऊस दिखलाया जाए। आंखों देखे और कानों सुने में बहुत फर्क होता है।

स्पीकर साहिब, इस सचाई से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि एक वर्ष के अन्दर पंजाब ने बहुत तरक्की की है। चूंकि वक्त बहुत थोड़ा है मैं हर एक पाइंट (Point) Briefly वर्णन करूंगी। पहले मैं Food Problem को लूंगी। पहले हमारा सूबा खाद्यान्न दूसरे सूबों से मंगवाता था। उस पर नियंत्रण था और राशन की व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी। परन्तु आज हमने न सिर्फ नियंत्रण ही उठा लिया है बल्कि राशन भी बन्द कर दिया है। सब से ज्यादा खुशी की बात यह है कि हम हज़ारों मन चावल और दूसरा अनाज दूसरे सूबों को दे रहे हैं। मुझे तो हर पहलू में उन्नति ही उन्नति नज़र आती है। Consolidation of Holdings के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहती हूं कि भाषण करना और बात होती है लेकिन अगर आप गांवों में जाकर किसानों से पूछें तो मालूम होगा कि किसान पहले की अपेक्षा कितने खुशहाल हैं। पांच सौ से अधिक Tube-well लगाये गये हैं। मैं ज़िला जालन्धर की रहने वाली हूं। अगर आप नकोदर में जाकर देखें तो आप लोगों को वैसा ही खुशहाल पायेंगे जैसा कि वे लायलपुर में थे। (*Interruptions*) जब आप लोग बोलते हैं तो मैं Interrupt नहीं करती (एक आवाज़-हम तो तारीफ़ करते हैं) अध्यक्ष महोदय, मैं बतला रही थी कि पंजाब में कितना नया काम Construction का हुआ है और कितनी उन्नति इसने की है। मैं मानती हूं कि Opposition होती है और होनी ही चाहिये, हैल्थी (Healthy) नुक्ताचीनी भी होनी चाहिये। परन्तु उन्होंने तो ऐसी ऐनक लगा कर रखी है जिस से एक चीज़ ही नज़र आती है। और असली चीज को वे देखने की कोशिश ही नहीं करते। हमारे एक नये साथी जो Opposition में गए हैं उन्होंने फरमाया है कि ये जो नहरें खोदी जा रही हैं, इन से कोई लाभ नहीं होगा। इस प्रकार उन्होंने ५ साला योजना को Criticize किया है। इसी प्रकार कहा गया था कि बिजली तो कांग्रेस निकाल कर ले जायेगी तो पानी किस काम का रहेगा। मैंने जालन्धर में यह भी सुना कि नहरों में एक बार तो पानी मिल जायेगा लेकिन उस के बाद पानी कहां से मिलेगा क्योंकि नदियों में पानी नहीं उपलब्ध होगा। इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करना चाहती हूं कि इंडस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि रावी, सतलुज व्यास और चनाब आदि नदियों में इतना पानी है कि केवल इस का 25 प्रतिशत ही प्रयोग में लाया जा रहा है और उस का 75 प्रतिशत समुद्र में बह कर वेस्ट (Waste) हो जाता है। आप के पास इतना पानी है और फिर तिब्बत

के बड़े २ बर्फानी पहाड़ों को कौन उड़ा कर ले जायगा। *(Interruptions)* ।

अगली बात में Transport की Nationalization के बारे में करना चाहती हूं। जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारें जमींदारी को समाप्त करना चाहती हैं और बड़े २ कारखानादारों के मुनाफों के रेट मुकर्र कर रही है, उसी प्रकार हमारी सरकार Minimum Wages Act आदि पास करके और दूसरे ऐक्ट पास कर के गरीब जनता को सुख पहुंचाना चाहती है। Nationalization of Transport भी इसी लिये की जा रही है। कहा गया है कि जहां जहां पर इस को अमल में लाया गया है लोग बहुत दुखी हो गए हैं। यह तो केवल लोगों को बहकाने वाली बात है। मैं कहना चाहती हूं कि जिस दिन सरकारी गाड़ियां चालू हुईं तो कई गांवों के लोगों ने तो लड्डू बांटे कि शुक्र है कि सरकार ने मोटरें चलाई हैं। Transport को चंद लोगों ने Monopoly बना रखा था। वे लोग लाखों रुपयों का मुनाफा कमाते थे लेकिन गरीब लोगों से २४ घंटे काम लेकर थोड़ी २ तनखाह देते थे। बेचारे वर्करज़ ज्यादा तनखाह मांगते थे तो उन को यह कह कर टाल दिया जाता था कि मुनाफा नहीं होता। इस लिये जब ट्रांसपोर्ट को नैशनलाइज़ किया जायगा तो गरीब लोग सुख महसूस करेंगे, इस लिये Transport की Nationalization जरूर होनी चाहिये। हां एक बात है कि वे लोग जिस किसी खास पार्टी को Finance करते थे उस के लिये वह सहायता समाप्त हो जायगी। मैं इन शब्दों के साथ इस Point को खत्म करती हूं।

इस के अतिरिक्त, स्पीकर साहिब, यद्यपि सरकार की अन्य सफलताओं और योजनाओं का उल्लेख करते हुए महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह भी बताया कि सरकार अपने राज्य में हरिजनों की स्थिति को सुधारने के लिये भी बहुत कुछ कार्य कर रही है, किंतु क्या ही अच्छा होता यदि वे एक और समस्या का, जो कि पंजाब में भयानक रूप धारण किये हुए है, भी कुछ थोड़ा बहुत उल्लेख करते। वह समस्या क्या है? वह भयंकर समस्या जो कि पंजाब की जनता और सरकार दोनों को परेशान किये हुए है, वह है लेबर (श्रमजीवियों) की समस्या। यह ठीक है कि गांव गांव में कोआपरेटिव सोसाईटियां (Co-operative Societies) स्थापित हैं.....................

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ : ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਨਾ ?

श्रीमती सीता देवी : ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਸੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। इस में कोई संदेह नहीं कि गवर्नमैण्ट इस समस्या पर सोई हुई नहीं। यह ठीक है कि श्रमिकों की हालत सुधारने के लिये कुछ न कुछ सोचा ही जा रहा होगा। यह भी ठीक है कि सरकार ने गांव गांव में कोआपरेटिव सोसाईटियों के संगठन के लिये सुविधाएं देने की घोषणा की हुई है। किंतु मुशकिल तो यह है कि इन सोसाईटियों को खोलना ही उन लोगों के लिये, जिन के पास अपना गुज़ारा करने के लिये भी चार पैसे नहीं, बड़ी कठिन समस्या है। अवल तो इनका बनाना ही मुश्किल है क्योंकि कई प्रकार के Regulations की सीमा में उन्हें रहना पड़ता है और अगर बन भी जायें तो उन्हें केवल Earthwork ही दिया जाता है जिस से गरीबों को कोई लाभ नहीं होता। वह तो सारे का सारा धन अमीरों की थैलियों में चला जाता है। इस लिये मैं, स्पीकर साहिब, आप के द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं और उन से विनय करना चाहती हूं कि वह इस बड़ी भारी समस्या

[श्रीमती सीता देवी]

की ओर विशेष रुची लें। अध्यक्ष महोदय, हैरानी की बात तो यह है कि हर एक जगह पर बड़े बड़े कारखानों का और दूसरी बड़ी बड़ी चीज़ों का तो नाम लिया जाता है कि उन को स्थापित करने के लिये, उन में सुधार लाने के लिये यह किया जाये और वह किया जाए किंतु इन मुसीबतज़दा लोगों के लिये बहुत कम कहा जाता है। स्पीकर साहिब, मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा मतलब यह नहीं कि सरकार इस दिशा में कुछ भी नहीं कर रही किंतु जो कुछ मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि इस ओर जो कार्यवाही की जाने वाली है उसे और भी अधिक तेज़ी से किया जाए। मिसाल के तौर पर जैसा कि उत्तर प्रदेश में लेबर के लिये सरकारी संघ बने हुए हैं और उसी प्रकार यहां अपने सूबे में भी किया जाए जिस से हमारे राज्य के लेबर कमिश्नर (Labour Commissioner) को और अधिक अधिकार मिल जायें और वे उन बेचारों की समस्या को हल करने के लिये कोई क्रियात्मक और रचनात्मक कार्यक्रम बना सकें। (इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय महिला सदस्या को अपना भाषण समाप्त करने का संकेत करते हुए घंटी बजाई)——स्पीकर साहिब, मैं केवल दो चार मिनटों में एक दो बातें और कह कर अपने स्थान पर बैठ जाऊंगी।

अब, अध्यक्ष महोदय, मैं देश में व्याप्त बेकारी की समस्या की ओर आती हूं। बेकारी की समस्या किसी भी देश के लिये एक ऐसी समस्या है जिस के होते वह देश किसी भी दिशा में उन्नति नहीं कर सकता। यह ठीक है कि महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में इस ओर भी संकेत किया है और यह घोषणा की है कि इस सिलसिला में सरकार ने चार करोड़ रुपया का प्रबन्ध किया है। किंतु मैं समझती हूं कि चार करोड़ रुपया भी इस जटिल समस्या के लिये बहुत कम है। जब तक इस समस्या का कोई संतोषजनक हल नहीं सोचा जाता तब तक, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि प्रान्त में कोई भी बड़ी स्कीम कामयाब नहीं हो सकती।

यह ठीक है कि हमारे शिक्षा मंत्री हर वर्ष कोई न कोई नया कालिज अपने प्रान्त में खोलने का निश्चय करते हैं। लेकिन जैसा कि मैं पहिले भी कई बार कह चुकी हूं ये कालेज आजकल तो बेकारी को ही ज्यादा पैदा करने का कारण बन रहे हैं। जो भी विद्यार्थी उन कालेजों से शिक्षा प्राप्त करके निकलता है——ऐफ. ए; और बी. ए. वगैरा की डिगरियां लेकर——नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता है परन्तु नौकरी नहीं मिलती। तो फिर क्या लाभ इन नये कालेजों का जो कि बजाये बेकारी को कम करने के इस में और भी ज्यादा वृद्धि करते हों?

इस के पश्चात्, स्पीकर साहिब, दो चार शब्द रोहतक के बारे में भी कह दूं। यद्यपि मेरा रोहतक के पालिटिक्स में पड़ने का कोई विचार नहीं और न ही मेरा रोहतक से कोई ताल्लुक है ....

श्रीमती शन्नो देवी : तो फिर मत कहो, कुछ!

श्री शेर सिंह : क्या रोहतक पंजाब में नहीं?

श्रीमती सीता देवी : मेरा मतलब यह नहीं। मैं जो कुछ कहना चाहती हूं वह यह है कि रोहतक का मसला एक बहुत बड़े वाद-विवाद का विषय बना हुआ है; इस लिये मुझे वहां की राजनीति में नहीं पड़ना है। मैं तो केवल एक दो बातें कहना चाहती हूं जो कि मुझे वहां

घटना स्थल पर जाकर मालूम हुई। हमारे सैनेट की एक सब-कमेटी की रोहतक में एक मीटिंग थी। मैं भी उस बैठक में शामिल होने के लिये गई थी। वह बैठक जाट कालेज के भवन में हुई। मीटिंग समाप्त हो जाने के उपरान्त जाट कालेज के प्रिंसिपल और दूसरे व्यक्तियों ने ज़िक्र किया कि यहां रोहतक में यह हुआ वह हुआ। तब उन्होंने स्त्रियों के बारे में भी कहा और मुझ से अनुरोध किया कि चूंकि आप इत्तफ़ाक से यहां आई हुई हैं, अच्छा हो अगर आप .खुद वहां जाकर स्थिति का निरीक्षण करें। मैंने भी सोचा कि जब इत्तफ़ाक से यहां आई हुई हूं तो क्यों न कुछ बहिनों को मिल कर असली हालात का पता करूं। मेरे मन में भी ऐसी उत्सुकता हुई। जब बहिनों का मामला था तो मेरा एक फ़र्ज़ भी हो गया और ज़िम्मेदारी भी हो गई कि स्वयं वहां जाकर अपनी आंखों से वहां की परिस्थिति को देखूं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है रोहतक का क्या पालिटिक्स है, वहां के लोग गवर्नमैण्ट के खिलाफ़ क्या क्या इलज़ाम लगाते हैं यह वह .खुद जाने या गवर्नमैण्ट। किंतु मेरा जागसी जाने का उद्देश्य वहां पर लड़कियों पर किये गये कथित अत्याचारों के विषय पर सही हालात का पता करना था। और इसी उद्देश्य से प्रेरित हो कर मैं वहां गई थी। विभाजन से पहले भी यहां पर क्या कुछ होता रहता था वे तो अखबारों में सुनते और पढते रहा करते थे, लेकिन इस जागसी की विशेष घटना के बारे में जो तरह तरह की बातें सुनी जा रही थीं उन की सच्चाई को जानने के लिये मैं वहां गई। तो खैर, हम लोग वहां गये और गांव के लोगों से मिले। वहां पर हम कोई दो तीन घंटे ठहरे। हमने उन लोगों से पूछा कि जिन कंवारी लड़कियों और जवान लड़कियों पर बलात्कार किये जाने के आरोप लगाये जा रहे हैं वे कौन हैं? इस चीज़ की छानबीन करने के लिये हम लोगों के घरों में भी गए लेकिन हमें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिस से यह साबित हो कि किसी बहन की बेइज्ज़ती हुई है या बलात्कार हुआ है। अगर स्पीकर साहिब, मुझे और ज्यादा समय दें तो मैं और भी बातें इस सिलसिले में आप के सामने रख सकती हूं, किंतु अपनी जगह पर बैठने से पहले मैं इतनी बात पूरी जिम्मेदारी से कह सकती हूं कि जब हम गांव से बाहर निकले तो लोगों ने हमें बड़े फ़खर से कहा कि इस गवर्नमैण्ट के बनने से पहले जब हम अपनी रक्षा के लिये घरों में छिपे रहते थे और औरतें अपना सिर घर से बाहर नहीं निकाल सकती थीं, वहां अब लोगों में इतना विश्वास पैदा हो गया है कि औरतें अकेली बाहर निकलने से भी नहीं झिझकतीं। इन शब्दों के साथ मैं, स्पीकर साहिब, आप का हार्दिक धन्यवाद करती हूं कि आप ने मुझे बोलने के लिये काफ़ी समय दिया।

श्री माम चन्द (गोहाना) : प्रधान जी, मैं पिछले दो दिनों से जागसी के मामले का ज़िक्र सुन रहा हूं। क्योंकि मैं खुद जागसी का रहने वाला हूं इस लिये मैं समझता हूं कि मैं उन भाईयों की अपेक्षा वहां के हालात को ज्यादा जानता हूं। जो कुछ, स्पीकर साहिब मुझे पता है वह मैं आप की सेवा में रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जो मैम्बर साहिबान वहां पर एक एक या आध आध घंटे के लिये गए वे वहां पर इतनी थोड़ी सी देर ठहरने से ही ठीक हालात का जाईज़ा नहीं ले सकते थे। इस लिये, जिन भाईयों ने कहा कि वहां कुछ नहीं हुआ या कि जो कुछ शोर मचाया जा रहा है वह गलत है, मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि वह बिल्कुल गलत बयानी करते हैं और फ़र्ज़ी कहानियां बना कर इस हाऊस के सामने रख रहे हैं...........

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके शब्द "फ़र्ज़ी" का इस्तेमाल न करें।

श्री माम चन्द : खैर, प्रधान जी, जिस तरह आप मुझे हुक्म देंगे वैसा में करूंगा। मगर मैं इतना ज़रूर कह दूं कि मैं तो वहां पर किसी का चाचू हूं और किसी का ताऊ, मुझे इन से ज्यादा पता है कि वहां पर असल में क्या हुआ है और कौन कौन सी दुर्घटनाएं वहां पर देखने में आईं। यह तो सब कुछ ठीक है जो कि मेरे माननीय मित्र चौधरी बदलू राम ने कहा। यह ठीक है कि वहां पर जो काला राम सिंह डाकू था जो कि मफ़रूर रहा वह मारा गया है। लेकिन वहां पर हेमराज जो पैप्सू का नामी डाकू है उस की बहिन भी वहां उसी गांव में रहती है। शायद मेरे दोस्त अभी तक भी वहां के हकीकी हालात से परिचित नहीं। जागसी में केवल वही तीन आदमी नहीं रहते जिन का नाम मेरे दोस्त चौधरी बदलू राम जी ने लिया। वहां पर तो पांच हज़ार आदमी रहते हैं। कितने अफ़सोस की बात है कि उन तीन आदमियों के लिये सारे गांव के लोगों को पीटा गया। प्रधान जी, आप की जानकारी के लिये मैं बता दूं कि वे पांच हज़ार लोग हमारे सूबे के बाकी अमन पसन्द लोगों में से ही थे। वे वही लोग थे जिन्होंने अपने घरों से दस-दस और ग्यारह २ मील दूर जा कर अपनी मिली जुली कोशिशों से सड़क बनाई। जब हमारे महामान्य गवर्नर साहिब वहां गये तो उन्होंने इन्हीं लोगों को अपने मुंह से शाबाश दी। मैं, स्पीकर साहिब, आप के द्वारा सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्यों पांच हज़ार आदमियों को उन तीन आदमियों के पीछे इतनी मार पीट की गई? मैं समझता हूं कि खास कर जागसी में उस वक्त जब कि वह "काला" डाकू ज़िन्दा था, इतना भय था कि मुझे खुद भी खतरा महसूस होता था। इसी कारण मैं खुद जागसी में कई महीनों तक नहीं गया था। इस तरह से जो ऊधम उस डाकू और उस के साथियों ने मचा रखा था उस से कोई इनकार नहीं कर सकता।

यह ठीक है जो चौधरी साहब ने बताया कि उन में से एक जाट था और दूसरा ब्राह्मण और यह कि उन दोनों का आपस में झगड़ा था। उन का झगड़ा तो था, यह ठीक है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उस झगड़े को ले कर सभी गांव वालों पर जो जुल्म हुआ और अत्याचार किये गये, वे क्यों? उन्होंने कहा कि पुलिस हरिजनों पर ज़्यादती करती रही है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि केवल हरिजनों की ही बात नहीं बल्कि सभी की बहू बेटियों की इज्जत पर डाका डाला गया, वहां पर उन स्त्रियों पर इतने अमानुषी अत्याचार किये गये और इतना गन्दा और बुरा व्यवहार किया गया कि जिन्हें बयान करने के लिये मैं वे लफ़ज़ भी मुंह पर नहीं ला सकता। इस लिये जो जो बातें पंडित श्री राम शर्मा जी ने कहीं वे बिल्कुल ठीक थीं। उन पर किसी भी तरह से इख्तलाफ़ राए नहीं हो सकता। जागसी में पुलिस ने इतने गन्दे हालात पैदा किये थे जो कि आज तक जब कि मेरी आयु 57 वर्ष की हो चुकी है, कभी नहीं देखे या सुने थे। कागज़ पर लिखने की तो बात ही क्या, ठीक ठीक लफ़्ज़ों में उस का बयान भी नहीं दिया जा सकता। इस में मुबालगे की कोई बात नहीं होगी, अगर मैं यह कहूं कि यदि सारे समुद्र का पानी और सारे पहाड़ों की स्याही भी क्यों न बना ली जाये तब भी उस शर्मनाक हालत को बयान नहीं किया जा सकता।

इस के अलावा, स्पीकर साहिब मैं आप की सूचना के लिये यह बताना चाहता हूं कि जब मंत्री महोदय गोहाना जा रहे थे तो उस समय सरदार अजमेर सिंह थानेदार और उन के साथ कुछ सिपाही जागसी में मौजूद थे। उस वक्त किसी व्यक्ति ने आकर उन्हें इत्तलाह दी कि इस

वक्त डाकुओं का गैंग (Gang) फ़लां जगह पर मौजूद है। इस सूचना को पाकर सरदार साहिब कुछ सिपाहियों को ले कर वहां गये। जब उन के वहां पहुंचने पर डाकुओं ने फ़ायर (Fire) किया तो थानेदार साहिब हिचकिचा गये। उन्होंने लोगों से कहा कि घोड़ियां ले कर हमारे साथ चलो. हम उनका पीछा करेंगे। लोग घबरा गये और कहने लगे कि जब आप के पास बन्दूक है तो भी आप उन को नहीं पकड़ सकते तो हम किस बाग़ की मूली हैं?

खैर, काला डाकू तो मारा गया। किंतु अब भी 22 आदमियों की पुलिस की एक ताज़ीरी चौकी वहां पर बैठी है और वे सिपाही बजाए लोगों की रक्षा करने के उन्हीं पर टूट रहे हैं। उन पर मनमाने अत्याचार कर रहे हैं। इस लिये मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके जब काला डाकू मारा गया है---इस चौकी को उठा दिया जाये क्योंकि लोग वहां से भाग रहे हैं। वे इस लिये भाग रहे हैं कि वे उस ताज़ीरी चौकी का दंड कहां से देंगे।

माननीय स्पीकर साहिब ! जागसी गांव में पुलिस ने जो मार कुटाई की, उस का ज़िक्र तो सब माननीय मैम्बरों ने किया है लेकिन एक बात मैं बताता हूं। वह यह है कि वहां जितने बदमाश थे या जिन का शुमार दस नम्बर के लोगों में था, वह एक भी नहीं पीटा गया और भले आदमी पीटे गये हैं। मेरे भाई की रज़ाई छीन ली गई। उसे भी मारा गया। जब पुलिस ने उस गांव के गिर्द घेरा डाल दिया तो वहां के जितने आदमी थे उन्हें पकड़ लिया गया। तब गांव में अकेली स्त्रियां रह गईं। वहां उन लोगों में इतना डर पैदा हो गया है कि यदि अब भी पांच या सात आदमी वर्दी डाल कर चले जायें तो वहां की स्त्रियां भी अपने घरों को छोड़ कर भाग जायेंगी और वहां कोई नहीं रहेगी।

स्पीकर साहिब ! यह है मामला जागसी का। जो बातें मेरी बहिन श्रीमती सीता देवी ने बताई हैं वह पता नहीं कहां से दरियाफ़्त कर लाई हैं। मैं उन से पूछता हूं कि वह वहां कितनी देर ठहरी थीं। वह किन किन से मिली थीं। उन्हें इतनी थोड़ी देर में कैसे असलियत का पता चल गया?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मैम्बर अपनी Speech को Wind Up करने की कृपा करें।

श्री माम चन्द : फिर एक माननीय मैम्बर ने यह कहा है कि उन का गांव माजरा है जो कि जागसी से दो तीन मील की दूरी पर है मगर चूंकि उन्हें तो वहां से कोई इत्तलाह नहीं आई कि जागसी में यह कुछ हुआ है, इस लिये यह सब बातें गलत हैं। मैं उन से यह अर्ज़ करता हूं कि करनाल में रहते हुए उन्हें कैसे सही हालात मालूम हो सकते थे। बाकी हमें क्या पता था कि श्री मूल चन्द जैन को भी करनाल में इत्तलाह देनी ज़रूरी थी। हमने देहली में पंडित जवाहर लाल नेहरू को और यहां चंडीगढ़ में तो इत्तलाह पहुंचा दी थी।

फिर स्पीकर साहिब! मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि जब डाकू तो मारा गया, फिर जागसी में 22 सिपाहियों की एक चौकी बिठाने की क्या ज़रूरत है।

मैं आप को बताता हूं कि किस तरह से पुलिस ने वहां भले लोगों को तंग किया है। वहां एक कन्हैया सुनार की लड़की का विवाह था और बरात को ठहरने की इजाज़त नहीं दी गई थी। बाद में मेरे कहने पर इजाज़त दी गई।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ (ਨਕੋਦਰ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਐਡ੍ਰੈਸ (Address) ਵਿਚ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਨਿਰਾਸਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕ Record ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਬਨ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਐਡ੍ਰੈਸ (Address) ਵਿਚ ਭਾਖੜੇ ਡੈਮ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਭਾਖੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਮਸਾਲੇ ਪਿਪਲਾ ਮੂਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਲ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਜੋ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਵਿਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਕੋਦਰ ਮੇਰੀ Constituency ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਦੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਉਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲ Opposition ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ British Parliament ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ Britishers ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਤੇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਤਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਉਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਜ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ British Guiana ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਦ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ Protest ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਯਾਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ

ਮਿਤ੍ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਧ ਵਧ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜੰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਲਗ ਚੁਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਕਤਲੋ-ਗ਼ਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਹੇਠ ਬਿਆਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਰਖਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿਠੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਖੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿਠੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਗਲ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਚਿਠੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ Chief Minister ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:--

> "I am sorry to say that you are perhaps unwittingly lending your support to the process of lawlessness and disorder. I repudiate the suggestions and insinuations made in your letter under reply."

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। Subversive Activities ਦਾ ਹਰਫ਼ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਹਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਤ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨਾ Subversive Activities ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਖਿਲਾਫ-ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਕੇ ਅਪਣੀ ਅਖੀਂ ਹਾਲਾਤ ਡਿਠੇ। ਅਖੀਂ ਵੇਖੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ "ਹਿ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। (Voices of shame, from Opposition Benches) ਇਹ ਬੀਬੀ Mrs. Sanyal ਹੈ।

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ]

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਬੜਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੇ 26 ਲਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਰਾਬੜਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਚਿਠੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ:—

> ਮੌਜ਼ਿਆ ਰਾਬੜੋਂ ਕੀ ਯਹ ਪੰਚਾਇਤ ਮਫਰੂਰੋਂ ਔਰ ਮਫਰੂਰੋਂ ਕੋ ਪਨਾਹ ਦੇਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਸਖਤ ਨਫਰਤ ਕੀ ਨਿਗਾਹ ਸੇ ਦੇਖਤੀ ਹੈ। ਇਨਮੇ ਨਾ ਕਭੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਥੀ ਔਰ ਨ ਅਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਫਰੂਰਾਂ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਪੁਰਅਮਨ ਔਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਗੋਂ ਪਰ ਜੋ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਇਸਕੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਜ਼ਅਮਤ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮਵਰਖਾ 24-1-54, 22-1-54 ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਏਕ ਭਾਰੀ ਜਮੀਅਤ ਇਸ ਗਾਂਵ ਮੇਂ ਆਈ। ਗਾਂਵ ਕੇ ਤਮਾਮ ਨੰਬਰਦਾਰ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਤੁਆਵਨ ਕਰਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਥੇ ਔਰ ਜਿਸਕੀ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦਿਲਵਾਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨਕੇ ਤੁਆਵਨ ਕੋ ਠੁਕਰਾ ਕਰ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਮਾਰਨਾ ਪੀਟਨਾ ਔਰ ਤਮਾਮ ਬੜੇ ਬੂੜੋਂ ਕੋ, ਬਹੂ ਬੇਟੀਓਂ ਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੇਂ, ਖੁਰਾਫਾਤ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਂ। ਗਲੀਓਂ ਮੇਂ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੇਂ, ਗਾਂਵ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਕੋਹਲੂਓਂ ਮੇਂ ਜੋ ਆਦਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਸ ਕੋ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪੀਟਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗਾਂਵ ਕੇ ਤਮਾਮ ਮਰਦਮਾਨ ਕੋ ਬਾਹਰ ਏਕ ਜਗਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੀਛੇ ਸੇ ਪੁਲੀਸ ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਘੁਸੀ ਔਰ ਔਰਤੋਂ ਮੇ ਛੇੜ ਛਾੜ ਕੀ, ਇਨਕੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕੀ। ਤਮਾਮ ਅਨਾਜ ਕੋ ਏਕ ਦੂਸਰੇ ਮੇਂ ਮਿਲਾ ਦੀਆ, ਦੂਧ ਔਰ ਘੀ ਕੇ ਬਰਤਨ ਫੋੜ ਡਾਲੇ। ਘੀ ਮੇਂ ਮਿੱਟੀ ਕਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਨਕਦੀ ਔਰ ਜ਼ੇਵਰ ਹਾਥ ਲਗਾ ਵਹ ਚਲਤੇ ਹੂਏ ਉਠਾ ਲੇ ਗਏ। ਯਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਾਸਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਔਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਰ ਸ਼ਦੀਦ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਮ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸੇ ਮਤਾਲਬਾ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਖੁਲੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ (Judicial) ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਇਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਇਖ਼ਲਾਕ-ਸੋਜ਼ ਹਰਕਾਤ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਨ ਕੋ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਏ।"

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਕੀ ਇਸ ਚਿਠੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ?

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਜੀ ਹਾਂ। ਮੰਗੇ ਰਾਮ ਵਲਦ....

Mr. Speaker: The hon. Member will have to lay this document on the Table. Now this is the property of the House.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਆਪ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਲੋ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮਿਲ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਧਾੜ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਘਮੰਡ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ (Law and Order) ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਈ ਮਿਤਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਲਾਸਲੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ (Classless Society) ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪੱਤ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ, ਹੀ ਇਕ (Classless Society) ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਆਖ਼ਿਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਗਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ Statement ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਖਰ ਇਥੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:--

> "ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਾ ਦੀ ਇਕੋ ਹੀ ਤਦਬੀਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ, ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਕ ਮਿਟਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਗੜੀ, ਸ਼ਾਂਤ, ਇਕ-ਮੁੱਠ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੀ ਇਕ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਅਸਲਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਤੇ ਇਕ-ਮੁਠ ਕੌਮ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤੇ ਹੈ? ਕੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ Administration ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਤਕੋ ਤਾਂ ਹੀ Stable ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ 90 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਘਮੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੋੜਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਟੁਟਕੇ ਰਹੇਗਾ।

श्री धर्म वीर वशिष्ठ (हसनपुर): अध्यक्ष महोदय ! मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये उन्हें धन्यवाद की तहरीक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। रोहतक के मामले को लेकर इस House के सामने यह कहा जाता रहा है कि वहां पर जुल्म हुआ है। श्रीमान् जी! मैं यह बात आप द्वारा सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि जुल्म रोहतक में नहीं बल्कि हम पर इसी हाउस में हो रहा है, (हंसी) न मालूम किन Administrative सहूलियतों के कारण मेरी सीट (Seat) यहां पर रखी गई जहां कि अखबारों के नुमायंदे मुझे घेरे रहते हैं।

Mr. Speaker: You are not the only one. आप के साथ और भी कई मैम्बर हैं। ऐसी बात तो नहीं कि सब ने Floor Cross कर लिया हो।

श्री धर्म वीर वशिष्ठ: श्रीमान् जी! मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक मेरा इस सिलसिले से सम्बन्ध है एक अखबार वाले ने, जो सरकारी बेंचों से सम्बन्ध रखता है, तो खबर निकाल दी है।

Mr. Speaker : We are not interested in your affairs. यह मामला ज़ेर बहस नहीं है ।

श्री धर्म वीर वशिष्ठ : मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि रोहतक का मामला जो कल भी ज़ेर बहस रहा है उस से कहीं ज़्यादा ज़रूरी मामले और भी हैं मगर इस की तरफ़ हाउस की तवज्जुह नहीं दिलाई गई ।

स्पीकर साहिब, मैं सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि इस ने पंजाब में कोई 9 हज़ार पंचायतों को कायम कर दिया है और सब में Elections कराए गये हैं । मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यू. पी. और बम्बई में कहीं भी ऐसी Elections नहीं हुई जैसे कि पंजाब में हुई हैं । मैं यह बात कहना चाहता हूं कि बाकी हर जगह फ़साद हुए कत्ल भी हुए मगर यहां पर एक भी ऐसा केस (Case) नहीं हुआ। Elections हुए और पंचायतें बना दी गईं हैं । स्पीकर साहिब! Pepsu और Travancore Cochin में दुबारा Elections हुए क्योंकि वहां पर Stability नहीं थी ।

स्पीकर साहिब, जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का सम्बन्ध है इन को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता । यह 16-17 साल पुरानी हैं । मैं तो आप के द्वारा सरकार से दरखास्त करूंगा कि वह इन को मोरूसी का Status दे दे । और इन को और इन के बाल बच्चों को पक्का कर दिया जाए (हंसी) ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ने राम्रो गजराज सिंह जी से मशवरा कर लिया है (हंसी) ।

श्री धर्म वीर वशिष्ठ : स्पीकर साहिब! खतरा दो चीजों से है । हमारे ऊपर दो सुर्ख आंखें Dragon की तरह देख रही हैं । और वह है Communalism और Corruption । इनका ज़िक्र नहीं किया गया ।

यहां पर पंजाब में हिंदी का नाम लेते डर लगता है और ऐसे ही पंजाबी का जो ऐसा कहे उसे फ़िरकेदार कहते हैं । स्पीकर साहिब, मद्रास और बम्बई में जहां तामिल और तिलगु ज़बानें हैं वहां राष्ट्रभाषा बहुत तरक्की कर रही है । उत्तर प्रदेश और बम्बई में इन ज़बानों के साथ राष्ट्रभाषा की तरक्की की जा रही है । वहां पर सोचा जा रहा है कि हिंदी के टाईप कैसे सरल बनाये जायें । और 15 साल के अन्दर हिंदी को अंग्रेज़ी की जगह कैसे फिर से रखा जाए ।

श्रीमान् जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम बंगाली और पंजाबी पीछे हैं और भारतीय पहले । इस लिये राष्ट्रभाषा के सिलसिले में इस को तरक्की देने के लिये हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिये । आप और हकूमत अगर चाहे तो इस को फैला सकते हैं । मैं यह नहीं चाहता कि पंजाबी न फैले । आप पंजाबी को गुड़गांव तक बढ़ा सकते हैं । मगर पंजाबी बोलने वालों को चाहिये कि वह राष्ट्रभाषा के फैलाने में मदद करें ।

मौलवी अब्दुल ग़नी दार (नूह) : जनाबे सदर ! मैं आप के सामने चंद गुज़ारिशात रखना चाहता हूं और जो मेरे ख्याल में आया है मैं आप के द्वारा अपनी सरकार से कहना चाहता हूं ।

साहिबे सदर, आप तो जल्लियां वाले बाग के हीरो (Hero) हैं और आप को याद होगा कि एक ज़ालम ने हम पर कैसे गोलियां चलाईं । जब उस से पूछा गया कि उस ने ऐसा किया तो

उस ने बिना झिझक के कहा "हां" मैंने गोलियां उस वक्त तक चलाई जब तक कि मेरे पास आखरी गोली खत्म न हो गई। वह विदेशी था और उस का Character था कि वह ऐसी कारवाई करे और खुले दिल से करे। मगर शुक्र है उस आईन का, उस विधान का जो हम ने फख्र के साथ बनाया है और जिसमें हमें मौका दिया गया है—हमारी सरकार को मौका दिया गया है कि वह मुल्क की बाग डोर सम्भाले! इस के बारे गवर्नर साहिब की जबान से तारीफ़ कराई गई है। जो काम अच्छा है उस की तारीफ़ होनी भी चाहिये और जो अच्छा नहीं उस की तारीफ़ नहीं करनी चाहिये। वह ग़ैर के नज़रिए से हालात को देखें।

मैं उन को बताना चाहता हूं कि रोहतक में जो जुल्म पुलिस ने लोगों पर किये हैं और जो ज्यादतियां कीं हैं और जिन का चर्चा यहां पर आप के और हाउस के सामने Opposition की तरफ़ से जोरदार शब्दों में किया गया है और जिन के बारे में दबी दबी ज़बान में सरकारी पार्टी की तरफ से ज़िक्र किया गया है उस को आप छिपाना चाहते हैं। यह अच्छा नहीं है।

आप उस महान आत्मा की तरफ़ देखें जिस का फ़ोटो आप के सामने है। इन्होंने शानदार असूल आप के सामने रखे और लोगों पर हाथ उठाने से रोका। मैं पुलिस वालों की तारीफ़ करता हूं अगर वह अच्छा काम करें। पर जिन पुलिस वालों ने मेरी बहिनों पर ज्यादतियां कीं, भाईयों को गोली का निशाना बनाया उन की तारीफ़ कैसे की जाए? आज वह मौजूद नहीं हैं जिन्होंने लोगों को कुरबानी का बकरा बनाया है। लेकिन जब यह कहते हैं कि वहां तो कुछ हुआ ही नहीं तो मुझे अफ़सोस होता है।

प्रधान जी, मुझे एक बात याद आ गई है। जब हम जेल में थे और श्री रला राम जी भी साथ थे तो रात को जब वार्डर (Warder) को आवाज़ दी गई तो उस ने कहा सब अच्छा—३२ की गिनती पूरी है। मैंने पूछा कि हम में से २ तो मर गए हैं पर तुम कहते हो कि गिनती पूरी है; तो उस वार्डर ने जवाब दिया कि मेरी तरफ़ से सब मर जाएं मगर जब तक ज़िन्दा या लाशों की गिनती ३२ पूरी है, तब तक सब अच्छा ही है। इसी तरह सरकार रोहतक में लोगों पर जुल्म कर रही है और कहा जाता है सब अच्छा है।

"करीब है यार रोज़े महशर
छिपेगा कुश्तों का खून क्योंकर।
जो चुप रहेगी ज़बाने खन्जर,
लहू पुकारेगा आसतीं का!"

जनाबे सदर, मेरी गुज़ारिश है कि इस तरह बातों को और वाक्यात को छिपाना अच्छा नहीं। एक तो सरकार लोगों पर जुल्म करती है और फिर Opposition को दबाना चाहती है।

"वही कातल वही शाहद वही मुन्सफ ठहरे,
अकर्बा मेरे करें खून का दावा किस पर।"

सरकार ही लोगों को पकड़ने वाली है, यही चलान करने वाली है और यही इनसाफ़ करने वाली है।

कौन है जो अपनी आंखों के सामने अपनी बहू बेटियों की आबरुरेज़ी देखे और इस का ज़िक्र न करे? फिर फखर के साथ कहा जाता है कि वहां पर कुछ नहीं हुआ।

[मौलवी अब्दुल ग़नी दार]

फिर जिन लोगों ने Walkout किया है उन्होंने ठीक ही किया है। उन्होंने अगर यह नाअरा बुलन्द किया है कि जुल्म करने वाली सरकार न रहे तो मैं भी कहता हूं कि जुल्म करने वाली सरकार न रहेगी (प्रशंसा)।

इस तरह Opposition को आप दबाना चाहते हैं। आप हम से चाहते हैं कि हम पुलिस के काम की तारीफ़ करें। हम उन के अच्छे कामों की तारीफ़ करने के लिये तैयार हैं मगर जब वह ज़्यादतियां करें तो हम तारीफ कैसे करें ? (इस मौके पर घंटी बजी) मेरा ख्याल था कि मेरे लिये १० मिनट रखे गये हैं मगर मैं अब दो एक मिनट में ही एक दो बातें कहना चाहता हूं।

जहां पर हमारी सरकार की कुछ बातों की तारीफ़ की गई है उस में ट्रांसपोर्ट की Nationalisation भी शामिल है। इस के बारे में हमारी प्रदेश कांग्रेस के प्रधान ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफ़िर और श्रीमती सीता देवी ने बहुत मुख़ालफ़त की है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि किसी तरह से उन शरणार्थियों को आबाद किया जाये जिन्होंने आज़ादी की जंग में बड़ी कुरबानी दी। ट्रांसपोर्ट की Nationalisation की तजवीज़ से मुझे बहस नहीं। हमारे सामने तो एक और तजवीज़ है। और यह है Text Books को nationalise करना। इस वक्त मेरे सामने 50 किताबें हैं। मेरी यह शिकायत नहीं कि बच्चों के लिये किताबें समय पर क्यों नहीं मिलीं। मगर मेरी शिकायत यह है कि यह 50 किताबें हिंदी और पंजाबी की हैं। लेकिन मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि इन में सैंकड़ों ग़लतियां हैं। इस को Nationalisation कहा जाता है।

वज़ीर साहिब, ट्रांसपोर्ट वालों से चंदे लें, दावतें उड़ायें. मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन यह हमारे बच्चों की तालीम का सवाल है। जनाबे आली, मैं बजट की बहस के दौरान में एक एक किताब और उस की गलतियों पर बहस करूंगा। अब वक्त की तंगी के बाइस इन को छोड़ कर एक बहुत ज़रूरी बात का ज़िक्र करता हूं। आप जानते हैं कि जिस इलाके से मैं और चौधरी यासीन खां साहिब मैम्बर हैं वहां गो कशी के ख़िलाफ़ एक भारी आन्दोलन चल रहा है। उस के बारे में हमारी सरकार ने इस एडरेस में कुछ नहीं बताया कि इस बारे में क्या कुछ किया जायगा, कितना रुपया इस काम के लिये रखा गया है। और क्या कुछ करने का इरादा है।

प्रोफैसर शेर सिंह (झज्जर): अध्यक्ष महोदय ! जब ज़मींदारा पार्टी के सदस्य खड़े हुए तो मेरा ख्याल था कि वे पार्टी भाव से बालातर रह कर बात करेंगे। लेकिन उन की बातें सुन कर मैं तो यही कहूंगा कि यह जो वावेला डेढ़ महीने से रोहतक में हो रहा है वह सब पार्टी बाजी के सिवाये कुछ नहीं है। हमारे ज़िला में जलूस निकला और मज़ाहरा हुआ। उस में सिवाये जाट कालिज के विद्यार्थियों और उस पार्टी के, जिस का इस कालिज पर अधिकार है, कोई नहीं था। देहातों से तो लोग आ न सके. विद्यार्थियों को ही उकसा कर रोहतक में जलूस निकाला गया। मैं पूछता हूं कि क्या इस कालिज के सिवा वहां कोई आबादी नहीं ? क्या किसी और को मां-बहनों की इज्जत का कोई ख्याल नहीं था ? क्या इन विद्यार्थियों के सिवा वह जलूस निकालने वाला कोई न रहा था ?

फिर Bar Association का नाम लिया गया है कि वह तो पार्टीबाजी से ऊंची है। लेकिन अगर आप वकीलों के नामों को पढ़ें तो मालूम होगा कि हर एक वकील का किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक है और वे सब सरकार की विरोधी पार्टियां हैं, और Inquiry के Chairman साहिब तो एक पार्टी की मुफ्त वकालत भी करते रहे हैं। अगर Inquiry ही करनी थी तो दूसरी पार्टियों के लोगों को भी शामिल कर लिया जाता। आखिर हमारे दिल में भी मां–बहिनों का दर्द है। क्या उन की इज्जत के वही ठेकेदार हैं?

फिर इस सिलसिले में कुछ बड़े आदमियों के नाम लिये गये हैं। स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी को मैं भी पन्द्रह बीस साल से जानता हूं। जब वे रोहतक आये तो मुझे बुलाया और मैंने उन से असल बात पूछी तो उन्होंने फ़रमाया कि हमने खुद तो किसी देवी से कुछ नहीं पूछा। अलबत्ता मारपीट की शिकायत हम से ज़रूर की गई है। उन्होंने चार आदमियों के नाम बताये। वे लोगों को अंगूठे दिखाते थे कि देखो हम आराम से बैठे हैं क्योंकि पुलिस उन के घरों में बैठी थी। चुनांचि लोगों ने कहा कि अगर पुलिस वाले इन चार आदमियों को भी पीट देते तो फिर सब की तसल्ली हो जाती। अब मैं पूछता हूं कि जितनी ज्यादती मेरे दोस्त कहते हैं अगर उतनी ही सचमुच हुई होती तो लोग किस तरह कह देते कि इन चार को पीट देते तो हमारी तसल्ली हो जाती। देवियों के अपमान को कोई कैसे भुला सकता है? बहन लक्ष्मी देवी का भी नाम लिया गया है। और उन्होंने लिया है जो उन को हराने के ज़िम्मेदार थे। मैंने उन से भी सब कुछ पूछा। जो बयान उन्होंने लिये थे वे भी पढ़े। उन्होंने कहा कि यह बातें हम से कहीं गईं लेकिन जिन बहिनों ने ये बातें कहीं उन का डाकूओं से सम्बन्ध है।

श्री सिरी चन्द : क्या सम्बन्ध है?

प्रोफेसर शेर सिंह : आप बहनों के मुंह और गाल काटने का ज़िक्र कर सकते हैं। मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता। आप ही बता दें किस का किस से क्या सम्बन्ध है।

श्री सिरी चन्द : इन में से एक तो काले की बहिन है। अब मैं पूछता हूं कि क्या उस के साथ पुलिस की ज़बरदस्ती इसलिये ठीक और जाइज़ है कि वह बेचारी एक मफ़रूर की बहिन है?

प्रोफेसर शेर सिंह : बुरा सलूक किसी से भी हो, बुरा है। ठीक है, परन्तु देखना तो यह है कि वह सत्य है या नहीं। अब दूसरे गांव की सुनिये। वहां कुछ वकील साहिबान गये थे मगर सिर्फ़ आध घंटा ठहरे। हम दो तीन घंटे वहां रहे। सब से पूछ ताछ की। किसी ने भी हमें कोई चोट नहीं दिखाई। यही कहा कि अंदर की मार मारी है। उन को ठीक मान कर भी जब तक किसी का नाम न लिया जाए और कोई सबूत न हो, कुछ कार्यवाही करना मुश्किल है। परन्तु यदि ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं हुआ। लोगों का माल लूटने की बात नहीं। आपने यह भी कहा है कि पुलिस ने वहां से 5 लाख का सामान लूटा। मगर हम से उन लोगों ने यही कहा कि जितना माल लिया वह सब सुनार की दुकान पर तुलवाया गया। हमने भरी पंचायत में पूछा कि क्या कोई ऐसा माल भी था जो फहरिस्त में दर्ज न किया गया था। हमें

[प्रोफ़ैसर शेर सिंह]

यकीन दिलाया गया कि वह तमाम माल जो वहां से ले जाया गया फ़हरिस्त में दर्ज था। हमने औरतों के बारे भी मालूमात हासिल की। हम से किसी ऐसी हरकत का किसी ने ज़िक्र नहीं किया जो हमारे मित्रों ने यहां पर बयान की हैं। मैं मानता हूं कि पुलिस के खिलाफ़ यह दो संगीन इलज़ाम हो सकते हैं। एक फ़हरिस्त में किसी माल का दर्ज न करना और माल घरों से ले जाना और दूसरे स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जाना। यदि यह दो इलज़ाम पुलिस के खिलाफ़ साबत कर दिये जायें तो हम सब से पहले Police के खिलाफ़ आवाज़ उठायेंगे और जब तक अपराधियों को पूरी सज़ा नहीं मिलती आराम से न बैठेंगे। हम देवी माताओं की बेइज्ज़ती किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। देवियों की बेइज्ज़ती हमारी और हमारे सारे राष्ट्र की बेइज्ज़ती है। हमने भारी पंचायत में (रावड़ा गांव की) स्त्रियों के बलात्कार के सम्बन्ध में की गई शिकायतों की, कि घरों में मारा, जांच करने के पश्चात् कहा कि हमें किसी देवी ने नहीं कहा कि बलात्कार हुआ और कहा तो वह विश्वास के लायक नहीं। और कोई शिकायत उन्हें हो तो बताने के लिये कहा और अन्त में अपना विचार सुनाया कि दोनों संगीन इलज़ामों में कोई सचाई नहीं है। लेकिन हमने रोहतक में जलसा किया और लोगों को अपनी तमाम मालूमात बताई। हमने कहा कि जिस शख्स को भी इन बातों के बारे में कुछ शक है वह बेशक हमारे साथ चले और अपनी तसल्ली कर ले। कोई भी हमारे साथ चलने को तैयार नहीं हुआ।

स्पीकर साहिब, मैं पंडित श्री राम जी शर्मा की बेशक तारीफ़ करता हूं कि उन के यहां कहने के अनुसार वे मफ़रूरों की रोक थाम के लिये हमेशा काम करते रहे हैं। कल जब उन्होंने यह बताया कि वे वज़ीरे आज़म को रोहतक से गुंडा गर्दी दूर करने के लिये लिखते रहे, हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ। मैं उन को इस काम पर बधाई देता हूं। लेकिन मुझे हैरानी है कि मेरे दूसरे दोस्त आप गुंडों के खिलाफ़ तकरीरें करने के लिये कैसे खड़े हो गये। वह उस समय कहां थे जब डाकू देवियों की बेइज्ज़ती करते रहते थे और पांच पांच सौ रुपया ले कर लोगों का खून कर दिया जाता था? बात केवल पार्टीबाज़ी की है। इस प्रान्त में आप से पहले बोलने पर कोई पाबन्दी नहीं थी। विधान सभा का अधिवेशन भी हुआ। परन्तु इस पर कभी भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। अब समाज विरोधी कार्यवाहियां और मनुष्यों की हत्या करने वालों के विरुद्ध सरकार ने कार्यवाही की तो वावेला मचा दिया। मैं समझता हूं कि इस बार पंडित श्री राम जी शर्मा ने भी ठीक काम नहीं किया। उन्होंने कहा है कि वे बयानात लेने इस लिये नहीं गये कि इस काम को पार्टी बाज़ी न समझा जाये। मैं समझता हूं कि उन्हें खुद जा कर सब बातों का पता करना चाहिये था। और इस कार्यवाही पर जो उन की पहली इच्छा के अनुसार हुई, सरकार को बधाई भी देनी चाहिये थी।

एक बात मैं Police Department के सामने रखना चाहता हूं हमारी Police का पिछला Record ऐसा है कि लोगों का उन पर विश्वास नहीं। आप लोग ख्याल करते हैं कि यह भले आदमियों की नहीं, बदमाशों की Protection करते हैं। मैं कहता हूं कि Police को ऐसा रवैया इख्तियार करना चाहिये कि लोगों का यह Impression दूर हो जाये। यह बात विभाग के लिये कोई शान की बात नहीं। क्योंकि लोगों पर कुछ ऐसा बुरा प्रभाव है कि पुलिस के विरोध में कही गई झूठी

बातों पर भी वे विश्वास कर लेते हैं। इस सम्बन्ध में भी, मैंने गांव में भ्रमण करते हुए जगह २ लोगों से यही सुना कि पुलिस ने बड़ा अत्याचार किया। पुलिस को लोगों की सेवा करके ऐसा वातावरण बनाना चाहिये कि उन के सम्बन्ध में कही गई झूठी बात और अतिशयोक्ति पर लोग विश्वास न करें।

ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਦਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ Address ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ U.S. ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ Pact ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ Leftist Groups ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ Party Politics ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ।

ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ Martial Spirit ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ Defence ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Arms ਦੇ Licence ਹੀ ਆਮ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। Licence ਦੇਣ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ Party Politics ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ Border ਟੱਪਣ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲਤ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਖੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ।

श्रीमती शन्नो देवी (अमृतसर शहर, पश्चिम): स्पीकर साहिब ! चूंकि समय बहुत थोड़ा है इसलिये अगर मैं इस हाउस की किसी मुश्किल को हल करने का सबब न बन सकूं तो कम से कम हाउस में मुश्किल पैदा करने का सबब भी नहीं बनना चाहती। जैसा कि मुझ से पेश्तर बोलने वाले भाई ने अपने विचार आप के सामने रखे हैं मैं गवर्नर महोदय के ऐड्रैस (Address) में जो आखिर का पैरा 19 है उस की तरफ़ ईवान के मैम्बरों का ध्यान दिलाना चाहती हूं। आम आदमी तो छोटी छोटी बातों पर लड़ना जानते हैं लेकिन सियासतदान, बहादुर और देशभक्त—चाहे वह पुरुष या स्त्रियां हों—समय की की आवश्यकता को पहचानते हैं। मैं चाहती थी कि डिप्टी लीडर सरदार प्रताप सिंह मेरे नजदीक आ जाते और मेरे विचारों को सुनते। अमृतसर में पाकिस्तान यू० एस० ऐ० गठ जोड़ की Meeting में जो सरदार प्रताप सिंह ने Address की थी और जिस के सभापति हमारे असैम्बली के सदर थे; उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि हमें आपस के मत-भेद खत्म कर के संगठित होकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिये। स्पीकर साहिब ! मैं आप की वसातत से इस ईवान के मैम्बरों

[श्रीमती शन्नो देवी]

को कहना चाहती हूं कि बड़ी से बड़ी खूबसूरत अमारत की अगर बुनयाद की ईंटें हिल जायें तो वह अमारत गिर जाती है। मुझे इस सिलसिले में पंजाबी का एक मुहावरा याद आ गया है—

"खान पीन नूं वखरे ते लड़न भिड़न नूं इकट्ठे"

अगर आज इस ईवान का कोई मैम्बर यह सोचे कि मैं किसी दूसरे को गिरा कर ऊंचा हो जाऊं या फुलां व्यक्ति मेरे विचारों से सहमत नहीं होता इसलिये इसे हटा दिया जाये तो यह नहीं हो सकता। जब मुश्किल से हासिल की गई आजादी को किसी तरफ़ से खतरे के आसार दिखाई देते हों तो पंजाब के लोग एक किनाराकश हो कर अलग नहीं बैठ सकते। जब तक मेरा इस पार्टी से सम्बन्ध है मैं भी गवर्नमैण्ट हूं और इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अगर यह कहा जाये कि सात आदमियों की गवर्नमेंट है तो यह ग़लत बात है। मैं और आप गवर्नमैण्ट हैं। अगर सरकारी बैंचों पर बैठे हुए लोग सोच लें कि चाहे वह गलती करें तो भी वह मज़बूत रह सकते हैं तो यह ग़लत बात है। स्पीकर साहिब ! मैं इस मौके का फ़ायदा उठा कर भाइयों को चेतावनी देना चाहती हूं और अपनी बहिनों को भी कहना चाहती हूं कि अगर किसी वक़्त हमारे देश पर आक्रमण होने का डर हो तो हमें उसका मुकाबला करने के लिये हमेशा तैयार रहना चाहिये। पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम हम लेते हैं। महात्मा गांधी का चित्र हमारे सामने है और उन का आचरण हमारे सामने है अगर हम उन के बताये हुए मार्ग पर नहीं चलते तो काम खराब हो जायगा। हमें पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिये ताकि जो आज़ादी हम ने मुश्किल से हासल की है उसे परमात्मा न करे कि कोई आंच आ जाये। स्पीकर साहिब ! मैं कहना चाहती हूं कि हमारी गवर्नमैण्ट कोई कायर गवर्नमैण्ट नहीं है। हमारी गवर्नमैण्ट कोई भूली हुई गवर्नमैण्ट नहीं है। हमारी गवर्नमेंट कोई नादानों की गवर्नमेंट नहीं—है हमारी गवर्नमैण्ट निकम्मे आदमियों की इकट्ठी की हुई गवर्नमैण्ट नहीं है। हमारी गवर्नमैण्ट बहुत सियाने और बुद्धिमान लोगों की गवर्नमैण्ट है। जब गवर्नर साहिब के ऐड्रैस (Address) पर कल बहस हुई तो मुझे यह कहते हुए शर्म आती है और अफ़सोस होता है कि हमारे ईवान में बहस का मियार बहुत गिर गया है। मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है कि कि हमारे Constitutional Head अर्थात् गवर्नर साहिब जिन की मार्फ़त गवर्नमैण्ट का संदेश इस हाउस में दिया जाता है और जिन्होंने यहां आकर गवर्नमैण्ट की नीति का खाका हमारे सामने पेश किया उन का अगर हम मुनासिब एहतराम न करें तो यह हमारे इखलाक की बुलंदी नहीं है। मैंने मन में सोचा कि किस तरह तसवीर खेंच कर दिखाई जा रही है और बहिनों का चरित्र बताया जा रहा है। अगर यह गवर्नमेंट निकम्मी गवर्नमेंट नहीं है तो इसे इन मामलात की जांच करने के लिये एक Enquiry Committee मुकर्रर करनी चाहिये। अगर उस ने यह फैसला दिया कि कुछ नहीं हुआ तो हम सुबकदोश होंगे और हमारी गवर्नमैण्ट का मुंह उज्जवल होगा। अगर हमारी गवर्नमैण्ट की ग़लती साबत हुई तो हमें मानने से कोई इन्कार नहीं होगा। स्पीकर साहिब ! मैं उन मैम्बरों में से नहीं हूं कि जब वह बोलने लगें तो Services को गालियां दें। लेकिन इस के साथ २ मैं यह भी समझती हूं कि सारे के सारे अफ़सर पापी नहीं हैं। मैं पुलिस का एक वाकिया सुनाना चाहती हूं। मैं पुलिस के

अफ़सर का नाम नहीं लूंगी। अगर आप अपनी Files खोल कर देखें तो आप को पता लग जायगा। बटवारे के बाद जब लोग दीवाने हुए थे तो लाहौर से बेगम फ़ातिमा जो Abducted Girls को बरामद करने के काम पर मुकर्रर हुई थी ने जालन्धर जाना था। मैंने भी लाहौर से फ़िरोज़पुर जाना था। मैंने उसे कहा कि मेरे साथ चलो। आप को अगर कोई मारेगा तो मुझे पहिले मारेगा। जिस वक्त हम Abducted Women को बरामद करने के काम में बाहर गये तो चार पांच बहिनें रो कर हमारे गले लिपट गईं। मैं समझती हूं कि अगर देश की किसी औरत की बेइज्जती होती है तो सारे राष्ट्र की बेइज्ज़ती होती है। वह रोई और अपना किस्सा सुनाया। पुलिस वाले उन्हें लाये और ला कर उन्हें थाना में रखा गया। मैं आगे बयान नहीं कर सकती कि उन के साथ क्या सलूक किया गया। मैंने उनका सारा किस्सा सुना और पुलिस के बड़े अफ़सरों के पास गई। Face is the index of mind. मैंने उन की कहानी पुलिस अफ़सरों को सुनाई।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्या को बता दूं कि उन के लिये तीन चार मिनट का समय बाकी है।

श्रीमती शन्नो देवी : मैं कहना चाहती हूं कि अगर मेरी गवर्नमैण्ट ने Enquiry Committee न बिठाई तो मैं जाती हैसीयत से दूध का दूध और पानी का पानी कर के दिखा दूंगी। इस के अलावा यहां पर स्वामी स्वतन्त्रानन्द का नाम लिया गया है। मैं बहिन लक्ष्मी को बहुत देर से जानती हूं। मैं खुद गांव में जाऊंगी और उन अफ़सरों को मिलूंगी जो अगवा-शुदा औरतों को बरामद करने के काम में लगे हुए हैं। मैं जानती हूं कि हमारी गवर्नमैण्ट ऐसी औरतों को बरामद करने के लिये एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रही है। अगर पुलिस अफ़सर जो Recovery करने पर लगे हुए हैं, औरतों पर अत्याचार करें तो मैं बरदाश्त नहीं कर सकती। इस लिये मैं गवर्नमैण्ट से कहना चाहती हूं कि वह एक Impartial Enquiry Committee ज़रूर बिठाए। अगर कोई अफ़सर कसूरवार है तो उसे ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिये और अगर कोई कसूरवार न हो तो कहो कि लोग पार्टीबाज़ी की बिना पर बातें करते हैं। हमारे डिप्टी लीडर साहिब बहुत होशियार हैं। मैं उन्हें फिर याद दिलाना चाहती हूं कि अमृतसर Meeting में उन्होंने जो कुछ कहा था उसे याद करें। हमें मुतहिदा महाज़ बना कर दुश्मन के साथ लड़ना है। मुझे यह देख कर दुःख होता है कि सरदार प्रताप सिंह इन बैंचों पर बैठे हों और श्री किदार नाथ सहगल मुख़ालिफ़ बैंचों पर। इसलिये हमें चाहिये कि हम आपस में मिल जायें।

"लड़न दी रात आवे पर बिछड़न दी रात न आवे"

मेरा समय हो गया है। मैं अपने सारे Point छोड़ कर अपने Opposition वाले भाइयों से अपील करना चाहती हूं कि वह सब इकट्ठे हो जायें। यद्यपि जो कुछ भाई साहिब ने अब कहा है उस के बाद किसी अपील की गुंजायश नहीं रही। लोगों में इस समय इत्तहाद इतहाद का जज़्बा है। पिछले दिनों अमृतसर में वह भारी वर्षा होते रहने के बावजूद हज़ारों की गिनती में इकट्ठे हुए थे। उन में कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, संघी भंगी (हंसी) सब मौजूद थे क्योंकि वह सब कहते थे कि हम पाकिस्तान की फ़ौजी ताकत को तोड़ देंगे। इसलिये मैं कहती हूं कि जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे जब तक आप अपने दिलों की

[श्रीमती शन्नोदेवी]

कदूरत दूर नहीं करेंगे और Power हासिल करने के मनसूबे नहीं छोड़ेंगे, आप लोगों की भलाई और पंजाब की बेहतरी नहीं कर सकेंगे ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ (ਟਾਂਡਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਡਰੇਸ (Address) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ —

> "Law and order have, however, to be maintained to enable the citizens to work in an atmosphere of peace, and I am glad to say that our position in this respect is on the whole satisfactory and hopeful."

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਇਸ ਐਡਰੇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Law and Order ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ । ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਭਰਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤ੍ਰ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ Custody ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਆਂਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ En-Counters ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਾ 107 ਅਤੇ 151 ਦੇ Cases 54,000 ਚੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਾ 109 ਦੇ 106 ਚੱਲੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ Law and Order ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਫ਼ਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਡਾਕੂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੋ ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਚਨਨ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਫੇਰ ਇਸ ਐਡਰੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਘਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਜਗਾਧਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ । ਜਾਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਇਕ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਰੀਜਨ ਲੜਕੀ ਲਿਆਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਅਗ਼ਵਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕੇ ਉਹ ਇਕ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ।

Chief Parliamentary Secretary : On a point of order. I stated on the floor of the House that the man has been prosecuted. He is making a misrepresentation of facts.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਐਡਰੇਸ ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ(walk out) ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ documents ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ rape ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਇਕ M.L.A. ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ documents ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ enquiry ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।

Mr. Speaker : It is not in good taste to say that.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : Good taste ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪੇ action ਲੈਣਗੇ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਫਿਰ, ਪਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ Security Act ਦੇ ਅਧੀਨ 25 ਮੁਖਾਲਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕਦਮੇ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਦੋ M.L.A. ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਪਿਰਟ (spirit) ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ C class ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ law and order ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

अध्यक्ष महोदय : समय काफी हो चुका है। पहले ही 30 मिनट सरदार उज्जल सिंह ने अनायत किये हैं और 15 मिनट मैंने दे दिये हैं। अब केवल सरदार वरयाम सिंह की तकरीर होगी जिन से मैं गुजारश करूंगा कि वह ठीक 5.30 बजे बैठ जायें।

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! Opposition Benches ਵਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਡਰੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਾਹਸ਼ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੁਟ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਿਤਰ ਨੇ ਐਡਰੇਸ ਦਾ ਇਕ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਵਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਕੀਆਂ ਨਿਕੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਕੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਫੁਟ ਹੈ।

[ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ]

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫ਼ਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ Seculer ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਨਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਨੇਸ਼ਨ (Nation) ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰ ਦੇਣ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਦਿਲੋਂ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਰਖਿਆ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਛਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵੰਡਾਰੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਵੰਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਦਿਲੋਂ ਕਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿਖ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਗਲਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਬਾਰਿਕ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ । ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਉਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਤਯਾਤ ਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਸਾਡੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਵਖੇਵਾਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਲ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਖੇ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਬਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਤਬਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕੇ । ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕੇਲ [illegible], ਕਲ ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਾਇਮ ਰਖ ਭੀ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਕੂਲ ਅਪਨਾਉਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਨਤੀ ਤੇ ਪਕਿਆਈ ਹੋ ਸਕੇ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ Address ਵਿਚ ਸਭ ਅੱਛਾ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਸਭ ਅਛਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰ ਹੀ ਹਨੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਵੇਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਤਵਾਰੀਖ ਕਿਸੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਮਾਲੀਆ ਦੇ ਸੀਨੇ ਪਰ ਭਾਖੜੇ ਡੈਮ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂ ਅਸਥੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਕਢਕੇ ਦਿਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾੜਾਂ ਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਰਹਾਦ ਬਾਵਾਂ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਪਾਤਾਲ ਚੋਂ ਖਿਚਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਟਯੂਬਵੈਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸਾਰੂ ਚਸ਼ਮੇ ਬਣਕੇ, ਸੱਚਰ ਕੈਰੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਰੋਂ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਮੂੰਹ ਖੋਹਲਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਦਸੇਗਾ, ਜਿਸਤੇ ਕੌਮ ਮਾਨ ਕਰੇਗੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਅਛਾ ਹੈ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਐਨਕ ਬਦਲਣ ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਅਛਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਜਦ ਕਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ Address ਉਪਰ Motion of Thanks ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੀ Opposition ਵਲ ਗਏ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ Montion of Thanks ਬੇਕਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਸਪੀਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹਨ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਇਹੀ ਹਾਊਸ, ਇਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹੀ Motion of Thanks, ਇਹੀ ਇਨਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਤਦ ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।

ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ । ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਾਦਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਬਗ਼ਲਗੀਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ —

ਕਿਆ ਖ਼ਬਰ ਥੀ ਇਨਕਲਾਬੇ ਆਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ।
ਯਾਰ ਕਾ ਮਿਲਨਾ ਨਸੀਬੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ।

Mr. Speaker : No insinuation please ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ।

ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Opposition Party ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਤੇ ਬੇਸੁਰੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ । consolidation of holdings ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਡੰਗਰ ਚਰਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਲ ਜਾਂਦੇ

[ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ]

ਸਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਡੰਗਰ ਰਜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਕੋ ਥਾਂ ਬਨ੍ਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਉਨਤੀ ਤੇ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਛਣਗੇ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਖੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖੂਹ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਛੱਡ ਯਾਰ ਖੂਹ ਨਾ ਲਵਾਈਂ, ਕੋਈ ਅੰਨ੍ਹਾ ਇਸ ਵਿਚ ਡਿਗ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨਤੀ ਭਰੇ ਉਸਾਰੂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਅੰਧਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਥ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛਡ ਸਕਦੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ judiciary ਨੂੰ executive ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਨ ਲਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ decentralization of administration ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ।

ਪੰਡਤ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾਂ: ਵਾਕਈ ਹਮ ਸਭਕੋ ਉਸ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ।

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਬੈਠ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਵਜੂਹਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸਰੂਫ਼ ਸਾਂ। ਇਸਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਪਰ ਕਰੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਯਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾਂ।

ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਨ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਉਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਰੋਹਤਕ

ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਐਡਰੈਸ (Address) ਵਿਚ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਨ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿਹਾ । ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਫ਼ਕੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੈ । ਜੁਰਮ ਘਟ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਸ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਜੋ ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਚਮੁਚ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਯਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹੀ ਭਾਵ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਕ ਡਾਕਾ ਪਿਆ । ਡਾਕੂ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਨ—ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ । ਪਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਸ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਿਕਲੀ—ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਗੈਂਗ (gang) ਪਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਅਤੇ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਭੈ ਅਤੇ ਡਰ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਬਾਕੀਆਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ?

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਓਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਮੂੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। [Cheers]

ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਦੂਜਿਆਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗੇ ਚਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰੇਟਰ ਸਿੱਖ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ nationalise ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਜੋ 1155 ਨੂੰ 1115 ਰਖਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਗਲ ਭੁਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹੀ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (nationalisation) ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਰੰਭ ਸੰਨ 1950 ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। (*Hear hear*) ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕਾਦਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। [*Cheers*]

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ।

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ : ਪਰ ਨਾਲ ਸਿਖ ਵੀ ਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ interest ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਫੇਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬਈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (Motor Transport) ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫ਼ਿਰਕਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਮੁਫ਼ਾਦ—ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ ਉਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਬੇਹਤਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਓਂ ਨੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ operators ਨੇ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ postpone ਕਰ ਦਿਉ । ਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮੰਨ ਲਿਆ । ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਨੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿਤਨੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਨੂੰ criticise ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਲੋਚਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਰਖਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੰਜ ਹਨ :---

ਕੁਲ ਸਰਮਾਇਆ ..	62,50,000	ਰੁਪਏ
ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸ ਮੁਨਾਫ਼ਾ	29,99,929	,,
ਡੇਪ੍ਰੀਸੀਏਸ਼ਨ (ਰੀਜ਼ਰਵ)	17,73,000	,,
ਸੂਦ ਲਈ ਕਢਿਆ ਗਿਆ .. ਰੁਪਿਆ	4,11,246	,,

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 62,50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਜ ਤਿਕਨ ਕੋਈ 52,34,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ਹੋਵੇ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ । ਇਸ ਵਿਚ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਓਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਅਮਰਨਾਥ ਵਿਦਿਆਲੰਕਾਰ ਨੇ picketing ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ pearl hosiery ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪਿਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਪ ਵਕੀਲ ਹਨ ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਈ ਗਈ ਲੀਗਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਇਹ ਦਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਡਿਤ ਅਮਰਨਾਥ ਵਿਦਿਆਲੰਕਾਰ—ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (*Cheers*) ਇਹ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।

[ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ]

ਫੇਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕਿਓਂ ਦਿਤਾ ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆਂ ਕਿਓਂ ਕਿ ਅਮਨ ਵਿਚ ਭੰਗ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ tribunal ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਕਟਿੰਗ ਅਮਨ ਵਿਚ ਖਲੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਨ ਛੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਦਆ ਅਮਨ ਵਿਚ ਖ਼ਲੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਿਵਾਇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਚੰਦ ਇਕ ਉਹ ਮਜਦੂਰ ਨਹੀ ਛਡੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। (*Interruption*). ਉਨ੍ਹਾਂਦੇ ਛੋੜਨੇ ਦੀ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਹਮਖਾਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ (*Interruption*)।

Mr. Speaker : You need not address those who interrupt you but address the Chair.

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੰਤਾ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਸੀ ਛਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। (*Interruptions*).

Mr. Speaker : Order, order.

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ : ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰੋਫੇਸਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਗੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਿਠੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿਠੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਸਨ ਲੈ ਗਏ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਵ੍ਹੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ Public Services Commission ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛੀ ਜਾ ਸੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ for comments ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇ। (*At this stage there were interruptions*).

Mr. Speaker: Order, order.

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ : ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ national workers ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ

ਬਾਕੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤਰਾਂ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਕੀਆਂ ੨ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਕੀਆਂ ੨ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੈਨ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਗਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਫੈਹਮੀ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Administration ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ (action) ਲੇਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ action ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ Court fee Stamp ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਖੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਦੋ ਜ਼ਾਮਨ ਦੇ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਦਮੀ ਦਸਤਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Industries ਵਾਸਤੇ subsidy ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 15 ਜਾਂ 20 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਅਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁਛ ਲੇਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ।

[ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ]

ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਲਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ order ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ) ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਮੇਰੇ ਮਿਤਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ Technical ਅਤੇ vocational education ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ Engineering College ਖੋਹਲਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ technical education ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ Central Government ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਇਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ private technical institute ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ technical education ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ unemployment ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ।

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤਰ ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਵੀਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ district board ਦੀਆਂ elections ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ । ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ reorganise ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਦੇਰ ਇਸਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣ । ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਥੇ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ । ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਰੇਸ ਵਿਚ Corruption ਅਤੇ communalism ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । (Corruption) ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਸ਼ਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਦੋਸਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਨਿਸਟਰ (Development Minister) ਨੇ ਡੰਡਾ ਡੋਡੇ ਨਾਲ consolidation ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚੋਂ ਕੁਰਪਸ਼ਨ (corruption) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ । (ਤਾਲੀਆਂ) ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਿਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵਡੀ achievement ਹੈ । (ਤਾਲੀਆਂ)

ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਚਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ

ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 'C class' ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀ ਰਾਮ ਨੂੰ 'C class' ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ better class ਦੇਣ ਦੀ offer ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸਤੇ ਸਾਮਣੇ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਸਚਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਵਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਹੋਵੇ । ਪਰੰਤੂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਪੰਡਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਧੇਰਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤ੍ਰੀ ਤਾਂ ਸਨ ਪੰਡਿਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਮੈਂਬਰ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ।

पंडित श्री राम शर्मा : यह ठीक है ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਤਫ਼ਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਥੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਦੋ ਗ੍ਰੋਹ ਬਣ ਗਏ । ਇਕ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਕ ਗ੍ਰੋਹ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੋਹ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਲੈਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ । ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ । ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ 1951 ਵਿਚ ਹੋਏ । ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਪੰਡਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤੀ ਰਹੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ? ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚ ਦਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 3, 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ੨ ਡਾਕੂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਂਦੇ ਰਹੇ । ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ਿਰ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ । ਫ਼ਰਵਰੀ 1951 ਵਿਚ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਕਤਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕੂ ਹੇਮ ਰਾਜ ਦੀ ਚਹੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਵੰਦ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਆ । ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਡਾਕੂ ਦੀਪੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ । ਅਪ੍ਰੈਲ 1951 ਵਿਚ ਇਸ gang ਨੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ । ਮਈ 1951 ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੇਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਕਰਵਾਇਆ । ਸਤੰਬਰ 1951 ਵਿਚ ਗਸ਼ਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਕ ਜੱਥਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 1 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 2 A.S.I.s, 4 ਹੈਡ ਕਨਸਟੇਬਲ ਸਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ mounted police ਦਾ armed reserve ਜਿਸ ਵਿਚ 1 ਇਨਸਪੈਕਟਰ, 2 ਹੈਡ ਕਨਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 25 ਫੁਟ ਕਨਸਟੇਬਲ ਸਨ, ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ

[ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ]

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 110 ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, detain ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 1951 ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਉਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ gang ਵਿਰੁਧ ਇਤਨੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ gang ਦੇ ਦੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੀਡਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਦਸਤਾ ਉਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ 1951 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ informer ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ 110 ਆਦਮੀ detain ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਪਿਛੋਂ 12 ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ detain ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ 122 ਆਦਮੀ detain ਕੀਤੇ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਨ ਦਸੰਬਰ 1952 ਵਿਚ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਧ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕੈਦ ਤੋਂ ਛੁਟ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 1952 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਫਿਰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਡਾਕੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਕਠਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। (ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ) (ਹਾਸਾ)

ਇਸਤਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੇਮ ਰਾਜ ਡਾਕੂ ਨਸ ਗਿਆ।

1953 ਵਿਚ ਡਾਕੂ ਹੇਮਰਾਜ ਨਾਲ 3 ਡਾਕੂ ਰਾਮ ਅਤੇ ਛਜੂ ਆਦਿ ਰਲ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਅਗਸਤ 1953 ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉਸ ਵਿਚ 2 ਸਬ ਇਨਸਪੈਕਟਰ, 4 ਹੈਡ ਕਾਨਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 50 ਫੁਟ ਕਾਨਸਟੇਬਲ ਸਨ। 105 ਪੁਲੀਸ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿਛੋਂ ਜਦ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕੂ ਸਿਰ ਕਢ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 97 ਆਦਮੀ ਪਕੜ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ detain ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿਚ 2,000 ਦੇ ਮਜਮੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਰਿਛਾਕ ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਪੁਲਸ ਫੋਰਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 3 ਸਬ ਇਨਸਪੈਕਟਰ 6 ਹੈਡ ਕਾਨਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 75 ਫੁਟ ਕਾਨਸਟੇਬਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਛਜੂ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਡਾਕੂ ਨੂੰ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹੇਮ ਰਾਜ ਡਾਕੂ ਦੇ 5 ਸਾਥੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਹੇਮ ਰਾਜ ਨਸ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਹੇਮ ਰਾਜ ਦੇ।

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ! ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਨ ਜੋਖੋਂ ਵਿਚ ਪਾਕੇ ਭਿਆਨਕ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਗਏ ਜਦ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ—ਰਾਈਫਲਾਂ 8, ਰੀਵਾਲਵਰ 9, ਪਿਸਟਲ 2, ਦੋਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕਾਂ 3, ਹੈਂਡ ਗਰਨੇਡ 6, ਕਾਰਟਰਿਜਜ਼ 412, ਗੰਨਾਂ 40, ਅਤੇ ਗੰਨਾਂ ਬੈਰਲਜ਼ 4।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੁਪ ਚਪਾਤੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁਟ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਿਆ:—

ਬੰਦੂਕਾਂ 2, ਸਟੇਨ ਗਨ 1, ਰੀਵਾਲਵਰ 8, ਪਿਸਟਲ 2, ਹੈਂਡ ਗਰਨੇਡ 108, ਪਿਸਟਲ ਬੈਰਲ 138, ਬੈਰਲਜ਼ ਆਫ ਗਨਜ਼ 32।

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ illicit (ਨਜਾਇਜ਼) ਅਸਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਅਸਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭੜਥੂ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। (ਆਵਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ) (ਹਾਸਾ)

ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਲੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਵੀ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਹਿਣੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ, ਅਸਲਾ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਕੈਸ਼ 7,086 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਪੜੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ।

ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਗਲ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲੀਸ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆ ਪਈ। ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੁਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਬੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਉਥੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਇਕ ਇਨਸਪੈਕਟਰ, 1 ਸਬ ਇਨਸਪੈਕਟਰ, 2 ਹੈਡ ਕਾਨਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 20 ਫੁਟ ਕਾਨਸਟੇਬਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।

[ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ]

31-12-53 ਨੂੰ ਜਾਗਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ 1 ਹੈਡ ਕਾਨਸਟੇਬਲ ਤੇ 20 ਫੁਟ ਕਾਨਟੇਬਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ।

25-1-1954 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 1 ਇਨਸਪੇਕਟਰ, 1 ਸਬ ਇਨਸਪੈਕਟਰ, 2 ਹੈਡ ਕਾਨਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 30 ਫੁਟ ਕਾਨਸਟੇਬਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ।

ਇਹ ਸੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।

11-2-54 ਨੂੰ 2 ਸਬ ਇਨਸਪੈਕਟਰ, 11 ਫੁਟ ਕਾਨਸਟੇਬਲ 6 ਮਾਊਂਟਿਡ ਫੋਰਸ ਅਤੇ 25 ਜਾਂ 30 ਆਦਮੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ । ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਪਰ ਦਸੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵਧ ਆਦਮੀ ਕਿਧਰੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੋਣ ।

श्री श्री चंद—मैं इस बात की तरदीद करता हूं और कहता हूं कि जो figures आप ने बताये हैं वह सब बिलकुल गलत हैं ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ! ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਏਥੇ ਹੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੀਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੇ facts and figures, ਡਾਇਰੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਿਆਂ, ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰੀਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ।

ਰਾਬਜ਼ਾ ਵਿਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ 25-30 ਫੁਟ ਕਾਨਸਟੇਬਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤ੍ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ Bar Association ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਗਏ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਲੀਤੇ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ । ਲੇਕਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਥੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ?

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵ ਰਾਜ ਸੇਠੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਲ ਹਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵ ਰਾਜ

ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਦੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਡਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਚ ਮਨਣਾ ਪਏਗਾ।

ਬਹਰ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਉਥੇ ਗਏ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮਰਦ ਯਾਨੀ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ (ਸਭ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ) ਕੋਈ ਵਜਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਾਰ ਪੀਟ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰ ਪੀਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਨੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Bar Association ਦੇ resolution ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 28 ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ resolution ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ। ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ. ਪੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ specific ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਹਕੀਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਸੂਰ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। D.I.G. ਸਾਹਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ D.I.G. ਅਤੇ D.C ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ (enquiry) ਕੀਤੀ। D.C. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ—

D. O. LETTER FROM DEPUTY COMMISSIONER, ROHTAK

I visited Jagsi and Rabrah villages on 15th February along with D.I.G. and S. P. These are the two villages where the worst police atrocities are alleged to have been committed. In these two villages we held open meetings which were attended by about 300 villagers in each. In these meetings I told the villagers that neither the Government nor the senior police officers or,I would ever tolerate the commisson of the offences of rape and loot by any subordinates of the police force and that we were prepared to ensure that deterrent punishment was given to any such men of the police force who may have committed such atrocities.

I asked them to come forthwith without any fear and give me information, in the open meeting or separately, about the atrocities of loot and rape, if any, had been committed in these villages, Despite my repeated exhortation to them to this effect, no body came forth to allege that any atrocities in the shape of loot or rape, or molestation of women had been committed by any men of the police force.

The members of the Panchayats and the leaders attended these meetings. They, in fact, admitted before us that the villagers had been beguiled into levelling these allegations by the communists and other interested parties.

ਇਸਤੋਂ ਅਲਾਵਾ Resident Magistrate ਨੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ (enquiry) ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖੀਆਂ।

ਫੇਰ Bar Association ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਓ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ

[ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਓਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਐਨਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਂਦੇ ਹਨ ਓਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਖਾਸ ਮਸਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ inquiry ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। (*Hear, hear*).

ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਖਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਟੋਲਣ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। U.S.A. ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਕਟ (pact) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਘਟਾਓ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਇਕਠ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ। (*cheers*)।

Mr. Speaker : Question is—

That at the end of the motion, the following be added :—

"but regret that adequate consideration has not been given to—

(a) remove unemployment and under-employment in the State ;

(b) remove disparities between the rich and the poor ;

(c) provide cheap credit to the landless—the tenants and the labourers and cottage industry ;

(d) change the pro-rich mentality of the administration ;

(e) fulfill the assurance of appointing Harijan lambardars ;

(f) fulfil the assurance of holding District Board elections ;

(g) provide technical and vocational education in the State :

(h) encourge the Bhoodan Sampatidan movement ;

(i) check the growing evil of Satta gambling ;

(j) make arrangements for settlement along with consolidation ;

(k) change rules regarding the rent of Arms licenses ; and

(l) provide good publicity facilities for Government activities.

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That at the end of the motion, the following be added :—

"but regret that the Government have failed to administer even-handed justice to people of all shades of opinion in the province and have pursued anti-national policies which have harmed the just interests of the State ".

The motion was lost

Mr Speaker : Question is—

That at the end of the motion, the following be added :—

But regret that—

(i) the atrocities perpetrated by the Police on men, women and children in the villages of District Rohtak, the rape and dishonouring of women and looting and destruction of property have not been mentioned and institution of a Judicial Enquiry into the Police excesses and punishment of those guilty have not been promised ;

(ii) the notices of eviction served on tens of thousands of tenants, encouragement given to the Landlords by the Government and the collusion of certain Government officials with landlords have not been mentioned ;

(iii) the general repression launched against tenants, arrest of hundreds of tenants and Kisan Sabha workers in all parts of Punjab and the arrest of two members of Punjab Legislative Assembly to suppress the tenants movement have not been mentioned ;

(iv) the repressive policy of Government imposition of Section 144 and posting of Punitive Police Posts have not been mentioned ;

(v) the policy of the Government to suppress and gag democratic and opposition Press and arrest of Journalists without even consulting Press Advisory Committee have not been mentioned ;

(vi) the increase in unemployment, retrenchment of workers and employees and wage-cuts have not been mentioned ; and

(vii) the failure of the Government to protect and encourage industry has not been mentioned.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That at the end of the motion, the following be added :—

But regret that—

"nothing has been done to safeguard the civil liberty, honour and property of the general public in the State".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is —

That at the end of the motion, the following be added :—

"but regret that—

(a) nothing has been done to check the high-handedness and unwanton attack on the Civil Liberties of the Public at the hands of the Police in the name of Law and Order,

(b) no mention has been made at the sensational abduction of the two sisters of Jamnanagar,

(c) nothing has been mentioned about the alleged atrocities perpetrated upon the residents of the various villages of the District of Rohtak under the garb of anti-dacoit operations".

The motion was lost.

Mr Speaker : Question is—

That at the end of the motion the following be added :—

"but regret that—

the address of the Governor did not refer to the Police atrocities committed in Rohtak District in connection with the anti-decoit operations in the last week of the January last".

The motion was lost

Mr Speaker : Question is—

That at the end of the motion, the following be added :—

"But regret that no mention has been made about the restoration of lands and homes to about 700 displaced Muslim families of Gurgaon District ; and no categorical assurance has been given regarding change over to Hindi within the stipulated time and early elections to a decade old District Boards."

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr Speaker : Question is—

That at the end of the motion, the following be added :—

But regret that—

(1) adequate consideration has not been given to the Muslim of Gurgaon District for restoration of their properties as yet ;

(2) nothing has been done to improve the so-called Criminal Tribes such as Bararia and Mirias, etc. in the State ;

(3) to improve the lot of "khana badosh" tribes as such Kanjar, Perna and Bhobalias in the Hariana Prant ;

(4) to improve the lot of landless cultivators ;

(5) to improve the lot of Beggars.

The motion was lost.

Mr Speaker : Question is—

"That the members of this House assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the address he has been pleased to deliver to both the Houses assembled together."

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think the Ayes have it ". This opinion was challenged and Division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those Members who challenged his decision and supported the claim for a Division, to rise in their places declared that the Division was unnecessarily claimed.

The motion was declared carried.

The Assembly then adjourned till 9 a.m., on Friday, the 12th March 1954.

107 PSLA 283 6 9 54 –CP and S. Pb Chandigarh

Punjab Legislative Assembly Debates

12th *March* 1954

VOL. I—No. 4

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday, the** 12th **March **1954.**
(Morning Session)

CHANDIGARH:
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab,
1954

Price : 0-4-0

PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY

Friday, 12*th March*, 1954.

The Assembly met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital at 9 a.m. of the clock. Mr. Speaker (Dr. Satyapal) in the Chair.

PRESENTATION OF BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1954-55.

Mr. Speaker : I would request the Finance Minister to present the Budget Estimates for the year 1954-55.

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I rise to introduce the Budget Estimates for the year 1954-55.

2. The past six-and-a-half years constitute in the economic realm of the Punjab, a period of consolidation and gradual progress. Thanks to the benevolence of nature, this period has been free from large scale calamities affecting the crops and general health of men and animals. The internal peace and absence of happenings in the international sphere likely to affect us adversely have helped our people to substantially repair the heavy damage sustained in the wake of the Partition. They also got an opportunity to re-build their economy on a more sound and scientific basis.

The acreage sown under various crops in the State rose from 1,33,37,000 acres in 1948-49 to 1,38,30,000 acres in 1952-53. The irrigated portion of this area improved from 31 to 38 per cent during this period, making the fruits of labour in agriculture more secure. This improvement also led to extension in the growing of the more paying commercial crops. The area under cotton increased from 2,39,000 acres in 1948-49 to 5,15,000 acres in 1953-54 and that under oil-seeds from 3,69,000 acres to 7,00,000 acres. (*Hear, hear*) Among foodgrains the cultivation of rice is becoming more popular ; this crop occupied 3,78,000 acres in 1948-49 and 5,75,000 acres in 1953-54. (*Cheers*). Not only there have been increases in area under these important crops, but yields have gone up too, thanks to the new varieties evolved and the better methods of cultivation.

The value of production of important crops in the State was estimated at Rs 1,25 crores in 1949-50. This figure improved to Rs 1,51 crores in 1952-53, despite recession in the wheat, sugarcane, oil-seeds and cotton prices.

It is gratifying to note that our farmers are zealously taking to the improved methods of farming and cultivation and the lethargy of ages is yielding place to dynamic activity in every sphere—social, economic and political.

[Minister for Finance]

Trade and industry do not occupy a very conspicuous place in the economy of our State, but even in this limited sphere there has been a healthy progress. Since the Partition 465 new companies have been registered in the State which have an authorized capital of Rs 13,69,75,000 and subscribed capital of Rs 1,55,15,537. The number of factories on the register of the Labour Commissioner stood at 715 in 1948, 820 in 1949, 1,270 in 1950, 1,486 in 1951, 1,688 in 1952 and 1,817 in 1953. The number of workers employed in the registered factories was 36,625 in 1948 and this figure rose to 62,000 in 1953 (*Hear, hear*). The value of goods produced by some of the major industries in the State was calculated at Rs. 8,83 lakhs in 1948. The corresponding figure for 1951 was Rs. 14,71 lakhs. Subsequent figures are not yet available, but they should show sustained progress. Not only have some new industries been established in recent years, but many among the old ones have stepped up their production by installing more machinery of the latest design. The recently established Industrial Finance Corporation, it is expected, will further speed up this progress in the State.

The trade of the State has witnessed a steady advance. Our products are finding a ready market in all parts of the country and even abroad. The banks have gradually shed the fear of advancing money in this border State and credit conditions are returning to normalcy.

With the gradual return to peace economy and the reversion of the price gear from the inflationary top, there are indications of some increase in unemployment in the State, particularly among young men passing out of schools, and colleges in increasing numbers without technical training or qualifications. Government is not unmindful of the situation and measures are being adopted to cope with this problem. It is, also, hoped that the multi-purpose River Projects and growing industry will before long expand considerably the avenues of fresh employment (*Hear, hear*).

Year 1953-54

3. *Revenue Account.* The original Budget for 1953-54 showed a deficit of Rs. 31 lakhs. As a result of the economies detailed in my last year's Budget Speech, savings to the extent of Rs. 18 lakhs were anticipated, which reduced the deficit from Rs 31 lakhs to Rs 13 lakhs. The Revised Estimates have been prepared, and I am glad to inform the House that the anticipated deficit of Rs. 13 lakhs has now turned into a surplus of Rs 16 lakhs. (*Cheers*). This shows an over-all improvement of Rs. 29 lakhs, or of Rs 47 lakhs according to original Budget. Although according to original Budget there is a decrease of Rs. 3 lakhs in the Revenue-Receipts, savings to the tune of Rs. 50 lakhs have occurred in the Revenue Expenditure. To state briefly Revenue Receipts have fallen from Rs 19,74 lakhs to Rs. 19,71 lakhs and Revenue Expenditure from Rs 20,05 lakhs to Rs 19,55 lakhs. The variations in the Revenue receipts are :

		(*In lakhs of rupees*)
Central Excise Duties	..	—4
Taxes on Income	..	+19

Land Revenue (Gross)	..	—20
Other Taxes and Duties	..	+8
Miscellaneous	..	+20
Grants-in-Aid from Central Government	..	—19
Extraordinary Receipts	..	—15
Other small variations	..	+8
Total	..	—3

On the Expenditure side where a saving of Rs. 50 lakhs has been effected, the variations are :—

Appropriation for Reduction or Avoidance of Debt	..	+18
General Administration	..	—7
Police	..	+10
Civil Works	..	—49
Pensions	..	+16
Miscellaneous	..	+13
Community Projects	..	—22
Prepartition Payments	..	—11
Other minor variations	..	—18
Total	..	—50

Detailed figures of Revenue Receipts and Revenue Expenditure, together with the reasons for these variations, will be found in the Finance Secretary's Memorandum.

4. *The Capital Expenditure.* The Capital Expenditure originally budgeted amounted to Rs. 32,57 lakhs. The Revised Estimates prepared now show an expenditure of Rs. 34,43 lakhs, i.e., an increase of Rs. 1,86 lakhs. The budgeted expenditure under heads Construction of Irrigation Works and Schemes of State Trading shows a decrease of about Rs. 3,30 lakhs. The expenditure on the Bhakra-Nangal Project has, however, gone up by Rs. 4,98 lakhs. This increase in expenditure is owing to the fact that strenuous efforts are being made to complete the Bhakra Canals well before the target dates, so as to run water during the coming *Kharif.*

[Minister for Finance]

5. *Loans and Advances*. Loans and Advances were anticipated at Rs. 2,77 lakhs, but the Revised Estimates reveal that advances would amount to Rs. 2,79 lakhs during the current year. A supplementary grant of Rs. 42 lakhs was obtained from the House during the October Session, and if this is accounted for, there will be a saving of Rs. 40 lakhs. There are, however, several important internal variations, details of which are given in the Finance Secretary's Memorandum, but some of which deserve mention here. A sum of Rs 1,60 lakhs was provided for Urban Rehabilitation Loans. As there came to be a decrease in the Government of India loan allotment, a corresponding decrease has occurred in this figure also, and there is a saving of Rs. 98 lakhs. On the other hand, Rs. 81 lakhs have been provided for advances for the purchase and distribution of fertilizers in the State, and Rs. 35 lakhs for meeting the outstanding claims of displaced Co-operative institutions.

On the recoveries side, an improvement of Rs. 34 lakhs has been shown in the Revised Estimates. This is because bulk of the loan advanced for fertilizers is to be recovered at the end of the harvest.

Year 1954-55

6. *Budget Proposals*. I now pass on to the Budget proposals for the coming financial year. The Estimates are summarised as follows:—

			(In lakhs of rupees)
I. Opening Balance—			
(a) According to Books	..	+1,39	
(b) Invested in Securities	..	+1,16	
Total	..		+2,55
II. Revenue Account—			
(a) Revenue Receipts	..	22,19	
(b) Revenue Expenditure	..	23,12	
Deficit	..	..	—93
III. Capital Expenditure		..	—31,73
IV. Loans and advances (Net)		..	—1,95
V. Public Debt (Net)		..	+29,81
VI. Other Debt, Deposits and Remittance Transactions (Net)		..	+4,10

VII. Closing Balance—

(a) According to Books	+69	
(b) Invested in Securities	+1,16	
Total ..		+1,85

Revenue Account, 1954-55—*Deficit*. The proposed budget shows Revenue Receipts at Rs. 22,19 lakhs and Revenue Expenditure at Rs. 23,12 lakhs, indicating a deficit of Rs. 93 lakhs. As compared with the Revised Estimates of the current year, it would be seen that there is considerable increase both on the Receipts as well as the Expenditure side. The Revenue Receipts show an increase of Rs. 2,48 lakhs over the Revised Estimates, while the Revenue Expenditure shows an increase of Rs. 3,57 lakhs. Major variations in receipts are:—

	(In lakhs of rupees)
Taxes on income ..	—6
Land Revenue (Gross) ..	+10
Other Taxes and Duties ..	+38
Irrigation (Net) ..	—26
Civil Works ..	+39
Electricity (Net) ..	—35
Stationery and Printing ..	+25
Miscellaneous ..	+1,06
Grants-in-aid ..	+44
Extraordinary Receipts ..	+21
Other Minor Variations ..	+32
Total ..	+2,48

The decrease in receipts under Irrigation is mainly on account of increase in working expenses which are accounted for in the Budget as deductions in receipts. These expenses are going up, as the banks of channels are proposed to be raised during the next year. On the Electricity side the decrease is the result of the contemplated transfer of Rs. 50 lakhs for assistance to the Electricity part of the Bhakra-Nangal Project. A substantial increase under "Other Taxes and Duties" has become possible on

[Minister for Finance]
account of increased income from Sales Tax, and the proposed re-introduction of the Tobacco Vend Fees Act. This Act was repealed with effect from April, 1952, when manufactured tobacco became liable to Sales Tax. This change resulted in large scale smuggling from neighbouring States and evasion of Sales Tax. Besides, dealers also raised objections to the levy of Sales Tax instead of the Vend Fees The Tobacco Vend Fees Act is, therefore, now being reintroduced and manufactured tobacco will no more be liable to Sales Tax but to Vend Fees. The increase under head 'Miscellaneous' is in the order of Rs. 1,06 lakhs, and bulk of this increase, namely Rs. 93 lakhs, is from gross receipts from nationalised transport.

On the Expenditure side, it would be noticed that the important increases are under Development heads. (*Hear, hear*). These items will be dealt with later when the activities of the various departments are discussed. However, the heads where increases in expenditure have taken place are:—

		(*In lakhs of rupees*)
Land Revenue	..	+13
State Excise	..	+13
Interest and Reduction or Avoidance of Debt	..	+26
Education (after deduct entries)	..	+9
Medical and Public Health	..	+15
Industries	..	+28
Civil Works	..	+1,25
Stationery and Printing	..	+9
Miscellaneous	..	+76
Community Projects	..	+30
Prepartition Payments	..	+12
Other small variations	..	+1
Total	..	+3,57

7. *Capital Expenditure.* Capital Expenditure during the year 1954-55 is estimated at Rs. 31,73 lakhs, of which the important items are:—

		(*In lakhs o rupees*)
Bhakra Nangal Project	..	22,78
Harike Project	..	1,04

		(In lakhs of rupees)
Tube-wells	..	1,25
Roads	..	1,07
Electricity Schemes	..	1,11
New Capital	..	2,13
Nationalisation of Transport	..	50

8. *Loans and advances.* The amounts for Loans and Advances budgeted for next year are Rs. 4,04 lakhs, and recoveries Rs. 2,09 lakhs, leaving a net expenditure of Rs. 1,95 lakhs. The main items are:—

		(In lakhs of rupees)
Grow-More-Food Schemes	..	1,46
Community Projects and National Extension Service Schemes	..	1,33
Rehabilitation Loans (including House Building Loans at Chandigarh)	..	73
Industrial Schemes	..	22
Taccavi Loans	..	10
Advances to Municipalities and Improvement Trusts	..	7
Loans to Government servants	..	13
Total	..	4,04

9. I have given briefly the financial picture of the next year's budget. To enable the House to appreciate the financial policy of the Government and the new directions in which the expenditure is being incurred, I propose now to give a brief description of the varied activities of the Government, emphasizing the changes that are being brought about. Subsequently I shall also deal with the economies effected and the steps taken to reduce further the deficit mentioned above.

10. *General Administration.* Decentralisation of Administration has been our guiding principle, so as not only to make the administration conform to the democratic pattern, but also to make available the services of the administration to the man in the village as near his home as possible. The District Reorganisation Committee, consisting of the two Divisional Commissioners and the Finance Secretary, submitted its report

[Minister for Finance]

to Government some time ago, and important decisions have since been taken after mature deliberation. One of the most important recommendations made by this Committee and accepted by Government is, that all districts should be divided into Sub-Divisions. (*Cheers*). A Tehsil should normally be the basis for the formation of a Sub-Division, but taking into account other factors, like area, population and means of communication, more than one Tehsil may be included in a Sub-Division. As a first step, the new scheme is being fully enforced in Gurdaspur District, where all three Tehsils are being converted into Sub-Divisions. In addition, eleven more Sub-Divisions are being created at Rewari, Nuh-cum-Firozpur-Jhirka, Jhajjar, Bhiwani, Panipat, Nawanshahr-cum-Phillaur, Una, Tarn Taran-cum-Patti, Muktsar, Hamirpur and Nurpur. What is contemplated is that the Sub-Divisional Officer should be in over-all charge of the Sub-Division as the Deputy Commissioner is of the district. This will save the villagers from the botheration and expense of going to district headquarters, as they will be able to get many of their needs attended to nearer home at the Sub-Divisional Headquarters. To mention a few, for the renewal of Arms Licences, for making applications for passports, for obtaining copies from the Copying Agency, for paying in taxes, none need go to district headquarters, as the Sub-Divisional Officers will be empowered to take necessary action.

It was, however, felt necessary that details involved in implementing the decisions regarding decentralisation should be worked out before the scheme in all its aspects is enforced throughout the State. An Officer-on-Special Duty, under the Commissioner, Ambala and Jullundur Divisions, has, therefore, been appointed, and it is expected that details would be ready within a month or so.

As far as possible, reorganisation will be carried out without adding to the existing number of officers. It has been decided that courts and residences should, wherever possible, be established in the new townships, or in the existing Government buildings available, so that expenditure on Civil Works is reduced. Fresh construction will be confined only to such places where no other buildings would be available, and a provision of Rs. 10 lakhs has been made in the Budget 1954-55 for the same. Another sum of Rs. 2 lakhs has also been provided for the Contingencies and additional staff which may be required as a result of the decentralization of the district administration.

11. *Clerical Grades*. Government has also decided to do away the different grades of clerks and their varying pay scales according to the class of offices they are employed in. They will in the next year be brought on to a common scale of Rs. 60—4—80/5—175. (*Cheers*). This will do away with the perplexing distinctions between clerks and clerks, thereby removing discontentment and ensuring simplification and efficiency (*Hear, hear*).

12. *Separation of the Executive from the Judiciary* We have also decided to take a step towards the separation of Judiciary from the Executive. (*Cheers*). This experiment will be tried, to start with, in the districts of Gurgaon, Simla, Ambala, Jullundur, Hoshiarpur and Kangra. Officers at present doing both Judicial and Executive work will be divided into two categories—those who will do judicial work only, and those who

will work under the Deputy Commissioner in the executive or non-judicial field. All the officers doing judicial work will be placed under the Additional District Magistrate, who will take over bulk of the judicial functions of the District Magistrate and would be himself under the control of District and Sessions Judge. The Judicial officers will be transferable only to those districts where this separation of judiciary from the executive takes place. This change will not only give independence to the judiciary as required under Constitution, but would also enable the Deputy Commissioners to devote more of their time to development activities. They would also now be more in a position to effectively supervise and co-ordinate the activities of the various departments in the district.

13. *Panchayats*. In a democratic country, decentralisation should also result in giving people an opportunity to administer their own affairs at certain levels. With this end in view, the institution of Gram Panchayats was introduced, as well as strengthened. Each village has now got a Panchayat, which is supposed to look after its social, economic, educational and cultural improvement. The total number of Gram Panchayats in the State, at present, is well over 9,000 and I am glad to state that in all these Panchayats the elected members have started performing the duties entrusted to them in right earnest. For the expansion of education alone, Panchayats have collected Rs. 4 lakhs and with a similar contribution from Government, they are setting up schools in a number of villages. (*Cheers*) In order to improve sanitary conditions, the Panchayats in the State were encouraged by Government to raise a sum of Rs. 50 lakhs. Government decided to contribute a sum of Rs. 37½ lakhs as their own share for this purpose. Out of this sum Rs. 15½ lakhs have already been disbursed in the years 1952-53 and 1953-54. For the next year Rs. 7½ lakhs are being provided, and the remaining amount will be contributed in the years following. It is hoped that with all this expenditure the sanitary conditions in villages will improve.

If the Panchayats are to do an effective job in the villages, their finances have necessarily to be strengthened. Ten per cent of the land revenue has already been assigned to them and for the next year the Panchayats are going to get an additional sum of Rs. 40,000, as the anticipated land revenue of the State is going to be higher. An increase in the land revenue is also expected through the process of land settlements, and this will bring in a further sum of Rs 3 lakhs to Panchayats. Apart from these contributions, another permanent source of revenue for the Panchayats is being created. Taking advantage of the consolidation operations in the villages, a decision has been taken at the instance of my colleague, the Development Minister, to carve out a fair-sized plot of land for every Panchayat, depending upon the total area of the village. The Panchayats will be expected to set up a model farm therein and also to earn income for augmenting their revenues. (*Hear, hear*).

Panchayati Adalats and Thana Panchayat Unions are also to be formed over the Panchayats, and it is expected that this work should be completed during the next year.

14. *Jails*. The efforts and plans initiated soon after the Independence for improving the living and disciplinary conditions of prisoners in Jails were continued with increasing vigour during 1953. Further steps in the same direction are contemplated during the year 1954-55. The District Jails,

[Minister for Finance]
Ferozepore, has been converted into a Central Jail, and the Camp Jail, Hissar, into a District Jail. The expansion of the Central Jail, Ambala, is well in hand, while a new jail is being constructed at Amritsar. Site having been selected, plans for the construction of a new Borstal Institute and Juvenile Jail at Karnal are under preparation. It is proposed to sell the land attached to the present District Jail at Hissar at an estimated cost of Rs. 2 lakhs and to utilize the sale-proceeds towards the construction of this Borstal Jail at Karnal. During the next year, the much-needed water-supply in the Sub-Jail, Karnal, is also being provided. To encourage literacy among prisoners, paid teachers have been appointed, and fifteen days' special remission is given when they secure a certificate of literacy. Facilities for imparting training in crafts in Jails have also been improved.

15 *Law and Order*. The improvement in the crime situation in the State was maintained during the year 1953. If a comparison of figures is made with any of the previous years after Partition it would be seen that serious crime has fallen considerably. As a matter of fact, the over-all crime position in the year 1953 was even better than that prevailing in the quinquennium preceding the Partition. Vigorous efforts for the recovery of illicit arms and for the suppression of illicit distillation of liquor continued. The P.A.P., which has come to be entrusted with the task of protecting the border, remained ever vigilant, confident and firm. The P.A.P. Jawans guarding the 300-mile long zig-zag and unnatural border certainly deserve a tribute. It is owing to their continued efforts that the number of border incidents fell to two only during 1953, which factor, in addition to other constructive measures, helped in producing a greater sense of security and confidence among the border people. The P.A.P., in collaboration with the Customs Staff, intensified the crusade against the smugglers, which in addition to lessening crime in the border area helped the Central Government in augmenting its revenues from Custom Duties by putting a virtual stop to the illicit trade. Our P. A. P. is considerably handicapped on account of inadequate transport, and a sum of Rs. 90 lakhs is required for repairs, replacements and purchase of new vehicles against which this State has been able to provide Rs. 5 lakhs only for 1954-55. The expenditure in addition on border defence, which this State is incurring is in the order of Rs. 64 lakhs which legitimately should be borne by the Centre. It is hoped that the Government of India would provide the necessary assistance as Punjab single-handed is not in a position to bear this burden. Representations to this effect have already been made.

The Punjab Police not only did well in maintaining law and order, but also won laurels for the State in the field of Sports. The Fourth All-India Police Athletic Sports Meet was held in the P.A.P. Lines in Jullundur in the first week of February, 1954. It is indeed creditable that our Police won the Athletics, as well as the Hockey Championships, and were runners-up in Foot-ball.

16. *Anti-Corruption Measures*. The State as well as District Anti-Corruption Committees kept up their drive against corrupt elements in the State. During the first nine months of the year 1953, more than 300 persons came to be proceeded against. Out of them three came to be convicted, and 117 dismissed or discharged. Twenty-eight came to be reverted and 26 were punished by stoppage of increments. Sixty-four came

to be warned or censured, two came to be retired compulsorily, while the resignations of 12 others were accepted. Special Judges also came to be appointed for trying corruption cases.

As a result of the measures taken one can confidently say that matters are improving, but the evil can be completely eradicated only with public co-operation. Government on its part is doing all that it can, and I appeal to the public at large for co-operation in rooting out this evil.

17. *Development Activities.* Punjab's Five-Year Plan stood at Rs. 20·2 crores according to the original publication issued by the Planning Commission. By the addition of new items, like Community Projects, National Extension Services, Developments in Scheduled Areas and the like, the Plan now stands at about Rs. 32 crores. The main items in the Plan are :—

		(*In lakhs of rupees*)
Agriculture	..	1,70
Consolidation	..	2,86
Irrigation	..	3,26
Electricity	..	38
Industries	..	64
Roads	..	75
Education	..	1,18
Medical and Public Health	..	1,24
Welfare of Backward Areas	..	75
Community Projects	..	3,87
National Extension Service	..	1,50
New Capital	..	12,80
Other items, like Veterinary, Co-operation, Industrial Housing, Labour, etc.	..	70
Total	..	31,63

Out of the total estimated expenditure of Rs. 32 crores for the First Plan period, this State will have incurred an expenditure in the order of Rs. 15·1 crores by the end of 1953-54. During the next year the expenditure is estimated at Rs. 8·6 crores, thereby raising the figure to a total expenditure of Rs. 23·7 crores up to the end of the year 1954-55, leaving a balance of Rs. 8 crores approximately for the last year of the Plan. It would thus be seen that this State is fully implementing the Plan even after its expansion by about Rs. 12 crores. (*Cheers*).

[Minister for Finance]

The Plan as it stands naturally could not contain many of the development projects, as the financial resources to meet the expenditure had yet to be fully explored. In a welfare democratic State, and particularly in a State where development activ ties under a foreign rule had been on a stereotyped and less bold a pattern, the demand for a rapid and progressive development can well be appreciated. Simultaneously, therefore, with the development activities under the Plan, certain other development schemes, keeping in view the urgent over-all needs of the State and of certain localities, came to be undertaken. The Planning Commission too had issued a direction to review the position and to provide for the additional items in the Plan itself, so as to ensure integrated development. The additional schemes of development which are being undertaken in 1954-55 have therefore, been examined and most of them have been found to fall within the objectives of the Five-Year Plan. These schemes have thus been treated as additional planning schemes and are to be included in the Plan itself. The House will be glad to know that for the year 1954-55, an additional provision of Rs. 8 5 crores has been made in respect of such schemes as under (*Cheers*) :—

		(*In lakhs of rupees*)
Agriculture	..	80
Irrigation	..	1,48
Industries	..	46
Civil Works	..	2,43
E ectricity	..	49
Transport	..	1,33
Miscellaneous	..	49
Education	..	66
Medical and Public Health	..	13
Other Miscellaneous items, like Land Revenue, Forests, Labour, Veterinary, Co-operation, etc.	..	20
Total	..	8.47

Some of these additional schemes have been sponsored by the Central Government, and expenditure is to be shared by them in prescribed proportions. It is expected that the Centre's share out of the expenditure of Rs. 8 5 crores is likely to amount to Rs. 4 6 crores. The rest of the expenditure is being financed from within the State resources.

It would thus be seen that in the year 1954-55, we have made a provision of over Rs. 17 crores for implementing Planning and Development Schemes. (*Hear hear*) This, of course, does not include expenditure on Bhakra-Nangal and Harike Projects and Relief and Rehabilitation, as these items, though falling in the sphere of this State, form part of the Central Plan.

18. *Bhakra-Nangal Project.* The year 1953 marked the completion of two diversion tunnels in the Bhakra gorge, and these have been designed for a flood discharge of 2,75,000 cusecs. These are the biggest tunnels ever constructed in a difficult strata like that of the Bhakra gorge. In the coming financial year the progress on the Bhakra Dam will be kept up according to the plan. All the roads in hand will be completed; excavations will be carried out on both the left and right abutments and on various subsidiary works, such as Power Plant No. I, and for the spillway apron. The construction of the Dam proper will be taken up after the flood season of 1954, and the diversion of the river will take place early in the coming winter.

The entire system of Bhakra Canal Project is now fast approaching completion. The work consists of remodelling the Rupar Headworks and the Sirhind Canal System, the construction of Bhakra Main Canal and branches along with a vast network of distributaries and minors and the construction of the Bist Doab Canal System. The Bhakra Canal System consists of 290 miles of lined canal and branches, 291 miles of unlined canal and branches, and 2,695 miles of distributaries and minors. I am giving these figures, so that the House can get an idea of the magnitude of this part alone of the Bhakra-Nangal Project. The Bhakra Main Line, a continuation of the Nangal Hydel Canal, is a lined channel 108 miles, and is supposed to be the largest and the longest lined canal in the world. It will be a matter of pleasure as well as pride to all to know that the entire work is expected to be completed by April 1954. The work on the various systems of the Bhakra Canals Project is being completed ahead of the programme. This would naturally result in prosperity coming to the areas served at an early date.

On the Electricity side, the Bhakra-Nangal Power Project envisages the supply of power for general, industrial and irrigation purposes to Punjab, PEPSU, Rajasthan and Delhi. The construction of Power Houses at Ganguwal and Kotla is progressing rapidly. Foundations of these power houses have been laid 68 feet and 91 feet, respectively, below sub-soil water level, and it would be a matter of interest to learn that the machinery for dewatering the foundations came to be manufactured in our own workshops. The Ganguwal Power House is expected to be switched on by the end of July, 1954, while the Power House at Kotla is likely to be completed a year after that.

The estimated expenditure on this Project for the year 1954-55 is likely to be in the order of Rs. 22·78 crores. By the end of 1954-55 the total expenditure on the Bhakra-Nangal Project, inclusive of interest charges is going to be Rs. 1,02 crores and 72 lakhs.

Side by side with the construction of the Dam and the canals, Killabandi and Sidhai line operations have been started in the areas to be served by these canals, so that alignment of watercourses is also done in time. These operations are estimated to cost Rs. 10 lakhs during the next year.

[Minister for Finance]

Similarly, the question of the construction of roads and development of mandis in this area has also not been lost sight of. A sum of Rs. 75 lakhs is being provided in the year 1954-55 for the construction of roads in this area out of a total plan of over Rs. 2 crores. This sum is being obtained as a separate loan from the Centre. The expenditure on the development of mandis in 1954-55 is, however, being financed from the State resources.

19. *Irrigation.* Soon after Partition, the development of Irrigation became a dire necessity as most of our canal systems were to be left in West Punjab. The figures pertaining to development may be of some interest to the House. Whereas in the year 1947-48, irrigated area stood at less than 40 lakh acres, in the current year it is expected to go up to 56 lakh acres, while in the next year it is likely to reach 60 lakh acres. (*Cheers*). These figures, of course, do not take into account the areas likely to be served by Bhakra-Nangal canals which alone will irrigate additional 38 lakh acres. (*Cheers*). Besides, the Jagadhri Tube-well Scheme, consisting of 256 tube-wells and costing about Rs. 1¼ crores is nearing completion, which will convert from flood to perennial irrigation an area of about three-and a-half lakh acres. Attention has not been confined to the canal systems alone. In Kangra, work of repairing the existing *kuhls* and construction of new *kuhls* has been taken up in right earnest, and a Special Kuhls Division has been created (*Hear, hear*) Even in the far off valley of Lahaul one *kuhl* is now under construction. Also under the T.C.A. Programme, work on 355 tube-wells came to be started a year ago, and about 49 wells have been completed so far. It is expected that 201 out of this programme will be completed during 1954. An additional programme of sinking 175 tube-wells in Jullundur, Hoshiarpur and Karnal Districts has also been undertaken under the T.C.A. 1953 agreement.

There are certain tracts in Punjab where need for irrigation has been very pressing, but tube-wells had not been sunk in the past, because of the strata being difficult or uncertain. A programme of trial borings has, therefore, been drawn up, and 46 sites in the State will be selected. The arid areas of Hissar, Rohtak and particularly Gurgaon are receiving special attention, and 31 trial borings will be done therein (*Hear, hear*).

20. *Drainage and Flood Protection Works.* To meet the problem of waterlogging and flooding, particularly in the Canal irrigated areas, and for stopping the spread of Thur, drainage schemes to the tune of Rs. 28 lakhs have been proposed for the coming year. It is expected that the Central Government will give a substantial subsidy, and the villages will also contribute their share. This State is going to contribute towards these schemes a sum of Rs. 7 lakhs, and a provision has accordingly been made.

Flood protection works along the banks of the Ravi are also being undertaken. In the Supplementary Estimates of this year a sum of Rs. 1 lakh is being provided for Narot Jaimal Singh Bund and Rs. 3 lakhs for Ballarwal Area Bunds. Another sum of Rs. 4 lakhs is being provided in the next year for the latter. A sum of Rs. 3 lakhs is being provided for the construction of irrigation-cum-protection bunds in Gurgaon District. (*Cheers*). Similarly, a sum of Rs. 2 lakhs is being provided for the control of *Chos* in Hoshiarpur and the construction of bunds on the right bank of River Jamuna. (*Hear, hear*).

21. *Some Land Problems*. Our efforts to give the tiller of the soil a position of honour and self-reliance continued with determination. The House passed the Punjab Security of Land Tenures Act last year and thus solved the two major problems of a tenant, namely, security of tenure and a fair rent. Ejectments of all kinds came to be stopped up to the 30th April, 1954, after which date alone can a tenant be ejected according to the conditions prescribed in the Act itself. However, under some misapprehension or incorrect understanding of the law a large number of notices were got issued by the landlords. Government have taken steps to lessen the handicaps which a tenant faces when contesting these notices. A notification has been issued by which a tenant has been exempted from the levy of court-fees when contesting his liability to ejectment. (*Hear, hear*). He has also been allowed certified copies of revenue records free of any cost for this purpose. (*Hear, hear*). In addition, efforts are being made to get the suits compromised so as to bring about harmonious relations between the landlords and tenants. I must point out, however, that those who are trying to exploit this situation are doing a great disservice to the country. (*Hear, hear*).

22. *Consolidation*. The pace of consolidation of holdings in the State is being quickened. For the next year a larger provision of Rs. 66.4 lakhs as against Rs. 59·6 lakhs (revised) of 1953-54 is being made. Out of a total area of 1,59 lakh acres to be consolidated in the State a little over 27 lakh acres came to be consolidated by the 31st January, 1954. With the speeding up of the process it is hoped that 20 lakh acres will be consolidated during 1954-55. (*Hear, hear*). At present consolidation operations are on in an area of about 30 lakh acres and 28 lakh acres more will come under operation during the next year. It is hoped that 40 Tehsils will be consolidated by August 1957, and work in the remaining seven will be completed by August 1959 (*Cheers*).

23. *Agriculture*. No country can have a high level of general prosperity without a prosperous agriculture. Agriculture, therefore, received the topmost attention when preparing the development schemes for the State and measures taken in the past are well known to everyone. The efforts made already in improving and enlarging the system of irrigation have been explained to this House. To get perennial benefits, it is necessary that simultaneously with expanded irrigation, greater attention should be paid to the supply of improved seeds and to the adoption of measures for the maintenance and improvement of soil fertility. During Kharif 1953, about 53,000 maunds of cotton seeds came to be distributed by the Agricultural Department, and for 1954 arrangements are being made for supplying an additional 5,000 maunds. Similarly, the distribution of gram, wheat and other seeds is being enlarged. To maintain soil fertility, steps were taken in the first instance to conserve and fully utilize the manure that was available in the village itself. With the increase in the intensity of cultivation it is becoming necessary that chemical fertilizers should also be made use of and as such a scheme was evolved under which the cultivators who were not in a position to buy such fertilizers were supplied the same on taccavi basis. The efforts made in this connection can be judged from the fact that, whereas previously about 5,000 tons of chemical manures were utilized in a year, in the year 1953 between July and December, only 13,000 tons of Ammonium Sulphate and Super-phosphates came to be used (*Cheers*). For

[Minister for Finance]

1954 arrangements for the supply of 29,000 tons are being made. Thus, with the credit facilities afforded, the average cultivator has been able to make use of these chemical manures in securing better yields from his crops and in maintaining soil fertility.

Apart from the sinking of tube-wells under the T.C.A., etc., sinking of wells is being encouraged either through the advancing of loans or by the supply of materials at fair rates. During the Agriculture year 1952-53, 665 percolation wells were sunk with the aid of loans, while 1,193 were sunk by the people after obtaining the essential materials from Government. During the Agriculture year 1953-54, it is anticipated that 1,400 wells will be sunk with the aid of loans and 1,500 otherwise. (*Hear hear*). In addition, 500 pumping sets have been distributed and 400 wells bored by the Agriculture Department. For the year 1954-55 a sum of Rs. 50 lakhs has been provided for advances for sinking of percolation wells, tube-wells and pumping sets. The House will be glad to know that since Partition 1,500 tube-wells have also been sunk by private people either on their own or with the help of Government loans. (*Hear, hear*).

The Japanese method of Paddy cultivation received sufficient impetus and yielded encouraging results. It is anticipated that this method would be used on a very much larger scale, and a target of 1,50,000 acres is being fixed for the next season as against 38,000 acres brought under this system in 1953.

This State has not only tried to become more than self sufficient in foodgrains but has also made a tremendous effort in producing commercial crops, like cotton and sugarcane. (*Cheers*). As cotton-growing areas were left in West Punjab, it was felt necessary that the cultivation of American cotton should be advocated and encouraged. The efforts have yielded remarkable results. Whereas there were less than 40,000 acres under American cotton in 1947-48, there were about 2,80,000 acres in 1953-54. (*Hear, hear*). In terms of rupees, Punjab is now earning an additional sum of over Rs. 3 crores by bringing more land under American cotton particularly of improved varieties—216 F and 320 F. Similarly, in the matter of food production, whereas the State was a deficit State soon after Partition, it will now be in a position to export during 1953-54, 74,000 tons of rice and 28,000 tons of wheat. In view of this improved position, all controls over the prices and distribution of foodgrains, including wheat and rice, have been done away with (*Cheers*).

As a result of the Partition we lost a first class institution in the Agriculture College, Lyallpur which was not only functioning as an educational institution but a research institute as well. At present, the College is located in Ludhiana in a makeshift arrangement. It is now proposed to construct a new building for this College in 1954-55 and a provision of Rs 18·5 lakhs is being made. (*Cheers*). It is hoped that a substantial grant from the Centre would be coming forth. About 500 acres of land have already been reserved for this College.

24. *Community Projects*. In addition to the four projects launched already, four more Community Project Blocks were added in October, 1953, at Kulu, Tarn Taran, Thanesar and Naraingarh at an additional cost of Rs. 60 lakhs. So far over 2,000 villages

having an area of about 9·5 lakhs acres of cultivated land have been covered by them. These Projects were launched primarily with the object of ensuring intensive and all-round development in these areas. The success of these projects can very easily be gauged by the enthusiasm created, the voluntary efforts made and the spirit of self-help shown by the people living in these areas. The value of land given free of cost for roads is estimated at Rs. 36 lakhs ; the earthwork done by them on a voluntary basis in terms of money is equivalent of Rs. 11 lakhs ; the value of land and buildings given for dispensaries and hospitals amounts to Rs. 1·25 lakhs and for schools and other recreation centres to about Rs. 24 lakhs. Cash contributions made by the people amount to Rs. 8·27 lakhs. (*Hear hear*). In all the share of the people comes to Rs. 80 lakhs, and any State can be well proud of the same. (*Cheers*).

25. *National Extension Service Scheme.* According to the directions laid down by the Government of India, one-fourth of the entire population is to be covered by the National Extension Service Scheme during the remaining period of the Five-Year Plan. The entire State is to be covered by 1960-61. In 1953, seven blocks consisting of about 100 villages each came to be taken up around Hansi, Gurgaon, Gohana, Nurpur, Una, Samrala and Moga. Eleven new blocks will be taken up during the year 1954-55 and twelve in the year thereafter. On these blocks, a total expenditure of Rs 2,25 lakhs will be incurred. The work under this scheme has already started, but it is expected that it will gather momentum during the coming year.

26. *Co-operation.* The Co-operative Movement in the Punjab suffered a heavy blow as a result of the Partition, as most of its assets came to be left in Pakistan. Settlement of outstanding claims was pursued with vigour throughout the year with the Punjab (Pakistan) Government. Several meetings took place between the representatives of both the Punjabs, and it is hoped that the claims, etc., would be verified soon, and other details regarding the locked-up money settled.

The set-back received on Partition, however, is disappearing gradually. Co-operative venture in the new field, namely, construction, has progressed satisfactorily, with the result that the number of Labour and Construction Societies has gone up from 60 to 138. The membership has increased to more than 11,000 with a working capital of over Rs. 2 lakhs. Similarly, co-operative irrigation and co-operative farms societies have also expanded. It has also been decided to promote the distribution of fertilizers and agricultural implements through Co-operative Societies. Purchase and Sale Societies have been set up in every district. The progress is visible all round, and is likely to become more rapid with the credit facilities which have been made available by the Reserve Bank of India and the Central and State Governments. The Reserve Bank has already made available a sum of Rs. 59 lakhs, while the Central Government has advanced Rs. 35 lakhs. The Punjab Government invested Rs 10 lakhs towards the Share Capital of the Punjab Provincial Co-operative Bank during the current year, and it is proposed to invest another Rs. 5 lakhs during the coming year. With this improvement in the capital structure there should now be no difficulty in expanding the co-operative movement.

[Minister for Finance]

27. *Education*. Keeping in view the directive contained in the Constitution, this State has been endeavouring for universal primary education. The progress achieved so far is worth mentioning. In 1948, Punjab had 2,821 Primary Schools for boys and 998 for girls. There has been a 50 per cent increase so far as the number of schools goes, while the enrolment has almost doubled. (*Cheers*). About 125 Basic Primary Schools for Boys and Girls have been started and 300 four-year Primary Schools converted into five-year Primary Schools during the current year. Another set of 300 four-year Primary Schools will be converted in the year 1954-55, and in addition to the 1,400 single-teacher Primary Schools started in the current year, another 1,000 single-teacher Primary Schools will be added next year (*Cheers*). The extent of expansion and improvement can be gauged from the fact that in the next year we are going to spend Rs. 48 lakhs on the expansion of primary and basic type education as against Rs. 26 lakhs in the year 1953-54 while over all expenditure on Education during the next year is going to be Rs. 297 lakhs against Rs. 263 lakhs in 1953-54. Considering the progress that the State is making in promoting education, it can be safely forecast that by the end of 1955-56 no Panchayat area will be left without a school. (*Hear, hear*). It will then be time for introducing compulsory education. The task, however, is a huge one, and the expenditure is likely to mount up in the years to come. Without the Centre's aid in future it may well nigh be impossible to maintain these schools.

With the co-operation of the public of the area, it is intended to start a new college at Gurdaspur next year (*Cheers*). People have contributed Rs. 1·25 lakhs in cash, 15 acres in land and four rooms for the college. In addition to the opening of this new college at Gurdaspur. funds have been provided for opening new institutions at Chandigarh, like Nursery School, Hostel for Boys and Girls, Senior Model School, Multi-lateral High School, one for boys and one for girls, Basic Training College, etc. Three Girls' Middle Schools will be started at Sri Hargobindpur, Naraingarh and Una, while four will be raised to the High Standard, namely, at Garli, Palwal, Kaithal and Narangwal (*Hear, hear*). Keeping in view the demand for Hindi and Punjabi teachers, provision is being made for starting a class for the training of teachers in these languages at Chandigarh, along with a Bureau for translation of literary and scientific works from English to Hindi and Punjabi, as well as for the translation of Government forms which are at present being printed in English and Urdu. To afford assistance to private educational institutions, a sum of Rs. 5½ lakhs has been provided for grants to colleges and Rs. 7 lakhs for schools. Another grant of Rs. 2 lakhs has been provided for 30 High Schools, 30 Middle Schools and 40 Primary Schools, in which craft work is to be introduced. A special grant of Rs. 50,000 has been made so as to assist the Child Welfare Council. Rs. 15,000 have been provided for the Guru Nanak Khalsa College for Girls, Sidhwan Khurd, and Rs. 25,000 for the D. A. V. College, Hissar. An additional grant of Rs. 7,000 has been provided for the Vishweswaranand Institute at Hoshiarpur, which is doing useful research work. In order to encourage sports in the State, it has been decided to make a separate provision of Rs. 20,000 for the next year. This will be in addition to the amount of Rs. 10,000 which is being given to the Olympic Association on a recurring basis.

The scheme for the nationalisation of books is progressing satisfactorily. Eighty-four books have already been printed, and put into the market for sale. During the next year the nationalisation scheme will be introduced in respect of books meant for eighth class also. The fundamental idea of bringing down prices within the reach of all sections of the community has almost been achieved, and the House will be glad to know that the prices of text-books have gone down by 30 per cent to 40 per cent (*Cheers*). A further reduction in the price of text-books would be possible as soon as the printing can be undertaken by the Government Printing Press at Chandigarh. At present printing is being got done through private presses.

As a result of the Partition, Punjab University had to start from a scratch. Assets worth over a crore (according to book value) came to be left behind, and if these assets had been divided, our University's share would have been to the extent of Rs. 40 lakhs. We have got to rehabilitate the University in Chandigarh, and Punjab Government is doing all that is possible within its limited resources. Land at a concessional price has been allotted at Chandigarh which has resulted in an indirect contribution of Rs. 15 lakhs. For building offices, etc. a grant of Rs. 5 lakhs was provided in the current year's Budget and Rs. 2 lakhs are proposed to be given in the next year. Necessary provision for this will be made in due course, as it is not included in the Budget Statement—the request having been received late. In addition, a normal grant of Rs. 5 lakhs is being given every year by the State. Without outside assistance it would not be possible for the University to rehabilitate itself, and we earnestly hope that the Centre would come forward with a helping hand, and provide a generous grant.

28. *Health*. Under the National Malaria Control Scheme initiated by the Government of India, intensive anti-malaria operations were commenced in 9 out of the 13 districts of the Punjab, in July 1953. Fourteen lakhs out of 70 lakhs population living in malarial tracts came to be practically protected against this disease. The results achieved in these tracts were very encouraging. In order to extend this benefit to the whole of the State, it has been decided that instead of four Malaria Units there should be the full number, i.e., seven in the coming year (*Hear, hear*). The Government of India is providing medicines and material, which will roughly cost Rs. 8·5 lakhs, while on our part a provision of Rs. 10·9 lakhs has been made for the coming year. It is anticipated that time is not far off when Punjab should be completely free from malaria.

The Solar Eclipse fair is being held in June-July, 1954 and a sum of Rs. 4 lakhs has been provided for making water-supply and medical arrangements. For grants-in-aid to local bodies for water-supply and drainage schemes, Rs. 4 lakhs are being provided in the coming year as against the sum of Rs. 2 lakhs this year. For the manufacture of iodised salts required for the prevention and treatment of goitre, a huge plant will be installed in Kangra District, with the assistance of the World Health Organisation and the Centre. Similarly, to meet the dearth of qualified Lady Health Visitors in the State it has been decided to start a training school for them at Amritsar. The cost will be shared between the Centre and the State.

[Minister for Finance]

The policy of improving the hospitals and dispensaries by bringing them under Government control will be continued in the next year also. Provision has been made for the provincialization of Tehsil Headquarters hospitals at Phillaur, Panipat and Jhajjar. Seventeen rural dispensaries—eight of Jullundur and 9 of Hoshiarpur District—are also being provincialised. Two new rural dispensaries will be opened, in addition, in the Bet areas of Ludhiana District. The District Headquarters hospital at Dharamsala is being modernized, while the hospitals at Rupur, Rohtak and Sonepat are being upgraded. An additional provision of Rs. 2 lakhs has been made for the supply of modern medicines and drugs to hospitals and dispensaries.

Simultaneously with the above, Government has decided to further encourage and improve the Ayurvedic system of medicines. We started 20 Ayurvedic and Unani dispensaries in the rural areas in 1952-53. A provision is now being made for starting 20 more such dispensaries during the next financial year. (*Hear, hear*). Mahant Shreo Nath of the Bohar Math, Rohtak, has offered a palatial building worth about Rs. 3 lakhs for starting an Ayurvedic College. In addition he has promised a sum of Rs. 4 lakhs for making additions to the building and for equipment and furniture. He has also undertaken to provide a sum of Rs. 50,000 every year for recurring expenses. This generous offer has been gratefully accepted by Government, and a provision of Rs. 50,000 has been made in the next year's budget for starting an Ayurvedic College in Rohtak. (*Cheers*). This institution will enable us to have properly-trained Hakims and Vaids, and the public will be saved from quacks. With this extension in the Ayurvedic system of medicines, it has further been decided to create a new post of an Assistant Director, Health Services, who will supervise the working of these Ayurvedic and Unani Dispensaries.

29. *Local Development Schemes*. Local Development Schemes had to be initiated in order to utilize the enthusiasm of the people in undertaking schemes which were for their immediate relief or benefit, and which they were keen to have without delay. These schemes mostly relate to water-supply for drinking, improvement of rural sanitation, buildings for schools and dispensaries, etc. With the assistance of the Centre, we hope to spend about Rs. 8·5 lakhs during the current year. For the next year a very much larger provision of Rs. 25 lakhs has been made for such schemes, and with a corresponding contribution from public/Local Bodies, it will mean that Rs. 50 lakhs will be spent on Local Development Works. Out of this amount, Rs. 10 lakhs (roughly) will be spent on water-supply scheme in the hilly areas of Kangra District (*Hear, hear*) where people have to walk miles in order to get drinking water. Similarly for Gurgaon, another backward district, a sum of Rs 6 lakhs is being earmarked.

30 *Electricity*. Government have been seriously devising ways and means for promoting electrification both in the urban and rural areas, particularly in the latter. The past procedure in respect of giving electric connections has been considerably liberalised, with the result that these connections are now within easy reach of even the poorest cultivator in the village. Another factor which may help in the development of load is the new tariff policy which Government and Bhakra Control Boards have adopted as a result of the report submitted by the Tariff Advisory Committee. The Committee recommended eight types of tariffs to cover

all categories of consumers, and in doing so special care was taken to ensure that new tariffs were attractive to all consumers whether they were utilising electricity for domestic, industrial or agricultural purposes.

For the information of the House, I may state that in 1953, the connected load reached 94,000 Kilowatts, as against 49,000 in 1952. About 300 miles of 11 kV. lines came to be constructed during 1953-54, electrifying 94 villages in the State. It is anticipated that during the next year about 400 miles of 11 kV. lines will be stretched, and 306 more villages will receive electricity for domestic as well as agricultural purposes. (*Cheers*). With the advent of power from Nangal there will be no shortage of energy, and the new tariffs and the rapidly expanding local distribution schemes will enable everyone in the State to enjoy the benefits of electricity. Government is trying to see that cheaper electrical appliances become available, so that stocks of coal and wood in the country are conserved, and the dung manure instead of being consumed in the hearths goes to the fields enriching the lands.

31. *Industries*. The Industries in the State suffered a virtual collapse on account of the effects of Partition, but it is heartening to see that a substantial recovery has been made since then. The pace of progress, particularly of late, has been quite appreciable. In the matter of industrial production it is rather difficult to give exact figures. Roughly speaking, the hosiery industry has an annual production of about Rs. 2 crores; cycle parts Rs. 1.5 crores ; chaff cutters Rs. 2.5 crores and Sports Goods half a crore. Practically all these industries started from a scratch after Partition and the figures now speak for themselves. The number of factories having medium sized power looms for producing art silk fabric is quite large. The new excise duty imposed by the Centre on such fabrics is likely to hit them hard, and I hope that the Central Government will re-examine this question with a view to meeting the demands of this industry.

In the first Five-Year Plan it was agriculture and food production mainly which received the top-most attention. It is now the turn of the industries, so that the development of the State is a balanced one. We on our part are doing everything that we can to attract the industrialists, and the House would be glad to know that the Delhi Cloth and General Mills, Ltd., are going to establish a Textile Mill with 25,000 spindles at Hissar. (*Cheers*). Another concern has also been granted a licence to set up a textile mill with 20,000 spindles. Likewise, the Wool Spinning Industry is also being expanded. While three concerns have already embarked on the expansion of their existing plants, two others are planning. Similarly the Paper Mill at Jagadhri is being expanded at a cost of Rs 1.5 crores. Messrs Wearwell (India) Ltd., propose setting up a new cycle factory with a projected capacity of one lakh bicycles a year. A sugar mill capable of crushing 1,000 tons of cane a day, and a concern for the production of boro-silicate type of glass are also likely to be set up in the State within 1954. Proposals are also under consideration for the establishment of an electric furnace for melting scrap, as well as for setting up a big factory for the production of electrical machinery and equiptment.

In view of the increased production of American cotton the demand for the installation of looms in the State is a very pressing and a genuine one.

[Minister for Finance]
Production of long-staple cotton has gone up already by 300 per cent and will go up further by another 8 lakh bales with the coming into operation of Bhakra irrigation schemes mentioned already. Nangal electric supply will be switched on during 1954 and there will be no dearth of power. There is no shortage of technicians either in the State while a great market for consumption of the materials produced exists within the State itself as *per capita* consumption of cloth is the highest in the Punjab. Besides, in the interest of balanced economy there should be regional dispersal of industrial undertakings in the country particularly keeping in view the natural advantages that exist. We do hope that the Centre would consider the industrial needs of this State, and particularly in this sphere, sympathetically.

To help industry expand, it is necessary that financial aid, technical assistance and facilities for technical training should be there. The Industrial Finance Corporation, which was set up in 1953, and in which Government holds 42 per cent shares, is playing its role adequately. So far loans to the extent of Rs. 23 lakhs have been sanctioned. In view of the difficulties experienced in the money market, the assistance from the Corporation is bound to play a very useful part in the industrial development of the State. In addition, Government will continue to give loans and subsidies to help the smaller industrialists. For the coming year it is proposed to obtain a loan of Rs. 20 lakhs from the Government of India, so as to afford a larger measure of assistance to the smaller industrialist under this scheme. (*Hear, hear*).

Arrangements for technical assistance to private industrialists are being made. An important step in this connection has already been taken. A finishing and testing centre for cycle parts is being established in Ludhiana and machinery and equipment are being purchased. This centre will help in improving the standard of cycle parts, which are being manufactured on a very large scale in this State.

Recently a Ford Foundation Team of international experts toured the State in connection with the setting up of an institute of technology. The need for the establishment of such an institute in Punjab is a very pressing one. The State is backward in the industrial sphere and also has a vast rehabilitation problem to solve. The human material for technical work is excellent and there will be no shortage of power for setting up factories. We earnestly hope that the Central Government will take all these factors into consideration and Punjab would be given an institute of technology. Facilities for technical training in various industrial schools and institutions are, however, being extended. Under the technical education scheme sponsored by the Centre, it is proposed to raise the standard of the Government Technical Institute, Ambala City, to Diploma Standard in Electrical Engineering. This will enable the students to qualify for the grant of Electrical Supervisor Licence. To enable the private institutions to raise their standards of technical education, provision has been made for subsidizing them. The All-India Council for Technical Education have promised to share the expenditure with the State Government, and a sum of Rs. 3 lakhs non-recurring and Rs. 20,000 recurring have been provided to meet the State share in this connection during 1954-55. It is also proposed to set up an Industrial Intelligence Bureau in the State, so as to effectively help the industrialists by supplying them accurate industrial statistics and other connected information.

The cottage and small scale industries have also received due attention. Marketing is the crux of the problem in the development of cottage and small scale industries. To provide marketing facilities it is proposed to open five Sales Depots at important centres in the State, where all standard varieties of goods manufactured in accordance with the given specifications will be displayed for sale. It is also proposed to establish Inspection Depots for the more important industries of small scale character in the State, with a view to extend the quality control, so that the buyers may gain confidence in the products of cottage and small scale industries. Before articles manufactured can be sent to the market, these will be checked and passed by the Inspection Depots. Similarly, for leather, a re tanning and finishing centre is set up in the State, as the leather produced by the village tanners is not fully tanned and cannot, therefore, be used in making high class foot-wear. Sericulture is another important cottage industry in the State which requires immediate expansion, and which can be a source of handsome income to villages in the off-season period. To help develop this industry, it is proposed to establish three new mulberry plantation-cum-demonstration farms in the next year. To encourage utilization of Bamboo a training-cum-production centre for the manufacture of bamboo articles is being established in the next year at a cost of Rs. 32,000.

In order to encourage the development of Khadi and handloom industries a provision of about Rs. 7 lakhs out of our share of the Fund created under Khadi and other Handloom Industries Act. 1953, has been made. Schemes have been formulated in consultation with the All-India Handloom Board so as to provide facilities to weavers in procuring yarn at cheap rates and in marketing their goods.

32. *Labour*. Side by side with the development of industry, it is essential that special attention should be paid towards labour welfare. Without a contented and well-looked after labour no industry in modern times can flourish. There are at present seven welfare Labour Centres functioning in the State which provide facilities to workers and their families for education and recreation. The scheme for the welfare of the Tea Plantation Labour in Kangra District is also being continued during the next year. Stipends are being awarded to the needy and deserving children of workers studying in different institutions. (*Hear hear*).

In view of the scarcity of suitable residential accommodation, State Government with the help of the Centre, is constructing one-room tenements for the industrial workers. Two hundred and forty such houses have already been built and 100 are nearing completion. It is hoped that within the next year 382 more houses will be completed—100 at Jullundur, 124 at Ludhiana, 100 at Jagadhri and 58 at Batala. (*Hear, hear*). These houses will be allotted by a Committee consisting of the representatives of the employers and workers and these Committees have been set up.

Unfortunately, there have been occasions recently when the relations between the industrialists and the labour got strained. Industrial conflicts result not only in loss and inconvenience to the employer and the employees, but are also detrimenttal to the community in general. Here and there industrialists may score a victory in view of their strong position, or the labour may bend the industrialists on account of a strong and

[Minister for Finance]

aggressive Union, but ultimately the outcome of lock-outs or strikes is not conducive to proper development. (*Hear, hear*). As pointed out by the Planning Commission, the employers and the workers relation is to be conceived as a partnership in constructive endeavour to promote the satisfaction and the economic needs of the community in the best possible manner. Our endeavour hitherto has been to bring about conciliation whenever disputes arose between the workers and the industrialists. In cases where due to the intransigency of either or both the parties it was not possible to bring about a settlement a reference was made to the Industrial Tribunal for adjudication. We strive for industrial peace, and it is desirable that it should be maintained at all costs, and especially so in a border State like the Punjab. (*Cheers*). In order to secure speedy adjudication, which will naturally result in better relations between the workers and the employers, Government has set up another three-man Industrial Tribunal with headquarters at Amritsar. It is hoped that the Tribunal will help in restoring harmonious relations between the Industry and the Labour. I take this opportunity to appeal to the Industrialists and the labour to work in unison as they are part and parcel of the same organism. (*Hear, hear*). The State's industry is already functioning under severe handicaps and if it is progressing it is because of the fine human material engaged in it. Any tendencies calculated to disturb the peaceful relations either through less progressive outlook on the part of the employers or the unreasonable demands of the labour may well nigh finish the industry in the State.

33. *Roads*. Roads in this State at the time of Partition were not as much developed as those in the West Punjab, and therefore it became imperative for the State Government to improve the road communications. With the development of Projects like Bhakra and Nangal and the Harike unless the roads were developed, prosperity could not be expected to reach every nook and corner of the State. Keeping all these factors in view, a huge programme of road construction has been drawn up for the State, and a substantial provision has been made for the coming year. We shall be spending more than 2½ crores next year on road construction, Rs. 75 lakhs out of this will go for road development in the area to be irrigated by Bhakra and Nangal Canals while Rs. 47 lakhs will be spent for developing inter-State communications and for opening up hilly and backward areas. (*Cheers*). This sum of Rs. 2½ crores will be in addition to Rs 31 lakhs which have been provided for the construction of roads under the Community Projects. (*Cheers*). This provision of almost 3 crores will result in completion of 110 miles of roads in the Community Project areas and the construction of 31·3 miles of roads outside them. (*Hear, hear*). Details of important roads have been given in the Finance Secretary's Memorandum. It may, however, be mentioned that my colleagues and I when selecting roads, kept the needs of every district in view, particularly the needs of backward districts. (*Cheers*).

In order to encourage self-help and to improve village communications, it is intended to spend Rs. 10 lakhs during 1954-55 for the construction of village roads. One-third of this amount will be contributed by the Centre, one-third by the State and the remaining one-third will be provided by the villagers themselves in the form of free land and labour. With the same object in view provision of another sum of Rs. 10 lakhs has been made for the next year for the construction of *pucca* roads. District Boards and villages will be expected to contribute an equal amount.

34. *Transport.* During the current year the Government transport services were extended mainly on routes linking the New Capital so as to provide facilities to the public travelling to Chandigarh. It is now proposed to operate through bus services linking up Chandigarh with all the district headquarters and important towns. In addition motor rickshaws will be brought on road in Chandigarh Capital for the convenience of local residents and visitors.

In pursuance of a resolution passed by the State Assembly in March, 1950, the nationalisation scheme was postponed for a period of three years. This period has already expired and Government after careful consideration has now decided to pursue further the policy of nationalisation. (*Cheers*). Up-to-date investment in the nationalised transport has been to the extent of Rs. 65 lakhs. A provision of Rs. 50 lakhs is being made for additional investment during 1954-55 as a result of this decision. Forty-two new routes will be taken over and this will involve an addition of 137 vehicles to the existing fleet of 234 buses and 6 trucks. The additional investment of Rs. 50 lakhs is expected to yield a net return of Rs. 11 lakhs during 1954-55. While taking this decision Government has kept in view the claims of the operators and the trade. To avoid dislocation, it has been decided to take over such of the vehicles from the private owners after evaluation as are found to be fit and suitable. The operational staff will also be absorbed as far as possible in order to avoid unemployment and discontent. (*Cheers*). The owners will in addition be paid compensation for goodwill or cessation of bussiness in accordance with the rules unless they agree to their rehabilitation on alternate routes. This further step towards nationalisation is likely to result in the Government road transport becoming compact, more efficient, economical and revenue yielding.

In order to provide transport facilities in response to a large scale demand from the public in the rural and inaccessible areas of the State new and kutcha routes are being opened. About 116 such routes have been approved and the Regional Transport Authorities will be granting permits in accordance with the procedure prescribed under the Motor Vehicles Act. The order of preference in the allotment of permits will be—

(i) Co-operative Societies.

(ii) Private individuals formed into companies, and

(iii) Private individuals.

We have also decided that *Harijans* should be encouraged to form co-operative institutions and for them 19 per cent of the total permits have been reserved. (*Cheers*).

35. *Development Expenditure.* I have briefly given an account of the development activities but to appreciate the pace of development during 1954-55 it is necessary to have a comparative view of the expenditure involved in the three years. Detailed picture is of course given

[Minister for Finance]
in the Finance Secretary's Memorandum but broadly the position of development expenditure in the Revenue Account is as follows :—

(*In lakhs of rupees*)

		Accounts, 1952-53	*Revised,* 1953-54	*Budget,* 1954-55
Consolidation of Holdings	..	43	60	66
Forests	..	47	42	47
Irrigation	..	1,55	2,08	2,37
Scientific Departments	..	1	1	1
Education	..	2,10	2,63	2,97
Medical and Public Health	..	95	1,17	1,34
Agriculture	..	55	52	51
Veterinary	..	26	28	28
Co-operation	..	16	17	17
Industries	..	26	27	56
Roads	..	31	72	1,20
Electricity	..	63	80	1,27
Local Development Works	..	..	9	25
National Extension Service	..	..	4	25
Transport	..	72	78	1,55
Panchayats	..	19	27	31
Community Projects	..	4	61	91
Total	..	8,63	11,46	15,08

On the Capital side the provision of Rs. 31.7 crores for 1954-55 is practically all for development schemes. These figures have surpassed all past records but even then my colleagues and I do not feel satisfied as so much still remains to be done in order to reach the standards of a welfare state. Our objective is to secure an all-round development at a apid pace. People have no doubt given us the necessary co-operation but our limitations have been and still are financial.

Unlike the pre-independence days when most of the expenditure was incurred on the development of the urban areas, the needs of the rural areas have been kept fully in view. (*Cheers*). It is difficult to apportion expenditure with absolute accuracy but it can be roughly stated that after excluding the expenditure on Bhakra-Nangal and the New Capital, development activities for the rural areas will cost the Exchequer Rs. 16 crores as against Rs. 5 crores for the urban areas.

In order to develop the State fully, it is necessary that every district should receive due attention. Hitherto some of the districts particutarly Kangra has been neglected and as such special provisions have been made in the next year's Budget to help this district reach the level of others, (*Voice hear, hear*). Detailed schemes sanctioned for this district will be found in the Finance Secretary's Memorandum but roughly it may be stated that there are 40 development schemes for Kangra alone involving an expenditure of over Rs. 41 lakhs. (*Cheers*). Similarly the needs of Gurgaon—another backward district—have been fully kept in view and necessary provisions therefor made.

36. *Unemployment*. The problem of unemployment either in the shape of total lack of employment or under-employment has always been facing the country. Generally in the rural areas under-employment has invariably been there and it was only during times of famine when rains failed that full-fledged unemployment confronted the people. In the urban areas unemployment is of a different type and has generally been confined to educated classes. These classes have been the outcome of a faulty educational system and have time and again been a problem for the State. Besides being vocal, they have fewer alternatives to fall back upon in times of distress. Of late the problem of unemployment in the urban areas was threatening to become acute with the result that immediate precautions had to be taken. In the matter of retrenchments on account of the winding up of certain Departments, care was taken that retrenchment took place at a staggered pace. Timely notices and terminal leave were given to avoid abrupt dislocations. Efforts were also made for absorbing them in other Departments. To provide immediate relief to the educated unemployment and also to solve the illiteracy problem of the State, a scheme of one teacher school was initiated in 1953 and is now being expanded. The road-building programme in the State is being considerably expanded both in the current year and in the next year, particularly, in the latter, when about Rs. 3 crores will be spent on it. This will also lead to development of transport services providing more employment. Similarly National Extension Service Schemes have been started which will absorb educated people. Intensive efforts are being made to develop the cottage and small scale industries and in order to provide encouragement Government has decided to give preference to the products of such industries for meeting its own requirements. A provision in the next year's budget for the development of *Mandis* in the areas to be irrigated by Bhakra and Nangal Canals has been made and this will provide further employment opportunities. In the rural areas unallotted evacuee lands in the *Bet* areas are being given on long leases to landless displaced tenants including Harijans and so far 4,175 families have been settled. Another 2,000 families are likely to be settled during the next year. Similarly the operation of a Land Utilization Act is also providing employment to large numbers on lands which hitherto had

[Minister for Finance]

remained uncultivated. These are of course the immediate steps that have been taken to mitigate unemployment. As soon as the big Projects like the Bhakra-Nangal, Harike and the Tube-wells start supplying water, employment to another 3 lakh people will become available. Similarly the electricity generated will enable the large scale as well as cottage industries to expand providing more avenues for employment. As stated earlier, big factories are already being attracted to the State to improve the economic conditions. Government in addition is actively considering ways and means by which the population of the State can be usefully and gainfully employed and unrestricted rush into already over-crowded professions regulated. The problem, however, bristles with enormous difficulties in view of the rapid growth in our population.

37. *Scheduled Areas and Backward Classes.* Special measures are being taken to develop the Scheduled areas of Lahaul and Spiti and particularly to improve the living conditions of the people there. Hitherto these people living in the northern-most part of our State had been neglected. The development of communications is the first pre-requisite for the economic uplift of the people in this area. The work for the construction of jeepable roads from Gramphoo to Kunzum Pass and from Khoksar to Zing Zing Bar has, therefore, been started and is making good progress. Development of irrigation, forests, cottage industries and educational facilities is receiving adequate attention.

For the promotion of education amongst the Backward Classes, we have provided the usual sum of Rs. 8 lakhs under the Harijan Welfare Scheme for stipends and fee concessions. Recently some more socially and economically backward castes/sects in the State came to be included among the Backward Classes. For them we have made a separate provision of Rs 1 lakh. (*Cheers*). In order to ensure that Scheduled Castes and other Backward Classes get their due share in Government services, it has been decided to adopt a block system of recruitment which should adequately safeguard their interests. Vacancies reserved for them have also been increased from 19 to 21 per cent. (*Cheers*). To look after the interests of Scheduled Castes and others, the existing organisation has been expanded and improved.

38. *Chandigarh Capital.* In my last Budget Speech I expressed the hope that the nucleus of the Government would move down to Chandigarh by the winter of 1953-54. This hope has been amply realised. Between last March and now almost all the Camp Offices of Government have shifted to Chandigarh, while some of the departments have moved down completely. The only major department which is still functioning in Simla in full strength is the Irrigation Department.

The formal inauguration of the Capital was performed by the President of India on the 7th October 1953. Exactly a month later this town was honoured by the visit of the Prime Minister who laid the foundation stone of the permanent Secretariat. The structural part of the High Court building is almost complete and it is expected that High Court would be functioning here next winter. (*Cheers*). Among other important buildings which have been completed during the year are a Health Centre, a High School, where Government College for Men and

Women is at present housed, and the Officers' Hostel. Other Civil Works, including residential buildings, nearly 2,000 in number, have been completed in all respects. Fifty-six miles of roads, 67 miles of pipelines for the water-works, 35 miles of sewerage, 12 miles of storm water drainage and 36 tube-wells have also been laid. In financial terms, the progress made by the Project is evident from the fact that a total expenditure of Rs. 6,50 lakhs will be incurred by the close of the current financial year. The House is already aware that Chandigarh came to be linked up with the Railway system through a loop-line last month.

For the next year a provision of Rs. 3,43 lakhs has been made for the Capital. The new buildings, which are already in hand, or which are shortly to be taken up, are the main Press building, the M. L. A.s quarters, a Maternity Hospital, two Junior Secondary Schools, a College for men and a College for women. One of the crying needs of Chandigarh has been the provision of accommodation for persons who has come to the Capital in order to provide necessary amenities and services to the population, I mean persons like washermen, barbers, sweepers, petty shop-keepers, etc. A scheme for the construction of 600 cheap houses is being taken up, in order to meet the requirements of persons of this category.

The demand for sites continues to be satisfactory. The total number of residential sites which have been sold so far is a little over 7,000. Sixty-seven industrial sites and 148 commercial sites, including a site for a cinema and a site for a hotel, have also been sold. The total value of sites sold so for works out to nearly Rs. 283 lakhs, and the amount is being recovered by instalments. Private construction has not been very encouraging, but work has started on 68 residential and commercial sites. It is anticipated that with the grant of house building loans to displaced site-holders in Chandigarh, against their verified claims, private construction should receive a fillip.

39. *Relief and Rehabilitation.* In the Finance Secretary's Memorandum, details of Relief and Rehabilitation expenditure have been clearly given. The main items are—

		(In lakhs of rupees)
Loans for displaced persons for constructing houses in Chandigarh and other towns	..	65
Industrial Rehabilitation loans	..	8
Grants to displaced students	..	16
Development of sites and plots	..	20
Water-supply and drainage facilities in New Townships		17
Shopping Centres and Mandis	..	5
8-Marla Cheap Housing Schemes	..	4

[Minister for Finance]

In addition to these items there is another scheme of providing cheap tenements to lower income groups of displaced persons at different places. 2,200 such tenements are under construction while steps for the construction of additional 3,000 tenements are being taken. It is hoped that all these will be ready by June, 1954. (*Hear, hear*). Nearly 19,000 mud-huts have also been transferred permanently to their occupants at concessional rates.

On the rural rehabilitation side the work of allotment of lands has now been almost completed. As already mentioned there was some evacuee waste land mostly in *Bet* areas and this is being utilized for settling landless displaced tenants particularly Harijans. The House would be glad to know that almost 41,400 acres have already been leased out under this scheme to about 4,175 landless tenants thereby rehabilitating them on land. 819 Harijans have also got their share out of it and they have received 8,861 acres on long leases. (*Cheers*). In the near future more land will be leased out providing employment to an additional 2,000 families.

On the relief side expenditure mainly relates to Women Homes and Infirmaries. Medical and Sanitation staff in the Mudhut Colonies is being maintained in the next year also.

The finalization of the scheme by the Government of India for payment in lieu of the property left in Pakistan is most eagerly awaited by the Displaced Persons. It is, however, a matter for some satisfaction that a scheme for interim payment for certain categories of Displaced Persons is now being enforced. Everyone is aware of the hardships that Displaced Persons are facing particularly now when most of them have exhausted their resources but it is earnestly hoped that early steps will be taken to compensate them for the immovable property lost in Pakistan.

40. *National Cadet Corps*. The National Cadet Corps has been in existence for about five years now, and is serving a very useful purpose not only in the bigger towns, but also in the smaller localities. It has helped in infusing a sense of patriotism and civic responsibility, and has partially met the demand of the people for military training. The organisation, at present, consists of ten units of 2,920 cadets commanded by 73 officers in the Senior Division, one troop of 90 cadets commanded by three officers in the Girls Division, and 162 troops of 5,346 cadets commanded by 162 officers in the Junior Division. An Air Wing has also been recently added. An innovation has recently been made by including social service as part of the training during the annual camps. A camp was organised last year at Rupar, and was attended by 444 cadets. These cadets were given an assignment of 3,000 feet of the Sirhind Canal for purposes of widening by 18 feet. The House would be glad to know that the Cadets displayed so much enthusiasm, and took up the work with such great zest that by the time the Camp concluded, they overshot the target by another 1,500 feet. In the coming year, it is intended to raise another Technical Unit, i.e. an Engineering Company, which will be attached to the Engineering College at Chandigarh. There is a persistent demand for the allotment of more and more N.C.C. Units to schools and colleges, particularly in the border areas of the State, but unfortunately we are not in a position to spend more. We earnestly hope that, keeping in view the location of this State, the Centre would extend a helping hand so as to meet this pressing demand from the martial people of the State.

41. *National Workers Relief Fund.* The National Workers' Relief Fund was started in 1951-52 and since then we have made contributions totalling Rs. 2,80,000. At present there are 90 political sufferers who are in receipt of pensions, while 800 applications from political sufferers are pending. It has been decided to make a recurring grant of Rs. 3 lakhs per annum from the year 1954-55 (*Cheers*). In addition to this financial assistance, 4,000 acres of land have been reserved for allotment to them.

42. *Assistance to Low-paid Employees.* Since we took over in 1952 several steps have been taken to improve the lot of the low-paid employees in the State. In the first year, we decided on the payment of an increased dearness allowance at the rate of Rs. 5 per mensem to employees whose salary was up to Rs. 100 per mensem. We also revised the scale of pay of Overseers by introducing a new grade, with a higher minimum and maximum. Similarly, the starting salary of First Class M.Sc who were employed as Lecturers in the Government Colleges was raised from Rs. 150 to Rs. 200 per mensem. In 1953, the posts of Road Inspectors and certain other categories paid from contingencies were created on a regular permanent establishment, so as to afford them the privileges enjoyed by permanent employees. We also introduced improved scales of pay where the basic pay of the low-paid Government servants was less than Rs. 50 per mensem. Those starting with a basic pay of less than Rs. 30 per mensem came to have an increase of Rs. 5 at either end of the scale, while the scales which were above Rs 30 and below Rs. 50 per mensem came to be augmented by Rs. 7½ per mensem at either ends. The scale pay of Local Body teachers was also improved. I am now glad to announce further improvements in the pay scales of low-paid employees. The employees on regular establishment as have scales with a starting salary of Rs. 40½ per mensem, or below, will be given a further increase of Rs. 2 per mensem at either end of the scale. (*Cheers*). This would mean a benefit of Rs. 2 per mensem to all such persons with effect from the pay for the month of April, 1954. In addition practically all the work-charged categories of the regular establishments will be brought on a permanent footing with effect from the next year. (*Hear, hear*). This would confer on them such of the benefits regarding pension, leave, security of service, etc. as have been available to permanent employees.

The College Lecturers have been representing for the improvement of their lot. In view of the recommendations made by the University Commission and in order to attract the best talent available for the teaching profession it has been decided to revise the scales of pay of the Lecturers. The present scale of Rs 150—10—190/10—350 will be raised to Rs. 180—10—320/16—400, with effect from the 1st April 1954. (*Cheers*). While fixing the pay of the existing incumbents in the new scale, everyone will be given three increments, excluding of course, those who had already received advance increments, like the First Class M A.s and M.Sc.s. The question of revision of the scale pay of B.A.B.T., Teachers and Teachresses has also been considered, and it has been decided to raise the present scale of Rs. 90—5—150 to Rs. 110—8—190/10—250. (*Cheers*). All B.A.B.T. and M A B T.s will be given four advance increments in their existing scale with effect from the 1st April, 1954, and will then be allowed to enter the new scale according to rules.

The case of Stock Assistants of the Veterinary Department has also been a very deserving one. They and the Veterinary Compounders used to be in an almost identical scale. While the pay scales of compounders came to be revised substantially they were left behind. It has now been decided to raise their pay scale of Rs. 37½—1—47½/2—67½ to the same level as that of the compounders, viz Rs. 50—3—70/4—90/5—120. (*Cheers*).

During 1953, medical facilities available to higher-paid Government servants came to be extended to employees whose pay was less than Rs. 150 per mensem. Government has decided to continue this concession. (*Hear, hear*).

All the concessions enumerated above are likely to involve an extra expenditure of more than Rs. 20 lakhs, and, in due course, the pensionary liabilities will raise the expenditure to a considerably higher figure. This amount has been included in the Budget before you, and has been shown in the major head of account on a rough basis as 'Add Lump Provision'.

43. *Resources to Finance Deficit* The deficit in the Revenue Account as indicated already is Rs. 93 lakhs. The figure will now go up to 95 lakhs as Rs. 2 lakhs additional are being provided for the Punjab University. This deficit has, however, been obtained after effecting economies. We have made efforts to effect savings as far as possible by examining the budgetary demands of the various departments and have reduced provisions for T.A. and Contingencies of some of them. The total economy effected thus is to the tune of Rs. 31 lakhs and this has been shown in the major heads concerned. This, however, does not satisfy us and with a view to effect further economy, we have decided to depute a special officer to look into the working of major departments so as to go deep into details with a view to explore the directions in which economy can be effected. In the search for economy we have to draw a distinction between false and true economy, between spending less and spending wisely. Public expenditure would be a waste if it were reduced below the efficiency level. We will, therefore, welcome co-operation and suggestions from all quarters in this matter as it is our sincere desire to effect economy and prevent wasteful expenditure.

We have no balances which we can fall back upon nor have we any reserves which can be diverted to cover up the anticipated deficit. Capital expenditure has since partition been financed from loans from the Centre and where loans could not be secured for development schemes, the expenditure had been met from State resources. This has exhausted almost all our balances in the Debt and Deposit Accounts. We have, therefore, to look to other directions.

We have considered this problem very carefully but feel that present is not the appropriate time for embarking on any new major taxation measures. A Taxation Enquiry Commission under the able Chairmanship of Dr. John Mathai is going round the country to examine the taxation structure. The Commission visited this State recently and examined the taxation problems at length. It will no doubt throw light on the possible sources of revenue still untapped and the tax capacity of different income groups falling in rural and urban areas in the country. Its recommendations may also bring in the needed rationalisation of taxation

which would result in the more even distribution of tax burdens. We are, therefore, inclined to await their recommendations before we can think of any major taxation proposal. All this will take time while our needs for more funds are immediate. After considering this matter carefully, we have come to the conclusion that there is scope for increasing Revenue in the directions which I will mention presently.

According to our present law, settlements of lands take place after every 40 years. In all our districts, settlements are long overdue except in Amritsar and Gurgaon. As trained staff was not available on account of the heavy rush of work connected with the rehabilitation of displaced persons and the consolidation of holdings, the settlements could not take place as they became due. We, now propose to go ahead with them without delay. The land revenue records are being revised through the process of consolidation and as such the new settlements should not take the time that these normally used to take. In order to curtail expenditure on these operations a rough and ready but equitable method would be evolved and it is expected that receipts from Land Revenue will increase by Rs. 30 lakhs.

Another source which we would like to tackle is the Motor Vehicles Tax. We have examined the position and find that the rates of taxes on motor vehicles plying in this State are very low as compared with other States. For instance, stage carriage vehicles in Punjab are at present paying a Motor Tax of Rs. 50 per annum for a vehicle having 18 to 20 seating capacity rising by Rs. 6 for each extra seat up to 32. Compared with other States this rate is ridiculously low. The tax in Bihar for similar vehicles ranges from Rs. 402-8-0 to Rs. 932-8-0, in Madhya Pradesh from Rs. 432 to Rs. 950, in Madras and Travancore from Rs. 2,160 to Rs. 3,840 and so on. In the case of vehicles having larger seating capacity than 32, the existing rate of tax in this State is Rs. 700, whereas in Bihar, it ranges from Rs. 977-8-0 to Rs. 1,292-8-0, in Madhya Pradesh from Rs. 1,000 to Rs. 1,350, in Madras and Travancore from Rs. 3,960 to Rs. 4,800. It is also felt that this flat rate of Rs. 700 for vehicles with seating capacity above 32 is not a rational one. We, therefore, propose to revise these rates in a rational way and to the extent that these remain within the paying capacity of the people concerned. The revised rates in respect of these and other vehicles which are being introduced from 1st April next will still be below those levied by most of the other States. This revision, it is expected, will bring an extra revenue of Rs. 12 lakhs round.

Yet there is another minor source which we propose to tap. The entertainment tax is not borne by the cinema proprietors but by the cinema-goers although they are reaping large profits through the cinema craze. We, therefore, propose to levy a Show Tax on the Madras model. We except an annual revenue of Rs. 5 lakhs from this source.

We can thus assume an extra revenue of Rs. 47 lakhs from these sources. There is yet another source which has not been taken into account and this source relates to Estates Duty and our share thereof. We made no provision for this in the Budget as no indications of the proceeds were available. Since the Budget proposals of the Government of India for 1954-55 provide receipts from this source, we can assume that on the basis of the figures indicated, our share will amount approximately to Rs. 14 lakhs. Our total extra revenue will thus amount to Rs 61 lakhs. This will mean a reduction in the deficit from Rs. 95 lakhs to Rs. 34 lakhs. This deficit I propose to leave uncovered.

[Minister for Finance]

44, *Conclusion*. I have given you a brief account of our financial position and a fairly detailed account of our development activities. Members must have particularly noticed the large expenditure which we are proposing to incur during the next year on development activities. This is inescapable if we have to raise the standard of living of our people and if we have to reduce unemployment. Members must have noticed the small figure of deficit that has been left uncovered and the new measures to expand the revenues. The deficit is much too small to be taken notice of. It is rather an indication of the all-out efforts that have been and are being made within our financial resources to develop the economy of the State. No progress is possible without adequate funds and as a matter of fact the people of the State should be prepared to come forward to contribute to the State resources through taxes and through voluntary labour. We are conscious of the fact that contributions are being made and we are grateful for the same but efforts on a much larger scale are needed if we have to fulfil the objectives that we have set before us.

I also feel it my duty to apprise the House of the Debt liability which perforce we are incurring in order to rapidly develop the State. At the end of the current year this liability will stand at about Rs. 1,08 crores. With the contemplated loans the liability will go up to Rs. 1,38 crores by the end of the next year. This increase in our liability should not cause any nervousness as it is mostly for productive purposes. Given a few years of peace and stability the hard-working Punjabis are sure to march forward and reconstruct and improve the economy of the State. (*Cheers*).

I must also point out the slow but sure and visible change that is taking place in the administrative set-up of the State. Instead of being a law and order State as in the days gone by, our State is definitely becoming a Development State. (*Cheers*). In spite of the fact that we had to provide more money for the year 1954-55 on account of the reorganization of the District Administration, the purchase of new vehicles for the Police Department and the move-down of the High Court from Simla to Chandigarh, as well as for the increase in the pay of low-paid employees in order to better their lot, our over-all expenditure on Civil Administration is gradually coming down. (*Hear, hear*). In 1951-52 the expenditure on Civil Administration including Jails and Police was 31 per cent of the total revenue expenditure, in the current year this percentage came down to 27, but in the next year, the House will be glad to know that it will come down still further to 23 per cent. (*Cheers*).

45. *Acknowledgements*. I would like, in the end, to acknowledge before the House my appreciation of the work done by the officers and men of the Finance Department. All of them performed the highly responsible and onerous duties placed on their shoulders willingly and zealously. (*Cheers*). The burdens on them are indeed on the increase on account of the unprecedented expansion in expenditure on development projects. During the course of the year, Shri E. N. Mangat Rai left the Department after piloting it successfully for 3 years. I must express my gratitude to him and record my appreciation of the ability and industry shown by him in shouldering the burdens at a crucial period.

I also wish to record the appreciation of this Government to the Accountant-General and his staff who share with us the burden of watching the financial interest of the State and who gave us valuable help.

And now, Sir, I request your leave to present the Budget, 1954-55.

JAI HIND

The Assembly then adjourned till 2 *p.m. on Friday, the* 12*th March* 1954.

108 PSLA—286—3-7-54—CP and S, Punjab, Chandigarh

Punjab Legislative Assembly Debates

12th March 1954.

Vol. I—No. 5

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday, 12th March 1954.

(*Evening Session*)

P.T.O.

CHANDIGARH :

Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab, 1954

PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY

Friday, 12th March 1954.

The Assembly met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital at 2 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Dr Satyapal) in the Chair.

QUESTION HOUR (DISPENSED WITH)

अध्यक्ष महोदय : मेम्बर साहिबान की ख्वाहिश के अनुसार, क्योंकि आज वह बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं, Question hour dispense with किया जाता है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या आज वाले questions अगले सोमवार को House में take up किये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

SITTING OF THE ASSEMBLY

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to move—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned till 2.0 p.m. on Monday, the 15th March, 1954.

Mr. Speaker: Motion moved—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned till 2.0 p.m. on Monday, the 15th March, 1954.

Mr. Speaker: Question is—

> That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned till 2.0 p.m. on Monday, the 15th March, 1954.

The motion was carried.

SUPPLEMENTARY ESTIMATES (SECOND INSTALMENT), 1953-54

अध्यक्ष महोदय: अगर कोई साहिब charged expenditure के estimates पर तकरीर फ़रमाना चाहें तो वह कर सकते हैं ।

(*No member rose to speak*).

Mr. Speaker : The House will now proceed with the next item on the Agenda, viz., voting of the demands for supplementary grants.

STATE EXCISE DUTIES

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to move—

> That a supplementary sum not exceeding Rs. 65,110 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 8—State Excise Duties.

Mr. Speaker: Motion moved—

> That a supplementary sum not exceeding Rs. 65,110 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March 1954, in respect of 8—State Excise Duties.

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 65,110 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 8—State Excise Duties.

The motion was carried.

STAMPS

Minister for Finance(Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,150 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 9—Stamps.

Mr. Speaker: Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,150 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 9—Stamps.

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,150 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 9—Stamps.

The motion was carried.

REGISTRATION

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,350 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 11—Registration.

Mr. Speaker: Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,350 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 11—Registration.

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,350 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 11—Registration.

The motion was carried.

OTHER TAXES AND DUTIES

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 25,640 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 13—Other Taxes and Duties.

Mr. Speaker: Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 25,640 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 13—Other Taxes and Duties.

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 25,640 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 13—Other Taxes and Duties.

The motion was carried.

IRRIGATION (WORKS)

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not excceeding Rs. 10,89,120 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of Irrigation (Works)

Mr. Speaker: Motion moved—

That a Supplementary sum not exceeding Rs. 10,89,120 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of Irrigation (Works).

Shri Ram Kishan (Jullundur, North-West): Sir, I beg to move—

That the demand be reduced by Rs. 100 .

स्पीकर साहिब ! इस demand के मुताबिक 10,89,120 रुपये लिये जा रहे हैं। इस मांग में बिस्त दोग्राब कैनाल (Bist Doab Canal) का भी जिक्र है। बिस्त दोग्राब कैनाल के ग्राने से दुग्राबे के लोगों की कई सालों की मांग को पूरा किया जा रहा है। इस नहर से वहां के लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। परन्तु इस नहर के बारे में मैं एक ग्रौर जरूरी बात की ग्रोर वजारत की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं। जालन्धर का ज़िला एक small holdings का जिला है। इस बिस्त दुग्राब नहर से वहां की 5 लाख एकड़ जमीन सैराब होगी। इस नहर से लोगों को एक बड़ी मुश्किल जो पेश ग्रायेगी, वह यह है कि main canal पर ग्रौर minor distributories पर जो पुल बनाये जा रहे हैं वह ग्रढाई २ ग्रौर तीन तीन मील के फ़ासले पर बनाये जा रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि यह पुल उसी ख्याल से इतने फ़ासले पर बनाये जा रहे हैं जिस ख्याल से पश्चिमी पंजाब में नीली बार ग्रौर सांदल बार में नहरों पर बनाये गये थे। जब वहां पर नहरें निकाली गई थीं तो वहां कोई मंडियां ग्रौर देहात नहीं थे। इसलिये शायद वहां तीन २ चार २ मील के फ़ासले पर पुल बनाये गये थे। परन्तु इस के उलट जालन्धर के ज़िले में थोड़ी २ दूरी पर शहर ग्रौर देहात बने हुए हैं। लेकिन इस के बावजूद पुल पिछले system पर ही बनाए जा रहे हैं। मैं ग्रर्ज़ कर दूं कि यही नहीं बल्कि इस ज़िले में एक एक ग्रौर ग्राध ग्राध मील के फ़ासले पर गांव हैं। जिस तरह से ग्रब पुल तामीर किये जा रहे हैं इस से जमींदारों को काफी तकलीफ़ होगी। मिसाल के तौर पर एक जमींदार की holding तीन-चार एकड़ है, वह नहर की वजह से दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, ग्राधी नहर के एक तरफ ग्रौर ग्राधी दूसरी तरफ चली जाती है। ग्रब दूर २ पुल होने के कारण उस जमींदार को ग्रपनी ग्राधी जमीन को काश्त करने के लिये कोई ग्रढ़ाई मील का चक्कर काट कर वहां जाना पड़ेगा। इसलिये, स्पीकर साहिब, ग्राप के द्वारा मैं वजारत का ध्यान इस बात की ग्रोर दिलाना चाहता हूं कि जहां उन्होंने जालन्धर के ज़िले के लोगों की मांग को

[Shri Ram Kishan]

स्वीकार करके यह नहर बनाई है जिस से न केवल उन को फ़ायदा होगा बल्कि सरकार को भी एक लाख टन अनाज ज्यादा मिलेगा, वहां उन की यह पुलों की मुश्किल को भी दूर किया जाये। जालन्धर की Public Relations Committee और Grow More Food Committee ने भी दो चार प्रस्ताव इस सिलसिले में पास करके सरकार को भेजे हैं और ज़मींदारों की मुश्किल को हल करने और जायज़ मांग को पूरा करने को कहा है।

स्पीकर साहिब! इस सिलसिले में मैं भी मंत्री मंडल का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ज़िला जालन्धर में, जहां पर बिस्त दोआब नहर का ताल्लुक है आबादी ज्यादा होने के कारण पुल एक २ या आधा मील के फ़ासले पर बनायें जायें। क्योंकि लोगों ने पशुओं आदि को ले जाना होता है तो पुल बहुत दूर होने के कारण उन को भारी कष्ट होता है।

अध्यक्ष महोदय! दूसरी मांग यह है कि पिछले दो सालों में सरकार ने जो ज़मीन लोगों से acquire की है उस का जो मुआवज़ा ज़मीन या cash की शक्ल में दिया जाना था, वह अभी तक नहीं दिया गया। इसलिए मैं आशा रखता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर तवज्जुह देंगे और लोगों की इन आवश्यक मांगों को शीघ्र ही पूरा करेंगे।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the demand be reduced by Rs. 100.

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਕੇਨਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਕੇਨਾਲਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਖੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (Bhakra Control Board) ਨੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪਾਲਿਸੀ (policy) ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਯੂਟਰੀਆਂ ਉਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਮੀਲ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਉਪਰ ਪੁਲ ਬਣਾਇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਜ਼ਿਲਾ ਜਾਲੰਧਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲ ਬਨਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਖਰਚ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖਰਚ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗਹ ਉਪਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅੱਧ ਪੁਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਜਗਹ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਇਕ ਅੱਧ ਪੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਨ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਜਾਲੰਧਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬਿਸਤ ਦਵਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ departure ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲ ਜਿੰਨੇ ਨੇੜੇ

ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਹਾਂ, ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਹੋਰ ਪੁਲ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਆਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

श्री राम किशन : वे लोग आधा खर्च बरदाश्त करने के लिये तैयार हैं ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ । ਫੇਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਅੱਧੇ ਪੁਲ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

Mr. Speaker: Question is—

That the demand be reduced by Rs 100 .

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10,89,120 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of Irrigation (Works).

The motion was carried.

OBSERVATIONS MADE BY THE SPEAKER

अध्यक्ष महोदय : मैं मैम्बर साहिबान की खिदमत में गुज़ारिश करना चाहता हूं कि Supplementary demands के समय सरकार की general policy पर बहस नहीं हो सकती। जो साहिबान demand या किसी cut motion पर कुछ फरमाना चाहें तो वही relevant समझा जायगा । बाकी जो साहिबान general policy discuss करना चाहते हैं, वे बजट की discussion के समय कर सकते हैं ।

ADMINISTRATION OF JUSTICE

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not excceeding Rs. 59,450 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 27—Administration of Justice.

Mr. Speaker: Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 59,450 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 27—Administration of Justice.

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 59,450 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 27—Administration of Justice.

The motion was carried.

POLICE

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to move—

> That a supplementary sum not exceeding Rs. 11,84,130 be granted to the Governcr to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 29—Police.

Mr. Speaker: Motion moved—

> That a supplementary sum not exceeding Rs. 11,84,130 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 29—Police.

Mr. Speaker: Question is—

> That a supplementary sum not exceeding Rs. 11,84,130 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 29—Police.

The motion was carried.

CIVIL WORKS

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to move—

> That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,17,420 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 50—Civil Works.

Mr. Speaker: Motion moved—

> That a supplementary sum not exceeding Rs 3,17,420 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 50—Civil Works.

Shri Ram Chandra Comrade (Nurpur): Sir, I beg to move—

> That the demand be omitted.

अध्यक्ष महोदय! यह कट मोशन (cut motion) पेश करने की वजह है कि अरसा सात साल से तहसील नूरपुर के लोगों की तरफ से हकूमत के नोटिस में बारहा बार लाया गया है कि उस इलाका की काफ़ी ज़मीन दरया बियास बहा कर ले गया है। जब डाक्टर गोपी चंद भार्गव वज़ीरे आज़म थे उस वक्त से हकूमत इस बारे में research करा रही है। सरकार को कई बार महकमाना रिपोर्टें (reports) भी भेजी गई हैं। लेकिन अभी तक कोई उपाय लोगों की तकलीफ़ को दूर करने के लिये नहीं किया गया। इस लिये मैं आप के द्वारा मंत्री महोदय की तवज्जुह इस ओर दिलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस तरफ कोई कदम उठाया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved—

> That the demand be omitted.

Mr. Speaker: Question is—

> That the demand be omitted.

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,17,420 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 50—Civil Works.

The motion was carried.

ELECTRICITY SCHEMES—WORKING EXPENSES

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 13,25,200 be granted to the Governor to defray the the charges that will come in course of payment for year ending 31st March, 1954, in respect of XLI—Electricity Schemes—Working Expenses.

Mr. Speaker: Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 13,25,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of XLI—Electricity Schemes—Working Expenses.

Shri Ram Kishan (Jullundur, North-West): Sir, I beg to move—

That the demand be reduced by Rs. 100.

स्पीकर साहिब ! बिजली की स्कीमों के लिये सपलीमैण्ट्री ऐस्टीमेट्स (Supplementary Estimates) में जो डीमांड (demand) पेश की जा रही है उस सिलसिले में आप की वसातत से मैं मंत्रिमंडल का ध्यान दो चार जरूरी बातों की ओर दिलाना चाहता हूं।

स्पीकर साहिब ! इस डीमांड में जालन्धर छावनी, जालन्ध नगर, माडल टाऊन, जालन्धर ईस्ट, मकसूदपुर जालन्धर बस्तियों वगैरा की ईलैक्ट्रिसिटी स्कीमों (Electricity Schemes,) के लिये रुपये का प्रबन्ध किया गया है। इस सम्बन्ध में स्पीकर साहब, तीन साढ़े तीन साल हुए जब कि जालन्धर इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को पंजाब सरकार ने अपने हाथ में लिया था। लेकिन पिछले तीन सालों से जब से यह पंजाब गवर्नमेंट के कब्जों में आई है, इस की वर्किंग (Working) से पता चलता है कि हर आठवें या पंद्रहवें दिन रात के वक्त जालन्धर में अंधेरा छा जाता है। स्पीकर साहब, आप को यह बात सुन कर हैरानगी होगी कि जब पिछले दिनों दीवाली के त्यौहार पर सारा हिन्दुस्तान दीवाली मना रहा था तो इस इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की defective working की वजह से सारे जालन्धर शहर और मंडी फेन्टनगंज के trade centre में अंधेरा छाया हुआ था। स्पीकर साहिब, अगर मैं ग़लती नहीं करता तो पिछले चार महीनों में आठ या दस दफा सारी की सारी बिजली जालन्धर में फेल (fail) रही। यहां तक कि हर इतवार को वहां पर बिजली बन्द कर दी जाती है जिस से industrial concerns को बड़ा भारी नुकसान होता है; उन की सारी business dislocate हो जाती है ! पहले तो, इस सम्बन्ध में यह कहा जाता था कि load बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसी लिये यह defects पैदा हो जाते हैं। इस कमी को और इस नुक्स को दूर करने के लिये गवर्नमैण्ट ट्रांसफारमर्ज़ (Transformers) मंगवा रही है। जब ट्रांसफ़ारमर्ज़ आ गये तो कहा गया कि उन को instal करने

[Shri Ram Kishan]

के लिये जापानी experts मंगवाये जा रहे हैं। लेकिन बावजूद ट्रांसफ़ारमर्ज़ और उन जापानी experts के आ जाने से मुझे बड़े अफ़सोस के साथ नोटिस में यह बात लानी पड़ी है कि जालन्धर में हर इतवार को आठ-आठ, नौ-नौ घंटे बिजली फ़ेल रहती है। पिछले चार महीनों में ऐसे २ मौके भी आए जब कि सारे शहर में अंधेरा ही अंधेरा रहा। तीन मौके ऐसे आये जब कि बिजली के न मिलने की वजह से सिनेमा घर तक बन्द रहे और चार मौके ऐसे आये जब कि Industrial sphere में कोई काम न हो सका। इस लिये, स्पीकर साहिब, आप की वसातत से मैं पंजाब गवर्नमैण्ट का ध्यान जालन्धर की ईलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की ओर दिलाना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि वह इस में रोज़-ब-रोज़ पैदा होने वाले नुक्सों को दूर करने की कोशिश करेगी।

दूसरी चीज़ जिस की तरफ, मैं पंजाब गवर्नमैण्ट का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है बिजली के रेट्स (rates) के मुताल्लिक। पिछले management के मुक़ाबिले में पंजाब सरकार ने पिछले दो महीनों से बिजली की शरह बढ़ा दी है। इन नए नए रेट्स के खिलाफ सारे पंजाब के अन्दर एक बड़ा जबरदस्त protest हो रहा है। पंजाब की तमाम अखबारात ने इस के खिलाफ प्रोटैस्ट (protest) किया—पंजाब के उद्योगपतियों ने इन नये रेट्स के खिलाफ अपनी protest की आवाज़ उठाई। आखिर, स्पीकर साहिब, नए रेट्स में वह कौन सी खास बात है जिस के खिलाफ ये प्रोटैस्ट किये जा रहे हैं? पहिले मैं घरेलू ज़रूरतों के लिये खर्च की गई बिजली की ताकत के सवाल को लेता हूं। इस से पहले कानून के मुताबिक उन लोगों को तीन या चार आने प्रति यूनिट के हिसाब से अपना बिजली का बिल देना पड़ता था। लेकिन नए कानून के मुताबिक यह procedure लागू किया गया है कि चाहे कोई बिजली consume करे या नहीं, हरेक consumer को दो रुपये आठ आने महीना तो ज़रूर ही देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ Industrial working की है। पहले तो यह तरीका था कि जितने हार्स पावर (horse power) की motor मोटर हो और उस के मुताबिक जितनी बिजली खर्च होती हो उसी के हिसाब में उस industrialist को खर्च अदा करना पड़ता था। लेकिन अब यह कर दिया गया है कि तीन रुपये फ़ी हार्स पावर के हिसाब से उसे ज़रूर charge किया जायगा। इस तरह से एक आदमी जिस के पास १० हार्स पावर की मोटर है उसे ३० रुपये तो हर हालत में देने ही होंगे। चाहे वह कोई यूनिट खर्च करे या न करे। इस नये फ्लैट रेट (Flat rate) के खिलाफ़ बटाला, अमृतसर, अम्बाला और जालन्धर सभी शहरों के industrialists ने बड़ा जबरदस्त protest किया है। स्पीकर साहिब, पहले तो यह ख्याल था कि चूंकि "ऊहल प्राजैक्ट" (Uhl Project) से बिजली आती थी उस से तो सन् १९५४ तक घाटा ही होता रहा। लेकिन अब जो हमारे पास facts and figures हैं उन से और पंजाब गवर्नमैंट ने फ़ाईनैंस कमिशन (Finance Commission) को जो मीमोरैण्डम (memorandum) पेश किया था उस से पता चलता है कि अब तो हालत कुछ और ही है। मीमोरैण्डम में लिखा है—

"The net revenues of the old scheme after meeting interest charges during the year 1949-50 and 1950-51 were Rs. 31,10,726 and 48, 15,585, respectively."

इस के बाद depreciation reserve fund 21,19,490 रुपये है । लेकिन इस के बावजूद अगरचि बिजली सस्ती होनी चाहिये—domestic और industrial दोनों purposes के लिये—उसे और भी महंगा कर दिया गया है । इन हालात में, स्पीकर साहिब, मैं बड़े अदब से आप की वसातत से माननीय मनिस्टर साहिब से अ र्ज़ करना चाहता हूं कि इन रेट्स (rates) को revise किया जाय ताकि industrialists and domestic consumers यह महसूस करने लगें कि बिजली सस्ती मिलनी शुरु हो गई है ।

इस के इलावा, स्पीकर साहिब, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जालन्धर डिस्ट्रिक्ट और इस के आस पास के ईलाकों में लोगों ने राष्ट्रीय विकास (national development) के काम में एक बड़ा अहम पार्ट अदा किया है । लेकिन बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है कि वहां के बिजली डिपार्टमैण्ट का working इतना खराब है कि लोगों की दरख्वास्तों पर फ़ैसला होने में दो दो साल अढ़ाई अढ़ाई साल लग जाते हैं जिस का नतीज यह होता है कि लोगों को connection मिलते ही नहीं । मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस red-tapism को दूर करने की भी कोशिश करेगी ताकि लोगों को इतनी लम्बी तकलीफ से बचाया जा सके ।

इसके इलावा जिस बात की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है एग्रीकलचरल पर्पज़िज़ (agricultural purposes) के लिये जमींदारों को सप्लाई (supply) की जाने वाली बिजली के बारे में । इस वक्त इस सिलसिला में जो रूल्ज़ (rules) मौजूद हैं वह इतने rigid हैं कि उन में एक ज़बरदस्त तबदीली की जाने की ज़रूरत है । इस वक्त minimum consumptions guarantee के मुताबिक installation charges दस साल के अन्दर किश्तों पर देने पड़ते हैं । इस सम्बन्ध में ज़मींदारों ने भी कई बार प्रोटैस्ट (protest) किया, तीन चार बार Grow More Food Commitees ने और Public Relations Committees ने प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजे हैं कि इस १० साल की time limit को बढ़ा कर १५ या २० साल तक कर दिया जाये, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

मैं आशा करता हूं कि इन सभी बातों पर, जो कि लोगों की genuine grievance हैं, सरकार जरूर ध्यान देगी और इन तक़लीफ़ों को दूर करने के लिये कदम उठायेगी ।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the demand be reduced by Rs. 100.

सिंचाई मंत्री (चौधरी लहरी सिंह) : स्पीकर साहिब! मेरे काबिल दोस्त श्री राम किशन ने बिजली की डीमांड पर बहस करते हुए जालन्धर ज़िला के मुतांल्लिक तीन चार बातों का ज़िक्र किया है । उन की पहली शिकायत यह है कि जालन्धर में बिजली फ़ेल होती रही है, दूसरी यह कि बिजली के रेट्स (rates) बढ़ा दिये गये हैं और तीसरी यह कि बिजली डीपार्टमैण्ट का working इतना खराब है कि शिकायतें बाकायदा तौर पर नहीं सुनी जातीं । स्पीकर साहिब, मैं आप से गुज़ारिश करना चाहता हूं कि इन सब बुराईयों को दूर करने के लिये मैंने हर ज़िला के अन्दर एक एक कमेटी बनाई है

[सिचाई मंत्री]

जिस में उस ज़िला के सारे एम. एल. ए.ज़ (M.L.A.s) और एम. एल. सीज़ (M.L.C.s) मैम्बर हैं। इन के अलावा वहां के (डिप्टी कमिश्नर) Deputy Commissioner, ऐग्ज़ैक्टिव इंजीनियर (Executive Engineer) और सुप्रिन्टैंडिंग इंजीनियर (Superintending Engineer) भी उस के मैम्बर हैं। यह इस लिये किया गया है ताकि लोकल (Local) शिकायतों को जल्दी से जल्दी दूर कराया जा सके और वहां के ऐम. ऐल. ऐज़. सच्चे अर्थों में पब्लिक की सेवा कर सकें।

उन की दूसरी शिकायत यह है कि इतने दिन बिजली फेल हो गई और रातों को अंधेरा छाया रहा। इस विषय पर मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह सब कुछ वहां पर लोड (load) ज्यादा हो जाने की वजह से था। इस चीज़ को regulate करने के लिये हमने पहले 5,500 Kw का transformer मंगवाया। जब उस से भी काम ठीक तरह से चलाना नामुमकिन हो गया तो 8,500 K.W का transformer मंगवाया गया। सन् १९५२ में जब यह मनिस्ट्री (Ministry) बनी तब से हमारी यह कोशिश रही है कि लोगों की डीमांड (demand) के मुताबिक installations की जाएं। लेकिन सरकार ने जिस वक्त जालन्धर ईलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी (Jullundur Electric Supply Company) को अपने हाथ में लिया उस वक्त न ही इतना लोड (load) था और न ही इतनी ज्यादा डीमांड (demand)।

स्पीकर साहिब, साढ़े पांच पांच हज़ार की मालियत के transformers लगाने के बाद भी अगर लोगों को बिजली न मिले और बिजली की extension न की जाए तो उन के लगाने का क्या फायदा है। मगर दरअसल extension की वजह से ही कई बार बिजली बन्द करनी पड़ती है जिस के लिये इतना शोर मचाया जाता है। मैं अर्ज़ करता हूं कि बिजली की लाईनें बढ़ाने के लिये बिजली बन्द करनी पड़ती है कई दफ़ा तो सारा सारा दिन बन्द करनी पड़ती है और कई दफ़ा ऐसा करने में कई घंटे लग जाते हैं। फिर मैं अर्ज़ करता हूं कि यह बिजली चुपचाप नहीं बन्द कर दी जाती। Public को बाकायदा तौर पर नोटिस दिया जाता है कि फलां दिन फलां वक्त बिजली बन्द रहेगी। यह तो एक Technical चीज़ है कि extension देने के लिये बिजली की सप्लाई (supply) कुछ वक्त के लिये बन्द रखनी पड़ती है। फिर माननीय मित्र जिन्होंने यह एतराज़ किया है वह अपने जिले की बिजली की कमेटी के मैम्बर हैं और उन के सामने इस किस्म की सारी बातें आती रहती हैं। यह शिकायत तो उन्हें नहीं करनी चाहिये थी। वह यह शिकायत करने में तभी हक बजानब हो सकते थे जब कि यह सारी बातें administration की खराबियों की वजह से होतीं। जब यह सिर्फ बिजली की extension देने की वजह से होती हैं तो शिकायत का स्वाल ही नहीं उठता।

फिर, स्पीकर साहिब, बिजली की consumption के rates के बारे में कहा गया है कि यह मौजूदा रेट्स (rates) बहुत ज़्यादा हैं। इस बारे में मैं अर्ज़ कर चाहता हूं कि जालन्धर में इस मतलब के लिये एक मीटिंग बुलाई गई थी जिस में मैं था, बहुत

सारे M.L.A.s थे और वहां के बहुत सारे मुख्य आदमी भी थे। हमारे बिजली विभाग के कुछ Engineers भी उस मीटिंग में शामिल हुए थे। वहां पर यह मामला discuss किया गया था। वहां पर public के आदमियों को यह बतलाया गया था कि पिछली कम्पनी की सप्लाई और गवर्नमैण्ट की सप्लाई में बहुत अन्तर है। गवर्नमैण्ट extension की सूरत में बिजली अपने खर्च पर मौके पर देती है। उसे ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इन हालात में बिजली के rates मौजूदा rates सस्ते नहीं हो सकते। फिर पब्लिक ने मान लिया है कि जो मौजूदा system है, वह ठीक है। इस के बाद Executive Engineer, Electricity की तरफ़ से एक statement भी जारी हुआ था। इन हालात में यह कहना ठीक नहीं कि private company सस्ते rates पर बिजली सप्लाई करती थी। एक बात में और अर्ज कर दूं वह यह कि industrial purposes के लिये बिजली के rates में कमी करने के सम्बन्ध में हम दुबारा ग़ौर कर रहे हैं। फिर यह कहा गया है कि जब बिजली से गवर्नमैण्ट को इतना ज्यादा मुनाफा हो रहा है तो वह बिजली के रेट्स (rates) कम क्यों नहीं करती। इस बारे में मैं हांऊस को बतला देना चाहता हूं कि हम बिजली की आमदनी में से भाखड़ा और नंगल के बिजली के काम पर ५० लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। यही income हम दूसरे कामों पर लगा सकते थे। हमें कोई वहम नहीं कि हम इतना खर्च अपने पास से करें लेकिन चूंकि यह भी ज़रूरी है इसलिये यह करना पड़ता है। इस में शक नहीं कि इतनी बड़ी रकम से हम प्रान्त में अस्पताल कायम कर सकते हैं कितने ही स्कूल खोल सकते हैं और कितने ही और काम लोगों की भलाई के लिये कर सकते हैं। खैर हम विचार कर रहे हैं कि बिजली के rates में क्या कमी की जा सकती है।

मैं हाऊस को यह भी बतला देना चाहता हूं कि मैंने कुछ dates मुकर्रर की हैं जब मैंने Chief Engineer और दूसरे Executive Engineers को बुलाया है। उन मीटिंगस (meetings) में जो पब्लिक की complaints होती हैं उन को दूर करने के लिये विचार किया जायगा। मैं हाऊस को विश्वास दिलाता हूं कि हम पब्लिक से justice करेंगे वैसे तो justice हो ही रहा है लेकिन लोगों को हकीकी हालात समझाने की ज़रूरत है। इस काम के लिये हमने इसी महीने की 16, 17 और कुछ आगे की तारीखें मुकरर की हैं। तमाम districts के electricity के Chief यहां आ रहे हैं और इन शिकायतों को दूर करने के तरीकों पर विचार करेंगे। मैं फिर अपने मित्र श्री राम किशन से अर्ज करता हूं कि जहां वह रहते हैं उसी शहर में Electricity के Executive Engineer भी रहते हैं। वह उन से मिल कर यह शिकायतें उन के सामने भी रखा करें।

Mr. Speaker: Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 13,25,200 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of XLI—Electricity Schemes—Working Expenses.

The motion was carried.

SUPERANNUATION ALLOWANCES AND PENSIONS

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs 11,29,870 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 55—Superannuation Allowances and Pensions.

Mr. Speaker: Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 11,29,870 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March 1954, in respect of 55—Superannuation Allowances and Pensions.

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 11,29,870 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March 1954, in respect of 55—Superannuation Allowances and Pensions.

The motion was carried.

CAPITAL OUTLAY ON MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,09,07,010 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 80—A. Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

Mr. Speaker: Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,09,07,010 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 80-A Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

Mr. Speaker: Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,09,07,010 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 80—A Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

The motion was carried.

CAPITAL ACCOUNT OF CIVIL WORKS OUTSIDE THE REVENUE ACCOUNT

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to move—

> That a supplementary sum not exceeding Rs. 12,15,930 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That a supplementary sum not exceeding Rs. 12,15,930 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 81-Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account.

Shri Ram Kishan (Jullundur City, North West) : Sir, I beg to move—

> That the demand be reduced by Rs. 100.

स्पीकर साहिब ! इस मांग में 1,52,300 रु. की रकम लुध्याना और बटाला में इंडस्ट्रीयल हाऊसिंग स्कीम (Industrial Housing Scheme) के तहत मकान बनाने के लिये मांगी गई हैं। इन स्थानों पर इंडस्ट्रीयल हाऊसिज़ बनाए जा रहे हैं मगर मैं आप का ध्यान जालन्धर की हालत की ओर दिलाना चाहता हूं। यहां पर इंडस्ट्रीयल हाऊसिज़ को improve करने की बड़ी ज़रूरत है। जालन्धर की आबादी में 51 हज़ार की ज्यादती हुई हैं और displaced persons भी काफी संख्या में आए हैं। जालन्धर पंजाब में industrial point of view से दूसरे दर्जे पर है। शहर में लगभग (77) छोटी मोटी फ़ैक्ट्रीज़ (factories) हैं। हाऊसिंग प्राबलम (Housing problem) acute हो गई है। एक २ मकान में चार २ पांच २ परिवार रह रहे हैं। हाऊसिंग की इस acute problem को improve करने के लिये industrial houses बनाये जायें।

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the demand be reduced by Rs. 100.

ਲੋਕ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ housing problem ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਭੀ ਕਾਫੀ acute ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਆਪ ਭੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਭੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਪਰੰਤੂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਸਕਣ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭੀ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀ ਬਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਥੇ ਭੀ ਬਨਾਏ ਜਾਣ।

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was by leave withdrawn.

Mr Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs.12,15,930 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 81—Capital Account of Civil Works outside the Revenue Account.

The motion was carried.

CAPITAL ACCOUNT OF OTHER STATE WORKS, ETC.

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,17,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,17,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,17,900 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 82—Capital Account of other State Works outside the Revenue Account.

The motion was carried.

CHARGES ON IRRIGATION ESTABLISHMENT—OPEN CANALS

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of Charges on Irrigation Establishment—Open Canals.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of Charges on Irrigation Establishment—Open Canals.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ੧੦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਤਨਾ ਵਡਾ ਹੈ ਇਸ ਵਲ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗ਼ਾਲਬ, ਅੰਬ, ਧਰਮਕੋਟ ਆਦਿ ਕਰੀਬਨ ੩੦੦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ

ਅਧੀ constituency ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਸੁਰਾਲ ਭੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਤਰਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ੨੦੦ ਫੁਟ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀ ਦਰਿਆ ਢਾਹ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੁਢਾ ਨਾਲਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 10, 12 ਲਖ ਦੀ ਰਕਮ ਰਖਦੇ ਹੋ ਉਥੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਟ ਖਰਚ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣੀਆਂ ਚਾਹਿਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਘਟੋ ਘਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਪਰੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਕਢਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਨ ੨੨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਫਿਊਜੀ refugee ਭੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੋ ਰੇਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਦਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਡਾ ਨਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਗੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਨ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜੰਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਛੀਨਾ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ problem ਨੂੰ ਨਜਿਠਨ ਲਈ ੧੦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। Situation ਬੜੀ grave ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

सिंचाई मंत्री—(चौधरी लहरी सिंह) : स्पीकर साहिब ! सरदार साहिब को अच्छी तरह मालूम है कि सरकार इस grave situation की तरफ से पूरी तरह alive है। इस बारे में दो तीन मीटिंगें भी हो चुकी हैं। हमने वहां पर अपने best इंजीनियर भेजे कि इस काम को अच्छी तरह से करने के लिये estimate तैयार करें। और तहकीकात कर के यह बतायें कि छीना जी के ससुराल को जो खतरा पैदा हो गया है उसे कैसे दूर किया जा सकता है। मैं अर्ज़ कर दूं कि इस काम के लिये 22 लाख रुपये का estimate लगाया गया है। इसे बढ़ा चढ़ा कर एक करोड़ कहने की ज़रूरत नहीं। सरकार सो नहीं रही है। जिस सरकार ने भाकड़ा जैसे बांध जिन पर पहले बहुत ज्यादा वक्त लगा करता था इतने थोड़े समय में बना दिया जो काम 1948 में शुरु होता है उसकी opening ceremony 1954 में हो रही है; जिस सरकार ने इतनी बड़ी २ नहरें बनाई हैं, उसे लापर्वाह बताना ठीक नहीं। और फिर जहां छीना जी और दूसरे जत्थेदार हों जो इतने vigilant हैं, तो इन गांवों को कोई खतरा हो ही कैसे सकता है। आप यकीन रखें कि सही estimate लगा कर रकम मन्जूर की जाएगी और season शुरु होने से पहले काम शुरु कर दिया जायगा।

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of Charges on Irrigation Establishment—Open Canals.

The motion was carried.

GENERAL ADMINISTRATION

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954 in respect of 25-General Administration.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954 in respect of 25-General Administration.

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : स्पीकर साहिब ! जैनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन (general administration) पर बोलते हुए इस demand के मुतालिक जिस में 10 रुपये की मांग की गई है मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो administration चल रहा है इस कि निगहबानी के लिये यह जरूरी है कि मनिस्टर साहिबान supervision करें। इस के लिये दौरे करें। लेकिन मुश्किल यह है कि इन में travelling allowances का ख्याल dominate कर रहा है। यह आम तौर पर देखा गया है कि यह administration को देखने के लिये दौरे पर नहीं जाते बल्कि घरेलू कामों के लिये जाते हैं। इन का दौरों पर जाना महज़ ceremonial और दिखावा है।

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ : ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਪਿਟੀ ਲਾਹੌਲ ਦੇ Backward tract charges ਬਾਰੇ ਹੈ।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : मुझे यह पता है। मैं तो यही अर्ज़ करना चाहता हूं कि सपिटी और लाहौल के लिये दौरे पर जाते हुए रास्ते में जालन्धर ठहरते हैं जैसे कि यह भी ज़रूरी काम हो।

अध्यक्ष महोदय : सपिटी और लाहौल जाते हुए रास्ते में अगर जालन्धर आता है तो वहां ठहर जाने में क्या हर्ज है ? आप अपनी तकरीर खराब न करें। अगरचे यहां पर यह फबती नहीं।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : मैं तो general admnistration पर कुछ और भी बोलना चाहता हूं। अगर आप कहते हैं तो नहीं बोलता।

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 25-General Administration.

The motion was carried.

MEDICAL AND PUBLIC HEALTH

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of Medical and Public Health.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of Medical and Public Health.

श्री रला राम (मुकेरियां) : अध्यक्ष महोदय ! इस demand पर मैं कट मोशन पेश करना चाहता हूं—

That the demand be reduced by Re. 1.

अध्यक्ष महोदय यह दरेहड़ा का इलाका मुकेरियां सब तहसील थाना हाजीपुर में है। जिला होशियरपुर में ऐसे और भी इलाके हैं जहां सात २ और आठ २ मील तक पीने के पानी की सख्त किल्लत है। सरकार ने बेशक बहुत योजनायें बनाई हैं लेकिन इस बारे में कोई योजना नहीं बनाई। पीने का पानी देने के लिये कांगड़े का जिक्र कर दिया है मगर दरेहड़ा का इलाका जो कि इस से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है इस का कोई जिक्र नहीं किया गया। यहां पर इतनीं पानी की किल्लत है कि गर्मियों में 6-6, 7-7 और 8-8 मील दूर जा कर हरेक व्यक्ति पानी लाता है।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧੀਨ ਪੰਮਟਰ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਬਲਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮੰਗ ਨਹੀਂ।

श्री रला राम : पर इस का Head तो General Public Health है।

अध्यक्ष महोदय : जिस item के लिये ग्रांट चाहिये उस के लिये आप बोल सकते हैं। Public Health तो Major head है और Supplementary Demand के लिए इसका नाम रखा गया है। इसलिए आप इस खास मद के बारे में बोल सकते हैं।

श्री रला राम : अध्यक्ष महोदय ! मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान इस तरफ़ दिलाना चाहता था। अब मैं इस motion को सभा की आज्ञा से वापस लेना चाहता हूं।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the demand be reduced by Re 1.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of Medical and Public Health.

The motion was carried.

AGRICULTURE

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 40—Agriculture.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 40—Agriculture.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 40-Agriculture.

The motion was carried.

CHARGES ON P.W.D. BUILDINGS AND ROADS ESTABLISHMENT.

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of Charges on P.W.D., Buildings and Roads Establishment.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of Charges on P.W.D., Buildings and Roads Establishment.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of Charges on P. W. D., Buildings and Roads Establishment.

The motion was carried.

MISCELLANEOUS.

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954 in respect of 57—Miscellaneous.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 57-Miscellaneous.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 57-Miscellaneous.

The motion was carried.

CONSTRUCTION OF IRRIGATION WORKS

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 68—Construction of Irrigation Works.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 68—Construction of Irrigation Works.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 68—Construction of Irrigation Works.

The motion was carried.

CAPITAL OUTLAY ON ELECTRICITY SCHEMES, ETC.

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 81-A—Capital Outlay on Electricity Schemes outside the Revenue Account.

Mr. Speaker : Motion moved—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 19 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 81-A—Capital Outlay on Electricity Schemes outside the Revenue Account.

Mr. Speaker : Question is—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of 81-A—Capital Outlay on Electricity Schemes outside the Revenue Account.

The motion was carried.

LOANS TO MUNICIPALITIES AND ADVANCES TO CULTIVATORS, ETC.

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh) : Sir, I beg to move—

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of Loans to Municipalities and Advances to Cultivators etc.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of Loans to Municipalities and Advances to Cultivators etc.

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : स्पीकर साहिब ! Advances to cultivators के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस में taccavi के advances भी शामिल हैं या नहीं । यह आम तौर पर Advances to cultivators में आ जाता है । किसानों को कर्जे देना अच्छा है मगर दरअसल जो रुपया कर्जों के लिये मनजूर किया जाता है वह कर्जा बांटने वाले अफ़सर ही ले जाते हैं । cultivators को तो मनजूर की गई रकम के आधे से भी कम रुपया मिलता है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस corruption को दूर किया जाए ताकि cultivators को कर्जों की पूरी रकम मिल सके ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Question is—

> That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year ending 31st March, 1954, in respect of Loans to Municipalities and Advances to Cultivators, etc.

The motion was carried.

(*The Assembly then adjourned till 2 p. m. on Monday, the 15th March* 1954).

109 PSLA—283—7-9-54—CP&S., Pb., Chandigarh.

Punjab Legislative Assembly Debates

15th March, 1954.

VOL. I—No. 6

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, 15th March, 1954.

CHANDIGARH :
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab,
1954

Price :/11/-

PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY

Monday, 15th March, 1954.

The Assembly met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital at 2 p. m. of the Clock. Mr. Speaker (Dr. Satyapal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

SEARCHES MADE BY THE POLICE IN THE HOUSES OF COMMUNIST WORKERS IN ROHTAK.

*2698. **Pandit Shri Ram Sharma**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that the houses of Communist workers were recently searched in Rohtak; if so, their names; together with the material found and taken possession of by the Police;

(b) the nature of the material found as a result of the searches referred to above?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : (a) House of no person in his capacity as a Communist worker has recently been searched in Rohtak District. Houses of certain persons were, however, searched in connection with the investigation of the cases registered under section 9 of the P.S.S.A., 1953.

(b) A statement showing their names and details of articles recovered from their houses and seized by the Police is give below:—

Serial No.	Case F.I.R. No.	Name of the person from whose possession articles seized.	Details of material seized.
1	20, dated 12th, February, 1954 Section 9, P.S. Act.	Chaudhri Dharam Singh, son of Hardhari Singh, Jat of Sampla, now Chhotu Ram Bhawan, Rohtak (Editor "Kamaoo Poot").	Copies of "Kamaoo Poot", dated 16th November, 1953 (1 copy), dated 1st December, 1953 (1 copy). 16th December, 1953 (1 copy), dated 1st January, 1954 (1 copy). 5th January, 1954 (1 copy). Press statement from B. Anand Sarup and Partap Singh Daulta, Advocate, typed, dated 30th January, 1954 (2 copies). Typed English note addressed to Shri Bhim Sen Sachar, Chief Minister of Punjab, Chandigarh, signed by Anand Sarup, Advocate, Secretary, Rohtak District Organising Committee, Communist Party of India and Partap Singh Daulta, Advocate, Vice President, Punjab Kisan Sabha,

[Chief Parliamentary Secretary]

Serial No.	Case F.I.R. No.	Name of the person from whose possession articles seized.	Details of material seized.
			Rohtak, dated 27th January, 1954 (2 copies) bearing signatures. An English written manuscript application addressed to D.M., Rohtak, from Narsingh Dass without date about Declaration "Kamaoo Poot". A statement written in Pencil containing notes about ten slogans. Five leaves written in Urdu under the heading "Kia Ye Sab Jhut Hain" in shape of a rough draft. One copy of supplement of "Kamaoo Poot". One paper containing notes about resolution of Bar Association, etc. All the above articles recovered from house search.
2	20, dated 12th February, 1954 Section 9, P.S. Act	Shri Narsingh Dass, son of Hari Chand Office "Kamaoo Poot", Rohtak.	The following articles were recovered from his house search:— Copies of "Kamaoo Poot", dated 5th January, 1954 (5 copies), dated 16th January, 1954 (1 copy). A book in Hindi called "Rus-ki-Chhithi" written by Devindra Nath Thakar. A book on Communist Party's Policy, June, 1951. Party letter in English No. 1, dated 8th January, 1953, No. 2, dated 30th January, 1953, No. 3, dated 12th March, 1953, No. 5, dated 30th April, 1953, No. 6, dated 24th June, 1953. A book in Hindi on Soviet Russia. Two books in Hindi on Stalin, etc. A book in Urdu on China's New Constitution. A book in Hindi on Stalin Lennin. A book in English on Lennin and Stalin, 1948. A book in English on Political Education 1951. A book in Urdu "Vote Kise Dena Hai" 1951. A book in English "American Order Intervention in Korea 1950". A copy of Soviet Land, October 25th, 1952. Risala No. 6, 1953. Risala Devat Bhomi in Hindi. Circular No. 34/53, dated 28th May 1953, regarding Naya Zamana. Circular No. 9153. dated the 16th February, 1953, regarding Nakodar Election. Circular regarding resolution on India today, dated the 12th November 1952, Circular No. 53/52, dated 29th November, 1952. Circular regarding appeal for funds for elections, dated 28th November 1952. Circular No. 4/52, dated 1952 about Bengal Party's members. Circular No. 5/52, dated 12th November, 1952, regarding National Freedom. Circular No. 6/52, dated 12th November, 1952, about some weaknesses of party. Circular No. 42/53, dated 26th June, 1953, about party school. Two copies in Punjabi of circular No. 1 on woman hearts. Two circulars on Woman Samaj A resolution of Kisan Sabha in pencil.
3	22, dated 12th February, 1954 Section 9, P.S. Act of P.S. City Rohtak	Shri Tara Chand, son of Ram Sarup Jat, B.T. Student, Rohtak.	8 copies of "Kamaoo Poot", dated 5th January, 1954. 2 copies of special supplement of papers "Badalti Dunia", dated 13th February, 1954. Two pages of paper "Partap", dated 12th February,

Serial No.	Case F.I.R No.	Name of the person from whose possession articles seized.	Details of material seized.
4	22, dated 12th February, 1954 Section 9, P.S. Act of P.S.City Rohtak.	Shri Randhir Singh, Advocate, Sonepat.	A copy of a notice to office-bearer students of the College to assemble opposite College Hall, dated 12th February, 1954, by Raghbir Singh, Secretary, Students Union. A copy of notice to members of the College Union to assemble opposite College Hall, dated 12th February, 1954, by Raghbir Singh, Secretary Students Union. Two copies of resolution of the Students Union, dated 12th February, 1954. Recovered from his house search.
5	Ditto	Shri Partap Singh Daulta, Advocate, Rohtak.	The following documents were recovered from his house search:— Report about months of December, 1952, January and February, 1953. A note in pencil about Punitive Tax and a voice against it. District Kisan Sabha and punitive taxes—a note written by him. A note on tenants in Rohtak District. A note about the resolution of the Working Committee, District Kisan Sabha, on punitive taxes. A note on Police firing in Jagsi Village.
6	Ditto	Chaudhri Suraj Mal, Advocate, Gohana.	His house was searched on 13th February, 1954, but nothing incriminating found.
7	Ditto	Shri Ram Bhaj, Advocate, Rohtak.	His house was searched on 13th February, 1954, but nothing incriminating found.
8	Ditto	Chaudhri Dharam Singh, Advocate, Karnal	His house was searched on 21st February 1954, but nothing incriminating found.
9	23, dated 12th February, 1954, Section 9, P.S.Act, of P.S. City Rohtak, Section 29, Telegraph Act.	Shri Anand Sarup, Advocate, Rohtak.	Documents of the following nature were seized from house search:— A receipt book of "Kamaoo Poot" paper. An envelope bearing the address of house No. RD/1449 containing a letter, dated 3rd December 1953. A note book containing notes of miscellaneous type. One letter No. Mes./E. 99A, dated 21st December, 1953, from Post Master General, Punjab, to Manager, "Kamaoo Poot". An open letter to Shrimati Sita Devi, M.L.A., from Mrs. Sanial typed copy. A copy of "Pursharthi Gazette" paper, dated 6th February, 1954. A diary containing notes of different nature. Papers "Kamaoo Poot", dated 5th February, 1954 (3 copies). Material for "Kamaoo Poot", dated 16th February, 1954 (9 leaves). Besides the above two lists containing names of persons of villages Rahrah and Jagsi were recovered from his personal search.
10	24, dated 12th February, 1954, Section 9, P.S. Act, City Rohtak.	Sardar Gurbax Singh, General Manager, "Naya Zamana", Jullundur.	8 copies of "Naya Zamana" paper of dates 5th February, 1954, to 9th February, 1954 and 11th February, 1954, to 13th February, 1954. One agency register. A draft in Urdu, dated 10th February, 1954, by Partap Singh Daulta about allegations against Police excesses.

[Chief Parliamentry Secretary]

Serial No.	Case F.I.R. No.	Name of the person from whose possession articles seized.	Details of materrial seized.
11	19, dated 12th February, 1954, Section 9 P.S. Act, City Rohtak.	Mahasha Mohinder Lal, Editor "Pursharthi Gazette" Rohtak.	3 copies of resolution of Gandhi Janta Congress Party meeting of 31st January, 1954, at Ludhiana. A copy of press statement, dated 29th January, 1954, signed by Anand Sarup and Chaudhri Partap Singh Daulta, Advocates, about alleged police excesses. Two papers in manuscript on the heading "Lawlessness and Punjab Government". One rough draft publication on the heading "Jat Gazette versus Pursharthi Gazette.".
12	20, dated 12th February, 1954, Section 9, P.S. Act.	Chaudhri Udhe Singh Dhankar.	Manuscript of "Kamaoo Poot" for its issue dated 16th February, 1954, seized from Vishnu Printing Press.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि समाचार पत्रों के विरुद्ध जो केस दर्ज हुए थे और इस सिलसिले में जो तलाशियां ली गईं थीं और जो मसाला पुलिस ने पकड़ा था, उन का ऐसे मुकद्दमों से क्या सम्बन्ध है ? मिसाल के तौर पर यह जो Three copies of the resolution passed by the Gandhi Janta Congress Party held at Ludhiana on 31st January, 1954, and a copy of the press statement, dated 29th January, 1954, signed by Anand Sarup, etc., पकड़ ली गई हैं, इन का इन cases के साथ क्या ताल्लुक है ?

मुख्य मंत्री : यह तो बाद में देखा जायगा कि यह चीज़ें जो पकड़ी गई हैं मुकद्दमे चलाने के लिये काम आती हैं या नहीं। अभी तो जो चीज़ें ज़रूरी समझी गइ थीं, पकड़ ली गई हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं यह दरियाफ्त कर सकता हूं कि जो चीज़ें कब्जे में ली गई हैं वे काबिले एतराज समझ कर ली गई हैं ?

Mr. Speaker : It does not arise.

पंडित श्री राम शर्मा : जनाब, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह material इस लिये कबज़े में लिया गया है क्योंकि यह इस character का था....

Mr. Speaker : No ; it does not arise.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं पूछ सकता हूं कि गांधी जनता कांग्रेस पार्टी के Resolutions का इन cases से क्या सम्बन्ध है ? चौधरी महेन्द्र लाल Editor, Pursharthi Gazette, Rohtak....

Mr. Speaker : This supplementary has no bearing on the question. Gandhi Janta Congress does not come in. मैं तमाम मैम्बर साहिबान का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि supplementary question केवल वही प्रश्न होता है जो दिये गये जवाब से relevance रखता हो।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. Supplementary question के जवाब में बताई गई बात से जो स्वाल पैदा हो, क्या वह नहीं पूछा जा सकता ?

Mr. Speaker : The question of Mohinder Lal does not arise out of the answer he has given.

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. Original question के जवाब में से जो चीज arise होती है, क्या वही या supplementary के जवाब....

Mr. Speaker : Order, please. I am just going to read a quotation from May's 'Parliamentary Practice' for the information of all the hon. Members. It relates to parliamentary procedure in regard to the asking of supplementary questions.

> "Supplementary questions, without debate or comment, may, within due limits, be addressed to them (the Ministers), which are necessary for the elucidation of the answers that they have given. The Speaker has called the attention of the House to the inconvenience that arises from an excessive demand for further replies and, to hinder the practice, he has frequently felt it necessary to call upon the Member, in whose name the next question stands upon the notice paper, to put his question, and has for the same reasons asked members not to ask supplementary questions and has suggested that lengthy answers should be circulated with the Official Report instead of being given orally. A supplementary question may refer only to the answer out of which it immediately arises".

Parliamentary Secretary ने बताया है कि पुलिस ने वे कागजात अपने कब्जे में ले लिये जिन की उसे ज़रूरत थी। इस पर यह supplementary तो पूछा जा सकता है कि पकड़े गये material की nature क्या थी और उस में क्या चीजें शामिल थीं। मगर यह नहीं कि वह क्यों पकड़े गये। मेरी हरगिज़ यह इच्छा नहीं कि supplementaries पूछने पर कोई बेजा हदबन्दी की जाए मगर मैं केवल एक दो सदस्यों को यह हक नहीं दे सकता कि वे सारे घंटे अर्थात् सवालों के वक्त को ही usurp कर लें। Question Hour सब सदस्यों के लिये है। मैं यह चाहता हूं कि केवल वही supplementary सवाल पूछे जायें जिन का असली सवाल के साथ सम्बन्ध हो। यदि एक ही सवाल पर बार २ वही supplementaries पूछने की आज्ञा दी जाये तो हर रोज़ बहुत सारे सवाल नहीं पूछे जा सकेंगे। और unstarred हो जायेंगे। ऐसा करना दूसरे सदस्यों के हक को मारना होगा। यह चीज हाऊस की dignity के खिलाफ़ होगी। मैं मुख्य मंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा कि वह सवालों का जहां तक हो सके मुकम्मल जवाब देने की कोशिश करें। उस की elucidation के लिये हर एक मैम्बर साहिब को points raise करने की आज्ञा होगी। Supplementaries पूछने के हक को मज़ाक बनाने को इजाज़त देने के लिये मैं तैयार नहीं।

पंडित श्री राम शर्मा : मुझे भी कुछ अर्ज करने की इजाजत दीजिये।

Mr. Speaker : After the ruling has been given, you can't raise the same point.

पंडित श्री राम शर्मा : I am not challenging the ruling. आप की इजाज़त से ही कुछ कहना चाहता हूं। आपने कहा कि मैं House का time usurp कर रहा हूं।

Mr. Speaker : Next question, please. आप अगला सवाल पूछिये।

(The Speaker called the Question Nos. 2699 and 2700 but Pandit Shri Ram Sharma did not put them.)

पंडित श्री राम शर्मा : मैं कोई सवाल ही नहीं पूछूंगा।

Mr. Speaker : All right. I shall go on calling upon you to ask the questions that stand in your name. I shall have to seek legal opinion on this matter as to whether a member's refusal to ask a question that has been put on the order paper does not constitute disobedience of and disrespect to the Chair. Anyway, this is an uncivil and discourteous behaviour.

REPRESENTATION FROM FATEH SINGH, SON OF BISHAN SINGH, OF VILLAGE CHARI, DISTRICT LUDHIANA.

2710. Sardar Harkishan Singh Surjit: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any representation, dated the 9th December, 1953, from one Fateh Singh, son of Bishan Singh, resident of Village Chari, Tehsil Samrala, District Ludhiana, was received by the Deputy Commissioner, Ludhiana, and the Government regarding illegal raid on his house and harassment by the Police;

(b) whether the Government is aware of the fact that the Panchayat of the said village passed a resolution on 5th December, 1953, protesting against the action of the Police and demanding due punishment of the Police Officer responsible for the raid referred to above;

(c) if the replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative the action, if any, taken by the Government in the matter?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Enquiries made by the Deputy Superintendent of Police, Ludhiana, on the spot revealed that S.H.O., Khamanaon, District Ludhiana, had conducted the house search of Fateh Singh, son of Bishan Singh, of Village Chari, on reasonable grounds and in accordance with the law. There was no harassment of any kind on the part of the Police. Most of the signatories of the resolution referred to in part(b) above stated before the D.S.P. that they had signed it out of ignorance of its contents due to their illiteracy.

CONFERENCES BETWEEN THE OFFICIALS OF PUNJAB (INDIA) AND PUNJAB (PAKISTAN).

***2718. Shri Ram Kishan**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of various conferences held between the officials of the Punjab (India) and Punjab (Pakistan) during the years 1953 and 1954 to date;

(b) the nature of the said conferences and the decisions, if any, arrived at by the Government together with the steps taken to implement these decisions?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary) : I regret it would not be possible to supply the information asked for as in the attempt to collect the information it has transpired that the labour and time involved in the collection of the entire information will not be commensurate with its usefulness.

श्री राम किशन : क्या मुख्य मंत्री साहिब बताने की कृपा करेंगे कि यह जो लिखा है कि I reget it would not be possible to supply the information asked for.... इस का क्या मतलब है ?

मुख्य मन्त्री : मैं अर्ज़ करूंगा कि यह इस लिये नहीं लिखा गया कि सरकार इस का उत्तर ही नहीं देना चाहती । बल्कि इस से यह मुराद है कि पंजाब (I) की पंजाब (P) के साथ कई किस्म की मीटिंगें (meetings) होती रहती हैं । जब तक आप किसी खास conference का नाम न बतायें तब तक इस का उत्तर नहीं दिया जा सकता । हमारी border conferences होती हैं । हमारे Financial Commissioners भी मिलते रहते हैं । इस लिये आप specifically किसी खास conference का हवाला देवें ताकि आप को जवाब दिया जा सके ।

ABDUCTION OF WOMEN IN AMRITSAR DISTRICT.

***2758. Sardar Darshan Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of women abducted in District Amritsar according to the reports made to the Police during the year 1953 and the number of Harijan women amongst them;

(b) the number of cases started by the Police in the said district in connection with the abductions referred to above and the results of such cases.

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): (a) 45 including 12 Harijan women.

(b) (i) Police registered 44 cases.

(ii) The results are as follows:—

Convicted	..	12
Acquitted	..	7
Untraced	..	5
Cancelled	..	14
Pending in courts	..	6
Total	..	44

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ: ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?

Mr. Speaker : It does not arise out of the main question.

ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸ ਬਿਨਾ ਉਪਰ ਕੈਂਸਿਲ ਹੋਏ ਹਨ?

मुख्य मंत्री : जिस वक्त कोई शहादत वगैरा नहीं मिलती तो उस वक्त केस को cancel करना ही पड़ता है ।

ENFORCEMENT OF SECTION 144 IN DISTRICT GURDASPUR.

***2809. Sardar Achhar Singh Chhina**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of times section 144 was enforced in Gurdaspur District during the years 1952 and 1953;

(b) the period for which the said section remained in force on each occasion during the years referred to above; and the reasons therefor in each case?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): (a) The number of times section 144, Cr.P.C., was enforced in Gurdaspur District during the years 1952 and 1953, is:—

1952 ..	1
1953 ..	4

(b) The period for which section 144, Cr. P.C., remained in force on each occasion during the years 1952 and 1953, the reasons therefor in each case and the area to which it applied, are given below:—

(1) 1st January, 1952 to 31st January, 1952.	To preserve public tranquillity during the general elections of Punjab Legislative Assembly.	Entire district.
(2) 4th February, 1953 to 15th July, 1953.	To preserve public tranquillity and to prevent danger to human life during the Praja Parishad agitation.	Ditto.
(3) 27th June, 1953 to 31th July, 1953.	To preserve public tranquillity and to prevent danger to human life in connection with Praja Parishad agitation.	Dit to.

(4)	For 26th September, 1953.	To preserve public tranquillity within 100 yards of the polling stations in connection with the bye-election in Seerah Constituency.	Area of Seerah Constituency only.
(5)	27th October, 1953 to 26th February, 1954.	To prevent danger to human life and to preserve public tranquillity in connection with the ejectment notices issued by the landlords to the tenants.	Entire district.

AMALGAMATION OF DEARNESS ALLOWANCE WITH PAY OF GOVERNMENT EMPLOYEES.

***2920. Sardar Partap Singh Rai**: Will the Minister for Finance be pleased to state whether he is aware of the fact that the Government of India have decided to amalgamate 50 per cent of the Dearness Allowance of its employees with their pay; if so, whether the Government contemplate taking similar action in respect of its employees; and when?

Sardar Ujjal Singh: Yes; Government have carefully examined the matter of merging a portion of Dearness Allowance in pay, but have decided that in view of the heavy financial commitments involved, it should be shelved for the present.

AMENDMENT IN CIVIL SERVICES RULES.

***2924. Shri Devi Lal**: Will the Chief Minister be pleased to state whether the Civil Services Rules have been recently amended so as to make the District Panchayat Officers eligible for recruitment to the P.C.S. cadre?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): No.

TOURS BY MINISTERS IN PEPSU.

***2926. Shri Mansa Ram Kuthiala**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of the Ministers who toured Pepsu during the recent General Elections in that State;

(b) the total amount of Travelling Allowance and other allowances drawn by Ministers mentioned in part (a) above in respect of the tours referred to above;

(c) the total mileage and the extent to which petrol and other fuel was consumed by them during the above tours;

(d) the number of hours and days respectively spent by the said Ministers in Pepsu before and during the polling?

Shri Prabodh Chandra (Chief Parliamentary Secretary): A statement containing the required information is given below—

Part (a)	*Part (b)*	*Part (c)*	*Part (d)*	
Names of Ministers who toured PEPSU during the recent General Elections there.	Total amount of Travelling Allowance and other allowances drawn by the Ministers mentioned in part (a).	Total mileage and extent to which petrol and other fuel was consumed by these Ministers during the said tours.	*Number of hours and days spent by these Ministers before and during the polling.*	
			Hours	Days
1	2	3	4	5
1. Shri Bhim Sen Sachar	Rs 15 on account of his visit to Patiala on 28th January, 1954 to attend a meeting of the Joint Advisory Council for Punjab, PEPSU and Himachal Pradesh at Patiala.	Private visits, all of which were before the polling, were undertaken in private vehicles, no record of mileage, petrol, etc., in respect of which is available.	It is difficult to state the number of hours	3½ approximately
2. Sardar Partap Singh Kairon	Nil	1,292 miles, 75½ gallons of petrol and 3/4 gallon of mobil oil were consumed, the cost whereof was borne by the Minister	203	11
3. Chaudhri Lahri Singh	Nil	Government car was not used for election purposes	No record was kept.	
4. Shri Jagat Narain	Nil	As the journeys were private, no record of mileage, petrol, etc., in respect of them is available.	The journeys being private, no record in respect of hours and days was kept.	
5. Sardar Gurbachan Singh Bajwa	Nil	Ditto	It is difficult to state the number of hours.	4 days
6. Chaudhri Sundar Singh	Nil	971 miles. 55½ gallons of petrol and 1¼ gallons of mobil oil were consumed, the cost whereof was borne by the Minister	Ditto	10 days

मुख्य मंत्री : इस के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि पैप्सू में चुनावों के सिलसिले में जो हमारे मिनिस्टर साहिबान वहां गए हैं वे official tour पर नहीं गए और न ही उन्होंने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल ही इस मतलब के लिये किया है । वे वहां private तौर पर गये हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜਾਲੰਧਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ tours ਦਾ ਖਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਥੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ।

TARN TARAN COMMUNITY PROJECT BLOCK.

***2760. Sardar Darshan Singh**: Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total expenditure proposed to be incurred by the Government on the Tarn Taran Community Project Block during the year 1953-54;

(b) the total amount of expenditure on Establishment and the Head-quarters;

(c) the expenditure proposed to be incurred on housing the Projects Staff?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) A total expenditure of Rs. 88,000 has been proposed for Tarn Taran Community Block during the year 1953-54.

(b) The total amount of expenditure on establishment in Tarn Taran Block is as under:—

		Rs.
(i) Block Headquarters	..	6,137
(ii) Field Staff	..	13,143
Total	..	19,280

(c) A sum of rupees 70 is proposed to be incurred on account of providing rent-free accommodation to one Lady Health Visitor in Tarn Taran Block.

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗਹ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਖਰਚ ਸਟਾਫ [Staff] ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜਹ ਹੈ ? ਮੁਰੱਬਾ ਬੰਦੀ ਉਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੋ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਇਤਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ?

Mr. Speaker : Disallowed.

ISSUE OF INSTRUCTIONS TO OFFICERS REGARDING THE OPERATION OF THE PUNJAB VILLAGE COMMON LANDS (REGULATION) ACT, 1953.

***2901. Shri Mool Chand Jain:** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that officers do not act upon a new law unless departmental instructions are sent to them by the Government;

(b) whether any instructions have been sent to the Revenue Panchayat and other departments concerned regarding the operation and passing of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1953; if so, a copy of the instructions be laid on the Table; if not, the causes of delay and the time likely to be taken for issuing such instructions;

(c) whether it is a fact that the Panchayats cannot utilise the lands vested in them under the Punjab Common Lands (Regulation) Act, 1953, unless the 'Manner' is prescribed under section 4 of the Act, and whether the State Government has made rules for carrying out this and other purposes of this Act; if so, a copy of the rules be laid on the Table; if not, the reasons for the delay and the time likely to be taken for making the rules in this connection?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) No.

(b) (i) Yes.

(ii) A copy of the instructions is given below.

(iii) Does not arise.

(c) (i) Yes.

(ii) No.

(iii) Rules are under preparation and will be issued shortly.

No. 782-R(CH)-54/116
Chandigarh, dated the 23rd February, 1954.

FROM

SARDAR HARKISHAN SINGH,
Under-Secretary to Government,
Punjab, Revenue Department.

To

All Deputy Commissioners in the Punjab.

SUBJECT:—*The Punjab Village Common Lands (Regulation) Act*, 1953—*Explanation of provisions thereof.*

MEMORANDUM:

The Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1953, was notified in the *Punjab Government Gazette* (*Extraordinary*) under the Punjab Government Legislative Department notification No. 1-Leg/54, dated the 9th January, 1954. Two copies of this Act are sent herewith for study and giving wide publicity to its provisions. Your demand for more

copies of this Act for official use as well as for distribution among the Revenue Officers working in your district may please be placed with the Deputy Controller of Printing and Stationery, Punjab, Chandigarh.

2. The important provisions of this Act are explained below:—

(i) Under sub-section (2) of section 1, the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1953, does not apply to such lands which have become shamlat due to river action nor to those which have been allotted to displaced persons on quasi-permanent basis.

(ii) Special attention is invited to the following definitions contained in section 2:—

(a) house;

(b) Collector;

(c) appointed date; and

(d) inhabitant.

(a) As would be observed from the definition of the term 'house', it not only includes regular constructed building but also the courtyard which may be walled or not.

(b) The definition of 'Collector' has been extended to include any officer not below the rank of an Assistant Collector of the First Grade who is specially empowered by the State Government to perform the duties of a Collector under the Act. In other words, the Government is competent to confer the powers of a Collector under this Act on any officer not below the rank of an Assistant Collector of the First Grade.

(c) The 'appointed date' in cases of villages where panchayats already exist and in those where panchayats may be formed is different i.e., in case of villages where panchayats exist, the 'appointed date' will be the date of commencement of this Act, viz., the **9th April*, 1954, while in other cases such date will be the date of constitution of a Panchayat with jurisdiction over the village.

(d) In the definition of 'inhabitant' no distinction has been made for the purpose of this Act between the proprietors and non-proprietors who reside in the same village nor has the temporary absence or absence due to employment of such persons elsewhere would affect their residence in the village.

(iii) Under subsection (a) of section 3 the administration and management of the Shamlat Deh of any village has been made the responsibility of the panchayat having jurisdiction over the village in whom all rights, title and interests whatever in the land have been vested. Under section 4 all such lands shall, however, be utilised by the panchayat for the benefit of the inhabitants of the village concerned in such manner as shall be prescribed in the rules which shall be framed in due course.

(iv) Under subsection (b) of section 3, the non-proprietors of villages who have built houses in Abadi Deh of a village have been granted proprietary rights in respect of sites under their houses.

(v) Under subsection (1) (b) of section 5, any structure or building erected by any person shall be allowed by the panchayat to retain possession of the same under such terms and conditions as may be determined by the panchayat subject, of course, to the rules which will be framed in due course.

(vi) Under section 5(1)(a) a person, who has already cultivated any shamlat land in a village, shall not be ejected forthwith by the panchayat but shall be allowed a reasonable time to harvest and collect his ripened and ungathered crops standing on the land. This provision is intended to safeguard the interests of persons who are already in cultivating possession of Shamlat Deh against any indiscrimination at the hands of panchayats.

(vii) Under section 6, the income accruing from sale, lease or otherwise of any Shamlat Deh which comes under the management of panchayat will go to the credit of the panchayat fund and the money thus derived will be spent for the benefit of the inhabitants under the rules which shall be framed later.

[Minister for Development]

(viii) Under section 7, no person shall be entitled to any compensation for any loss suffered as a result of the coming into force of this Act. In other words the Shamlat Deh will vest in the panchayat and the sites under houses of non-proprietors in Abadi Deh of a village will become the property of non-proprietors concerned.

3. It is requested that the above explanations of the provisions of the Act should be gone through very carefully and the Revenue Officers and staff should be made thoroughly acquainted with them. It should also be ensured that the provisions of the Act are given wide publicity correctly and are adequately enforced by the Revenue Officers in your district.

HARKISHAN SINGH,
Under-Secretary, Revenue.

No. 782-R(CH)-54/117, dated the 23rd February, 1954

A COPY, with a copy of the enclosure, is forwarded to the—

(1) Commissioner, Ambala and Jullundur Divisions, Jullundur City.

(2) Director of Land Records, Punjab, Jullundur City.

(3) Director, Consolidation of Holdings, Punjab, Jullundur City, for information.

By order,
HARKISHAN SINGH,
Under-Secretary, Revenue.

No. 782-R(CH)-54/118

A COPY, with a copy of the enclosure, is forwarded to the Director of Panchayats, Punjab, Jullundur, for information, and giving wide publicity.

2. After the enactment of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1953, the Shamlat Deh vests in the village panchayats and its management and the expenditure of the income of the same has to be done by the panchayats under the rules to be framed. It is, therefore, requested that in view of the various activities which the panchayats will be required to look after in the interest of the village community, the necessary rules may kindly be drafted and forwarded to this Department within a week through the Secretary to Government, Punjab, Transport, Co-operative and Panchayat Departments.

By order,
HARKISHAN SINGH,
Under-Secretary, Revenue.

No. 782-R(CH)-54/119

A COPY, with a copy of the enclosure, is forwarded to the Director, Public Relations, Punjab, Chandigarh, for information and with the request that the provisions of the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1953, should be given wide publicity through the Press.

By order,
HARKISHAN SINGH,
Under-Secretary, Revenue.

No. 782-R(CH)-54/120

A COPY, without enclosure, is forwarded to the Deputy Controller of Printing and Stationery, Punjab, Chandigarh, for information and necessary action in due course.

By order,
HARKISHAN SINGH,
Under-Secretary, Revenue.

A COPY, with a copy of the enclosure, is forwarded to the Secretary to Government, Punjab, Transport, Co-operative and Panchayat Departments, Punjab, Chandigarh, for information.

2. The draft rules when received from the Director of Panchayats may kindly be sent to this Department immediately with such comments as he may have to make thereon.

HARKISHAN SINGH,
Under-Secretary, Revenue.

To

The Secretary to Government, Punjab, Transport, Co-operative and Panchayat Departments, Chandigarh.

U.O. No. 782-R(CH)-54/908, dated the 23rd February, 1954.

श्री मूल चन्द जैन : क्या मंत्री महोदय कृपा करके बतायेंगे कि जो स्टेटमैण्ट टेबल पर रखी गई है इस के सफा दो पर date of commencement, *9th April 1954 रखी गई है, हालांकि ऐक्ट में इसका कोई हवाला नहीं है। वह उन्हों ने देखी है कि नहीं ? अगर देखी है तो क्या वह ग़लत है या जान बूझ कर ही रखी गई है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਵੇਖ ਕੇ ਬਤਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ:---

(c) The appointed date in cases of villages where Panchayats already exist and in those where Panchayats may be formed, is different, i.e. in cases of villages where Panchayats exist the appointed date will be the date of commencement of this Act, viz., the 9th April, 1954 while in other cases such date will be the date of constitution of a panchayat with jurisdiction over the village.

श्री मूल चन्द जैन : क्या वज़ीर साहिब को पता है कि पंचायतों में नये चुनाव सन् 1953 में हो चुके हैं और उन के मुताबिक बनी नई पंचायतें अब function भी कर रही हैं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਪਤਾ ਹੈ।

श्री मूल चन्द जैन : लेकिन जवाब में दी गई तारीख़ *9 अप्रैल, 1954, क्यों है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ verify ਕਰਾਂਗਾ।

श्री मूल चन्द जैन : मैंने अपने सवाल के पार्ट "c" में पूछा था कि क्या Common Lands (Regulation) Act, 1953, के मुताबिक कोई rules अभी तक बनाये गये हैं या नहीं। इस स्टेटमैण्ट में, जो कि मुझे supply की गई है साफ़ तौर से लिखा है कि पंचायतों के डायरेक्टर साहिब को लिखा गया है कि एक हफ़ता के अन्दर २ रूल्ज़ बना कर भेजें। यह आर्डर 23 फरवरी, 1954, को जारी हुआ था। इस को जारी किये हुए आज करीब तीन हफ़ते हो चुके हैं लेकिन वह रूल्ज़ अभी नहीं बने।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਗਲ ਤਾਂ verify ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ।

श्री मूल चन्द जैन : क्या मैं वज़ीर साहिब से पूछ सकता हूं कि जब 26 दिसम्बर का यह ऐक्ट बन चुका है और जब यह मानी हुई बात है कि यह एक बहुत ज़रूरी कानून है तो तीन महीने गुज़र चुकने के बाद भी अभी तक रूलज़ क्यों नहीं बनाये गये ?

---

*For the words "9th April, 1954" read "9th January, 1954",—*vide* letter No. 782-R(CH)-54/376, dated 22nd March, 1953, from the Under-Secretary to Government, Punjab, Revenue Department.

Mr. Speaker : It does not arise out of the main question.

ZONAL SCHEME FOR DISTRIBUTION OF CANAL WATER.

***2789. Shri Mani Ram**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) (i) whether any Zonal Scheme regarding the distribution of canal water in the State has been approved by the Canal Authorities after the partition; if so, its main features;

(ii) a copy of the said scheme be laid on the Table;

(b) whether the Zonal Scheme referred to in para (a) above has been enforced in any part of the State; if so, where;

(c) whether under this scheme the authorised discharge of a canal outlet has been reduced or is proposed to be reduced; if so, to what extent; together with the reasons therefor?

Chaudhri Lahri Singh: (a) (i) No.

(ii) Does not arise.

(b) No.

(c) Does not arise.

AUTHORISED DISCHARGE OF WATER OF CERTAIN CANALS.

***2790. Shri Mani Ram**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the authorised discharge of water of Main Branch, Upper Bari Doab Canal, Lahore Branch, Lower Kasur Branch and the Sabron Branch of the Upper Bari Doab Canal in the summer and winter seasons respectively;

(b) (i) the total area under the command of each of the canal branches referred to in part (a) above;

(ii) the quantity of canal water allowed per one thousand acres over each of these canal branches;

(c) (i) whether during the winter season the main branch referred to in part (a) above is allowed to flow twice the period of the other branches; if so, the reasons therefor ;

(ii) when the warabandis of the canals referred in part (a) above were approved during the year 1953;

(iii) the period for which the canal water was allowed to flow in each of the canals referred to in part (a) above from 1st October, 1953 to 31st January, 1954;

(d) whether during the winter, ordinarily in each canal water is allowed to flow for equal periods; if not, the reasons therefor;

(e) (i) whether all the perennial and non-perennial canal minors and canal distributaries in the Majitha and Jandiala Divisions of Upper Bari Doab Canal Circle are treated as at par regarding the supply of canal water; if not, the reasons therefor;

(ii) the list of the perennial and non-perennial canal minors and canal distributaries in each of the Divisions referred to in part (e) (i) above;

(iii) the quantity of water sanctioned for each of the water channels referred to in part (e) (ii) above;

(f) whether there is any difference in the rate of abiana per acre in the Divisions referred to in part (e) (i) above; if so, to what extent;

(g) the steps, that have been taken or proposed to be taken to put an end to the disparity in the allotment of canal water to the water channels referred to in part (e) (ii) above; if not, the reasons therefor?

Chaudhri Lahri Singh: The answer to this Assembly question is not yet ready. The information is being collected and it will be supplied to the member as soon as possible.

JAGADHRI TUBE-WELLS SCHEME.

***2821. Shri Wadhawa Ram**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state —

(a) whether it is a fact that Messrs Associated Tube-wells Ltd., did not carry out the agreement for the installation of tube-wells under the Jagadhri Tube-well Scheme;

(b) whether it is a fact that a supplemental agreement was entered into with the said company which provided for extension of the period of installation; if so, the reasons for the extension;

(c) whether it is a fact that the supplemental agreement provided for penalty in case of any shortfall; if so, the penalty so charged?

Chaudhri Lahri Singh : (a) Yes. Messrs Associated Tube-wells Ltd. could not carry out the programme of construction of tube-wells as provided in the original agreement.

(b) Yes. Supplemental agreement was entered into with Firm at their request for the extension of the period of installation as due to certain delays work could not be taken up immediately after the signing of the original agreement.

(c) Yes. A penalty of Rs. 71,000 has been ordered to be charged from the contractor on the basis of the Supplemental Agreement for shortfall in the time schedule provided therein. The firm has represented against it and the matter is under consideration.

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ਰਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ contract ਕਿਓਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

मंत्री : पहले तो हालात ऐसे थे कि उस agreement में कुछ एक ज़रूरी क्लाज़िज़ (clauses) शामिल नहीं कि गए थीं । कुछ एक का मतलब भी साफ़ नहीं था । अब जो दोबारा agreement किया गया है उस में penal clause भी दर्ज है और हरेक लफ़ज़ की बाकायदा जांच करके उसे agreement में लाया गया है । पहले agreement के अनुसार काम वक्त पर पूरा न करने के लिये उन्हें 71,000 रुपया जुर्माना भी किया गया है ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਫ਼ਰਮ ਨੇ ਅਪਣਾ agreement ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

मंत्री : मैं अपने मोहतरिम साथी के notice के लिये यह बताना चाहता हूं कि यह फ़र्म कोई ऐसी नहीं कि इधर-उधर से बना कर लाई गई हो ।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ contract ਕਿਓਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ? ਕੀਹ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ?

मंत्री : मैं मैम्बर साहिब को बताना चाहता हूं कि इन contracts के agreement यूं ही नहीं किये जाते । पहिले tender मंगवाये जाते हैं । इस सिलसिले में भी tender मंगवाये गये जिन में इस कम्पनी का भी tender मौजूद था । हालात का मुनासिब जाईज़ा ले कर इसी कम्पनी के साथ दोबारा agreement कर लिया गया ।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਇਸ ਫ਼ਰਮ ਦੇ ਪਾਸ ਅਜਕਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ?

मंत्री : इस सवाल का जवाब देने के लिये मुझे नोटिस चाहिये ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਜਿਹੜਾ 71,000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਫ਼ਰਮ ਨੇ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

मंत्री : अभी नहीं ।

श्री रणजीत सिंह कैप्टन : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि original agreement के तहत जो वक्त मुकर्रर हुआ था उस के और agreement की compliance होने तक कितना अरसा लगा ?

मंत्री : मैं समझा नहीं । क्या मेम्बर साहिब अपने सवाल को फिर दोहरायेंगे ?

श्री रणजीत सिंह कैप्टन : मेरे कहने का मतलब यह है कि शुरु के यानी पहिले agreement में जनाब ने जो वक्त मुकर्रर किया था और उस में और तब, जब कि final कम्पनी ने काम पूरा किया उस में कितना ज्यादा अरसा लगा ? यानी कितनी देर हुई इस agreement की compliance में ?

Mr. Speaker: I have followed your question but the hon. Minister seems to ask notice for this.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ agreement ਕਿਸ ਨੇ sign ਕੀਤਾ ਅਤੇ penalty ਦੀ clause ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨ ਰਖੀ ਗਈ ?

मंत्री : गवर्नमेंट ने ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ penalty clause ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਅਫ਼ਸਰ involved ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀ action ਲਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

मंत्री : इस के लिये मुझे नोटिस चाहिये ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਜਿਹੜਾ 71,000 ਰੁਪਏਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਮੁਆਫ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

INCLUSION OF VILLAGES JORUSI, DIKADALA, ETC., DISTRICT KARNAL, IN A CANAL DIVISION.

***2930. Shri Mool Chand Jain**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether the Villages Jorusi, Dikadala, Dehra, Rakeshra, Hatwala, Atala, Patti Kalvana, Mahoti, etc., Tehsil Panipat, District Karnal, are included in any Canal Division;

(b) if the answer to part (a) be in the negative, whether his department takes care of the drainage of the said villages;

(c) whether any representation was received by the Government from the villagers concerned asking for the inclusion of these villages either in Karnal or Delhi Division; if so, the action, if any, taken thereon?

Chaudhri Lahri Singh: (a) No.

(b) Yes.

[Minister for Irrigation]

(c) A representation was received from Shri Mool Chand Jain, M.L.A. Possibility for the inclusion of these villages or otherwise is under investigation.

श्री मूल चन्द जैन : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जब कुछ गांव ऐसे हैं जहां drainage की बहुत तकलीफ है तो क्यों उन्हें Canal Division में शामिल नहीं किया जाता ?

मंत्री : जहां पर नहरों का पानी जाता है, वहीं पर ही drainage के काम को confine किया जाता है। जहां पर नहर ही न हो तो वहां पर drainage का काम कैसे किया जाए ?

DRAINS IN KARNAL DISTRICT.

*2931. **Shri Mool Chand Jain:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the main and small drains maintained by the Irrigation Department in Karnal District and the names of villages covered by each drain respectively with a map;

(b) the total amount spent in cleaning the silt of each of the abovementioned drains in the jurisidiction of Karnal District during the years 1952-53 and 1953-54 ?

Chaudhri Lahri Singh: The answer to this question is not yet ready. The information is being collected and it will be supplied to the Member as soon as possible.

CANCELLATION OF ALLOTMENTS OF LAND OF BIGGER ALLOTTEES AT TOWN PATTI.

*2535. **Sardar Sarup Singh:** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) (i) whether any bigger allottees whose allotments of land were cancelled from Town Patti, District Amritsar during the year 1951 had filed any writ petitions in the High Court at Simla against their cancellations; if so, their list and the area to which each of them was entitled;

(ii) whether they had obtained any stay order from the said High Court to retain their possession till the decision of their writ petitions; if so, their list and the total area from which they were not to be disturbed till the decision of their cases;

(b) the decision, if any, arrived at by the High Court in the above cases together with the dates thereof;

(c) (i) the action, if any, taken by the Rehabilitation Authorities in the light of the High Court's decision in the above cases; if none, the reasons therefor;

(ii) the provision of law under which no action was taken in the light of the decision of the High Court and the reasons for doing so;

(d) (i) whether any representations from any of the persons, namely Labh Singh, son of Arur Singh, and Lehna Singh, etc., referred to in part (a) above were received by the Director, Rehabilitation (Rural), Jullundur, during his visit to Amritsar between 16th July, 1952 and 18th July, 1952 after the decision of the High Court; if so, their list;

(ii) the nature of the orders passed by the Director, Rehabilitation (Rural), Jullundur, in connection with these representations;

(e) whether any of the persons referred to in parts (a) (i) and (d) (i) above were made any allotments in the district of Ferozepur; if so, their list and the places of allotment in each case;

(f) (i) whether any of the persons referred to in part (d) (i) above were allowed to retain possessions of land at Patti, in addition to the allotments referred to in part (e) above; if so, the reasons therefor;

(ii) the provision of law under which they were allowed to hold evacuee area at two places;

(g) whether any steps were taken by the Rehabilitation Authorities to restore any of the temporary allottees whose review applications were accepted during the year 1951 after the decision of the High Court referred to above; if not, the reasons therefor?

Sardar Ujjal Singh: The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

Sardar Sarup Singh: How long will it take the Government to collect the information?

Minister: The Government is trying to collect the required information as early as possible.

Sardar Sarup Singh: It is a stereotyped answer.

Chief Minister: The question of the hon. Member is also a stereotyped one (*Laughter*).

REVIEW APPLICATIONS OF THE TEMPORARY ALLOTTEES OF PATTI.

*2536. **Sardar Sarup Singh**: Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any review applications of the wrongly ousted temporary allottees of Town Patti, District Amritsar, were accepted by the Director-General, Rehabilitation, Jullundur, before 4th July, 1951; if so, their total number and the total area required to satisfy their claims;

[Sardar Sarup Singh]

(b) whether the persons referred to in part (a) above were restored to Patti Town up to 31st August, 1951 in the light of the Government instructions issued for the restoration of original allotments; if not, the reasons therefor;

(c) whether the allotments of any bigger allottees were cancelled from Patti Town between 1st August, 1951 and 25th May, 1952 to provide accommodation to the persons referred to in part (a) above; if so, their list and the area held by each of them at Patti before the cancellations;

(d) (i) whether after the cancellations of their allotments the persons referred to in part (c) above were allotted lands outside Patti Towns between 1st August, 1951 and 15th June, 1952; if so, the names of the places district-wise where such allotments were made;

(ii) the date when these allotments were made in each case;

(iii) whether the allottees were informed of the places of their allotments; if so, by what method;

(iv) whether any of these allottees took possession of his allotment referred to in part (d) (i) above; if so, their list and the date of delivery of possession in each case;

(e) (i) whether any of the persons referred to in part (c) above was allowed to retain possession of any lands at Town Patti after the cancellation of his original allotment orders from there up to 31st December, 1953; if so, their list;

(ii) the provision of law under which they were allowed to retain the possession?

Sardar Ujjal Singh: The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

RULES REGARDING WEIGHTS AND MEASURES.

***2576. Shri Rala Ram**: Will the Minister for Finance be pleased to state the details of modifications, if any, that have been made by the Government in the existing rules regarding weights and measures in the State to redress the grievances of the traders and whether any orders have been issued to this effect?

Sardar Ujjal Singh: Following modifications have been carried out in the existing Punjab Weights and Measures Rules, 1943, with a view to meet the grievances of traders, etc.—

(1) Bullion dealers have been allowed to use cast iron weights of the denominations of 200 tolas and above for the weighment of silver only, for a period of one year with effect from 17th April, 1953, in the first instance. The position will be reviewed on the expiry of this period.

(2) The use of weights with or without adjusting holes and head plugging with shapes, sizes and tolerances conforming to the specifications laid down in the Rules, has been allowed.

(3) Condition in regard to the registrations of Repairers under the Rules has been abolished and the traders are now at liberty to get their weights, measures, weighing instruments, etc., repaired from any source.

(4) The period of reverification and stamping of weights, yard measures and milk measures has been extended from two to three years.

(5) Weighmen in Mandis, hawkers and traders in rural areas have been allowed the use of wooden beam scales of capacities not exceeding five seers instead of iron beamscales.

(6) Yard measures have been allowed to be marked in girahs on one side in addition to inches on the other.

श्री राम किशन: क्या वज़ीर साहिब यह बतायेंगे कि क्या पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी (Punjab Provincial Congress Committee) की तरफ से गवर्नमैण्ट को इस ऐक्ट को repeal करने के लिये एक resolution मौसूल हुआ है ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ।

Speaker : How does it arise from the main question, whether the Provincial Congress Commttee has sent a resolution to the Government or not ?

श्री राम किशन : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जो Weights and Measures Committee ने सिफ़ारिशात गवर्नमैण्ट को की थीं उन सब को अमली जामा पहनाया गया है या नहीं ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ।

श्री राम किशन : क्या Weights and Measures Committee की सिफ़ारिशात को पूरी तरह जामा पहनाया गया है या कोई सिफ़ारिश ऐसी भी है जो नहीं मानी गई ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

श्री राम किशन : यह इन सिफ़ारिशात पर कब से अमल हो रहा है ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤਾਰੀਖ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ।

श्री राम किशन : पिछले दिनों जब जालन्धर में छापे मार कर जो बाट पकड़े गये थे आया ऐसा होने से पहिले ही गवर्नमैण्ट ने इन सिफ़ारिशात को अमल में लाने के लिये instructions जारी कर दी थीं या बाद में ?

Mr. Speaker : It does not arise.

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : Instructions ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

श्री राम किशन : On a point of Order, Sir. फाईनैंस मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि instructions जारी कर दी गई थीं जो मैं उन से पूछना चाहता हूं कि उन पर अमलदरामद क्यों नहीं हुआ ? यह तो सवाल का पार्ट ही है।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੇਣ। Enquiry ਕਰਾ ਲੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

श्री गोपी चन्द : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि क्या अब दुकानदार अपने लिये बाट किसी भी जगह से खरीद सकते हैं और क्या उन्हें मोहर लगवाने की अब भी ज़रूरत होगी कि नहीं ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਵੱਟੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।

श्री गोपी चन्द : पहिले तो बाट खरीदने के लिये गवर्नमैण्ट की तरफ़ से agent मुकर्रर थे, क्या अब भी agent मुकर्र हैं ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਕੱਰਰ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ Licensees ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਰਖੇ ਹਨ।

श्रीमती सीता देवी : वित्त मंत्री जी ने कहा है कि instructions जारी की गई हैं तो क्या वह बतायेंगे कि वह किस तारीख को जारी हुई हैं ? वह सचमुच जारी हो चुकी हैं या अभी जारी होनी हैं ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ।

श्रीमती सीता देवी : क्या यह उन की knowledge में है कि उन पर अमलदरामद हो चुका है या नहीं ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਲਦਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਭੈਣ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ।

श्री गोपी चन्द : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि क्या कमेटी ने यह सिफ़ारिश नहीं की है कि जो वाट और माप तोल के पैमाने हैं उन की कीमतें अब भी ज्यादा हैं ?

Mr. Speaker : It does not arise.

श्री राम किशन : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि Weights and Measures Act के मुताबिक Weights and Measures बनाने का जो मनोपली (monoply) system था वह क्या हटा दिया गया या नहीं ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ monopoly system ਸੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ Weights ਅਤੇ Measures manufacture ਕਰਨ ਲਈ licensee ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਟੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ।

खान अब्दुल गफार खान : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि उन की समझ में वह हिदायतें जारी हो चुकी हैं तो क्या वह बतायेंगे कि वाकई वह जारी कर दी गई हैं या यह उन का ख्याल ही है ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।

श्री राम किशन : क्या पिछले दिनों में माननीय वज़ीर साहिब को इस सिलसिले में मंडी नवांशहर से या जालन्धर की मंडी फैज़गंज से शिकायत मौसूल हुई हैं ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੌਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

श्री राम किशन : क्या मंडी डबवाली या करनाल से कोई शिकायत आई है ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ।

PLAN TO ENCOURAGE KHADI

***2577. Shri Rala Ram:** Will the Minister for Finance be pleased to State—

(a) whether the Government of India's Plan for encouraging Khadi has been accepted by the State Government and is being given a practical shape; if so, in what form;

(b) the nature of help under this scheme that has been given by the Government to the weavers of Hoshiarpur in order to rehabilitate the handloom industry of the District?

Sardar Ujjal Singh: (a) The work of encouraging Khadi has been entrusted by the Government of India to the All-India Khadi and Village Industries Board, and the scheme drawn up by the Board in this regard postulates that the work will be done through the existing Khadi institutions and organisations, newly started ones, and through the centres to be opened by the Board directly. The Board has decided to make its own arrangements for the purpose in view and the question of giving practical shape to these schemes by the State Government does not arise.

(b) The All-India Khadi and Village Industries Board are paying from the funds placed at their disposal by the Government of India, a subsidy of 0-3-0 in the rupees on the sale of certified Khadiin this State, including the Hoshiarpur District, with a view to stepping up its offtake. The details o help given by the Board in other forms, if any are not available as the Board deals direct with the weavers.

INDUSTRIAL SCHEMES IN THE STATE.

***2603. Shri Jagat Ram Bhardwaj:** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that much youthful energy is being wasted because of growing unemployment in the State ; if so, whether any Industrial Scheme is under the consideration of the Government to provide employment to those youngmen who are unemployed or semi-employed together with its details ;

(b) whether the Government has under the consideration the starting of large scale Cottage Industries on the Japanese Model to increase production and provide gainful employment to the unemployed ?

Sardar Ujjal Singh: (a) Government are fully aware that unemployment has recently shown a tendency to increase in this State as in the rest of India and consider that an alround increase of economic activity in the State and not one single industrial scheme is essential for meeting the problem. Government, however, recognise the importance of developing suitable industries in the State for creating additional employment and are taking the necessary steps to encourage the development of industries, especially cottage and small scale industries, which have a relatively better employment value. The important measures adopted by Government to encourage the development of industries are provision of facilities for technical training, financial assistance, technical guidance and marketing facilities, etc. A number of schemes designed to assist and encourage the development of industries have also been included by Government in the next year's budget, which would help directly or indirectly to alleviate the unemployment problem. Brief particulars regarding the more important of these schemes are given in the attached statement.

(b) Under the Japanese system of industrial organisation, the key role is played by big industrial interests which distribute the different operations connected with the manufacture of an article among a number of satellite units and produce the finished article from the components made by such units. The system can thrive in this State only if private enterprise is

willing to play the same role as in Japan. It is not possible for Government to fill the place of private enterprise, because its policy is not to undertake State owned industrial enterprises, except in the limited field set apart for the public sector by the Government of India. Government would, however, be willing to provide the necessary facilities to private industrialists who might like to work on the Japanese system.

Statement of important new schemes of the Department of Industries, included in the budget for 1954-55.

(i) *Scheme for raising the Government Technical Institute, Ambala City, to Diploma Standard.* In order to meet the growing demand for higher technical education, it is proposed to raise the standard of the Government Technical Insitute, Ambala City, to Diploma Standard in electrical and mechanical engineering of Aligarh University. This will enable such diploma-holders of the Institute to qualify themselves for the subordinate engineering services and as supervisors and foremen in industry. The diploma in electrical engineering would also qualify the candidates for the grant of electrical supervisors licence. The scheme will be enforced subject to 1/3rd of its non-recurring expenditure being provided by the Central Government. The total cost of the scheme is Rs. 5,21,110.

(ii) *Aid to private institutions for raising their standard of instruction.* In order to enable the private institutions providing technical education, the All-India Council for Technical Education have worked out a Five-Year Plan under which the Central and the State Governments are required to subsidise these institutions. Accordingly a provision of Rs. 3 lacs to cover the non-recurring expenditure of the private institutions in raising their standard of instructions and Rs. 20,000 as recurring expenditure for this object has been made in a new scheme, included in the budget of this Department.

(iii) *Setting up of Industrial Intelligence Bureau.* The collection and supply of accurate industrial statistics and allied information constitute essential pre-requisites for the industrial advancement of a country. No organisation exists in this State to perform these functions and the responsibility for supplying the information rests upon the Department of Industries. The Department has been doing its best to meet the demands of the industrialists in this respect but experience has shown that with a view to giving effective and expeditious assistance to industrialists in this regard, it is imperative that the work of collection and supply of statistical information should be brought on a sound footing by the creation of a separate Industrial Intelligence Bureau. The scheme is estimated to cost Rs. 11,040.

(iv) *Setting up of Re-tanning and Finishing Centre.* The leather produced by the village tanners of the State is not fully tanned and cannot, therefore, be used in making high class foot-wears. It is, therefore, proposed to set up a retanning and finishing centre which would provide facilities to the tanners to tan their crudely tanned leather as fully tanned and to finish it under the supervision of well-trained staff. The scheme will cost about Rs. 94,550 of which 50 per cent will be paid by the Government of India.

(v) *Marketing of the products of cottage and small scale industries.* Marketing is the crux of the problem in the development of cottage and small scale industries. The marketing facilities at present provided by the Department of Industries are inadequate to meet the needs of the cottage workers now engaged in the various lines of manufacture. It is, therefore, proposed to open five sales depots at important centres in the Punjab, where all standard varieties of goods manufactured in accordance with the given specifications will be displayed for sale. This scheme has also been sponsored for the grant of assistance from the Centre amounting to 50 per cent of its total cost, viz. Rs. 3,23,650.

(vi) *Standardisation of products of cottage and small scale industries.* The products of cottage and small scale industries largely , suffer from a strong consumer prejudice owing to the lack of standardisation in them. It is imperative that quality control should be extended to these industries in order that the buyer may gain confidence in their qualities. It is proposed, accordingly, to establish Inspection Depots for the more important industries of small scale character in the State, which would pass the articles conforming to the standards of quality previously prescribed, before they are put on market. This Scheme has also been sponsored for the grant of assistance from the Centre amounting to 50 per cent of its total costs, viz. Rs. 52, 990.

[Minister for Finance]

(vii) *Grant of financial assistance to industries.* The progress of industries in this State is being greatly hampered owing to the paucity of financial resources. There are no big capitalists in the State while the banks are generally reluctant to advance loans for industrial development owing to the State's proximity to the border. The State Government too has been able to provide only limited funds owing to its lean finances, under the State Aid to Industries Act for the grant of financial assistance to private enterprise. It is, therefore, proposed to raise a loan of Rs. 40 lacs in two years i.e. 1954-55 and 1955-56 from the Central Government for financial assistance to the industrialists.

(viii) *Schemes for the development of Sericulture.* Sericulture is an important cottage industry providing subsidiary occupation to about 1,000 families in the State. To help development of this industry it is proposed to establish three new mulberry plantation-cum-demonstration farms, to set up incubation centres for rearing of Chawki worms on co-operative basis and to send three students for higher education in Sericulture in India at total cost of about Rs. 61,000.

PRODUCTION OF RAW SILK IN THE STATE.

***2604. Shri Jagat Ram Bhardwaj :** Will the Minister for Finance be pleased to State—

(a) the annual production of Raw Silk in the State during each of the years 1948 to 1953 ;

(b) whether he is aware of the fact that hilly and sub-hilly areas in the State are best suited for Toot Plantations ; if so, the steps taken or proposed to be taken by the Government to intensify Toot Plantation and the rearing of the Silk Worm ?

Sardar Ujjal Singh : (a)

Year		*Approximate production of Raw Silk*	
1948-49	..	10,113 lbs.	
1949-50	..	13,178 lbs.	
1950-51	..	13,844 lbs.	
1951-52	..	13,523 lbs.	
1952-53	..	14,400 lbs.	
1953-54 Already produced	..	14,300 lbs.	16,500 lbs.
Expected	..	2,200 lbs.	

(b) Submountainous areas and hilly tracts below 4,000 feet high are suitable for mulberry plantation. In order to intensify mulberry plantation in such areas like Kangra District and some of the areas in the districts of Hoshiarpur and Gurdaspur, the State Government have already set up three nurseries in this State at Sujanpur, Amritsar and Mukerian from where Saplings of good type mulberry are supplied to the interested persons on nominal rates. During the year 1953-54, 40,000 mulberry Saplings have been distributed in such areas.

With a view to developing silk worm rearing in the aforesaid areas Government maintains s riculture farms at Palampur, Mukerian and Sujanpur. Two more plantation-cum-demonstration Farms are proposed to be set up very shortly at a cost of Rs. 25,000, one at Kangra and the other at Rupar. Besides the above, a Model Sericulture Demonstration Farm is also proposed to be set up at Sujanpur in the near future.

श्री जगत राम भारद्वाज : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि 1948 में raw silk 10 हज़ार पौंड पैदा हुई। फिर तीन साल तेरह तेरह हज़ार पौंड होती रही। और फिर 14 हज़ार पौंड पैदा हुई तो मैं पूछता हूं कि यह कौन सी खास तरक्की हुई कि इतने सालों में पैदावार कुल दो हज़ार पौंड ही बढ़ी ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1952-53 ਵਿਚ raw silk 14 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 1953-54 ਵਿਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਇਹ ਕੋਈ ਘਟ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ mulberry ਦੇ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਇਕ farm ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਜਿਥੋਂ mulberry saplings ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ।

श्री जगत राम भारद्वाज : क्या वज़ीर साहिब की ज़िम्मेदारी mulberry saplings तकसीम करने तक ही महदूद है या कि वे यह भी देखते हैं कि लोग उन्हें अच्छी तरह लगाते और बढ़ाते भी हैं ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਅਸੀਂ ਇਹ saplings ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਅਤੇ saplings ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਾਲਦੇ ਵੀ ਹਨ।

श्री जगत राम भारद्वाज : क्या मिनिस्टरों की ज़िम्मेदारी इस बात की नहीं कि वे देखें.

Mr. Speaker : Order, Order, Next question please.

MACHINERY FOR THE TREATMENT OF COCCONS AND RAW SILK.

***2605. Shri Jagat Ram Bhardwaj :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether the Government has in its possession any machinery for the treatment of Cocoons and Raw Silk, if so, the details of such machinery together with its annual output during the last 5 years ?

Sardar Ujjal Singh : No. Does not arise.

ALLOTMENT OF EVACUEE LAND IN TANDA URMAR.

***2618. Sardar Chanan Singh Dhut :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the evacuee land in Mandi Darapur, situated within the Municipal limits of Tanda Urmar, District

[Sardar Chanan Singh Dhut]

Hoshiarpur, has been allotted to Baba Dalip Singh, Municipal Commissioner, Tanda Urmar, in exchange for his land in Darapur Dharmkot, Police Station Tanda, District Hoshiarpur ; if so, when and for what reasons ;

(b) whether it is also a fact that before the allotment of land to Baba Dalip Singh Bhalla, in the year 1952, the said land was given on rent by the Custodian ; if so, the names of the persons to whom the land was rented out and the total amount of rent so realised ?

Sardar Ujjal Singh : The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

TOTAL AREA UNDER REGISTERED CO-OPERATIVE GARDEN COLONIES.

***2619. Sardar Chanan Singh Dhut :** Will the Minister for Finance be pleased to state the total area of land District-wise under Registered Co-operative Garden Colonies in the State during the years 1947, 1950, 1951 and 1953 together with the number of owners of land in these colonies ?

Sardar Ujjal Singh : The statement is given below ;—

Details of Garden colonies in the State

Serial No.	Name of the District.	Name of the Garden Colony.	*Total area of the colony.*			*Number of allottees.*		
			Ordinary acres.	Standard acres.		Full units.	Half units.	Total.
				S.A.	U			
1	Ferozepur ..	(i) Balluana	1,021	906	1	44	11	55
		(ii) Jalalabad	548	417	4	21	6	27
		(iii) Patti Bhatian (Muktsar)	1,233	1,139	8½	52	9	61
		Total ..	2,802	2,462	13½	117	26	143
2	Amritsar	(i) Khan Kot ..	716	737	8	32	8	40
		(ii) Patti ..	938	1,315	2½	41	16	57
		Total ..	1,654	2,052	10½	73	24	97

Serial No.	Name of the District.	Name of the Garden Colony.	Total area of the colony.			Number of allottees.		
			Ordinary acres.	Standard acres.		Full units.	Half units.	Total.
				S.A.	U			
3	Gurdaspur ..	(i) Dyal Garh ..	572	581	3¼	23	10	33
		(ii) Khojepur	760	613	15½	25	15	40
		Total ..	1,332	1,194	2¾	48	25	73
4	Hoshiarpur ..	(i) Panam	864	689	1	36	8	44
		(ii) Dalamwal	187	150	1¾	8	2	10
		Total ..	1,051	839	2¾	44	10	54
5	Jullundur ..	(i) Boot Kingra	2,220	2,062	3	87	14	101
		(ii) Mahaloun	970	920	1¾	43	8	51
		Total ..	3,190	2,982	4¾	130	22	152
6	Ludhiana ..	(i) Bir Akhara ..	256	208	5	11	3	14
		(ii) Agwar Khawaja Baju	546	488	4	23	5	28
		(iii) Jugiana Kanganwal	784	607	7½	33	4	37
		(iv) Rahaoun	685	676	15½	31	6	37
		Total ..	2,271	1,980	15¾	98	18	116
7	Hissar ..	(i) Bahaudin	172	168	12¾	7	2	9
		(ii) Mirza ki Patti ..	998	1,036	1½	42	6	48
		(iii) Mughalpur Uklana	491	343	4¼	21	6	27
		Total ..	1,661	1,548	2½	70	14	84

[Minister for Finance]

Serial No.	Name of the District.	Name of the Garden Colony.	Total area of the colony.			Number of allottees.		
			Ordinary acres.	Standard acres.		Full units.	Half units.	Total.
				S.A.	U			
8	Rohtak ..	(i) Kharkhoda ..	595	432	12	22	10	32
		(ii) Lahli ..	435	399	4	15	10	25
		(iii) Panchi Gujran	959	730	$\frac{1}{4}$	36	8	44
		Total ..	1,989	1,562	$\frac{1}{4}$	73	28	101
9	Gurgaon ..	(i) Khajinke	262	238	$5\frac{3}{4}$	11	9	20
		Total ..	262	238	$5\frac{3}{4}$	11	9	20
10	Karnal ..	(i) Jundla	2,066	1,331	$3\frac{1}{2}$	88	20	108
		(ii) Kachrauli ..	1,223	1,094	$8\frac{1}{2}$	56	11	67
		Total ..	3,289	2,425	12	144	31	175
11	Ambala ..	(i) Barara	1,434	893	$7\frac{1}{2}$	59	11	70
		(ii) Khanpur	518	378	$14\frac{3}{4}$	20	8	28
		(iii) Morinda	500	478	$8\frac{1}{2}$	21	9	30
		Total ..	2,452	1,750	$14\frac{3}{4}$	100	28	128
	Grand Total	27	21,953	19,038	$4\frac{3}{4}$	908	235	1,148

ALLOTMENT OF EVACUEE LAND IN THE STATE.

***2620. Sardar Chanan Singh Dhut :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the total area of Evacuee land in the State just after the partition ;

(b) the total area of Evacuee Land allotted to displaced persons under the Quasi-Permanent Land Allotment Scheme ;

(c) the total area of Evacuee Land which still remains unallotted ;

(d) the total number of claimants for the allotment of Evacuee Land together with the number of displaced persons who have been allotted land so far ;

(e) the steps, if any, taken by the Government to satisfy the claims of those who have not so far been allotted any land and their number district-wise in the State ? ,

Sardar Ujjal Singh : The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

SPORTS INDUSTRY, JULLUNDUR.

***2720. Shri Ram Kishan :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether he is aware of the fact that the uprooted sports industry of District Sialkot (West Punjab) has been established in Jullundur after the partition ; if so, the steps, if any, taken by the Government to grant facilities to persons engaged in this industry with regard to residential quarters and business premises as well as with regard to exemption from the levy of certain taxes.

Sardar Ujjal Singh : Information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

श्री राम किशन : क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि यह information कब तक collect हो जाएगी ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ।

ALLOTMENT OF EVACUEE HOUSE NO. 83 AT VILLAGE SHAMSABAD, DISTRICT JULLUNDUR.

***2791. Shri Mani Ram :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) (i) whether any orders were passed by the Revenue Assistant (Rehabilitation), Jullundur in the month of February, 1952 about the allotment of evacuee house No. 83 (Eighty-three) situated in Village Shamsabad, Tehsil Phillaur, District Jullundur ; if so, to whom was this house allotted ;

(ii) the date when this order was passed ;

(b) (i) whether the file of the case was sent to the Tehsil Office for compliance ; if so, the date when it was received there ;

(ii) the date when the order was complied with ;

(c) whether the file under reference was sent to the Tehsil or District Record Office after compliance ; if so, when and to which Record Office ;

[**Shri Mani Ram**]

(d) whether any applications were received from certain persons, including Narain Singh for the grant of certified copies of the order of the Revenue Assistant, Jullundur referred to in part (a) above by the Sub-copying Agency, Phillaur, District Jullundur in the month of September, 1953 ; if so, the date thereof ;

(e) whether the file under reference was ever sent to the Sub-copying Agency referred to in part (d) above up to 12th February, 1954 ; if so, when ; if not, the reasons for delay ;

(f) (i) whether the copy of the order asked for was ever prepared and handed over to the applicants up to 12th February, 1954 ; if so, when ;

(ii) if the answer to part (f) (i) above be in the negative, the reasons therefor ;

(iii) the action, taken or proposed to be taken by the Government against the persons responsible for delay in the matter ; if not, the reasons therefor ?

Sardar Ujjal Singh : The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

REFORMS BY THE SECONDARY EDUCATION COMMISSION OF GOVERNMENT OF INDIA.

***2578. Shri Rala Ram :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the steps so far taken by the Government to examine and consider the measures and reforms proposed by the Secondary Education Commission of the Government of India which has recently published its report ;

(b) whether the Committee which was proposed to be set up to examine the State of Secondary Education in the State has been formed, if so, whether its personnel already announced still holds good ?

Shri Jagat Narain : (a) The recommendations of the Secondary Education Commission have been brought to the notice of all Headmasters/Headmistresses of recognised schools, Principals of Training Colleges and Headmasters of Training Institutions in the State and they have been asked to give effect to the recommendations as far as possible and reorientate methods of teaching and other school activities accordingly. Further the Matriculation syallbus is being examined by a sub-committee of the School Board in the light of the recommendation of the Secondary Education Commission.

(b) In view of the publication of the Secondary Education Commission Report and the recommendation of the Central Advisory Board for Education, on it, steps are being taken to dissolve it. Instead an implementation Committee is being set up by the Department to implement the recommendations of the Secondary Education Commission.

श्री रला राम : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह कमेटी कब तक स्थापित होगी ?

शिक्षा मंत्री : बहुत जल्दी ।

DISPENSARY AT DHARUBERA, DISTRICT GURGAON.

*2657. **Shri Babu Dayal :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that the dispensary at Dharubera, Tehsil Rewari, District Gurgaon has had no doctor for the last six months and that the patients are being inconvenienced a great deal ; if so, the reasons therefor ;

(b) the total number of dispensaries in the State running without any doctors ;

(c) the action, if any, taken or proposed to be taken by the Government in the matter ?

Shri Jagat Narain : (a) Yes. 50 posts are at present vacant on the cadre of Civil Assistant Surgeons, Class II (Non-Gazetted) and as a result thereof some other dispensaries are also without doctors. In spite of best efforts it has not been possible to get suitable candidates to fill up these posts in their present grades of pay.

(b) 28, including 5 Rural Dispensaries under the control of District Boards.

(c) Government have taken the following steps to remedy the shortage of qualified doctors for Civil Assistant Surgeons, Class II (Non-Gazetted) cadre —

(1) amalgamation of the cadre of Civil Assistant Surgeons, Class II (Non-Gazetted) and Sub-Assistant Health Officers ;

(2) advertisement of vacancies through the Subordinate Services Selection Board, Punjab ;

(3) Re-employment of superannuated doctors ;

(4) absorption of de-mobilized and retired Military Medical personnel.

श्री बाबू दयाल : क्या वज़ीर साहिब कृपया बतायेंगे कि बहुत से हस्पताल कई महीनों से बिना डाक्टर के हैं ?

शिक्षा मंत्री : इस का जवाब तो मैंने पहले ही दे दिया है ।

श्री बाबू दयाल : यह हस्पताल खुले रहेंगे या बन्द कर दिये जायेंगे ?

Mr. Speaker : This does not aries.

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਕਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੈ?

[Minister for Education]
मंत्री : इस के लिये नोटिस चाहिये ।

TRANSPORT CO-OPERATIVE SOCIETIES.

***2672. Shri Teg Ram :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total number of Transport Co-operative Societies that have been established in the State up to 31st January, 1954 ;

(b) the total number of members of the said Societies and also the capital raised by them ?

Chaudhri Lahri Singh : The answer to this Assembly Question is not yet ready. The information is being collected and it will be supplied to the member as soon as possible.

स्पीकर साहिब, कई आनरेबल मैम्बर बहुत ही लम्बे २ सवाल पूछते हैं जिन के जवाब बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं। उन्हें ऐसे लम्बे २ सवाल पूछते हुए शर्म भी नहीं आती।

APPOINTMENT OF AD HOC COMMITTEE FOR TRANSPORT SERVICES.

***2719. Shri Ram Kishan :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether any *ad hoc* committee was appointed by the Government to frame Rules and Regulations for the Subordinate Services of the Government Transport Services in the State ; if so, the personnel of the Committee and the terms of its reference ;

(b) the number of meetings, if any, of the said Committee held so far and the recommendations made by it together with the action taken by the Government thereon ?

Shri Jagat Narain : (a) No *ad hoc* committee was appointed by the Government to frame Rules and Regulations for the Subordinate Services of the Government Transport Services in the State. However, an *ad hoc* Committee was set up by Government to consider the question of confirmation, grant of Provident Fund, Gratuity or Pension and to determine the status of the non-pensionable staff of Government Transport Services in relation to the Civil Service Rules and the labour legislation. The Committee consisted of Education Minister, Punjab, Secretary to Government Punjab, Transport Department, Provincial Transport Controller, Punjab, Labour Commissioner, a representative of the Finance Department and two non-officials nominated on the recommendations of the Punjab Government National Motor Transport Workers Union.

(b) The Committee held two meetings and it was recommended that the conductors, drivers and workshop staff should be governed under the labour legislation and given all the concessions admissible thereunder. The recommendations made by them were accepted by Government in entirety. Standing Orders have been drafted on the basis of these recommendations, which are under scrutiny with the Finance Department/Accountant General, Punjab (Outside Audit Department).

श्री राम किशन : क्या Education Minister साहिब बतायेंगे कि आर्डर कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

मंत्री : जल्द से जल्द ।

श्री राम किशन : यह कितनी देर से under consideration है ?

मंत्री : 3 या 4 महीनें से ।

श्रीमती शन्नो देवी : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि अभी कितनी देर लगेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप उन का जवाब जानती ही हैं ।

BASIC SCHOOLS IN THE STATE.

***2759. Sardar Darshan Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of basic schools in the State at present, district-wise ;

(b) the difference in curriculum of the Basic Schools and the non-basic schools ;

(c) the total amount of expenditure incurred on the basic schools during the year 1953 and the average expenditure annually being incurred on a basic school and a non-basic school respectively ;

(d) the earnings, if any, made by the Government through basic schools during the year 1953 ?

Shri Jagat Narain (a) A statement is given below.

(b) In the basic primary schools either agriculture or spinning and weaving is taught as a basic craft but in non-basic primary schools no craft is taught. There is, however, no difference in the curriculum followed at the secondary stage.

(c) The total "Direct" expenditure on basic schools during the year 1952-53 was Rs. 2,15,163. The average annual expenditure on a single teacher basic primary school is estimated to be Rs. 2,500 during the first year and Rs. 2,000 on a non-basic school. Similarly the annual expenditure on two teachers basic primary school is estimated at Rs. 3,500 and on non-basic schools Rs. 3,000.

(d) Nil.

Statement showing the total number of basic schools in the State at present, District-wise.

1.	Amritsar ..	6
2.	Ferozepore ..	8
3.	Gurdaspur ..	30

[Minister for Education]

4.	Hoshiarpur	..	9
5.	Jullundur	..	6
6.	Ludhiana	..	6
7.	Kangra	..	7
8.	Gurgaon	..	5
9.	Ambala	..	57
10.	Hissar	..	9
11.	Karnal	..	6
12.	Rohtak	..	4
	Total	..	153

VACANCIES IN MEDICAL AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENTS.

***2820. Shri Wadhawa Ram :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of vacancies in the Medical and Public Health Departments, which could not be filled during the years 1952 and 1953 and the categories of services where vacancies remained unfilled ;

(b) the reasons, if any, for not filling the said vacancies ?

Shri Jagat Narain : The required information is being collected and will be supplied to the member, when ready.

REMOVAL OF EXECUTIVE OFFICER, PATTI.

***2534. Sardar Sarup Singh :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether any special meeting of the members of the Municipal Committee, Patti, District Amritsar was convened during the month of November, 1953 to consider a resolution for the removal of its Executive Officer ; if so, the date thereof ;

(b) (i) whether any resolution was passed by the said Committee in the meeting referred to in part (a) above for the removal of its Executive Officer ; if so, a copy of the same be laid on the Table of the House ;

(ii) the reasons that were put forward by the mover of the resolution for the removal of the said Executive Officer ;

(c) (i) the number of the members constituting the Municipal Committee, Patti, on the date when this resolution was passed;

(ii) the number of the members who voted in favour of this resolution together with the number of those who voted against it ;

(d) whether the mover of the said resolution secured the five-eighth majority in his support as required by subsection (7) of section 3 of the Punjab Municipal (Executive Officer) Act, 1931 ;

(e) whether a copy of this resolution was received by the Deputy Commissioner, Amritsar for necessary action ; if so, when and the date when it was received by him ;

(f) whether the resolution under reference was forwarded by the Deputy Commissioner, Amritsar to the Government, if so, when ; and the date when it was received by the Government from the Deputy Commissioner, Amritsar or Commissioner, Jullundur and Ambala Divisions ;

(g) (i) the action, if any, taken by the Government in the matter ;

(ii) the date when the decision, if any, in the matter was reached by the Government ;

(iii) the nature of the decision arrived at by the Government in this behalf ;

(iv) whether the decision of the Government was communicated to the Municipal Committee, Patti ; if so, when ;

(h) whether the Executive Officer under reference has been removed up to now ; if not, the reasons therefor ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Attention of the Member is invited to the reply given to Starred Assembly Question No. 2781** on the same subject.

CONSTRUCTION OF ROADS IN FEROZEPORE DISTRICT.

***2673. Shri Teg Ram :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether any scheme for constructing pacca roads in Ferozepore District during the years 1954 and 1955 is under the consideration of the Government ;

(b) the total mileage and the routes along which roads shall be laid out during the period mentioned in part (a) above in Abohar and the total amount of expenditure likely to be incurred by the Govenment thereon ;

(c) whether the entire expenditure shall be borne by the Government and District Boards or some of it shall be contributed by the local inhabitants ;

(d) if the reply to last portion of part (c) above be in the affirmative, the amount that shall be contributed by the local inhabitants ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) Yes.

(b) (i) Malout-Fazilka road 6 miles cost .. 3.5 lacs

**Reply to*Q. No. 2781 appears in the debate Vol. I, No. 1, dated 9th March, 1954.

[Minister for Public Works]

(ii) Malout-Alanwala road 12 miles cost .. 5.12 lacs

(iii) Gidderbaha-Kotbhai road 5 miles cost .. 2.06 lacs

(c) In case of (i) above expenditure will be shared equally by Government and District Board.

(d) In case of (ii) and (iii) expenditure of Rs. 1·80 lakhs and 0·68 lakhs respectively has been offered to be shared by local inhabitants and the contribution for the balance is being obtained from Government.

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ! ਜੋ 6 ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਬਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮਲੋਕ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ।

ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਇ : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਸੜਕ 1951-52 ਵਿਚ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ 24,978 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਲੁਕ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਰੋੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ?

Mr. Speaker. This does not arise.

FAZILKA-FEROZEPURE ROAD

***2918. Sardar Partap Singh Rai :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether the Fazilka—Ferozepur Road was recently metalled ; if so, when ;

(b) the total cost for its repairs during the years 1951-52, 1952-53 and up to 31st December, 1953, respectively ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa: (a) The metalling of Fazilka-Ferozepore Road was completed in the year 1951-52.

(b) The total cost of its' repairs during each year is given below :—

		Rs.
1951-52	..	24,978
1952-53	..	59,108
1st April, 1953 to 31st December, 1953	..	53,101

MUNICIPAL COMMITTEE, BHIWANI.

*2921. **Shri Ram Kumar Bidhat :** Will the Minister for Public Works be pleased to state the condition of the finances of the Municipal Committee, Bhiwani as at present and as at the time when the present Committee took charge of the Municipal Administration ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : The cash balance in hand when the present Committee took charge of the municipal administration was Rs 56,582-0-1 while the balance on the 28th February, 1954 is Rs. 47,281-3-6..

WATER STAND POSTS AT BHIWANI MUNICIPALITY.

*2922. **Shri Ram Kumar Bhidhat :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the fact that the top covers and spring-stop-rods of all the Public Water Stand Posts of Bhiwani Municipality have been removed by some unknown person or persons and the filtered and chlorinated water flows to the gutters without any check ;

(b) whether any report of the removal of the said top covers and other parts of the public water stand posts has been made to the police by the Bhiwani Municipal Authorities, if so, with what results ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) Yes. There is, however, no question of the filtered and chlorinated water flowing to the gutters without any check as due to the shortage of water there is a great rush at the stand posts till the supply is closed.

(b) No.

श्री राम कुमार बिढ़ात : क्या मिनिस्टर साहिब फ़रमायेंगे कि जब म्यूनिसिपल property इस तरह ज़ाया हुई है तो क्यों पुलिस को इस की रिपोर्ट नहीं की गई और क्या गवर्नमैण्ट इस पर कोई action लेगी ?

Mr. Speaker ; This question does not arise.

FLOW OF WATER FROM THE PUBLIC WATER STAND POSTS AT BHIWANI.

*2923. **Shri Ram Kumar Bidhat :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether the Executive Officer, Municipal Committee Bhiwani, has received any complaints from the public that costly filtered and chlorinated water is flowing unchecked from the public water stand posts, if so, the steps, if any, so far taken by him in the matter.

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Yes. The complaints were received in the case of low-level areas where the supply remains for longer hours. Enquiries on the spot, however, revealed that even at these places there was rush of people for taking water and consequently there was practically no wastage of water. However, as a precaution, push cocks are fixed from time to time but these are either broken or fastened up by the residents to keep a continuous flow.

REPRESENTATION AGAINST MEMBERS OF MUNICIPAL COMMITTEE, HOSHIARPUR.

*2925. **Shri Mansa Ram Kuthiala :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether the Government has recently received any representation from certain citizens of Hoshiarpur City against some members of the Municipal Committee, Hoshiarpur; if so, the names of the Municipal Commissioners against whom the representation has been made together with the nature of allegations made ;

(b) whether any enquiry was held by the Inspector, Local Bodies, Jullundur Division, on the said representation ; if so, the action, if any, taken or proposed to be taken by the Government thereon ;

(c) whether he will lay a copy of the representation and the report of the Inspector, Local Bodies referred to above on the Table?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

ALLOTMENT OF RESIDENTIAL PLOTS AT CHANDIGARH CAPITAL.

*2927. **Shri Mansa Ram Kuthiala :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the total number of residential plots so far allotted in the Chandigarh Capital to (i) Government servants and (ii) the Public ;

(b) the number of buildings whose construction was (i) started and (ii) completed by the Government servants and the public respectively up to 15th Feburary, 1954 ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) The total number of residential plots so far allotted in Chandigarh is 7,021. It is not possible to give the break of this number for Government servants and the public separately, since applications for sites do not contain any information as to whether the applicant is a Government official or a non-official.

(b) *Residential*

(i) 6 (Government servants)	..	3
(Public)	..	3
(ii) Nil		
Non-residential		
(i) 60 (Government servants)	..	Nil
(Public)	..	60
(ii) 3 (Government servants)	..	Nil
(Public)	..	3

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਜਦ ਕਿ ਸਾਈਟਾਂ (sites) ਏਨੀਆਂ ਵਿਕ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਕਿਨੇ ਥੋੜੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹਨ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਨਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛੋ ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ।

HOLDING OF ENQUIRY AGAINST MUNICIPAL COMMITTEE, HISSAR.

***2929. Shri Balwant Rai Tayal :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether any enquiry was held against the Municipal Committee, Hissar, by a Magistrate on the complaint of Shri Madan Lal Bagi in the year 1953; if so, a copy of the findings of the enquiry together with the action taken by the Government thereon be laid on the Table ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Yes. The reports submitted by the two Magistrates, who conducted the inquiry, are under examination by Government and the decision taken will be communicated to the Member in due course.

SALE OF LIQUOR IN THE STATE.

***2711. Sardar Harkishan Singh Surjit :** Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) the total number of licenses issued for retail sale of liquor in the State district-wise during the years 1950, 1951, 1952 and 1953, respectively ;

(b) whether it is a fact that the Excise Department invited the views of the Municipalities and the District Boards in the State on the opening of new liquor shops during the year 1953 ; if so, the names of the Municipalities and District Boards whose views, were asked and the view, if any, given by each of them ;

(c) whether it is a fact that the number of liquor shops in the State has increased in the year 1953 ; if so the reasons therefor ?

Chaudhri Sundar Singh : (a) A statement is given below.

(b) *First Part*—Yes.

[Minister for Labour]

Second Part—District Board, Karnal and Ludhiana Municipality.

Third Part—The District Board, Karnal in its resolution No. 13, passed at its meeting held on the 10th June, 1952, favoured the opening of new licenses.

The Administrator, Ludhiana Municipality, too stated that there was no objection to the opening of new licenses.

(c) *First part*—Yes.

Second part—New licenses for retail vend of country spirit in sealed bottles were opened in the interest of both excise revenue and public health and morals so as to suppress illicit distillation and smuggling and unlicensed sale of cheap and non-standard liquor, which is more harmful to the health of consumer than licit liquor.

STATEMENT—I

Showing the total number of licences issued for retail sale of liquor in sealed bottles in the State district-wise during the years 1950, 1951, 1952 and 1953.

Serial No.	Name of District	Total number of licenses issued for retail sale of liquor during the year.			
		1950	1951	1952	1953
	I. AMBALA DIVISION				
(1)	Hissar ..	22	22	22	22
(2)	Rohtak ..	..	..	..	..
(3)	Gurgaon ..	14	14	14	14
(4)	Karnal ..	18	18	18	27
(5)	Ambala ..	37	37	38	38
(6)	Simla ..	4	4	4	4
	Total ..	95	95	96	105
	II. JULLUNDUR DIVISION				
(7)	Kangra ..	41	41	41	41
(8)	Hoshiarpur ..	37	37	37	37
(9)	Jullundur ..	43	43	43	43
(10)	Ludhiana ..	38	39	39	40
(11)	Ferozepore ..	86	86	86	86
(12)	Amritsar ..	59	59	59	59
(13)	Gurdaspur ..	45	45	45	43
	Total ..	349	350	350	349
	Grand Total ..	444	445	446	454

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ: ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਨਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਾਈਸੰਸ ਕਿਤਨੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ?

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੋ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ: ਮਨਿਸਟਰ concerned ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇਵੋ।

अध्यक्ष महोदय : चीफ़ मिनिस्टर साहिब को पूरा इख्तियार है कि वह मिनिस्टरों की मदद करें।

APPLICATION OF RULE 37

Mr. Speaker: Since all the questions entered in today's list have not been covered during the Question Hours, the remaining questions will be deemed to have been answered under Rule 37 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly.

UNEMPLOYMENT IN THE STATE.

***2606. Shri Jagat Ram Bhardwaj :** Will the Chief Minister be pleased to state whether he is aware of the growing unemployment specially amongst the educated youngmen in the State ; if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken by the Government in this respect ?

Shri Bhim Sen Sachar : To relieve unemployment amongst the educated, Government have drawn up a scheme to employ 1,600 teachers during 1953-54, another 1,300 in 1954-55 and yet another 500 in 1955-56. These teachers will be utilized in opening new single teacher schools and in strengthening the existing single teacher schools which in the course of their development are considered to be understaffed. Actually 1,400 new single teachers schools have been started this year. 1,000 will be started next year and another 300 in 1955-56.

In addition 120 social education centres have been started and these have offered employment to an equal number of educated unemployed.

PERSONS OF VILLAGE MAHIPUR ETC. DISTRICT ROHTAK ARRESTED OR BEATEN.

***2702. Pandit Shri Ram Sharma:** Will the Chief Minister be pleased to state the names of persons of villages Mahipur and Salimsar Majra, Police Station Sonepat, District, Rohtak who were either arrested or beaten by the police together with the reasons for doing so in each case?

[Pandit Shri Ram Sharma]

Shri Bhim Sen Sachar: The following persons were arrested in villages, Mahipur and Salimsar Majra, for the offences mentioned against each:—

Village Mahipur—

1. Shri Chand, son of Indraj, Jat, was arrested on 22nd January, 1954 in case F.I.R. No. 12, dated 20th January, 1954, P.S. Sonepat, under section 215, I.P.C. (Harbouring) and Section 412, I.P.C. (receiving property stolen in a dacoity).

Village Salimsar Majra—

1. Guggan, son of Harbhaj, Jat, was arrested on 22nd January, 1954, in case F.I.R. No. 12, dated 20th Janaury, 1954, under section 216/412, I.P.C. Police Station Sonepat. In the course of interrogation one C.M. Pistol 12 bore and 4 cartridges were recovered from him and case F.I.R. No. 27, dated 5th February, 1954, under section 19/11/78 Arms Act, Police Station, Sopnepat, was registered.

2. Mange, son of Lallman, Jat, was arrested on 27th January, 1954 in case F.I.R. No. 12, dated 20th Janauary, 1954, under section 216/412, I.P.C., Police Station, Sonepat. In the course of interrogation one C.M. Gun, 12 bore was recovered from him and case F.I.R. No. 22, dated 31st January, 1954, under section 19/11/78 Arms Act, Police Station, Sonepat, was also registered against him.

3. Risala, son of Ramji Lal, Jat, was arrested in case F.I.R. No. 12, dated 20th Janaury, 1954 under section 216/412, I.P.C., Police Station, Sonepat.

4. Roop Chand, son of Bholar, Jat, was arrested in case F.I.R. No. 23, dated 21st January 1954, under section 19/11/78 Arms Act, Police Station, Sonepat. In this case 35 cartridges of 12 bore were recovered from his house.

5. Ude, son of Chandgi, Jat was arrested in case FI.R. No. 24, dated 2nd February, 1954, under section 19/11/78 Arms Act, Police Station Sonepat. In this case on .38 bore, 6 chambered. Foreign-made revolver and 6 cartridges of ·38 bore were recovered from him.

No person was beaten by the police.

CANCELLATION OF FIRE-ARMS LICENCES IN ROHTAK DISTRICT.

***2703. Pandit Shri Ram Sharma**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of fire-arms licences for (i) revolvers (ii) guns and (iii) others cancelled in each category in Rohtak District in the latest check up together with the reasons therefor in each case;

(b) whether the licences were cancelled on the report of the police and the Ilaqa Magistrate; if so, the consideration that weighed with them for recommending cancellations;

(c) the names of the licensees who live in towns whose licences have been cancelled;

(d) the number of licensees who were suspected of helping the proclaimed offenders?

Shri Bhim Sen Sachar: (a) Fire-arms licences for (i) 24 revolvers, (ii) 194 guns and (iii) 21 others were cancelled in Rohtak district in the latest check up. It is not in the public interest to disclose the reasons for which each of these licences was cancelled. Government have examined the reasons and are satisfied that the cancellations were justified.

(b) Yes, the licences were cancelled on a report submitted by a Board comprising the Illaqa Magistrate and Senior Iallaqa Police Officers. It is not in the public interest to disclose the considerations that weighed with this Board for making its recommendations, but Government have examined their reasons and are satisfied that the recommendations were justified.

(c) 1. Ram Kishan, son of Nathu Ram of Jhajjar Town.

2. Arjan Singh, son of Salag Ram of Jhajjar Town.

3. Moola Ram, son of Shiv Ram of Beri Town.

4. Ram Kishan, son of Surja Singh of Beri Town.

5. Hira Lal, son of Bhagwan Dass of Beri Town.

6. Karan Singh, son of Kalyan Singh of Sampla Town.

7. Ram Singh, son of Harwant Singh of Beri Town.

8. Murari Lal, son of Mangat Rai Mahajan of Beri Town.

9. Prem Dass, Headmaster, Government Industrial School, City Rohtak.

10. Kehar Singh, Agent of Chaudhri Sri Chand, Advocate, City Rohtak;

11. Sohan Lal, son of Chandgi Ram, Jat, City Rohtak.

12. Brij Nath, son of Ajudhya Nath, Mahajan, City Rohtak.

13. Bhagwan Dass, son of Mansha Ram, Jat, City Rohtak.

14. Sat Parkash, son of Manohar Lal, City Rohtak.

15. Chaudhri Ram Sarup, Jat, Ex-M.L.A., City Rohtak.

16. Rattan Singh son of Man Singh, City Rohtak.

(d) 36.

PRICES OF FOODGRAINS IN THE STATE.

*1713. **Sardar Harkishan Singh Surjit**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the controlled price of foodgrains and wheat atta at the time of the lifting of control in the State in the main cities including Amritsar, Jullundur, Ludhiana, Hoshiarpur, Ferozepur, Pathankot, Rohtak, Karnal, Ambala and Hissar;

(b) the prices of foodgrains and wheat atta in the said cities month by month after de-control;

(c) whether it is a fact that the prices of foodgrains increased in the months of December, 1953 and January, 1954 in the State; if so, the reasons therefor;

(d) the steps taken by the Government to bring down the prices and with what results?

Shri Bhim Sen Sachar: The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

CONSTITUTION OF INDIA.

*2721. **Shri Ram Kishan**: Will the Chief Minister be pleased to state whether the Union Government had invited any suggestions for amending the constitution of India; if so, the details of amendments, if any, suggested by the State Government?

Shri Bhim Sen Sachar: It would not be in public interest to disclose the information asked for.

PROTEST BY THE STUDENTS OF CHHOTU RAM ARYA COLLEGE, SONEPAT, AGAINST POLICE EXCESSES IN ROHTAK DISTRICT.

*2762. **Sardar Darshan Singh**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a meeting of the students of the Chhotu Ram Arya College, Sonepat, under the presidentship of the Principal, protested against the atrocities committed by the police in District Rohtak and demanded an enquiry into the Police excesses;

(b) whether it is also a fact that the Secretary of the Students Action Committee has been arrested by the Police; if so, the reasons therefor?

Shri Bhim Sen Sachar: (a) Yes.

(b) No.

REGISTRATION OF CASES UNDER SECTIONS 302 AND 117 IN DISTRICT GURDASPUR.

*2810. **Sardar Achhar Singh Chhina**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of cases registered under sections 302, 392 and 117 of the I.P.C. in district Gurdaspur during the years 1952 and 1953;

(b) the number of cases in which the prosecution failed to get a conviction?

Shri Bhim Sen Sachar : The required information is given below—

Section	Total No. of cases registered. (a)		The number of cases in which the prosecution failed to get a conviction. (b)	
	1952	1953	1952	1953
302, I.P.C.	38	32	15	7
392, I.P.C.	25	19	..	2
117/392/447	..	3	..	3
117/302/307	..	2	..	1

OPENING OF FIRE BY THE POLICE IN VILLAGE JAGSI, DISTRICT ROHTAK.

***2812. Sardar Achhar Singh Chhina**: Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the Police opened fire on the residents of village Jagsi in Rohtak district on 11th February, 1954; if so, the number of persons injured as a result of the firing together with the reasons therefor?

Shri Bhim Sen Sachar: A Police Party consisting of 2 S.I.s, 11 Foot Constables and 6 Mounted Foot Constables, all armed, headed by Shri Bhag Singh, S.H.O., Baroda, raided village Jagsi on the morning of 11th February in order to effect the arrest of Hem Raj and his associates, about whose presence in the village, Police had received reliable information. The houses of the suspected harbourers, 6 of them were surrounded and searched one by one. The house of Birkha, a bad character, was also secured for conducting a search, and Police were posted outside the house. This house is on one side of the village. The Police had good grounds for believing that Birkha harboured Hem Raj and his associates and that his house was likely to contain looted property. But before the search could be commenced, a mob of 25/30 persons, including women, suddenly came up armed with Jellies (two pronged forks with long handles) and lathis and attacked the Police keeping guard on the house. On hearing the uproar, the S.H.O. and his men rushed to the spot and tried to dissuade the villagers from assaulting the Police, but without any

[Chief Minister]

effect. 9 Policemen and one lambardar received injuries from this concerted and pre-planned attack. The Police had then to open fire on the unruly mob purely in self-defence. One person, named Hukmi, son of Birkha, received an injury on his arm. No other person out of the assailants received any injury. 18 of the assailants were rounded up thereafter at the spot.

TIME-LIMIT IN CASES OF SUSPENDED GOVERNMENT SERVANTS.

***2932. Shri Mool Chand Jain**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any time-limit fixed by the Government within which the cases of suspended Government servants are required to be decided; if so, what, if not, the reasons therfor ;

(b) whether there is any time-limit fixed within which inquirics against suspended Government servants are required to be started; if so, what; if not, the reasons therefor ?

Shri Bhim Sen Sachar: (a) and (b) No. It is difficult to prescribe uniform time limits because the circumstances of different cases differ.

REORGANISATION OF THE PROSECUTNG AGENCY.

***2967. Shri Ram Dayal Vaid**: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government intends to reorganise the Prosecuting Agency of the Punjab Police, in the new set-up wherein separation of judiciary has been made from the Executive; if so, the steps proposed to be taken by the Government in this direction,

(b) whether the Prosecuting Agency shall continue to be under the Executive Branch of the Police or will it be under the Legal Remembrancer;

(c) whether the Government also intends to promote suitable personnel thereof to the P.C.S.?

Shri Bhim Sen Sachar: (a) The matter is under consideration of Government.

(b) and (c) Does not arise.

DESTRUCTION OF CROPS BY WILD COWS IN GURGAON DISTRICT.

***2660. Shri Babu Dayal Sharma**: Will the Minister for Development be pleased to state whether he is aware of the fact that several herds of wild cows in Gurgaon District specially in Rewari Tehsil are destroying crops badly; if so, the steps taken or proposed to be taken by the Government in this respect?

Sardar Partap Singh Kairon: Yes. About 225 wild cows are roaming about and destroying crops near the villages Dharuhera, Chelar, Jhatwa in

Rewari Tehsil and Sohna Bhora Kalan and Bhondsi circles of the Gurgaon tehsil. An effort to domesticate these wild cows made in the past but the scheme proved failure as it was found very difficult to catch them and tame them.

GRANT OF LOANS TO ZAMINDARS FOR THE PURCHASE OF TRACTORS

***2761. Sardar Darshan Singh**: Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that loans for the purchase of tractors are proposed to be given by the Government to zamindars from the funds meant for the Tarn Taran Community Project Block;

(b) whether it is also a fact that the loanees will be required to give the tractors so bought on hire to other zamindars;

(c) the conditions on which a zamindar will be granted loans referred to in part (a) above;

(d) whether it is a fact that the Government has decided to wind up the Mechanical Cultivation Scheme, whereunder the Government gave on hire tractors to the zamindars; if so, the reasons therefor?

Sardar Partap Singh Kairon: (a) Yes.

(b) Loans for the tractors will be advanced for cultivating big blocks of area and reclaiming Banjar lands. It will also be presumed that the loanees will be giving their tractors purchased with the loans advanced on hire to other zamindars;

(c) The loans will be advanced under the condition prescribed in Land Improvement Act, 1883.

(d) An Enquiry Committee at higher level was appointed by the Punjab Government during 1952, to look into the working of the Land Reclamation and Mechanical Cultivation Scheme. Its financial as well as other aspects were fully examined by the said Committee. According to one of its recommendations this Department gave up reclamation and cultivation of private lands with State-owned tractors on hire system because it was this part of the work which resulted in heavy financial losses to Government.

IRRIGATION BY CANALS AND TUBE-WELLS.

***2608. Shri Jagat Ram Bhardwaj**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the area irrigated by Canal water in each district of the State during the years 1952, 1953;

(b) the number of tube-wells constructed by the Government for irrigation purposes in each district during the years 1951, 1952 and 1953?

Chaudhri Lahri Singh: (a) A statement containing the required information is given below:—

(b) (i) Up to 1953, over 200 tube-wells have been completed under the Jagadhri Tube-well Scheme, which discharge into the Western Jumna Canal for converting Sundar and Bhalaut Sub-Branches into perennial;

(ii) Up to 1953, following tube-wells for irrigating zamindara land were completed:—

Karnal district	..	24
Ambala district	..	18
Total	..	42

STATEMENT

Serial No.	Name of District.		Area irrigated by canal water in each district of the State during the year—	
			1952-53	1953-54
			Acres	Acres
1	Hissar	..	534,857	565,369
2	Rohtak	..	467,911	491,025
3	Karnal	..	340,729	341,474
4	Ambala	..	8,550	4,263
5	Kangra	..	1,364	1,421
6	Hoshiarpur	..	26,435	38,337
7	Ludhiana	..	112,872	120,186
8	Ferozepur	..	1,355,257	1,509,267
9	Amritsar	..	733,948	758,652
10	Gurdaspur	..	169,007	144,191
	Total	..	3,747,930	3,974,185

Note. (1) No irrigation is being done in Jullundur, Gurgaon and Simla Districts of the Punjab.

(2) Figures of area irrigated in PEPSU, Delhi and Bikaner State are not included in the above.

(3) Figures for the year 1953-54 are upto 31st January, 1954.

MALAKPUR AND DAULATPUR MINORS OF ABOHAR BRANCH OF SIRHIND CANAL.

*2575. **Shri Teg Ram:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total number of villages where temporary moghas have been allowed on the Malakpur and Daulatpur minors of the Abohar Branch of Sirhind Canal during the year 1953;

(b) the total number of applicants for temporary moghas on the said minors, together with the number of those who were given and the number of those who were not given temporary moghas respectively;

(c) whether it is a fact that when he visited Abohar in the middle of May 1953, he declared that no temporary moghas would be allowed to any body in that year and instructions to the Canal Authorities were issued so that no temporary moghas be sanctiond to anybody ; if so, the reasons for the grant of temporary moghas referred to above?

Chaudhri Lahri Singh: (a) (i) Malakpur Distributary 6 Nos.

(ii) Daulatpur Minor Nil

(b) (i) Applications for temporary outlet were invited as per Government orders.

(ii) The number of temporary shoots allowed is as stated at (a) above.

(c) Orders were issued in November, 1952 that no temporary shoots should be given with effect from Kharif, 1953. However these orders were revised in April, 1953 according to which temporary shoots were allowed only to those areas where they were previously given in Kharif, 1952.

IMPOSITION OF CUT ON THE CULTURABLE EVACUEE AREA AT TOWN PATTI.

*2537. **Sardar Sarup Singh:** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any proposal for imposing special cut on the culturable evacuee area at Town Patti, District Amritsar, was sent by the State Government to the Union Government for approval; if so, when;

(b) the decision, if any, arrived at by the Union Government in the matter;

(c) whether the decision of the Union Government was communicated to the State Government: if so, the date on which it was received by the State Government;

(d) the action, if any, taken by the Rehabilitation Authorities up to 31st December, 1953 in the light of the Union Government's decision regarding the allotment of the area which was made

[Sardar Sarup Singh]

available by cancelling certain allotments and which could not be allotted to the deserving persons pending the decision of the Union Government; if none, the reasons therefor;

(e) whether any of the allottees whose allotments were cancelled from Patti Town up to 26th April, 1952 were allotted land anywhere in Amritsar and Ferozepore Districts up to 31st December, 1953; if so, the list of such persons and the places, district-wise, of allotment in each case;

(f) whether the allotments of any of the persons referred to in part (e) above were cancelled after 30th July, 1952, from the places referred to in part (e) above to restore them to Patti Town; if so, their list and the provision of law under which these allotments were cancelled;

(g) whether any amendments to rule 14, sub-rule 6 of the Administration of the Evacuee Property Act have been made by the Union Government between 21st July, 1952 and 31st December, 1953; if so, copies of such amendments be laid on the Table;

(h) whether any instructions were received by the State Government from the Government of India regarding the implementation of the orders passed by the competent Rehabilitation Authorities which were not enforced between 15th May, 1952 and 31st December, 1953, if so, a copy of the same be laid on the Table ;

(i) whether any of the instructions referred to in part (h) above were transformed into rules under the Act referred to in part (g) above; if so, copies of such instructions and rules be laid on the Table?

Sardar Ujjal Singh: The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

ALLOTMENT OF LAND OF MUSLIM EVACUEE TENANTS IN TEHSIL PATTI.

***2538. Sardar Sarup Singh**: Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether there is any culturable evacuee area which is owned by non-Muslims but which was held by Mulsim occupancy tenants at village Margindpura, Tehsil Patti, District Amritsar; if so, its total;

(b) whether this area has been allotted to any displaced persons; if so, their list and the area allotted to each one of them;

(c) whether at the time of the allotment referred to in part (b) above any part of the said area was set apart for the owners referred to in part (a) above, and whether entry to that effect was made in the allotment *sanads* of each of the allottees; if so, the total of such area;

(d) (i) whether the possession of the area referred to in part (c) above has been delivered to its owners; if not, the reasons therefor;

(ii) the procedure, if any, laid down for the delivery of the possession to the owners in such cases;

(e) if the answer to part (d) (ii) above be in the negative, the purpose for which the entry for setting apart certain areas for the owners was made;

(f) whether any law has been passed since 15th August, 1947 bringing about any change between the relations of the landlords and the occupancy tenants of evacuee area; if so, when;

(g) if the answer to part (f) above be in the negative the provision of law under which the area referred to in part (c) was set apart for the landlords;

(h) the rent paid by the occupancy tenants of the area referred to in part (a) above to the land-owners together with the rate at which it is being paid; if none, the reasons therefor?

Sardar Ujjal Singh: The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

PRESENTATION OF APPLICATION REGARDING THE WITHDRAWAL OF POSSESSIONS OF LAND AT TOWN PATTI, DISTRICT AMRITSAR.

***2539. Sardar Sarup Singh**: Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any urgent application bearing No. 30735 was received at the Office of the Superintendent, Copying Branch, Organisation of Land Rehabilitation Department, Civil Secretariat, Jullundur, on 10th October 1953 for copies of orders passed by the Commissioner, Relief and Rehabilitation Department and the Director, Rehabilitation (Rural), regarding the withdrawal of possessions of land at Town Patti, District Amritsar;

(b) the date when this application was sent to the Officer Incharge, Records, by the Copying Branch;

(c) the date when the file concerned was received by the Copying Branch;

(d) the date when the required copies were prepared;

(e) (i) whether there was a delay of more than three months in the preparation of copies asked for; if so, the reason therefor;

(ii) the person responsible for this delay together with the action, if any, taken or proposed to be taken against him by the Government;

(f) the steps, if any, taken or proposed to be taken to avoid such delays in future;

[Sardar Sarup Singh]

(g) the maximum period fixed by the Government for the preparation of copies on urgent applications?

Sardar Ujjal Singh: The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

CHANDIGARH ALLOWANCE.

***2607. Shri Jagat Ram Bhardwaj**: Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any special Simla Allowance is being paid to all Government servants stationed at Simla; if so, the reasons therefor;

(b) whether he is also aware of the fact that living at Chandigarh is not cheaper than at Simla; if so, whether the Government has under consideration the payment of Chandigarh allowance to all Government servants stationed at Chandigarh?

Sardar Ujjal Singh: (a) Yes; the allowance is being paid to all non-gazetted Government servants and to gazetted Government servants drawing basic pay up to Rs. 350 per mensem with marginal adjustments in the case of those drawing pay exceeding Rs. 250 per mensem on account of the expensiveness of the locality.

(b) No; Chandigarh is cheaper than Simla. The level of prices at Chandigarh is not higher than some other towns in the plains.

CANCELLATION OF ALLOTMENTS OF LAND IN THE STATE

***2621. Sardar Chanan Singh Dhut**: Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the total number of allotments of land in the State which were cancelled;

(b) the number of allottees whose allotments were cancelled on their own requests;

(c) the total number of displaced persons who were reallotted lands afresh after the cancellation of their first allotments?

Sardar Ujjal Singh : (a), (b) and (c) : The required information is not readily available and in case an attempt is made to collect the same, the time and labour involved in the collection of data will not be commensurate with any possible benefit whatsoever.

PERMANENT ALLOTMENT OF LAND.

***2622. Sardar Chanan Singh Dhut**: Will the Minister for Finance be pleased to state whether the Government has decided to convert the quasi-permanent allotment of land to displaced persons into permanent allotment?

Sardar Ujjal Singh : The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

KAZI CINEMA, JULLUNDUR.

***2623. Sardar Chanan Singh Dhut**: Will the Minister for Finance be pleased to state whether it is a fact that Kazi Cinema, Jullundur, an Evacuee Property, is under the unauthorized occupation of Hakim Ganga Ram; if so, the action, if any, taken by the Government in the matter ?

Sardar Ujjal Singh: The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

ALLOTMENT OF EVACUEE HOUSES AT VILLAGES DHARAMPURA AND GOBINDGARH, DISTRICT FEROZEPORE.

***2676. Shri Teg Ram**: Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the total number of evacuee houses in villages Dharampura and Gobind Garh in Thana Abohar, District Ferozepore, together with the names of persons to whom these were allotted;

(b) whether he is aware of the fact that the local inhabitants have taken possession of these houses; if so, the action, if any, Government proposes to take to allot these houses to displaced persons?

Sardar Ujjal Singh: The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

ALLOTMENT OF LAND TO SARDAR BACHU SINGH IN VILLAGE MOTH, DISTRICT HISSAR.

***2714. Sardar Harkishan Singh Surjit** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the area of land allotted to Sardar Bachu Singh in Village Moth, Tehsil Hansi, District Hissar;

(b) the cut applied to the land owned by Sardar Bachu Singh in Pakistan;

(c) whether any complaints have been received by the Government that the area allotted to the said Sardar Bachu Singh is in excess of his land in Pakistan; if so, the action, if any, taken thereon?

Sardar Ujjal Singh: The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

ALLOTMENT OF EVACUEE HOUSES IN VILLAGE MOTH, DISTRICT HISSAR.

***2715. Sardar Harkishan Singh Surjit**: Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Evacuee Houses in Village Moth, Tehsil Hansi, District Hissar, have been allotted to only those refugees, who owned land and have been allotted land in the said village;

[Sardar Harkishan Singh Surjit]

(b) whether it is a fact that no tenant has been allotted any house in the said village; if so, the reasons therefor?

Sardar Ujjal Singh: The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

ALLOTMENT OF LAND TO DISPLACED PERSONS OF VILLAGE QADIWIND, DISTRICT LAHORE.

***2792. Shri Mani Ram**: Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the decision, if any, arrived at by the Government in the matter referred to in part (d) of Unstarred Assembly Question No. 339 printed in the list of Unstarred Questions, dated 11th March, 1953;

(b) whether any instructions have been issued by the Government to implement the decision referred to in part (a) above; if so, the copy of the instructions so issued be laid on the Table?

Sardar Ujjal Singh: The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

DISTRIBUTION OF MOVABLE EVACUEE PROPERTY IN THE STATE.

***2811. Sardar Achhar Singh Chhina**: Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the total amount of movable Evacuee Property distributed by the Village Committees amongst Refugees in rural areas of the State during the years 1947-48;

(b) whether any accounts were kept of the property thus distributed;

(c) whether it is a fact that the property so distributed has been converted into Taccavi Loans against the receivers;

(d) the total amount of such Taccavi Loans recovered by the Government so far;

(e) whether it is a fact that in the course of the recovery of these loans the Government had to confiscate the property of the refugees and take other necessary actions; if so, the number of cases in which property has been thus confiscated?

Sardar Ujjal Singh: The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

LEASING OUT OF 'BANJAR' EVACUEE LAND IN THE STATE.

***2823. Shri Wadhwa Ram** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether it is a fact that unallotted 'Banjar' Evacuee land in the State has been leased out by public auction; if so, the total area so leased out and the conditions of lease;

(b) whether he is aware of the fact that landless and poor peasants find it difficult to reclaim such land; if so, the action proposed to be taken by the Government in the matter?

Sardar Ujjal Singh: The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

ALLOTMENT OF DEFECTIVE OR ERODED LAND IN THE STATE.

***2824. Shri Wadhawa Ram**: Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the allottees to whom defective or eroded land was allotted in the State were debarred from having it exchanged after 23rd December, 1953;

(b) whether the Government intends to extend the time limit in the case of those allottees to whom eroded land or reverain tracts were allotted and in whose case exchange has not yet taken place?

Sardar Ujjal Singh: The information is being collected and will be supplied to the Member when ready.

SINGLE TEACHER AND DOUBLE TEACHER SCHOOLS.

***2579. Shri Rala Ram**: Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the district-wise number of single teacher schools and double teacher schools, respectively, opened by the Government in the State during the year 1953-54;

(b) the number of primary schools for girls started during the period mentioned in part (a) above?

Shri Jagat Narain: (a) During 1953-54 fourteen hundred single teacher primary schools were opened by Government through the District Boards in the State under the Government of India's Scheme " Programme to relieve educated unemployment ". In addition to this 200 additional teachers have been given to an equal number of schools which were actually started by the District Boards during 1952-53 and which in their course of development had become understaffed.

A statement showing the district-wise distribution of these schools is given below—

(b) All the schools referred to in para (a) above are co-educational.

[Minister for Education]

Serial No.	Name of District	No. of Schools opened during 1953-54	No. of additional teachers appointed during 1953-54
1	Ambala ..	108	20
2	Karnal ..	113	15
3	Rohtak ..	123	3
4	Gurgaon ..	123	13
5	Hissar ..	124	30
6	Ludhiana ..	98	20
7	Jullundur ..	118	11
8	Hoshiarpur ..	103	..
9	Amritsar ..	119	21
10	Ferozepore ..	118	21
11	Gurdaspur ..	119	26
12	Kangra ..	134	20
	Total ..	1,400	200

NATIONALISED BOOKS.

***2580. Shri Rala Ram**: Will the Minister for Education be pleased to state the total number of books nationalised till January, 1954 together with the number of nationalised books written by or allotted to the:—

Divisional Inspectors; Deputy Divisional Inspectors, District Inspectors; Additional District Inspectors; Teachers in Government Schools; Professors in Government Colleges; Deputy Director of Public Instruction; Director of Public Instruction and non-officials?

Shri Jagat Narain: 93. The requisite information is contained in the two lists given below:—

List showing names of Authors/others whose books have been selected under the scheme of Nationalisation of Books.

Serial No.	Name of the book.	Name and address of the author and co-author/others.	No. of of books
1	Hindi Reader for Class IV ..	Messrs Indian Press Limited, Nicholson Road, Ambala Cantt ..	1
2	Hindi ki Sahayak Pustak No. 1 for Class IV	Shri Ranbir Khanna, 15/91, Civil Lines, Ganges Bank, Kanpore ..	1

Serial No.	Name of the book	Name and address of the author and co-author/others	No. of books
3	Hindi ki Sahayak Pustak No. 2 and No. 3 for Class IV	Shri Ranbir Khanna, 15/91, Civil Lines Ganges Bank, Kanpore. Dr. S.N. Vohra, Government College, Rupar.	2
4	Punjabi Reader for Class IV ..	Dr. Gopal Singh Dardi, M.A., Ph.D., 7/30, Rup Nagar, Civil Lines, Delhi-8.	1
5	Punjabi Supplementary Readers I, II and III for Class IV	1. Shri Balwant Gargi, 27, Curzon Road, New Delhi. 2. Shri Teja Singh, M.A., 25, Race Course Road, Amritsar.	3
6	Arithmetic for Class IV ..	Shri Prem Chand Markanda, B.Sc., B.T., Head Master, D.S.S.D. High School, Jullundur City.	2
7	Sadharan Vigyan for Class IV	1. Professor Gurdial Singh Phool, M.A., Khalsa College, Amritsar. 2. Professor Ram Singh, M.Sc., Khalsa College, Amritsar. 3. Professor Narain Singh, M.Sc., Khalsa College, Amritsar.	2
8	Hindi Reader for Class VII ..	Principal Suraj Bhan, M.A., D.A.V. College, Jullundur City.	1
9	Hindi Regional Reader for Class VII	Shri Satya Kam Vidyalankar, Editor "Dharam Yug" Chandereshar Bhawan, Bombay-22.	1
10	Hindi Grammar for VII Class	Messrs Adhunik Prakashan Grih, 13, Strachy Road, Allahabad (U.P.).	1
11	Punjabi Reader for VII Class	1. Shri G.S. Talib, M.A., Principal, Lyallpur Khalsa College, Jullundur. 2. Shri Balwant Gargi, 27, Curzon, Road, New Delhi. 3. Shri Amrik Singh, M.A., Professor, G.T.B. College, Delhi.	1
12	Punjabi Regional Reader for VII Class	Shri Harnam Singh, B.A., Headmaster, Government High School, Dalhousie.	1
13	Punjabi Grammar for Class VII	Dr. Sher Singh Gyani, M.A., Ph.D., Government College, Ludhiana.	1
14	Sanskrit Book for Class VII ..	Shri Vishwa Bhandu Shastri, M.A., M.O.L., Director, V. Vedic Research Institute, Hoshiarpur.	1

Serial No.	Name of the book.	Name and address of the author and co-author/others.	No. of books
15	Arithmatic Book for Class VII ..	Messrs P. C. Dwadesh Shreni, Ltd., Aligarh (U.P.).	2
16	Geography book for Class VII	Shri Jawahar Singh, P.E.S. (Retired), C-8, Radio Colony, Delhi.	2
17	Sadharan Vigyan for Class VII	Messrs Indian Press Ltd., Nicholson, Road, Ambala.	2
18	English Reader and two Supplementaries for Class VIII ..	Mrs. A.E. Harper, M.A., Village School for Teachers. Moga (District Ferozepore).	3
19	English Grammar for Class VIII	Shri Chaman Lal, M.A., M.L.C., Headmaster, S.D.A.S. High School, Jullundur.	2
		Shri Mathra Dass Chopra, Senior English Teacher, S. D. A. S. High School, Jullundur.	
20	Social Sudies and Health Activities for VI Class	1. Shri B. N. Duggal, B.A., B.T., Headmaster, V.K.M. High School, Rohtak.	2
		2. Shri Pyare Lal Aggarwal, B.A., B.T., Kalalan Street, Rohtak.	
21	Social Studies and Health Activities for Class VII	Messrs Delhi and Punjab Publications, 1492, Gali Pipalanwali, Nai Sarak, Delhi.	2
*22	English Grammar for Class VII	Shri Ish Kumar, P.E.S., Government College, Ludhiana.	1
*23	Hindi Grammar for Class VI	Shri D. C. Sharma, Government, High School, Gurdaspur.	1
*24	Punjabi Grammar for VI Class	Shri Karam Singh Gangowala, Amritsar.	1
		Total	37

*These books were selected in 1952 and the authors have been paid suitable remuneration.

List of Authors selected by Government for writing books according to the detailed syllabi on the subjects reserved by it for classes noted against their names.

Serial No.	Names and address of editors and collaborators	Subject	Classes	No. of books written
1	Dr. P. N. Mehra, University Professor, Khalsa College, Amritsar (Editor).	Basic Craft (Agriculture)	I to V	8

Serial No.	Names and address of editors and collaborators	Subject.	Classes.	No. of books written
2	Shri Inder Singh, Khalsa College, Amritsar (Collaborator).	Basic Craft (Agriculture)	..	..
3	Shri Jagdish Raj, Headmaster, Basic Training School, Jagraon (Collaborator).	Ditto	..	..
4	Professor Guru Charan Singh, Inspector of Schools, Jullundur (Editor).	Agriculture with special reference to soil conservation measures	VI to VIII	6
5	Shri Isher Dass, care of Government College, Ludhiana (Collaborator).	Ditto	Ditto	..
6	Dr. S. K. Roy, Training School, Moga (Collaborator).	Ditto	Ditto	..
7	Miss M. Alfred, Senior Lecturer, Government College for Physical Education, Rupar (Editor).	Physical Education	I to V and VI to VIII	6
8	Shri Ram Rakha Mal, District Inspector of Schools, Jullundur (Collaborator).	Ditto	Ditto	..
9	Shri Sujan Singh, Government College, Rupar. (Collaborator)	Ditto	Ditto	..
10	Mrs. A. Dharni, Basic Training School, Jagraon (Editor).	Health and Social Activities	I and II	4
11	Dr. B. L. Kapur, Maternity Hospital, Ludhiana (Collaborator).	Ditto	Ditto	..
12	Miss H. Chowla, District Inspectress of Schools, Ferozepore (Collaborator).	Ditto	Ditto	..
13	Shri Sita Ram Kohli, M.A., P.E.S. (Retired), 19-A, Model Town, Rohtak (Editor).	Social Studies and Health Activities (excepting Geography)	III to V	6
14	Shri Jai Chand Vidyalankar, 49, Tagore Town, Allahabad-2 (Collaborator).	Ditto	Ditto	..
15	Shri K. L. Malhotra, M.A, P.E.S., Punjab University College, Hoshiarpur (Collaborator).	Ditto	Ditto	..
16	Professor Waryam Singh, M.A., M.L.C., Khalsa College, Hoshiarpur (Collaborator).	Ditto	Ditto	..
17	Shri Kishan Singh Thapar, M.A., P.E.S., Government College, Rohtak (Collaborator).	Ditto	Ditto	..

[Minister for Education]

Serial No.	Names and address of editors and collaborators.	Subject.	Classes.	No. of books written.
18	Shri G. D. Khanna, Professor Government College, Ludhiana (Editor).	Recreational Activities and also Guide Book	I to V	7
19	Mrs. A.E. Harpar, Training School, Moga (Collaborator).	Ditto	Ditto	..
20	Shri Atma Ram, Government Training College, Jullundur (Collaborator).	Ditto	Ditto	..
21	Mrs. S. Sehgal c/o Shri N. Sehgal, I.C.S., Deputy Secretary, Home Affairs, Government of India, New Delhi.	Ditto	Ditto	..
22	Shri Panna Lal, Madan, House No. 1080, Sudan Mahalla, Ludhiana (Collaborator).	Ditto	Ditto	..
23	Shri Jai Dyal, S.D. College Hoshiarpur (Collaborator.)	Ditto	Ditto	..
24	Professor I.C. Nanda c/o Bank of Rajasthan, Mirza Ismail Road, Jaipur (Collaborator).	Ditto	Ditto	..
25	Shri Harish Chander Bali, Mohalla Ballian, Jullundur (Collaborator).	Ditto	Ditto	..
26	Shri Atma Ram, Government Training College, Jullundur (Editor).	Drawing	VI to VIII	6
27	Shri K.K. Jeswami, Central Institution of Education, 33, Probyn Road, Delhi-9 (Collaborator).	Do	Ditto	..
28	Shri Harish Chander Bali, Mohalla Ballian, Jullundur (Editor).	Music	VI to VIII	6
29	Shri Sagar Pandit, Christ Church College for Women, Simla (Collaborator).	Do	Ditto	..
30	Shri B.D. Kaley Shastri, Christ Church College for Women, Simla (Collaborator).	Do	Ditto	..
31	Mrs. H.M. Ryburn, Christian High School, Kharar (Editor).	Tailoring	VI to VIII	2
32	Mr. Moses, Christian High School, Kharar (Collaborator).	Ditto	Ditto	..
33	Shri Ujagar Singh, M.A., LL.B., P.E.S. (Retired), formerly Inspector, Higher Education, PEPSU, Nabha.	Handbook of Social Workers	..	2

Serial No.	Names and address of editors and collaborators.	Subject.	Classes.	No. of books written
34	Shri Indar Singh, P.E.S. (Retired) (Collaborator)	Handbook of Social Workers.	..	..
35	Shri Dev Indar Lal, Senior Lecturer, Government Training College, Jullundur (Collaborator).	Ditto	..	..
36	Shri D.D. Mal, M.A., P.E.S. (Retired). 84, The Mall, Simla (Editor).	Teachers' guide book on Secondary Education.	Middle School teachers.	..
			Total ..	56

COMPLAINTS BY BOOKSELLERS.

***2581. Shri Rala Ram:** Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) whether he is aware of the large number of complaints made by the booksellers to the effect that in spite of their having deposited huge sums with the Controller of Printing and Stationery they did not get the required books for months together;

(b) whether he is also aware of the fact that small dealers got a large supply of books which they could not possibly dispose of while the big dealers remained clamouring for the supply of an adequate number of books;

(c) if the answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the steps Government proposes to take in the matter?

Chaudhri Sundar Singh: (a) Books were supplied to Booksellers according to the availability of stock;

(b) Books were supplied to the indentors whether big or small according to the availability of stock on the receipt of indents from the agents;

(c) Sale Depots for Text Books have been opened at Ambala and Jullundur in addition to the one at Chandigarh.

IMPLEMENTATION OF URBAN EMPLOYMENT SCHEME.

***2723. Shri Ram Kishan:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the number of one teacher primary schools so far opened by the Government in the State district-wise under the Government of India's Urban Employment Scheme;

[Shri Ram Kishan]

(b) the number of men and women teachers trained and untrained appointed in the schools mentioned in Part (a) above, respectively;

(c) whether any District Board in the State has withheld its co-operation with regard to the implementation of this Scheme;

(d) the total expenses so far incurred by the Government in this connection?

Shri Jagat Narain: (a) Probably the Hon. Member is referring to Government of India Scheme to relieve unemployment. A list of schools opened in the State under this scheme is given below:—

(b) Fourteen hundred teachers have been employed in the schools referred in part (a) above. In addition to this 200 additional teachers have been given to an equal No. of schools which were started by District Boards during 1952-53 and which in their course of development have been considered to be understaffed. It is not possible to indicate at this stage separately the number of men and women teachers and trained and untrained teachers employed so far. The information on the point is being collected.

(c) Hoshiarpur. Efforts are being made to overcome the difficulties.

(d) Rs 5,65,773 up to the close of the year 1953-54.

Serial No.	Name of District.		No. of Schools opened during 1953-54.	No of additional teachers appointed during 1953-54.
1	Ambala	..	108	20
2	Karnal	..	113	15
3	Rohtak	..	123	3
4	Gurgaon	..	123	13
5	Hissar	..	124	30
6	Ludhiana	..	98	20
7	Jullundur	..	118	11
8	Hoshiarpur	..	103	..
9	Amritsar	..	119	21
10	Ferozepore	..	118	21
11	Gurdaspur	..	119	26
12	Kangra	..	134	20
	Total	..	1,400	200

STARTING SALARY OF SENIOR TEACHERS.

*2934. **Shri Mool Chand Jain**: Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the starting salary of B.A., B.T. and M.A., B.T. Senior Teachers working in Government schools in the State;

(b) whether the Government has received any representations from the Teachers Union, Punjab, for giving better grades to the senior teachers; if so, the action taken by the Government on such representations;

(c) whether there is any proposal under consideration of Government for improving the grades of the said teachers; if so, the estimated additional expenditure likely to be incurred in this connection;

(d) whether he is aware that the senior teachers working in Government schools observed the 1st February of 1954 as a "Protest day" against the Government's indifferent attitude towards their reasonable demand; if so, the action, if any, proposed to be taken in the matter?

Shri Jagat Narain: (a) Rs. 90 per mensem in the grade of Rs 90—5—150 to the B.A., B.Ts./Rs 110 per mensem to M.A./M.Sc. III B.Ts. and Rs 120 per mensem to M.A./M.Sc. II B.Ts.

(b) Yes. The matter is under consideration.

(c) Does not arise in view of answer to 'b'.

(d) No. A news item was published in some papers that the Senior Teachers have decided to observe 1st February 1954 as a protest day.

CATTLE FAIR, PATAUDI, DISTRICT GURGAON

*2661. **Shri Babu Dayal**: Will the Minister for Public Works be pleased to state whether he is aware of the fact that the District Board, Gurgaon, has not implemented its resolution No. 6, dated the 5th June 1950, regarding the payment of 10 per cent of the cattle fair income of Pataudi to the Pataudi Small Town Committee; if so, the action, if any, taken by the Government in this respect?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa: The claim of the Town Committee, Patuadi, for a share of the income from cattle fairs held at Pataudi by the District Board, Gurgaon, is under examination.

ELECTIONS TO DISTRICT BOARD, GURGAON.

*2662. **Shri Babu Dayal**: Will the Minister for Public Works be pleased to state when the elections to the District Board, Gurgaon, are proposed to be held?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa: Elections to the various District Boards will be held as soon as possible after the necessary formalities regarding the finalization of the method of elections have been gone through.

COMPLAINTS OF CORRUPTION IN THE MUNICIPAL ENGINEERING DEPARTMENT, ROHTAK.

***2701. Pandit Shri Ram Sharma**: Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that complaints giving detailed information and references about corrupt practices in the Engineering Department of the Rohtak Municipality were recently made to the Administrator of the said Committee; if so, whether any enquiry was made into the said complaints;
(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the name of the person who was appointed to conduct the enquiry and whether he examined the material referred to in the complaints and any witnesses in this connection; if so, his recommendations?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa: The information is being collected and it will be supplied to the Member, when ready.

ELECTIONS TO MUNICIPALITIES IN THE STATE.

***2722. Shri Ram Kishan**: Will the Minister for Public Works be pleased to state the names of Municipalities in the State where elections have not been held so far together with the reasons for the delay and the steps, if any, Government intends taking for holding early elections in those places?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa: A statement of Municipal Committees where elections have not been held so far is given below.

Elections to these committees could not be held earlier as their wards have to be delimited on geographical basis which takes considerable time. Local officers have been asked to give top priority to the delimitation of wards so that elections can be held as soon as possible.

Names of Municipal Committees where elections have not been held so far.

1. Jullundur.
2. Khanna.
3. Jagadhri.
4. Ludhiana.
5. Kaithal.
6. Thanesar.
7. Rohtak.
8. Sonepat.
9. Ballbgarh.
10. Hissar.

CONSTRUCTION OF A BRIDGE OVER SWAN NADI.

***2928. Shri Mansa Ram Kuthiala:** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether he visited Una early in the year 1953 and inspected the site, under consideration, for the construction of a bridge over the Swan Nadi;

(b) whether the Government has examined the possibility of taking up the construction of the bridge (i) from State finance or (ii) by raising loan from the Public and by having a contributory bridge; if so, with what results?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa: (a) Yes.

(b) The possibility of a bridge over Swan Nadi near Una has been examined from time to time but owing to paucity of funds it cannot be provided in the near future. The estimated cost of the bridge is about 30 lakhs and public contributions, which cannot be substantial, will not help in a work of this size.

HOLDING OF DISTRICT BOARD ELECTIONS IN THE STATE.

***2933. Shri Mool Chand Jain :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether the Government has decided to hold District Board Elections in the State on the basis of panches as electors ;

(b) whether any date has been fixed for holding the District Board Elections ;

(c) whether he is aware of the persistent demand of the public that these elections should be held without delay ;

(d) whether he has received any representations that these elections should be held on the basis of adult franchise ;

(e) if the answers to parts (c) and (d) above be in the affirmative, the action, if any, Government propose to take in the matter ?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) to (e). Representations from different sources suggesting early elections to various District Boards have been received from time to time. Government are already quite alive to the need for immediate elections and these will be held as soon as possible after the necessary formalities regarding the finalization of the method of elections have been gone through.

LICENSED SHOPS OF LIQUOR, OPIUM AND CHARAS IN THE STATE.

***2674. Shri Teg Ram :** Will the Minister for Labour be pleased to state the total number of licensed shops of liquor, opium and charas that exist-

ed in the State during the year 1953 together with the total amount for which each of the above-mentioned shops was auctioned out ?

Chaudhri Sundar Singh :

		Liquor	Opium	Charas
First Part.	..	451	375	Nil
Second Part.	..	Rs 65,00,000	Rs 60,00,000	Nil

APPOINTMENT OF ASSISTANT PUBLICITY OFFICERS IN GURGAON DISTRICT.

***2663. Shri Babu Dayal Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state the qualifications prescribed by the Government for the posts of Assistant Publicity Officers in the Gurgaon District ?

Shri Bhim Sen Sachar : There are no Assistant Publicity Officers in the Gurgaon District.

POLICE ENCOUNTERS IN ROHTAK DISTRICT.

***2704. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the details of the Police encounters in which the proclaimed offenders, Chhaju at village Silana, Ram Singh at Kala at Village Mandothi and Chander at Gapper at village Ghulana, District Rohtak were shot dead ;

(b) the names of any other proclaimed offenders killed by the Police in Rohtak District during the last three years ;

(c) the rewards and commendations awarded by the Government to Policemen in this connection ;

(d) the punishments, if any, given to Policemen in this connection for failure in the discharge of their duty ?

Shri Bhim Sen Sachar : (a) A statement giving a brief account of these encounters is given below.

(b) Bhima, son of Jaggan Brahmin, resident of Kanoda, Police Station Bahadur Garh, was killed in a Police encounter during 1951. None was killed in 1952.

(c) None so far.

(d) Nil.

Statement giving a brief account of the encounters.

(a) (i) On the night between 22/23rd December 1953 at about 1-30 a.m. one Assistant Sub-Inspector and a Foot Constable while on patrol duty witnessed two persons stealthily crossing the Rohtak-Sonepat Road. They shadowed them until both the suspects entered a hut situated on the outskirts of village Silana. The Assistant Sub-Inspector took his position nearby. Early in the morning when both the persons came out of the hut they were challenged to stop but they opened fire on the Police. Both the Assistant Sub-Inspector and the Foot Constable fired in self-defence and shot dead one of them, while the other escaped through sugarcane fields. The dead body was later indentified to be that of Chhaju, a notorious proclaimed offender, resident of Pepsu, who was wanted in several murder and robbery cases of Rohtak and Pepsu.

(ii) On 18th January 1954 on receiving information that some outlaws were present in the house of Mula, Jat, of Village Mandhoti, the Station House Officer, Sampla, organised a raiding party and surrounded the house. One of the culprits named Ram Singh at Kala, resident of Jagsi, a Proclaimed offender in a murder case and a dangerous outlaw concerned, in other serious offences, challenged the Police and started firing at them. The house, had, therefore to be smoked in order to drive out the P.O. The outlaw came out and continued firing at the Police, but he was killed during the encounter. From the search of the house two other associates of the outlaw Dharama Beragi, resident of Billa, District Karnal, and Mange, resident of Garhi Bala, Police Station Rai, District Rohtak, were arrested.

(iii) Dharma accused, captured in the case mentioned in para (a) (ii) above was interrogated immediately, who revealed that Hem Raj outlaw, with Chand Ram at Gappar, residen of Jasia, Police Station Sadar Rohtak was hiding in Village Chuliana with Sube, Dipti and Ase of that village and that they would be in a sugarcane field. A raiding party was organised under the supervision of Deputy Inspector-General of Police, Ambala Range and the said field was surrounded. On 19th January 1954 at about 7.15 a m. Chand Ram outlaw armed with a pistol emerged from the field. On being challenged he started firing at the Police which returned the fire and he was shot dead at the spot. He was wanted in Khadwali double murder and Bhidhana murder case, wherein Randhir Singh (Clerk of Chaudhri Rizak Ram, Advocate and M.L.A.) was shot dead.

RESOLUTION PASSED BY BAR ASSOCIATION, ROHTAK.

***2775. Sardar Harkishan Singh Surjit :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Government has received the resolutions passed by the Bar Association, Rohtak in its meeting held on 5th February 1954, along with the report of the Sub-Committee of the Association on police atrocities committed in the village of Rohtak District ; if so, the action, if any, taken by the Government thereon ;

(b) whether the Government intends instituting an open and judicial enquiry into the excesses committed by the Police in the villages of Rohtak District as demanded by the said Bar Association ; if not, the reasons therefor ?

Shri Bhim Sen Sachar : (a) Yes. Immediately on receipt of the unsigned copies of Resolution, the Deputy Commissioner, Rohtak, and Superintendent of Police communicated with the Secretary, Bar Association, and requested him to furnish concrete instances of Police excesses and to give the names of Police Officers responsible for the same. It was requested further to furnish original material collected by the Bar to enable detailed inquiries. The Bar refused to furnish the original material or to cite concrete instances until judicial enquiry was instituted. As for the names of policemen responsible for it, it was said that none was given out to them.

The Deputy Inspector-General of Police, Ambala Range, Ambala Cantt., Deputy Commissioner, Rohtak, Superintendent Police, Rohtak and a 1st Class Magistrate have all personally visited villages concerned and that not one single specific instance of rape, molestation of women, beating, torture, or looting by the Police was brought to the notice of any of these officers either publicly or privately, openly or secretly.

(b) The Government do not consider it necessary to institute a separate judicial enquiry. Moreover, the allegations are subjudice in the cases registered already.

POLICE EXCESSES AT VILLAGE JAGSI, DISTRICT ROHTAK.

***2776. Sardar Harkishan Singh Surjit :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the date when Village Jagsi was raided by the Police in connection with the 'anti-dacoit operations' in District Rohtak ;

(b) the total number of persons arrested by the Police from the said village and the number of those who were asked to join investigation in connection with the arrest of the absconders ;

(c) whether he is aware of the fact that the inhabitants of the said village complained to the sub-committee of the Bar Association, Rohtak, that the Police while raiding the village beat them indiscriminately, molested the womenfolk and looted their property ; if so, the action, if any proposed to be taken by the Government in this connection ;

(d) whether it is a fact that 'Gur' belonging to the inhabitants of the said village was seized and sold to shopkeepers at Rs. 8-0-0 per maund ; if so, the reasons therefor ?

Shri Bhim Sen Sachar : (a) Villages Jagsi was raided by the Police on the following dates—

31st December 1953.

25th January 1954.

11th February 1954.

(b) Number of persons arrested for harbouring and receiving stolen property	..	12
Number of persons arrested for making assault on Police	..	34
Number of persons asked to join investigation	..	24

(c) Yes. Allegations were enquired into by very senior officers of Government including Deputy Inspector-General of Police, Ambala Range, Deputy Commissioner and Superintendent of Police, Rohtak. The allegations were found to be baseless.

(d) No.

SENDING OF SPECIAL POLICE FORCE TO ROHTAK.

***2777. Sardar Harkishan Singh Surjit :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any special police force was sent from Jullundur in the month of February 1954 to Rohtak ; if so, the reasons therefor ?

Shri Bhim Sen Sachar : Yes. Four Armed Reserves of I.S.I., 2 Head Constables and 25 Foot Constables each were sent to Rohtak from Jullundur Range, in the month of February 1954. These were sent in connection with operations against Hem Raj, Jat gang and other outlaws.

SEPARATION OF JUDICIARY FROM EXECUTIVE IN THE STATE.

***2797. Shri Teg Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any proposal for the separation of the judiciary from the Executive is under the consideration of the Government ; if so, the steps so far taken by the Government in this connection and the time by which the judiciary is likely to be separated from the Executive ?

Shri Bhim Sen Sachar : Yes. It is proposed to start the scheme under executive orders in the six districts of Gurgaon, Ambala, Simla, Jullundur, Hoshiarpur and Kangra. Details are being worked out by an Officer on Special Duty and the scheme will be implemented in consultation with the High Court, on receipt of the report of the Officer on Special Duty.

ANTI-DACOIT OPERATIONS IN ROHTAK DISTRICT.

***2813. Sardar Achhar Singh Chhina :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Anti-Dacoity Operations in District Rohtak were started in the month of January 1954, under his orders ; if so, the nature of the instructions given by him to the Police ;

(b) whether any complaints have been received by the Government about excesses committed by the Police in the course of the said operations ; if so, the action, if any, taken by the Government in the matter ?

Shri Bhim Sen Sachar : (a) The anti-dacoity measures in Rohtak District have been in operation since 1951, when two gangs of dangerous outlaws, known as Jat and Brahmin gangs came to notice. Punjab Police took intensive action in collaboration with the PEPSU Police, for their liquidation. A special mobile force comprising one Sub-Inspector, 2 Assistant Sub-Inspectors, 4 Head Constables and 37 Foot Constables was located in 62 villages in the district which were notorious for harbouring dacoits in September, 1951. In addition, a reserve of the Mounted Police comprising one Sub-Inspector, 2 Head Constables and 25 Foot Constables and a contingent of armed police from the P.A.P. comprising one Sub-Inspector, 7 Head Constables and 35 Foot Constables were also deputed. This force maintained a steady and vigorous pressure against dacoit gangs, and during 1951, 110 notorious harbourers were detained under the Public Defence Act. As a result, the Brahman gang and two members of the Jat gang, Dalia and Hazari, surrendered. Chandgi was killed in an encounter in 1952 by the PEPSU Police and Ram Kishan was killed by the Delhi Police in 1953. This crippled the Jat gang. But about the middle of 1953, Hem Raj reformed his gang and committed one murder in Sisana and a double murder in Village Khidwali in August 1953. The Police strength was supplemented with 2 Sub-Inspectors, 4 Head Constables and 50 Foot Constables in August 1953 and large scale raids on the houses of known harbourers in 23 villages all over the district were conducted immediately. 93 persons were arrested under the preventive sections of the Cr. P.C. In December 1953, the Hem Raj gang committed a daring broad-day light murder in Village Badhana in the presence of 2,000 persons. The anti-dacoity measures were further intensified and three extra armed reserves comprising 3 Sub-Inspectors, 6 Head Constables and 75 Foot Constables were sent to

[Chief Minister]

Rohtak in December 1953. But as the situation did not show any marked improvement and there was considerable nervousness and consternation in the district, it was deemed necessary to call a meeting to review the situation. Consequently a meeting was called by the Chief Minister on 4th January 1954 at which besides the Chief Minister, Minister for Industries and Power, Home Secretary, Inspector-General of Police, Deputy Inspector-General of Police, Ambala Range, Deputy Commissioner and Superintendent of Police, Rohtak, were present. The situation was discussed and the Chief Minister expressed his anxiety over it, and stressed the urgency for vigorous and well-planned action. The Deputy Inspector-General of Police, Ambala Range, was asked to personally organise and supervise the operations, and he was given a further assistance of one Deputy Superintendent of Police, 2 Sub-Inspectors, 4 Head Constables and 50 Foot Constables to reinforce the Police already in Rohtak. Vigorous well-planned action by the Police resulted in the liquidation of three outlaws, namely, Chhajju in December 1953, Ram Singh at Kala and Chander at Gappar in January 1954, and five others were arrested. 27 foreign made and 86 country-made illicit arms were recovered and 96 harbourers were arrested.

The above facts will show that the anti-dacoity operations were not started under the Chief Minister's order in January 1954, but have been in force ever since 1951.

(b) Yes. The Deputy Inspector-General of Police, Ambala Range, Deputy Commissioner and Superintendent of Police, Rohtak, have all personally visited the villages concerned and enquired into the allegations on the spot, but not a single specific allegation was brought to the notice of any of these officers either publicly or privately.

JOURNEYS PERFORMED BY CHIEF PARLIAMENTARY SECRETARY.

***2814. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that a Government Cheverolet car had been placed at the disposal of the Chief Parliamentary Secretary for his use ; if so, the total expenditure incurred on the journeys made by the Chief Parliamentary Secretary up to the end of February 1954, together with the purposes of journeys performed by him ?

Shri Bhim Sen Sachar : It is a fact that from time to time cars including a Cheverolet car have been placed at the disposal of the Chief Parliamentary Secretary for his use. The expenditure incurred on the journeys made by him till 28th February 1954 comes to about Rs. 4,000. The journeys performed were in connection with the work of the Chief Parliamentary Secretary.

POLICE EXCESSES IN THE VILLAGES OF DISTRICT ROHTAK.

***2815. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that several complaints were made to the Government against the police highhandedness in the Anti-Dacoity Operations in the villages of Rohtak district ; if so, the main allegation contained in these complaints ;

(b) the steps taken by the Government to ascertain the truth about the said complaints and with what results ;

(c) whether the Bar Association, Rohtak, approached the Government by forwarding resolutions passed by it on the report submitted to it by its Enquiry Sub-Committee ?

Shri Bhim Sen Sachar : (a) It is a fact that several complaints were received by Government making allegations of Police highhandedness in the course of Anti-Dacoity Operations in some villages of Rohtak District. The main allegations contained in these complaints were that the Police had molested and raped women and had also resorted to indiscriminate beating and to looting. All complaints received by Government were of a general and vague nature and no specific case of misbehaviour on the part of the Police has yet been brought to the notice of Government.

(b) The allegations have been enquired into on the spot by Senior officers of Government personally including Deputy Inspector-General of Police, Ambala Range, the Deputy Commissioner, Rohtak, the Superintendent of Police, Rohtak, and a 1st Class Magistrate of Rohtak. Results of the enquiries have shown that the allegations are without doubt unfounded and that not a single instance of rape, molestation of women, beating or loot was brought to notice of the enquiring officers either in public or in private, openly or secretly by any inhabitant of the villages concerned or by any other person. The enquiries have also made it clear that the complaints were submitted by interested parties in order to gain their private and political ends.

(c) The Bar Association, Rohtak, did approach the Government by forwarding to it a copy of its resolution passed on the report submitted to it by its Enquiry Sub-Committee.

RECOVERY OF COST OF POLICE POST FROM VILLAGE TARKHANWALA, DISTRICT FEROZEPORE.

***2827. Shri Wadhawa Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any punitive police post was posted at Village Tarkhanwala, Tehsil Fazilka, District Ferozepore, before the partition ;

(b) whether it is a fact that the whole of the population of the said village was Mohammadan and they have since migrated to Pakistan ;

(c) whether it is a fact that the expenses of maintaining this Punitive Police Post are now being realised by the Government from the refugees ; if so, the reasons therefor ?

Shri Bhim Sen Sachar : (a) No.

(b) No. The Mohammadans were the minority community in this village and they migrated to Pakistan.

(c) No. The cost now being realised from the inhabitants, including refugees , is in respect of the Punitive Police Post located with effect from 1st February, 1951.

ARMS LICENCES IN THE STATE.

***2935. Shri Mool Chand Jain :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the details of the instructions of the Government in the matter of granting and cancelling arms licences in the State ;

(b) whether he will lay a copy of these instructions on the Table ?

Shri Bhim Sen Sachar : (a) and (b). It is not in the public interest to disclose the information asked for. If, however, the Hon'ble member would like to bring to Government's notice any specifiic case or grievance, that would be duly looked into. The granting and cancelling of arms licences is governed by Rule 31 of the Indian Arms Rules, 1951 and Section 18 of the Indian Arms Act, 1878, respectively.

DACOITIES AND MURDERS IN THE STATE.

***2980. Shri Maru Singh Malik :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of cases of dacoities and murders registered in the State, district-wise, during the last five years ;

(b) the total number of absconders in each district of the State during the years from 1951 to 1954;

(c) the description of offences in which each of the said absconders was involved during the period mentioned in part (a) above ?

Shri Bhim Sen Sachar : The information in respect of this question is being collected and will be supplied to the member shortly.

PUNITIVE POLICE TAX IN ROHTAK DISTRICT.

***2981. Shri Maru Singh Malik :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total amount levied for punitive police on the inhabitants of Rohtak District during the years 1951, 1952 and 1953, respectively ;

(b) whether any distinction was made in regard to the levy of this tax ; if so, the reasons therefor ?

Shri Bhim Sen Sachar : (a) The total amount levied for punitive police on the inhabitants of Rohtak District during the years 1951, 1952 and 1953 was s. 1,51,688-6-0, Rs. 1,11,060 and Rs. 36,960, respectively.

(b) No distinction was made in regard to the levy of this tax. It was imposed on all the residents of the notified villages irrespective of caste and creed. In respect of mobile additional police post located on 62/18 villages of this district from 16th September, 1952 onwards, however, the punitive Police tax was imposed only on the land-holders of the villages concerned,

excluding the displaced persons. The reason for restricting the imposition of this tax on land-holders alone was that the displaced persons and the non-land-holders, in general, did not have any sympathies with the outlaws and proclaimed offenders, and they did not resort to harbouring them. The poor paying capacity of the non-land-holders and the displaced persons was also kept in view in making this distinction.

DETENTION OF PERSONS HARBOURING PROCLAIMED OFFENDERS IN ROHTAK DISTRICT.

*2982. **Shri Maru Singh Malik :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of cases registered in Rohtak District for harbouring proclaimed offenders during the years 1951, 1952, 1953 and 1954, respectively ;

(b) the total number of persons detained under the Preventive Detention Act for harbouring proclaimed offenders during the years 1951, 1952 and 1953, respectively ?

Shri Bhim Sen Sachar : (a) The number of cases registered in Rohtak District for harbouring proclaimed offenders is as under—

1951 ..	4
1952 ..	1
1953 ..	1
1954 (up to 28th February, 1954) ..	14

(b) The number of persons detained under the Preventive Detention Act in Rohtak District for harbouring Proclaimed Offenders is—

1951 ..	110
1952 ..	12
1953 ..	1
1954 ..	Nil

SUSPENSION OF DISTRICT AND TEHSIL PANCHAYAT OFFICERS.

*2995. **Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that several District and Tehsil Panchayat Officers were suspended during the last two years ; if so, the names of such officers and the period for which each of them has remained under suspension up to the end of February, 1954;

(b) the charges against those referred to in part (a) above together with the names of the officers who held enquiries against them and their findings in each case ;

[Maulvi Abdul Ghani Dar]

(c) the names of the officers who after reinstatement were posted back to the places from where they had been suspended, together with the reasons for doing so ?

Shri Bhim Sen Sachar : The required information is being collected and will be supplied to the member when ready.

COLLECTION OF RED CROSS FUNDS.

***2997. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Red Cross Funds in the State are largely collected by Government Officers in the Districts either through donations or by selling tickets for Red Cross Fairs ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative whether the Government has issued any instructions to its District Officers to collect funds for the Red Cross in the manner referred to above ; if so, a copy of such instructions be laid on the Table;

(c) whether the Government is aware of the fact that such officers collect these funds by official pressure ; if so, the action, if any, he proposes to take in the matter ?

Shri Bhim Sen Sachar : (a) Government officers in districts are permitted to associate themselves with the collection of funds for the Red Cross Society. It cannot be said if Red Cross Funds are largely collected by them. They are collected by donations, fairs, lucky bags, etc.

(b) There are no instructions of Government to District officers to collect funds for the Red Cross.

(c) The answer to the first part is in the negative and the second does not arise.

LEASING OUT OF VILLAGE FAIZGARH, DISTRICT FEROZEPORE.

***2825. Shri Wadhawa Ram :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Village Faizgarh, Tehsil Fazilka, District Ferozepore has been leased out on instalments at Rs. 14,000 per annum for five years ;

(b) whether it is a fact that the Government has changed the terms of the lease referred to in part (a) above by increasing the yearly instalment from Rs. 14,000 to Rs. 30,000 ; if so, the reasons therefor ?

Sardar Ujjal Singh : The information is being collected and will be supplied to the Member, when ready.

OWNERSHIP RIGHTS OF OCCUPANCY TENANCIES.

***2826. Shri Wadhawa Ram :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether it is a fact that in case of those local Zamindars whose occupancy tenants were Muslims, their ownership rights are still being honoured in the State ;

(b) whether it is a fact that the Local Landlords demand batai at the same rate from their tenants as they did from their former Muslim occupancy tenants ;

(c) the date when the proprietary rights of such owners will cease to exist ?

Sardar Ujjal Singh : The information is being collected and will be supplied to the Member, when ready.

COMMUNITY PROJECT AND EXTENSION SERVICE BLOCKS IN THE STATE.

***2937. Shri Mool Chand Jain :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the total amount of money sanctioned by the Government for each (i) Community Project Block and (ii) Extension Service Block in the State ;

(b) the period within which this amount has to be spent ;

(c) the amounts allocated to various heads, namely (i) Agriculture, (ii) Health, (iii) Cottage Industries, (iv) Education and (v) Communications, etc. for each year ;

(d) whether the amounts allocated for cottage industries in each block were spent in time ; if not, how much of it remains unspent and the reasons therefor ;

(e) whether it is a fact that funds allocated for the development of cottage industries are being diverted to other heads ; if so, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon (a) (i) The total amount of money sanctioned in case of each Community Project/Block is as under:—

		Amount in lakhs.	
		Grant	Loan
1. Community Project, Batala	..	31·09	27·49
2. Community Project, Nawanshahr	..	33·21	29·82
3. Community Project, Sonepat	..	31·26	23·92

[Minister for Development]

	Amount in lakhs.	
	Grant	Loan
4. Community Project, Jagadhri ..	33·82	24·00
5. Community Project, Faridabad ..	22·60	19·93
6. Community Block, Nilokheri ..	14·53	7·78
7. Community Block, Kulu ..	7·51	7·49
8. Community Block, Tarn Taran ..	7·51	7·49
9. Community Block, Thanesar ..	7·51	7·49
10. Community Block, Naraingarh ..	7·51	7·49

(ii) The total amount of money sanctioned for each Extension Service Block is given below:—

	Amount in lakhs.	
	Grant	Loan
1. National Extension Service Block, Hansi ..	3·50	4·00
2. National Extension Service Block, Gurgaon	3·50	4·00
3. National Extension Service Block, Gahla ..	3·50	4·00
4. National Extension Service Block, Samrala	3·50	4·00
5. National Extension Service Block, Una ..	3·50	4·00
6. National Extension Service Block, Nurpur ..	3·50	4·00
7. National Extension Service Block, Moga ..	3·50	4·00

(b) Three years.

(c) The amounts allocated to various heads in Community Projects for the years 1952-53, 1953-54 and 1954-55 are given below:—

——	*Amount in lakhs.*					
	1952-53		1953-54		1954-55	
	Grant	Loan	Grant	Loan	Grant	Loan
1. Agriculture ..	1·50	..	7·62	1·73	8·32	4·73
2. Health ..	1·51	..	16·63	..	15·16	..

—	Amount in lakhs.					
	1952-53		1953-54		1954-55	
	Grant	Loan	Grant	Loan	Grant	Loan
3. Cottage Industries ..	0·25	..	2·12	4·42	4·46	7·46
4. Education ..	0·30	..	10·80	..	11·92	..
5. Communications ..	0·23	..	37·14	..	22·62	..

In so far as National Extension Blocks are concerned, no such separate allocation has been made. The consolidated budgets in respect of the National Extension Service Blocks are still to be approved.

(d) The amounts allocated for Cottage Industries could not be utilized in the past as the integrated programme in this regard pertaining to each project area was to be first approved by the Community Project Administration, Government of India. Now that the integrated programmes are being approved by them, the funds sanctioned for Cottage Industries will be utilized in full.

(e) No.

PROGRESS MADE IN THE COMMUNITY PROJECT AREAS.

***2999. Shri Dharam Vir Vasisht :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the progress so far made by the Government in the Community Project Areas in the State with particular reference to Irrigation, Communications, Education, Health, Agriculture and Village Industries ;

(b) whether the targets fixed in each particular case have been achieved ; if not, the reasons therefor ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) A statement on the progress of work under major schemes in the Community Development Programme is given below.

With regard to Village Industries no accurate statistical information can be supplied. Demonstration Parties are at work in rural areas imparting training in various crafts, and these training courses are of varying durations.

(b) Targets in respect of Community Development Programme have to be realised over a period of three years. Work in all Projects, except Faridabad, started in October, 1952. In the case of Faridabad Project, it started in April, 1953. Targets are expected to be realised before the expiry of the scheduled period. Work is generally progressing satisfactorily ; and where the progress is slow, steps are being taken to accelerate the work.

Progress of work under major schemes of Community Projects up to 31st January, 1954.

——	Sonepat	Jagadhri	Nawanshahr	Nilokheri	Batala	Faridabad	Total
I. AGRICULTURE							
1. Seeds distributed (Mds) ..	2,685	4,386	3,380	5,918	9,310	2,507	28,186
2. Fertilizers distributed (Mds) ..	3,875	8,117	31,386	1,969	11,887	1,662	58,896
3. Model Farms established ..	114	102	735	26	44	64	423
4. Demonstration held ..	690	994	1,692	2,037	4,165	1,116	10,694
5. Areas deratted (Acres) ..	7,636	43,586	51,058	10,686	98,404	42,732	254,102
II. IRRIGATION							
1. Wells repaired ..	125	36	216	21	20	140	558
2. Wells constructed ..	70	13	14	35	2	17	151
3. Pumping sets installed ..	1	4	16	17	92	..	130
4. Tube-ewlls sunk ..	1	53	1	15	..	..	70
III. LAND RECLAMATION							
1. Area reclaimed (Acres) ..	2,407	3,048	2,337	2,995	113	16,476	27,376
2. Area cleared of weeds (Acres) ..	46,278	25,275	126,041	55,068	29,408	30,460	312,530
IV. ANIMAL HUSBANDRY							
1. Animals vaccinated or inoculated ..	108,682	56,993	127,170	44,245	46,504	25,640	409,234
2. Animals castrated ..	14,240	3,981	4,614	2,775	2,307	6,042	33,959

—		Sonepat	Jagadhri	Nawanshahr	Nilokheri	Batala	Faridabad	Total
V. HEALTH								
1. Persons vaccinated	..	20,320	..	21,059	8,697	..	..	50,076
2. Health and First Aid Centres opened	..	46	..	19	13	7	1	86
3. Maternity cases attended	..	703	848	953	256	615	28	3,403
4. Dais enrolled or trained	..	127	215	138	76	118	45	719
VI. SANITATION								
1. Drains constructed (C.Ft)	..	17,550	14,006	72,648	10,208	40,674	..	155,086
2. Streets paved (Sq.ft)	..	663,625	7,035	226,456	31,442	138,254	23,500	1,190,312
3. Wells purified	..	98	455	2,659	976	105	357	4,650

VII. COMMUNICATION

		Sonepat	Jagadhri	Nawanshahr	Batala	Nilokheri	Faridabad	
1. Kacha Roads constructed (Miles)	..	$58\frac{1}{2}$	$78\frac{1}{8}$	132	$247\frac{1}{8}$	$18\frac{3}{4}$	48	$582\frac{1}{2}$
2. Pucca Roads constructed (Miles)	..	..	$\frac{3}{4}$ miles plus 4 miles by District Board	1	..	7 (Earthwork)	$32\frac{1}{2}$ (Earthwork) (4 miles consolidated)	$41\frac{1}{4}$ plus 4 miles by District Boards

——	Sonepat	Jagadhri	Nawanshahr	Batala	Nilokheri	Faridabad	Total
VIII. EDUCATION							
1. School building donated or constructed/ under construction ..	15	29	22	60	3	..	129
2. Schools for children ..	22	27	51	48	29	..	177
3. Adult Literacy Centres ..	114	46	37	56	19	30	302
4. Attendance in Adult Centres ..	2,412	1,067	989	968	Not available	570	6,006
5. Child Welfare Centres ..	52	3	3	..	8	..	66
6. Reading Rooms ..	20	26	31	40	10	..	127

CONFERENCE OF PROJECT OFFICERS AND DEVELOPMENT COMMISSIONERS AT BATALA.

*3000. **Shri Dharam Vir Vasisht :** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Project Officers and the Development Commissioners of Punjab, Pepsu, Himachal Pradesh and Delhi, etc., recently met in a conference at Batala, District Gurdaspur and arrived at certain decisions about the administration of Projects ;

(b) the nature of the decisions arrived at and the extent to which the Punjab Government proposes to have them implemented ?

Sardar Partap Singh Kairon : (a) Yes.

(b) Questions relating to people's participation including role of Panchayats, Co-operatives and Project Advisory Committees, Social Education, technique of reporting progress and Administration including Administrative co-ordination were discussed in the conference. The regional Conference was organised by the Community Projects Administration, Government of India, with a view to provide an opportunity to the workers in the field to exchange their experience, take stock of the work done, discuss ways and means to overcome the difficulties and to seek a solution of the problems faced by them in carrying out the Community Development Programme in their respective areas. The Punjab Government proposes to implement the decisions taken at the Conference in full.

IRRIGATION FACILITIES IN HOSHIARPUR DISTRICT.

*2609. **Shri Jagat Ram Bhardwaj :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that even though the Nangal Canal Head Works is situated in the district of Hoshiarpur the vast areas of this district will not be benefited by the water from its canals ;

(b) whether he is also aware of the great demand of the farmers of the said district for the construction of tube-wells, and the supply of electricity for irrigation purposes ;

(c) if the answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the steps, if any, Government proposes to take in the matter ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) It is proposed to give restricted perennial irrigation to the feasible areas of Hoshiarpur District, from Nangal to Rupar, between the river and the Nangal Hydel Canal. Whether it will be lift or flow irrigation, will be determined on receipt of the contoured plans of the area in question from the Survey of India.

(b) There is no such specific demand by the zamindars for the construction of tube-wells and supply of electricity for irrigation of the areas through which the canal passes. Six exploratory tube-wells are, however, likely to be installed in Una, Garhshankar, Dasuya and Hoshiarpur Tehsils.

(c) As at (a) and (b) above.

ACQUISITION OF LAND IN VILLAGE LOHAR MAJRA KHURD, DISTRICT LUDHIANA.

***2626. Sardar Chanan Singh Dhut :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state—

(a) the total area of land acquired by the Irrigation Department in Village Lohar Majra Khurd, Tehsil Samrala, District Ludhiana, for a Rajbah from Ram Garh to Kheri on the Bhakra Main Line ;

(b) the total amount of compensation assessed to be paid to the owners for the land thus acquired together with the amount paid so far ;

(c) whether he is aware of the fact that the Executive Engineer, 1st Division, Bhakra Main Line, Rupar, has refused permission to the residents of the said village to dig a khal under the minor (Rajbah) referred to above ; if so, the reasons therefor ;

(d) whether it is also a fact that the land revenue for the land already acquired by the Irrigation Department is being charged from the original owners of the land referred to above; if so, the reasons therefor ?

Chaudhri Lahri Singh : (a) 6.84 acres.

(b) Compensation to be paid has not yet been assessed by the Land Acquisition Officer.

(c) No application for the construction of a well watercourse crossing the minor was received by the Executive Engineer, 1st Division, from the villagers of this village. However, an application from Shri Karnail Singh, son of Shri Dhir Singh, was rejected as the necessity for construction of a well watercourse crossing the minor was not considered essential. The areas served by the minor from the well will receive canal irrigation. Besides the owners will be paid severance allowance.

(d) Yes, since the acquisition proceedings culminating in the payment of compensation have not yet been completed. The land revenue paid by the owners from the time of taking possession of the land to the time of announcement of Award will be refunded at the time of payment of compensation.

LABOUR RATES ON BHAKRA CANAL.

***2836. Sardar Achhar Singh Chhina :** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether it is a fact that labour rates for workers on Bhakra Canal in Pepsu Territory are higher than those in Punjab ; if so, the exact difference and the reasons therefor ?

Chaudhri Lahri Singh : It is not a fact that labour rates for workers on Bhakra Canal in Pepsu Territory are higher than those in Punjab.

ISSUING OF ALLOTMENT SANADS.

***2540. Sardar Sarup Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any allotment sanads bearing Nos. Am/3/314/59, Am/3/314/57, Am 3/314/58 and Am 3/314/46, were issued by the Revenue Assistant, Amritsar, during the month of February 1952 and delivered to Sardar Natha Singh, son of Fateh Singh, Asa Singh, son of Natha Singh, Sohan Singh, son of Natha Singh, and Narain Singh, son of Boota Singh, of Village Kot Mohammad Khan, Tehsil Tarn Taran, District Amritsar ; if so, the dates when they were delivered to the said allottees ;

(b) (i) whether any representations from the allottees referred to in part (a) above were received by the District Rehabilitation Authorities for the delivery of possession of the areas allotted to them after the receipt of their allotment sanads ; if so, when ;

(ii) the action, if any, taken by the Authorities in the matter ;

(c) whether the possession of the areas allotted was delivered to the allottees concerned before 22nd July 1952 ; if not, the reasons therefor ;

(d) whether any writ petitions were filed by any persons against the allottees referred to in part (b) above in the High Court at Simla and stay orders secured ; if so, the date or dates when these stay orders were received and complied with ;

(e) the decision of the High Court in these cases ;

(f) whether after the decision of the High Court any applications from the allottees referred to in part (a) above were received by the District Rehabilitation Authorities of Amritsar District for the delivery of possession of the areas allotted to them in the month of November or December 1953 ; if so, the action, if any, taken by the said authorities in the matter ;

(g) whether any instructions were issued by the Government to the Rehabilitation Officers on 24th July 1952, for guidance in the matters like the ones referred to above ; if so, a copy of these instructions be placed on the Table ?

Sardar Ujjal Singh : The information is being collected and will be supplied to the Member, when ready.

APPLICATIONS REGARDING THE ALLOTMENT OF LANDS RECEIVED FROM DISPLACED PERSONS.

***2541. Sardar Sarup Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the number of applications regarding the allotment of lands received by the Director, Rehabilitation (Rural), at Civil Secretariat, Jullundur, between 1st June 1953 and 31st December 1953 from displaced persons ;

[Sardar Sarup Singh]

(b) (i) whether these applications were sorted out to be dealt with; if so, the number of categories in which these were divided;

(ii) the number of applications of each category;

(c) whether any action has up to 7th January 1954 been taken on any of the applications; if so, their number and the nature of the action taken;

(ii) the number of applications finally disposed of up to 7th January 1954 ?

Sardar Ujjal Singh : (a) 10,338

(b) (i) Yes in four categories.

(ii)	Unsatisfied	..	6,487
	Land Rights	..	3,192
	Change of allotment	..	277
	Complaints	..	382
		Total	10,338

(c) Yes. Applications as under have been dealt with and disposed of—

(1)	Unsatisfied claims	..	3,090
(2)	Complaints	..	382
(3)	Change of allotment	..	217

(ii) 3,689.

EVACUEE CULTURABLE AREA AT VILLAGE SUR SINGH, TEHSIL PATTI, DISTRICT AMRITSAR.

***2542. Sardar Sarup Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the total evacuee culturable area in Village Sur Singh, Tehsil Patti, District Amritsar, owned by the Muslims excluding the area held by non-Muslim occupancy tenants;

(b) the total evacuee culturable area in the said village owned by the Muslim evacuees, but held by the non-Muslim occupancy tenants;

(c) whether any instructions regarding the procedure to be adopted about the allotment of area owned by Muslim evacuees, but held by non-Muslim occupancy tenants, were issued by the Government during the quasi-permanent allotment of land; if so, a copy of these instructions be laid on the Table;

(d) whether during the quasi-permanent allotment the area referred to in part (b) above was proportionately allotted to the allottees of the said village ; if not, the reasons therefor ;

(e) the number of the allottees who have been allotted land in Village Sur Singh referred to in part (a) above ;

(f) (i) the list of persons to whom the area referred to in part (b) above has been allotted ;

(ii) the total area allotted to those referred to in part (f) (i) out of the area referred to in part (b) above ?

Sardar Ujjal Singh : The information is being collected and will be supplied to the Member, when ready.

ALLOTMENT OF HOUSES AT VILLAGE PAOUT, DISTRICT LUDHIANA.

***2625. Sardar Chanan Singh Dhut :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether it is a fact that 14 houses have been allotted to one Harnam Singh, son of Takhat Singh Arora and his family in Village Paout, Tehsil Samrala, District Ludhiana ;

(b) whether he is aware of the fact that the said Harnam Singh is not an allottee of Village Paout, but that of Village Chuharpur, Tehsil Samrala, District Ludhiana ;

(c) whether he is also aware of the fact that a number of allottees of Village Paout referred to above have not been allotted any houses so far ; if so, the action, if any, proposed to be taken by the Government in the matter ?

Sardar Ujjal Singh : The information is being collected and will be supplied to the Member, when ready.

SHRI MOHAMMAD UMAR OF VILLAGE DHAUJ, DISTRICT GURGAON.

***2665. Shri Babu Dayal Sharma :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that one Shri Mohammad Umar, son of Shri Ismail Khan, of Village Dhauj, Tehsil Ballabgarh, District Gurgaon, has been deprived of his land on the basis of a false entry in the papers to the effect that he has gone to Pakistan, by a Patwari ;

(b) whether any representation in this connection was received by the Deputy Commissioner, Gurgaon ;

(c) if the answers to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the action, if any, taken by the Government in the matter ?

Sardar Ujjal Singh : The information is being collected and will be supplied to the Member, when ready.

MUD HUTS IN THE STATE.

*2725. **Shri Ram Kishan** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether the right of ownership in mud huts constructed by the Government in the State has been transferred to their occupants ; if so, the number of such owners in the State colony-wise ;

(b) the number of mud huts where full rights of ownership have not been given together with the reasons therefor ;

(c) the amenities in the shape of roads, schools, water, sanitation, bathrooms, latrines and community rooms provided in each colony by the Government before or after transferring the said rights of ownership ;

(d) whether the Government intends to make more mud huts in the State ; if so, the number and places where these mud huts are proposed to be constructed.

(e) whether he received during his recent tour in the State any memorandum from or deputation of the colonists of the mud huts referred to above in connection with their demands ; if so, their demands and the action, if any, taken thereon ?

Sardar Ujjal Singh : The information is being collected and will be supplied to the Member, when ready.

CHECKING OF THE ALLOTMENT OF CULTURABLE EVACUEE LANDS IN RURAL AREAS OF THE STATE.

*2795. **Shri Mani Ram** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether any staff or agency was set up by the Government during the year 1952 or 1953 to check the allotment of culturable evacuee lands in the rural areas of the state ; if so, its strength ;

(b) the period of its working ;

(c) whether any area was made available for allotment on the report of this agency ; if so, its total ;

(d) whether the staff or agency referred to in part (a) above was brought to an end without checking the whole of allotted evacuee area; if so, the reasons therefor ;

(e) the number of localities checked by this agency in each district of the State before its final wind up ; together with the dates when it started and when it stopped its work in each district ;

(f) (i) the other procedure that has been followed or is proposed to be followed to find out excess in the allotments of culturable area after the winding up of this agency ;

(ii) whether the check of allotment referred to in unstarred Assembly Question No. 468 printed in the list of unstarred questions, dated 28th September 1953, has been completed ; if so, with what results ;

(iii) whether the persons referred to in part (b) of unstarred Assembly question No. 486 have been allotted any culturable area either in the village referred therein or in any other village ; if so, where, if not, the reasons therefor ?

Sardar Ujjal Singh : The information is being collected and will be supplied to the Member, when ready.

JAMABANDI RECORDS OF VILLAGE KHARA, DISTRICT LAHORE.

***2796. Shri Mani Ram :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the names of the share-holders of Khata No. 13 (thirteen) entered in the Jamabandi records of Village Khara, Tehsil Kasur, District Lahore, for the year 1946-47 ;

(b) the shares of each of the persons referred to in part (a) above as entered in the Jamabandi records received from Pakistan Government ;

(c) the culturable area owned by each one of them in the village ;

(d) the culturable area of this village which was taken into consideration for assessing the value of the land for allotment purposes to each of the persons referred to in part (a) above and the value assessed in each of these cases ;

(e) whether any of the persons referred to in part (a) above was allotted any culturable area in Village Gharyala, Tehsil Patti, District Amritsar, during the quasi-permanent allotment ; if so, their list and the area allotted to each one of them in the first instance in lieu of the area owned by each one of them in the village referred to in part (a) above ;

(f) (i) whether any of the above persons had filed their review applications with the Rehabilitation Authorities, Amritsar, for rectification of the mistakes in the calculation of the area owned by them in the village referred to in part (a) above ; if so, the action taken in the matter in the light of the orders passed by the Deputy Commissioner, Amritsar, or Director-General, Rehabilitation, Jullundur, on their review applications ;

(ii) the total area allotted to each one of them after the acceptance of their review applications ;

(g) (i) whether any action has been taken by the Government on the representation of the persons referred to in Starred Assembly Question No. 1114, printed in the list of questions, dated 30th October 1952, whose files were lost in transit or otherwise ; if so, the nature of the action taken ; if not, the reason therefor ;

[Shri Mani Ram]

(ii) the nature of the orders passed by the Director-General, Rehabilitation, on the files referred to in part (g) (i) above and the steps, if any, so far taken for their implementation ;

(h) (i) whether any of the persons referred to in part (a) above has been allotted less area than that to which he was entitled; if so, their list and the reasons for treating their cases on a different footing from those of the other co-sharers of their khata on the authority of one and the same revenue records ;

(ii) the steps that have been taken or are proposed to be taken to rectify the mistakes referred to in part (h) (i) above; if not, the reasons therefor ?

Sardar Ujjal Singh : (a) The names of share-holders of Khata No. 13 are—

1. Inder Singh, son of Dhayan Singh.
2. Sham Singh, son of Jaimal Singh.
3. Sunder Singh, son of Jaimal Singh.
4. Surain Singh, son of Hakam Singh.
5. Wassan Singh, son of Hakam Singh.
6. Gurbux Singh, son of Ajaib Singh.
7. Sucha Singh, son of Ajaib Singh.
8. Sunder Singh, son of Jawala Singh.
9. Isher Singh, son of Jawala Singh.

(b) The shares of the persons referred to in part (a) above are—

Serial No.	Name of the person.	Share.
1	Inder Singh, son of Dhayan Singh ..	1/16
2	Sham Singh, son of Jaimal Singh ..	1/16
3	Sunder Singh, son of Jaimal Singh ..	1/16
4	Surain Singh, son of Hakam Singh ..	1/48
5	Wassan Singh, son of Hakam Singh ..	1/24
6	Gurbux Singh, son of Ajaib Singh ..	1/24
7	Sucha Singh, son of Ajaib Singh ..	1/24
8	Sunder Singh, son of Jawala Singh ..	1/3
9	Isher Singh, son of Jawala Singh ..	1/3

(c) The details of the culturable area owned by each one of them in this village are—

Serial No.	Name of the person.	Area		
		A.	K.	M.
1	Inder Singh, son of Dhayan Singh ..	20	0	17
2	Sham Singh, son of Jaimal Singh ..	18	5	18
3	Sunder Singh, son of Jaimal Singh ..	8	3	0
4	Surain Singh, son of Hakam Singh ..	2	6	7
5	Wassan Singh, son of Hakam Singh ..	5	4	13
6	Gurbux Singh, son of Ajaib Singh ..	10	7	3
7	Sucha Singh, son of Ajaib Singh ..	10	7	5
8	Sunder Singh, son of Jawala Singh ..	57	5	3
9	Isher Singh, son of Jawala Singh ..	79	5	10

(d) The details of culturable area and the value assessed are—

Serial No.	Name of the person.	Area.			Value assessed		
		A.	K.	M.	S.	As.	U.
1	Inder Singh, son of Dhayan Singh ..	20	0	17	9	7½	
2	Sham Singh, son of Jaimal Singh ..	18	5	18	8	15	
3	Sunder Singh, son of Jaimal Singh ..	8	3	0	5	3¼	
4	Surain Singh, son of Hakam Singh ..	2	6	7	1	11	
5	Wassan Singh, son of Hakam Singh ..	5	4	13	3	6	
6	Gurbux Singh, son of Ajaib Singh ..	10	7	3	7	7	
7	Sucha Singh, son of Ajaib Singh ..	10	7	5	7	7	
8	Sunder Singh, son of Jawala Singh ..	57	5	3	46	4	
9	Isher Singh, son of Jawala Singh ..	79	5	10	54	8¼	

[Minister for Finance]

(e) The list of the persons referred to in part (a) above who have been allotted land in Village Gharyala, Tehsil Patti, District Amritsar, in lieu of their land of Village Khara is as under—

Serial No.	Name of the person.		Area allotted. S.A.	U.
1.	Sham Singh, son of Jaimal Singh	..	16	½
2.	Wassan Singh, son of Hakam Singh	..	9	2¼
3.	Inder Singh, son of Dhayan Singh	..	19	2¾

The allotments have been made after consolidating their holdings of other villages, namely, Laliani, etc. etc.

(f) (i) Review applications from Inder Singh, son of Dhayan Singh and Wassan Singh, son of Hakam Singh, were received. As according to the jamabandi previously received the chhant was correctly prepared in the name of Inder Singh, son of Dhayan Singh, no action was needed on his request. On the application of Wassan Singh, son of Hakam Singh, his case was enlisted for comparison with the original record at Wagha. The jamabandi of Village Khara has recently been received after comparison and as such the case is under action.

(ii) As above.

(g) (i) As in (f) (i) above.

(ii) As above.

(h) (i) Yes, the list is as under:—

Serial No.	Name of the person.
1.	Inder Singh, son of Dhayan Singh.
2.	Sham Singh, son of Jaimal Singh.
3.	Sunder Singh, son of Jaimal Singh.
4.	Surain Singh, son of Hakam Singh.
5.	Wassan Singh, son of Hakam Singh.

As the entries of the jamabandi previously received from Pakistan were incomplete and incorrect, the above-mentioned persons were allotted less area.

(ii) The jamabandi entries have been got compared with the original record at Wagha and according to that chhant jamabandi for this khata is to be prepared afresh and as soon as it is completed, adjustment in the accounts of the persons concerned would be made.

RETRENCHMENT IN THE REHABILITATION DEPARTMENT.

***3001. Shri Dharam Vir Vasisht:** Will the Minister for Finance be pleased to state whether the Government has further retrenched some staff of the Rehabilitation Department; if so, the nett saving to the State Revenues on that account during the year 1953-54?

Sardar Ujjal Singh: The information is being collected and will be supplied to the Member, when ready.

GOVERNMENT STIPENDS FOR GIRLS AND BOYS.

***2582. Shri Rala Ram:** Will the Minister for Education be pleased to state whether he is aware of the fact that the rate of Government stipends for girls and boys getting the same number of marks in a University Examination are different; if so, whether the Government proposes to take steps to equalise the amount of the stipends for both boys and girls?

Shri Jagat Narain: Yes, the rate of scholarships awarded to girls and boys is different. There is no proposal before the Government to equalise the scholarhsips.

GOVERNMENT COLLEGE, HOSHIARPUR.

***2610. Shri Jagat Ram Bhardwaj:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether the Government College, Hoshiarpur, is also called the University College;

(b) the authority which controls the said college?

Shri Jagat Narain: (a) Yes.

(b) The Punjab University.

The members of the staff of the college who are on deputation from Government are, however, under the administrative control of the Punjab Government for purposes of promotion, transfer, etc.

AYURVEDIC SYSTEM OF MEDICINE.

***2611. Shri Jagat Ram Bhardwaj:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether he is aware of the fact that 90 per cent of the people of rural areas of the State depend for treatment of diseases upon local Vaidyas and Hakims; if so, the steps that the Government has taken or proposes to take for the teaching of the Ayurvedic science of medicine and thetraining of Vaidyas to meet the demand of the public;

[Shri Jagat Ram Bhardwaj]

(b) the steps, if any, which Government has taken or proposes to take to encourage research in and the manufacture of pure Ayurvedic medicines;

(c) the steps, if any, that the Government has taken or proposes to take to encourage the research in the manufacture and the supply of pure Ayurvedic Drugs?

Shri Jagat Narain: (a) The opinion is divided, but Government recognize that most of the people of rural areas depend for treatment of diseases upon local Vaidyas and Hakims. In recognition thereof, Government have adopted the policy of setting up Ayurvedic and Unani Dispensaries wherever possible and within the limited finances at their disposal. Government have also under consideration a scheme for setting up an Ayurvedic College with private help .

(b) and (c) The matter will be considered after an Ayurvedic College starts functioning.

PROFESSORS IN GOVERNMENT COLLEGES.

***2677. Shri Teg Ram**: Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the grades of pay of English and Hindi Professors in the Government Colleges of the State at present;

(b) whether there is any difference in the girs Hindi and English Professors who have got equal academic qualifications; if so, the reasons therefor?

Shri Jagat Narain: (a) There is no post of Professor of Hindi in the Punjab Education Department. The grade of pay of the Professor of English is Rs. 350—40—750/40—950/50—1,200. The grade of pay of Senior Lecturers both in English and Hindi is Rs. 250—25--550/25—750 while that of Lecturers in these subjects is Rs. 150—10-—190/200—10-—250/10—300/10—350.

(b) No.

CONSTRUCTION OF ROAD BETWEEN ABOHAR AND BIKANER.

***2678. Shri Teg Ram**: Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the decision for the construction of a Pacca road between Abohar and Bikaner was taken by the Government long ago; if so, the extent to which the said work has been completed, and the total amount of expenditure that has so far been incurred by the Government on this road;

(b) the share contributed by the State Government and the Central Government respectively for the construction of this road ;

(c) whether any specific date has been fixed by the Government to complete the said road; if so, what?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) The decision was taken sometime in the end of 1951, but the sanction of the Government of India to the estimate for cost of construction of the road is still awaited. As such no expenditure has been incurred so far.

(c) The Punjab Government is to bear the cost of the land and the Central Government will pay for the construction of the road.

(b) Yes. The road is to be completed by the end of 1955-56.

PLAN FOR THE CONSTRUCTION OF ROADS IN THE STATE.

***2724. Shri Ram Kishan**: Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether any long-term road plan has been suggested by the State Public Works Department Experts; if so, the details thereof;
(b) whether any proposals have also been put forward for financing and expediting the plan; if so, the details therefor ;
(c) the action, if any, taken or intended to be taken by the Government in this connection?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : (a) Apart from the 5-Year Plan, no long term road plan has been drawn up.

(b) Does not arise.

(c) The yearly road plan which will appear in the budget has been framed by Government.

CONSTRUCTION OF RUPAR-GUZAR NANGAL ROAD.

***2835. Sardar Achhar Singh Chhina**: Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the date when the construction of Rupar-Guzar Nangal Road was started by the Government and the area of the land acquired for the purpose;

(b) the total amount of compensation paid by the Government for the land so acquired and the year when it was paid?

Sardar Gurbachan Singh Bajwa: (a) The construction of Rupar-Guzar Nangal Road was started in January, 1946 and 329 acres of land has been acquired for this road.

(b) The total amount of compensation paid for the land is given below:—

		Rs.
In 1951-52	..	1,24,640
In 1952-53	..	2,25,000
Total	..	3,49,640

LABOUR DISPUTES IN THE STATE.

***2584. Shri Rala Ram**: Will the Minister for Labour be pleased to state the total number of labour disputes in the State settled by arbitration; together with the total number of strikes and lock-outs in the State during the year 1953-54?

Chaudhri Sundar Singh: None by arbitration. There were 63 cases of strikes and lock-outs.

RESTRICTION ON WINE BOTTLES PRODUCED BY SEMI-AUTOMATIC MACHINES.

***2996. Maulvi Abdul Ghani Dar**: Will the Minister for Labour be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Excise Department proposed to impose restrictions on the use of wine bottles produced by Semi-Automatic Machines in the Glass Factories in India; if so, the reasons therefor;

(b) the present proportion of the bottles produced by Semi-Automatic Machines and Automatic Machines which are used in the Punjab;

(c) whether to his knowledge such restrictions exist in other States of India?

Chaudhri Sundar Singh: (a) Yes. In view of persistent complaints from excise licensees that the glass bottles used by the distillers for the supply of country spirit to the former were kacha ones and resulted in frequent breakages in transit with consequential loss to excise licensees and, in turn, to the Punjab excise revenue, it was decided after full consideration that, with effect from the 1st April, 1953, only pucca glass bottles, manufactured on fully automatic machines, should be used in Punjab for the bottling of both country spirit and Indian-made foreign spirit.

(b) Does not arise.

(c) Government are not aware whether such restrictions exist in other States, but Pepsu Government are following the same practice.

OBSERVATIONS MADE BY THE SPEAKER.

अध्यक्ष महोदय : मैं हाऊस के मुअज़्ज़ मेम्बर साहिबान के सामने दो बातें रखना चाहता हूं। एक अखबार में एक Adjournment Motion छप गई है जो मेरे पास नहीं आई। कायदा यह है कि जब कोई मोशन (Motion), सवाल या रेज़ोलियूशन (Resolution) हमारे पास न आ जाये और हम उसे admit न कर लें उस का इस तरह छप जाना नावाजिब है। वह मोशन तो खैर एक मज़ाक ही सही मगर काइदे के मुताबिक ऐसा करना मुनासिब नहीं।

दूसरी बात यह है कि बाज़ मुअज़्ज़ज़ अखबार इस हाऊस और उस के मैम्बर साहिबान के बारे में मुनासिब हद से ज्यादा liberty ले रहे हैं। मैं खुद और सब मैम्बर

साहिबान अखबारों की मुकम्मल आज़ादी के हक में हैं लेकिन हाऊस के हकूक के कस्टोडियन के नाते से मेरा फ़र्ज़ है कि इस बात का नोटिस लूं। मैं इस वक्त तो सारा मामला आप के सामने नहीं रखूंगा। पहले Press Gallery Committee के प्रधान श्री बाली जी से इस के बारे में ,बात चीत करूंगा। फिर अगर आप साहिबान के सामने इसे पेश करने की ज़रूरत पेश आई तो करूंगा। लेकिन अखबारों से यह दरखास्त ज़रूर करूंगा कि बेशक वह जहां ज़रूरत समझें कड़ी से कड़ी नुक्ताचीनी करें मगर मुनासिब हद से न बढ़ें।

PAPERS LAID ON THE TABLE.

Minister for Education (Shri Jagat Narain): Sir, I beg to lay on the Table of the House the Rules made under the Motor Vehicles Act, 1939, as required by Section 133(3) of the said Act.

THE PUNJAB APPROPRIATION BILL, 1954.

(SUPPLEMENTARY ESTIMATES)

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to introduce the Punjab Appropriation Bill.

Minister for Finance: Sir, I beg to move—

That the Punjab Appropriation Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Punjab Appropriation Bill be taken into consideration at once.

इस बिल पर बहस के सिलसिले में मैं आप को इस बात पर मतवज्जो करना चाहता हूं कि यह बिल उन Supplementary Demands से ताल्लुक रखता है जो आप पास कर चुके हैं। जिस तरह demands के बारे में यह कायदा है कि सिर्फ़ उसी मामले पर बात करनी चाहिये जिस से कि कोई demand ताल्लुक रखती हो इसी तरह इस बिल पर बहस करते वक्त भी अगर आप आम पालिसी पर तकरीर करेंगे तो वह ग़ैर-मुताल्लिका करार दी जायगी। पस आप अपनी तवज्जोह को उन्हीं बातों तक महदूद रखें जो इन demands से ताल्लुक रखती हों।

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब! हमारी सरकार की तरफ से यह Supplementary Demands की दूसरी किश्त पेश की जा रही है और इस में चार करोड़ के लगभग रुपया मांगा जा रहा है जो खर्च के शुरु में लगाये गये तखमीने से ज्यादा निकला और जिस का पहले अंदाज़ा न हो सका। अब इस चार करोड़ के Supplementary Budget में से तीन-चौथाई से कुछ ज्यादा यानी $3\frac{1}{2}$ करोड़ के आस पास नहर के महकमे और नहरों के ही मामलात से ताल्लुक रखता है। यह चीज़ बेशक हमारे सूबे के लिये बहुत ही अहम चीज़ है और इस लिये इस पर इस लिहाज़ से गौर होना चाहिये कि जो खर्च हम कर रहे हैं उस से पूरा पूरा फ़ायदा भी उठा रहे हैं या नहीं।

[पंडित श्री राम शर्मा]

अब जनाब यह जो 3,96,47,310 रुपया खर्च करने का फ़ैसला किया गया है और जिस पर यहां हम से तसदीक की मुहर लगवाई जा रही है इस में से सिर्फ़ पौने दो करोड़ voted है और बाकी charged । अब उन खास खास मद्दों को लीजिये जिन के लिये demand पेश किये गये हैं । Demand No. 5 में जो रुपया मांगा है उस में सफ़ा 7 पर item No. 4 है Running charges of Engines installed on Bhakra and Jahangirpur Minors और फिर No. 6 है Increase in other minor works । चूंकि इन का ताल्लुक मेरे ज़िले से है और फायदा या नुकसान जो कुछ होगा वह भी वहीं होगा, इस लिये मैं इस सिलसिले में लोगों की शिकायतें अर्ज़ करना चाहता हूं । फिर अगर वज़ीर साहिब मुनासिब समझें तो उन पर रौशनी डाल सकते हैं । बताया गया है कि नहरों का फैलाव हो रहा है और पानी ज्यादा जगहों तक ले जाया जा रहा है । यह दुरुस्त है और इस पानी की मांग भी है लेकिन आम शिकायत यह है कि जितनी नहरें फैलाई गई हैं..............

सिचाई मंत्री : इस का demand के किस हिस्से से ताल्लुक है ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो तीन करोड़ की सारी demand का ज़िक्र कर रहे हैं ।

सिचाई मंत्री : मगर वह रुपया खर्च कहां कहां हो रहा है ?

पंडित श्री राम शर्मा : जब मैं इस का ज़िक्र करने लगा तो आप को परेशानी क्यों हो रही है ? मैं गुज़ारिश यह कर रहा था कि इतनी बड़ी रकम के हर खर्च और आमदनी पर तो बहस नहीं की जा सकती । लेकिन नमुने के तौर पर इन में से कई चीजें चुनी जा सकती हैं और उन पर बोला जा सकता है । इसलिये मैं समझता हूं कि मैं in order था । Demand No. 5 के एक item के बारे में जो इंजनों के द्वारा खेतों को पानी पहुंचाने से सम्बन्ध रखता है मुझे कुछ कहना है । मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह काम हमारी सरकार ने किस तरह किया है । Supplementary Estimates में भाकरा का लफ़ज़ ग़लत छापा गया है । यह लफ़ज़ भाकरा नहीं बाकरा है । सब माननीय सदस्य जानते हैं । यहां तो Bakra Minor का ज़िक्र है । इंजनों से पानी उठा कर दूर के ऊंची सतह वाले खेतों को इस minor के ज़रिये पहुंचाया जाता है । इस minor की तमाम तफ़सील तो सरकार के पास होंगी लेकिन मुझे तो इतना पता है कि तीन लाख के करीब रुपया इंजनों और इस स्कीम पर लगा है और पिछले डेढ़ दो साल से यह काम होता रहा है । मैं यह भी जानता हूं कि जो रस्म इस सम्बन्ध में अदा हुई बड़ी धूम धाम से हुई और इस के लिये Centre से एक वज़ीर साहिब आये । इस काम में कुछ रुपया तो सरकार का लगा, कुछ लोगों का और कुछ ठेकेदारों का । लोगों का ख्याल होता है कि जो चंदा दिया जाता है........

Mr. Speaker : Are you very relevant ?

पंडित श्री राम शर्मा : Quite relevant, Sir, यह item, Running Charges of Engines installed on Bakra and Jahangirpur Minors से सम्बन्ध रखता है । मैं सभा के सामने यह ध्यान करना चाहता हूं कि यह इंजन किस तरीका से लगाये गये हैं और यह कैसा काम कर रहे हैं । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि शुरु में सरकार की तरफ से publicity के बावजूद लोगों की इस स्कीम के बारे में क्या राये है । मैं समझता हूं यह सब चीजें relevant हैं ।

स्पीकर साहिब, मैं यह कहना चाहता हूं कि इंजनों, डराइवरों और तेल वगैरा पर कोई दस हज़ार के करीब खर्च आता है । यदि यह रकम ठीक न हो तो बेशक वज़ीर साहिब इसे ठीक कर दें । फिर यह काम कोई डेढ़ साल के करीब जारी रहा । अब तक नतीजा यह है कि पानी कोई ५० एकड़ ज़मीन को ही मिल सका है। भाकरा minor से जो पानी दिया जा रहा है इस के बारे लोगों को बहुत शिकायत है । यह अमर वाकिया है कि इंजन अमूमन बिगड़ी हुई हालत में रहते हैं और डराइवरों ने यह वतीरा इख्तियार कर रखा है कि वे उन दिनों इंजन चलाते हैं जब उन खास खास लोगों की बारी हो जो उन की खातर तवाज़ो करते रहते हों । यह बात बिलकुल सही है । यदि सरकार या कोई वज़ीर साहिब इस बात की जांच पड़ताल करें तो मुझे यकीन है कि यह बात ठीक साबत होगी । इस में शक नहीं कि दूसरी जगह जहांगीरपुर माईनर पर जो इंजन काम कर रहे हैं उन की हालत इस के मुकाबले में ज़रूर बेहतर है । हम करोड़ों रुपये इन बातों पर खर्च कर रहे हैं और हम पर लाज़िम आता है कि हम इस बात को देखें कि काम किस खूबी से चल रहा है । मैं तमाम महिकमे और इस के काम को बहस में नहीं लाना चाहता । लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस item की तरफ ज़रूर लाना चाहता हूं जिस के द्वारा पानी को उठा कर ऊंची सतह के खेतों को दिया जा रहा है । मेरे विचार में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि item छोटा है या बड़ा। यदि मुझे समय मिला तो मैं सब details ऐवान के सामने रखूंगा कि यह काम कितनी देर हुआ, कितना पानी पहुंचाया गया । और कहां कहां पहुंचाया गया । मैं यह भी बता सकूंगा कि यह इंजन कितनी कितनी देर खराब हालत में रहे और जब चले तो किन किन कारणों से । यह इंजन काफी देर खराब रहते हैं । जब यह चलाये जाते हैं तो कई लोगों से मिल कर । (आवाजें) : आप को उन लोगों का पता होगा । यह पता तो उन लोगों को होगा जिन को पानी नहीं मिलता । मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि नहर की extension का यह काम बहुत अफसोसनाक हालत में है । लोगों को फायदे की बजाये परेशानी हो रही है । यह काम सरकार की बदनामी का मूजिब है । मैं दावे से कह सकता हूं कि इंजन बेकार हैं और चलाने वाले भी खासे निकम्मे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप को केवल ५ मिन्ट और मिलेंगे ।

सिंचाई मंत्री : क्या इस बात के लिये ?

पंडित श्री राम शर्मा: तो फिर मैं बैठ ही जाता हूं ।

अध्यक्ष महोदय: आप हर बात पर रूट पायेंगे तो काम कैसे चलेगा ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ (ਰਮਦਾਸ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ Demand No. 5 ਉਤੇ ਬੋਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਹਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਨਾ ਬੜ, ਨੰਗਲ ਅੰਬ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ, ਘੋਣੇਵਾਲ ਵਿਚ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਉਜੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਤ ਏਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸਿਰਫ 200 ਫੁਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ 250 ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ Supplementary Estimates ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਰਖਿਆ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਬਧ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨੰਗਲ ਅੰਬ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ (importance) ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ 20, 30 ਮੀਲ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹਰ ਜਗਹ ਇਕਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਲਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦਰਿਆ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਰੁੜ੍ਹ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਸੁਝਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ੩੦ ਮੀਲ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਜੇ ਕੰਮ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਥੋਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤ੍ਰੀ ਮੰਡਲ ਅਗੇ ਬਿਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਬਲਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਪਏ ਦੀ

ਕਠਨਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ 20, 30 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਣ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਬਿਨੈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ (ਟਾਂਡਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ Supplementary Estimates ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ Supplementary Demand ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚੋਂ $3\frac{1}{2}$ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹਨ।

श्री राम किशन : On a point of order, Sir. क्या माननीय मेम्बर इस समय पुलिस विभाग पर बहिस कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मेम्बर को चाहिये कि वह अपनी बहस इस Supplementary demand तक महदूद रखें।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 3½ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ—ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਫ਼ ਰਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?

Shri Ram Kishan : That C. I. D. Staff is meant for the recovery of abducted girls.

Mr. Speaker : The hon. Member should confine his discussion to the supplementary demands covered by the Appropriation Bill.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਬੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ..........

Minister for Irrigation : The hon. Member is not relevant.

अध्यक्ष महोदय : माननीय मेम्बर केवल इस मांग पर तकरीर करें जो इस वक्त ज़ेरे बहस है। गवर्नमेंट की नीति पर बहस उस वक्त की जा सकेगी जिस रोज़ बजट पर बहस की जायेगी।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : construction के लिये जो प्रबन्ध..

Mr. Speaker : The whole of the Irrigation Department is not under discussion.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪੁਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ

ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਪੁਟਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

सिंचाई मंत्री : इस समय माननीय सदस्य को सब नहिरों पर बहस नहीं करनी चाहिये ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚੋਂ ਕਢੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ construction ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੌ ਕਿ ਇਕ ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੀਮੇਂਟ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Mr. Speaker: Please confine your discussion to the demand under consideration. The general policy of the Govt. is not under discussion.

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

श्री राम किशन (जालन्धर शहर, उत्तर पश्चिमी) : स्पीकर साहिब, इस Appropriation Bill के द्वारा हमारी सरकार को 3,96,47 640 रु. की ग्रांट दी जा रही है । जो Items इस बिल में शामिल किये गये हैं उन में से केवल एक Item की ओर मैं मिनिस्ट्री की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं । अगर इस Appropriation Bill को ग़ौर से देखा जाये तो पता चलेगा कि इस में दो जगहों पर Electricity का ज़िक्र आया है । Supplementary Estimates में दो जगहों पर Uhl River Scheme का ज़िक्र आता है । क्या यह महकमे की ग़लती है या एक ही काम के लिये ज़ायद रुपया लिया जा रहा है ? मिनिस्ट्री को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये ।

दूसरे मैं मिनिस्ट्री का ध्यान Electricity के बारे में स्वीकार की जा रही मांग की ओर दिलाना चाहता हूं । इन Estimates में बहुत से ऐसे Items हैं जिन का पिछले साल भी Supplementary Estimates में ज़िक्र आया था । इस बात से पता चलता है कि Electricity Department ने जिन Lines के लिये पहले रुपया मनज़ूर कराया था, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ । इस लिये मैं मिनिस्ट्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिन Items के लिये रुपया मनज़ूर किया जाता है उन पर अमल दरामद किया जाना चाहिये । जब तक construction और finance में co-ordination नहीं होती तब तक मनज़ूर हुई हुई lines वैसी पड़ी रहती हैं । इस लिये मैं कहता हूं कि जिन Items के लिये रुपया मनज़ूर होता है उन पर अमल होना चाहिये ।

[Shri Ram Kishan]

तीसरी बात जिस की ओर मैं मिनिस्ट्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं यह है कि कई बार ऐसा हुआ है कि ऊपर से तो नकशे मनजूर हो जाते हैं, परन्तु..............

सिंचाई मंत्री : general बातें बजट पर बहस के वक्त होंगी।

अध्यक्ष महोदय : आप तो औरों को relevant होने के लिये कह रहे थे ?

श्री राम किशन : मैं स्पीकर साहिब फिलौर, फगवाड़ा आदि के बारे में जो बिजली के खर्च के items इन Estimates में शामिल हैं, बोल रहा हूं। मैं general बातें नहीं करता हूं। इन items के लिये पिछले साल भी Supplementary Estimates में रुपया मनजूर किया गया था मगर शायद उन पर अमल नहीं हुआ। सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि किस Lineman की गलती से मनजूर किये गये items पर अमल-दरामद नहीं हुआ।

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, यह Supplementary Estimates के लिये जो Appropriation Bill आया है इस में वज़ीर खज़ाना वह रकमें मनजूर कराना चाहते हैं जिन्हें वह anticipate नहीं कर सके। मैं इन Grants में से सिर्फ महकमा नहिर के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। general बात Budget में आई है। जो बात anticipate हो सकती थी वह उस में आनी चाहिये थी। असल में मैं ने इस point पर बोलना है कि कुछ बातें तो उन्होंने anticipate की और कुछ रह गईं।

अध्यक्ष महोदय: जो रह गई हैं उन पर आप बहस न करें। जो मांगें इन Supplementary Estimates में शामिल हैं उन पर बातें कीजिये।

श्री मूल चन्द जैन: अच्छा जी, वह General बातें मैं बजट पर बहस के समय कर लूंगा। एक और बात है जिस का इन ग्रांटस (Grants) से सम्बन्ध है। वह है महकमा नहिर और Labour के ताल्लुकात।

Mr. Speaker: You are a very capable lawyer. You know that this point will not be allowed to be discussed now.

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ (ਫਾਜ਼ਲਕਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਬੋਲਨ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਇਸ Appropriation ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਦਸ, ਯਾਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ Irrigation ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨੇ ਬਨ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਨਸਰਾਲੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਬਨ੍ਹ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

सिंचाई मंत्री: क्या उन के लिये कोई रकम यहां पर है ?

ਸਰਦਾਰ ਚਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ: On a point of Order Sir, ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਲਈ, ਬੰਦਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਤੇ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

अध्यक्ष महोदय: जिन बन्दों का वह ज़िकर करते हैं मंत्री जी कहते हैं कि उन के लिये रुपया इन Supplementary Estimates में नहीं रखा गया ।

ਸਰਦਾਰ ਚਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ: ਜੇ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਜੇ $2\frac{1}{2}$ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਹਤਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ Disturbed Area ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ Discuss ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ: ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।

सिंचाई मंत्री : वह बातें अजनाले के बंद के बारे में थीं ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

अध्यक्ष महोदय:—आप general बातें न करें ।

ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ $2\frac{1}{2}$ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ Supplementary Estimates ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

अध्यक्ष महोदय :—जिन चौकियों का ज़िक्र इन में आया है उन पर बोलिये ।

ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 12 ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਹਨ ।

सिंचाई मंत्री : आम चौकियों के लिये नहीं बल्कि खास २ के लिये मांग की गई है ।

ਸਰਦਾਰ ਚਨੰਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : On a point of Order, Sir, 13 ਸਫੇ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ । ਨਿਚਲੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਜਿਥੇ 2½ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਦੋ ਲਖ ਰੁਪਿਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

Mr. Speaker : This is not relevant.

ਸਰਦਾਰ ਚਨੰਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : On a point of Order, Sir, Supplementary Demands vote ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

अध्यक्ष महोदय : इस अवसर पर पुलिस चौकियों पर General Discussion नहीं हो सकती । जब पुलिस की मांग पर Voting होगी तो आप इस मामले पर बहस कर सकेंगे । इस समय तो उस खास मद पर बहस हो सकती है जिस पर रुपया खर्च किया गया है ।

ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਢਾਈ ਲਖ (2.5 lakhs) ਰੁਪਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਬਿਠਾਣ ਉਪਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਹੁਣ ਅਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਰਖਣ ਦੀ ਉਕਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਮਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿਖ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੌਕੀਆਂ ਉਠਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।

श्रीमती सीता देवी (जालन्धर शहर-दक्षिण उत्तर) : माननीय स्पीकर साहिब, Demand No. 9 के Item No. 10 की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि यह रुपया Jullundur Model Town, Jullundur Basties, Jullundur East और Jullundur West पर खर्च किया गया है ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहती हूं कि लोगों के इकट्ठे होकर और व्यक्तिगत तौर पर भी प्रार्थना पत्र भेजने के बावजूद बसती दानिशमंदां और बसती शेखां को अभी तक बिजली नहीं दी गई। वे Administrator साहिब को कई बार representations भेज चुके हैं। Khosla साहिब को भी representation दे चुके हैं।

सिंचाई मंत्री : इस Item में बसती दानिशमंदा का कोई ज़िक्र नहीं है ।

श्रीमती सीता देवी : चौधरी साहिब, ज़रा सबर से काम लीजिये । इस में जालन्धर बसती का ज़िक्र किया गया है ।

Mr. Speaker: Please, don't address your remarks to the Minister.

श्रीमती सीता देवी : तो मैं यह कह रही थी कि वहां तक अभी बिजली नहीं पहुंची । बसती शेखां की main streets में रात को अंधेरे के कारण आये दिन accidents होते रहते हैं जिन की वजह से वहां के रहने वाले बहुत परेशान हैं । मेरे ख्याल में इस रुपये का जो अब मनज़ूर करवाया जा रहा है उचित प्रयोग नहीं किया गया ।

जालन्धर शहर में बहुत देर से बिजली का खुदा ही हाफ़िज़ है । आये दिन बिजली fail हो जाती है और छः छः घंटे तक बन्द रहती है, जिस के कारण students और hospitals में patients को बहुत तकलीफ़ होती है । Industries वाले अलग प्रेशान हैं । examination days में students को बिजली fail होने की वजा से बड़ी परेशानी हो रही है ।

सिंचाई मंत्री : यह तो आप ने General Discussion शुरू कर दी है ।

Mr. Speaker: The hon. Minister should know that he has no jurisdiction over the hon. Member. He should address his observations to me and not to the hon. Member who is speaking.

श्रीमती सीता देवी : मैं यह निवेदन कर रही थी कि इस रुपये को खर्च करते समय वहां के लोगों की तकलीफ़ों की ओर ध्यान किया जाना चाहिये था । इन तकलीफ़ों की चर्चा समाचार पत्रों में भी हो चुकी है ।

श्रीमान् जी, बैठने से पहले मैं एक Point of Order raise करना चाहती हूं । क्या मंत्रियों का यह विशेष अधिकार है कि वे हर बोलते हुए सदस्य को बीच में ही टोकते रहें या कि उन्हें चाहिये कि सब points का वह अपनी speech में जवाब दें ।

अध्यक्ष महोदय : वे उन्हीं को interrupt करते हैं जिन पर वे अपना अधिकार समझते हैं । (*laughter*)

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਬ) : ਪਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕ, ਦੋ Items ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ

[Sardar Sarup Singh]

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 138 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Joint Tattoo Show, Phillaur ਉਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫੇਰ All-India Atheletic Meet ਉਪਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ Special Repairs to Vehicles ਉਪਰ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ Items ਉਪਰ ਇਤਨਾਂ ਵੇਖਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ Punjab Contingency Fund ਦਾ gross abuse ਹੈ।

ਉਹ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ sanction ਦੇ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ sanction ਦੇ ਬਤਹਾਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ Supplementary Demands ਵਿਚ ਘਸੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ; ਉਹ ਹਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਖਤ ਨਾਵਾਜਿਬ ਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ solvent ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੇਨਰਲ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਕਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (machinery) ਜਾਂ ਟੂਲ (tools) ਆਦਿ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ proper tenders call ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਿਰਮਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਰਖ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆੜ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ purchase ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ economical ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ competetive rates ਉਪਰ based ਹੈ। ਇਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਉਸ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ justified ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ

tender ਵੀ ਕਾਲ (call) ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ purchase ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਝਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ specific date ਨਹੀਂ ਮੁਕਰੱਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਭਾਂਵੇਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਲਗ ਜਾਵੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ tender ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ lowest rates ਤੇ ਖਰੀਦਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇ।

प्रोफैसर शेर सिंह (झज्जर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं Demand No. 5 के सिलसिले में अर्थात् बाकरा और जहांगीरपुर माईनर्ज़ पर जहां कि engines लगाये गये हैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। यह वह इलाका है जिस के सम्बन्ध में हमारी Unionist विज़ारत ने भी अंग्रेज़ों के ज़माने में कह दिया था कि पानी नहीं पहुंच सकता। ऊंची ज़मीन के इन इलाकों को उन्होंने कहत की ससुराल कहा था। इस बात का श्रेय तो हमारी कांग्रेस सरकार को जाता है जिस ने कि नौ नौ फुट और पांच पांच फुट पानी को ऊपर उठा कर ऐसी ऐसी ज़मीनों को सैराब कर दिया है जहां के लोग कभी स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं कर सकते थे। अब वे लोग हज़ारों मन गेहूं और दूसरा अनाज पैदा कर रहे हैं। (*Cheers*) इस में कोई शक नहीं कि सरकार का इस योजना पर काफ़ी रुपया खर्च हुआ है और यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ऐसे इलाके के लिये दिल खोल कर काम किया है। लेकिन जब एक पुराने parliamentarian ने इस योजना को criticize करना आरम्भ किया तो मुझे बहुत हैरानी हुई और मैंने ख्याल किया कि शायद उन्होंने Floor cross करने के बाद सियासत की नई ट्रेनिंग (training) लेनी शुरू की है और वह 'कमाऊ पूत से लेने लगे हैं। (*Interruption*) उसी पत्र में एक बार यह बात ज़रूर चली थी कि केवल एक आदमी है जिस के इलाका में पानी पहुंचाया जा रहा है, आगे पानी नहीं जाता और यह कि 50 एकड़ से ज्यादा ज़मीन सैराब नहीं हुई, वगैरा वगैरा।

अध्यक्ष महोय! मैं उन की वाकफीयत के लिये कहना चाहता हूं कि बाकरा (Bakra Minor) से करीबन पांच हज़ार एकड़ ज़मीन को पानी का तोड़ flow मिल रहा है और 10 हज़ार एकड़ ज़मीन को Lift के ज़रिये पानी दिया जा रहा है। पिछले वर्ष काफी area में आबपाशी की गई है और हज़ारों मन अनाज पैदा हुआ है। पिछले साल तो रेत के टीले से इधर कम अज़कम एक हज़ार एकड़ ज़मीन सैराब हुई थी। इस वर्ष तो रेत के टीले को पार कर के भी पानी पहुंचाया गया है और कम से कम चार पांच सौ एकड़ ज़मीन उधर भी सैराब हुई है। यह ठीक है कि रेत का टीला ज़रूर रुकावट डालता है। उस में पानी की काफी मिकदार जज़ब हो जाती है। उस के लिये हकूमत जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था करेगी ताकि पानी उस में जज़ब न हो और ज़ाया न जाये।

[Shri Sher Singh]

अध्यक्ष महोदय ! इसी तरह जहांगीरपुर माईनर के सम्बन्ध में अर्ज़ करूंगा कि उसके द्वारा 10 गांवों के करीब सैराब हुए हैं । किसी में ज्यादा और किसी में थोड़ी ज़मीन सैराब हुई है । एक गांव में तो 2 हज़ार बीघे के करीब ज़मीन सैराब हुई हैं और दूसरों में कहीं 50 एकड़ कहीं 100 एकड़ और कहीं पर 250 एकड़ ज़मीन सैराब हो रही है । इन सब बातों के होते हुए मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे पुराने parliamentarian ने महज़ एक नये अखबार की बिना पर जो कि लोगों में ग़लत-फहमियां फैला रहा है इतनी आलोचना क्यों की है । उन को तो दुबलयान माजरा, जहांगीरपुर इत्यादि गांवों की ऊंची ज़मीन को पानी देने के लिये बधाई देना चाहिये थी ।

सिंचाई मंत्री (चौधरी लहरी सिंह): स्पीकर साहिब ! हाउस में काफी बातें हुई हैं । एक बहिन ने तो गवर्नमण्ट को मुबारकबाद भी पेश की है कि किसानों को पानी देने की स्कीमें बनाई जा रही हैं और कि वह बहुत नेक कदम है । लेकिन दूसरी बहिन ने नाराज़गी ज़ाहिर की है और कहा है कि बिजली के इन्तज़ाम ने उन की तसल्ली नहीं की है । और पंडित श्री राम शर्मा की नुक्ता चीनी ने तो मुझे हैरान ही कर दिया है । यह वह इलाका है कि जिस के मुतअल्लिक Unionist Party के वज़ीर सर छोटू राम मरहूम को जो कि किसानों के बही-खाहां थे best engineers ने कह दिया था कि पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल है । अब उसी जहांगीरपुर और बाकरा के इलाके में हमारी सरकार के engineers ने लोगों की गुरबत को दूर करने के लिये Minors के ज़रिये पानी पहुंचाया है । यह वह इलाका है जहां पर लोगों को बरसात में भी पानी नहीं मिलता था, उन के जोहड़ भी सूखे पड़े रहते थे और बड़ी दूर दूर से पानी लाना पड़ता था । वहां पर हमारे engineers ने लिफ्ट के ज़रिये 9,9 फुट ऊंचा पानी चढ़ा कर किसानों की मुसीबत को दूर किया है । पंडितजी ने कहा है कि खास वक्त में यह Minors चलते हैं और खास वक्त पर यह बंद हो जाते हैं लेकिन इस के मुतअल्लिक हमें अभी किसी ज़मींदार की शिकायत नहीं आई कि वहां पर ठीक आबपाशी नहीं हो रही । मेरे दोस्तों के पास जो उन का अपना अखबार है उस में कभी इस बात का ज़िक्र तक नहीं आया और न ही कभी किसी ने गवर्नमैण्ट को इस बात के मुतअल्लिक represent ही किया है । उल्टा, वहां की पब्लिक तो बहुत खुश है । जहांगीरपुर में श्री देशमुख जी आये थे, श्री गुलज़ारी लाल नन्दा आये थे, उन्होंने इस की opening ceremony की थी । उस वक्त वहां पर 15, बीस हज़ार आदमी मौजूद थे । किसी ने कोई शिकायत नहीं की । जिस इलाका में लोग बूंद 2 पानी को तरसते थे वहां पर हज़ारों मन अनाज पैदा हो रहा है, शानदार फसलें हो रही हैं । मालूम होता है कि पंडित जी वहां खुद नहीं गए । वे खुद वज़ीर रहे हैं यह उन का अपना इलाका था । उस वक्त कहते थे कि सरकार ने बड़ा अच्छा किया है गरीब लोगों को पानी मिलेगा । दूसरी बात जो लोगों को गुमराह करने वाली पंडित जी ने कही है वह यह है कि ये साल के अन्दर कभी कभी चलते हैं । ये तो बरसाती नाले हैं जो कि साल में 3, 4 महीने तक चलते हैं । यह उन का गलत ख्याल है कि वे बन्द हो जाते हैं । वे तो दर असल बन्द ही रहते हैं । जब दर्याओं के अन्दर पानी ज्यादा होता है तो सिर्फ उस वक्त उन में पानी आता है । वे तो 9 महीने तो बन्द ही रहते हैं । मुझे मालूम होता है कि पंडित जी वहां कभी नहीं गए ।

स्पीकर साहिब ! मैं आप की बिसातत से सामने बैठे हुए रोहतक के मैम्बर साहिब को बताना चाहता हूं कि मैं खुद ऐसे गांव में गया, लोगों को वहां पर इकट्ठा किया, उन से बातचीत की। उन से पूछा कि आप को पानी के बारे में कोई शिकायत तो नहीं। उन्होंने बड़े खुश हो कर जवाब दिया कि साहिब हम सब को पानी मिल रहा है—हमें इस महकमा के खिलाफ़ कोई शिकायत नहीं। इन चीजों को जब, स्पीकर साहिब मैं देखता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि क्यों इस तरह के प्रापेगेंडा से, जैसा कि सामने बैठे अप्पोज़ीशन के साथी करते रहते हैं, लोगों को गुमराह किया जाता है? मैं चैलेंज (challenge) करता हूं, स्पीकर साहिब, आपोज़ीशन में बैठे अपने रोहतक के भाई को कि वह मेरे साथ रोहतक के गांवों में चलें। मुझे यकीन है कि उन्हें कोई भी ऐसा किसान नहीं मिलेगा जो यह कहे कि उसे पानी नहीं मिलता। तो फिर यह ग़लत-बयानियां कैसी ?

इस के साथ ही साथ, स्पीकर साहिब, मेरे महकमा पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि यह एक पुराने ढंग का ही चला आ रहा है इस का सारे का सारा system ही defective है और यह कि इस महकमा को चलाने वाले अफ़सर और दूसरे मुलाज़म खराब और बईमान हैं। पंडित जी ने यह भी कहा कि मशीनरी भी वही है जिस से काम किया जा रहा है। यही नहीं। उन्होंने तो यहां तक कहा कि इस महकमे में Inefficincy ही inefficiency है। यह बात ग़लत है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उनका impression बिल्कुल ग़लत है। अगर पंडित जी मेरे महकमे का working देखें तो उन्हें पता लगेगा कि मेरे अफ़सर कितने efficient और मेहनती हैं। मैं उन्हें यह बता दूं कि मशीनरी भी बिल्कुल नई है और उसे protect करने के लिये sheds वग़ैरा भी बने हुए हैं। बड़े २ expert अफ़सर उस को handle करते हैं।

मौलवी अब्दुल गनी : कोई रीकार्ड भी है या बिना रीकार्ड के ही आप ये सब बातें कहे जा रहे हैं ?

सिंचाई मंत्री : बिना रीकार्ड के कैसे कह सकता हूं। मैं हर रोज़ सारे महकमे की पड़ताल करता हूं—देखता हूं कि किस जगह क्या कमी है ताकि उसे दूर किया जाये और गरीब लोगों के फायदे के लिये कदम उठाए जाएं। मैं तो खुद उन अफ़सरों के काम को देखता हूं। मैं तो उनकी इज्ज़त करता हूं, regard करता हूं। मैंने खुद machinery की inspection की है। अगर पंडितजी खुद जा कर देखें तो उन्हें मालूम होगा कि सच्चाई को किसी भी हालत में छिपाया नहीं जा सकता और यह कि ग़लत-बयानियां करने से कोई फायदा नहीं होता।

इस के बाद मेरी बहिन श्रीमती डाक्टर प्रकाश कौर जी ने भल्लर वाल का ज़िक्र किया। इस सिलसिले में, स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमें पूरा ख्याल है। क्या हम कभी भी यह बरदाश्त कर सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का इलाका पानी में बह कर पाकिस्तान की हद में चला जाये ? कभी नहीं। इस के साथ हम यह बात भी सहन नहीं कर सकते कि हर साल हमारे किसान भाईयों को, जो कि ज़मीन पर हल चला कर अपनी

[Minister for Irrigation]
गुजर करते हैं, बाढ़ की वजह से नुक्सान उठाना पड़े। इस सवाल पर सरकार अपनी खास तवज्जोह दिए हुए है। डेरा बाबा नानक से ले कर कोई तीस मील दूर तक के रकबे को इस नुक्सान से बचाने के लिये हम एक planned programme पर काम करना चाहते हैं। इस मकसद के लिये हमारे पंजाब के मशहूर इंजीनियर—चार बड़े इंजीनियर—वहां मौका पर गए और स्थिति की जांच की। उन्होंने सारे इलाके का सर्वे (survey) करके अपनी एक रीपोर्ट (report) हमारे पास भेजी जिस पर कि सारी कैबीनेट (Cabinet) ने फ़ैसला किया। इस मकसद के लिये अगले साल के लिये 22 लाख रुपये की रकम का प्रबन्ध किया गया है। भला यह कोई ऐसी मामूली सी बात है जिस को कि नजरन्दाज़ किया जाये? यह ठीक है कि आप को—मेरे कहने का मतलब यह है कि बहन जी को—इस बात की चिन्ता है लेकिन, स्पीकर साहिब, मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि इन से भी बढ़ कर हमारी कैबीनेट (Cabinet) को इस बात का फ़िक्र है। इस लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर माननीया लेडी मैम्बर इस subject को मेरे साथ या मेरे डीपार्टमैण्ट के अफ़सरों के साथ discuss कर लेतीं तो उन्हें यह शिकायत करने की ज़रूरत ही न पड़ती।

इस के बाद, स्पीकर साहिब, एक दो बातें और कहना चाहता हूं और वह हैं बिजली की सप्लाई के मुतअल्लिक। मेरे भाई श्री राम किशन ने खास तौर से जालन्धर का हवाला दिया था। उन्होंने कहा था कि वहां जालन्धर में कई कई घंटे बिजली फ़ेल हो जाती है, ब्लैक आऊट (blackout) हो जाते हैं और लोगों की बिजली की डीमांड (demand) को पूरा नहीं किया जाता। स्पीकर साहिब, मैं आप की वसातित से उन्हें यह बताना चाहता हूं कि जब कभी भी वहां पर या जहां कहीं भी कुछ घंटों के लिये बिजली बन्द की जाती है, लोगों को पहले इस बात की इत्तलाह दे दी जाती है। आखिर महकमे वालों ने शहर में फैली हुई बिजली की मुखतलिफ़ 'lines' की inspection भी तो करनी होती है। अगर current को कुछ देर के लिये बन्द न किया जाये तो inspection कैसे हो सकती है? बाकी, जहां तक बिजली की डीमांड (demand) और regular supply का ताल्लुक है, मैं आप को बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने परसों भी बताया था हमने पहले 5½ हज़ार किलोवाट के Transformers मंगवाये और जब डीमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो 8½ हज़ार के भी मंगवाये। इस तरह से साफ़ ज़ाहिर है कि ज्यूं ज्यूं डीमांड demand में expansion होती जाती है, हम उस को meet करने के लिये मुनासिब कदम उठाते रहते हैं। इस के अलावा, सपीकर साहिब इन शिकायतों को दूर करने के लिये हर ज़िला में मैंने एक कमेटी बना रखी है जिस के मेम्बर हैं उस ज़िला के एम. एल. एज़. और एम. एल. सीज़। ऐक्स. ई. एन. (X.En.) उस कमेटी का सैक्रेट्री है और ज़िला का डिप्टी कमिश्नर (Deputy Commissioner) उस का चेयर मैन।

Shri Ram Kishan : But with no powers.

Sardar Acbhar Singh Chhina : And the Committees are not functioning.

मंत्री : यह बात गलत है। उस डिस्ट्रिक्ट ईलैक्ट्रीसिटी कमेटी (District Electricity Committee को हक है कि लोगों की शिकायतों को सुने और मुनासिब फैसले करे। गवर्नमैण्ट ने यह announce भी किया हुआ है कि जो फैसले वह कमेटी करेगी उस को रद्द नहीं किया जायगा।

ये शिकायत जो कि कुछ माननीय मेम्बर साहिबान ने की हैं उन के मुतअल्लिक ऐक्स ई. एन. (X.En.) ने भी दो तीन बार स्टेटमैण्टस (statements) दी हैं, डिप्टी कमिश्नर ने कमेटी की मीटिंगों में उस का जिक्र किया है और गवर्नमैण्ट ने भी अखबारात में कुछेक difficulties लोगों के सामने रखी हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि डीपार्टमैण्ट (Department) की difficulties को appreciate क्यों नहीं किया जाता ? मैं हैरान हूं कि मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्त असलीयत को समझने में क्यों गल्ती करते हैं ? इस लिये यह मुनासिब नहीं कि आप उन अफ़सरों पर शक करें या उन्हें बुरा भला कहें जो कि दिन रात आप की सेवा करने में लगे हुए हैं। जब ऐम. एल. एज़, साहिबान और ऐम.एल. सीज़ साहिबान खुद उन कमेटियों के मालिक हैं और खुद फैसले करने के मजाज़ हैं तो क्यों ऐसी चीजें हाउस के अन्दर लाई जायें। आप का फर्ज़ है कि आप खुद कमेटी के चैयरमैन और सैक्रेटरी साहिबान से मिल कर लोगों की तकालीफ़ दूर करें। मैं चैलेंज (challenge) करता हूं, स्पीकर साहिब, कि एक एक आईटम लेकर मेरे सामने लाएं। मैं facts को face करने के लिये तैयार हूं बशर्ते कि वे भी face करने के लिये तैयार हों। यह बात मेरे इन मोहतरिम भाईयों को शोभा नहीं देती कि एक सूई की नोक की सी बात लेकर अफ़सरों को criticise किया जाए और उन्हें condemn किया जाए।

इस के अलावा, स्पीकर साहिब, दानिशमन्दां बस्ती का भी जिक्र किया गया है। इस सिलसिले में भी मैं यही कहना चाहता हूं कि हम बड़ी तेज़ी के साथ बिजली के काम को expand कर रहे हैं। आखिर जब expansion का काम हो तो किसी न किसी लाईन को थोड़ी देर के लिये बन्द तो करना ही पड़ता है। मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि एक साल के अन्दर हर लाईन को ठीक कर देंगे।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਕਿ Supplementary Estimates ਵਿਚ 3,96,47,640 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ (demand) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ

[Minister for Finance]

ਗਿਆ ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸ Appropriation Bill ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 2,08,12,220 ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ । 1,38,00,000 ਰੁਪਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ways and means ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ Reserve Bank of India ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਸੀ । ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਕਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ Supplementary Estimates ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਗਏ Rehabilitation Loans ਸਨ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 2,08,12,280 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਡੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ 1,40,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰਕਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਦੋਸਤ--ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ । ਇਹੋ ਵਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਬਾਕੀ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਖਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਗਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਮਾਂਡ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 15 ਵਿਚ ਵਖਰਾ ਵਖਰਾ ਰੁਪਿਆ ਕਿਉਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ Demand No. 9 ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Uhl River ਵਿਚ ਹੜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ Tramway Track ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਂ Contingency Fund ਵਿਚੋਂ ਰੁਪਿਆ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। Demand No. 21 ਥਲੇ ਉਹ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ Uhl River ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੜਾਂ ਦਵਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਕਰਾਣ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਜਟ estimates ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Budget Estimates ਵਿਚੋਂ ਮੀਟ (meet) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦਸ ਰੁਪਏ ਦੀ Token Demand ਹਾਊਸ ਅਗੇ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਰਚ Budget Estimates ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਲੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ Demand No. 9 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ Budget Estimates ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ Supplementary Demand ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚ ਇਕੋ ਕੰਮ ਉਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਨ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਬਲਰਵਾਲ ਅਤੇ ਡੇਹਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਤਅਲਿਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤ੍ਰੀ ਤੇ ਚੀਫ ਇੰਨਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਵਡੇ ਇਨਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਉਥੇ ਹੋ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਇਨਜੀਨੀਅਰ

[Minister for Finance]

ਭੇਜੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਢਾਹ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਢਾਹ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲ ਹੀ ਮਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਵਲ ਨ ਮਾਰੇ।

ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤਰ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਉਤੇ 11 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਉਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਉਤੇ ਨਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਸ Special Staff ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਵਾ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ trained ਅਤੇ efficient staff ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 63 kidnapped ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 39 kidnappers ਪਕੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ kidnappers ਦੇ gangs ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੁਖੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ Special Staff ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਤਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ Special Trained Police ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਉਹ Disturbed Area ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : Disturbed Area ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਫ਼ਾ 13 ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ 1,69,580 ਰੁਪਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਸਿਆ ਹੈ ਉਹ Special repairs to vehicles

ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੱਮਤ ਨ ਕਰਾਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ Border Police ਜਿਹੜੀ Border ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ duty effeciently ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਖਰਚ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਵਾਜਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਮਾਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕੇ।

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਰਕਮ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ Tatoo show ਅਤੇ Atheletics ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Tatoo show ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ sports ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ tatoo show ਲਾਹੌਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਦੱਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫਿਲੌਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ discipline ਅਤੇ training ਦੀ ਬੜੀ ਦਾਦ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਰਚ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ tatoo show ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਡੇ ਆਲਾ ਪਾਏ ਦੀ Trained Police ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Atheletics ਨੂੰ encourage ਕਰੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ Atheletics ਜਾਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸਤ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Atheletics ਵੀ ਜਿਤ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਹਾਕੀ ਦੀ championship ਵੀ ਜਿਤ ਲਈ ਹੈ। ਸੈਨੂੰ ਇਹ

[Minister for Finance]
ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਉਪਰ ਉਸਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਉਹ Supplementary Demands ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Budget Estimates ਵਿਚ provision ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ agriculture ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ Supplementary Demand ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Appropriation Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SCHEDULE

Mr. Speaker: Question is—

That Schedule stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Finance (Sardar Ujjal Singh): Sir, I beg to move—

That the Punjab Appropriation Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Punjab Appropriation Bill be passed.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ) : ਪਰਧਾਨ ਜੀ, ਅਸੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨੈਨਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਬਜਟ ਅਤੇ Appropriation Bill ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਾਈਨੈਨਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਧੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ industry ਦਾ ਹੈ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ੩ ਜਾਂ ੪ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ Appropriation Bill ਪਹਿਲਾਂ ਭੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸਾਡਾ ਇਕ ਗਿਲਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ agriculture ਨੂੰ finance ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ provision ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

अध्यक्ष महोदय—आज तो आप relevant नहीं।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਕਮ ਦੀ provision ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ ਬਚਾ ਕੇ agriculture ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

Mr. Speaker: I have great respect for the legal knowledge of the hon. Member, but I would like to point out that he is not relevant when he says that provision for a particular item or items of expenditure should have been made in the Bill under discussion. The question now before the hon. Members is whether they agree to pass the Bill or not.

Sardar Amjer Singh: Sir, we oppose it on the ground that such expenditure as should, in our opinion have been incurred, has not been provided for in the Bill.

Mr. Speaker: The hon. Member is at liberty to oppose it.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ: ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। industries ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ Finance Corporation ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ agriculture ਲਈ ਭੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ ਜੋ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਜਾ ਹੈ। ੬੪ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਜੋ ਬੋਡਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ special ਪੁਲਸ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ridden ਸਟੇਟ ਬਨ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੋਡਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਨੇ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਚ Law and Order ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ figures ਦਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਰਾਇਮ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ regular ਪੁਲਿਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਅਤੇ P. A. P., C. I. D., Border Police ਆਦਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਪ੍ਰੰਤ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ dacoities ਅਤੇ murders ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਲਈ ਅਡ ੨ ਪੁਲਿਸ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ training ਭੀ ਵਖੋ ਵਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲ ਵਿਚ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर)—स्पीकर साहिब, आम तौर पर बजट सैशन (Session) में Supplementary Expenditure के लिये demand और appropriation के नाम पर बिल पास किये जाते हैं। पहले में कुछ जैनरल (general) बातें कहना चाहता हूं और फिर कुछ specific बातें भी कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय—आप जैनरल (General) बातें न कहें। Demands बारे जो चाहें कहें।

It has been stated in Demand No. 7 that—

> A sum of Rs 1,34,640 is to be paid to the Government of India, being the contribution of the Punjab State towards the Co-ordinated Scheme for Locust Control in the desert areas for the years 1947-48 (15th August 1947 to 29th February 1948) and 1953-54. A sum of Rs 2,830 pertains to the year 1947-48 and Rs 1,31,810 to the year 1953-54.

I feel that the Government should give reasons to satisfy this House and the poor people in the State that the enhancement of the State's contribution from Rs 2,830 to Rs 1,31,810 has been rightly made.

प्रोफैसर मोता सिंह—स्पीकर साहिब, असल में बजट का main object यह होता है कि सरकारी expenditure के मुतअल्लिक तजवीजें पेश की जायें और हकूमत को चलाने के लिये जरूरी खर्च को जाहिर किया जाये। इस Appropriation Bill में मुझे खर्च ही खर्च के सिवाये कोई खास बात नज़र नहीं आती। यह इस बिल की कमज़ोरी है। इस में appropriation पूरी तरह explicitly show नहीं किया गया। इस लिये मेरी ख्वाहिश है कि हम इसे ठीक करें। जैसे कि मैंने demand 17 का हवाला दिया। हम आज तक locust pest पर control नहीं कर सके। इस ने पंजाब के अन्दर बहुत बार हमला किया। गवर्नमैण्ट ने वादे किये मगर पैसा एक नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय—आप relevant नहीं हैं।

प्रोफैसर मोता सिंह—इस बारे में खर्च को 1,28,000 रुपये से घटा कर एक दम एक लाख कर दिया गया। यह बात मैंने मिसाल के तौर पर कही है। इसी तरह General Administration, Medical, Police, etc., की Items भी मैंने देखी हैं। सब में रुपये की Demand की गई है। खैर payment तो हो गई मगर उस की appropriation के लिये ठीक explanation नहीं दिया गया। इस लिये मैं दरखास्त करता हूं कि ऐसी चीजें explicitly होनी चाहियें न कि implicitly।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ appropriation

[Minister for Finance]

ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ Supplementary Estimates ਦਾ ਸਫ਼ਾ 40 ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ Locust ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ agriculture ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ locust ਨੂੰ ਇਕਠਿਆਂ ਹੋਕੇ ਨਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤਕ ਇਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕਸਟ (locust) ਨੂੰ ਦਬਾਨ ਲਈ ਇਕ ਸਕੀਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਸਟ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ consolidated ਲੋਕਸਟ ਸਕੀਮ ਬਨਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚ ਸਾਡਾ 1947-48 ਦੇ ਹਿਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਆਂਉਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਹਿਸਾ 1,34,000 ਰੁਪਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। 1953-54 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ Consolidated Control ਲਈ ਦੇਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਿਡੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਸੀਂ appropriate ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ Agriculture Department ਤੋਂ ਬਚਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾ ਇਸ ਬਚਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

Agriculture ਨੂੰ finance ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 4½ ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਕਾਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ)।

1953 ਵਿਚ fertilizers ਲਈ 57 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ: ਅਤੇ fertilizers ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ: ਪਰ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ 3-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਥੇ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਰ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 35 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਕੁਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਵਿਨਸ਼ਲ ਕੁਅਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸੇ ਲਏ। 10 ਲਖ ਦੇ ਇਕ ਵੇਰੀ ਤੇ 5 ਲਖ ਦੇ ਇਕ ਵੇਰੀ।

Sardar Ajmer Singh : What is the Security that they get ?

Mr. Speaker : The hon. Finance Minister need not reply to the irrelevant parts.

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਲਫਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਗਲਾਂ ਤੇ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖੁਲੇ ਤੌਰ ਤੇ discuss ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ Border Police ਤੇ 64 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ Central Government ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁਪ ਨਹੀਂ ਬਠੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 3-4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ demand ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੌਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ।

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Appropriation Bill be passed.

The motion was carried.

The Assembly then adjourned till 2 *p.m. on Tuesday, the* 16*th March* 1954.

135 PSLA—283—8-10-54—CP & S., Pb., Chandigarh

Punjab Legislative Assembly Debates

16th March, 1954.

VOL. I—No. 7

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, 16th March, 1954.

CHANDIGARH :
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab,
1954

Price : -/7/-

PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY

Tuesday, 16th March 1954.

The Assembly met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh Capital, at* 2 *p. m. of the Clock. Mr. Speaker* (*Dr. Satyapal*) *in the Chair.*

QUESTION HOUR (DISPENSED WITH)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁਛੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ Question Hour dispense with ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

Minister for Development: As you like it, Sir.

Mr. Speaker : I want to know the opinion of the hon. Members about it.

(Voices: Question Hour may be dispensed with)

Mr. Speaker: All right. The Question Hour is dispensed with today.

OBSERVATIONS MADE BY THE SPEAKER.

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਹੁਣ ਰੁਝੇਵਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਉਪਰ General Discussion ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। Opposition ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ Majority Party ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ convention ਹੈ ਓਸ ਅਨੁਸਾਰ Opposition ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਧਾ ਵਕਤ Treasury Benches ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਧਾ ਸਮਾਂ Opposition ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਸਾਡੀ ਤਰਫ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਰੀਫ਼ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨਣੇ ਹਨ। (*Laughter*)

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही अर्ज़ कर दी है कि Opposition वालों की numerical strength बहुत कम है लेकिन चूंकि उन के views सुनने का मौका भी ministers को बजट की debate के वक्त ही मिलता है इसी लिये उन को कम गिनती में होने के बावजूद बराबर का समय दिया गया है।

दूसरी बात जिस की तरफ मैं मैम्बर साहिबान की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं यह है कि—
Only questions of broad policy underlying the particular department or an account head should be discussed at the time of the general discussion. General discussion on the Budget is to be confined to the provisions of the Budget and the general policies of Government. Details should be considered at the time of the discussion on the demands for grants.

[अध्यक्ष महोदय]

दूसरे शब्दों में इस का मतलब यह है कि आज या कल जो discussion होगी उस में specific या खास २ चीज़ें नहीं लाई जायेंगी । बल्कि सरकार की general policy और उसके general फैसलों के हक में या बरखिलाफ मैम्बर साहिबान जो कुछ चाहें फरमा सकते हैं । Now Sardar Gopal Singh will initiate the discussion.

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET.

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਗਰਾਓਂ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਉਜੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ parliamentary ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਦਾਦ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ (*cheers*) ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਦਾਦ ਨ ਦਿਤੀ ਜਾਇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਸਾਹਿਬੇ ਸਦਰ ! 1954-55 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸਾਡੇ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ Revenue Receipts 22 ਕਰੋੜ 19 ਲਖ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ revenue side ਤੇ expenditure 23 ਕਰੋੜ 12 ਲਖ ਰੁਪੈ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਂ 13 ਲਖ ਰੁਪੈ ਦਾ ਖਸਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 2 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੁਲ ਖਸਾਰਾ 15 ਲਖ ਰੁਪੈ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਖੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ Motor Stage Carriage Vehicle ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ 12 ਲਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ, Cinema Houses ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ 5 ਲਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ Revision of Land Settlement ਨਾਲ 30 ਲਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ । Estate Duty ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ Share 14 ਲਖ ਰੁਪੈ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ 61 ਲਖ ਰੁਪਈਆ ਬਨਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਰਕਮ ਕਢ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ 34 ਲਖ ਰੁਪੈ ਦਾ ਖਸਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਫੇਰ Central Government ਦੀ Finance Commission ਵਲੋਂ 1, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚਲਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਉਪਰ 1,08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 1,38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਨਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਹੇ ਸੂਬੇ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ।

ਸਾਹਿਬੇ ਸਦਰ ! ਇਸ਼ ਦੇ ਅਗੇ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ Universal Pay Scale ਉਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ standard of living ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਅਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਿਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ 150—10—350 ਤੋਂ 180—10—320—16—400 ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Revision University Commission ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ।

University Commission ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ 200—15—320—20—400—25—500 ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਨਿਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਯਕੱਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 1954 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ starting salary 250 ਰੁਪੇ ਮਾਹਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ 20 ਰੁਪੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਡਿਗ੍ਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ 150 ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ 375 ਅਤੇ 600 ਪਾਊਂਡ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਨੀ 670 ਰੁਪੇ ਮਾਹਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ U.S.S.R., ਵਿਚ Elementary Schools ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਬਲਜ਼ ਮਾਹਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 24 ਘੰਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ 850 ਰੁਬਲ ਮਾਸਕ ਤਨਖਾਹ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕੇਵਲ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। U. S. A. ਵਿਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ 3,100 ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਨੀ 1,150 ਰੁਪਿਆ ਮਾਹਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਂਡ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ :—

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ	..	120 ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ
ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ	..	120 ,,
ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿਚ	..	140 ,,
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ	..	154 ,,
ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ	..	120 ,,
ਅਜਮੇਰ ਵਿਚ	..	120 ,,
ਅੰਡੇਮਾਨ ਵਿਚ	..	120 ,,

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ Secondary Schools ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ 180 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 120 ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਅਤੇ ਮਗਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 125 ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਅਗਲੀ ਗਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚ ਤਾਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਤਦ ਹੀ ਵਾਜਬ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਬਦਸਤੂਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਲਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਹਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਖਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਹਾਊਸ ਟੁਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਖਾਂ ਰੁਪੇ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਪਰ ਖਰਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ

[ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ]

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ condemn ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਾਹਿਬੇ ਸਦਰ ! ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗਲ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ administrative set-up ਪੁਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਜ਼ੂਲ ਰੁਪਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (Commissioners) ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਘਟਾਕੇ ਇਕ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ duties ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ discharge ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਵਾਏ ਇਕ 'ਲੈਟਰ ਬਕਸ' ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ post ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਉੜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਰੇਟਰੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਰੇਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਮਦ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ੂਲ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਫਿਰ, ਸਾਹਿਬੇ ਸਦਰ, ਫਿਲੌਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ Police Tatoo ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਫਜ਼ੂਲ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ united ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ ਰਕਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 6 ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ; ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰਕਬਾ ਵਗੈਰਾ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਇਥੇ 8 ਵਜ਼ੀਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਲਉ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਅਲਾਉਂਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ; ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅਲਾਉਂਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਲਾਉਂਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। Dearness Allowance, Temparory Allowance, Uniform Allowance, House Rent Allowance, Board Allowance, Compensatory Allowance, Hill Compensatory Allowance, Travelling Allowance, Local Compensatory Allowance, Other Allowances and Honoraria, Travelling Allowance (Fixed), Travelling Allowance (open). Non-practising Allowance, Simla Compensatory Allowance, Hill Allowance. Fixed Cycle Allowance, Project Allowance, Deputation Allowance, Conveyance Allowance. Frontier Allowance, Clothing

Allowance, Equipment Allowance, Recreation Allowance ਅਤੇ Election Allowance 24 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਲਾਊਂਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਸਨਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਜਨਾਬ ! ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ communal ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ administration ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜਕਨ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਿਬੇ ਸਦਰ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਦੋ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੈਰ ਫਿਰਕਾ-ਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ secular ਹੈ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਉ । ਉਸ ਵਿਚ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ minority community ਦਾ ਨਹੀਂ । Superintending Engineers ਵੀ 4 ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ minority community ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ । Electrical Inspector ਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ Minority Community ਦਾ ਹੈ । Executive Engineers Residential Engineers 28 ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 7 ਹੀ minority community ਦੇ ਹਨ । 15 Assistant Engineers Class I ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 6 minority community ਨੂੰ belong ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਕ Accounts Officer ਅਤੇ ਇਕ Tarrif Officer ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ majority community ਦੇ ਹਨ । second Class Assistant Engineers ਦੀਆਂ 41 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 13 ਬੰਦੇ ਹੀ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ minority community ਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ minority community ਲਈ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ scope ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਿਸਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਹਦ ਤਕ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਆੜ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਤੇ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ minority community ਦੇ members ਲਈ high position ਲੈਣਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਗਲ ਹੈ । ਕੀ ਇਸ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ? ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ action ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਤੋਂ ਸੰਗੀਨ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਇਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ clerical staff ਦੀ disintegration ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਂਲਕੋਟ ਵਿਚ 15 ਫਰਵਰੀ 1953 ਨੂੰ ਇਸ

[ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ]

ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ Head ਅਤੇ Circle Offices ਦੇ staff ਨੂੰ disintegrate ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Legal Remembrancer ਦੀ ਰਾਇ ਲਿਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ । ਸੋ Legal Remembrancer ਦੀ ਰਾਇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ । ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ uphold ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ Head Office ਆਪਣੇ junior ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ circle staff ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ senior ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਹਕਤਲਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ 1951 ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਸੰਨ 1952 ਵਿਚ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮ ਘਟ ਹੋਏ । ਅਤੇ ਸਨ 1952 ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਸਨ 1953 ਵਿਚ ਅਠ ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮ ਘਟ ਹੋਏ । ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੁਖ ਵਲ ਝਾਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਰੀ ਚੌਕੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੇਰੀ constituency ਵਿਚ ਧਰਕਾ ਝੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ Punitive Police Post establish ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਨਗੇ ? ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ । ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ element ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ action ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਸੀ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਸੀ ਮਫ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਤਾਜ਼ੀਰੀ ਚੌਕੀ ਬਿਠਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ । ਜਦ ਅਸਲੀ position ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ logic ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ "ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਭਰੇ ਕੋਈ" । ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ military ਦਾ deserter ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਠੋਰ ਵਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ?

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੋਰਾਣਾ ਨਾਉਂ ਦੀ ਇਕ ਜਗਾਹ ਜਗਰਾਵਾਂ constituency ਵਿਚ ਹੈ । ਉਥੇ ਸੂਆ ਟੁਟਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਤਾਵਾਨ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਆ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਆਪਣੇ

ਆਪ ਹੀ ਟੁਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤਾਵਾਨ ਨੂੰ ਘਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ administration ਦਾ !

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਵਲ ਫ਼ਿਰਕਾਦਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਗਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । punitive post ਬਠਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ discrimination ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ੀਰੀ ਚੌਕੀ ਬਿਠਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੀ locality ਵਿਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਇਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ! ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬਿਠਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ discrimination ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਵਾਜਿਬ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ । ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕ ਹਨ । ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਮਿਸਾਲ ਹਨ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸੁਣ ਚੁਕੇ ਹੋ। ਉਥੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ rape ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

Chief Minister : No.

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "no" ਵਿਚ ਕੋਈ force ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੀਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ Enquiry Committee ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਥੇ ਜਾਕੇ enquiry ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੇ। ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ findings ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਥੋਂ ਤੀਕਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ 'No' ਬੇ ਮਹਿਨੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ efficiency ਦਾ standard ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਗਿਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਡਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕੂ ਮਾਲ ਲੁਟਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮੂੰਹ ਹੀ ਤਕਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰਾਹਜ਼ਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੁਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਡਾਕੂ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਇਸਿਕਲ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਹੀ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰਖ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ 'ਨੇਕ ਨਾਮ' ਪੁਲਿਸ ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਇਤਨੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ !

[ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ]

ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ interfere ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਇਆ। ਬੋਗਸ ਈਲੈਕਸ਼ਨ (bogus election) ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬੋਗਸ (bogus) ਪ੍ਰੋਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਿਆ....।

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके उन लोगों के खिलाफ, जो कि यहां हाऊस में अपने आप को defend नहीं कर सकते, कुछ भी कहने से परहेज़ करें ।

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ—ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਇਸਲਈ ਖ਼ੁਦ ਵਜ਼ੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ, defend ਕਰਨਗੇ। ਖ਼ੈਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਦਾਖ਼ਲਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਪੁਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਗਰੁਪ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ political sufferer ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ੍ਰੋ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ (policy) ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਯਾਨੀ "divide and rule"। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੁਟ ਪਾਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ services ਵਿਚ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ representation 19% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 per cent ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਸਣ ਜਿਥੇ ਕਿ 21 per cent ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਇਕ per cent ਵੀ ਅਛੂਤ ਨੌਕਰ ਹੋਣ।

अध्यक्ष महोदय : अब तो कोई अछूत यहां रहा ही नहीं । आप अछूत न कहें । आप Scheduled Caste कह सकते हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ Scheduled Caste ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 21 per cent ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਿਹਾ ਇਕ per cent ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖੋ, ਤਹਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖੋ ਕਿਥ 19 per cent ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਗਿਰਦਾਵਰ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖ ਲਵੋ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵੀ ਉਹ 5 per cent ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ

ਰਖੇ ਗਏ । ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ Scheduled Castes ਨੂੰ 21 per cent ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬੇਵਕੂਫ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਲਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ proportion ਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨ ਗਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਸੌ ਜਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ right ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਨ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਓਸੇਤਰਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੇਤਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੰਬਰਦਾਰ ਬਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਬਰਦਾਰ ਬਨਾਇ ਜਾਨਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ੨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਲਾਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ । ਸਾਡੇ Labour Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਇ ਹਨ ਲੁਧਿਆਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ।

ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੋ ਸੱਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 21 per cent ਡਿਪੋ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ Scheduled Castes ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਨਗੇ । ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੋਟਿਆਂ (Quotas) ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਤਦ ਤਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀ ਫੜਕਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 21 per cent ਡਿਪੋ ਦੇਨ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ control ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀ ਡਿਪੋ ਲੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਠੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਕ ਗੱਲ ਭੈੜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਓਹ ਇਹ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ rationing ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਿਠੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ (ਹਾਸਾ) ।

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੰਤਾ ਦੀ civil liberties ਵਲ

[ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ]
ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । Public Safety Act ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰੇਗੀ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਤਨਾਗਰ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਹੜੇ ਤੋੜ ਫੋੜ ਦੇ ਕਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਖਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ । ਇਸ ਦੇ ਮਾਤਿਹਤ ਮੇਰੇ ਉਤੇ "ਪ੍ਰਭਾਤ" ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਦਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦਫਾ 124 ਅਲੱਫ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ (124-A. I. P. C.) ਦੇ ਹੇਠ ਤੇ ਬਾਕੀ Section 9 of the Public Safety Act ਦੇ ਥਲੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਚਲਾਇ ਗਏ ਸਨ । ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰ New York Times ਨੇ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ democracy ਅਜਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮੁਕਦਮੇ ਚਲਾਏ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸੀ ।

ਸਾਹਿਬੇ ਸਦਰ ! ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਗਠ ਜੋੜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਬ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਈਏ । ਇਸ ਗਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ....

Mr. Speaker: The hon. Member should not discuss the U.S.A.'s Military aid to Pakistan. It has got nothing to do with the Punjab Government.

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਸਾਹਿਬੇ ਸਦਰ ! ਅਸੀ Law and Order ਤਾਂ discuss ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਾਂਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ । ਪਰ ਇਥੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Rifle Clubs ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਅਸਲਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸ ਪੁਰ, ਅੰਮਰਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਅਨੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ।

ਸਾਹਿਬੇ ਸਦਰ ! ਫਿਰ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ transport ਨੂੰ nationalize ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮੈਂ

Transport nationalization ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅਖਬਾਰ Tribune ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਂਦਾ ਹਾਂ।

"The question of Nationalisation of Transport, however, must be viewed in the light of contribution that private enterprise has made and is making in the development of road transport. Has the stage been reached when it can be thrown over-board without caring for the consequences ? Will it not be more advisable on the part of the Government to develop in the first instance undeveloped areas leaving private enterprise untouched for the present"

ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ transport ਨੂੰ nationalize ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਵੀ communalism work ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ PEPSU election ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਰੋਪੜ Sub-division ਵਿਚੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰਾਂ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਉਥੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ particular ਆਦਮੀ ਨੂੰ elect ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ! ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

राम्रो गजराज सिंह (गुड़गांव) : श्रीमान् स्पीकर साहिब ! बजट पर जो अभी Opposition के लीडर साहिब ने तकरीर फ़रमाई है उसे सुन कर मुझे बड़ी हैरानी हुई है। मैं समझता हूं कि जब एक ठीक और सही बात कही जाये तो उस का असर होता है लेकिन अगर उसे गलत बयान किया जाये तो उस का असर नहीं हो सकता। आज इस बजट पर जो इस तरह की बहस हुई है वह शायद आज से छः साल पहले लाहौर में हुई होगी जब यह सोचा जाता था कि services में इस community की इतनी proportion हो और उस की इतनी। यहां तो proportion का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि किस नज़रिये से हम ने इस बजट को देखना है।

मैं कोई गवर्नमैण्ट का apologist नहीं हूं लेकिन यह चीज़ तो दिखाई दे रही है कि यह बजट डिवैलपमैण्ट वाला और एक Welfare State का बजट है, पुलिस State का बजट नहीं है। पुराना रवैया तो हकूमत का यह था कि इन्तज़ाम किया जाये और डंडे के ज़ोर से किया जाये। उस में अब तबदीली आ गई है लेकिन expectation के मुताबिक पूरी बात नहीं हो सकी। अगर पूरी तरह राम राज्य स्थापित हो जाये तो शायद असैम्बली की भी ज़रूरत न रहेगी। इसलिए देखना यह चाहिये कि गवर्नमैंण्ट आगे जा रही है या पीछे।

मैं कोई ज्यादा लम्बी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा लेकिन आप का ध्यान Finance Minister की speech के सफ़ा 37 के पैरा 35 में दी गई figures की

[राम्रो गजराज सिंह]

तरफ दिलाता हूं। मैं इन figures को दोहराना नहीं चाहता। यहां पर Consolidation of Holdings, Local Development Works, National Extension Service, Community Project, etc., 6, 7 heads दिये हैं। इन के देखने से ही पता चल जाता है कि State किस तरफ जा रही है। इन पर बहस करने की जरूरत नहीं। इन figures को देखने के बाद भी अगर आप कहें कि यह एक development का बजट नहीं है तो क्या है ? मैं समझता हूं कि जहां तक गवर्नमैण्ट की policy का ताल्लुक है वह तो एक वैल्फ़ेयर स्टेट (Welfare State) की है। हां ; इस की execution में खामियां हो सकती हैं।

पालिसी के मुतअल्लिक अगर शिकायत हो सकती है तो वह दो जिलों अर्थात् कांगड़ा और गुड़गांव के मुतअल्लिक ही हो सकती है। (विघ्न)। बाकी जिलों जैसे जालन्धर डिवीजन, जहां कि top heavy administration है, के मुतअल्लिक अगर कम्यूनिस्ट भाई कुछ शिकायत करें तो यह उन की पालिसी के बमूजब होगा। जितना भी undeveloped area रहेगा उतनी ही discontentment भी रहेगी। (*Interruptions*) यह अहसान फरामोशी का सवाल नहीं है, हक का सवाल है। इन जिलों के मुअताल्लिक वाजे तौर पर रिकार्ड में लिखा है कि यह recruitment areas हैं। भूखा आदमी जल्दी cannon fodder बनने के लिये तैयार हो जाता है। इसलिय इन इलाकों को develop नहीं किया गया। दूसरी वजह इस की यह थी कि गदर के दिनों में अंग्रेज के मुकाबले में यहां के लोगों ने नुमायां काम किया था जब कि दूसरे इलाकों ने अंग्रेजों की मदद की थी। हमें इस की यह सजा मिली। लेकिन मैं गवर्नमैण्ट का मशकूर हूं कि इस ने अब भूखे लोगों की तरफ भी ध्यान देना शुरु किया है। गुड़गांव की खुशहाली के लिये हमारे काबिल Chief Engineer ने बड़ा काम किया है और स्कीमें बनाई हैं जिन्हें अमली शकल दी जा रही है। गुड़गांव प्राजैक्ट स्कीम के बारे में अमली कदम उठाने के लिये मैं मिनिस्टर साहिब का फिर मशकूर हूं। (तालियां) यह मदद अगर्चि उस मदद का 10 फी सदी बल्कि 1 फी सदी भी नहीं है जो कि इन जिलों की होनी चाहिये लेकिन यह right direction में एक कदम है। मसलन पीने के पानी के लिये sanitary grant दी गई है। जो लोग इधर गये हैं उन्हों ने देखा होगा कि सौ २ गांवों में पीने का पानी नहीं मिलता। महमान के आने पर फ़िक्र यह होती है कि पानी कहां से आयेगा ? खाने के मुतअल्लिक इतनी फ़िक्र नहीं होती। इस लिये इस तरफ यह अच्छी इब्तदा की गई है। फिर Education की grant है। जो लोग यह कहते हैं कि Education के लिये रखी गई रकम फालतू है वह ठीक नहीं कहते। मेरी यह दरखास्त है कि backward areas में Education को फैलाने की पालिसी की तरफ सरकार को खास ध्यान देना चाहिये।

इस पहलू से भी अगर हम बजट को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि यह एक development करने वाला और एक Welfare State का बजट है।

हां, अगर कोई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर इन ज़िलों को मदद दी गई तो यह हमारे बराबर हो जायेंगे तो उन की इस जहनियत से हम पता लगा सकते हैं कि ऐसे लोग State और पार्टी के कितने बहीखाह हो सकते हैं। State की तरक्की तभी होगी जब इस के तमाम हिस्से तरक्की करें। अगर कुछ इलाके ऊपर न उठाये गये तो सारी स्टेट backward रह जायेगी—इस के मुतअल्लिक मैं इतना ही कह कर इक्तफा करूंगा।

फिर हमारे Finance Minister साहिब ने deficit budget पेश किया है और उस में 30 लाख रुपये की एक रकम Land Revenue से पूरी की गई है। इस से मुझे इत्तफ़ाक नहीं है। मैं अर्ज़ करूंगा कि पिछले सालों में जो बजट सामने आये उन में 90, 95 लाख रुपये के घाटे को uncovered छोड़ा जाता रहा था Land Revenue से पूरा करने की कोशिश नहीं की गई। पहले एक Taxation Enquiry Committee बनाई गई थी जिस ने All over India enquiry की और रिपोर्ट तैयार की, इस में हमारे Finance Minister बतौर गवाह पेश हुए थे। इस कमेटी ने जिस में प्रोफैसर बृज नारायन जैसे माहरे इक्तसादियात भी शामिल थे, फ़ैसला किया कि Land Revenue एक टैक्स नहीं बल्कि एक feudal estate का rent है। बिसवेदारों की तादाद कम है और ज़मींदारों की ज़्यादा। इसलिये माल गुज़ारी किसानों को देनी पड़ती है। इन के पास आगे ही कुछ नहीं होता—माल गुज़ारी देने के लिये इनके पास एक पैसा भी नहीं होता। अगर आप sliding scale पर चलें और छोटे बिसवेदारों को मामला ज़मीन के बोझ से मुसतस्ना कर दें तो अच्छा होगा। मामला ज़मीन मालगुज़ारी नहीं है। Unionist Government ने भी यही फैसला किया था। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस का बोझ मालगुज़ारी पर डालना अच्छा नहीं। यह कांग्रेस की सही पालिसी नहीं है और न ही यह सरकार की पालिसी कहला सकती है।

इस के बन्दोबस्त के लिये अगर हम सही टाईप (type) के S. D. O. लगायेंगे और Settlement अफसर इमानदारी से काम करेंगे तो curruption दूर होगी और माल गुज़ारी का बोझ छोटे बिसवेदारों पर कम हो जायगा। अगर इस बात पर सरकार ज़मीन की consolidation से पहले ग़ौर कर लिया करे तो यह बात मुमकिन हो सकती है। मगर इस बात की indication बजट में नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि यह बजट ready and rough method से तैयार किया गया है। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि छोटे बिसवेदारों पर जो बोझ हो रहा है इस की तरफ ध्यान दिया जाए।

इस में शक नहीं कि गवर्नमैण्ट ने रिश्वत को दूर करने के लिये anti-corruption measures adopt किए हैं लेकिन यह अब भी continue कर रहीं है। जो कि इस method से दूर नहीं की जा सकती। consolidation के बारे में corruption की वजह यह है कि इस में छोटे २ पटवारियों और तहसीलदारों को rapid promotions दी गई हैं। नालायक तहसीलदारों को

[राम्रो गजराज सिंह]

Sub-Divisional Officer, Settlement Officer और Consolidation Officers बना दिया गया है। यह भी एक किस्म की corruption है। मैं Development Minister साहिब से दरखास्त करूंगा कि वह इस बात का ख्याल रखें कि उन आदमियों को तरक्की दी जाए जो consolidation के काम से अच्छी तरह वाकिफ़ हों ताकि वह सरकार की इस तरफ की कोशिशों को पूरा कर सकें।

इसी तरह ही पुलिस का महकमा है। हम देखते हैं कि आज तक वही अफसर हैं—वही Superintendent Police, Senior Grade Superintedent, Police हैं जो कि जाबराना period में थे। अंग्रेज़ों के वक्त जो Sub-Inspector थे उन को तरक्की देकर Superintendent, Police और इस से भी बड़े ओहदों पर लगा दिया गया है। उन के हाथों में पुलिस की सारी ताकत है और वह इस का अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नमैण्ट को ऐसे लोगों पर और इन की कार्रवाईयों पर vigilant eye रखनी चाहिये और strict control करना चाहिए ताकि उन्हें उन के जाबराना तरीकों से check किया जाये। इस में शक नहीं कि उन की तनखाहें बढ़ा दी गई हैं लेकिन मैं समझता हूं कि वह तनखाहें कम होने की वजह से रिश्वत लेने पर मजबूर थे। मगर अब हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि इन से corruption दूर हो जाये और हमारी पुलिस एक ideal पुलिस बन जाये।

तीसरा महकमा जिस में बहुत रिश्वत चलती रही है और जो सब से ज्यादा बदनाम है वह Civil Supplies Department है। अब जब कि इस Department को तोड़ा जा रहा है मैं चाहता हूं कि उन अफ़सरों को जिन की वजह से यह डिपार्टमेंट बदनाम हुआ है दुबारा employ न किया जाये। इस से मेरा यह मतलब नहीं कि इस महकमे के सब के सब लोग बेईमान या corrupt थे लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 80 या 90 प्रतिशत अफ़सर corrupt थे। इस महकमे में जो थोड़े बहुत ईमानदार अफ़सर हैं उन को दूसरी जगहों पर employ किया जा सकता है और जिन के बारे में रायआमां सख्त खिलाफ़ है उन को अगर employ कर लिया गया तो corruption को बढ़ने का और भी ज्यादा मौका मिलेगा।

इस के बाद मैं देखता हूं कि Civil Supplies Department के Officers को Community Pojects के मातहत employ किया जा रहा है। चूंकि इन स्कीमों से villages में development होनी है इसलिये अगर ऐसे अफ़सर वहां लगा दिय गये तो उन को लोगों की हमदर्दी या सहयोग न मिल सकेगा और वह national programme को मिल कर पूरा न कर सकेंगे। इसलिये मेरी यह suggestion है कि Community Project के महत्त्व के पेशे नज़र यह ज़रूरी है कि यहां पर ईमानदार अफ़सर लगाये जायें और ऐसा element लगाया जाय जो corruption से पाक हो।

एक और बात जिस के बारे में मैं ज़िक्र करना चाहता हूं वह Judiciary को Executive से separate करने के मुतअल्लिक है। इस का ज़िक्र फ़िनांस मिनिस्टर (Finance Minister) साहिब की बजट स्पीच में आया है। ठीक है कि गवर्नमेंट इस बात की ओर ध्यान दे रही है और यह एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है मगर इस में एक lacuna नज़र आता है जो नहीं होना चाहिये। इस separation का ज़िक्र साफ़ तौर पर होना चाहिये। मेरी तजवीज़ है कि Additional District Magistrate और Superintendent Police मैजिस्ट्रेटों की सालाना रिपोर्टें न लिखा करें। वरना यह Separation बे-मानी हो जायगी। मैं समझता हूं कि इन की रिपोर्टें सैशन जज लिखा करें। Superintendent Police की domination से Judiciary separate नहीं होती। रिपोर्टें लिखने वाली अगर Executive ही रहे तो यह separation नहीं कहला सकती।

ठीक इसी तरह हमारे बराबर की स्टेट पैप्सू में राजाशाही के ज़माने में Judiciary को Executive से separate करने का फ़ैसला किया गया था। अब तो हिन्दुस्तान के आईन में भी यह रखा गया है कि Judiciary को Executive से अलग करने के लिये सूबाई हकूमतें मुनासिब कदम उठायें। इसलिये मेरी गुज़ारिश है कि चीफ़ मिनिस्टर साहिब इस मामले पर खुद ज़रा और ध्यान दें। मैं चाहता हूं कि बेशक यह तजुरबा 6 की बजाये एक ज़िले में ही किया जाये मगर Judiciary को पूरे तौर पर आज़ादी दी जाये। मजिस्ट्रेटों को सैशन जजों और हाईकोर्ट के मातहत कर दिया जाये और prosecution स्टाफ़ को Advocate-General के मातहत कर दिया जाये। अगर ऐसा न किया गया तो यह सारी स्कीम illusory होकर रह जायगी।

एक बात decentralization के बारे में भी मैं अर्ज़ करना चाहता हूं और वह यह है कि यह अच्छा किया गया है कि तहसीलों को Sub-Division बनाया जा रहा है और हैडक्वाटर्ज़ में 8—10 अफ़सर काम करेंगे। मगर इन्सान से गलती हो सकती है और इन अफ़सरों से भी। इस लिये हमें कोशिश करनी चाहिये कि राज्य का prestige कायम रखने के लिये ऐसे अफ़सर लगाए जायें जिन की integrity above board हो और जिन पर कोई शक न कर सके ताकि यह experiment सफल हो। अगर ग़लत किस्म के आदमी लिये गये तो वह गलत काम करेंगे और गवर्नमेंण्ट की बदनामी का बाइस होंगे।

स्पीकर साहिब! मजमूही तौर पर, इस बजट में खामियां तो ज़रूर हैं मगर मैं समझता हूं कि चाहे कोई भी पार्टी administration की बागडोर अपने हाथ में ले ले यह खामियां रहेंगी। लेकिन फिर भी जब मैं बजट की खूबियों को देखता हूं तो फिनांस मनिस्टर (Finance Minister) साहिब को मुबारकबाद दिये बिना नहीं रह सकता।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ (ਨਕੋਦਰ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ (Finance Minister) ਦੀ ਸਪੀਚ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਘੇੜ ਕੇ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ]

ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਲਾ ਐਂਡ ਆਡਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ Development State ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਗਲ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ adminisrtation ਦਾ ਖਰਚ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗਲ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਵੈ ਵਿਰੋਧ (self contradiction) ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਅਜੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਜੋ ਔਕੜਾਂ ਹਾਇਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! development ਸੰਬਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਜੇਕਰ ਆਰਥਕਤਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਹਦ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁਤਹਰੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਨ (plan) ਕਰਨਾ ਅਤੇ development ਕਰਨਾ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਭਦੀਆਂ।

ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਸਿਰਫ ਖਰਚੇ ਪਾਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮਿਤਰ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਸਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਤੇ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਕਪੜੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਛਾਂਗਾ ਕਿ ਫੇਰ handloom cloth ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ? ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਥੇ handloom industry ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਾਲ ਲੈਕੇ ਆਏ ਉਹ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਆਖਰ ਇਹਦੀ ਵਜਹ ਕੀ ਹੈ ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੀ 10,000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ

ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਖਰ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਪੜੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ cost ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 4 ਆਨੇ ਫੀ ਰਛ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਕਮਾਈ 5 ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ । ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਉਥੇ ਉਸ ਦੇ ਟੋਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੰਦਵਾੜਾ ਵੀ ਅਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਇਕੋ ਪਾਸਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, Five-Year Plan ਨੂੰ finance ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ plan ਨੂੰ finance ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਹਨ । ਇਕ taxation ਤੇ ਦੂਜਾ deficit financing । ਜਿਥੋਂ ਤਕ taxation ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Betterment Levy ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਤੇ tax, ਬਿਜਲੀ ਉਤੇ tax ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਛਡਿਆ ਹੈ । ਹਾਲਾਂ ਤੀਜਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਸ ਇਹੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ !

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕੀ ਅਸਾਂ industry ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਿਆਨ ਦੀ ਇਕ ਮਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਇਆ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿਚ metal ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ industry ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 horse power ਦੀ ਮੋਟਰ ਵਰਤਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ 21 horse power ਦੀ ਮੋਟਰ ਵਰਤੇਗਾ ਤਾਂ ਓਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ 21 horse power ਦੇ rate ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ plan ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ development ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ? ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧਾਨ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਹਸ਼ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਖਦੇ ਹਨ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਵੀ development ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ plan ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ । ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ plan ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ । ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ plan ਬਨਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਹੋਰ tax ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹੀਓ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ]

ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ plan ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

Federation of Commerce and Industry ਦੇ ਰਸਾਲੇ 'Commerce' ਵਿਚ ਇਕ article ਛਪਿਆ ਹੈ " plan ਫੇਲ ਕਿਓਂ ਹੋਇਆ "। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਏਡੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ plan ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹਨ ਓਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ plan ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਓਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ plan ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ? ਅਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਮਲੂਮ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗਲ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮਿਆਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਫ਼ਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ (Finance Minister) ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਸਨ ਕਿ ਇਤਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਹੁਣ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਤਨੇ United Punjab ਵਿਚ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਓਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਚੀਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਜਰਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਚਾਰ ਆਨੇ ਦੀ ਥਾਂ 5 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਨਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਥੇ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਕਾ ਨਹੀਂ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਤੀਸਰੀ ਗਲ ਸਨਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ Industries ਦੀ Demand ਉਤੇ ਬਹਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿਛੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਈ ਮਾਤ੍ਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਨਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨਾ ਹੀ ਰੁਪਿਆ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਸ ਕਈ ਚੀਜ਼ੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਚਾ ਮਾਲ ਬਾਹਿਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਨਿਆ ਹੋਇਆ (manufactured) ਮਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਚਾ ਮਾਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਹਦੇ ਕਿ ਬਨੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦੇਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਖੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਚਮੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਨੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਕਚਾ ਮਾਲ ਆਪ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਬਨਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਸ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ nationalisation of transport ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ books nationalize ਹੋ ਜਾਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਹਾਂ 30 ਜਾਂ 40 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਏਹ ਕਮ ਸਨਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਨਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਵਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡੀ ਸਨਅਤ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਅਸੀ ਕਦੇ ਆਸੂਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ figures ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਲ ਅਉਂਦਾ ਹਾਂ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਤੁਹਾਡਾ 'ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ' ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ expert ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ jugglery ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਇਨਾਂ ਸਰਲ ਬਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਰਲ ਬਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਖਰਚ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ roads ਦੀ development ਵਲ ਵੇਖਿਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਸੜਕ ਦਾ ਟੋਟਾ ਕਈ ਮਦਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਟੋਟਾ Community Project ਦੀ ਸਕੀਮ, National Development ਅਤੇ P.W.D. Buildings and Roads Branch ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ administration ਉਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਵਖਰੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ Centre ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ grant ਮਿਲ ਜਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਾ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਤਨਾਸਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘਟ ਹੋ ਗਿਆ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ]

ਹੋਵੇ । ਫੇਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 750 ਰੁਪੇ ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਂ ਧਮਕੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਜਾਗੀਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਗੀਆਂ । ਇਸ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ police ਅਤੇ administration ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟ ਮਲੂਮ ਹੋਵੇ । ਨਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਘਟ ਖਰਚ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ Supplementary Estimates ਵਿਚ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਏਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਦ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ police ਅਤੇ administration ਉਤੇ ਖਰਚ ਘਟੇ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ deficit budget ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਕਸਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ । ਜੇ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ budget surplus ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਵੇਲੇ deficit budget ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ development ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਘਾਟਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕੁਝ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਟੈਕਸ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਲਗਾਨ । Deficit ਵਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਕਰਜ਼ਾ ਇਸਤਰਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ output ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਏਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸੂਦ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾਂ Pepsu ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ budget ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇੰਝ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦੀ budgeting ਹੈ ।

ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ relief ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਣਕ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਆਬਿਆਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਕੀ relief ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? ਹਾਂ, ਉਸਤਰਾਂ ਤੇ professors ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਲੋਕ 300 ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰੰਤੂ ਹਕੂਮਤ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਕਰੋ । ਇਸ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਹ ਗਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । 30 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ

ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 20 ਜਾਂ 30 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ Surcharge ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Motor Vehicles Tax ਨੂੰ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋਹੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਕੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ relief ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ development ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ radical change ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ Agrarian Reforms ਤੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Rehabilitation policy ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : Please wind up your speech.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ development ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ bureaucratic system ਵਿਚ radical change ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1947 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ tax structure ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਧ ਜਾਣ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਸੂਲੀ 25 ਲਖ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚ 32 ਲਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚ 7 ਲਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ 57 ਲਖ ਖਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਕੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਸਨਅਤ ਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਮਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

चीफ़ पार्लीमेंट्री सैक्रेटरी (श्री प्रबोध चंद्र) : स्पीकर साहिब ! मैंने अपने मोहतिरम दोस्तों यानी अकाली पार्टी के लीडर और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर की तकरीरों को सुना है और चन्द मिनटों में उन की तकरीरों का जवाब दूंगा इसलिये नहीं कि वह हकीकत पर मबनी हैं बल्कि इसलिये कि वह लोग पार्टी के लीडर हैं। यहां पर जो तकरीरें विरोधी

[चीफ़ पार्लीमेंट्री सैक्रेटरी]

दल की तरफ से की जाती हैं उन के मुतअलिक बाहर के लोग समझते हैं कि जिम्मेदार पार्टियों के लीडर होने की हैसीयत से जो कुछ वह कहते हैं हकीकत पर मबनी होगा। इसलिये मैं मुनासिब समझता हूं कि उन की बातों का जवाब दिया जाये। मेरे अकाली पार्टी के दोस्त ने अपनी तकरीर इस बात से शुरू की कि services में फ़िरकाप्रस्ती बहुत बढ़ गयी है। उस के बाद उन्होंने कहा कि जब पुलिस चौकियां किसी जगह बिठाई जाती हैं तो उस में देहात और शहर के लोगों का ख्याल रखा जाता है। उस के बाद उन्होंने कहा कि लुध्याना ज़िला के हालात को देखें तो ऐसा मालूम होता है कि गवर्नमेंट नाअहिल है और पुलिस का महकमा नाअहिल है। डाकू शहर में डाका डालते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकती। आखिर में उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की पालिसी वही है जो ब्रिटिश गवर्नमैण्ट के वक्त थी और गवर्नमैण्ट divide and rule के सिद्धांत पर अमल कर रही है। जहां तक उन के इस इलज़ाम का ताल्लुक है कि सरकार divide and rule के असूल पर चल रही है मैं समझता हूं कि उन का यह कहना बिल्कुल गलत है। यह लोग जो ऐसा कहते हैं वह असल में खुद इसी असूल पर चल रहे होते हैं। उन्होंने अपनी लीडरी को कायम रखने के लिये कुछ साल पहिले हिन्दुओं और सिखों को आपस में लड़ा दिया और मुसलमानों और ईसाईयों को लड़ा दिया। पिछले दिनों जब गवर्नर के एड्रैस पर बहस हुई तो मेरे बहुत से भाइयों ने गवर्नमैण्ट का ध्यान रोहतक के हालात की तरफ दिलाया। जब बार बार बहिनों का नाम लेते हुए उन के जज़बात को सुनता था तो मेरा सिर शर्म के मारे झुक जाता था। 1947 में खून की होली खेली गई और लोगों के जज़बात भड़काये गये और हज़ारों की तादाद में लोगों को कत्ल कराया गया। उस के बाद प्रजा परिषद् आन्दोलन जारी हुआ और ऐसी literature छापी गई और ऐसे नारे लगाये गये कि बहुत सी औरतों की बेइज्ज़ती की गई। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि अब औरत के नाम के साथ इतनी इज्ज़त की छाप लगी हुई है कि कोई आदमी औरत की बेइज्ज़ती को बरदाश्त नहीं कर सकता। मैं विरोधी दल से कहूंगा कि अगर उन्हें औरत की ज़ात से सचमुच प्यार है तो अव्वल तो कोई बात ऐसी वहां नहीं हुई अगर हुई भी होती तो भी उन्हें इस एवान से बाहर जा कर करनी चाहिये थी। मैं समझता हूं कि उन्होंने ऐसा करने से हाऊस की शान नहीं बढ़ाई। मैं उन्हें कहूंगा कि इस जमहूरियत के ज़माना में आइनी राजा का बेटा ही उस के बाद आइनी राजा नहीं बन सकता बल्कि एक अरदली का बेटा मुख्य मंत्री और मुख्य मंत्री का बेटा दाता गंज का मुजावर बनाया जा सकता है। जो बातें आज जज़बात के ज़ेरे असर कही जा रही हैं उन के मुतअल्लिक हमारी आने वाली नसलें कहेंगी कि आज़ाद पंजाब में पहली इलैक्शन के बाद असेम्बली में गैर ज़िम्मेदारी से तकरीरें होती थीं और यह कहेंगी कि बहस का मियार बहुत नीचा था। जनाबे वाला! मैं जज़बात से नहीं खेलना चाहता और न ही लोगों के जज़बात भड़का कर अपनी leadership कायम रखना चाहता हूं।

यह कहा गया है कि हमारी गवर्नमैण्ट नाअहिल है। मेरे माननीय मित्र विरोधी दल के नेता इस वक्त अपनी जगह पर विराजमान नहीं हैं। उन के दोस्त यहां मौजूद हैं। मैं उन से

पूछता हूं कि क्या पाकिस्तान और अमरीका को मज़बूत करने का यह नमूना है जो फ़तहगढ़ में पेश किया गया था। जनाब वाला ! हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल की शान के खिलाफ़ आवाज़ें कसे गए जिन्हें सारे हिंदुस्तान की जनता का एतमाद हासिल है। उन के इस किस्म के मुज़ाहिरे से यह पता लगता था कि सिख जनता पंडित जवाहर लाल नेहरू की गवर्नमैण्ट के साथ नहीं है। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि क्या हिंदुस्तानी अवाम पंडित जवाहर लाल नेहरू के साथ हैं या नहीं। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह मुज़ाहिरा करने का तरीका है कि हिंदुस्तानी अवाम अमरीका-पाकिस्तान के समझौते के खिलाफ हैं ?

श्रीमान् जी ! मेरे इस दोस्त की पार्टी के लोगों की तरफ़ से PEPSU के election campaign में हमारे एक वज़ीर के बरखिलाफ़ जो नारे लगाये गये थे वह किस किस्म के थे ? फिर भी मेरे वह दोस्त कहते हैं कि PEPSU के election में सरकारी अफ़सरों की मुदाखिलत कराई गई है। मैं पूछता हूं कि जो नारे जवाहर लाल जी के विरुद्ध लगाये गये थे वह किस किस्म के थे ?

Sardar Sarup Singh : He is again persisting in irrelevant things.

Mr. Speaker : He is not doing so.

चीफ़ पार्लीमैंटरी सैक्रेटरी : फिर श्रीमान जी, यह कहा गया है कि शिरोमणि गुरद्वारा कमेटी का कब्ज़ा नागोके ग्रुप को पुलिस की लाठियों के साये में दिलाया गया था। मैं इन दोस्तों से कहता हूं कि अगर अब भी आप के पास शिरोमणि गुरद्वारा कमेटी में majority है तो आओ इमतिहान ले लो। इन की ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुरद्वारा कमेटी के बजट पास होने के समय जहां नागोके ग्रुप को 78 वोट मिले इन को केवल 38 वोट मिले। फिर भी यह लोग कहते हैं कि हमने इन से बेईमानी के साथ गुरद्वारा कमेटी की गद्दी छीनी है। इन हालात में जब कि majority इन के साथ नहीं है तो इन्हें गुरद्वारा कमेटी की गद्दी कैसे मिल सकती है ?

Sardar Sarup Singh : I would pay you back.

Chief Parliamentary Secretary : You will be amply paid back.

Mr. Speaker : I wonder why a sober man like you should interrupt so often.

चीफ़ पार्लीमैंटरी सैक्रेटरी : श्रीमान जी ! शायद इन को पता लग गया है कि मैंने आप से वायदा किया है कि मैं कोई नामुनासिब बात नहीं कहूंगा और इसी वजह से यह इस तरह interrupt कर रहे हैं। मुझे इस सामने बैठे अपने दोस्त का एहतराम है चाहे वह अकल की बात करें या न करें।

Sardar Sarup Singh : Shut up.

Mr. Speaker : You cannot use such expressions. If you behave like that again, I will have to name you.

Sardar Sarup Singh : Sir, he is talking about irrelevant things.

Mr Speaker : It is for me to decide whether a Member is making a relevant remark or not. As the Leader of the Opposition levelled certain charges against the Government in connection with the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee he is perfectly within his rights to reply to those charges.

मौलवी अब्दुल गनी दार : On a point of order, Sir. मैं अर्ज करना चाहता हूं कि क्या आप जाती हमले करने की इजाजत देते हैं ?

Mr. Speaker : Carry on please.

चीफ पार्लीमैंटरी सैक्रेटरी : श्रीमान जी ! क्योंकि debate में कुछ तलखी आ गई है इसलिये मैं अब इन बातों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा ।

मेरे कम्युनिस्ट दोस्त ने एक बात का ज़िक्र अपनी तकरीर में किया है । उन्होंने कहा है कि पहले जहां एक मज़दूर चार आने फ़ी गज़ के हिसाब से मज़दूरी लेता था आज वह पांच पैसे फ़ी गज़ लेता है । मैं उन से जानना चाहता हूं कि आज से 10 साल पहले मज़दूर की रोज़ाना मज़दूरी क्या थी और आज क्या है ? मैं समझता हूं कि अगर वह इस बात को जानते होते तो यह न कहते । आज से 10 साल पहले कारखानों में जो spindles होते थे वह दकयानूसी किस्म के थे । उस वक्त अगर एक मज़दूर एक घंटे में एक गज़ कपड़ा बनाता था तो आज वह एक घंटे में 10 गज़ बनाता है । और इस तरह से वह 1942 में रोज़ाना मज़दूरी के तौर पर केवल १ रुपया ८ आने या एक रुपया 10 आने लेता था । आज उस की रोज़ाना मज़दूरी २ रु. ८ आने बन जाती है ।

दूसरी चीज़ जो मेरे सामने बैठे दोस्त ने कही है वह betterment fee के बारे में है । मुझे इस बात का फ़ख्र है कि भाकड़ा डैम जो आज से पांच छः साल पहले एक ख़ाब था आज एक हकीकत बन गया है । मुझे फख्र है कि पंजाब की सरकार इतना बड़ा डैम बना रही है और इस ने नहरों का एक जाल बिछा दिया है । आज से पहले उस इलाके में जहां इन नहरों का पानी जाना है ज़मीन पानी न होने की वजह से १५ रु. एकड़ मिल सकती थी । आज वहां पर चप्पा चप्पा ज़मीन को पानी दिया जाना है । इसलिये उसी ज़मीन की कीमत ५०० रु. फ़ी एकड़ हो गई है । यह उस ज़मीन की कीमत नहरों का पानी आ जाने से बढ़ गई है । आज अगर उस ज़मीन से एक मन फ़ी एकड़ की पैदावार होती है तो नई नहरें खुल जाने से यह पैदावार १० मन फ़ी एकड़ हो जायगी । अगर सरकार ज़मींदारों को यह कहे कि इस मुनाफ़े का कुछ हिस्सा सरकार के कर्ज़े की तरफ़ लगाओ तो यह किस तरह से घाटे का सौदा है ? अगर उस ज़मीन से जिस से आज एक पाई की आमदन नहीं होती, १५ रु. फ़ी एकड़ की आमदन हो जाये तो betterment fee देने में क्या घाटा है ? यह हकीकत है । अगर मेरे दोस्त लोगों के जज़बात के साथ खेलते हैं और हकीकत से इनकार करते हैं, तो यह ठीक नहीं है ।

फिर मेरे दोस्त ने कहा है कि सरकार ने electric charges के बारे में एक horse power पर 3 रुपये का tariff लगा दिया है, इस तरह से अगर सरकार किसी को 20 horse power देती है तो उसे 60 रु. tariff के तौर पर देने पड़ते हैं। अगर एक आदमी के पास 20 horse power बिजली है परन्तु उसे इतनी power की जरूरत नहीं तो वह किसी दूसरे को जिस को connection नहीं मिला power दे कर उस से रुपये वसूल कर लेता है। जब सरकार से एक कारखानदार 20 horse power बिजली मांगता है तो सरकार को उस के लिये 20 horse power reserve करनी पड़ती है। अगर वह उसको इस्तेमाल नहीं करता और दूसरों को दे देता है तो वह कारखानेदार का कसूर है। इस बात को रोकने के लिये यह tariff रखा गया है ताकि जिन कारखानेदारों की जरूरत genuine है उन को बिजली मिल सके। ऐसा करने से ही हमारा देश और सूबा आगे बढ़ सकेगा।

एक दोस्त ने कहा है कि पंजाब को गिरवी रखा जा रहा है। मैं पूछना हूं कि पंजाब ने जितना कर्जा लिया है क्या उस में से एक पाई भी ऐसी है जिसे सरकार ने अपने day-to-day expenses को पूरा करने के लिये इस्तेमाल किया है? अगर यह कर्जा सरकार ने नहरें बनाने के लिये और घर घर में बिजली मुहैया करने के लिये इस्तेमाल किया है तो इस लिये कि लोगों का standard of living ऊंचा हो। आखिर सरकार के पास कोई अलादीन का लैम्प तो है नहीं। लोगों का standard of living ऊंचा करने के लिये रुपया खर्च करना ही होगा। अगर मेरे दोस्त चाहते हैं कि लोगों का standard of living ऊंचा हो तो आवश्यक खर्च करना ही पड़ेगा।

स्पीकर साहिब! मुझे यह देख कर हैरानी होती है कि एक तरफ़ तो दुहाई दी जाती है कि अवाम का standard ऊंचा नहीं किया जाता और दूसरी तरफ़ जब सरकार विकास योजनाओं द्वारा ऐसा करने की कोशिश करती है तो कहा जाता है कि पंजाब को गिरवी रखा जा रहा है। रोहतक के बारे में हमारे दोस्त अगर यह कहते कि डाकुओं को खत्म करके सरकार ने उन की लीडरी खत्म कर दी है तो यह ज्यादा ठीक होता मगर अफ़सोस की बात है कि उन्होंने बहिनों और औरतों का नाम ले ले कर जज़बात से खेलना मुनासिब समझा। उन्हें तो मायूसी हो रही है क्योंकि नहरों के जाल बिछा कर लोगों की भलाई की स्कीमों पर करोड़ों रुपये का खर्च कर के सरकार उन के हाथ से वह मसाला छीन रही है जिस पर उन की पार्टी की खुशहाली निर्भर है। उन की पार्टी तो केवल उसी सूरत में चल सकती है कि अवाम मुफ़लिस और तंगहाल रहें। वह जानते हैं कि सरकार ने सूबे को आगे ले जाने के लिये जो इकदाम किये हैं वे Communist Party को पनपने का अवसर नहीं देंगे। अगर वह इस चीज़ को मान लेते और साफ़ २ शब्दों में कह देते तो मैं उनकी प्रशंसा किए बिना न रह सकता।

इन चंद शब्दों के साथ मैं अपने सामने बैठे दोस्तों से अपील करूंगा कि वे हर बात की constructive तरीके से जांच करें और constructive suggestions दे कर लोगों को आगे ले जाने में सरकार की मदद करें क्योंकि तीन साल के बाद उन्हें फिर उन के सामने जाना होगा जिन्हें वे 'अवाम' कहते हैं।

मौलवी अबदुल गनी दार (नूह): स्पीकर साहिब ! किसी मुस्सवर का यह कमाल नहीं कि वह हमारे हाऊस के Leader या Chief Parliamentary Secretary साहिब की तसवीर बनाये। मुस्सवर तो वह है जो Development Minister साहिब या मेरे जैसे आदमी की तसवीर को खूबसूरत बना कर दिखाये।

Mr. Speaker : I fail to appreciate your point.

मौलवी अबदुल ग़नी दार : मुझे भी फखर है और मेरे सूबे को भी फखर है कि उन्होंने मेरे जैसे आदमी की तसवीर भी निहायत खूबसूरत बना कर सारे पंजाब बल्कि सारी दुनिया के सामने पेश की है।

इस में शक नहीं कि मेरी सरकार ने बाज़ ऐसी बातें कही हैं जिन की तारीफ़ मुझे करनी है लेकिन Finance Minister साहिब ने जो बजट पेश किया है उस को पढ़ कर मुझे वह कहावत याद आती है कि 'हलवाई की दुकान, और नाना जी का फातिहा'। यह बात ग़लत नहीं है क्योंकि मरकज़ी सरकार से कर्जे ले २ कर ही खाते को पूरा किया जा रहा है, नहरों के जाल बिछाये जा रहे हैं, भाकड़ा-नंगल के चर्चे हो रहे हैं और Community Projects चलाये जा रहे हैं। इन से पंजाब के लोगों को कितना फायदा पहुंचेगा, यह तो वक्त ही बतायेगा। कहा जाता था कि अंग्रेज़ अपना और अपनी कौम का भला पचास साल पहले सोचता है, हिंदू भाई 10 वर्ष पहले और मुसलमान वक्त पर या वक्त के बाद सोचता है। मेरा ख्याल था कि हमारी सरकार हर बात को कम से कम कुछ वर्ष पहले तो सोचेगी लेकिन जनाब स्पीकर साहिब, आप जानते हैं कि हमारी सरकार को कितने ही बिल जो इस ने किसी एक session में पास करवाये, अगले session में amend करवाने पड़े। अगर यह हर चीज़ को सोचती, तो उन बिलों के बार २ लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती ? साफ़ ज़ाहिर है कि या तो हमारे अफ़सरों ने इन की वक्त पर मदद नहीं की, या वज़ीर साहिबान ने खुद मेहनत नहीं की।

फिर जानबेवाला, चंदीगढ़ को बनाने का idea और सरकारी दफ़तरों को यहां लाने का ख्याल बहुत नेक और मुबारक था लेकिन काश कि हमारी सरकार यह सोच लेती कि सरकारी दफ़तरों को चंदीगढ़ ले जाने का कौन सा मौका ठीक था ! यह बात पहिले ही सोच लेनी चाहिये थी। अगर ऐसा किया गया होता तो यह Budget Session late शुरु न होता। उस समय कहते थे कि हम अभी चंदीगढ़ जायेंगे, ज़रूरत पड़ी तो पेड़ों के साये के नीचे बैठेंगे, कुटिया में रहना पड़ा तो खुशी से रहेंगे। अब हम देखते हैं कि यह सब कहने की ही बातें थीं।

फिर यह चर्चा किया जाता है कि हम मसावात लाना चाहते हैं— गरीबों और अमीरों में जो तमीज़ है उसे खत्म करना चाहते हैं। मगर हम यहां क्या देखते हैं ? खिदमत करने वाले चपड़ासी भाइयों को जो quarters दिये गये हैं उन का किराया तो अढ़ाई रुपये माहवार है और Chief Minister साहिब की कोठी का 1,250 रुपये माहवार। कहा जायगा कि वकार का सवाल है। मैं कहता हूं कि वकार तो वही होता है जो लोगों के दिलों में

होता है। चपड़ासी और Chief Minister के बीच हज़ार गुना नहीं तो 500 गुना का फ़र्क ज़रूर है। यह बात हमारी सरकार को शोभा नहीं देती। अगर हम में त्याग की spirit है और हम उस mission को पूरा करना चाहते हैं जिसे ले कर हम उठे थे, तो मैं पूछता हूं कि क्या Chief Minister साहिब उस मकान में नहीं रह सकते जिस में वह Chief Minister बनने से पहले रहा करते थे चाहे वह नर्क का नमूना ही क्यों नहीं था? उन के दिमाग में यह ख्याल क्यों नहीं आता कि industries को तरक्की दी जाये, जहालत को दूर किया जाये, मज़दूरों को ऊपर उठाया जाए, और मुज़ारों के मसले को हल किया जाये? दो २ लाख रुपये की कोठियों में रहते हुए क्यों उन्हें इस बात का ख्याल नहीं आता कि तीन साल क बाद फिर अवाम के सामने जाना होगा और जो वायदे पूरे नहीं किये उन के लिये अवाम को जवाब देना होगा? अफ़सोस है कि हमारी सरकार वक्त पर भी सोचने की कोशिश नहीं करती।

मेरा ख्याल था कि हमारी सरकार की हर बात में कोई न कोई भलाई होती है। हमारी सरकार कहती है कि इस की nationalisation of road transport की policy बहुत कामयाब हुई है। मुझे nationalisation पर कोई एतराज़ नहीं। मैं इस का हामी रहा हूं और अब भी हूं। मगर हर चीज़ के करने का कोई ढंग होता है। यह नहीं कि एक route यहां पर ले लिया और एक वहां पर। Nationalisation ज़रूर हो मगर ऐसे ढंग से कि ग़रीब शरणार्थी जिन्होंने खून पसीना एक करके transport के काम को East Punjab में चलाया और लोगों को सफर करने की सहूलतें मुहैया कीं, दोबारा न उजड़ जायें, और फिर बर्बाद न हो जायें। बजाये इस के कि सरकार उन की कदरदानी करती, वह उन को उजाड़ने पर तुली हुई है। Refugee transport operators के साथ बड़ी बेइनसाफ़ी हो रही है। उन से मश्वरा किये बिना सरकार को कोई route नहीं लेना चाहिये। क्या सरकार यह चाहती है कि वह लोग कच्चे रूटों को आबाद करें, चालू करें, अपना रुपया लगायें, ताकि बाद में सरकार उन्हें अपने हाथ में ले ले?

स्पीकर साहिब! इस nationalisation की पालिसी ने लोगों को बहुत परेशान कर रखा है। हमारे Finance Minister साहिब ने तकरीर करते हुए फ़रमाया कि सरकार का 65 लाख रुपया लगा था और इस को 50 लाख रुपया आ गया है तो यह बहुत अच्छा कारोबार है। ऐसा कारोबार सारे हिंदुस्तानियों को मिल जाय तो हमारा देश राम राज्य के तसव्वर से भी बिहतर नमूना पेश करेगा। लकिन अगर दरअसल सरकार एसे रूट्स (routes) को पहले nationalize करती जिस से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होता तो यकीनन मुझे भी खुशी होती। मगर सरकार तो बिना सोचे समझे इस पालिसी पर अमल कर रही है। इसी तरह इस ने किताबों को nationalize करने का बीड़ा उठाया। बहुत अच्छा विचार था क्योंकि यह चाहती थी कि बच्चों को सस्ती किताबें मिलें और वे सस्ती विद्या हासिल कर सकें। यह निहायत नेक और मुबारिक विचार था। लेकिन स्पीकर साहिब, जो किताबें इन्होंने छपवाईं उन की second edition में 5 हज़ार के ऊपर गलतियां हैं। अगर पहली बार छपने में गलतियां होतीं तो मैं सोचता कि चलो पहली

[मौलवी अब्दुल ग़नी दार]

बार हैं इसलिये गलतियां हो गई हैं लेकिन second edition में तो इतनी गलतियां नहीं होनी चाहियें थीं। साहिबे सदर! मैं जानता हूं कि हमारे Leader of the House बहुत त्यागी हैं और निष्पक्ष हैं। मेरा विचार था कि ये लोग बर सरे हकूमत आकर corruption को खत्म करेंगे। हुआ यह है कि corruption इस वक्त पायाए तकमील तक पहुंच चुकी है। जब किसी भाई ने एक थानेदार के बारे में कहा कि उस ने किसी आदमी को दरख्त पर चढ़ा कर उस को एक एक रुपया फेंकने के लिये कहा और इस तरह उस से 400 रुपये रिश्वत के लिये तो कहने लगे कि आज कल के राम राज्य में कौन अफ़सर इतना दलेर हो सकता है कि गांव में जाकर एक एक रुपया रिश्वत का इस तरह सारे गांव के सामने फेंकने के लिये कहे। साहिबे सदर! मैं गुज़ारिश करना चाहता हूं कि अब रिश्वत का technique ही बदल गया है। अफ़सरों और मातहतों ने रिश्वत लेने के मुहज़्ज़ब ढंग निकाल लिये हैं। Leader of the House बहुत शानदार आदमी हैं। मैंने उनकी पहले वाली सब बातें सुनी हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पहले तो लोग Bhakra और Nangal के बारे में ही कहते थे कि sons-in-law और sons का महकमा है लेकिन अब किताबों की nationalization होने लगी है तो यह भी sons-in-law का महकमा बन गया है। इस से मुझे कोई सरोकार नहीं कि nationalization का काम उन्होंने Chopra Printing Press के सुपुर्द किया है या किसी अलिफ़, बेया जीम को दिया है। वे मालिक हैं जिस को मर्जी हो उस को देवें। वे अपने आदमियों की, अगर वे अच्छे हैं, तो मदद करें। लेकिन मेरी हैरानी की कोई हद न रही जब मैंने देखा कि सब से ज्यादा ग़लतियों की percentage चोपड़ा प्रिंटिंग वालों की ही थीं। वे कहेंगे कि पगला आदमी है, किताबों की ग़लतियों को ले बैठा है; यह नहीं जानता कि यहां पर तो करोड़ों रुपयों का कारोबार है। मुझे भी मालूम है कि सरकार की नीयत बहुत नेक है लेकिन इन की nationalization of text books का नतीजा यह हुआ है कि लड़कों को 6,6 महीने तक किताबें नहीं मिलीं और अगर मिलती हैं तो उन में इतनी ग़लतियां होती हैं कि खुदा की पनाह। तो इन हालात में, स्पीकर साहिब, आप फ़रमायें कि विद्या कितनी सस्ती हो सकती है और कितनी पनप सकती है? मैं जानता हूं कि हमारे Education और Transport Minister हंसेंगे कि पगला ग़लतियों का ज़िक्र बार बार कर रहा है। वे हंसें, हंसना भी चाहिये। लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिये कि ऐसे पंजाब के, जो कि तबाहशुदा है, बरबाद हुआ है, वे नेता हैं। और इस पंजाब के लोगों की अगवाई करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि वे अपने अज़ीज़ों की मदद न करें, अगर अज़ीज़ अच्छे हैं तो उन को भी मौका मिलना चाहिये। लेकिन खुदा के लिये उन से कहें कि तुम गलतियां करते हो तो मेरी निन्दा होती है लोग मेरी मुज़म्मत करते हैं। इसलिये एहतियात से काम करें! स्पीकर साहिब, यह मैंने अपनी सरकार की पालिसी के बारे में चंद अलफ़ाज़ कहे हैं। अब मैं बजट के बारे में कुछ अर्ज़ करूंगा।

साहिबे सदर! चीफ़ पार्लीमेंटरी सैक्रेटरी साहिब ने अच्छा नहीं किया। उन्होंने पुराने ज़माने की याद को ताज़ा कर दिया। उन्होंने फ़रमाया है कि 1947 में अकालियों का क्या

रोल (role) था, किस किस का क्या ole था। यह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन मैं उन से कहना चाहता हूं कि Rape of Rawalpindi लिख कर पंजाब में आग लगाने वाले भाई में भी यह ताकत है कि वे आगे आयें और लोगों पर नुक्ताचीनी करें। साहिबे सदर ! अगर पंडित जगत राम जैसे सज्जन ऐसी बात करते तो मुझे कोई एतराज़ न होता....

चीफ़ पर्लीमेंटरी सैक्रेटरी . On a point of order, Sir. मेरे दोस्त ने फ़रमाया है कि आज उस शख्स ने criticize किया है कि अकालियों का role क्या था और दूसरों का रोल क्या था जिस ने Rape of Rawalpindi किताब लिखी थी और यह कि उसी किताब को पढ़ कर पंजाब में तमाम कत्ल हुए। इस बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह किताब तो Partition से पहले लिखी गई थी और जो लोग इस वक्त ताने दे रहे हैं उनके ईमा पर लिखी गई थी। जब Muslim League ने...... (*Interruptions*).

Mr. Speaker : Order, please order. This is not a point of order.

श्री केदार नाथ सहगल : वह किताब सच्चर साहिब की मेहरबानी से लिखी गई थी। मेरे दोस्त ने गलत कहा है कि इन के कहने पर लिखी गई थी।

मौलवी अबदुल ग़नी दार : साहिबे सदर ! मैं ने किसी का दिल दुखाने की नीयत से यह बात नहीं कही थी.........

अध्यक्ष महोदय : यह बात किसी का दिल लुभाने वाली भी तो नहीं थी।

मौलवी अबदुल ग़नी दार : साहिबे सदर ! असल में मुझे यह भी कहना है कि हमारे Finance Minister ने बहुत अच्छा किया जो उन्होंने कुछ गरीब क्लर्क भाइयों की तनखाहें बढ़ा दीं हैं। अच्छा होता अगर उन का ध्यान veterinary doctors की तरफ़ भी जाता। उन का ग्रेड जो 1929 में था वही 1954 में भी है। अच्छा होता अगर दूसरे मुलाज़मों की तरफ़ भी उन का ध्यान जाता लकिन वे कहेंगे कि उन की तरफ़ हम कैसे ध्यान दें ? आबयाना कैसे छोड़ें जिस का हम ने election के दिनों में वायदा किया था ? गुड़गांवां जिला का फिक्र कैसे करते ? मैं क्या कहूं मैं तो गुनहगार हूं, गर्दन ज़दनी हूं लेकिन उन तमाम ग़रीब लोगों को निराश होना पड़ा है जो पहले ही उजड़े हुए हैं। अगर कोई एक आधा काम अच्छा हो जाता तो मैं भी खुश होता कि चलो अच्छा हुआ। उन्होंने मुझ को Opposition में बिठा दिया है, सही है, ऐसी बातें होती रहती हैं। लेकिन अगर इन्हें भी सूबे की भलाई मकसूद थी तो यह ऐसी पालिसी इख्तियार न करते। साहिबे सदर, election लड़ते वक्त तो ये लोग एलान करते थे कि 90 फ़ीसदी अफ़सर corrupt हैं लेकिन आज वही लोग पुलिस के गुनाहों पर पर्दा डालते हैं और इस महकमे की corruption को छिपाते हैं। मेरे भाई Finance Minister ने इस तरफ़ क्यों नहीं ध्यान दिया कि जब U. P. में सरकार कमाद और गन्ने की खेती या फ़सल पर cess लगा कर लाखों रुपये कमाती है तो इस नये दौरे में वे क्यों नहीं इस तरफ़ तवज्जुह देती ?

[मौलवी अब्दुल गनी दार]

पंजाब में भी इस cess के मुतअल्लिक में कुछ कहना चाहता हूं। यह 100 per cent ठीक है हम तरक्की करना चाहते हैं और करनी भी चाहिये। हमारे हां जगाधरी शुगर मिल्ज़ किसी दूसरी मिल्ल से कम नहीं। बल्कि यह बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस की तरफ इन का ध्यान क्यों नहीं गया ? जब फाईनांस मिनिस्टर (Finance Minister) साहिब ने और मामलों में यू. पी. का हवाला दिया तो क्यों नहीं cess के मामला में भी यू. पी. को follow किया जाता ?

एकाध लफ़ज़, स्पीकर साहिब, आप की इजाज़त से और कहना चाहता हूं। अफ़सरों के बारे में मेरी अपनी कुछ और ही राये थी। लेकिन मुझे हैरत हुई यह जानकर कि एक मिनिस्टर साहिब ने एक जगह बैठ कर एक अफ़सर साहिब को खूब गाली गिलोच किया। मैं नहीं समझता कि अगर ऐसा ही होता रहा तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अफ़सर लोग बदले हुए हालात के मुताबिक अपने आप को बदलेंगे ! स्पीकर साहिब ! अगर यही हालत रही तो सरकार की administration किस तरह smoothly चल सकेगी, सरकार का सारा धंधा कैसे चलेगा ? इस लिये, स्पीकर साहिब, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सूबा फले, फूले और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े तो हमें दो बातों का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। इन दोनों बातों की तरफ़ ध्यान देना निहायत लाज़मी है। वे ये हैं कि यह ठीक है कि हम अपनी भलाई सोचें, लेकिन ऐसा करते वक्त कहीं ऐसा न हो कि हम अवाम की भलाई को नज़रअन्दाज़ कर दें। मिनिस्टरों को चाहिये कि अगर अपने रहने के लिये 12,12 लाख रुपये की लागत के बंगले बनवाते हैं तो उन गरीबों का, जो कि गन्दी और टूटी-फूटी झोंपड़ियों में रहते हैं, भी ध्यान रखें। (Interruptions) ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। मैं माननीय मेम्बर से प्रार्थना करूंगा कि वह अब अपनी तकरीर को खत्म करें।

मौलवी अबदुल ग़नी दार : बस, स्पीकर साहिब, मैं एक मिनट और बोल कर अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा।

चूंकि हमारा सूबा बार्डर पर वाकिया है और बार्डर स्टेट होने की वजह से हमारी सरकार को इस की देखभाल करने के लिये काफ़ी रुपया खर्च करना पड़ता है इस लिये मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि मर्कज़ी हकूमत से कहा जाये कि वह इस सीमा की defence में होने वाला खर्च अपने ज़िम्मे ले ले और इस तरह से हमारा जो हिस्सा बनता है वह हमें Centre के funds में से दे। यह सिर्फ़ पंजाब को defend करने का ही सवाल नहीं, बल्कि सारे मुल्क की रक्षा का मामला है। इस के इलावा पार्टीशन (Partition) के बाद हमारा मुल्क—हिन्दुस्तान—एक food deficit country रहा है। पंजाब भी बटवारे के बाद deficit area ही था। लेकिन जिस मेहनत और लगन के साथ यहां के किसानों ने गवर्नमैण्ट की Grow-More-Food campaign को पायाए-तकमील तक पहुंचाया है और न सिर्फ़ पंजाब को ही food surplus area बनाया है बल्कि सारे हिन्दुस्तान की demand को भी काफ़ी हद तक पूरा किया

है—उस को देखते हुए इस मकसद के लिये पंजाब गवर्नमैण्ट ने जितना रुपया खर्च किया उस का कुछ हिस्सा मर्कज़ी सरकार को contribute करना चाहिये । और इस तरह जो रुपया मिले वह रफ़ाए-आमा के दूसरे कामों पर खर्च किया जाये । इन इलफ़ाज़ के साथ मैं अपनी जगह पर बैठता हूं ।

श्री राम चंद्र कामरेड (नूरपुर) : स्पीकर साहिब, कहा है:—

"यूं तो कदम कदम पै तेरा राह गुज़र मिले,
लेकिन किसी किसी को ज़ौके नज़र मिले ।
कम बीनीए निगाह का या रब ! मैं क्या करूं ?
जलवे तड़प रहे हैं कोई दीदावर मिले ।।"

मैंने आज बहुत सी तकरीरें सुनी हैं लेकिन, स्पीकर साहिब, मैं हैरान हूं कि उन में से बेश्तर तखरीबी नुक्ताचीनी से भरी पड़ी थीं । फाईनैंस मिनिस्टर (Finance Minister) साहिब की तकरीर को सुन कर क्या कोई शख्स इस बात से इनकार कर सकता है कि उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं कि इस वक्त तक पांच लाख एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन ज़ेरे काश्त लाई गई. वह ठीक नहीं ? जब स्टेट में अनाज और दूसरी चीज़ों की पैदावार इतनी बढ़ गई है तो क्या कोई शख्स इस बात से इनकार कर सकता है कि इतनी तरक्की हमारी हकूमत की तरफ़ से लोगों को हर पहलू में सहूलयतें पहुंचाने से और हकूमत के अच्छे इंतज़ाम की वजह से ही हुई ? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पंजाब के बटवारे के वक्त जहां 40 लाख एकड़ ज़मीन ज़ेरे-आबपाशी थी वहां अब वह रकबा पिछले चंद सालों में बढ़कर 56 लाख एकड़ हो गया है । क्या यह तरक्की की बात नहीं है ? कौन शख्स इस इस बात से इनकार कर सकता है कि पहले जहां पंजाब में सात हज़ार कारखाने थे, वहां अब कारखानों की यह गिनती बढ़ कर 18,000 तक पहुंच गई है ? क्या इसे तरक्की नहीं कहा जा सकता ? स्पीकर साहिब ! मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब से हमारी इस हकूमत ने पंजाब का नज़मो-नसक अपने हाथ में लिया है, हमारे सूबे में मुखतलिफ़ पहलुओं में तरक्की हुई है । इसलिये मैं यह समझता हूं कि हर सही ख्याल आदमी का यह फर्ज़ है कि वह उस की इन ach evements की दाद दे । इस में कोई शक नहीं कि यह वह सब कुछ नहीं हो सका जो कि हम चाहते थे । लेकिन कहते हैं कि एक आदमी जब तखैयल में होता है तब बिलाशक वह सैंकड़ों चीज़ें बना लिया करता है मगर जब एक आदमी को किसी असूल या ज़ाबते के मुताबिक काम करना होता है तो उस पर बड़ा ध्यान देने और ग़ौर से कदम उठाने की ज़रूरत होती है । कारण कि उस पर एक खास किस्म की ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है । इसलिये इस ख्याल को सामने रखते हुए, पिछले छ, सात सालों में जो कुछ गवर्नमैण्ट से बन पाया, जो कुछ मुमकिन हो सका; वह उस ने सूबे की बेहतरी के के लिये किया है । यह ठीक है कि अगर और ज़्यादा तेज़ी से काम किया जाता तो इस से भी ज़्यादा स्टेट के अन्दर improvement हो सकती थी, लेकिन इस वक्त तक जो कुछ भी हमारी गवर्नमैण्ट ने किया उस के लिये मैं उसे मुबारकबाद पेश करता हूं क्योंकि इस में कोई शक नहीं कि जो कुछ भी इस थोड़े से अर्से में इसने किया उस से सूबे को तरक्की के रास्ते पर आगे ही ले जाने की कोशिश की गई है ।

[श्री राम चन्द्र कामरेड]

इस के बाद, स्पीकर साहिब, बेकारी की समस्या का जिक्र किया गया। मैं समझता हूं कि बेकारी को इस सूबे से दूर करने के लिये बहुत कुछ किया जा सकता था। लेकिन वह सब कुछ एकदम थोड़ ही किया जा सकता है ? आखिर कई बात ऐसी भी होती हैं जो मैं समझता हूं कि हर शख्स के ख्याल में नहीं आतीं। इसलिये वह omit हो जाती है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी चीज के रह जाने और जान बूझ कर छोड़ जाने में फ़र्क होता है। कहने का मतलब यह है कि किसी काम का omit हो जाना और बात है और नीयत से जान बूझ कर छोड़ देना दूसरी बात है। जहां तक नीयत से काम करने का ताअल्लुक है, हमारी इस सरकार ने कुछ कम कदम नहीं उठाये। जहां चंद साल पहले सूबे के 7,000 कारखानों में 36,000 मज़दूर काम करते थे वहां अगर सही आदादोशुमार को देखा जाए तो इस वक्त सूबे में 18,000 कारखाने हैं और उन में 62,000 मज़दूर काम कर रहे हैं। यकीनन यह भी बेकारी को कम करने के लिये भारी काम है। इसी तरह पैदावार की कीमत को आप लीजिये। सन् 1948 में सनअती पैदावार की कीमत का अंदाज़ा करीब 8,48,00,000 रुपये था लेकिन अगर आप सन 1953 के अदादोशुमार को लें तो पैदाववार की कीमत 14,71,00,000 रुपये थी। क्या इसे तरक्की नहीं कहते ?

इसके इलावा, स्पीकर साहिब, Administration को decentralise करने की भी पूरी पूरी कोशिश की गई है और इस पहलू में सरकार की तरफ़ से ठोस इकदाम किये गये हैं। इस सिलसिले में इस साल दो बड़े अहम फ़ैसले किये गये हैं। वे हैं तहसील को sub-division बनाने और Judiciary को Executive से अलग करने के बारे में। स्पीकर साहिब ! मुझे विश्वास है कि तहसीलों को sub-divisions बनाने का जो फ़ैसला किया गया है यह इन्साफ़ को अवाम तक ले जायेगा और इस से अब हर गरीब आदमी के लिये यह मुमकिन हो जायगा कि वह सस्ता और जल्दी इन्साफ़ हासिल कर सके। इसी तरह ही Judiciary को Executive से अलग करने का फ़ैसला भी एक अहम फ़ैसला है। मैं समझता हूं कि इस मे अदलो-इन्साफ़ के मुतअल्लक सूबे के लोगों की ख्वाहिशात पूरी हो जायेंगी। और उन की शिकायतें दूर होंगी। मैं समझता हूं कि यह भी सही जानब में एक अहम कदम उठाया गया है। मैं यह भी समझता हूं कि यही ख़ास चीज़ें हैं जो कि आम आदमी हकूमत से मांगता है और इस लिये, जिस शख्स के दिल में सूबे की बेहतरी का ख्याल है वह ज़रूर हकूमत की तरफ़ से उठाये गये इन इकदाम को appreciate करेगा और इस के लिये उस की दाद देगा।

इसी सिलसिले में, स्पीकर साहिब, मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं और वह है सोशल जस्टिस (Social Justice) का सवाल। यह एक ऐसा मसला है जो सीधा दिल और दिमाग़ से ताअल्लुक रखता है। इस चीज को लेकर मैं देखता हूं कि हर तरफ़ discontentment फैली हुई है। यह ठीक है कि इस पहलू में उतना कुछ नहीं हो सका जितना कि होना चाहिये था। लेकिन फिर भी इस हकूमत ने इस सिलसिला में कुछ कदम

उठाए हैं। चुनांचि श्रोवरसीअर्ज़, रोड इन्स्पैक्टर, कालेजों के लैकचरार, स्कूलों के बी. ए. बी. टी. टीचर्ज़, वैटेरेनरी असिस्टैंटस और क्लर्कों के ग्रेडों में जो revision किया गया है वह एक अच्छा खासा low-paids को assistance देने का फ़ैसला है। इस के इलावा जिन लोगों की तनख्वाह साढ़े 40 रुपये माहवार या इस से कम है उन में दो रुपये माहवार का और इज़ाफ़ा किया गया है। यह एक ऐसा फैसला है जिस के लिये मैं हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन मैं समझता हूं कि इस से ही सोशल जसटिस मुकम्मल नहीं हो जाती। मैं समझता हूं कि अभी हमें इस पहलू में और भी बहुत कुछ करना होगा। मैं समझता हूं, स्पीकर साहब, कि इस वक्त जो बड़े और छोटे में disparity ratio है उसे कम करने के लिये कोई तरक्कीकुन कदम नहीं उठाया गया। यह एक निहायत लाज़मी चीज़ है जिस की तरफ हमारी गवर्नमैंट और खास कर वज़ीरे खज़ाना को अपनी खास तवज्जोह देनी चाहिये। इस मकसद के लिये गवर्नर साहिब और मिनिस्ट्रों से ले कर जितने भी बड़े बड़े अफ़सर हैं उन की तनख्वाहों को कम किया जाना चाहिये। मैं तो यह चाहता हूं कि सारे के सारे pay structure को ही revise किया जाये। अगर ऐसा किया जाये तो हमें उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा जो कि आज हम कदम कदम पर कर रहे हैं।

इस के बाद जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि इस में शक नहीं कि हमारी गवर्नमैंट की यह दिली ख्वाहिश है कि मज़दूरों के साथ इन्साफ़ हो। लेकिन मैं गुज़ारिश करना चाहता हूं कि इस वक्त यह तबका असली इन्साफ को हासिल नहीं कर रहा। आखिर कहां पर और क्या कसर है ? यही हमें सब को मिल कर सोचना है। यह एक ऐसी हकीकत है जिस से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमृतसर, खासा, जालन्धर, बटाला, लुध्याना और करनाल वग़ैरा दूसरी जगहों में बड़ी भारी बेचैनी फैली हुई है। मैं महसूस करता हूं कि हकूमत की पूरी और दिली ख्वाहिश है कि इस बेचैनी को दूर किया जाये।

फिर जनाबे वाला, मैं Indian National Trade Union के नुमाइंदा होने की हैसियत से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश यह है कि पंजाब की सनअत तरक्की करे, खूब फले और पंजाब में मज़दूरों और मालकों में अच्छे ताअल्लुकात हों। हमारे पंजाब की बेहतरी इसी में है कि यहां सनअती तरक्की के लिये अमन की फिज़ा कायम रहे। आजकल के बदले हुए हालात में यहां जो मालिकान और मज़दूरों में बड़े झगड़े पैदा होते हैं हकूमत यही चाहती है कि उन का कोई तसल्लीबख्श फ़ैसला हो जाये लेकिन इस सम्बन्ध में मुझे एक शेअर याद आ गया है —

दवाए दर्द दिल क्या खाक हो जब वह दूआगो है।
मेरा प्यारो उलफत ऐ खुदा अच्छा न हो जाए।

हमारे वज़ीर साहिब को चाहे इन झगड़ों के संतोषजनक निपटारे की कितनी ही ख्वाहिश क्यों न हो और हकूमत भी इस बारे में कितनी ही ख्वाहिश क्यों न करे जब तक हमारे Labour Commissioner साहिब जो सारा महिकमा चलाते हैं नहीं चाहते कि.....

Mr. Speaker. It is not a good compliment.

श्री राम चंद्र कामरेड : बहुत सारे झगड़े इस वास्ते पैदा होते हैं कि मुलाज़मत की शरतें नहीं बनी होतीं। मैं अर्ज़ करूंगा कि वह जल्दी बनाई जानी चाहियें। मैं वज़ीर साहिब से पूछता हूं कि दो साल के अरसा के अन्दर Labour Commissioner साहिब ने कितनी मुलाज़मतों की शरतें तैयार की हैं। उन को इस काम की तरफ़ तवज्जुह देनी चाहिये। जब कारखानों के मालिकों की तरफ़ से मज़दूरों के साथ सखत बरताव किया जाता है और उन्हें गलत वक्त पर भी काम करने के लिये मजबूर किया जाता है तो उन मालिकों के खिलाफ़ क्यों कोई मुकद्दमे नहीं चलाए जाते या उन के खिलाफ़ कोई और कार्यवाई क्यों नहीं की जाती ?

एक मसला जिस पर अभी झगड़ा हुआ था और जिसे देख कर Indian National Trade Union को भी मायूसी हुई है वह यह है कि तीन साल के बाद अब कारखानों के मालिकान ने यह कह दिया है कि Labour Tribunal की तकर्ररी invalid है। यह हमारी समझ में नहीं आता कि तीन साल के बाद उन्हें अब यह कैसे ख्याल आ गया कि यह तकर्ररी नाजाईज है। मैं समझता हूं कि महकमे के incharge को यह देखना चाहिये कि तीन साल के बाद Labour Tribunal के जाइज़ या नाजाइज़ होने का सवाल कैसे उठा ? पहले तो हमारी गवर्नमैण्ट की तरफ़ से यह कहा गया था कि इस Tribunal की तकर्ररी जाइज़ है लेकिन बाद में इस ने मान लिया कि यह तकर्ररी नाजाइज़ थी। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि इस सूरत में यह कैसे कहा जा सकता है कि यह मालिकों और मज़दूरों के झगड़े निपटाने की तरफ़ एक कदम है। होना तो यह चाहिये था कि जो फ़ैसला गवर्नमैण्ट पहले कर चुकी थी उसी पर अड़ी रहती। अब इस से तो गवर्नमैण्ट की कमज़ोरी ज़रूर बढ़ जाती है।

एक अर्ज़ मैं और करना चाहता हूं वह यह है कि परसों जब हमारे वित्त मंत्री जी अपनी बजट की तकरीर पढ़ रहे थे तो उन्होंने फरमाया था कि मज़दूरों के लिये 240 मकानात पहले बनवाये जा चुके हैं और एक सौ मकान करीबन मुकम्मल हो चुके हैं और अगले साल के अंदर 382 मकान और मज़दूरों के लिये बनाये जायेंगे। मेरी गुज़ारिश यह है कि हमारे हज़ारों और लाखों मज़दूरों के लिये छः या सात सौ मकान बनाये जायें तो वे बहुत कम हैं। इस लिये मैं मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करूंगा कि अगले साल जब वह बजट बनायें तो मज़दूरों के मकानों के लिये बहुत सा रुपया रखें क्योंकि यह समय की मांग है।

फिर जनाबे वाला ! देखने से तो यह मालूम होता था कि यह तरक्की का बजट है। इस में बहुत अच्छी २ बातें हैं लेकिन जब मैंने इसे तफ़सील में देखा तो मुझे इस में कुछ कमियां भी नज़र आईं। पहले भी माता विधि ने हमारे नूरपुर तहसील के इलाके को बड़ा गरीब इलाका बनाया है। हमारे प्रान्त में सब से ज़्यादा पिछड़े हुए और कम तालीमयाफ़ता दो ज़िले हैं एक गुड़गांव और दूसरा कांगड़ा। लेकिन कांगड़े के ज़िला में सब से ज़्यादा गरीब इलाका नूरपुर का है। वहां लोगों को इतनी तकलीफ़ है कि बयान नहीं की जा सकती। वहां लोगों के इलाज के लिये अभी तक कोई अच्छा हस्पताल नहीं खोला गया। वहां पहले एक प्राईवेट स्कूल था वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को इस ख्याल से दे दिया गया था कि इसे develop

किया जायगा। और उस की बिलडिंग में इजाफ़ा किया जायगा लेकिन अफ़सोस से कहना पड़ता है कि उस पर कोई खर्च नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ है कि वह ज़रा भी तरक्की नहीं कर पाया है। मैं इन इलफ़ाज़ के साथ स्पीकर साहिब, आप का शुकरिया अदा करता हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਦਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਕ welfare state ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਸ ਬਜਟ ਨੂੰ development state ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ commercial state ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਮਦਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ Budget ਵਿਚ co-operative, veterinary, medical ਅਤੇ public health ਜਿਹੇ beneficent ਮਹਕਮਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤ੍ਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ Opposition ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ top heavy administration ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ Partition ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ State ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ top heavy administration ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੋ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ election ਹੋ ਗਏ ਹਨ administration ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਇਕ administrative unit ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਤਹਸੀਲਾਂ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਧਕੇ ਨਾ ਖਾਣੇ ਪੈਣ।

ਫੇਰ ਜ਼ਨਾਬ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬੜੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ law and order ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਰੁਪਿਆ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ law and order ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ police ਵਧਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਨੀ ਜਿਹੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਹਤਕ ਦੇ incidents ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੇਖਨ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ incident ਦੀ impartial enquiry ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ House ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ enquiry ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ incident ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਹੋਏ Balia District ਦੇ incident ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲਵੇਗਾ।

[ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ]

ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹਮਦਰਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਜਟ ਵਿਚ Industrial Finance Corporation ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ Agricultural Finance Corporation ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਬਿਆਜ ਉਤੇ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ Co-oporative Societies ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਠੋਸ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਲੋਂ ਸਾਡੀ State ਨੂੰ ਜੋ ਅਨਾਜ ਵਿਚ deficit ਸੀ surplus ਬਨਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ fertilizers ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੇ State ਨੂੰ surplus ਬਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਬੀਤਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਵਿੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। Finance Minister ਨੇ ਮਿੱਠੇ ੨ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ tax ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੁਆਰਾ 30 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ Taxation Bill ਦੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਦੀ ਬੜੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹ 30 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਦਾਵ੍ਹੇਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਚਾਰ ਸੌ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜੁਤੀਆਂ ਬਨਾਨ ਦੀ industry ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ Finance Corporation ਬਨਾਏ ਤਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ unemployment ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Transport nationalisation ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਹੁਣ border ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਹ ਕਿ nationalisation ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਇਕ ਹੀ community ਤੇ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ communal dissensions ਵਧਨ ਗੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਡੀ unity ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ। Transport ਦੀ nationalisation ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ State ਦੀਆਂ development ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ

ਅਸੀਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਜ ਸਾਨੂੰ border ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਓਨਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੈ। unemployment ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਤਵਜੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜੇਹਾ volcano ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਦੇ ਭੀ ਫਟ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਲ ਜਲਦੀ ਧਿਆਨ ਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿਖਤ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।

Cottage industries ਦੇ develop ਕਰਨ ਵਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਆਦਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ cottage industry ਦੀ study ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੇਖਨ ਕਿ ਉਥੇ cottage industry ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ, ਬਜਾਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਤੀ industrialists ਨੂੰ ਭੀ ਬਾਹਰ ਇਹ ਵੇਖਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ social inequalities ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। Police ਦੇ ਸਪਾਹੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਥਾਨੇਦਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ allowance ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ। ਵਰਨੇਕੂਲਰ ਟੀਚਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਜ਼ਿਲੇਦਾਰ Co-Operative Sub-Inspector ਆਦਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚ ਟਬਰ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ low paid ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ (ਰਾਮਦਾਸ): Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਕ Development State ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ debt ridden Development State ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ੧ ਅਰਬ ੮ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 1 ਅਰਬ 38 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਧੁਮਾਂ 1914 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਭੀ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰੂਸ, ਜਿਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਭੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਰਕੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ Development ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਭੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ

[ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ]
ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ State ਦਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਉਚਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ Development Projects ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕੀਏ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 96¼ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਤੇ 12¼ ਕਰੋੜ Capital ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ surplus ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ 1952-53 ਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 1½ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਇਹ ਕਣਕ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਕ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਰਾਇਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਨਾਣ ਦੀ ਏਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਨੂੰ irrigation ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਅਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ (supply) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਤਾਰਨ ਜੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਅਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਬਲਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ----

ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦਸਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ

irrigation ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤਰਕੀ ਐਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਨ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਨਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ Betterment Charge ਆਦਿ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਖਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਸਟੀ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ (Publicity Department) ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ (propaganda) ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗਲ education ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ। Education Department ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ Education Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ।

ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ Education ਦੀ ਮਦ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਟ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਿਵਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ....

अध्यक्ष महोदय : पांच मिनट और।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

अध्यक्ष महोदय: आप स्पीच जारी रखें। आप खुद ही थक जाएंगी।

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿਥੇ ਵੀ Primary Education ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਉਨਤੀ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਝ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ adult education ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ

[ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ]

ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਝਟਾਪਟ ਜਾਚ ਦਸੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਿਚ ਉਨਤੀ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਣ।

ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (Agriculture) ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ Useful ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Agriculture ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਕਮ ਰਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ 1948-50 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 70 ਲਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ, 1951-52 ਵਿਚ 65 ਲਖ. 1952-53 ਵਿਚ 53 ਲਖ ਹੈ। 1954-55 ਵਿਚ 51 ਲਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (Agriculture) ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (Administration) ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ importance ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ function ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਯਤੀਮ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਟਰੀਨਰੀ (Veterinary Department) ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਕ approach ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਨੀਯਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨ ਦਸ ਸਕਣ। ਜਾਂ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਹਿਲੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ educate ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ suggestion ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਰੈਡ ਕਰਾਸ (Red Cross) ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਮੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰੈਡ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਲੇ ਜੇ ਕਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦਾ ਹਫਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੇਲੇ District-wise ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧੇ

ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਿਖ ਸਕਨਗੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਨੱਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜਾ point ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ Agriculture ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਸਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਦਿਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਾਵੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਓਥੇ ਇਸ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਾਵੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਈ ਜਾਏ ਉਥੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਦ ਮੁਆਮਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਤਹਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ order ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ੩੦ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਾਵੀ ਲਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਮੁਆਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਕਾਵੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਵੇ । ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਬੀਜਦੇ ਹਨ । ਬਿਜਾਈ ੨੦ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ end ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੂਣੀ ਭੀ ੯੦% ੩੦ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸੋ ਇਹ ਉਗਰਾਹੀ ਹਾੜ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ । ਪਰ ਉਗਰਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਤਕਾਵੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਦਾ burden feel ਕਰਤੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਾਵੀ ਛੇਤੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕ suggestion ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ Agriculture Information Service ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨੱਤੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਉਨੱਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ literature ਛਪਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ੯੦ ਫੀ ਸਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਟਰੇਚਰ (Literature) ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ District ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜੇਹਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਤੀਜਾ point ਜਿਸ ਵਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ।

ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤੀ ਕੰਮ ਬਲਦਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੁਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਦੌਲਤ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਦੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਗਲ਼ੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾ ਵਾਸਤੇ Veterinary

[ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ]

ਇਮਦਾਦ ਵਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਖਰਚ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਖਰਚ 29 ਲਖ ਰੁਪੈ ਦੇ ਲਗ ਭਗ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 24 ਲਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ Veterinary Assistant ਕੋਲ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਯਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾ ਥੋੜੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਥੇ ਬੀਮਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਵਾਂ ਗਾ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬੀਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਦਵਾਈ ਉਥੇ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕ ਹੋ ਸਕੇ । ਬਾਕੀ ਦਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਅੱਛੀ Institute ਡਗਸ਼ਈ ਵਰਗੀ Vaccine ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਇਸ item ਬਾਰੇ Central Government ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਨੂੰ ਆਪ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ Institute ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ Vaccine ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲਗੇਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲਗਾ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਮੈਂ ਬਸ ਇਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ । ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਇਕ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਉਥੇ breeding ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁਧ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਨ । ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ........

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਬਸ ਇਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ । ਦੂਜਾ point ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸਾਂ Projects ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਲ ਪਹਿਲੋਂ ਤਵੱਜੁ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Public Health ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ 38 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ । 10,38,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤ ਐਂਟੀ ਮਲੇਰੀਆ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਨੇ ਹਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲਖ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘਟ ਦਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਬਸ ਹੁਣ ਵਰਕਾ ਨਾ ਉਥਲੋ ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਇਕ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਬਸ ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਹੀ । ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ : ਬਹੁਤ ਅਛਾ, ਮੈਂ Co-operative ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਇਸ organisation ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਬਲਕਿ ਠੋਸ ਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਇਗਾ ।

श्री मनी राम (फतेहाबाद) : सभापति जी ! आज मैं दोनों तरफ की तकरीरें सुन रहा था। Opposition वाले तो नुक्ताचीनी से शुरू करते थे और नुक्ताचीनी पर ही खत्म करते थे। और बरसरेइकतदार पार्टी वाले अपनी तकरीरें अफ़सोस और नुक्ताचीनी से शुरु करके तारीफ़ पर खत्म करते रहे। अब देखना यह है कि किस बात में कितनी सचाई है। इस बजट को Welfare State बजट कह कर इस की सराहना की गई है। मगर इसे ज़रा गौर से देखें तो असलीयत खुल जाती है। प्रधान जी, Welfare State का यह मतलब नहीं कि ग़रीब ज्यादा ग़रीब और अमीर ज्यादा अमीर होते जाएं। Welfare State का यह मतलब नहीं कि पुलिस के डंडे से लोगों की आवाज़ को दबा कर यह समझ लिया जाए कि सब कुछ ठीक है। सब से पहली बात इस में यह देखनी चाहिये कि रुपया कहां से और किन से लिया जाता है और कहां खर्च किया जाता है। अगर आप किसानों पर और उन की भलाई के लिये रुपया खर्च नहीं करते तो यह Welfare State नहीं हो सकती। इस से वज़ीर खुश हो सकते हैं बड़े बड़े अफ़सर खुश हो सकते हैं मगर अवाम खुश नहीं हो सकते। हम सब अवाम के चुने हुए पंच हैं। अवाम के पंचों को यह समझ लेना चाहिये कि अगर अवाम और किसानों की खबर न ली गई तो Opposition और बरसरे इकतदार पार्टी दोनों खतम हो जायेंगे। मैं आप को बता देना चाहता हूं कि 50 लाख आदमी आप के इखतियार किये हुए तरीकों से बेकार और बेरोज़गार हो रहे हैं। इस से किसानों की हकीकी नुमाइंदों को उन्हें अपनी भलाई के लिये हाथ पांव हिलाने की सलाह देने का मौका मिलेगा। यह जो बाज़ मेम्बर आप के दबाओ और discipline के डर से यहां चुप हैं अपने इलाकों में जा कर इन को भी मुंह खोलना पड़ेगा। मगर इस से भी ज्यादा अजीब बात यह है कि अकाली, कम्युनिस्ट और बरसरे इकतदार पार्टी किसी ने भी किसानों का जिक्र नहीं किया। किसानों की तिकलीफ़ों का यह कोई जबाब नहीं कि बरसरेइकतदार पार्टी के मुखालिफ़ उन्हें भड़का रहे हैं।

उन्हें बरसरेइकतदार पार्टी को अपनी सफ़ाई देनी चाहिये। सवाल यह है कि पंजाब के अंदर बेकारी बढ़ रही है या नहीं। बड़े बड़े दावे किये जाते हैं कि पंजाब आगे जा रहा है। परन्तु समझ नहीं आती कैसे आगे जा रहा है। ज़रा मज़दूरों की हालत को देखिये ! क्या वज़ीर साहिबान जो इस समय बरसरेइकतदार हैं या वे माननीय सदस्य जो किसी समय वज़ीर थे परन्तु अब opposition में जा चुके हैं नहीं जानते कि मज़दूर किस कदर गंदे quarters में रहते हैं। मैं हैरान होता हूं कि वे इतनी गंदगी में ज़िन्दा कैसे रहते हैं। शायद वे इस लिये ज़िन्दा हैं वे समझते हैं कि एक दिन उन के यह पंच जो इस समय सभा में मौजूद हैं उन की हालत को ठीक कर देंगे।

[श्री मनी राम]

स्पीकर साहिब ! यदि हमें ज़्यादा अनाज पैदा करना है तो हम अपने अन्नदाता किसान को सुखी करना होगा । हमें किसान को विश्वास दिलाना होगा कि उसे अपनी ज़मीन से उखेड़ा नहीं जायगा । वह केवल इसी हालत में मन लगा कर काम कर सकता है जब उसे पता हो कि ज़मीन उसी की है । लोग अपने घर वालों को गहने और अच्छे अच्छे कपड़े लेकर देते हैं महिमानों को नहीं । वह इस लिये कि महिमान तो चले जाते हैं परन्तु अपनी औरतें और लड़के बाले तो घर में ही रहते हैं । इस लिये किसान उसी समय मन लगा कर काम कर सकता है जब उसे विश्वास हो कि उसे उस की ज़मीन से कोई न उखाड़ेगा । यदि ऐसा न किया जाये तो उस में श्रम शक्ति पैदा ही नहीं हो सकती । फिर जब तक यह श्रम शक्ति किसान में नहीं आती हम अपने सूबे को Welfare State नहीं बना सकत ।

श्रीमान जी! कई भाइयों ने कहा है कि रोहतक के किस्से को क्यों उठाया जाता है और औरतों की बेइज्ज़ती का ज़िकर बार बार क्यों किया जाता है । मैं कहता हूं कि अगर केवल मेरी अपनी मां या बहन की बेइज्ज़ती हुई होती तो मैं इस बात को पी जाता और नाम तक न लेता । लेकिन यहां तो बात और है । हमें दूसरे की इज्जत को अपनी इज्ज़त समझना है । मैं कहता हूं कि यदि Police ने दशद्दुद किया था तो बरसरेइक्तदार पार्टी ने किसी Magistrate या हाईकोर्ट के जज से inquiry क्यों न करवाई । और तमाम बात जनता के सामने क्यों न आने दी । यह ठीक है कि सूबे में ऐसे अनसर को खत्म करना चाहिये जो अमन में खलल डालता है लेकिन मैं कहता हूं कि एक डाकू और उस Police Officer में क्या फर्क है जो लोगों की औरतों की इज्ज़त पर डाके डालता है और प्रदेश की शान्ति और अमन को भग करता है ।

अध्यक्ष महोदय: यह public meeting या किसी स्कूल का declamation contest नहीं । आप आराम से अपनी बात कीजिये ।

श्री मनी राम: आप को एतराज़ क्या है ।

अध्यक्ष महोदय: जिस ढब से आप तकरीर फरमा रहे हैं ठीक नहीं । House के एहतराम के लिये आप को आराम से बोलना चाहिये ।

श्री मनी राम: मैंने कोई ऐसा लफ़ज नहीं कहा जो House के एहतराम के विरुद्ध हो । यह तो मेरे बोलने का तरीका है । हां यदि मैं ने कोई ग़लत लफ़ज कह दिया हो तो उसे वापिस लेने के लिये तैयार हूं ।

श्रीमान् जी! कहा जाता है कि corruption दूर नहीं होती । मगर यह दूर हो ही कैसे सकती है । देखने में आ रहा है कि हमारी पंजाब सरकार सड़क की किसी गलत तर्फ को नहीं जा रही है बल्कि सड़क के बीचों बीच जा रही है । हमारे वज़ीर साहिबान लोगों को ठीक होने को कहते हैं लेकिन अपनी corruption दूर नहीं करते । हमारे वज़ीर चौधरी लहरी सिंह ने हिसार के लोगों को कहा कि अगर वे कांग्रेस को vote न देंगे तो उनको भाकड़ा का पानी और बिजली नहीं मिलेगी ।

श्री मनी राम : यह सब ग़लत है ।

सिचाई मंत्री: मुझे समझ नहीं आती कि House के descipline को तोड़ने का हक किसी वज़ीर को कैसे हो सकता है ।

Minister for Finance : Sir, the hon. Member should address the Chair.

अध्यक्ष महोदय: आप किसी मेम्बर से बात न करें । आप मेरी तरफ देखें ।

श्री मनी राम: यदि आप चाहते हैं तो microphone का मुंह मैं आप की तरफ किये देता हूं । मैं अर्ज़ कर रहा था कि फतेहबाद में चौधरी लहरी सिंह ने लोगों से कहा कि यदि वे कांग्रेस को वोट न देंगे तो हिसार के लोगों को भाकड़ा की नहर का पानी और बिजली न दी जायेगी । यदि वज़ीरों का यह इखलाक हो तो छोटे लोगों को कैसे कहा जा सकता है कि वे corruption को दूर करें ।

कहा जाता है कि पंजाब तरक्की पर जा रहा है । गया होगा । परन्तु कौनसा पंजाब तरक्की पर गया है । वह पंजाब जो गांवों में बट रहा है । वह तो तरक्की पर नहीं बल्कि तनज़ली पर गया है । हिसार और फिरोज़पुर में कहत और पानी के न होने के कारण कोई डेढ़ लाख पशु भूख से तड़प तड़प कर मर गये ।

अध्यक्ष महोदय : Order please खत्म कीजिये ।

सिचाई मंत्री: इन को खत्म ही करना चाहिये । (हंसी) ।

श्री मनी राम: श्रीमान् जी, वज़ीर साहिब बीच में बोल रहे हैं । यदि यह या Chief Minister भी बीच में बोलेंगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा । आप इन्हें कहें कि यह बीच में न बोलें ।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी तकरीर जारी रखें ।

श्री मनी राम: मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि कल से चौधरी लहरी सिंह House के discipline को तोड़ रहे हैं ।

Mr. Speaker : You please go on with your own speech. What right have you to talk of others ?

श्री मनी राम: मैं तो House का ध्यान इस बात की ओर दिला रहा था ।

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा नहीं कर सकते ।

श्री मनी राम: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ज़िला हिसार में लाखों मन चना black में बिका ।

अध्यक्ष महोदय: आपके केवल तीन मिनट और रहते हैं ।

श्री मनी राम: मुझ से ही आप यह सलूक करना चाहते हैं ।

Mr. Speaker : Order, order

श्री मनी राम: आपने और सदस्यों को बहुत समय दिया । ना मालूम मुझे क्यों नहीं देते ।

अध्यक्ष महोदय: आप को यह लफ़ज़ वापिस लेने पड़ेंगे । आपका कहना है कि मेरा आप से treatement partial है । क्या आप को मालूम है आप को कितना वक्त दिया गया है ?

श्री मनी राम: चलो जी, वापिस लेता हूं ।

अध्यक्ष महोदय: चलो जी नहीं । अपने लफ़्ज़ वापिस लीजिये ।

श्री मनी राम: मैं अपने लफ्ज़ वापिस लेता हूं और अपनी तकरीर भी खत्म करता हूं ।

ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ (ਰਣੀਆਂ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅਜ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਮਾਨਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਹਾਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵਖਰੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਇਸਤਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾਂ ਕਿ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਿਆਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪੈਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਥੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇ । ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਨਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡੋਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸੁਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਚਾਲਾਕ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਕ ਵਡੀ ਸਾਰੀ ਚਾਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡੋਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਹ ਚਾਦਰ ਫੈਲਾ ਦੇਂਦੇ ਹਣ ਤੇ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਹਾਸਾ)।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ Wholesale Co-operative Societies ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਥੇ Assistant Registrar ਸਾਹਿਬ ਦਸਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ Co-oprative Societies ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । Co-operative Societies ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਤਦ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਕਿ Co-operative Societies ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ 200 ਜਾਂ 500 ਘੁਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ Co-operative Societies

ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ Assistant Registrar ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਨਾਉਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਮੈਂ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਨ ਜਾਉ । ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਢਿਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਫੀਸ 51 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਬ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਥੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਨਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਕ Retired ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Co-operative Society ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਜੱਣ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕ Co-operative Store ਬਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਇਕ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. (M.L.A.) ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ । ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ Assistant Registrar ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਬਨ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ।

Mr. Speaker : I would ask the hon. Member to wind up his speech.

ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿਬ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਧੱਨਾਢ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਦਸਤੂਰ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਾਇਮ ਸੀ ।

ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ Agriculture Department ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ cane-growers ਦੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਨਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਬਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ (ਵਿਘਨ) ।

Mr. Speaker : I would now ask the hon. Member to resume his seat.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ) **:** ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਕ ਉਸ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਬਕਤਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ । ਉਸ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹੋਦੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਉਜੱਲ ਸਿੰਘ ਸਵਾਰ ਹਨ । ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਛੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਸ ਜਲੂਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ Opposition ਵੀ ਇਸ ਜਲੂਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ । ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਦਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵਡਾ ਹਾਥੀ ਕਿੱਧਰੇ ਜੰਤਾ ਨੂੰ ਲਤਾੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਇਸ ਹਾਥੀ ਅਗੇ ਕਿਧਰੇ ਐਨਾਂ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਪਸ਼ੂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਓਣਤਾਈ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ Opposition ਤੋਂ ਆਸ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਲ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ Opposition ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਹਨ ।

ਇਸ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ Civil Liberties ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ । ਅਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਦਫਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਕਦਮੇ ਦਫਾ 188 ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਤੇ Security of State Act ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । Section 9 of Punjab Security of State Act ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Religious ਜਲੂਸ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸਨ । ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਚਰ ਜੀ ਨੇ Security Act ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀ Normal ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ । ਕੀ ਹੁਣ abnormal ਹਾਲਾਤ ਹਨ ? ਇਹ ਭਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਕਤ ਮੰਘ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਭ ਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ Leader of the Opposition ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਚੋਦਾਂ ਮੁਕਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਦਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ A.D.M. ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ । ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ Legal ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇਸਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਛਪੀ ਸੀ । ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ Opposition ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ Congressman ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨਹੀਂ । ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਉਸ ਬਾਣੀਏ ਵਰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੇ ਉਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੱਟ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਨਸਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਕ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਟਿਆ; ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿਗ ਪਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । ਇਕ ਲਫਜ਼ Anti-social ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੜ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਧਕ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । red tapism ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਾਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । inefficiency ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸੁਸਤੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ ।

ਉਹ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ appreciation ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਉਸ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫੇਰ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਆਦਮੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਢਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪੇਂਡੂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਕਰੋ।

ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹ ਹਨ; ਪਾਲ ਮਾਜਰਾ, ਪਾਨਾ, ਰੋੜਾ, ਢਾਂਡਾ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੀ ਤਰਖਾਨਾਂ, ਇਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੇਮ ਨਾਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦਰਖ਼ਾਸਤ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 1953 ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨ ਅਨਾਜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈਂ Judiciary ਅਤੇ Executive ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਲ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਦਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ Constitution ਦੇ directive ਨੂੰ ignore ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ half-hearted measure ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ Judiciary ਤੋਂ ਅਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ separation ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ communal considerations ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ P.S.I. ਨੂੰ ਆਪ ਥਾਨੇਦਾਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਥਾਨੇਦਾਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮੈਨਿਆਂ ਵਿਚ Executive ਤੇ Judiciary ਨੂੰ separate ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਸਾਰੇ Districts ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਤਜਰਬਾ ਕਰਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Prosecuting Branch ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ High Court ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Judicial Magistrates ਹਨ।

ਹੁਣ ਮੈਂ National Extension Service Scheme ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਗੁੜਗਾਂਵਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ—ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਂਦੇ ਹਨ। National Extension Service Scheme ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਅਬਾਦੀ ਤੇ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

case ਵਿਚ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਥੇ ਇਤਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੰਜ ਕੋ ਮੀਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਬਨਾਇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ develop ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਰਧਾਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Congressmen ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ Administration ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Consolidation ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਇਕ Judicial ਮਹਿਕਮਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ Executive powers ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ consolidation ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਕਿਸੇ Minister ਦਾ ਕੋਈ right-hand ਜਾਂ left-handman ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ charge ਲਗਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਮਡੀ, ਕੋਲੋਵਾਲ ਅਤੇ ਲਖਨਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ congressmen ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਨ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੇ Consolidation Operations ਨੂੰ cancel ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ congressman ਦੇ ਭਣਵੱਯੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਚ ਇਕ Congressman ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਫਾ 82 ਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤੀਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਕੀਕਾਤ ਕਰਾਉਨ ਕਿਉਂ ਇਕ Congress-man ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਨ ਤੇ ਕੁਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

Cinema shows ਉਪਰ tax ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ Exhibitors ਬਹੁਤ ਰੁਪਿਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਫੀ (show) tax ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ Cinema ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮਾਂ ਆਪ ਹੀ ਚੂੰਡੀ ਵਢ ਕੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੁਆ ਰਹੀ (ਹਾਸਾ)। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ Cinemas ਨੂੰ nationalise ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ Distributors ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ investment ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ tax ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲਖ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਰਕਮ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Cottage Industries ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ Budget Speech ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ Budget Speech ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹੰਢੇ ਹੋਏ Politician ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼

ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । Cottage Industries ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ—

Cottage and small scale industries have also received due attention.

ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ Small Industries ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ Industries ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਵਾਲੇ ਲੁਹਾਰ, ਤਰਖਾਨ, ਰਾਮਦਾਸੀਏ, ਚਮਾਰ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਛੋਟੀਆਂ Industries ਲਈ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਡੀਆਂ Industries ਵਾਲੇ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ Industries ਉਪਰ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਡੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ 'ਕਮਲਾ ਕਾਟੇਜ' ਜਾਂ 'ਅਨੰਦ ਕੁਟੀਰ' ਰਖੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ Cottage Industries ਦੀ ਉਕਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ।

ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਕੂਲ ਚਲਾਣ, ਹੋਰ ਸੌ ਕੰਮ ਕਰਨ । Land Revenue ਦੇ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 25 ਜਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਕੁਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਆਵੇਗਾ । ਕੀ ਏਨਾ ਥੋੜਾ ਰੁਪਿਆ ਰਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ? ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗੂੰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Please wind up now.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : Just a minute, Sir. ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ Agriculture College ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਨੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਨਾਂ considerations ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਨਾ ਬੜੀ central ਥਾਂ ਹੈ । ਤੇ ਉਥੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਸਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ requisition ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਕ Tube-well ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ provide ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜੇ ਉਹ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ । Budget speech ਵਿਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ Agriculture College ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ shift ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ।

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ briefly ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ local ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ।

Clerks ਦੇ grades ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ Sessions Judge ਦੇ Reader ਤੇ Sub-Judge Fourth Class ਦੇ Reader ਦੇ grades ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Inspection clerk ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ grades ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ posts ਦੇ grades ਵਿਚ ਬੜੀ ਬਹੁਤ distinction ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ posts ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦਾ incentive ਹੋਵੇ।

Efficiency must be kept in view.

ਮੈਂ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕਲਾਂ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਓਨਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਦੋ, ਚਾਰ, ਰੁਪਏ ਲਏ ਬਿਨਾ, ਓਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ system ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹਰ ਅਰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ register ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛੋਂ ਪੁਛ ਗਿਛ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ common man ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਥੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹਨ।

श्री तेगराम (खुईयां सरवर): श्रीमान् प्रधानजी। हमारे वित्त मंत्री जी ने इस साल का बजट पेश किया और उन्होंने अपना भाषण भी दिया। मैंने बजट को भी पढ़ा और उन के भाषण को भी ध्यान से सुना है। हमारे विपक्ष के भाइयों ने काफी नुक्ताचीनी की। इस सम्बन्ध में मुझे एक बात याद आई है। नटों की एक फिरका पार्टी होती है। वे लोग कलाबाजियां वगैरा लगा कर लोगों को दिखाते हैं। उन में से एक नट बहुत ऊंचे बांस पर चढ़ता है और उस पर अपने हाथ छोड़ कर कई तरह के खेल करता है और कलाबाज़ियां लगाता है। कभी सिर को ऊंचा करता है कभी नीचा करता है। यहां तक कि जान की बाज़ी लगा कर वह कई प्रकार की कलाएं दिखाता है। लेकिन उस का साथी जो नीचे ढोल बजाता है वह, ऊपर वाला चाहे एक से एक बढ़ चढ़ कर कलायें दिखाए, एक ही आवाज़ ढोल वजा कर लगाता है कि कसर रह गई। मैं समझता हूं कि हमारे उधर के साथी, भी, चाहे गवर्नमैंण्ट कितनी ही कोशिश जनता की तरक्की के लिये करे और कितना रुपया लोगों के लिये खर्च करे, उसी ढोल वाले नट की तरह कहते रहेंगे कि अभी कसर रह गई है। मेरे विचार में उन की यह कसर तो पूरी होने वाली नहीं है। पंजाब सरकार 23 करोड़ से ज़्यादा रुपया लोगों की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर रही है लेकिन हमारे विपक्ष के भाइयों को संतोष नहीं हो रहा। हमारी सरकार ने बजट बहुत सोच विचार के बाद तैयार किया है और मैं समझता हूं कि इस के लिये, हमारे वित्त मंत्री और सारा मंत्री मंडल बधाई का पात्र हैं। निस्सन्देह, उन्होंने

बड़ा अच्छा बजट हमारे सामने रखा है लेकिन इस के बारे में एक बात मुझे कहनी है। अगर मुझ से कोई पूछे तो इस सारे बजट का सारांश में एक ही फिकरे में बतलाऊंगा कि "अंधा बांटे शीरनी फिर फिर अपनों को दे" (Interruptions)। प्रधान जी, आप के द्वारा मैं मंत्रियों के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि जो मंत्री जिन जिन इलाकों से चुने गये हैं या जिन के जहां खास खास अड्डे हैं। किसी का गुरदासपुर, किसी का अमृतसर किसी का जालन्धर, किसी का लुधियाना और किसी का रोहतक है। (एक आवाज़:—लुधियाना तो किसी का नहीं) या जो मेम्बर डंडा लेकर पीछे पड़ते हैं उन डंडों का ख्याल रख कर हमारे मंत्रिमडल ने यह बजट तैयार किया है। सब से कम ख्याल फिरोज़पुर के ज़िले की तरफ और उस से भी कम ध्यान फाज़िलका की तहसील की ओर और सब से कम ध्यान मेरे हलके खुइयां सरवर की उन्नति की ओर दिया गया है। यह बार्डर का इलाका है और मुझे खेद तो इस बात का है कि यह वह हलका है जहां के लोगों ने विभाजन के पश्चात हमारे सूबे का उन दो चीज़ों को सब से ज़्यादा सप्लाई किया है जिन की विभाजन के बाद इस को सब से ज़्यादा ज़रूरत थी वे चीज़ें हैं रूई और अनाज। ये दोनों चीज़ें मेरे हलके ने सब से अधिक और बढ़िया किस्म की दी हैं। बावजूद इस के उस इलाका की उन्नति का ध्यान नहीं किया गया ! आप यह जान कर खुश होंगे कि पिछले दिनों खेती बाड़ी के महकमे ने मुकाबला रखा था कि कौनसा ज़मींदार और किस इलाके में से सब से ज़्यादा अमरीकन रूई अपने हां पैदा करता है। तो वह इनाम मेरे हलके के ज़मींदार ने ही जीता था। उस ने अपने खेत में सब से ज़्यादा कपास की पैदावार की थी। और इस का श्रेय सारी फाज़िलका तहसील को जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सब चीज़ों के होते हुए सरकार ने सब से कम ध्यान उस इलाके की ओर दिया है। जो इलाका सारे सूबे में सब से ज़्यादा फसलें पैदा करता है यदि सरकार उस की उन्नति की ओर उचित ध्यान नहीं देती तो यह उस की कोताही है।

इसी सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरह से यह इलाका उपेक्षित किया गया है। पंच-वर्षीय योजना को आरम्भ हुए हमारे देश में ३ साल हो गये हैं। उस के अन्तर्गत पंजाब में पहले 20 करोड़ रुपया खर्च होना था लेकिन बाद में यह रकम 20 करोड़ से 32 करोड़ तक बढ़ा दी गई उस में से 15 करोड़ रुपया खर्च भी हो चुका है लेकिन इस का असर मेरे इलाका में कुछ नहीं पड़ा। मुझे अफसोस है कि मेरे हलके में सरकार ने कुछ भी खर्च नहीं किया। Community Project सामुदायिक योजना के मातहत पंजाब में 2,000 गांवों से ज़्यादा में काम शुरु हो गया है। इस पर कुल राशि जो खर्च होनी है और जो लोगों द्वारा दी गई है उस का अनुमान 80 लाख रुपया है। करीब 60 लाख रुपया खर्च हो चुका है लेकिन इस से भी मेरे इलाका को वंचित रखा गया है। इस से आगे सरकार का विचार स्थानीय उन्नति योजना पर खर्च करने का जो है वह रकम साढ़े आठ लाख रुपया है मुझे अफ़सोस है कि इस में से भी मेरे हलके के हिस्से में कुछ नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय ! इसी प्रकार राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना पर सभी बलाकों पर 225 लाख रुपये की राशि खर्च होगी। इस के मातहत हांसी, गुड़गांव, गोहाना, नूरपुर और ऊना आदि में काम शुरु हो गया है लेकिन यहां भी मेरे इलाके को छोड़ दिया गया है।

[श्री तेग राम]

इसी प्रकार सरकार ने अलग अलग महकमों के लिये किये जाने वाले काम बतलाये हैं। अब मैं सड़कों के बारे में निवेदन करूंगा कि 110 मील लम्बी सड़कें सामुदायिक विकास योजना के मातहत और 313 मील लम्बी सड़कें इन क्षेत्रों से बाहर बनाने का विचार सरकार का है। मैं अर्ज करूंगा कि मेरा हलका बहुत रेतला है। वहां पैदावार बहुत होती है लेकिन चूंकि सड़कें नहीं हैं लोगों को पैदावार मंडियों में लाने के लिये बहुत कठिनाई होती है। एक गांव गुमजाल अबोहर से 22 मील के फासले पर है। वहां के लोगों को अपना कपास का गड्डा गांव से मंडी में लाने में एक दिन लगता है और एक दिन वहां पर जिनस बेचने में और एक दिन वापिस आने में लगता है उन के तीन दिन जाया हो जाते हैं। मंडी में कपास का जो भाव होता है उस से गांव में उन को ढाई रुपये मन में कम मिलते हैं। मैं पिछले दो अढ़ाई वर्षों से बहुत कोशिश कर रहा हूं कि इस इलाके में पक्की सड़क बना कर गांवों को मंडी से मिला दिया जाये क्योंकि आने जाने में देहातियों के दो तीन दिन नष्ट हो जाते हैं। वे बहुत परेशान हैं लेकिन इस बजट में उन के लिये कोई गुंजाइश नहीं रखी गई। कई बार कहा गया है कि पटवारी गांवों में नहीं रहते। क्योंकि उन्हें शिकायत होती है कि गांव में हमारे बच्चों के पढ़ने का प्रबन्ध नहीं, यदि गांव से शहर तक पक्की सड़क हो तो पटवारी के लड़के साईकिलों पर चढ़ कर शहर पढ़ने आ सकते हैं। सरकार ने इस तरफ भी ध्यान नहीं दिया। इस इलाके के लोग भारी पैदावार करके और लगान आदि देकर सरकार का खज़ाना इस तरह भरते हैं उन की सुविधाओं की ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। वह इलाका बार्डर का इलाका है। आपने सुना होगा कि वहां खानपुर गांव (तहसील फाज़िल्का) में एक शिवनाथ नामी आदमी जब कि वह अपने खेत में जो बार्डर के बिल्कुल ऊपर है काम कर रहा था पाकिस्तान पुलिस के हाथों मारा गया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां के लोग बहुत बहादुर हैं। बार्डर के साथ की एक एक इंच ज़मीन काश्त कर रहे हैं और बावजूद इतनी कठिनाइयों के इतनी अच्छी फसलें पैदा करते हैं, जिस इलाका को दूसरे लोग डर के मारे छोड़ आये हैं। इस इलाके की ज़मीन मोटे रेत वाली है जहां मोटर नहीं चल सकती। उनकी बड़ी भारी मांग है कि वहां पर सड़कें बनाई जायें ताकि वे अपनी पैदावार मंडियों में सुविधा से ला सकें। सिवाना गांव बिल्कुल बार्डर पर है। पाकिस्तान बनने के बाद से एक आदमी वहां से नहीं हिला, चाहे सारे देश में हैदराबाद के झगड़े से या काश्मीर के उपद्रव से लोगों में घबराहट रही। छोटा सा गांव है, लोग बड़े हौसले से रहते हैं। इतना साहस करके बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया फसलें पैदा करते हैं लेकिन मुझे खेद है कि सरकार का उन की तरफ कोई ध्याना नहीं है। प्राइमरी स्कूल तक इस गांव में नहीं खोला गया।

प्रधान जी, इस के आगे मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं पिछले साल 95 गांव में बिजली पहुंचाई गई और बजट में लिखा गया है कि अब के 306 अन्य गांवों में घरेलू तथा खेती बाड़ी के कामों के लिये बिजली प्राप्य की जायगी। लेकिन मेरे हलके के गांवों तक बिजली पहुंचने वाली नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस में वज़ीरों का कोई कसूर नहीं कुदरती बात है। जैसे रोपड़ से सरहंद नहर निकलती है तो उस में इतना पानी होता है कि देख कर हैरानी होती है लेकिन जब वह मेरे इलाके में गुमजाल टेल पर पहुंचती है तो उस में बहुत थोड़ा मामूली सा पानी रह जाता है। हैरानी होती है कि इतना पानी कहां

जाता है । यही हाल बिजली का है । मेरे इलाका में बिजली की सुविधा का भी ध्यान नहीं रखा गया । इस तरह, स्पीकर साहिब, गुमजाल गांव में जो सरहद्द नहर की टेल (tail) पर है साढ़े तीन हज़ार के सिंचाई के रकबे में से गतवर्ष केवल साढ़े तीन सौ एकड़ के लगभग ज़मीन में पानी मिला जिस के बारे में असेम्बली में पूछे गये एक सवाल के जवाब में बताया गया था । यही हाल बिजली के विषय में भी है । इस में कोई संदेह नहीं कि जोगेंद्र नगर में काफ़ी बिजली पैदा होती है लेकिन मुझे बड़ा अफ़सोस होता है, प्रधान जी, यह कहते हुए कि मेरा इलाका बिजली से भी वंचित है ।

यही स्थिति, अध्यक्ष महोदय, स्कूलों के क्षेत्र में भी है । मेरे इलाके में अस्सी से भी ज़्यादा गांव हैं किंतु एक भी हाई स्कूल नहीं है । यह ठीक है, स्पीकर साहिब, कि अमीर लोगों के बच्चे दूर दूर जाकर और होस्टलों में रह कर अपनी पढ़ाई का इन्तज़ाम कर सकते हैं किंतु इन निर्धन लोगों के लिये अपने बच्चों को गांव से दस पन्द्रह मील दूर शहर में पढ़ने भेजने के लिये सिर्फ़ भोजन पर खर्च करने के लिये प्रतिमास कम से कम 20 या 25 रुपये चाहियें । वह कहां से आयें ? उन के पास तो दो वक्त रोटी खाने के लिये भी पैसे नहीं होते । तो फिर वह बच्चों की पढ़ाई का फालतू खर्च कहां से जुटायें ? मिडल स्कूल भी वहां काफी नहीं हैं । केवल मात्र मेरे सारे हल्के में दो या तीन ही हैं । जब यह कहा जाता है कि गांव वाले हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं और इस में कोई शक नहीं कि ग्राम विकास और ग्राम उन्नति के लिये और जगहों पर हमारी सरकार काफी कुछ कर रही है लेकिन मैं हैरान हूं कि मेरे इलाके के लोगों का ख्याल मेरी गवर्नमैण्ट को क्यों भूल गया, जब कि इस इलाके की जनता बहुत अधिक और बढ़िया फसलें पैदा करके अपने कर्त्तव्य का पालन करती है । इसलिए मै आप के द्वारा, प्रधान जी, सरकार से प्रार्थना करता हूं कि मेरे इलाके की तरफ भी, जो कि इतना धान्य पैदा करता है और जहां खेती बाड़ी इतनी होती है, खास ध्यान दिया जाये और उसे दिन-प्रति दिन की आवश्यक सहूलियतें पहुंचाई जायें । प्रधान जी ! मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब पिछले दिनों दिसम्बर में यहां एक मीटिंग हुई और उस में भी मैंने विनती की थी कि इस इलाके में हाई स्कूल खोले जायें तो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि वहां पर स्कूलों को क्या आवश्यकता है ? मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों की आवश्यकताओं और उन के भविष्य को सामने रखते हुए वहां पर भी स्कूलों के खोलने की अत्यन्तावश्यकता है ।

अब मैं चिकित्सा और स्वास्थ्य के प्रश्न को लेता हूं । गत वर्ष 20 आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने का उपबन्ध किया गया किंतु मैं यह देख कर हैरान हूं कि क्यों मेरे इलाका में या इस के आस पास कोई औषधालय नहीं खोला गया है ?

मंत्री : आप को चुनाव में सफलता कैसे मिली ?

श्री तेग राम : मैं पिछले 25 वर्षों से इस इलाके के ग्रामों में काम कर रहा हूं । इस इलाके में कोई ऐसा गांव नहीं जहां मैं पैदल सौ-सौ बार न गया हूं । यद्यपि मैं दोहराना नहीं चाहता, किंतु प्रसंगवश कह दूं कि सिंचाई के मामले को ही आप लें । गुमजाल गांव में सरकार ने साढ़े तीन हज़ार एकड़ के लगभग रकबा सिंचाई के नीचे रखा, किंतु उपरोक्त वर्ष

[श्री तेग राम]

साढ़े तीन सौ एकड़ रकबे को ही पानी मिला है । मेरे इलाके को 40 प्रतिशत पानी allot हुआ हुआ है किंतु बहुत ही कम मिलता है । कारण कि सरहन्द नहर की डेढ़ सौ मील लम्बाई पर यह इलाका आखरी टेल पर है । एक तो रास्ते में कई जगहों पर नहर टूट जाती है और दूसरे टेल (tail) पर होने की वजह से और भी कम पानी पहुंचता है । वहां तो यह स्थिति है कि पीने तक के लिये पानी भी नहीं मिलता ।

सिचाई मंत्री : एक तरफ तो आप कहते हैं कि यहां पैदावार बहुत होती है और खेती बाड़ी का काम लोग बहुत करते हैं । मगर दूसरी तरफ आप कहते है कि बहुत थोड़ा इलाका ज़ेरे काश्त है । आखिर यह मुतज़ाद बयान क्यों ?

श्री तेग राम : मेरे कहने का अभिप्राय यह हैं कि वहां के लोग इतने मेहनती हैं कि वह उपज को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं और जो साधन उन्हें उपलब्ध हैं उन से वे औरों के मुकाबिले में काफी पैदावार दिखा रहे हैं । जब कि पंजाब सरकार इस इलाके की उपज को देखते हुए उतना खर्च नहीं करती जितना करना चाहिये । किंतु पानी की वहां पर अभी भी काफ़ी कमी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता । पिछली दफ़ा भी मैंने ग़ैर-सरकारी दिन इस विषय पर एक प्रस्ताव इस सदन में पेश किया था जिस में मैंने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया था कि लोगों को खेती बाड़ी के लिये तो क्या पीने तक के लिये पानी नहीं मिलता । उस वक्त मंत्री महोदय के आश्वासन दिलाने पर कि वह इस मामले पर अवश्य ध्यान देंगे और लोगों के इस कष्ट को दूर करेंगे, मैंने वह प्रस्ताव वापस ले लिया था किंतु मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आश्वासन को कार्यान्वित नहीं किया गया । पानी की वहां इतनी तकलीफ़ है कि गांव की औरतें अपने सिर पर घड़े उठा कर आध आध मील दूर से गर्मियों के जलते दिनों में पानी लाती हैं । जहां जहां वहां पर स्थानीय जगहों पर डिग्गियां हैं, उन पर ज़मींदारों का कब्ज़ा है । और नहर का पानी भी ज़मींदारों के पास होता है जो नहीं डालने देते । इस प्रकार ग़रीब लोगों को पीने के पानी की बड़ी कठिनाई है । इसलिये, मैं उम्मीद करता हूं कि सिंचाई मंत्री साहिब अब इस विषय पर अवश्य ध्यान देंगे और लोगों की इस तकलीफ को दूर करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री केशो दास (पठानकोट) : माननीय स्पीकर साहिब ! जहां मैं इस बजट के पेश करने पर फाईनैंस मिनिस्टर (Finance Minister) साहिब को बधाई देता हूं, वहां मेरे इलाके में कुछेक तकलीफें हैं जिन की ओर मैं अपनी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

सब से पहिले, स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यहां पर सिर्फ एक ही सड़क—पठानकोट-डलहौज़ी सड़क है । यहां पर और सड़कें बनाने की बड़ी ज़रूरत है । पठानकोट की आबादी भी कोई 60,000 से ज़्यादा तक पहुंच चुकी है । यह एक पहाड़ी इलाका के साथ है जहां पर आने जाने के लिये सड़कों की कमी की वजह से लोगों को बहुत तकलीफ़ है । इसलिये मैं सरकार से सिफ़ारिश करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (District Board) को सड़कें बनाने के लिये ग्रांट दी जाये ।

दूसरी तकलीफ़, स्पीकर साहिब, मेरे इलाके के लोगों को पीने के पानी की है। पानी एक निहायत ज़रूरी चीज़ है। इसलिये सरकार को चाहिये कि इस तरफ भी ध्यान दे। क्योंकि लोगों को पांच-पांच और छः छः मील दूर जा कर पानी लाना पड़ता है। सन् 1949 में शप्परकंडी की स्कीम बनी थी लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। मैं गुज़ारिश करता हूं सिंचाई के मंत्री साहिब से कि वह इस स्कीम को चालू करवायें और लोगों की तकलीफ़ को दूर करें। हमें पिछले दो वर्षों से यह बताया जा रहा है कि लोगों की पानी की तकलीफ़ को दूर करने के लिये और आबपाशी के लिये ज्यादा पानी मुहैया करने के लिये tube-wells लगाये जा रहे हैं। लेकिन मेरे इलाकों को इस स्कीम में भी नज़रन्दाज़ किया गया। मुझे आशा है कि मिनिस्टर साहिब इस चीज़ पर भी ग़ौर करेंगे।

अब मैं इश्तमाल अराज़ी की तरफ आता हूं। बटाला के बाद इस स्कीम के नीचे पठान कोट की बारी थी लेकिन पठानकोट को छोड़ कर पहले गुरदासपुर में यह काम शुरू किया गया है। मैं डीवैलपमैण्ट मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करता हूं कि मेरे इलाके में यह काम पहले किया जाये।

सिंचाई के बारे में भी मैंने एक बात और कहनी है। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि माधोपुर और सुजानपुर की नहरों के किनारे इलाकों को lift system से पानी दिया जाये ताकि पैदावार ज्यादा हो सके और लोग अपनी रोज़ी कमा सकें।

तालीम के सिलसिले में भी, स्पीकर साहिब, मैं एक दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूं। एक ग़रीब लड़के और एक अमीर लड़के की तालीम में अभी तक बड़ा फ़र्क चला आ रहा है। जहां कि शहरों के लड़कों के लिये तालीम का मियार ऊंचा रखा हुआ है वहां गांव के लड़कों को बहुत कम तालीम दी जाती है। हमें चाहिये कि गांव वालों को ऊंचा उठाने के लिये सब से पहले उन के लिये अच्छी तालीम का इंतज़ाम करें। ऐसा करने के लिये हर गांव में 10 एकड़ ज़मीन अलग की जाये और वह पंचायतों के सुपुर्द की जाये ताकि उस से आने वाली आमदन को पंचायतें बच्चों के लिये स्कूल खोलने पर लगा सकें।

इस के इलावा, स्पीकर साहिब, महाभारत से पहले जिस तरह श्री कृष्ण जी और सुदामा इकट्ठे एक ही स्कूल में तालीम हासिल करते थे, उसी आदर्श को हमें आज भी अपनाना चाहिये। अमीर और ग़रीब दोनों के बच्चों को यकसां तालीम दी जानी चाहिये। जिस तरह महाभारत के ज़माना में लोगों पर कोई टैक्स नहीं था और जिस प्रकार लोग चैन और आराम की जिन्दगी बसर करते थे उसी तरह अब भी हालात पैदा किये जाने चाहियें। उस ज़माने में तो हिंदुस्तान में बनी हुई चीज़ें बाहर के मुल्कों में जाया करती थीं। अब उस के उल्ट ही है। इसलिये हमें चाहिये कि हम खुद यहीं पर चीज़ें बनायें और मुल्क के पैसे को बाहर जाने से बचायें। मिसाल के तौर पर दवाइयां हैं। उन को बनाने के लिये कच्चा माल यहां से जाता है। हमें चाहिये कि बजाये इस के कि पहले हम कच्चा माल सस्ते दामों पर बेच कर उससे बनी हुई दवाइयां महंगे दामों पर खरीदें, हम खुद ही अपने मुल्क की laboratories में वे दवाइयां तैयार करें।

अध्यक्ष महोदय: आप पंजाब के बारे में कह रहे हैं या सारे हिंदुस्तान के बारे में ?

श्री शेर सिंह: देश-विदेश की बातें कर रहे हैं।

श्री केशोदास : इस के इलावा, स्पीकर साहिब, मैं teachers के grade के मुतअल्लिक भी कुछ कहना चाहता हूं। सन् 1944 से पहले teachers का ग्रेड 80–5–100–5–175 था। सन् 1944 के बाद बी.टी. टीचरों का ग्रेड 90–5–150 और प्रोफैसरों का 150–10–190/10–350 हो गया था। यह ठीक है कि अब बी. ए. बी. टी. टीचरों का ग्रेड 110–8–190/10–250 और प्रोफैसरों का ग्रेड 180–10–320/16–400 कर दिया गया है लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि दूसरे टीचरों का ग्रेड नहीं बढ़ाया गया। मुझे उम्मीद है कि हमारे फ़ाईनैंस मनिस्टर (Finance Minister) साहिब उन की तकालीफ़ को भी महसूस करेंगे और उनकी हालत को सुधारेंगे।

एक बात और कह कर मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। हमारे कम्युनिस्ट भाइयों ने बेरोज़गारी का ज़िक्र किया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बेरोज़गारी को पैदा करने के ज़िम्मेदार वे खुद हैं। आखिर बेरोज़गारी कैसे हुई ? इस का आगाज़ दिहातों से हुआ। बजाए लोगों को आपस में लड़ने से बचाने के, इन्होंने ज़मींदारों और किसानों को आपस में लड़ाया। दिहातों में मजदूरों और किसानों की आबादी ज़्यादा हुआ करती थी, जब इन्होंने किसानों और ज़मींदारों को आपस में लड़ा कर किसानों की बेदखलियां करवाईं तो वे लोग शहरों में आ गये। इस तरह जहां पहले शहरों में एक मजदूर था वहां अब 10 हो गए और इस तरह बेरोजगारी बढ़ती बढ़ती और भी ज़्यादा बढ़ गई। जब दिहातों में पैदावार कम हो गई तो उस का असर शहरों में लगी हुई फ़ैक्ट्रियों पर पड़ा और वहां पर भी काम की कमी होने के कारण मज़दूरों में बेरोज़गारी का इज़ाफ़ा हो गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंबर साहिब ने आज बड़ी enlightened speech की है। इसलिये अब वह खत्म करें और बाकी चीज़ें फिर किसी वक्त कह लें। दूसरे मैम्बरों ने भी बोलना है।

श्री केशो दास : बहुत अच्छा, स्पीकर साहिब जैसा आप का हुक्म। इन लफ़्ज़ों के साथ मैं फाईनैंस मिनिस्टर साहिब (Finance Minister) को फिर बधाई देता हूं, और अपनी जगह पर बैठता हूं।

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਿਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਭਰਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਚ ਮੁਚ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀ ਜੋ Opposition ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ Treasury Benches ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਾਂ ਤਾਂ ਸਚੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਲ ਫੇਰ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਗਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਾ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਖੈਰ ਖ਼ੈਰੀਅਤ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਤੇਰੀ ਕੁੱਤੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ

ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੁਤੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਮਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉਠ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਸ ਖਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਈ ਸੀ । ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਠ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕਾਲਵਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਬਨਾਣ ਲਈ ਮਿਟੀ ਢੋਹ ਢੋਹ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਕੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛਤ ਢਹਿ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਹੇਠਾਂ ਆਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਰਦੇ ਨੇ । ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਆਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ । ਸਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਰ ਹੈ । ਅਸੀ ਤਾਂ ਸਿਧੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ।

ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰਖ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੱਕੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਸਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਇਸਨੇ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਠੇਗਾ ? ਇਕ ਲਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਮਿਲ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਨੋਟਸ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ । ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਕ ਇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾਲ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸਿਰਫ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਸਮਝ ਰਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੈਲੇਗੀ । ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗੀ । ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਉਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟਿਆਂ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰਖ ਕੇ ਆਪ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ । ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਗਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे साथ बातें करें, उन से नहीं ।

ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਓਹ tractor ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਰੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ tractor ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ

[ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ]

ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ! ਇਹ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਸਵਾਰਨ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ Address ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮੇਹਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ! ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਹੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਣ ਲਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਰਕਮ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਕਿ ਓਹ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੰਡਕੇ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੋ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਗਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝੇ। ਖੁਦਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਸਮੇਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ੨ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਵਲਾਇਤ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਚਾਰੇ border (ਬੋਰਡਰ) ਤੇ ਬੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਹੁਣ ਆਪ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਥੇ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲ ਆਖਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ੨ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ industry ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋ ਚਾਰ ਵਡੇ ੨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬ ਦਿਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੀ industry ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਮਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਭੰਗੜ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੇਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ 30,000 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ " ਉਏ ਤੁਸੀਂ ਕਮਯੂਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ......".

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਅਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰੋ। ਦੋ ਮਿਨਟ ਹੋਰ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਨੀਲੋਖੇੜੀ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜੋ ਬਨਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਲਕ ੨ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਡੁਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। 80 ਫੀ ਸਦੀ ਮਕਾਨ ਕ੍ਰੈਕ (Crack) ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਨ ਮੈਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 6, 6 ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 12 ਰੁਪੈ ਫੀ ਆਦਮੀ ਦਿਉ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ $2\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{2}$ ਲਖ ਰੁਪਿਏ ਦਿਆਂ ਬਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੇਹਨਤ ਕਰੋ।

ਹੁਣ ਇਕ ਦੋ ਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ ? ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਕਯੂਸੇਕ ਵੀ ਪਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਸਰਾਲਾ ਆਦਿ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦ ਬਹਿ ਗਏ ਹਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਪੁਛਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਚਾਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਨ ਦੇਵੇਗਾ।

श्री बाबू दयाल (सोहना) : अध्यक्ष महोदय, बजट जो Finance Minister साहिब ने पेश किया है वह एक घाटे का बजट है। इस में ग्रामदनी 22 करोड़ 19 लाख रुपये है ग्रौर खर्च 23 करोड़ 12 लाख रुपये है। किसी बजट की जांच करने के लिये यह देखना होता है कि इस में ग्रामदनी कितनी है ग्रौर खर्च कितना है। इस बजट में ग्रामदनी से खर्च ज्यादा है इस लिये Treasury Benches को इस बात के मानने में कोई एतराज़ न होगा कि यह एक घाटे का बजट है।

दूसरी बात यह है कि जो ग्रखराजात बजट में दिखाए गए हैं वे किस किस्म के हैं जैसा के मेरे से पहले कुछ मेम्बरान ने फरमाया कि यह एक Welfare State का बजट है। यह बात समझ में नहीं ग्राती कि यह एक Welfare State का बजट कैसे हो सकता है। जैसा कि ग्रभी एक ग्रानरेबल मेम्बर ने फरमाया कि Welfare State का वह बजट होता है जिस में लोगों की भलाई के लिये ज्यादा खर्च हो। मैं तो कहूंगा कि यह बजट एक पुलिस State का बजट है, क्योंकि इस के ग्रन्दर पुलिस का खर्च 2 करोड़ 92 लाख 44 हज़ार रुपया है। जो कि बाकी सरकारी विभागों से बहुत ज्यादा है। फिर हम किस तरह से कह सकते हैं कि यह एक Welfare State का बजट

[श्री बाबू दयाल]

है ? यह तो हिसाब किताब की बात है। 2 करोड़ 92 लाख 44 हज़ार की रकम क्या पुलिस के लिये कम है । जबकि 51 लाख 52 हज़ार और 91 लाख 30 हज़ार beneficent कामों के लिये खर्च किया है। हमारे मुल्क के लिये 3 मदें बहुत ज़रूरी हैं। पहली, Industries की जिस पर 56 लाख रुपया खर्च किया गया है, दूसरे Agriculture है जिस पर 51 लाख 22 हज़ार रुपया खर्च किया गया है और तीसरी है पंचायत । Community Project के बारे में कहा जाता है कि यह ईश्वर की देन है और इस से पंजाब में राम राज्य स्थापित हो जायगा और पंजाब बहिश्त का नमूना बन जायगा । मुझे ताज्जुब है कि इन बातों से यहां राम राज्य कैसे कायम हो सकता है ? जिस बजट में इतना कम खर्च public की भलाई के लिये किया गया हो वह Welfare State का बजट कैसे हो सकता है ? कहते हैं कि गवर्नमेंट की पालिसी से यहां पर राम राज्य स्थापित हो जायगा, यह बात समझ में नहीं आती । मैं दावे से कहता हूं कि गवर्नमैण्ट की पालिसी महात्मा गांधी और जवाहर लाल के नाम पर public को exploit करने के सिवाए कुछ नहीं है । (Interruptions) अगर गवर्नमैण्ट की नौकरी में कोई दयानतदार और ईमानदार अफ़सर आजाये तो उस को penalise करना ताकि वह नौकरी छोड़ कर चला जाये, यह है गवर्नमैण्ट की पालिसी ।

मुझे ताज्जुब है कि महात्मा गांधी जी ने जो असूल कायम किये हैं उन को इन लोगों ने बिल्कुल नहीं अपनाया है । और उन की एक भी बात पर अमल नहीं किया है । फिर जब यह फ़रमाते हैं कि हमने हरिजनों का उद्धार किया है तो मैं पूछता हूं कि इन्होंने हरिजनों का उद्धार कैसे किया है ? एक मिनिस्टर (Minister) बना दिया और और दो चार एम. एल. ए. बना देने से हरिजनों का कैसे उद्धार हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : हरिजन एम. एल. एज़. की गिनती 2-4 नहीं हैं ।

श्री बाबु दयाल : श्रीमान् जी, चाहे यह गिनती 10-20 हो चाहे 20-50 हो चाहे पांच सौ एक हज़ार हो मैं यह अर्ज़ करना..................

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इस बात का फैसला कर लिया है कि आप गलत ही कहेंगे । 1-2 की गिनती भी गलत थी और पांच सौ एक हजार भी गलत है ।

श्री बाबू दयाल : श्रीमान जी ! मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस तरह क्या हरिजनों का उद्धार होगा ? गांधी जी के नाम पर इन का नाम चल रहा है । मैं आप के सामने अर्ज़ कर रहा हूं कि स्पीकर साहिब आप इनको इनके कान खोलकर फ़रमा दें कि महात्मा गांधी तो यह फ़रमाते थे कि कांग्रेस का राज्य किसानों और मज़दूरों का राज्य होगा । वे फरमाते थे कि इन किसानों और मज़दूरों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें दी जायें । महात्मा गांधी का फरमाना था कि हिंदुस्तान का पहला प्रेजीडेंट कोई किसान हो या मज़दूर हो । मगर हम देखते क्या हैं ? मैं सच कहता हूं और मुझे रोना आता है जब मैं अपनी constituency (कांस्टीट्यूऐंसी) की तरफ़ आता हूं । Consolidation के अन्दर गांव में एक एक कोठरी में 20-20 आदमी रहते हैं । कोठरियां गांव से बाहर होती हैं और इन में सब आदमी ठीक से नहीं रह सकते । मैं तो हैरान हूं कि यह लोग अंग्रेजों को बदनाम करते हैं

कि उन्होंने ब्लैक होल (Black Hole) में बन्द करके लोगों को मारा। पर ये लोग भी तो अंग्रेज़ों से कम नहीं हैं। हरिजनों के लिये गांवों में लाखों ब्लैक होल (Black Hole) बने हुए हैं तो हरिजनों का उद्धार क्या होगा ?

फिर स्पीकर साहिब ! हरिजनों को ज़मीन नहीं दी जाती। हालांकि इन को consolidation से ज़मीन मिलने का हक है। लाखों हरिजनों को इस का हक है पर वे यह कहते हैं कि उन की आवाज़ कोई नहीं सुनता। पहले पटवारी उन की खबर लेते हैं फिर उन के ऊपर गिरदावर और तहसीलदार बैठे हैं। एक आंखों देखा हाल सुनाता हूं। छठोंवास गांव में मैं खुद देख आया हूं वहां हरिजनों के लिये जो ज़मीन रखी गई थी........

अध्यक्ष महोदय : आप किसी अहम मामले पर फरमायें।

श्री बाबू दयाल : मैं तो अहम मामला ही अर्ज़ कर रहा था। गांव में हरिजनों ने सैटलमेंट अफीसर (Settlement Officer) से शिकायत की कि उन के लिये ज़मीन छोड़ी जाये। इस बारे में मैं खुद डायरैक्टर साहिब से भी मिला। जिस पर उन्होंने नाले में एक कीला ज़मीन छोड़ दी। मैंने फिर सैटलमैण्ट आफीसर (Settlement Officer) से कहा कि यह ज़मीन नाले में है तो उस ने कोई परवाह न की। उस ने यह भी कहा कि गवर्नमैण्ट ने पक्का इरादा कर लिया है कि हरिजनों को दरिया में बहा कर समुद्र तक पहुंचा दिया जाये ताकि वापिस न आ सकें।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर आप की बात मानी गई।

श्री बाबू दयाल : मानी कहां गई है। ज़मीन तो नाले में ही है। लोगों की यह हालत है और वह समझते हैं कि हरिजनों का उद्धार हो रहा है। सरकार के रुकन तो यह समझते हैं कि जितना झूठ बोला जाये अच्छा है। उन्होंने तो झूठ बोल बोल कर इस को magnify कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप को पता होना चाहिये कि 'झूठ' शब्द unparliamentary है। इस का इस्तेमाल न करना चाहिये।

आवाज़ें ('गलत' कह दीजिये)।

श्री बाबू दयाल : तो स्पीकर साहिब ! जितना यह ग़लत कह सकते हैं कहते हैं। वह फरमाते हैं कि प्रापेगेंडा करो। प्रोपेगेंडा का यह मतलब लेते हैं कि एक सौ या दो सौ आदमी इकट्ठे कर लिये और वे इतना झूठ बोलें कि उन के मुखालिफ वाले उन के सामने बोलने की जुरअत न कर सकें।

एक और बात मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। वे यह कहते हैं कि उन्होंने Judiciary को Executive से अलग कर दिया है। पर मैं इस बारे में अर्ज़ कर दूं कि Judiciary और Executive में जो लोग हैं वे अंग्रेज़ों के वक्त के अफ़सर हैं। और जो मेरे Opposite में बैठे हैं इन में से भी बहुत से ऐसे हैं जिन की ज़हनियत अंग्रेज़ों की सी है। इसलिये जब तक इन की यह ज़हनियत न बदलेगी Judiciary और Executive को अलग अलग करने से कुछ फ़ायदा न होगा। इन्होंने अंग्रेज़ों से राज्य लिया, इस लिये इन के दिमाग में राज चलाने के वही ढंग भरे पड़े हैं जो अंग्रेज़ों के थे। उन की पालिसी अंग्रेज़ों की पालिसी है। उन को चिन्ता है कि कहीं उन का prestige

[श्री बाबू दयाल]

न खत्म हो जाये। वह हमेशा डरते रहते हैं। मैं कहता हूं कि महात्मा गांधी भी prestige रखते थे। जब महात्मा गांधी विलायत में गये और उन्होंने देखा....

अध्यक्ष महोदय : यह बात किसी और दिन सही।

ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ (ਦਸੂਆ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਜਟ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ (Finance Minister) ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਤਾ ਹੈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਉਨਤੀ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇ ਦਿੰਦਾ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Welfare State ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂ decentralization ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟਯੂਬ ਵੈਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸਟੇਟ ਵਿਚ Electricity ਆ ਰਹੀ ਹੈ। Extension ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Community Projects ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਗਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ Exploit ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਗਏ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕਮਯੂਨਿਸਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਵਲ exploit ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ Constituency ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤੇ ਸਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾਂ ਹੁੰਦੀ।

ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ House ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ Opposition ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਲੈਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਜਟ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਹ ਬਜਟ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਇਕ ਗਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀ Unionist ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਚੋਆਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੨ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਕਮ ਵਾਸਤੇ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ॥

श्री दौलत राम शर्मा (हमीरपुर) : प्रधान जी, इस बजट को देख कर अगर पहल बजटों से मुकाबिला किया जाये तो मालूम होगा कि हमारे सूबे में लगातार progressive बजट पेश किया जा रहा है। इस बजट की तीन बातें खासतौर पर ज़िक्र करने के काबिल हैं। पहली बात तो यह है कि पिछले साल की तरह upper grade और lower grade का फर्क कम करने की कोशिश की गई है। पिछले साल भी यह बात की गई थी और अब के इस तरफ एक और कदम बढ़ाया गया है। मैं इस पर सरकार को बधाई देता हूं

दूसरी बात यह है कि ज़रायत के बारे में भी काफ़ी तरक्की की गई है। अगर कोई jaundiced eye से देखे तो और बात है। जब मुल्क तकसीम हुआ तो हम को 60 हज़ार टन ग़ल्ला बाहर से मंगवाना पड़ता था और हमारे पास कपास भी नहीं थी। नहरों का system पाकिस्तान में रह गया था और हमारे पास सिर्फ दो नहरें रह गई थीं। इस के इलावा अच्छा इलाका उधर रह गया और हमारे हिस्से में कम पैदावार वाला बंजर इलाका आया। मतलब यह कि हर तरह से घाटा ही नज़र आ रहा था। मगर अब आप देखते हैं कि लोगों और सरकार की co-operation ने वह कमी किस तरह पूरी कर दी है। हमने अनाज के बारे में अपनी कमी पूरी करके 75,000 टन ग़ल्ला बाहर भेजा है। यह आसमान से तो नहीं गिरा, हमने ही पैदा किया है।

फिर जनाब, अमरीकन कपास हमारे हां बहुत थोड़ी थी। पहले इस की पैदावार 60,000 bales थी मगर अब 2,50,000 bales हो गई है। यह तरक्की बहुत प्रशंसनीय है। हम इस पर फख़र कर सकते हैं।

इसी तरह agrarian reforms का भी बहुत चर्चा है और इन से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है अगर्चि यह reforms अभी मुकम्मल नहीं हुई फिर भी situation को ease कर दिया गया है। बाज़ दोस्तों ने बेदख़लियों का बहुत ज़ोर से ज़िक्र किया है। यह ठीक है कि कुछ दिन बेदख़लियों का ज़ोर बढ़ गया था। मगर यह बाज़ लोगों के ग़लत प्रापेगेंडा का नतीजा था। Opposition वाले दोस्त लोगों से कहते फिरते थे कि तुम्हारी ज़मीनें छिन जायेंगी और मुज़ारे मालिक बन जायेंगे। पालमपुर, हमीरपुर और देहरा में यही प्रापेगेंडा किया गया और इस का असर दूर करने के लिये counter propaganda करना पड़ा तब लोगों को असल बात मालूम हुई। मुमकिन

[श्री दौलत राम शर्मा]

है कि हिसार में ज्यादा बेदखलियां हुई हों। मगर बड़े मालिक के लिये कानून मौजूद हैं। बाज़ लोग औरतों और लड़कों के नाम ज़मीन करके लोगों को बेदखल कर रहे होंगे। लेकिन जब दावे होंगे तो गलत और खिलाफ़े कानून बेदखलियां कायम न रह सकेंगी।

बजट में सब से बड़ी चीज़ यह देखी जाती है कि इस में लोगों की भलाई के कामों, मसलन आबपाशी, ज़रायत, तालीम और पब्लिक हैल्थ पर क्या खर्च किया गया है। आप देखते हैं कि इन सब महकमों पर काफ़ी खर्च करने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इन महकमों पर खर्च तो बेशक ज्यादा से ज्यादा करना चाहिये मगर कुछ बातों में economy हो सकती है। वह ज़रूर करनी चाहिये। आप देखते हैं कि जो District Health Officers रखे हुए हैं इनका काम Civil Surgeon के मातहत तबदील किया जा सकता है। जिस तरह Director of Public Health का अलहदा ओहदा हटा कर Director of Health Services के मातहत कर दिया गया है उसी तरह इसे भी Civil Surgeon के मातहत किया जा सकता है।

अब आखिर में एक बात अपने इलाका के बारे में कहना चाहता हूं — ज़िला कांगड़ा को सब जानते हैं कि backward इलाका है। इस में भी हमीरपुर की तहसील सब से ज्यादा backward है। यहां हमें सड़क की बड़ी तकलीफ है। नूरपुर को पक्की सड़क जाती है और इसी तरह देहरा को भी। मगर मैं दो साल से अपने इलाका के लिये all weather सड़क मांग रहा हूं। मेरी अर्ज़ है कि हमें पंजाब के साथ मिला दिया जाये। 6 महीने तो हम पंजाब से बिल्कुल अलग रहते हैं। हमें कम से कम चार महीने के लिये खाने पीने का सामान बरसात के मौसम के लिये जमा करके रखना पड़ता है क्योंकि बाहर से बिल्कुल ताल्लुक टूट जाता है। बस मेरी अर्ज़ यह है कि हमारी तकलीफ़ पर ध्यान कर के हमें एक all weather सड़क बना दी जाये।

प्रधान जी, बजट हमारे सामने पेश हुआ। बजट एक ऐसी चीज़ है जिस के ज़रिये गरीबी मुखतलिफ़ वर्गों में तकसीम की जाती है। इस तरीके से बहुत सी सामाजिक बुराइयों को दूर किया जाता है। जमहूरी हकूमतों में जब बजट पेश होता है तो उन सब तबकों की तरफ खास तौर पर देखा जाता है जो समाज में पिछड़े हुए होते हैं। जब मैंने बजट को कुछ सरसरी तौर पर पढ़ा और इसमें पहले गवर्नर साहिब के Address और इस के बाद अपने Finance Minister साहिब की speech को सुना तो इस से ज़ाहिर होता था कि आज़ादी के बाद जो रकम पिछड़े हुए वर्गों के लिये रखी गई थी उस में कोई इज़ाफ़ा नहीं हुआ। 1948 में एक हरिजन welfare scheme जारी हुई थी और इस के लिये आठ लाख रुपया सालाना हरिजन बच्चों की तालीम और दूसरी रियायतों के लिये provide किया गया था। आज भी इस साल के बजट को Welfare State का Budget और development budget कहा गया है। परन्तु development है किस बात को। चीज़ तो मुझे नज़र आ रही है और यह कोई

निराली बात नहीं । मेरी समझ में तो यह agriculturist biased budget है । जैसा कि अंग्रेज किताबों और लैक्चरों के ज़रिये हम पर यह ठोंस गया है हिंदुस्तान खेती का मुल्क है । हम अब भी यही ख्याल किये जा रहे हैं । हम इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि यहां ऐसे लोग भी बसते हैं जिन का खेती या ज़मीन से ज़्यादा सम्बन्ध नहीं । या है तो कम है और इन के लिये भी कुछ बजट में रखा जाना चाहिये । हमने कई तजावीज़ सरकार के सामने रखी थीं । और ख्याल था कि एक इनकलाबी बजट बनेगा । और उन लोगों के लिये जिन के means of production नहीं हैं या पैदावार के ज़रियों से महरूम हैं उन के लिये भी केवल ज़्यादा रुपया ही नहीं रखा जायगा बल्कि पैदावार के ज़रियों को अच्छी तरह तकसीम किया जायगा । लेकिन आज हमारे सामने यह तालीम का मसला है । अकेली Harijan Welfare Scheme में तालीम पर ज़ोर दिया गया है । हमारा यह हाल है कि पंजाब में 24 लाख हरिजन रहते हैं । इन पर आठ लाख रुपया सालाना खर्च होता है । पंजाब के पिछड़े हुए तबके पर सवा पांच आने फ़ी कस खर्च आता है । मेरा विचार है कि इस रफ़्तार पर काम करने से तो इस तबके को 100 साल में भी नहीं उठाया जा सकता । कहा जाता है कि हरिजनों को 19 की जगह 21 फ़ीसदी हकूक दिये जा रहे हैं । परन्तु जब असैम्बली में सवाल पूछे जाते हैं कि सरकार के मुख्तलिफ महकमों में कितने कितने हरिजन हैं तो जवाब मिलता है कि सरकारी नौकरियों के लिये योग्य हरिजन मिलते ही नहीं । यह बहुत निराशाजनक जवाब है परन्तु मैं पूछता हूं कि इस बात की कि योग्य हरिजन नहीं मिलते यह ज़िम्मेदारी किस पर है । सरकार पर । उस जमहूरी सरकार को जो हरिजनों को उठाने का दावा करती है चाहिये कि योग्य उम्मीदवार पैदा करे ।

प्रधान जी, हमारे बजट में कहा गया है कि गवर्नर साहिब के Address में भी कहा गया था कि इस पंजाब में ७ लाख एकड़ भूमि waste land है । यह ऐसी ज़मीन है जो काबले काश्त नहीं । हम कहते हैं कि यदि इस तबका को जिसे निहायत नफ़रत की निगाह से देखा जाता है और जिस के लोगों को कूओं पर जाने की आज्ञा नहीं, उठाना है तो यह ज़मीन इन को क्यों नहीं दी जाती । ज़मीन के मिलने से उन की ग़रीबी खुद बखुद दूर हो जायगी । उनकी गरीबी रुपया देने से या तालीम की सुविधाएं देने से दूर न होगी । उनकी ग़रीबी उस समय दूर होगी जब उन को समाज में उचित दर्जा दिया जायगा । हम ज़मीन इस लिये मांगते हैं कि इस से हमारा दर्जा बढ़ेगा और हमारे ज़मींदार भाई हम पर अत्याचार न कर सकेंगे । ज़मीन में हमें अवश्य हिस्सा मिलना चाहिये । इस का यह मतलब नहीं कि हम किसी की ज़मीन मांगते हैं । हम तो अपनी उस जमहूरी सरकार से जो गांधी जी की photo सामने रख कर काम करती है यह प्रार्थना करते हैं कि ज़मीन की ठीक प्रकार तकसीम की जाये और उन हरिजनों को जिन से गांधी जी का इतना प्यार था हिस्सा दिया जाये ।

प्रधान जी, रोहतक में पसमांदा जातियों की एक conference हुई थी । इस में Chief Minister साहिब, Development Minister साहिब, और कई और वज़ीर भी शामिल हुए । Centre से भी कुछ लोग आये । इन्होंने ऐलान किया कि सरकारी ज़मीन लाज़मी तौर पर हरिजनों को दी जायगी । लेकिन जब मैंने गवर्नर साहिब

[श्री दौलत राम शर्मा]

का Address पढ़ा और उस के बाद Budget Speech और बजट को पढ़ा तो इन में कोई ऐसा इशारा नज़र न आया। प्रधान जी इस समय दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में नये नये इनकलाब आ रहे हैं। इन इनकलाबों में कोई नई बात नहीं। यह इनकलाब लोगों की ज़मीन हासिल करने की भूख से पैदा होते हैं। मैं कहे देता हूं कि यदि यहां भी ज़मीन की तकसीम का सही हल न किया गया तो वह बड़ा इनकलाब जिस से हम सब डर रहे हैं आकर ही रहेगा

प्रधान जी, इनकलाब तीन तरह से आते हैं। एक तो प्रेम से आते हैं और एक कानून के ज़रिये।

श्री स्पीकर साहिब : बाकी के इनकलाब कल आयेंगे (*Laughter*)।

The Assembly then adjourned till 2 *p.m. on Wednesday, the* 17*th March* 1954.

205 PSLA—283—13-10-54— CP and S, Punjab, Chandigarh

Punjab Legislative Assembly Debates

17th March, 1954.

VOL. I—NO. 8

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, 17th March, 1954

CHANDIGARH

Printed by the Controller, Printing and Stationery, Punjab

1954

Price : -/7/-

PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY

Wednesday, 17th March, 1954

The Assembly met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital, at 2 p.m. of the clock. Mr. Speaker (Dr. Satyapal) in the Chair.

QUESTION HOUR (DISPENSED WITH)

अध्यक्ष महोदय : मैम्बर साहिबान की खाहिश का एहतराम करते हुए आज भी सवालों का वक्त बहस के लिये इस्तेमाल किया जायगा। अब सैक्रेटरी साहिब एक announcement करेंगे।

ANNOUNCEMENT BY THE SECRETARY RE. CERTAIN BILLS.

Secretary : In pursuance of Rule 2(ii) of the Punjab State Legislature (Communications) Rules, 1952, I have to inform the House that the Sikh Gurdwaras (Second Amendment) Bill, 1954 passed by the Punjab Legislative Assembly on the 9th March, 1954 and transmitted to the Punjab Legislative Council on the 10th March, 1954 and the Punjab Appropriation Bill, 1954 passed by the Punjab Legislative Assembly on the 15th March, 1954 and transmitted to the Punjab Legislative Council on the same day have been agreed to by the said Council without any amendment/recommendation on the 15th March, 1954 and 16th March, 1954, respectively.

TRANSACTION OF GOVERNMENT BUSINESS ON THURSDAY, THE 18TH MARCH, 1954.

Minister for Development (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, I beg to move—

> That Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and the Government business transacted on Thursday the 18th March, 1954.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and the Government business transacted on Thursday, the 18th March, 1954.

Mr. Speaker : Question is—

> That Rule 23 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and the Government business transacted on Thursday, the 18th March, 1954.

The motion was carried

RESUMPTION OF GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET

Mr. Speaker : Yesterday, when the House adjourned, Shri Chand Ram Ahlawat was on his legs. Now I would call upon him to resume his speech.

श्री चान्द राम एहलावत (झज्जर) : प्रधान जी ! कल मैं इस हाऊस में सामाजिक और आर्थिक इनकिलाब का जिक्र कर रहा था। आज की दुनियां में तीन प्रकार के इनकिलाब आते हैं। एक इनकिलाब तो वह है जो हमारे पूज्य स्वर्गीय बापू जी के अनन्य भक्त आचार्य विनोवा भावे जी बड़ी तेजी से हमारे मुल्क के सामने ला रहे हैं। यह इनकिलाब अज खुद है क्योंकि तजारत और पैदावार के साधनों की जननी-भूमि-का बटवारा एक नई ही प्रणाली अर्थात् "भू-दान" के माध्यम से शीघ्र ही होने वाला है। इस में पर्याप्त मात्रा में भूमि आचार्य जी को प्राप्त हो चुकी है। उन का परिश्रम केवल भूमि तक ही सीमित नहीं। वे दौलतमन्द लोगों के धन को भी "सम्पत्ति दान" के अन्तर्गत इकट्ठा कर रहे हैं जिस से वे गरीब लोगों का उत्थान कर उन का भविष्य उज्ज्वल बनायेंगे।

एक इनकिलाब और है जो हम प्रजातन्त्र के युग में यहां इस हाऊस में बैठ कर कानूनों के ज़रिये लाते हैं। यह हम भिन्न प्रकार की लोक हितकारी legislation पास करके लाते हैं। इस इनकिलाब को पहली प्रकार का इनकिलाब मदद देता है—प्रोत्साहित करता है। वह इस कानूनी इनकिलाब की मदद इस तरह से करता है कि वह ऐसा वातावरण तैयार करता है जिस में ऐसे कानून बनाये जा सकें। इस समय हम क्या देखते हैं ? इस वक्त खुदादाद चीज़ों पर कुछ ही इने गिने लोगों का कब्ज़ा है। इस इनकिलाब का मुख्य कार्य property की इस पुरानी notion को बदलना और इस सम्पत्ति को progressive तरीके से अपना कर अमीर-गरीब सब में एक जैसा बांटना है। इस इनकिलाब का ध्येय इस सम्पत्ति को उन लोगों में बांटना है जिन के पास वह नहीं है। तो इस तरीके से जहां पहली किस्म का इनकिलाब दूसरी प्रकार के इनकिलाब को अस्तित्व में लाने के लिये वातावरण तैयार करता है, वहां यह कानूनी इनकिलाब उस सामाजिक और आर्थिक इनकिलाब के सिद्धांतों को कार्यान्वित करता है।

तीसरा इनकिलाब वह है जिस को न पहले इनकिलाब की तरह आम लोगों के बहुमत की support हो और न ही कानूनों द्वारा लाया जाये। वह है खूनी इनकिलाब।

अध्यक्ष महोदय : ख्याल रखें कि दस मिनट के अन्दर अन्दर ही आपने अपने भाषण को समाप्त करना है।

श्री चान्द राम एहलावत : तो स्पीकर साहब, हम आज पंजाब के नये बजट पर बहस कर रहे हैं। मैं बड़ी खुशी से कहना चाहता हूं कि पिछला वर्ष अर्थात् सन् 1953 का साल हमारे पंजाब राज्य के इतिहास में कानूनी इनकिलाब के लिये हमेशा के लिये याद रखा जायेगा। इस साल हमने गरीब लोगों की भलाई के लिये बड़े अच्छे अच्छे कानून बनाये। शामिलात देह का कानून जो कि सरदार प्रताप सिंह जी ने इस हाऊस के सामने रखा, इस वर्ष पास किया गया जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। यह इनकिलाब ऐसा था जिसे सदियों तक आने वाली पुश्तें याद रखेंगी।

अध्यक्ष महोदय, इस देश में बहुत सी हकूमतें आईं—हिंदुओं की हुकूमत इस देश में आई, सिखों की आई, मुसलमानों की आई और आखिर में विदेशी हुकूमत ने—अंग्रेजों की हुकूमत ने—इस देश में शासन किया। लेकिन उन लोगों को जो कि सदियों से जमीनों पर झोंपड़ियां बना

कर रहते आए हैं, उस ज़मीन का मालिक बनाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया। इस कदम को उठाने का श्रेय केवल इस कांग्रेस हुकूमत को ही जाता है जो सदियों तक लोगों को याद रहेगा। इस के लिये इस सरकार को जितनी भी मुबारकाबाद दी जाये थोड़ी है।

इस के अतिरिक्त इस वर्ष सरकार ने प्रशासन का विकेंद्रीकरण और गरीब तबके के सरकारी कर्मचारियों को भी ऊपर उठाने के लिये कदम उठाये। नौकरियों में विशेष रियायतें दी, टैकनिकल और दूसरी प्रकार की शिक्षा के लिये लोगों को साधन उपलब्ध किये, ग्रामों में सही मानों में पंचायती राज स्थापित किया तथा इन पंचायतों में हरिजनों के लिये विशेषकर जगहें सुरक्षित थीं। इस के इलावा, जो दूसरे तरीके उन के लिये उत्थान के लिये प्रयोग में लाये वह यह सर्वथा सराहनीय है और इस बात के सूचक हैं कि हमारी हुकूमत पिछड़े हुए तबकों के उत्थान के लिये कितनी जागरूक है।

लेकिन, स्पीकर साहिब, मैं कहना चाहता हूं कि इतना ही काफी नहीं। डाक्टर मार्शल जो कि बीसवीं शताब्दी के एक बड़े भारी economist हैं, लिखा है कि "Poverty is the greatest degradation of mankind" अर्थात् गरीबी इनसानियत का खात्मा कर देती है। हमारे गवर्नर महोदय ने भी अपने भाषण में कहा था कि "Slavery—Mental, Social and Political—creates among other things, proverty, and poverty again, leads to some kind of slavery" अर्थात मानसिक, सामाजिक तथा राजनैतिक दासता अन्य कई परिणामों के अतिरिक्त निर्धनता पैदा करती है और निर्धनता पुन: किसी प्रकार की दासता की ओर ले जाती है। जो हमारे गवर्नर महोदय ने कहा है वह इस बात का प्रतीक है कि हमारी गवर्नमैण्ट अज़ख़ुद इस बात के लिये सोचती है कि उन सामाजिक तबकों को जो काफी देर से पददलित और गुलाम रहे हैं, ऊपर उठाया जाये—उन का उद्धार किया जाये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक सामाजिक गुलामी बनी रहेगी गरीबी हमारे देश से दूर नहीं हो सकती। जब ऐसा होगा तो देश में शान्ति कायम नहीं रह सकेगी क्योंकि गरीबी कई प्रकार के भयंकर परिणामों को पैदा करती है। (घंटी बजती है)

हमारे देश में untouchability भी एक ऐसी ही बला है। अछूतपन गुलामी से भी नाकस और बदतर वबा है। यह अछूतपन भी सदियों की गुलामी का ही नतीजा है। हमारी समाज में जो निचले दर्जे के तबके थे—हरिजन और जिन्हें लोग कम्मी कहा करते थे—उन को किसी वक्त ऐसे पेशे इख्तियार करने पर मजबूर किया गया कि जिन से आज वे अछूत कहलाते हैं। वे पेशे ऐसे हैं जिन्हें कि दूसरे तबकों के लोग घृणित समझते हैं। यद्यपि हमारी सरकार ने काफ़ी मात्रा में इस दिशा में भी सुधार किया है किंतु मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हरिजनों और इस प्रकार के दूसरे भाइयों को इन पेशों से राहत नहीं दिलाई जाती, हिंदुस्तान की तरक्की के रास्ते में यह एक बड़ी ज़बरदस्त बाधा बनी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर। एक तो आप कागज़ से पढ़ रहे हैं और दूसरे घंटी की आवाज़ को भी नहीं सुनते। यह क्या बात है? कृपा करके पांच मिंट के अन्दर अन्दर अपनी तकरीर खत्म करें। आप का समय खत्म होने वाला है।

श्री चांद राम एहलावत : क्षमा कीजिये, स्पीकर साहब, मैं पढ़ तो नहीं रहा। मैं यह अर्ज कर रहा था कि अगर ऐसी अवस्था हो तो हमें मानना पड़ेगा कि—'Desperate diseases require desperate remedies' जब बिमारियां ऐसी खतरनाक हों तो उन के इलाज की जल्द जरूरत होती है। इस लिये हमारी गवर्नमेंट को ज़रूर जल्दी ऐसे कदम उठाने चाहियें जिन से इस बिमारी का इलाज हो सके। इस लिये मैं कहता हूं कि उन को शिक्षा देने के लिये केवल ८ लाख रुपया, काफी नहीं है। उन्हें घरेलू दस्तकारियां सिखलाने के लिये ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जायें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी तकरीर समाप्त करता हूं। और अन्त में मैं यह फिर कह देना चाहता हूं कि इस बजट में काफी इनकिलाब की बातें आई हैं और मैं समझता हूं कि आगे और भी इस तरफ ध्यान दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरी गुज़ारिश यह है कि आप साहिबान इस बात का कोई हल निकालने में मेरी मदद करें कि वक्त तो है बहुत महदूद और तकरीरें करने वालों की तादाद है बहुत ज्यादा। केवल Opposition वालों ने दस नाम दिये हैं आप खुश नसीबी कहिये या बदनसीबी, उन में प्रोफैसर मोता सिंह का नाम नहीं है। गवर्नमैंट की जानिब से भी कुछ नाम दिये जायेंगे। इस के इलावा बहुत से साहिबान ने तो, यूं कहिये कि कल से ही अपना वक्त लिया हुआ है। अब मेरी बड़ी मुश्किल यह है कि अगर किसी मेम्बर साहिब से यह कहा जाता है कि उन का वक्त खतम हो गया है तो वह बिगड़ जाते हैं। आखिर में बहस तो चीफ़ मनिस्टर साहिब की स्पीच पर खत्म होनी है और मैं समझता हूं कि Irrigation Minister साहिब भी काफी वक्त लेकर आप के एतराजात का जवाब देंगे। इस मुश्किल के दो ही हल हो सकते हैं। या तो मेम्बर साहिबान अपनी speeches करने में बहुत थोड़ा लें या बोलने वालों की तादाद कम की जाये। Unfortunately घड़ी की सूइयां तो मैं रोक नहीं सकता।

मुख्य मंत्री : यह आप की बड़ी मेहरबानी है कि आप मैम्बरान के जज़बात का इतना ख्याल रखते हैं। आपने अपनी तशवीश को कम करने के लिये हाऊस को मुखातिब किया है इस लिये मैं यह तजवीज़ पेश करता हूं और वह यह है कि आप यह procedure इख्तयार करें कि जो नाम अपनी तरफ़ के मैम्बरान में से मैं आप की सेवा में पेश करूं तो आप वही नाम बोलें उन के इलावा और किसी को बोलने न दिया जाये। इसी तरह जो नाम Oppositions की तरफ से आयें केवल उन्हीं को बोलने दिया जाये। हर जगह यही तरीका होता है कि parties अपनी तरफ से बोलने वालों के नाम खुद मुनतखिब करके स्पीकर साहिब को भेज देती हैं। अगर इस तरह से यहां भी कर दिया गया तो जनाब को तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस लिये जहां तक मेरी पार्टी का ताल्लुक है आप को मेरी तरफ से नाम आयेंगे और आप उन नामों के सिवाय और किसी को बोलने की इजाज़त न दें।

अध्यक्ष महोदय : चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने यह जिम्मेदारी फिर मेरे पर डाल दी है कि मैं उन मैम्बरान को न बोलने दूं जिन के नाम उन की पार्टी के लीडर की तरफ से नहीं भेजे जाते। यह बेहतर होगा कि वह ही अपनी पार्टी के मैम्बरान को समझा दें कि वह बोलने के

लिये न तो मेरे पास चिटें भेजें न ही खड़े होने की कोशिश करें। मैं अपनी आंखें बन्द कर के नहीं रख सकता जब कि Principal Rala Ram जैसे माननीय मैम्बर बोलने के लिये खड़े हों। पहले Opposition दल की तरफ से दस नाम आये हुए हैं और अब प्रोफैसर मोता सिंह ने भी अपने नाम की पर्ची भेज दी है। जैसे कि चीफ़ मिनिस्टर साहिब ने मेरी मदद के लिये तकलीफ़ फरमाई है इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि Opposition वाले भी उस मसले को हल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे।

मुख्य मंत्री : जनाब ने यह जो सवाल किया है जहां तक मैं इसे समझता हूं वह है कि जो recognised Opposition हो पहले आप उन को देखें और बाद में जो Un-official opposition या दूसरे ग्रुप हैं उन को बोलने का मौका दें। हमारी तरफ से Irrigation Minister साहिब बोलेंगे। और debate का जवाब हमारे वित्त मंत्री जी देंगे।

ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੀ list ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਨਾਮ order ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਬੋਲਣਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

अध्यक्ष महोदय : अगर Opposition के १२ मैम्बरों को पन्दरह पन्दरह मिनट तकरीर करने के लिये दिये जायें तो तीन घंटे केवल उन्हें चाहियें। और वज़ीर साहिबान.........

मुख्य मंत्री : हमारे सिंचाई मंत्री सिर्फ आधे घंटे के लिये बोलेंगे और डेढ़ घंटा हमारे वित्त मंत्री बोलेंगे क्योंकि debate का जवाब उन्हों ने ही देना है और जो कुछ point मेरे मुतअल्लिक रह जायेंगे मैं General Administration की discussion के जवाब में उन के बारे में भी अर्ज़ कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इस का मतलब यह हुआ कि बाकी बहस के लिये हमारे पास 2½ घंटे हैं। अच्छा तो अब सरदार अच्छर सिंह अपनी तकरीर फरमाएं।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ : (ਅਜਨਾਲਾ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇਕ Development State ਦਾ ਬਜਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ phrasography ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ Social State ਦਾ ਬਜਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ bankrupt State ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕ Development State ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ un-employment is on the increase। ਹੋਰ ਇਹ plans ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਲ ਹੀ un-employment ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ analogy ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ students ਦੀ un-employment ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦੱਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ un-employment ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Single Teacher ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ un-employment ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰੀ ਨੂੰ

[ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੇਕਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲੀਮ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਕਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਨ ਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਮਾਹਿਨਿਆਂ ਵਿਚ educated ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਭ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹਨ education ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ, ਪਹਿਲੀ ਨਸਲ ਦੀ technique ਅਤੇ cultural ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ literate ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ educated ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ।

ਫਿਰ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਜਗਹ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲ ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ Inter-provincial language ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਖਾਂ ਨੇ ਥੋਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ lino type ਮਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, technical education ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ cultural education ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰਾਂਤ social services ਮਸਲਨ history ਆਦਿ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਵੋ। History ਵਿਚ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਰਜ ਚਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ education ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਫੀ ਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 12·8 ਫੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ। ਹੁਣ ਇਹ revenue ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਹਨ ਤਾਂ teacher ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ teacher ਹਨ ਤਾਂ furniture ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ relief ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲ ਰੁਖ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ।

Nationalisation of Books ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ quality ਭੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਭੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ economy industrial ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਕ agricultural economy ਹੋਵੇ ਉਥੇ nationalisation of Text Books ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ heavy industry ਦੀ nationalisation ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ nationalisation ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ Text Books ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ authors ਦੀ monoply ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਇਕ monoply ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ Transport Nationalisation ਹੈ। ਅਸੀਂ nationalisation ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਬਰ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ co-opertive basis ਤੇ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Encourage ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (interruptions)। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਓਮਨੀ ਬਸਾਂ (Omni Buses) ਚਲਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੜ 2 ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਟ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਣੀ ਬਸਾਂ ਚਲਾਵੇ। ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ Nationalisation ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਟ (route) ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਮਿਲ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ nationalise ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ foreign capital ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Transport ਨੂੰ nationalise ਕਰਨ ਤੇ ਬਜ਼ਿਦ ਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿਉ। 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਟ੍ਰਕ ਦੇ ਰੂਟ ਦਾ 2,000 ਰੁਪਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੀ ਉਥੇ ਬਸ ਦੇ ਰੂਟ ਲਈ 500 ਰੁਪਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੁਝ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਸ ਲਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਲਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਉ ਅਤੇ evaluate ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਉ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਉ। ਆਪ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨਡਕਟਰ matric ਪਾਸ ਰਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ, 10, 10 ਅਤੇ 12, 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਨਡਕਟਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

[ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ border area ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਰਬ ਡਿੰਡੀ, ਉਲਕ, ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡ ਜੰਗਲ ਅਤੇ undeveloped area ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਥੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਟੀ ਪਰਾਜੈਕਟ (Community Project) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਸੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨਟੀ ਪਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ extension ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਉ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਏਪਨ ਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਲੋਡ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੋਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ Ways and Means ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ Special Committee for Utilization of Electric Power ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਉਸ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "you should develop cement, aluminium and chemical industries to utilise Electric Power."

ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਇਨਜੀਨੀਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸ ਦਿਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ observer ਹਨ ਉਹ neutral ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਇਨਜੀਨੀਅਰ ਵੀ neutral ਨਹੀਂ ਹਨ।

श्री राम किशन (जालन्धर शहर, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र) : स्पीकर साहिब ! मैं फाइनेंस मिनिस्टर (Finance Minister) साहिब को उन के Development Budget और Progressive Budget पर मुबारिकबाद देने के लिये खड़ा हुआ हूं। कल भी और आज भी मैंने अपने दोस्तों और Opposition के मेम्बरों से इस बजट के मुतअल्लिक कई एक तकरीरें सुनी हैं। उन्हों ने अपनी तकरीरों में ऐसे नक्शे खींचे हैं कि जिन से पता चलता है कि पंजाब में हालात बहुत खराब हैं। हर तरफ तबाही हो रही है और बरबादी आ रही है। इस बजट से पंजाब का किसी हालत में भी भला न होगा। स्पीकर साहिब ! मैं आप की वसातत से Leader of the Opposition से कहना चाहता हूं कि पिछले छः साल में जो बजट पंजाब में पेश हुए हैं उन को मद्देनजर रखते हुए किस को मालूम नहीं कि पंजाब में कितनी तरक्की हुई है। Partition के यानी 15 अगस्त 1947 के बाद जब इस पंजाब में पहला बजट पेश हुआ तो उस समय पंजाब के फाइनेंसिज़ (Finances) की क्या हालत थी ? इस पहले बजट में जब ये पेश किया गया तो कुल Revenue 11 करोड़ 28 लाख था। और 1952-53 में यह Revenue 18 करोड़ हो गया। मगर आज 6 साल बाद जो बजट पेश किया गया है इस में सरकार

पहुंचा है। तनखाहदार और दूसरे लोगों को फायदा हुआ है। और आज यह Revenue 22 करोड़ या 22½ करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। अगर इन 6 सालों में पंजाब सरकार के Revenue में 17 करोड़ का इजाफा हुआ है तो मैं पूछता हूं, स्पीकर साहिब, कि क्या मेरे दोस्त मुझे यह बतायेंगे कि यह पंजाब राज्य की तरक्की हुई है या इस से राज्य बरबाद हो गया है ? लोगों को अच्छी तरह पता है कि हमें कैसा पंजाब मिला था। इस की हालत 15 अगस्त 1947 को क्या थी ? Wheat के इलाके पाकिस्तान में रह गये। Rice, cane और दूसरे food-grains पैदा करने वाली ज़मीनें पश्चिमी पंजाब में रह गईं। जहां तक cotton का ताल्लुक है यह सारी की सारी undivided पंजाब मुहैया करता था। उस वक्त हालत यह थी कि यह सारा इलाका हम से छिन गया था मगर अब पंजाब की हालत और है। Wheat, rice, cane, food-grain की पैदावार बहुत बढ़ गई है। हर तरह के control उड़ा दिये गये हैं। Food grains न सिर्फ हमारे लिये ही काफी है बल्कि दूसरी स्टेटों को भी भेजे जाते हैं। स्पीकर साहिब ! फिर यह कहा गया है कि बार्डर पर न बिजली का और न ही पानी का इन्तज़ाम है। पंजाब सरकार ने border पर ऐसा इंतजाम नहीं किया है। यह ठीक है कि वहां पर न पानी है न बिजली। पर क्या मैं पूछ सकता हूं कि कपास के लिहाज़ से वहां की हालत क्या है ? बार्डर के इलाके में फिरोज़पुर और फाज़िलका cotton के यानी अमरीकन स्टेपल के point of view से कहां पर खड़ा है ? स्पीकर साहिब मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि इन बातों से साफ पता चलता है कि बार्डर पर आला किस्म की काटन होती है मगर Leader of the Opposition ने बजट की technicalities में जाने की कोशिश नहीं की। वह भूल गये हैं कि उस में facts and figures भी दिऐ गये हैं जिन की स्टडी (study) ज़रूरी है।

फिर लीडर ओफ दी अप्पोज़ीशन (Leader of the Opposition) ने टीचरों की बुरी हालत का जिक्र किया है। उन्हों ने कहा है कि टीचरों की बुरी हालत है। इन की तनखाहें कम हैं। मगर वह facts and figures को भूल गए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में पंजाब ही एक ऐसी स्टेट है जहां पर टीचरों को कम से कम तनखाहें दी जा रही हैं। लेकिन अमरेवाक्या यह है कि अगर आप 26 स्टेटों के आदादोशुमार देखें जिन में पार्ट बी (Part B States) स्टेट भी शामिल हैं मगर पार्ट 'सी' की 2,3 स्टेटें शामिल नहीं की गईं तो उन्हें देखने से आप को मालूम होगा कि आसाम, उत्तर प्रदेश, बम्बई, उड़ीसा, बंगाल से लेकर मद्रास तक सब स्टेटों में टीचरों को 16 रु. से 3,2 और 35 रु. तक तनखाहें मिल रही हैं। मगर यहां पंजाब की हालत यह है कि यहां पर एक बेसिक टीचर को भी 47 रु० माहवार तनखाह मिलती है और 30 रु. मासिक अलाऊंस मिलता है। यह ऐसे facts and figures हैं जिन को कोई चैलेंज challenge नहीं कर सकता। और इन की दूसरी स्टेटों के मुकाबले की लिहाज पर भी चैलेंज नहीं किया जा

[श्री राम किशन]

स्पीकरसाहिब ! मेरे दोस्तों ने U.S.A., U.S.S.R. और England के हवाले दिये हैं। मगर इन्हें मालूम नहीं कि हमारे देश की हालत क्या है। U.S.S.R के मुकाबले में पंजाब की हालत क्या है ? दूसरे मुल्कों का हवाला तब दिया जाये जब वहां की और यहां की आमदनी बराबर हो। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक आदमी की जितनी आमदनी है अमरीका में एक आदमी की आमदन इस से बहुत ज्यादा है। इस देश की आमदनी को दुगुना करने के लिये पूंजी को चार गुना बढ़ाना होगा। फिर इस के लिये देश की सरकार और सूबे की सरकार कोशिश करती है।

स्पीकर साहिब ! देश की पूंजी को बढ़ाने के लिये ही Developement की स्कीमें बनाई जा रही हैं। इस बात का पता एक ही बात से चल सकता है। दूर जाने की जरूरत नहीं। 1949-50, 1950-51 और इस तरह 1953 तक सारे पंजाब राज्य में किसानों ने फ़सलों से कितना रुपया कमाया है ? अगर आप इस का अंदाजा लगायें तो आप को पता चलेगा कि इन्होंने पूंजी के बढ़ाने में कहां तक काम किया है। जब हम 1949-50 की रिपोर्ट देखते हैं तो हमें पता लगता है कि सारे देश में और सारे पंजाब राज्य में किसानों ने कितनी तेजी से काम किया है। 1949 से लेकर 1953 तक 1 करोड़ 26 लाख रुपया किसानों ने कमाया है। पिछले एक साल के अन्दर इस तरफ 26 करोड़ का इज़ाफा हुआ है। और यह 26 करोड़ रुपया पंजाब के किसानों के पास ही है। अब आप ही बतायें कि कपास और wheat के सम्बन्ध में किसानों ने स्टेट में कहां तक तरक्की की है।

फिर स्पीकर साहिब ! भाखड़ा के मुतअल्लिक कहा गया है कि भाखड़े के सम्बन्ध में जो loan लिया जा रहा है उस की वजह से पंजाब स्टेट को रहन रखा जा रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब रेलवे का system शुरु हुआ था तो वह loan से ही शुरु हुआ था। Loans लिये बिना कोई भी ऐसी स्कीम नहीं चलाई जा सकती और यह तो फिर productive loan है। इस के सामने उस मुनाफे को भी देखना है जो स्टेट को इन स्कीमों के पूरा होने पर होगा और अब भी हो रहा है।

स्पीकर साहिब ! मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह कहा गया है कि जालन्धर के इलाके में एक छोटी सी नहर आ रही है और इस पर 3 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। इस के मुकाबले में 18 लाख रु. Water charges लिये जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 18 लाख Water charges वसूल कर के स्टेट की 1 करोड़ रुपये की आमदनी बढ़ाई जा रही है। और इस बढ़ोतरी से किसानों को और सहूलतें दी जा रही हैं। अब मैं यह पूछता हूं कि यह सब स्कीमें और facts and figures क्या हमें आगे ले जाने वाले हैं या पीछे ? क्या इस से किसानों को फायदा नहीं हो रहा ?

फिर मेरे एक दोस्त ने अमरीका के Now York Herald Tribune का हवाला दिया है। इस अखबार ने उस action के खिलाफ protest किया है जो कि पंजाब सरकार ने Leader of the Opposition को इस बात पर गिरफ्तार करने के लिये कि उन्होंने एक अखबार के एडीटर होने की हैसीयत में अपने अखबार में Objectionable Articles छापे हैं।

यह वही New York Herald Tribune है जिस ने हिंदुस्तान के खिलाफ प्रचार किया है और हमारे बड़े लीडर पंडित जवाहर लाल नेहरू की पालिसी के खिलाफ लोगों को भड़काया है। यहां पर ही बस नहीं इस अखबार ने पिछले तीन महीने से पैप्सू के लोगों को खूब उकसाया है। स्पीकर साहिब यही अखबार है जिस ने लिखा था कि पंडित जवाहर लाल नेहरू को जो एशिया का लीडर बना हुआ है पैप्सू के 40 लाख सिक्खों के लीडर ने चैलेंज (challenge) किया है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू की शेखी इस इलैक्शन (Election) में किरकिरी हो जायगी। अब उस चैलेंज (challenge) का नतीजा आप सब के सामने है। आप ही बतायें कि शेखी किस की किरकिरी हुई है। ऐसा करना अच्छा नहीं लगता और ऐसे अखबार की हिमायत की कोई वुकअत नहीं होती।

फिर स्पीकर साहिब कल यहां Rape of Rawalpindi के हवाले दिये गये इस बारे में मैं आप की विसातत से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब सर ज़फरुल्ला खां ने U.N.O. में Genocide in India पेश कर के अमरीका और सारी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान को बदनाम किया उस वक्त किसी को ऐसे हवाले देने की न सूझी लेकिन जब मुस्लिम लीग की बुराइयां और खराबियों का ज़िक्र हुआ तो यहां हवाले दिये जाने लगे।

फिर बड़े ज़ोर शोर से कहा गया है कि पांच साला प्लैन (Five-Year Plan) फ़ेल हो गया है। बेशक यह प्लैन फ़ेल हो गया है क्योंकि 72,00,00,000 की inflated currency कम कर दी गयी है (*hear, hear*) दूसरी निशानी इस के फेल होने की यह है कि जितना कपड़ा हम को पहले बाहर से मंगाना पड़ रहा था वह सारी ज़रूरत पूरी कर के हम ने 7 अर्ब का कपड़ा बाहर भेजा है। फिर Foodgrains और Agriculture के बारे में देखिये पहले हम को 5,47,00,00,000 रुपये का अनाज बाहर से मंगाना पड़ता था अब आइंदा एक पैसे का भी नहीं मंगाया जायगा (*hear, hear*) यह भी प्लैन के फेल हो जाने का सबूत है। इस के बाद यह कहा गया है कि लोगों की purchasing power कम हो गई है। बेशक यह कम हो गई है। पिछले दो तीन साल के एदादो शुमार को देखें। सीमेंट, कोइले कपड़े की खपत पहले से दुगनी हो गई है। यह सब कौन ले गया? क्या यह सब कुछ अमीरों ने खरीद लिया? यह आम लोगों ने खरीदा इस लिये यह कहना ग़लत है कि जनता की purchasing power कम हो गई है।

इस के बाद बेकारी के बढ़ने का बार बार ज़िक्र किया गया है। कौन नहीं जानता कि बेकारी बहुत है? मगर क्या यह सिर्फ नुकता चीनी और तकरीरों से खत्म हो जायगी। और फिर पांच छः साल की मुदत ही क्या होती है। बेकारी का रोना रोने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि वह ज़रा रूस की 1947 से 1933 की रिपोर्ट पढ़ें तो उन को मालूम होगा कि सन् 1933 में जब उन की हकूमत को काम करते 17 साल हो चुके थे तो वहां 4,33,000 लोग registered बेकार थे। यहां तो अभी छः सात साल ही हुए हैं। फिर भी Cottage Industries और दूसरी स्कीमों से बेकारी को घटाने और दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। स्पीकर साहिब मैं आप की विसातत से अपने दोस्तों से अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारी State एक सीमा प्रान्त है। हमारे लिये ज़रूरी है कि इस Border State के राज्य को इस तरह चलायें कि लोगों का रहन सहन ऊंचा हो। इस के लिये हमें

[श्री राम किशन]

किसानों की पैदावार बढ़ाना जरूरी है और इस काम के लिये हम उन को बिजली दे रहे हैं ताकि उन की पैदावार बढ़े और standard of living ऊंचा हो। आप देखते हैं कि Development की स्कीमों पर जहां पहले 8,53,00,000 खर्च होता था अब यह रकम 15 करोड़ 4 लाख तक पहुंच गई है (*hear, hear*) अंग्रेज के वक्त में जहां सिर्फ 5 फ़ी सदी पानी exploit किया जाता था अब हम 45 फी सदी पानी exploit कर के लोगों को खुशहाल बना रहे हैं। लेकिन सावन के अंधों को यह सब कुछ नज़र न आये तो मैं क्या कर सकता हूं।

स्पीकर साहिब ! कल Opposition के लीडर ने हरिजनों का हवाला दिया था कि यह कांग्रेस सरकार उन के लिये क्या कर सकती है जिस ने मुलाजमतों और सीटों वगैरा में उन के लिये सिर्फ 10 साल के लिये reservation रखी है। मैं उन को बताना चाहता हूं कि यह कांग्रेस सरकार का कसूर नहीं इतनी कम मुद्दत के लिये reservation डाक्टर अम्बेदकर ने रखी थी जो हिंदुस्तान भर में कांग्रेस के सब से बड़े दुशमन हैं। सरदार पटेल और दूसरे कांग्रेसी लीडर ज्यादा मुद्दत के लिये यह reservation रखना चाहते थे मगर डाक्टर अम्बेदकर जो Drafting Committee के प्रधान थे यह कहा कि हम हमेशा के लिये अछूत नहीं बने रहना चाहते इस लिये reservation की मुद्दत कम रखी जाये।

अब एक और बात पर भी उन की तवज्जुह दिला दूं, 1939-40 में जब Opposition के लीडर साहिब Parliamentary Secretary थे तो opposition की तरफ से Land Alienation Act तालीम और हरिजनों की दूसरी जरूरतों और मुशिकलात के बारे में तजवीजें पेश की गईं इन्होंने Unionist Ministry के Parliamentary Secretary की हैसीयत से जवाब दिया था कि पंजाब के Finances इस की इजाज़त नहीं देते। मगर अब आप को उन के welfare की सूझ आ रही है। मैं उन से अर्ज़ करता हूं कि सरकार पर नुक्ताचीनी बेशक करें मगर वह healthy criticism होना चाहिये। हम सब का फर्ज़ है कि पंजाब को हर तरह आगे बढ़ायें। पिछले तीन चार साल में यह काफी आगे बढ़ गया है और अब हम यह चाहते हैं कि यह एक ऐसा admistrative unit बन जाये कि सारा मुल्क हैरान रह जाये (*hear, hear*)।

Opposition के लीडर साहिब ने यह भी कहा है कि पुलिस बहुत ज्यादा है, इस में कमी होनी चाहिये। वह भूल गये कि इस वक्त International हालात क्या हैं और बार्डर की दूसरी तरफ क्या हो रहा है। मैं उन से अर्ज़ करता हूं और वज़ारत से भी कहता हूं कि जो International हालात हमारे सामने हैं जिस तरह Communalism और Violence का प्रचार हो रहा है उन को देखते हुए पुलिस में बिल्कुल कमी नहीं की जा सकती। इस के अलावा कुछ forces ऐसी भी हैं जो इस बात का challenge दे रही हैं कि हम Constitutional हकूमत न चलने देंगे। इन के इरादे नेक हैं या बद यह बात आप खुद समझ सकते हैं।

Opposition के लीडर ने पुलिस के बारे में England के भी हवाले दिये। मैं उन को बताना चाहता हूं कि वहां 457 आदमियों के पीछे एक पुलिस का आदमी और हमारे हां 927 के पीछे एक है। इस के अलावा अगर वह (England) के साथ चलना चाहते हैं तो बाकी बातों में भी उन के तरीके पर उन्हें चलना होगा। वहां सरकार पर खाह मखाह नुक्ताचीनी नहीं की जाती। अच्छे काम की सराहना भी की जाती है और जहां नुक्ताचीनी की जरूरत हो वहां healthy नुक्ताचीनी की जाती है।

स्पीकर साहिब ! यदि हमने अपने देश को उस हद तक ले जाना है तो हमें अपनी पूंजी को बढ़ाना होगा और तब वैसे काम चल सकेगा। मैं आप की विसातत से अपने मित्रों को बताना चाहता हू कि तालीम, सिहत Agriculture और सनअत के लिहाज से पंजाब के राज ने तरक्की की है। मैं मानता हूं कि इस राज में कुछ खामियां भी हैं परन्तु वे इस तरह दूर नहीं की जा सकतीं जैसा कि हमारे मित्र चाहते हैं। इन खामियों को दूर करने के लिये सरकार पंजाब के हर आदमी को welcome करती है कि नुक्ताचीनी करे और अपनी राय दे। लेकिन इस बात की कोई आज्ञा नहीं दे सकता कि कोई बने बनाये महल या building को गिरा दे। हां यदि इस महल को ज्यादा खूबसूरत बनाना है तो बड़े शौक से आगे आये।

कल सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत और श्री मनी राम जी ने कहा कि मुजारों को eject किया जा रहा है लेकिन इस सम्बन्ध में सरकार ने कुछ नहीं किया है। उन के विचारानुसार सरकार केवल कहती है कि इसने मुजारों को बसा दिया है परन्तु कुछ करती नहीं। कहा गया कि हिन्द सरकार ने एक किताब छापी है जिस में इस बारे में पंजाब सरकार को बहुत झाड़ दी गई है। मैंने खुद इस किताब को पढ़ा है और पंजाब के chapter को खास ध्यान से पढ़ा है। इस में झाड़ की बजाये पंजाब सरकार की तारीफ़ की गई है। इस में लिखा है कि peasant proprietorship अर्थात् छोटे किसानों के मसले को हल करने के लिये इस सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। मालूम होता है कि मेरे मित्रों ने ग़लत नुकताचीनी करने का ठेका ले रखा है। वे शायद समझते हैं कि यह किताब किसी ने पढ़ी नहीं हमारा पंजाब छोटे छोटे जमींदारों का देश है यहां कुल land owners 2,675,300 है जिन में 2,004,371 यानी 80 प्रतिशत वे है जो 15 एकड़ तक के मालिक हैं। 100 एकड़ से ज्यादा के मालिक कुल· 45 प्रतिशत है। यह ठीक है कि पंजाब में ejectment के notices दिये गये है। लेकिन ejectment कोई नहीं हुई। स्पीकर साहिब, मैं अपने मित्रों से पूछता हूं कि क्या वह यह चाहते हैं कि इस मसले को violence से हल किया जाये। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने non-violent revolution से स्वराज हासिल किया था और आगे भी अपने सब मसलों को non-violent तरीकों से हल करेंगे। मैं सरदार प्रताप सिंह जी को इस बात के लिये मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने किसानों के मसले को हल करने की दिल से कोशिश की है (*Cheers*)। मैं पूछता हूं कि आखिर Communists ने अकालियों ने और प्रजा सोशलिस्टों अपनी तकरीरों से कितने मुजारे बहाल कर दिखाये हैं। परन्तु कौन नहीं जनता कि पिछले तीन साल में सरदार प्रताप सिंह जी ने हजारों Tenants का मसला हल कर दिया है। मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि वे कुछ ठोस काम करें। यदि उन के दिल में मुजारों के लिये सचमुच

[श्री राम किशन]

दर्द है यदि उन के दिल में small proprietors की बेहतरी के लिये तड़प है तो वे इस मसले के हल करने में मदद दें। पंजाब का मसला बड़े ज़मींदारों का मसला नहीं बल्कि small peasants का मसला है।

स्पीकर साहिब! एक और बात जो मैं आप की विसातत से कहना चाहता हूं वे यह है कि मेरे दोस्त कहते हैं कि पंजाब में हज़ारों मज़दूर बेकार हो गये हैं। मैं अपने दोस्तों को दावत देता हूं कि यदि उन के दिल में मज़दूरों के लिये सच्चा दर्द है तो वे इतनी देर कोई strike न होने दें जब तक कि हमारा Five-Year Plan चल रहा है। मैं समझता हूं कि हमारा Five-Year Plan देश को आगे ले जाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। कल मेरे मित्र सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत जी ने कहा था कि अमृतसर में मज़दूर ५ पैसे रोज़ लेने के लिये फिर रहे हैं।

श्री वधावा राम : उन्होंने ऐसा नहीं कहा था।

अध्यक्ष महोदय : हां यह ठीक है, इन्होंने यह नहीं कहा था।

श्री राम किशन : स्पीकर साहिब! मैं आप की विसातत से कहना चाहता हूं कि पंजाब के लोगों ने, पंजाब के बहादुर किसानों ने, पंजाब के दूकानदारों ने अपना सहयोग दे कर इस नये पंजाब को, इस उजड़े हुए पंजाब को फलदार और खुशहाल बनाने के लिये शानदार part अदा किया है। आज cotton के लिहाज़ से हम हिंदुस्तान भर में तीसरे या चौथे दर्जे पर है। Sugarcane में तीसरे दर्जे पर। जहां तक wheat का सवाल है हम सारे हिंदुस्तान की granary बनने वाले हैं।

स्पीकर साहिब,! यह बजट जो सरदार उज्जल सिंह जी Finance Minister ने पेश किया है इस में कई तरह की Development Schemes की तरफ इशारा किया गया है। Low-paid staff और teachers की तनखाहें बढ़ाई गई हैं और इस काम के लिये मैं सरदार साहिब को मुबारक बाद पेश करता हूं।

एक बात मैं ने Transport की nationalization के बारे में कहनी है। जब मद्रास में बजट पेश हुआ था तो वहां की Communist Party ने कहा कि Transport को nationalize क्यों नहीं किया जाता। लेकिन यहां की Communist Party का काम कुछ उलटा सा हो रहा है। मैं अपने मित्रों से दरखास्त करता हूं कि यदि वे चाहते हैं कि यह सूबा आगे बढ़े तो वे हमारी सरकार का हाथ बटायें।

स्पीकर साहिब एक चीज़ मैंने अपनी Ministry से अपनी constituency के बारे में कहनी है। मैंने Budget को अच्छी तरह से देखा है और Public Health Department के बजट को खास तौर पर पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : अब अपना भाषण खत्म कीजिये।

श्री राम किशन : केवल एक बात कहनी है और इस पर अमल करने से सरकार का कोई पैसा न लगेगा। मेरी प्रार्थना है कि जालन्धर सिटी सारे पंजाब में एक Semi-capital City है। यह बहुत important city है और इस की आबादी लगातार बढ़ रही है। पिछले चार साल से Municipal Committee Water Works के

लिये बार बार चीख रही हैं । Municipal Committee ने एक लाख रुपया Public Health Department को जमा करके दिया है । लेकिन इस के बावजूद Water Works का मसला हल होने में नहीं आता । मेरी प्रार्थना है कि हमारी इस demand को जल्द से जल्द पूरा किया जाये । इन लफ़्ज़ों के साथ में Finance Minister साहिब को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूं ।

श्री केदार नाथ सहगल (बल्लभगढ़) : स्पीकर साहिब ! मैं आप की इजाज़त से माननीय वित्त मंत्री, सरदार उज्जल सिंह को मुबारकबाद देने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि उन के बजट की जो कापियां हैं वह बहुत नफ़ीस तरीके से छापी गयी हैं । और उन का get-up बहुत अच्छा है । साथ ही में यह कहना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री ने 48 के करीब किताबें छापी हैं वह बेहद गलतियों से पुर हैं लेकिन बजट में कम से कम अलफ़ाज़ी ग़लतियां नहीं हैं इस लिये मैं माननीय वित्त मंत्री को मुबारकबाद पेश करता हूं । मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि अगर कोई item देखनी मतलूब हो तो बजट का एक एक सफ़ा उलट कर देखें तो बड़ी मुश्किल से मिलती है । इस लिये क्या ही अच्छा होता कि हर item elphabetical तौर पर बजट में दर्ज की जाती । ऐसा करने से उन्हें ढूंढने में आसानी हो सकती थी और ऐसा हो जाने पर फिर हम हर साल उनके बजट की तारीफ किया करेंगे । और उन्हें मुबारकबाद देंगे । अब मैं Public Relations Department (जन सम्पर्क विभाग) के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इस विभाग पर हर साल लाखों रुपया खर्च किया जाता है और इस का काम गवर्नमेंट की publicity (प्रचार) करना है । मैं कहूंगा कि यह विभाग इतना निकम्मा है कि इस को पता ही नहीं कि प्रचार कैसे किया जाता है इस का काम सिवाये मंत्रियों की फोटो उन रिसालों में छापने के जो पिछले दिनों छपते थे और कुछ नहीं था । इन रिसालों में कोई काम का मज़मून नहीं छपता था । इस सिलसिले में मुझे एक पुरानी बात याद आ गई है । लाहौर में एक 'हक' अखबार निकला करता था जो गवर्नमैण्ट का था । यह अखबार निहायत नफ़ीस काग़ज़ पर छापा जाता था और इस की लिखाई और छपवाई बहुत अच्छी हुआ करती थी । यह अखबार हज़ारों की तादाद में छपता था लेकिन इस के खरीददार बहुत कम होते थे । एक दफा का वकाया है कि एक दूकानदार 'हक' अखबार के दफ़तर में पहुंचा । पहिले वह इस अखबार की रद्दी अखबार बेचने वाले से लिया करता था । 'हक' अखबार के दफ़तर में पहुंच कर उस ने पूछा कि अखबार के सम्पादक (Editor) या मैनेजर कहां हैं ? उसें बतलाया गया है कि मैनेजर साहिब से मिल लीजियें क्योंकि उस का Editor (सम्पादक) एक अंग्रेज था । जब मैनेजर ने उस को देखा तो बहुत खुश हुआ कि शायद कोई खरीददार आया है । उस ने दूकानदार से पूछा कि क्या अखबार चाहते हैं तो उस ने जवाब दिया कि तीन मन अखबार मेरी दुकान पर भेज दो । मैनेजर के दर्यापत करने पर कि इतनी अखबारों की क्या ज़रूरत है दुकानदार ने जवाब दिया कि उस की दुकान में रद्दी के लिये चाहियें । इस लिये स्पीकर साहिब मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि यह Publicity Department के रिसाले रद्दी में बिकते हैं । अगर आप किसी वक्त जा कर इन के दफतर में देखें तो इन रिसालों के अम्बार लगे हुए आप को दिखाई देंगे । यह हमारे Publicity Department की हालत है । पिछले

[श्री केदार नाथ सहगल]

दिनों राजकुमारी अमृतकौर, स्वास्थ्य मंत्री. यहीं तशरीफ लाईं। उन के सत्कार में एक पार्टी दी गई जहां बिल्कुल कोई इन्तज़ाम नहीं था। जो प्रैस के रिपोर्टर थे वह वहां से walk-out कर गये। ग्राम तौर पर देखने में ग्राया है कि जहां भी कहीं सरकारी function होता है वहां कोई तसल्ली बख्श इन्तज़ाम नहीं होता, जिस का नतीजा यह होता है कि लोगों को वहां से मायूस होकर वापस ग्राना पड़ता है। ग्रगर वहां कोई ग्रच्छी तरह से बैठ सकता है तो वह होते हैं मिनिस्ट्री के henchmen। इस हालात में मैं समझता हूं कि गवर्नमैण्ट को चाहिये कि वह Public Relations Department को बन्द कर दें। ग्रगर सरकार इस महकमे को कायम रखना चाहती है तो उसे देखना चाहिये कि यह महकमा गवर्नमैण्ट के कामों का ग्रच्छी तरह प्रचार करता है। मैं समझता हूं कि सिवाए उन चन्द मैम्बरों के जो वज़ीर साहिबान के दायें बायें फिरते रहते हैं किसी को गवर्नमेंट की कार्रवाइयों का पता नहीं लगता। ग्रब मैं चंडीगढ़ कैपीटल के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। यह हमारे वज़ीर साहिबान ने भी कभी नहीं सोचा कि वह यहां क्या तरीके इख्तियार कर रहे हैं। ज़मीन के प्लाट बहुत ज्यादा कीमत पर बेच कर गवर्नमैण्ट 8 करोड़ रुपया इकट्ठा करने का इरादा रखती है जितने प्लाट ग्रभी तक बिके हैं उन में से मुश्किल से पांच छः ग्रादमियों ने ग्रपने मकान बनाने शुरु किये हैं। मैं समझता हूं कि बेशक रास कुमारी से ले कर बम्बई तक या कलकत्ते तक ग्राप चले जायें तो किसी जगह ज़मीन की कीमत इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी कि चंडीगढ़ में है। पिछले दिनों एक दुकान का प्लाट जो 8 फुट चौड़ा ग्रौर 10 फुट लम्बा था छ. हज़ार रुपये में बिका। इस हिसाब से एक गज़ की कीमत 500 रुपये बनती है। मैं कहता हूं कि क्या यह शहर बसाया जा रहा है या इसे तुग़लक ग्राबाद बनाना है? इस वक्त माननीय मुख्य मंत्री ग्रपनी जगह पर बैठे नहीं हैं नहीं तो मैं उन से पूछता कि जब डा. गोपी चंद भार्गव इस प्रान्त के मुख्य मंत्री थे तो वह कहा करते थे कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ बनानी चाहिये तो उस वक्त सच्चर साहिब सारे पंजाब में फिरे ग्रौर प्रापेगंडा किया कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ नहीं बननी चाहिये। जब यह खुद मुख्य मंत्री बने तो पता नहीं कि यह शहर कैसे ग्रच्छा हो गया। एक दफा कांगड़ा में भूचाल ग्राया। एक शख्स दफ़्तर में बैठा हुग्रा था कि दफ़्तर गिर पड़ा। वह मरने से बच गया क्योंकि वहां बड़ी बड़ी ग्रलमारियां थीं। उस ने चपड़ासी को ग्रावाज़ दी कि मैं मर जाऊंगा कोई जाकर तहसीलदार को इत्तलाह दे दे। उस ने कहा कि तहसीलदार नहीं हैं। फिर [illegible] ने कहा कि मुनसफी में जा कर इत्तलाह दे दी जाये तो उसे जवाब मिला कि मुनसफी भी गिर गई है। तो उस ने कहा कि किसी ग्रौर जगह जाये तो उसे मालूम हुग्रा कि सारा कांगड़ा ही गिर गया है। चंडीगढ़ में किसी मकान को देखो तो उस की छत में से पानी टपक रहा होता है। पिछले दिनों में मैं सैक्रेटरी साहिब को मिला तो उन्हों ने भी बताया कि उन के मकान का छत भी leak कर रहा है। इतने में रंधावा साहिब वहां ग्रा गये उन्होंने बताया कि उन की मोटर भी रास्ते के कीचड़ में फंस गई थी। जो ग्रादमी यहां मिलता है वही कहता है कि उस के मकान की छत से पानी टपक रहा है। इस की वजह यह हो सकती है कि या तो construction में नुक्स है या इस लिये कि मकान कच्चे बने हैं।

यह हालत है हमारे इस चंडीगढ़ की। शिमले में हमारे चीफ़ मिनिस्टर (Chief Minister) साहिब ने बड़े तमतराक से कहा था कि हम दरख़तों के नीचे इजलास लगायेंगे। मगर यहां आकर हुआ क्या है? 2½ लाख रुपये की कोठी चीफ मिनिस्टर साहिब ने ली है और जो कोठियां Ministers को दी गई हैं उन में से हरेक पर 80,000 रुपये खर्च आया है। क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब 2½ लाख रुपये का रुतबा रखते हैं जब कि बाकी मंत्रियों को 80,000 रु. की लागत वाली कोठियां दी गई हैं? आप यह चीफ़ मिनिस्टर हैं तो कल को चौधरी साहिब या सरदार साहिब चीफ़ मिनिस्टर बन सकते हैं। (*Laughter*)

Minister for Development : I have no such desire (*Laughter*)

श्री केदार नाथ सहगल : अब मैं कुछ पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं। अगर हम इस बजट के सारे औराक उलट जायें तो पुलिस का item इस में सब से लम्बा निकलता है। पुलिस का item कुल 3 करोड़ और चन्द लाख रुपये का है। वह महकमा हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहिब के पास है। मुझे तो यह महकमा पहलवानों का महकमा मालूम होता है। एक दफ़ा एक बरात ने किसी गांव में जाना था जहां उन्हें डाकुओं वग़ैरा का डर था। चुनांचि बरात वालों ने कुछ पहलवानों को कहला भेजा कि वे हमारे साथ चलें।

अध्यक्ष महोदय : अगर तकलीफ़ न हो तो mike में बोलिये क्योंकि मैं बहुत से अच्छे २ लफज़ नहीं सुन सका।

श्री केदार नाथ सहगल : मैं जनाब कुछ बीमार हूं इसलिये ज्यादा नहीं बोल सकता। मैं कह रहा था कि बरात वालों ने पहलवानों को उन के साथ जाने के लिये कहा। वे साथ जाने के लिये रज़ामन्द हो गये। इसलिये बरात जाने से एक महीना पहले ही वे पहलवान उन के पास चले गये। उस समय में उन को खूब बादाम आदि अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई गईं। परन्तु जब शादी के बाद बरात लौट रही थी तो रास्ते में उन पर डाकू टूट पड़े। पहलवान एक तरफ हो गये और डाकू बरात को लूट कर चले गये। जब उन से पूछा गया कि तुमने डाकुओं का मुकाबला क्यों न किया तो वे कहने लगे कि वाह जी वाह कौन सी उस्तादी के साथ लड़े थे, न हाथ मिलाया न कुछ और कहा। (*Laughter*)। पुलिस पर यह 3,15,00,000 रुपये का खर्च केवल 13 ज़िलों के लिये किया जाना है। हिमाचल पहले ही निकल गया है। शिमले का ज़िला तो बराये नाम है। वह तो एक बाबुओं की जगह है। चीफ़ मिनिस्टर साहिब के कई henchmen और खुशामदी कहते हैं कि पुलिस ने बड़ा काम किया है।

मुख्य मंत्री : खुशामदी कहना मुनासिब नहीं।

अध्यक्ष महोदय : खुशामदी न कहिये। यह मुनासिब नहीं है।

श्री केदार नाथ सहगल : बहुत अच्छा जी मैं साथी कहूंगा। मैं अर्ज़ कर रहा था कि पुलिस के महकमे पर 3,15,00,000 रुपये खर्च आ रहा है। मगर फिर भी कई महीनों से पुलिस

[श्री केदार नाथ सहगल]

उन दो लड़कियों को जिन का पहले ज़िक्र आ चुका है, अभी तक नहीं ढूंडी जा सकी है। अम्बाले से एक लड़की चली गई। उस लड़की के बाप ने डरते डरते चीफ़ मनिस्टर साहिब से अर्ज़ की तो उन्हों ने वाइदा किया कि वह उस आदमी की लड़की को निकलवायेंगे। परन्तु उस वाइदे के बावजूद वह लड़की आज तक नहीं मिली। जालन्धर में, हिसार में, रोहतक में कत्ल हुए, मगर कातल अभी तक नहीं पकड़े गये। यह हमारी पुलिस उन पहलवानों जैसी है। वह कहते हैं कि न कोई हाथ मिलाता है। वह कैसे उन को पकड़ सकते हैं। फिर चीफ़ मिनिस्टर साहिब का रोअब भी खूब है। उस दिन जब गवर्नर साहिब के भाषण पर तकरीरें हो रही थीं तो आप ने कहा कि अब कोई walk-out कर के देखे तो हम देख लेंगे। मैं कहता हूं कि अगर आप ऐसी बदउनवानियां करेंगे तो हम हज़ार बार वाक आऊट करेंगे। (*Cheers from the Opposition Benches*) आज आप चीफ़ मिनिस्टर हैं कल को कोई और मेम्बर चीफ़ मिनिस्टर बन सकता है। इस लिये यह हिटलर जैसा ग़रूर ठीक नहीं।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन साहिब यह मुझ पर ज़बरदस्ती हो रही है। अर्ज़ यह है कि चीफ़ मिनिस्टर साहिब का walk-out से कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री केदार नाथ सहगल: श्रीमान् जी इन्हों ने एक Subordinate Services Selection Board कायम किया है जो छोटे छोटे मुलाज़म रखने के लिये बनाया गया है। इस बोर्ड का एक मेम्बर एक Retired Suprintendent of Police है। दूसरा मेम्बर एक डाक्टर है जिस की बाबत मुझे पता लगा है कि उस की आमदन 25 रुपये आठ आने थी।

श्री देव राज सेठी: He is one of the most respected persons.

श्री केदार नाथ सहगल: आप जैसा।

श्री देव राज सेठी: मेरे से और आप से भी ज्यादा।

Mr. Speaker: What are you doing Mr. Sethi! You cannot enter into personal discussion with him. You can draw my attention if he makes any objectionable observation.

श्री केदार नाथ सहगल: अगर मैंने कोई objectionable बात कही है तो मैं मुआफ़ी चाहता हूं। उस बोर्ड का एक मेम्बर और है जिस का मुझ को पता नहीं। मिनिस्टरों ने यह सोचा कि महकमों के अफ़सर छोटे छोटे मुलाज़म खुद रख लेते हैं और उन को कहना मुश्किल होता है कि फलां रामलाल या हरभजन सिंह को रख लो। इस मुश्किल को दूर करने के लिये उन्होंने यह बोर्ड बना दिया। जिस आदमी को रखवाना होता है उस के बारे में बोर्ड के मेम्बरों को इशारा कर दिया जाता है।

Mr. Speaker: No. no. There are so many other things which you can say.

श्री केदार नाथ सहगल : मैं श्रीमान् जी ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता । अगर आप इजाज़त दें तो मैं चीफ़ मनिस्टर साहिब के एक दोस्त की अखबार में छपे चंद शेयर पढ़ दूं ।

अध्यक्ष महोदय : कोई काम के पढ़ने ।

श्री केदार नाथ सहगल :

अलह अलह यह लीडराने असैम्बली, जिन को दावा है पारसई का,
रहबरी का लगा के साइन बोर्ड, खून करते हैं इक खुदाई का ।
कर रहे हैं बलैक मेल, मगर फिर भी दावा है पारसाई का ।
जिस तरफ़ देखिये दफ़ातर में, है भला इन के बाप भाई का ।
देख ले काएनात के मालिक, हाल यह है तेरी खुदाई का ।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਤਰੀ ਹਿੱਸਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਉਜੱਲ ਸਿੰਘ ਅਜ ਕਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ late ਲਾਲਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਵਾਇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ T. A. ਘਟਾ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ Allowance ਉੜਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ finance ਦੇ ਅਸਲੀ problems ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ window dressing ਵਲ ਹੀ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ financial problems of the State ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ time ਨਹੀਂ।

United Punjab ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ Government of India ਵਲੋਂ taxes other than corporation taxes ਦਾ ਜੋ share ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ 8 ਫੀ ਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਦੇਸ਼ਮੁਖ award ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5.5 per cent ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ latest achievement ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ 3.25 per cent fix ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 80,15,000 ਰੁਪੈ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ Ministry ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਆਮਲੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਵਾ ਲੈਣਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਨੀ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ problems ਨੂੰ Centre ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ Ministry ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ Centre ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ ਕਿ border police ਦਾ ਖਰਚ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ Centre ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ strategic importance ਰਖਣ ਵਾਲੀ roads ਦਾ ਖਰਚ Central Government ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। partition ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ problems ਇਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਝਾਨ

[ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ]

ਵਿਚ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, Centre ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ-ਬਖਸ਼ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। Central Divisible Pool ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗਲ ਨਹੀਂ।

ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ Ministry ਬਣੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ 1947-48 ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 24,75,000 ਰੁਪੈ ਵਧ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਮੈਂ ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ State ਉਪਰ ਜਿਹੜਾ debt ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉਪਰ ਜੋ interest ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ rate 1947-48 ਵਿਚ 2 7/8 per cent ਸੀ। ਹੁਣ rate of interest 4⅛ per cent ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੀ State ਨੇ ਜਿਹੜਾ interest ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ 4,18,75,000 ਰੁਪੈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ State ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ 57,48,46,000 ਰੁਪੈ Central Government ਤੋਂ ਲੈ ਚੁਕੇ ਹਾਂ। ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ opposition ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ expenditure ਦਾ control ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। Debt ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ Bhakra Control Board ਹੈ। ਇਸ Control Board ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ministerial level ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ Project ਉਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ control ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਜਨਾਬ, routine ਕੰਮਾਂ—Ganguwal Power-house, Rupar Circle, Narwana Circle, Bhakra Main Line Circle—ਦੇ incharge ਤਾਂ Indian engineers ਹਨ ਪਰ ਭਾਖੜਾ site ਤੇ ਸਭ Foreign Experts ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕੰਮ ਦੀ progress ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ divert ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ construction late ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ post-pone ਕਰਨਾ ਪਿਆ। Mr. Slocum ਨੂੰ appoint ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ dam ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 1956 ਤਕ ਇਹ Project complete ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਬਾਦਦਰੀਜ dates ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ postpone ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। Foreign Experts ਦੀ total pay ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 74,84,400 ਰੁਪੈ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ Public Health ਉਪਰ ਕੁਲ 42 ਲਖ ਰੁਪਏ, Veterinary ਉਪਰ 27 ਲਖ ਰੁਪਏ, Co-operative Department ਉਪਰ 17 ਲਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ Agriculture ਉਪਰ 51 ਲਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਾਲ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ। Foreign Experts ਉਪਰ ਜੋ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ demands ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ

ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ progress ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਤਸ਼ਵੀਸਨਾਕ ਗਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ productive ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਬੰਗਲੇ ਬਨ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਉਪਰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ furniture ਹਰ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ productive ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ prestige ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ prestige ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ prestige ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗਾ।

ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 1954 ਨੂੰ Minister for Transport ਹੋਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ reception ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ।

Mr. Speaker : You are too big to indulge in such things. Better leave it.

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ Omni Buses ਦੇ ਅੱਡੇ ਦੀ opening ceremony ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਕਾਸਿਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ Omni Buses ਦੇ ਅੱਡੇ ਦੀ opening ceremony ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੋਈ official ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ dignitary ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਥੇ Omni Buses ਦੇ ਅੱਡੇ ਦੀ opening ceremony ਕਰ ਦਿੰਦਾ ? Official ਦੌਰਾ ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ marriage party ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਥੇ haltage ਰਖਣੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ 2548 starred question ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ (public money) ਨੂੰ waste ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਗੋਂ waste ਨਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ prestige ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਚੀਪ (cheap) ਨਾ ਬਨਾਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵੁਕੱਅਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ Ministry ਅਤੇ administration ਦੀ ਵੀ ਵੁਕੱਅਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ Deputy Commissioner, Reception ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ normally ਹਰ ਰੋਜ਼ Deputy Commissioner ਦੇ 2, 3 ਘੰਟੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 10, 15 ਦਿਨ ਉਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

[ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ]

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ Public Health ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ provision ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 3½ ਆਨੇ per head ਖਰਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ T. B. Patients ਦੀ ਲਿਸਟ 300 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ bed ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲਭਦਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਫਜ਼ੂਲ ਕਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਿਆ ਖੁਲ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੀ victimization ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਦੀਆਂ Municipal Committee ਦੇ Vice-Chairman, Giani Labh Singh ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, rather Municipal Committee ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਨੂੰ suspend ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ Deputy Commissioner ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ suspend ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ enquiry ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। Enquiry ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ Secretary ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੇ । Enquiry ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ Committee ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸਣ ਲਗੇ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਕੜੇ ਗਏ ।

सिंचाई मंत्री : On a point of order, Sir, आप ने हुकम दिया था कि कोई सदस्य किसी particular demand पर ही बोल सकता है और general discussion नहीं कर सकता ।

Mr. Speaker: The hon. Member should continue his speech.

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ: ਗਿਆਨੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹੋਰਾਂ ਉਪਰ ਉਲਟਾ ਡਾਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ (*Interruption*) ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ: ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਬੈਠ ਜਾਉ ।

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) : ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਜਟ ਉਪਰ ਆਪਣੇ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ 249 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ । ਕਈ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਅਲਿਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਇਕ ਵਾਰ ਤਲੰਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਲਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕੋ ਆਦਮੀ ਸੀ । ਦੂਸਰੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣ ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਪੈਸੇ ਰਖ ਲਵੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਰੁਖ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਉ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੋਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦਸੀ ਜਾਵੇਗਾ । ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ । ਉਹ ਰੁਖ ਉਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ 'ਪੰਜੂ ਦੂਨੀ ਦਸ, ਟੱਬ ਆਇਆ ਇਕ' ਇਤਨੀ ਗਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਕ ਲੈ ਗਿਆ (ਹਾਸਾ) । ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਜਟ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ 249 ਲਖ ਵਿਚੋਂ 96 ਲਖ ਦੀ ਰਕਮ Central Government ਨੇ ਹੀ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ Nationalization ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ Nationalize ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ Nationalization ਵਿਚੋਂ ਹੀ 25 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ anti-national activities ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਕਾਲਿਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ education ਮਿਲੇਗੀ । ਇਹ ਗਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ।

ਇਸ ਉਪਰਾਂਤ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕੇਪੀਟਲ investment ਛਡਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚੋਂ 65·2 ਫੀ ਸਦੀ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ administration ਆਦਿ ਉਪਰ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਆਈਟਮ (item) ਉਪਰ ਵੀ opposition ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਯਾਦ ਆਈ । ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਆਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਲਈਆਂ । ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਆਨਾ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਰਿਉੜੀਆਂ ਚਬਣ ਲਗਾ ਤੇ ਆਨਾ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਘਟ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਏ । (ਹਾਸਾ) ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਉਹ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ 1225 ਪਿੰਡ ਹਨ । ਉਥੇ 2001 ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤੇ ਸਨ । ਪੌਣੇ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਇਕ ਪਿੰਡ ਪਿਛੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 1,705 cases ਵਿਚ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾਮੇ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । 296 ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਹੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ (cheers) ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Community Projects ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜੇਕਰ ਨਕਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ

[ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ]

ਕਿ ਛੀਨਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਆਦਿਕ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਨ ਬਾਰਡਰ ਉਪਰ ਵਾਕਿਆ ਹਨ ਪਰ Community Project Scheme ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ । (ਅਵਾਜ਼ਾਂ : ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀ) ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 3,3 ਮੀਲ ਤਿਕਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਜਣ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਛਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਉ । ਕੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ? ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ excise duty ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਇਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰ ਰੋਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰੋਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੀਕੇ ਇਸ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ।

Mr. Speaker : Please wind up.

ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ : ਬਸ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਮਿੱਤ੍ਰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ (Oppositior) ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਪੱਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੀ ਪੱਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ—ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ—ਦੀ ਘਟ-ਸਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋਹ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇ ਪਰਤੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿਤਾ । ਚੁਨਾਂਚਿ ਪਿਛਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਰੁਪਿਆ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ reject ਕਰ ਦਿਤਾ । ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ judicial commission ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤੀ । ਉਸਦੇ ਪਿਛੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸੀ ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨ ਰਿਹਾ ਸਿਵਾਏ ਮੀਤ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੁਟੀ ਤੇ ਸੀ........

Mr. Speaker: Please, sit down, your time is now over.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਝੱਬਾਲ) : ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ (Finance Minister) ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਲਈ

ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਬਾਵਜੂਦ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲ (ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ) ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਗਲ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂ ।

चीफ़ पार्लिमेंटरी सैक्रटरी: क्या उन बैंचों पर बैठने से आप पर कोई असर नहीं हुआ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ: ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਹੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਨ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਕੇਵਲ ਇਕ ਗਲ ਵਲ ਆਪਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (Services) ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਕਿ ਕਿਸ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ (Services) ਵਿਚ ਇਨਤਕਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲ ਸੁਣਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (Services) ਉਤੇ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆ ਆ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕਾਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਅਹਿਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਕੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆਈ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (Services) ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ । ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ Secular State ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ exploit ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਹਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ Secular State ਵਿਚ communalism ਦਾ future ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ । ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਈਲੇਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਰਮਿਕ ਨੀਹਾਂ ਉਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਸਦੇ ਇਕ ਹਿਸੇ, East Bengal, ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ Vicious Circle ਵਿਚ ਨ ਭਰਮੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਇਥੇ communalism ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪਕੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ।

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦੀ visit ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ important subject ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ importance ਨਾ ਦਿਓ । ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗਲ ਕਰੋ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ prohibition ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਏ। ਮੈਂ ਗੋ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ prohibition ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ।

चीफ पारलीमेंटरी सेक्रेटरी : हमसाये जो ठहरे ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ prohibition ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਵਜਹ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ illicit distillation ਅਥਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵਾਧੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਨਾਉਣ ਲਈ illicit liquor ਦੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ illicit distillation ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ smuggling ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ restrictions impose ਕਰੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਛੁਟਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗਏ। ਉਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਮੇਜ਼ ਉਤੇ ਰਖਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਛਕੋ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। (ਹਾਸਾ) ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪੁਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ illicit distillation ਪੁਰ ਚੋਖੀ vigilance exercise ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਇਤਨੇ ਗੜੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਸ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗਿਹਰੀ, ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ, ਲਈਆ ਵਗੈਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਯਾ ਦੋ ਦੋ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਥੇ

ਕ ? ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਰਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣ ਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ special privileges ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਪਰ arms licenses ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ liberally ਦਿਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਗਲ ਮੈਂ Tractor cultivation ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ spare parts ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਲਾਕ ਹਰ ਤਹਸੀਲ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Central Tractor Organisation ਨਾਲ contact ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੀਨਾ ਬੀਧੀ ਚੰਦ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਉਥੇ ਜਦੋਂ ਵਾਲੀ ਬਾਲ (volley ball) ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਬਾਲ(ball) ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਟਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर): स्पीकर साहिब! पंजाब का बजट एक खास अहमियत रखता है। हमने यह देखना है कि आया इस में Welfare State के लिये कोई चीज़ मिलती या नहीं। इस के पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि एक financial desert है और उस में कहीं कहीं oasis यानी नखलिस्तान दिखाई देते हैं। वह चीज़ें इस तरह से दिखलाई गई हैं जैसा कि उन सब की provisions की गई है लेकिन सही चीज़ यह है कि इस में यह लिखा होता है कि इन चीज़ों की provision अगले साल की जायगी। और इस साल कुछ नहीं। हर department के मुतल्लिका provisions को देखा जाये तो वहां यह दिया हुआ होता है कि यह चीज़ next year की जायगी या coming year में की जायगी। इस बजट में ९५ लाख रुपया का deficit दिखाया गया है। मुझे इस से गरज़ नहीं कि deficit कितना है। deficit चाहे इस से भी ज्यादा होता। मगर देखना यह है कि efficiency और national economy को कायम रखने के लिये इस में क्या कुछ किया गया है। पंजाब की खूबसूरती दो बातों में है। एक तो efficiency को maintain किया जाये और दूसरा national economy को ऊंचा लाया जाये और साथ ही जो national income है उस की equitable distribution की जाये। दूसरे शब्दों में एक चीज़ है national efficiency और दूसरी है national prosperity। अगर दोनों चीज़ें हैं तो बजट खुशनुमा है और ideal

[प्रोफैसर मोता सिंह]

है। Ideal Budget वह होता है जिस में जो पिछले टैक्स हों उन्हें बढ़ाया न गया हो और नये टैक्स लगाये न गये हों। यह चीज़ें होती हैं जो मैं समझता हूं तमाम advanced countries के बजटों में पाई जाती है। फिर हमारा एक Socio Economic System होना चाहिये। हमारे देश का Capital तो सचमुच लेबर (labour) है। जिस को पूरी तरह से utilise करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप कौन सी बोली में बोल रहे हैं। क्या यह अंगरेज़ी है, या हिंदी या कि पंजाबी।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : मैं हिन्दी बोल रहा हूं जिस में अंगेज़ी के लफ़ज़ बोलने पड़ते हैं क्योंकि अंगेज़ी तो यहां बोलने नहीं दी जाती और हिन्दी या पंजाबी में पूरी वज़ाहत से बात की जा नहीं सकती। मेरी तो सारी उमर अंगेज़ी पढ़ने और पढ़ाने में बीत गई है। अगर आप चाहते हैं कि मुलक के अन्दर हिन्दी या पंजाबी तरक्की करें तो आप इन चीज़ों.... ....(*Interruptions*).

स्पीकर साहिब ! मैं कह रहा था कि अगर हमारे मुल्क में सचमुच यह चीज़ें लाई जायें तो हमारा बजट एक ideal budget हो सकता है। हमारे देश में दूसरे advanced countries की तरह capital की accumulation नहीं है। हमारे देश का Capital, man power है। हमारे यहां man power बहुत ज्यादा है और इस में भी Unemployment बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूं कि जितना ज्यादा हम मैन पावर (Man power) को काम में लायेंगे उतना ही हमारा Socio Economic System का बजट अच्छी तरह तैयार हो जायगा। मैं ने अपने देश के Fiver-Year Plan को अच्छी तरह से देखा है और इस की commentary को भी खूब पढ़ा है। हमारी Five-Year Plan की जो तरज़े तहरीर है अगर उस का मुकाबला दूसरे मुल्कों के Five-Year Plan से किया जाये तो यह उन से बिल्कुल मुखतलिफ मालूम होगा। America के Five-Year Plan में हमारे मुल्क से $2\frac{1}{2}$ लाख Tractors का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। हमारे मुल्क में कुल दस हज़ार Tractors हैं और हमारा पंजाब तो इस बात में बहुत ही पीछे है। फिर America में Fertilizers इतने ज्यादा इस्तेमाल किये जाते हैं कि हमारा उन से कोई मुकाबला ही नहीं। उन के मुकाबले में हमारे हां Tractors का इस्तेमाल आटे में नमक भी नहीं है।

फिर स्पीकर साहिब ! मैं देखता हूं कि इस बजट में industries के लिये कुछ नहीं रखा गया। हां electricity के लिये ज़रूर कुछ किया गया है जो किसी वक्त जा कर factories के लिये इस्तेमाल की जायगी। और जो कुछ industries के लिये किया गया है वह modest है और पांच साल बीत जाने पर हमें इन में कोई तरक्की नज़र नहीं आयगी। (*The bell rings*) स्पीकर साहिब ! बजट पर बहस हो रही है बहुत सारी बातें कहनी हैं कुछ time और दें। क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ों पर बोलना है इस लिये healthy concession दें।

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके दो मिनटों में अपनी स्पीच (speech) को wind up करें। बोलने वाले बहुत हैं और समय बहुत थोड़ा है।

प्रोफ़ैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : अगली बात यह है कि जो ग़रीब तबका है वह तो सब से ज्यादा परेशान है और जो मुलाज़म तबका है उस के लिये तो कुछ किया ही नहीं गया। वह मुलाज़म जो ५० रुपया के अन्दर तनखाह लेते हैं उन के लिये तो कुछ किया गया है लेकिन जो पचास रुपया से १०० रुपया तनखाह लेने वाले हैं उन्हें कुछ नहीं दिया गया है। clerical class जो कम तनखाहें लेने वाले हैं उन के लिये न पिछले साल के बजट में और न ही इस साल के बजट में कुछ किया गया है। मैं समझता हूं कि कुछ इधर उधर की चीज़ें मिला कर खुशनुमा बनाया गया है। इसे दर असल poor man's Budget बनाया जाना चाहिये था। इस बजट से मेरे ख्याल में इस प्रान्त में खुशहाली नहीं आ सकेगी। इस में बहुत थोड़े sources को tap किया गया है। सिर्फ Cinema shows पर tax लगाया गया है। अगर Death Duty या Estate Duty से प्रान्त की आमदनी बढ़ाई जाती तो बेहतर होता।

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਬਜਟ ਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਲ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਸੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਭੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਦਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਰੁਪਿਆ ਲਿਆਂਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਸਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਆਂ ਚੁਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ? ਮੈਨੂੰ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ ਜੋ ਇਥੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ 819 ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ challenge ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 819 ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰਿਹਾ ੧੯ ਵੀ ਅਜੇਹੇ ਹਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ ਚੰਦ ਜ਼ਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਰੀਜਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਹੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲ-ਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜ ਜੋ ਆਪਣੀ 7 ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੀ

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਚਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਖਿਆਂ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਨੰਗਿਆਂ ਰਖਣ ਦੀ ਹੈ ।

ਕਲ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ party discipline ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ discipline ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ 2 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਨੇ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਦਸਵੀਂ ਤਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲੇ ।

ਫਿਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ 20, 20 ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜੇਕਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣ (ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਵਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ) ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਲਈ ਥਾਂ ਮੁਲ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਮਰਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 50 ਰੁਪੈ ਮਰਲੇ ਤਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਸ ਉਤੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ 107 ਅਤੇ 152 ਵਿਚ ਜਕੜ ਕੇ ਮੁਕਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਥਾਂ ਦੇਵੇ ।

ਫੇਰ ਮੈਂ ਸੁਝਾਵ ਰਖਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਸੂਦ ਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਵੇ। ਸਸਤੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਰਜ਼ੀ ਗਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਨਾਂ ਗਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਤਾ ਸਿੰਘ (ਆਦਮਪੁਰ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਬੂਤ ਦਿਤੇ

ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 40½ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਭੀ 2 ਰੁਪਏ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਨਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ Education Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ vernacular teacher ਨਾਲੋਂ english teacher ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ vernacular teacher ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ education ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1 400 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। (*The bell rings*)

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਗਲਾਂ ਕਹਿਨ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਘੰਟੀ ਬਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

अध्यक्ष महोदय : मास्टर साहिब मैं आप को एक सलाह दूं कि अगर आप घण्टी नहीं सुनना चाहते तो घड़ी को बन्द कर दीजीए ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 10 per cent ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ common pool ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫਿਰ 2 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਅਜਿਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਸਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਕ ਗਲ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਟ ਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ। ਫੇਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਨ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਅਜ ਕਲ 1,400 ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚੰਗੀਆਂ ਟ੍ਰੇਂਡ ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਅਗੇ ਰਖੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ training ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ

[ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਰਾਂਇਆ ਸਿੰਘ]

ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਉਚੀ ਸਿਖਿਆ ਬੀ. ਟੀ. ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਪਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਂਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਟ੍ਰੇਂਡ ਟੀਚਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਨ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਏ ਜਿਸ ਦਾ ਤਅਲਕ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ welfare ਨਾਲ ਏ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਏ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਯਨਿਸਟ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਵੇਲੇ ਜਦ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਿਯਾਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਐਕਟ ਇੰਤਕਾਲ ਅਰਾਜ਼ੀ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਚਮਾਰ ਚਮਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਇੰਤਕਾਲ ਅਰਾਜ਼ੀ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਕਟ ਇੰਤਕਾਲ ਅਰਾਜ਼ੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਏਸ ਨੇ ਐਕਟ ਇੰਤਕਾਲ ਅਰਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ consolidation ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ 1940 ਜਾਂ 1942 ਵਿਚ ਇਤਲਾਏ ਆਮਾ ਲਈ ਇਕ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਡਿਪਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਰੀਜਨ ਅਫਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤ ਹੈ।

श्री डी. डी. पुरी (जगाधरी) : स्पीकर साहिब मैंने प्रोफैसर मोता सिंह की तकरीर सुनी है। उन्होंने इस बजट को finance का desert बताया है और वह उस में oasis को तलाश करते रहे। मगर मैं हैरान हूं कि उन्होंने इसी बजट का जिक्र किया था या और किसी का।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : इसी का ही।

श्री डी. डी. पुरी : स्पीकर साहिब ! इस बात से इनकार करना कि यह development का बजट है सूर्य के प्रकाश में अंधकार की शंका करना है। अगर आप बजट को देखें तो आप को पता चलेगा कि विकास व्यय (Development Expenditure) जो कि पहले ११ करोड़ ४६ लाख था अब बढ़ा कर १५ करोड़ ८ लाख कर दिया गया है। जिस की पिछले

बजट से ३१.५ प्रति शत वृद्धि increase हुई है। इस का मतलब यह हुआ कि एक वर्ष में (विकास व्यय) Development Expenditure और ज्यादा खर्च किया गया है।

स्पीकर साहिब, इस बजट में Capital Expenditure और Revenue Expenditure का टोटल (Total) ५४ करोड़ ८५ लाख बनता है तो इस में Development के लिये ४६ करोड़ ८० लाख रुपये का provision किया गया है। इस तरह Total Expenditure अर्थात् सारे खर्च का ८५ प्रति शत Development Expenditure है। स्पीकर साहिब, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक देश की बाकी स्टेटों के बजटों को मैंने देखा है और पढ़ा है कहीं भी ऐसा बजट नहीं है जिस में कुल खर्च का ८५ प्रति शत Development पर खर्च किया गया हो। मुझे हैरानी होती है कि फिर भी प्रोफैसर साहिब इस बजट को Financial desert बताते हैं और इस में oasis की तलाश करते रहे हैं।

फिर बजट के सफा १७ पर नहरों का ज़िक्र है। इस में दर्ज है कि २९० मील लम्बी पलस्तर शुदा नहर है। २६१ मील गैर पलस्तर शुदा है और २,६९५ मील distributaries और Minors हैं। इन सब का टोटल ३,२७६ मील बनता है। तो अगर इन १६ और १७ नहरों के बावजूद भी प्रोफैसर साहिब को oasis नहीं मिला। तो फिर कहीं भी नहीं मिल सकेगा।

किसी मुल्क की तरक्की के मैयार का पता वहां की उपज से चलता है। अगर यहां की पैदावार का १९४८-४९ और १९५२-५३ का मुकाबला किया जाये तो स्पीकर साहिब साफ पता चल जाता है कि इस तरफ कितनी तरक्की हुई है। १९४८-४९ के मुकाबले में १९५२-५३ में २१ प्रति शत की बढ़ोतरी हुई है। इस का ज़िक्र बजट में है। इस बढ़ोतरी में ज़ेर काश्त ज़मीन में ३.७ प्रति शत और पैदावार की value में २१ प्रति शत की वृद्धि हुई है। इस से produce बहुत बढ़ गई है। हालांकि इस period में depression था और produce की कीमतें कम हो गई थीं मगर फिर भी लोगों के हिस्से में produce ज्यादा आई है और उन की आमदनी बढ़ी है। कहना यह है कि कम से कम होने के बावजूद केवल ३.७ प्रति शत ज़ेर काश्त ज्यादा भूमि में से इतनी उपज हुई जिस की कीमत २१ प्रति शत अधिक थी। इस में अधिक भाग किसानों का है। इस के लिये सरकार को और पंजाब के मेहनती किसान को बधाई देता हूं। और जनता की तरफ से वे बधाई के पात्र हैं। इसी के फलस्वरूप जहां पहले इस स्टेट में तीस हज़ार टन अनाज का deficit था जिस का बार बार ज़िक्र किया गया है वहां अब १ लाख टन से ज्यादा का surplus है।

स्पीकर साहिब, मैंने केंद्रीय सरकार का बजट देखा है। उस में वित्त मंत्री ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि जिन स्टेटों ने अभी तक पंच वर्षीय योजना के अधीन अपनी ज़िम्मेदारी का अनुभव नहीं किया वे इसे महसूस करें और अगर वे इस बारे में अपना काम पूरा नहीं कर रही हैं तो उन्हें पूरा करना चाहिये। अब चूंकि पांच साला योजना के पूरा होने में थोड़ा समय रह गया है इस लिये जो स्टेटें पीछे हैं वे इस काम को पूरा करने का प्रबन्ध करें। इस तरह हमारे राज्य में जितनी भी अनाज में वृद्धि हुई है और जो किसानों ने

[श्री डी. डी. पुरी]

रुपया कमाया है इस से पता चलता है कि पांच साला योजना पंजाब में सफल हो रहा है। इस कुल जिम्मेदारी में से हमारी स्टेट पर ३१ करोड़ की जिम्मेदारी बनती है। इस ने १९५३-५४ में १५ करोड़ रुपये खर्च किये हैं और ८ करोड़ ७० लाख रुपये का १९५४-५५ में खर्च किया जाना है। इस का अर्थ यह है कि इस साल के अन्त में ३१ करोड़ में से हमारी स्टेट २३ करोड़ ७० लाख रुपये की अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी होगी और बाकी ८ करोड़ की रकम की जिम्मेदारी हमारी सरकार आसानी से बाकी के वक्त में पूरा कर लेगी।

इस के बाद स्पीकर साहिब ! दो चार बातें और हैं जिन की तरफ में गवर्नमैण्ट की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं, और suggestions देना चाहता हूं। पिछले साल १९५३-५४ में इस बात का credit लेने की कोशिश की गई है कि खर्च में ५० लाख की रकम कम रखी गई है बजट के सफा ३ पर मैं देखता हूं कि २२ लाख रुपये की बचत Community Project में हुई है और ४९ लाख रुपये की Civil Works में से हुई है। इस से अगर Development Account का टोटल (Total) करें तो ७१ लाख रुपये बनता है। इस का अर्थ यह हुआ कि ५० लाख रुपये की जो सेविंग (Saving) दिखाई गई है उस से Non-Development की activities पर २१ लाख रुपये ज्यादा खर्च किये गये हैं। यह जो ३१.५ प्रति शत Development Expenditure पर बढ़ोतरी का जिक्र मैंने किया है इस में मैं समझता हूं कि इस से शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के साथ इनसाफ़ नहीं हुआ।

इस ३१.५ प्रति शत बढ़ोतरी में से education में सिर्फ १३ फ़ी सदी बढ़ोतरी हुई है। खैर मैं इस सिलसिले में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जैसी तालीम हमारे स्कूलों और कालिजों में दी जा रही है इस पर बेकारी बढ़ाने की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। यह तालीम हमें गांवों में जाकर अपने आप को adjust करने के काबिल नहीं बनाती। हर तालीमयाफ्ता आदमी शहरों में नौकरी ढूंढता है और गांवों में जाने को तैयार नहीं होता। इस लिये तालीम में तबदीली की बहुत जरूरत है। दूसरे कई सूबों में तो rural universities बनाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यहां भी हमें ऐसा ही करना चाहिये। इस के इलावा practical education का इंतज़ाम बहुत जरूरी है और इस तर्फ बहुत जल्द तवज्जुह दी जानी चाहिये।

Medical में केवल ५ फ़ी सदी की बढ़ोतरी की गई है। इस सिलसिले में एक आम शिकायत यह है कि हस्पतालों में दवायें काफी नहीं हैं और मरीज़ों को इन से पूरा फायदा नहीं हो रहा। इस मद्द में खर्च को बढ़ा देना चाहिये। अगर development बजट में से कुछ रुपया इस मद्द के लिये रख लिया जाता तो अच्छा था। एक बात और कह दूं। शिमले में जो वाकर हस्पताल (Walker Hospital) है उस के बारे में यह बात आप को मालूम है कि वहां डाक्टर और काम करने वाले ज़्यादा हैं और मरीज़ कम। वहां साल भर में इतने मरीज़ नहीं होते जो डाक्टरों की तादाद के मुताबिक काफ़ी हों। अगर इस को बंद कर दें तो यही रुपया दूसरे हस्पतालों के काम आ सकता है और इस से लोगों को भी फायदा होगा।

अब industries को लीजिये । यहां ४४,००,००० के loans में से industries के हिस्से में सिर्फ २२ लाख रुपये की रकम आई है। इस रकम से हमारा सूबा industrialise नहीं हो सकेगा। हमें बताया गया है कि जहां १९४७ में हमारे हां ७१५ फैक्ट्रियें थीं वहां १९५३ में उन की गिनती १,८१७ तक पहुंच गई है इसी तरह मजदूरों की गिनती भी बढ़ा के दिखाई गई है। मगर वे इस बात को भूल जाते हैं कि इस दौरान में Factories Act में तरमीम हो गई है और उस से factory की definition में एक बड़ी तबदीली हो गई है। पहले act के मुताबिक जिस कारखाने में कम से कम २० आदमी काम करते हों वह ही factory कहलाती थी, मगर अब दस आदमियों वाला कारखाना भी factory में शुमार होगा जिस का मतलब यह हुआ कि जो बढ़ौतरी दिखाई गई है उस में ऐसे कारखाने भी शामिल हैं जो पहले भी मौजूद थे मगर पहली definition के मुताबिक factories में न गिने जाते थे।

स्पीकर साहिब ! हमें यह बताया गया है कि artificial silk fabrics पर Centre ने जो duty लगाई है उस के बारे में हमारी सरकार ने उस पर जोर दिया है कि यह duty न लगाई जाये क्योंकि इस से हमारी इस industry और तजारत को नुकसान पहुंचेगा। मैं इस बात पर अपनी सरकार की सराहना करता हूं। मगर इस के साथ ही यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि उधर तो यह duty हटाने पर जोर दे रहे हैं और इधर आप सिनेमा शो कर (Cinema Show Tax) लगा रहे हैं। मैं अर्ज़ करता हूं कि यह tax उचित नहीं। इस से हमें तो सिर्फ ५ लाख रुपये की आमदनी होगी मगर सिनेमा वालों पर बड़ा भारी बोझ पड़ जायगा। यह गुनाहे बेलज्जत के समान है। एक एक सिनेमा पर इस का बोझ ६०० रु. से १,००० रुपये मासिक पड़ जायगा जिस से सिनेमा industry को धक्का पहुंचेगा। इस के बाद हमारे cash balances की हालत भी गौर के काबिल है। १९५२-५३ में यह रकम ६,६७,००,००० थी और १९५३-५४ के अन्त में २ करोड़ से भी कम, यानी सिर्फ १,८५,००,००० का balance रह जायेगा। मैं अर्ज़ करता हूं कि cash balances को इस तरह खर्च करते जाना मुनासिब नहीं।

एक और जरूरी बात यह है कि National Cadet Corps को तो ठीक तरक्की दी जा रही है मगर अब हमें Rifle Clubs भी खोलनी चाहियें। इन की जरूरत के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता मैं यह अर्ज़ कर देता हूं के इस के लिये आप बेशक कोई नया tax लगा दें पंजाब के लोग कुरबानी कर के भी यह tax देने के लिये तैयार होंगे।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जो Industrial Finance Corporation बनाया है उस पर मैं पिछले साल भी बधाई दे चुका हूं लेकिन यहां Rural Finance Corporation की भी गुंजाइश है। दूसरे सूबों में इस बारे में कोशिशें हो रही हैं। नाम खाह कुछ भी रख लें काम वही है जो मैंने अर्ज़ किया। खास कर बम्बई ने इस बारे में कोशिश की है और Centre ने इस के २० फी सदी capital की जिम्मेदारी लेली है। इसी किसम की कोशिश हमें भी करनी चाहिये।

राय हरि चंद (आनन्द पुर) : स्पीकर साहिब ! मैं सब से पहले अपने Finance Minister साहिब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक progressive बजट पेश किया है। इस बात से इनकार नहीं हो सकता कि इस बजट के जरीये Development State कायम करने की कोशिश की गई है। फिर मैं सरकार का भी मशकूर हूं कि हमारे ज़िला होशियारपुर का भी कुछ ख्याल रखा गया है और ऊना (Una) में एक गरल स्कूल (girls school) जारी कर दिया गया है। मगर इस बात का अफ़सोस भी है कि इस जिले की अहम जरूरीयात का ख्याल नहीं रखा गया है। हमने इन जरूरीयात का बड़े ज़ोर से D. C. के सामने भी ज़िक्र किया और जब वज़ीर साहिबान दौरे पर गये तो उन को ऐडरेस पेश कर के उन का इस तरफ ध्यान दिलाया मगर बजट में इस काम के लिये बहुत थोड़ी रकम रखी गई। होशियारपुर का सब से बड़ा मसला चो, खड्ड और नदी नालों का है जिन्होंने इस जिले को जो पंजाब का बाग़ कहलाता है जंगल बियाबान में तबदील कर दिया है। वज़ीर साहिबान सब कुछ अपनी आंखों से देख आये हैं और हमने भी ऐडरेसों में उन को सब कुछ बता दिया है। वह उन के जवाब में वाइदे भी कर आए मगर नतीजा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं निकलता है। मुझे यह देख कर अफ़सोस हुआ कि हुशियारपुर जिला के एक कांग्रेसी मेम्बर साहिब २ लाख की रकम पर ही इतने खुश हो गये और बड़े ज़ोर शोर से कहा कि सरकार ने ५० साल में चोओं पर control हासिल कर लेने का पक्का इरादा कर लिया है। मगर जनाब यह तो वही बात है कि दवा आने तक मरीज़ मर जायगा।

ज़रा ख्याल फरमाइये कि उस दवा का क्या फ़ायदा होगा जो उस वक्त पहुंचेगी जब मरीज़ मर चुका होगा। सरकार को चाहिये कि मेरे ज़िले की तरफ़ भी तवज्जुह दे। इस में शक नहीं कि consolidation का काम जोरों पर है और Grow-More-Food पर खूब खर्च किया जा रहा है लेकिन हैरानी की बात है कि काश्त का रकबा कम हो रहा है। मैं मानता हूं कि पंजाब में तरक्की हो रही है। Grow-More-Food Campaign के ज़रिये सूबा self-sufficient ही नहीं बल्कि खुराक पैदा करने के लिहाज़ से surplus हो रहा है। परन्तु इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि ज़िला हुशियारपुर की हालत बद से बदतर हो रही है। मेरा विचार है कि यदि इस ज़िले को ignore किया गया और इस की तरफ ध्यान न दिया गया तो यहां के निवासियों को कहीं और जा कर रहना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब खतम कीजिये !

राय हरि चंद : इस बात के लिये आप का बहुत शुकरिया। लेकिन मुझे एक दो बातें और कहने की आज्ञा दीजिये, स्पीकर साहिब ! एक बात यह है कि ज़िला होशियारपुर stray cattle और जंगली जानवरों के हाथों बहुत तंग है। consolidation और Grow-More-Food पर लाखों रुपया खरच हो रहा है लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। stray cattle और wild animals गरीब ज़मींदारों की फसलों को बरबाद कर देते हैं और वह देखते रह जाते हैं। सरकार को इस के बारे कोई प्रबन्ध ज़रूर करना चाहिये।

ऊनावेवाला, हमारा एक और बड़ा मसला स्वां का है । जब ऊना और हमीरपुर के दर्मयान स्वां चढ़ जाता है तो हम लोग हर civilized तरफ़ से कट जाते हैं । मेरी दरख्वास्त है कि इस पर पुल जल्द अज़ जल्द बना दिया जाये ।

मुझे water-supply के बारे भी कुछ कहना है । मेरे विचार में तीन रुपया का rate बहुत ज्यादा है इसे कम किया जाये । अच्छा होता यदि District Board की इस तजवीज़ पर अमल कर लिया जाता कि यह खर्च लोगों, District Board और सरकार में बांट दिया जाये । यदि ऐसा नहीं हो सकता तो मैं कहूंगा कि water-works के लिये नंगल की बिजली दे दी जाये । इस से water-works पर कम खर्च आयगा, और लोगों का भार खुदबखुद हलका हो जायगा ।

मेरी एक दरख्वास्त और है—वह यह है कि मेरे लिये मेरे इलाका को सज़ा न दी जाये । वज़ीर साहिबान नंगल को देखने जाते हैं । वहां बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं । क्या कभी उन्होंने उस Anandpur की constituencv के नुमाइंदे को मिलने की कोशिश की है, जो कांग्रेस का मैम्बर नहीं । क्या उन्होंने इस Constituency की improvement के लिये एक पैसा भी बजट में रखा है ? मैं कहता हूं कि सरकार को तंगदिल न होना चाहिये । ५० हजार लोगों की आंखे उन की तरफ लग रही हैं । बराए मेहरबानी उन के लिये कुछ ज़रूर किया जाये । उन लोगों के देहात में पुल नहीं बनाये जाते जिन्हों ने Congress को वोट नहीं दिया ।

Minister for Irrigation : No. This is not correct.

राय हरि चंद : मैं आप की इस 'No' को challange करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री देवी लाल जी तकरीर फरमायेंगे ।

श्री देवी लाल (सरसा) : श्रीमान् स्पीकर साहिब ! मैं इस बजट के लिये सरकार को बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं । परन्तु इस के इलावा मैंने सरकार का ध्यान कुछ उन बेइनसाफियों की तरफ भी दिलाना है जो हरयाना के लोगों से हो रही है ।

जहां तक इस बजट का सम्बन्ध है हरेक ने इसे Development Budget कहा है । इस बात से इनकार नहीं हो सकता कि सड़कों, नहरों और दूसरे तमाम मामलात पर अगले साल इस साल की निसबत दुगना खर्च किया जाना है । तालीम पर तो खास तौर पर ऐसे होना है । चंडीगढ़ पर बहुत खर्च किया गया है और अगले साल भी होना है । परन्तु इस खर्च का फायदा आम जनता को न पहुंचेगा । इस का फायदा केवल सरकारी मुलाज़मों को ही होगा । बेहतर होता यदि यह खर्च देहात की भलाई के लिये किया जाता ।

स्पीकर साहिब, मुझे सरकार को यह भी कहना है कि मुलाज़मत और दूसरे मामलों में जलन्धर Division के मुकाबला में अम्बाला Division के साथ मुनासब सलूक नहीं हो रहा । यह बात मैं अदादोशुमार से साबत कर सकता हूं । जलन्धर Division में १८६ E.A.C. हैं लेकिन अम्बाला में सिर्फ २१ । जालन्धर में ४८ तहसीलदार हैं । मगर अम्बाला में सिर्फ ७ । हर लिहाज़ से जालन्धर के मुकाबला में अम्बाले को नज़रन्दाज किया

[श्री हरी लाल]

जा रहा है। यह हाल केवल मुलाजमतों के सिलसिले में ही नहीं और बातों में भी है। फिर Transport ऐसी चीज है जो सारे हिन्दुस्तान में nationalise की जा रही है। मुझे हैरानी होती है कि जब दूसरे सूबों में Communist इस पालिसी के हक में हैं तो यहां के Communist इस के खिलाफ क्यों हैं। बहरहाल Nationalisation of Transport हो रही है। परन्तु यह काम सिरफ जालन्धर और अमृतसर में हो रहा है। फ़िरोजपुर, रोहतक और गुड़गांव में कोई route nationalise नहीं हुआ। इस बात की तरफ खास तौर पर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आया इस पालिसी का कुछ फायदा होगा या ना कुछ समय के बाद देखा जायगा। मैंने अपनी सरकार की तवज्जुह मुजारों की बेदखलियों की समस्या के बारे भी दिलानी है।

यह मानना पड़ेगा कि कि मुजारों सम्बन्धी कानून पिछली दफा हमारी असेम्बली में पास किया गया था। उस कानून द्वारा मुजारों को काफी relief दिया गया है और यह कोशिश की गई है कि उन की बेदखलियां बन्द की जायें। उस में यह भी प्रबन्ध किया गया था कि १९४७ के बाद जो मुजारे बेदखल हुए हों उन को अपनी ज़मीन पर बहाल कर दिया जाये। लेकिन drafting के वक्त कानून इस ढंग से बना कि एक भी बेदखल-शुदा मुजारे को ज़मीन वापस नहीं मिली। यह मानना पड़ेगा कि सरकार की नियत अच्छी है इस लिये वह कोशिश कर रही है कि ३० एकड़ से ज्यादा ज़मीन के मालिकों को नोटिस के ज़रिये उन का बाहमी फैसला करा के दोबारा ज़मीन पर restore किया जाये। जहां तक गवर्नमैण्ट की मैशीनरी का ताल्लुक है सरकारी अफ़सर बड़े बड़े मालगुज़ारों से मिल कर गवर्नमैण्ट की जो मनशा होती है उसे पूरा नहीं होने देते। मैं यह कह रहा था कि जहां तक गवर्नमैण्ट की मनशा का ताल्लुक है वह चाहती है कि हमारा सूबा तरक्की करे और हमारे किसान खुशहाल हों और ज़मीन का मसला सुलझाया जाये लेकिन मैं गवर्नमैण्ट का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमैण्ट की पालिसी चलाने के लिये यह ज़रूरी है कि उस की मैशीनरी उस के साथ मुतफिक हो। हर काम में गवर्नमैण्ट की मैशीनरी रुकावट डालने की कोशिश करती है। अगर यही हालत रही तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसा कि कल या परसों मशरकी बंगाल के चुनावों के बारे में नूरुलअमीन ने कहा था कि सरकारी अफ़सर उन की मुखालिफत करते हैं। मुझे डर है कि हमारे मंत्रिमंडल को भी कहीं ऐसी शिकायत पैदा न हो जाये। जहां तक गवर्नमैण्ट की ख्वाहिश का ताल्लुक है उस में कोई शक नहीं लेकिन गवर्नमैण्ट अपनी मनशा के मुताबिक प्रोग्राम तभी चला सकती है जब उस की मैशीनरी उस का पूरा पूरा सहयोग दे।

इस के इलावा मैं आप की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाता हूं कि जितना रुपया चंडीगढ़ में खर्च किया जा रहा है अगर दिहातों के सुधारने पर खर्च किया जाता तो ज्यादा मफीद साबत हो सकता था। लेकिन यह मौजूदा गवर्नमैण्ट का कसूर नहीं। जिस वक्त यह तजवीज़ बनाई गई थी उसी वक्त रुपया खर्च करने का प्रोग्राम भी बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे असेम्बली चेम्बर बनाया जाना है उस के लिये पहिले ही रुपया खर्च करने का ढंग तजवीज किया जायेगा। इसी तरह लाखों रुपये M.L.A.'s Quarters पर खर्च किये जाने हैं। यह स्कीम भी पहले बन चुकी है और इस पर दोबारा और कहना मुमकिन नहीं

हो सकता । आखिर में मैं जहां माननीय वित्त मंत्री को मौजूदा बजट पेश करने पर मुबारिकबाद पेश करता हूं वहां यह उम्मीद करता हूं कि गवर्नमैण्ट मुज़ारों की समस्या को हल करने की तरफ भी ध्यान देगी ।

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ (ਡੇਲੋਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਕਰੀਬਨ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ⅓ ਹਿੱਸਾ ਅਰਥਾਤ ੪ ਜਾਂ ੫ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ ਹੁਣ ੪ ਜਾਂ ੫ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ conditional ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਬੋਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਖ਼ਾਹ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਖਿਆ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਹਲ ਕਰਨ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੁਫਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਲੀਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਸੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ 90 ਫੀ ਸਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਬਾਦ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਤਰਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਵਲ ਖਿਆਲ ਰਖ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 1947 ਤੇ 1948 ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਖਰਚ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਦਾ ਸਾਲ ਨਾਰਮਲ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਹੱਤਾਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ activities ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ dues ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ teacher ਦੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਉਸ ਸਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ । ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1948 ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ, ਲੁਧਿਆਣੇ, ਦਾ ਖਰਚ ਉਸ ਸਾਲ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਘਟ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਪਰ ਇਸ ਬਿਨਾ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 1,76,000 ਘਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 1947–48 ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ

[ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ]

ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ੩੧ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,76,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ੧੨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚੋਂ ੯੫,੦੦੦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ main function ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਪਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ 95,000 ਰੁਪਿਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ agitation ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ Agitation ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। teachers ਨੇ agitation ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ grade 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 90 ਰੁਪਏ ਤਕ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ teachers ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ, memorandum ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ deputation ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ agitation ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ discipline ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ agitation ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਬ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Prosecuting Sub-Inspector ਜਿਹੜਾ B.A.,LL.B. ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ 80—5—100/5—120 ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ practice ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ resources ਵਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ agitation ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਬਾਰਿਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਦ ਤਕ satisfy ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मैम्बर साहिबान! अब discussion का समय खत्म हो गया है। अब हमारे Irrigation Minister साहिब और Finance Minister साहिब जो बहस हुई है उस का जवाब देंगे।

सिंचाई मंत्री : मेरे ख्याल में कैप्टन रणजीत सिंह बोलने के बहुत ख्वाहशमंद थे। इस लिये आप हमारे वक्त में से इन को पांच या दस मिनट दे दें।

अध्यक्ष महोदय : अगर वह चाहते हैं तो मैं दे दूंगा ।

श्री रंजीत सिंह कैप्टन (हिसार सदर) : प्रधान जी! आज जिस बजट पर हमारे सामने बहस हुई है यह कांग्रेस हकूमत की तर्फ से सातवां बजट हमारे सामने पेश किया गया है । मैं contradiction के खौफ़ के बगैर कह सकता हूं कि पिछले छः सात साल के अरसे में पंजाब तरक्की के रास्ते पर चल रहा है (*cheers*) । सब से पहले जब Partition हुई तो एक ज़रूरत पैदा हुई कि हमारे देश में जो हमारे भाई पाकिस्तान से मारधाड़ की वजह से आये थे उन को यहां बसाया जाये । मैं कह सकता हूं कि पंजाब के नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के रहने वाले जानते है कि गो यह मसला १०० फी सदी हल नहीं हुआ है फिर भी यह कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान से आये हुए लोग अच्छी तरह आबाद नहीं हुए । जो उन लोगों का उधर नुकसान हुआ है उस का मुआवज़ा देने पर भी हमारी हिंद सरकार गौर कर रही है ।

उस के बाद जो हमारी नहरों की कमी थी उस को tackle किया गया । जो नहरों का काम आज से छः साल पहले शुरु हुआ था वह आज ५० फी सदी पायाए तकमील तक पहुंच गया है और इस साल लोगों को पानी दिया जायगा । इन छः सालों से पहले यह सूबा एक ग़रीब सूबा था और यह हिंदुस्तान की तरफ देखता था कि वह इस को खाने के लिये अन्न दे । आज यह हालत है कि वह हिंदुस्तान को कहता है कि जितना ज़रूरत हो हम से अनाज लो (*cheers*) । इन बातों से मैं आप को दिखाना चाहता था कि इस तरक्की के रास्ते पर चलते हुए हमें यह बजट पास करना चाहिये । हमारे दोस्त कांग्रेस से यह उम्मीद रखते हैं कि हर बजट में कोई नई चीज़ दिखाई जाये । हर रोज़ भाखड़ा और नंगल नहीं बन सकते । हर रोज़ कैपीटल (Capital) नहीं बनाये जा सकते । एक कैपीटल (Capital) हम ने लाहौर में बनाया था, वह उधर रह गया । अब हमने यह कैपिटल (Capital) बनाना है । अगर पहले कुछ जिम्मेदार आदमी मुखालिफ़त न करते तो कैपीटल (Capital) पहले बन गया होता । इस में कोई शक नहीं है कि अब यह कैपीटल (Capital) बनेगा। हमारी सरकार ने यहां मकान बनाने के लिये सरकारी मुलाज़मों को loan दिये थे। यह ज़रूरी चीज़ है परन्तु जिन rules के अधीन यह loans दिये गये थे वह आम हालात के थे । इस कैपीटल में हरेक उजड़े हुए सरकारी मुलाज़म ने मकान बनाना है । मैं चाहता हूं कि आप दो साल की नौकरी का करज़ा दें और वसूली का अरसा भी लम्बा करें । यह छोटी छोटी तनखाहों वाले मुलाज़मों के लिये बहुत ज़रूरी है ।

इस के बाद मैं आप के द्वारा अपनी सरकार को कहना चाहता हूं कि भाखड़ा बन्ध बन जाने से सारा irrigation का मसला हल नहीं होता । मैं जिस ज़िले से आया हूं उस इलाके के लिये सरकार कहती है कि हम ने भाखड़ा प्रोजेक्ट दिया है । यह अमरे वाक्या है और इस के लिये हम मशकूर हैं । लेकिन एक तहसील हमारे ज़िले की इतनी बड़ी है कि जालन्धर का सारा ज़िला उस से आधा है । जब से हमारी सरकार बनी है भिवानी तहसील के लिये आटे में नमक के बराबर भी काम नहीं हुआ । इस तहसील के लिये एक Drinking Water-supply की ज़रूरी स्कीम थी । वह स्कीम अंग्रेज़ के ज़माने से चली आ रही थी ।

[रंजीत सिंह कैंपटन]

परन्तु हमारी सरकार इतनी कंगाल थी कि वह हरेक स्कीम शुरु नहीं कर सकती थी। इस लिये मैं गुज़ारिश करूंगा कि अगर सरकार इस साल भिवानी को वह Drinking Water-supply की स्कीम नहीं दे सकी तो अगले साल वह ज़रूर दे।

इसके इलावा मैं Irrigation Minister से एक और अर्ज़ करना चाहता हूं कि हिसार के एक major का ७० cusecs पानी बंद किया गया है क्योंकि इस को आप भाखड़ा की नहरों से पानी देंगे। मैं अर्ज़ करता हूं कि वह 70 cusec पानी आप भिवानी को दें। मैंने engineers की भी राये ली है। वह कहते हैं कि वह पानी भिवानी को मिल सकता है। यह पानी अगर आप उस प्यासी तहसील को देंगे तो यह उन लोगों पर इहसान नहीं होगा. यह आप का फ़र्ज़ है। मैं समझता हूं कि अगर सारा सूबा तरक्की करेगा तो हमारा ज़िला पीछे नहीं रहेगा। परन्तु कुछ स्कीमें दो तीन साल से चली आती हैं वह अब पीछे पड़ गई हैं। मैं समझता हूं कि हमारे P.W.D. मनिस्टर हम पर कोई ज़ुलम करना नहीं चाहते हैं। वह स्कीमें ५७-५८ में जो दूसरा ५ साला plan बनना है उस में शामिल की जायेंगी। मैं तवक्क़ु रखता हूं कि यह चीज़ चाहे दफ़तर में हुई है और चाहे Government level पर हुई है इस बेइनसाफी को दूर किया जायगा।

जनाब स्पीकर साहिब! मैं एक गुज़ारिश और करना चाहता हूं। इस Budget में Agricultural College बनाने के लिये भी रुपया रखा गया है। मुझे इस बात से कोई गिला नहीं कि यह लुधियाना में क्यों बनाया जा रहा है। मेरे लिये जैसे करनाल, रोहतक और हिस्सार हैं वैसा ही लुधियाना है। मगर मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि इस समय हमारी सरकार को बेहद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाहिर से कर्ज़ा लेना पड़ रहा है, फिर भी खर्च पूरा नहीं होता। इन हालात में अगर यह college हिस्सार में जहां कि हज़ारों एकड़ सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है बनाया जाये, तो Government को ज़मीन पर रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा।

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ : ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।

श्री रंजीत सिंह कैंपटन : यह तो ग़लत बात हुई है। और फिर Veterinary college पहिले ही हिसार में मौजूद है, दोनों कालिजों का आपस में गहरा सम्बन्ध है। अगर Agricultural College भी वहीं खोला जाता तो विद्यार्थियों को बहुत आसानी हो जाती। (*Interruptions*) बेशक Veterinary College को लुधियाने में ले जाया जाये। दोनों एक जगह पर होने चाहियें। अगर किसी वक्त हम समझेंगे कि हम में ताकत है तो हम हरयाने के लिये कोई और चीज़ ले लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब वज़ीर साहिबान इस बहस को खत्म करेंगे। मुझे हाऊस को यह बताने में खुशी महसूस होती है कि बावजूद कुछ सदस्यों के नाराज़ हो जाने के ३३ सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया है और हाऊस के दोनों पक्षों को वक्त और बोलने वाले सदस्यों की तादाद के हिसाब से करीब २ बराबर हिस्सा मिला है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य वज़ीर साहिबान की तकरीरों को शान्ति से सुनेंगे।

सिंचाई मंत्री (चौधरी लहरी सिंह) : साहिबे सदर ! बजट पर की गई बहस का जवाब देने से पहले मैं अपने माननीय मित्र कैप्टन रंजीत सिंह के एतराजात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने जो बातें की हैं, उन से public खुश होने वाली नहीं हैं। उन से मैं यह कहना चाहता हूं, आपके वक्त में सारी ताकत आप के हाथ में थी, आप हर तरह के programme बना सकते थे। Agricultural College को इधर से उधर ले जाने का फैसला कर सकते थे। श्रीमान् जी, अब तो Agricultural College बनाने के लिये लुधियाने में ज़मीन खरीदी जा चुकी है, budget में provision भी कर दी गई है। अब क्यों हमारे दोस्त नाहक नुक्ताचीनी कर रहे हैं। इन बातों से वह लोगों की खुशनूदी हासिल नहीं कर सकेंगे। एक ऐसे सज्जन के मुंह से जो इतनी देर वज़ीर रहा हो ऐसी बातें कुछ अच्छी नहीं लगतीं।

उन्हों ने हिस्सार के ज़िले में पानी दिये जाने के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। यह बात ग़लत है कि हिस्सार के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। मैं उन को सूचित करना चाहता हूं कि हांसी को पानी देने के लिये सरकार ने बहुत सारा रुपया खर्च कर के 156 tube-wells लगवा कर, उन के पानी को 100 मील से ज्यादा दूर ले जाकर सुन्दरी नहर को जो साल में दो तीन महीने चलती थी perennial कर दिया है। क्या यह कम बात है ? मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि Government को यह ख्याल नहीं होता है कि यह रोहतक है, हिस्सार है या गुरदासपुर है। हमारे लिये सब इलाके पंजाब का भाग हैं और उन की development के लिये ज़रूरी कदम उठाना हमारा फरज़ है। सुन्दरी नहर से जिन किसानों को फायदा पहुंचना है, हमने सारा खर्च उन से नहीं लिया। अगर सारा खर्च betterment fees की शक्ल में उन से लिया जाता है, तो वह अदा न कर सकते। Sirsa Branch का पानी इस नहर में डाला जायेगा और कुछ पानी Western Jamuna Canal में भी डाला जायेगा ताकि हिस्सार के दूसरे इलाके और झज्जर के ग़रीब इलाके भी ज़िन्दा रह सकें। जिन जगहों पर सुकना था वहां पहिली अप्रैल के बाद नेशकर और कपास की फसलें उगाई जायेंगी।

फिर, मेरे दोस्त ने कहा है कि भिवानी की तहसील इतनी बड़ी है कि ज़िला जालन्धर का रकबा उस के रकबे से आधा है। मैं हाऊस को बताना चाहता हूं कि वहां पर दो नहरों की खुदाई हो रही है। वहां जुलाई में पानी चालू कर दिया जायगा (तालियां)। इस के इलावा लोहारू में tube-wells लगाने के लिये survey करने के लिये 15 अप्रैल को Government of India के कर्मचारियों की एक पार्टी आ रही है। वहां पर trial borings की जायेंगी और अगर पानी निकल आया, चाहे वह 700 फुट की गहराई पर ही क्यों न मिले वहां पर tube-wells लगाये जायेंगे। हमने रिवाड़ी, गुड़गांव और होशियारपुर के खुश्क इलाकों को जहां पर नहरें नहीं पहुंच सकती हैं पानी देने के लिये tube-wells लगाने की एक बड़ी स्कीम बनाई है। 42 trial borings में से, 17 गुड़गांव को, 7 या 8 ज़िला होशियारपुर की भिन्न २ जगहों को और कुछ लोहारू और झज्जर तहसील को allot की गई हैं। नारायणगढ़, रोपड़ और खरड़ तहसीलों में tube-wells लगाने के लिये भी trial borings मनज़ूर की गई हैं।

[सिंचाई मंत्री]

हमारे दिल में जालन्धर और अम्बाला divisions में तमीज़ करने का ख्याल कभी नहीं आया । Seventy-five per cent of the trial borings have been sanctioned for Ambala Division (*cheers*). मगर इस मामले में Ambala Division के साथ कोई रियायत नहीं की जा रही है । उस इलाके में जहां नहरें नहीं जा सकतीं सिवाये tube-wells लगाने के, पानी देने का और कोई साधन ही नहीं था ।

तो स्पीकर साहिब ! मैं उन से कहना चाहता हूं कि इतने छोटे ख्याल हमारे दिलों में नहीं आ सकते । हमने 42 टयूब वैल ज्यादातर गुड़गांव, होशियारपुर और अम्बाला के ज़िलों को ही दिये हैं और बाकी ज़िलों को जहां ज़रूरत थी थोड़े थोड़े दिये हैं । यह सरकार चाहती है कि किसी को ज़रा सा भी मौका न मिल सके यह कहने का कि किसी भी किसान या किसी ज़िमींदार को पानी नहीं दिया गया । मुझे यह सारी बातें इस लिये कहनी पड़ रही हैं क्योंकि मेरे भाई उज्र करते हैं ।

मेरे काबिल कम्यूनिस्ट और अकाली भाई बड़े नाज़ के साथ हाऊस में खड़े होकर कहते हैं कि यह बजट सूबे की development के लिये नहीं है । मैं उन से कहना चाहता हूं कि सरदार उज्जल सिंह जी ने जो बजट पेश किया है उस में फ़र्ज़ी आंकड़े नहीं हैं बल्कि यह बजट facts and figures पर based है । इसी लिये जब बजट स्पीच पढ़ी जा रही थी तो कदम कदम पर तालियां बजती रहीं थीं । इस से अच्छा बजट इस सूबा में कोई सरकार नहीं पेश कर सकती थी और इस के लिये हम को केंद्रीय सरकार से मुबारिकबाद आ रही है । अब वह वक्त नहीं जब कि हाऊस में बड़े बड़े भाषण दिये जाते थे और जाली facts और figures पेश किये जाते थे और अखबारों में छापे जाते थे । हम तो इस बजट की कापी को brief करवायेंगे और पंजाब में तमाम पंचायतों को भेजेंगे ताकि उन को मालूम हो जाए कि गरीब किसानों और देहातियों के लिये यह बजट कितना मुफ़ीद है ।

स्पीकर साहिब,! इस से आगे जो मेरे भाई एतराज़ करते हैं वह यह है कि सूबा में unemployment बहुत है, industrial development नहीं है । तो मैं उन से कहना चाहता हूं कि unemployment का मसला ज़बानी बातों से तो हल नहीं होगा और industrial development तो इसी तरह हो सकती है कि raw material ज्यादा पैदा हो । लोगों के लिये रोटी का इंतज़ाम हो । इस बारे में मैं अर्ज करूंगा कि जिस वक्त हमारे देश की तकसीम हुई थी उस वक्त 43 फीसदी population इधर आई थी और उस के मुकाबिला में 21 फीसदी पानी इधर मिला था । करीब करीब सारा खुश्क इलाका था लेकिन इन हालात के अन्दर भी हमारे Chief Engineers ने और हमारी सरकार ने इस ओर मुतवातर कोशिशें कीं । किसी को साल में ३ महीने पानी दिया किसी को थोड़ा और किसी को ज्यादा और इस तरह से इस सूबे को surplus बनाया । जब मैं किदवाई साहिब को पिछले दिनों मिला और अपनी demand पेश की तो उन्होंने कहा कि इस सूबे ने जिस प्रकार से दूसरों को चावल वगैरा दिये हैं और अनाज देने में मदद की है हम इस की मदद करेंगे और demand पूरी करेंगे । मेरा मतलब यह है कि हमारा ही पहला सूबा है जिस ने यह मिसाल कायम की है । बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि मैं अब कह

कर irrigation की demand पर दुहराना नहीं चाहता । लेकिन यह बात मैं आप भी कहूंगा और फिर भी कहूंगा कि दो तीन जिले —कांगड़ा, होशियारपुर और गुड़गांवा हैं जिन को शिकायत है । बाकी जिलों के मुतल्लिक मेरे M.L.A. भाई जानते हैं कि किसी प्रकार की शिकायत नहीं है और वहां पर नहरें और खाल्वाह निकाले जा रहे हैं। और दूसरी election के वक्त जब मेरे भाई पब्लिक के सामने जायेंगे तो उन को यह शिकायत कोई नहीं करेगा कि हमारे जिला में पानी नहीं मिला यह दूसरी बात है कि इस का credit भी मेरे Communist और अकाली भाई खुद ही ले लेवें । रही बात इन तीन जिलों की, उन के लिये हमने एक division कायम किया है । मुझे राओ गजराज सिंह जी शिकायत करते रहते थे कि हमारे साथ ठीक सलूक नहीं हो रहा, हम दिल्ली स्टेट के साथ मिल जायेंगे । चुनांचि वह division इस तमाम इलाके की survey करेगा मुमकिन है कि survey supplementary बजट तक ही मुकम्मल हो जायगी । और उस में इस इलाका की irrigation के लिये substantial scheme होगी । मेरे भाइयों को कोई शिकायत नहीं रहेगी । वे यह बात नहीं कह सकेंगे कि गुड़गांव को ignore किया जा रहा है ।

इस के बाद, स्पीकर साहिब! मैं चोओं के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । सब लोग जानते हैं कि हमारी सरकार होशियारपुर के बारे में कितनी दिलचस्पी ले रही है । मैं ने Finance Minister साहिब से दर्खास्त की और Cabinet ने 12 Overseers, Sub-Divisional Officers और Executive Engineer लगा दिये हैं । उन से कहा गया है कि मेहरबानी करके होशियारपुर का survey complete करो और वह पार्टी Survey कर रही है । जब यह survey मुकम्मल हो जायगी तो एक या दो Chief Engineers नहीं, ८७ लाख रुपया नहीं बल्कि दो करोड़ रुपया या इस से ज्यादा रकम भी खर्च कर सकेंगे । survey पूरी होने पर इकट्ठे बैठेंगे, स्कीम बनायेंगे जिस से कि तमाम M.L.A.s की तसल्ली हो जाये । नसराला चो का मसला हल करने के लिये हम हर पार्टी के M.L.A.s को साथ लेंगे । अगर पब्लिक की Co-operation न भी हुई तो भी सरकार इतना रुपया खर्च करेगी जिस से किसी को शिकायत न रह जाये । मैम्बर साहिबान को यह नहीं समझना चाहिये कि हमारी सरकार लापरवाही कर रही है । हमने 12 Overseers और 2 Sub-Divisional Officers मज़ाक के लिये या महिज़ शौक के लिये नहीं रखे बल्कि हमारा मुसम्मम इरादा है कि चोओं के बारे में लोगों को ज़रा भी शिकायत न रह पाये । इस लिये यह मसला हम सब भाइयों के साथ मिल कर हल करेंगे । गुड़गांवां और कांगड़ा के बारे में भी ज़रूर लोगों को तकलीफ़ है लेकिन इतनी नहीं जितनी कि ज़ाहिर की जा रही है । स्पीकर साहिब, सरदार प्रताप सिंह और सरदार उज्जल सिंह बल्कि सारी Cabinet की कोशिश है कि कुल्लू को Community Project Scheme के मातहत लाया जाये । इस सारे इलाके की development के लिये ६,७ लाख रुपया रखा गया है । हम केंद्रीय सरकार के मंत्री श्री किदवाई जी के पास गये और उन से कहा कि हमें इतनी ग्रांट दो जिस से हम किसी की शिकायत न रहने दें । तो मैं यह दोबारा यकीन दिलाना चाहता हूं कि चाहे हमारे सूबे के १२, १३ जिले ही हैं चाहे इन की

[सिंचाई मंत्री]
आमदनी limited सी है हम लोगों की कोई शिकायत नहीं रहने देंगे । लेकिन मेरे भाइयों को wait तो करना चाहिये । पहले लोगों का ख्याल नहीं था कि कभी भाकड़ा में भी पानी आ सकता है । मैं उन की इत्तलाह के लिये बताना चाहता हूं कि जून के पहले हफ्ते में पंडित नेहरू आयेंगे और उन को भी मद्दउ किया जायगा और सारी नहरों को चालू कर दिया जायगा । इस साल जो २२ करोड़ रुपया खर्च हो रहा है उस से सब इलाकों को पानी दिया जायगा ।

स्पीकर साहिब, जो लोग कहते हैं कि development नहीं हो रही है । मैं उन से अर्ज करूंगा कि मद्रास में मुझे पिछले दिनों एक Major General ने बताया कि हमारी फौजें जब पंजाब से गुज़रती हैं तो हमारी तबियत बहुत खुश होती है । हम देखते हैं कि जगह जगह पर नहरें खोदी जा रही हैं कदम २ पर पुल बनाये जा रहे हैं (*cheers*) । मेरे भाइयों को ऐसी बात कहते शरम नहीं आती । उन को यह पता नहीं है कि हमारी सरकार ने उन लोगों की तकलीफ को दूर कर दिया है जो नंगे भूखे रहते थे और जिन को १०, १० मील के फासले पर से ऊंटों पर पानी लाद कर लाना पड़ता था । हमारी सरकार ने उन के भले के लिये सारे Province में नहरों का जाल बिछा दिया है । पब्लिक पागल नहीं है कि आंखें मीच मीच कर उन के बहकाने से बहक जायेगी । लोग उन के ऐसी बातें करने से गुमराह नहीं होंगे । मैं उन को कहना चाहता हूं कि वे बजट को छोड़े, स्पीचों को छोड़ें और किसी मोटर या रेल गाड़ी में किसी तरफ जायें तो उन को चारों तरफ नहरों का जाल बिछा हुआ दीख पड़ेगा । ये सब बातें महज फीकी बातें नहीं हैं । हमारे देश में नहरें होंगी, कपास होगी और बिजली होगी । इन से industry की development होगी । हमारे Finance Minister साहिब ने उन लोगों की लिस्ट देखी है जो कि बाहर के प्रदेशों से आकर यहां पर अपनी industry कायम करना चाहते हैं । कोई Bhiwani और कोई सरसा में अपनी industry लगाना चाहता है । इस से यहां की unemployment काफी हद तक दूर हो जायगी ।

आप इस के लिये रूस की हिस्ट्री को पढ़ें । आप को पता लगेगा कि electric power के बगैर मुल्क में कोई भी तरक्की नहीं हो सकती । हमारा प्रोग्राम क्या है ? यह आपने बजट को पढ़ कर आसानी से अंदाजा लगा लिया होगा । जहां जून के महीने में हम भाखड़ा कैनाल का पानी चलता कर देंगे वहां हम आप को अगस्त के महीने में नंगल से इतनी बिजली देंगे कि आप को कोई शिकायत नहीं रहेगी (तालियां) । जब बिजली हमारे पास होगी, material हमारे पास होगा तो निश्चय ही मुल्क की सनअत बढ़ेगी, तरक्की होगी और लोग खुशहाल होंगे । आप जो unemployment का हौआ हमें नज़र आ रहा है इस से हम कभी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते और यह कभी दूर नहीं हो सकती जब तक कि देश की industry न बढ़े, देश की पैदावार न बढ़े और यह सब कुछ तभी हो सकता है जब industries को चलाने के लिये बिजली अच्छी खासी मिकदार में दस्तयाब होती हो ।

फिर हम शहरों में ही बिजली नहीं देंगे, गांवों में भी देंगे । स्पीकर साहिब, आप की वसातत से मैं अप्पोज़ीशन के भाइयों की जानकारी के लिये बता दूं कि हम ने इस साल ९४ गांवों को electrify किया है । भाखड़ा नंगल की बिजली से नहीं । दूसरे तरीकों से आने वाले माली साल में हम 306 और नये गांवों को electrify कर देंगे । इस के इलावा 37 नये towns को भी । मैं तो कहता हूं स्पीकर साहिब हमने किसी गांव या कस्बे को electrify किये बगैर नहीं छोड़ना है । तमाम गांव और तमाम शहरों को बिजली देंगे । Tube-wells से पानी निकालने के लिये बिजली मुहैया करेंगे । और शहरों में नई Industries चलाने के लिये भी बिजली देंगे । बड़ी बिजली पैदा होने वाली है हमारे सूबा में । Ohl नदी और thermal plants के इलावा चार लाख किलोवाट इस नंगल से पैदा होगी । इस लिये मैं फिर आप को यकीन दिलाता हूं कि हम हर गांव को बिजली देंगे, हर शहर को बिजली मुहैय्या करेंगे । हम कोई discrimination नहीं रखेंगे जैसा कि आपोज़ीशन वालों को अंदेशा है । उन का यह भ्रम है । आखिर गांव में बिजली के लिये जो ऊंचे ऊंचे tower लगाये जा रहे हैं वह तो इन्होंने स्वप्नों में भी नहीं देखे होंगे । आखिर वे towers जो गांव में जगह जगह पर ज़िमींदारों के खेतों में लगाये गये हैं, वह कोई शान बढ़ाने के लिये नहीं लगाये गये हैं । वे इस लिये नहीं लगाये गये कि उन के नीचे जलूस निकालने हैं । उन के ज़रिये हम गांव वालों को बिजली देंगे । बिजली से मुल्क की पैदावार बढ़ेगी और इस तरह unemployment खत्म होगी । मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल आप को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा ।

चूंकि अब टाईम थोड़ा है और फाईनेंस मिनिस्टर साहिब ने भी अपनी तकरीर फरमानी है, इस लिये बाकी चीज़ों पर और खास तौर से industries की हालत पर वे ही रौशनी डाल देंगे । इन लफ़ज़ों के साथ, स्पीकर साहिब मैं अपनी जगह पर बैठता हूं ।

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਉਜੱਲ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਲਭ ਕੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਤਕ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨਿਸਟ੍ਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਉਤੇ ਬਠਾਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਨੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ (Budget Speech) ਵਿਚ ਅਗੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀ ਕਹਿਣਾ

[ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਖਾਸਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19½ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਖਰਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰਚ ਨਾਲ 3½ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਬਹੁਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਅੱਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ (leader of the Opposition) ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੇਡਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ "ਏ ਕਲਾਸ" ਸੂਬੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਿਲਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ "ਸੀ ਕਲਾਸ" ('C' Class) ਸਟੇਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਅਗਰਚਿ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ 50 ਰੁਪਈਏ ਮਾਹਵਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾਕੇ 60 ਰੁਪਈਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ (ਤਾੜੀਆਂ)। ਤੁਸੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲਉ। ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 47½ ਰੁਪਈਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਰੁਪਈਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ।

ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਥੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦਸਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਮਧਯਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੇਡ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦਸ ਦਿਆਂ। ਬੰਬਈ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ । ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਪਲੇ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਹੁਣ 20 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਬੜ੍ਹੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਰੇਡ ਹੁਣ 110—8—190/10—250 ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਗਰੇਡ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਟੇਜਾਂ ਹਨ । ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿਚ 50 per cent ਦੂਜੀ ਵਿਚ 35 per cent ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਚ 15 per cent ਅਧਿਆਪਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ (time-scale) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਥਲੇ ਦੇ 50 per cent ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇਕਦਮ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 per cent ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਪਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਿਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹ ਮੁਕਾਬਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਨੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਖਰਚਾਂ ਵਿਚ ਕਫ਼ਾਇਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ । Economy ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਉਂਸ ਗਿਨਾਇ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਓ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟਾ ਦਿਓ । ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਰੇਟਰੀਆਂ, ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ posts ਨੂੰ abolish ਕਰ ਦਿਓ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਪਰ ਹਾਓਸ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਪਰ ਹਾਊਸ ਰਹੇ ਯਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਨਾਉਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੋੜਣ ਦਾ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Upper House ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਠਾਇਆਂ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉੜਾਉਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਕੁਹਾਉਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ Constitution ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਨੀ ਹੈ ਉਹ constitutional ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋੜੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਬਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ economy ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ । ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਉੜਾਉਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੋਸਟ ਘਟਾਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ posts ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਪਿਲੇਟ ਅਥਾਰੀਟੀ (appelate authority) ਹੈ

[ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਸੁਨਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰੇਵੀਨੀਊ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ duties ਵੀ ਉਸਨੇ ਨਿਭਾਉਨੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਰਾਇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਲੋਕਰਾਇ ਨੂੰ ਸਾਮ੍ਹਨੇ ਰਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਿਛੇ-ਖਿਚੂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਬਾਕੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, Secretaries' salaries ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕੁਝ ਕਹਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਵਾਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। Special pays ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਘਟਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ Central Government ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ allowance ਨੂੰ ਵੀ ਘਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਇਹ ਗਲ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਂ special pays ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬਾਕੀ allowances ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਣਾਂ ਚਾਂਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕ ਇਕ allowance ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ allowances ਦੀ ਮੱਦ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ 31 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਫਸਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਕਫ਼ਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਿਤ੍ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਦਾਰੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਆਮ ਗਲ ਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਗੱਲ ਕਹਿਨੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰਕਾਦਾਰੀ ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਆਪਨੇ ਹਥ ਆਪ ਹੀ ਕਟ ਕੇ ਇਹ ਇਖ਼ਤਿਆਰ Public Service Commission ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਅਫਸਰ ਆਪਨੇ ਆਪਨੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ

ਵਿਚ ਵਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ Subordinate Services Selection Board ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਇਹ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਵਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ State ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਇਆ : ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀ ਚੜ੍ਹੀਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸਾਂ ਸਭ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਲੈ ਕੇ Subordinate Services Selection Board ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਅਸੂਲ ਵੀ ਬਨਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ senior ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ junior ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ Subordinate Services Selection Board ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਖ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕੀ ਠੀਕ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਅਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਨੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆਪਨੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟਟੋਲਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।

ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਜਦੋਂ ਜੁਰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਸਚ ਮੁਚ ਜੁਰਮ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। Murders ਘਟ ਗਏ ਨੇ dacoities ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ robberies ਦੇ cases ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਘਟਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁਰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਚੋਖੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਓਂ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਰਚ ਉਤੇ ਕੜਾ control ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀ ਵਧਨ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੱਦ ਤੋਂ ਰਕਮ ਬਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਵਿਚੋਂ border police ਦਾ ਖਰਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ Border State ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Border Police ਦਾ ਖਰਚ 64 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਰਚ

[ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਨ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸਾਂ ਆਪਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ total ਖਰਚ ਵਿਚੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਰਚ ਕਢ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਰਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਰਚ ਆਪਨੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਦਾ 8 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ 9 ਫੀ ਸਦੀ, ਮਦਰਾਸ ਦਾ 9 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਿਆਰਾਂ ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ $8\frac{1}{2}$ ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਹਨ। ਇਥੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢੂੰਡਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖਿਆਈ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਨੇ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕੂ ਤਾਂ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਸ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛੋਂ ਖੱਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਤਹਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹੁਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਗਾਧਰੀ ਦੀ abducted girls ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਢ ਸਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਕ ਮਿਤ੍ਰ ਨੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨ ਕੇ ਬੜਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਾਨਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਓਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਓਨ੍ਹਾਂ ਲਈ human nature ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਟੋ ਘਟ ਮੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਨੇ ਬੈਠੇ ਮਿਤ੍ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਤਾਂ ਲੈਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਦਬੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਢਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹ ਹਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰੇਸ ਪਾਰਟੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਾਂਹ ਚੁਕਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਓਂ ਭੁਲ ਗਏ ਨੇ।

ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰਾਇਜ ਛੂਤ ਛਾਤ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਛੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ political, economic ਅਤੇ social disabilities ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੰਬਰਦਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ

ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਦਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 19 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 21 ਫੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ (ਤਾੜੀਆਂ) ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ (reserve) ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭੀ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹਨ । Age limit ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ minimum qualification ਭੀ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ (service) ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬਲਾਕ ਸਿਸਟਮ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 5 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਸਾਮੀ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਤਾੜੀਆਂ) ਜੇਕਰ ਹਰੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੀ ਆਦਮੀ ਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 5 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਨਗੀਆਂ । ਹਾਂ ਇਹ ਗਲ ਜੁਦਾ ਹੈ ਕਿ minimum qualifications ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹਰੀਜਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 25 ਆਦਮੀ ਕਲਾਸ II ਦੇ ਹਨ, 2,034 ਕਲਾਸ III ਅਤੇ 2,200 ਕਲਾਸ IV ਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਿਚ 2 ਅਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । (*Interruption*) ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੱਰਰਾ minimum qualifications ਦੇ ਆਦਮੀ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ।

ਫਿਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ Legislature ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਰੀਜ਼ਰਵ (reserve) ਹਨ । ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਿਸਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਿਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ । (ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਵਲੋਂ ਵਿਘਨ)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਈ ਬਾਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ *interruption* ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿਘ ਧੂਤ : ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ! ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਾਰੀ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾ ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਘਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, Legislature ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਅਠ ਨੌਂ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਿਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਇਹ ਖਰਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ।

[ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਨਿਕੰਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਅਤੇ landless tenants ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਹਜ਼ਾਰ families ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ families ਹਰੀਜਨ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ industry ਨੂੰ subsidy ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਬੋਰਡ ਭੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਿਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 75 ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ subsidy ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਇਸਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੇਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨ ਭੀ ਹਿਸੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਉਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। (ਤਾੜੀਆਂ)

ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ civil liberty ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਖੁਦ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ article ਭੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ (ਤਾੜੀਆਂ) ਇਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਜ਼ਾਦ ਰਹਿ ਸਕੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। (ਤਾੜੀਆਂ)

ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤਰਾਂ ਨੇ Transport Nationalisation ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ Ministry ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਸਟ ਵਜਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਥ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। Transport Nationalisation ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ Nationalisation of Transport ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ nationalise ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਨੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । (ਪ੍ਰਸੰਸਾ) ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ । ਜਨਤਾ ਜੋ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਧ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵਧ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਮੁੜ ਪਬਲਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਘਾਟੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 63 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਬਸਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ 29 ਲਖ ਰੁਪੈ ਦੀ ਰਕਮ ਖਾਲਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਵਿਚ ਰਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । 78 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ depreciation ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਲੇਹਦਾ ਰਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ।

ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਛਡ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਬਾਕੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਣੀਆਂ ਪਾਸ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਸਾਂ ਹਨ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲਖ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 234 ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ 234 ਬਸਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਇਕ ਲਖ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ 29 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੂਦ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 1954 ਤਕ 9½ ਲਖ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1951-52 ਵਿਚ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਸੀ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਯਾ ਨਾ ? ਪਰ ਖੈਰ, ਕੇਬੀਨਟ (Cabinet) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ figures ਤਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਘਸਾਈ (depriciation) ਤੇ ਸੂਦ ਕਢ ਕੇ ਵੀ 9½ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ 50 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ beneficent departments ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

[ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਏ ਪਰ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਈਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਲਗੇ ਰਹਿਨ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਗੋਂ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਕੁਝ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂ ਗੇ।

ਮੇਰੇ ਮਿਤਰ ਰਾਓ ਗਜਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਅਜਕਲ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਦਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬਜਟ ਜੇਕਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਨੋਟ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਰੀਜ਼ਰਵ (ਜਮਾ) ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲਭ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਅਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ? ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਖਰਚ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਇਕ ਪਾਈ ਵੀ productive ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਛੁਟ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਨਤੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੀਏ। ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਫਿਰ ਦਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਫਿਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। settlement ਅਤੇ resettlement ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਰਥਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਇਆਂ ਚਾਲੀ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਹੁਣ settlement ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ settlement ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਭਰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1. matured area, 2. ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ 3. ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧਨਾ। ਚੂੰਕਿ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਐਸੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛੋਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਬੀਆਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਹਨ। ਅਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇਹਸਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮੇਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ੧੦ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੀਏ (ਵਾਹ ਵਾਹ)।

ਫਿਰ sliding scale ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ sliding scale ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਗਿਰਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਮਿਤਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ 10,000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ? ਇਹ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਟਰਾਈਕਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ industrialists ਨੂੰ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਹੋਰ ਰੁਪਿਆ invest ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਿਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਣ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ industrialists ਨੇ industry ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ invest ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ industry ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੌਲਾ ਪਾਣ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ? ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਗੀ ਮੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ।

[ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਿਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ depression ਅਤੇ unemployment ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਮਹਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਦੇ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ Exchanges ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਮ register ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਲਰਕੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਲੋਕੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1951 ਵਿਚ 107,239 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਂ register ਕਰਾਏ ਅਤੇ 31,923 ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। 1952 ਵਿਚ 116,898 register ਹੋਏ ਤੇ 32,356 ਨੂੰ ਜਗਾਹ ਮਿਲੀ। ਫੇਰ 1953 ਵਿਚ register ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ 117,221 ਅਤੇ ਜਗਾਹ ਮਿਲੀ 22,438 ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ register ਕਰਉਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਭਣ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੜਾ ਮੁਗ਼ਾਲਤਾ ਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ Public Service Commission ਅਤੇ Subordinate Services Selection Board ਸਿਧੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ centre ਵਾਲੇ Employment Exchanges ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਗਲ ਇਹ ਦਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗਿਰਨ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਮੰਦਵਾੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਥੇ ਮੰਦਵਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਭ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਕਮਯੂਨਿਸਟ ਮੈਂਬਰ: ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਡਦੇ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਲ ਜਾ ਵੇਖੋ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਪਰ, ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (laughter) ਫੇਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੂੰ economists ਲੋਕ depression ਆਦਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਦਵਾੜਾ ਆਵੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ 38 ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਨਹਿਰ ਬਣ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 3 ਲਖ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ (*Hear, hear*)। Planning Commission ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 3½ ਲਖ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਲਖ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਫਰਾਖੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ station ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕ ਮੰਡੀ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 10,000 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ 14,000 ਟੀਚਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ illiteracy ਵੀ ਕੁਝ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਕਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 50,00,000 ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਸਿਰਫ਼ ਰੁਪਿਆ ਰਖਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਕਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ (*Hear, hear*) । ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਤਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਤੇ overseer ਵਗੈਰਾ ਪਲਨਗੇ । ਅਸੀਂ waste lands ਆਦਿ ਇਸੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧੇ । ਇਸ ਤੋਂ $4\frac{1}{2}$ ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਹੋਰ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । Land utilisation ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਹੋਵੇ । ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਟੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਆਪ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 120,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਬਾਦ ਹੋ ਵੀ ਚੁਕੀ ਹੈ (*Hear, hear*) ।

ਫੇਰ ਅਸੀਂ cottage ਅਤੇ small scale industries ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਏਸ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਸ ਮਦ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਰਖੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਬੇਕਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧੇ ।

ਫੇਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਭਰਾ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਮੈਂ ਅਜ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਰੁਪੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿਆਂਗੇ (*Hear, hear*) । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ । ਫੇਰ ਉਹ ਲਾਟੂ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੀਕਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਕੋਇਲਾ ਲਕੜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਵਧੇਗੀ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ cooker ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ cooker ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਮੁਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣ । Domestic consumption ਦਾ tariff rate ਵੀ ਇਸੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਘਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਲਗਾਣ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਫੇਰ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਦਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1950 ਵਿਚ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ connection 2,850 ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ 6,300 ਹਨ । ਗੋਯਾ 2 ਸਾਲ ਵਿਚ double ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲੇ ਨੰਗਲ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

[ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਪੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ, ਖਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਹੁਣ control ਦੇ ਹਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਪੜੇ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਖਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਵਲੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਸਨਅਤ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਖਡੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਤ ਸਸਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। Designing ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ rates ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ rate Industry ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ ਸਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ rate ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ industry ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟ੍ਰਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਵੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ load ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ connection ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ reconsider ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ industrialists ਦੀ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੀ industry ਲਈ ਜਿਹੜੇ rate ਹਨ U. P. ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ industrialists ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ Five-Year Plan ਉਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। Chamber of Commerce ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਇਕ ਮੈਂਬਰ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੋ ਗਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।) ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ plan ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਫੌਰਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ modest ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ plan ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਜ਼ੂਲ ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ plan ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ Agriculture, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, Community Projects ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Agriculture ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀ? ਕਪੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਝ

target ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ? ਇਹੋ ਹਾਲ ਖਾਦ ਤੇ cement ਦਾ ਹੈ। Minor Irrigation Schemes ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ programme ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਏਹੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ steel plant ਲਗਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ progress ਹੋਰਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਕ German Firm ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Refinery ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲ ਕਰੋ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : Five-Year Plan ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੇ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਉਸ ਤੋਂ $1\frac{1}{2}$ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੀਏ।

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ Backward areas ਤੇ labour ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜੇਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ Minimum Wages Act ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ Industry ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ agricultural labour ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਾਂ Plantation Labour Act ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ Employees Provident Fund Act ਅਤੇ Health Insurance Act ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ Central Government ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਂ labour ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ Co-operative Societies ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ।

ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Road Development Programme ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰੁਪਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਲ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਵਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ road mileage 313 ਮੀਲ ਬਨਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $2\frac{1}{2}$ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। Community Project ਦੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਨਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਆਪ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧਾ ਰੁਪਿਆ contribute ਕਰੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Civil Administration ਨੇ ਕਾਫ਼ ਵੱਧੀ ਹੈ

[ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ ਆਦਿ ਤੇ ਖਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਖਰਚ ਦੀ percentage 27 ਤੋਂ 23 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 23 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਆਬਾਦ ਕਰਣ ਦੀ ਅਰਥਾਤ Rehabilitation Policy ਨਾਕਸ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ Landlordism ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉਥੇ 4,000/5,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹ ਏਥੇ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ (allotment) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ 25 ਫੀ ਸਦੀ cut ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਵਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, 95 ਫੀਸਦੀ cut ਲਗਾਈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। Standard ਏਕੜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ Director of Rehabilitation ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ standard acre ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ working expenses ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਯਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ pumping sets ਅਤੇ fertilizers ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਕਾਵੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿਤਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲਗਾ ਹੈ। ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ fertilisers ਦਿਆਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ fertilisers ਦੀ ਵੰਡ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Irrigation ਦੇ working expenses ਇਸ ਲਈ ਵਧੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਚੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ejectment notice ਮਿਲ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗ ਭਗ 60,000 ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਗਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ 7,191 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ

5,615 cases ਵਿਚ ਬਾਹਮੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 92 cases ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੇ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਹੈ :—

ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ		104 ਕਰੋੜ
ਹਰੀਕੇ ਸਕੀਮ		8 ਕਰੋੜ
ਬਿਜਲੀ		1 ਕਰੋੜ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨ ਉਪਜਾਉ ਤੇ		
Minor Irrigation Scheme	..	8 ਕਰੋੜ
Rehabilitation Loans Pumping Sets, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਲਈ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਲਈ	..	9 ਕਰੋੜ
Due Capital	..	5 ਕਰੋੜ
Miscellaneous	..	3 ਕਰੋੜ
ਕੁਲ	..	138 ਕਰੋੜ

ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ common man ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ common man ਦੇ ਸਵਾਇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Road Programme ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ dispensaries ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। Ayurvedic Dispensaries ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। Anti Malaria Scheme ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਲਈ fertilisers ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

[ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ]

Pumping Sets ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ extension ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 306 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ Pumping Sets ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ tube-wells ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਹ ਇਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ item ਹੈ ਜਿਹੜੀ common man ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨ ਹੋਵੇ ? ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਰਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

The Assembly then adjourned till 2 p.m. on Thursday, the 18th March, 1954

206 P.S.L.A.—283—26-11-54—C.P. & S. Pb., Chandigarh.

Punjab Legislative Assembly Debates

18th March, 1954

VOL. I, NO. 9

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, 18th March, 1954.

CHANDIGARH :
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab,
1954

Price : Re. 0-8-0

PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY

18*th* *March*, 1954

The Assembly met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital, at 2 p. m. of the clock. Mr. Speaker (Dr. Satyapal) in the Chair.

QUESTION HOUR (DISPENSED WITH)

अध्यक्ष महोदय : मैम्बर साहिबान की खाहिश का एहतराम करते हुए आज फिर Question hour dispense with किया जाता है ।

DEMAND FOR GRANT

General Administration

Chief Minister. (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I beg to move—

> That a sum not exceeding Rs. 1,45,51,800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year 1954-55 in respect of General Administration.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That a sum not exceeding Rs. 1,45,51,800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year 1954-55 in respect of General Administration.

अध्यक्ष महोदय : मैं आप की खिदमत में यह अर्ज़ करना चाहता हूं that the following motions or cut motions will be deemed to have been moved. अब यह सब आप के सामने हैं । इस लिये जिन साहिबान ने cut motions का नोटिस दे रखा है, जब व तकरीर करने उठेंगे तो उन के बारे में यह समझा जाएगा कि उन की motion या cut motion originally move हो चुकी है ।

1. **Shri Daulat Ram Sharma :**

   that item of Rs. 2,69,880/- on account of h-1—Ministers be reduced by Rs. 100/-:

2. **Shri Wadhawa Ram :**
3. **Sardar Darshan Singh :**
4. **Sardar Bachan Singh :**
5. **Sardar Chanan Singh Dhut :**
6. **Sardar Harkishan Singh Surjit :**

7. **Sardar Achhar Singh Chhina :**

That item of Rs. 3,76,820 on account of h-1—Ministers and (h) 2—Purchase and mainte nance of cars of Ministers and Deputy Ministers be reduced by Rs 1,50,000/-

8. **Shri Wadhawa Ram :**

9. **Sardar Bachan Singh :**

10. **Sardar Achhar Singh :**

11. **Sardar Chanan Singh Dhut :**

12. **Sardar Darshan Singh :**

13. **Sardar Harkishan Singh Surjit :**

That item of Rs. 3,21,220/- on account of (i) Legislative Council be omitted.

14. **Shri Wadhawa Ram :**

15. **Sardar Darshan Singh :**

16. **Sardar Bachan Singh :**

17. **Sardar Chanan Singh Dhut :**

18. **Sardar Harkishan Singh Surjit :**

19. **Sardar Achhar Singh Chhina :**

That the demand be reduced by Rs. 15 lakhs.

20. **Pandit Shri Ram Sharma :**

That the demand be reduced by Rs. 100/-

21. **Shri Ram Kishan :**

That the demand be reduced by Rs. 100/-

22. **Shri Babu Dayal :**

23. **Maulvi Abdul Ghani Dar :**

That the demand be reduced by Rs. 100/-

24. **Shri Babu Dayal :**

That the demand be reduced by Rs. 100/-

25. **Maulvi Abdul Ghani Dar :**

26. **Shri Babu Dayal :**

That the demand be reduced by Rs. 100/-

27. **Shri Ram Sarup :**

That the demand be reduced by Rs. 100/-

28. **Shri Ram Kishan :**

That the demand be reduced by Rs. 100/-

29. **Shri Ram Chandra Comrade :**

That the demand be reduced by Rs. 100/-

30. **Shri Rala Ram :**

That the demand be reduced by Re. 1/-

31. **Rao Gajraj Singh :**

That the demand be reduced by Re. 1/-

32. **Shri Mool Chand Jain :**

That the demand be reduced by Re. 1/-

33. **Shri Kasturi Lal Goel :**

That the demand be reduced by Re.1-

34. **Shri Ram Chandra Comrade :**

That the demand be reduced by Re. 1/-

35. **Sardar Ajmer Singh :**

That the demand be reduced by Re. 1/-

36. **Sardar Wazir Singh :**

37. **Sardar Sarup Singh :**

38. **Master Partap Singh :**

39. **Sardar Iqbal Singh :**

That the demand be reduced by Re. 1/-

40. **Shri Dharam Vir Vasisht :**

That the demand be reduced by Re. 1/-

41. **Shri Khushi Ram Gupta :**

That the demand be reduced by Rs. 100/-

42. **Bakhshi Partap Singh :**

That the demand be reduced by one per cent.

43. **Shri Chand Ram Ahlawat :**

That the demand be reduced by Rs. 100/-

44. **Shri Ram Parkash :**

That the demand be reduced by Rs. 100/-

45. **Shri Teg Ram :**

That the demand be reduced by Rs. 100/-

46. **Sardar Khem Singh Tung :**

That the demand be reduced by one per cent.

47. **Sardar Darbara Singh :**

That the demand be reduced by Rs. 100/-

Mr. Speaker : Now I call upon Sardar Wazir Singh to Speek.

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ (ਡੋਲਹੋਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ General Administration ਦਾ morale ਬਹੁਤ low ਹੋਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਕਈ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, General Administration ਦੇ low morale ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ Administration ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਬੜਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ honest ਜਾਂ straight forward ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਖਵਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਾਰਾਂ ਲੈਕੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ rest-houses ਵਿਚ ਜਾ ਠੈਹਰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਰਦਾ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਅਨਵਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਥੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ accommodate ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ Administration ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

मुख्य मंत्री: माननी मैंम्बर आम बात न करें। वह definet cases बताएं। इस तरह से general बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं।

ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ : ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਵਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ Education Minister ਦੇ ਮਿਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਤੀ ਚੰਦਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲ ਆਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਇਤਆਦਿ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨਿਸਟ੍ਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ workers ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਵਾ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਕੰਮ ਕਰਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Administration ਦਾ morale ਉਦੋਂ ਤਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ Administration ਦੀਆਂ ਇਹ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਆਦਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ Head of the Departments ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Depot ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਾਂਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇਣ, ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਜ਼ (Workers) ਦੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਠੇਕੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਮ ਕਾਜ ਦੂਜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਿਏ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਚੂੰਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰੇਸ ਕਮੇਟੀ

[ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ]

ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ ਹੋਇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਪਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਮੁਨਵਨ ਸਿੰਘ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਉਸ (ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਪੁਛਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ Head of the Departments ਦਵਾਰਾ ਰੋਅਬ ਪਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ (local bodies) ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨਿਸਟਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ੨ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਉਤੇ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ disqualify ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਖਦਾ ਉਹਦੇ ਮਿਊਨਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ disqualify ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ party in power ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਬਮੂਜਬ ਨ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨਿਸਟਰ Administration ਦੇ ਕੰਮ

ਵਿਚ ਦਖ਼ੱਲ ਦੇਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੱਰਕੀ ਵਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਨ ਦੀ ਖਾਤਰ Administration ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਉਹ interference ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਡ ਦੇਣ ਤੇ Administration ਨੂੰ ਖੁਲੇ ਹਥ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ Administration ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦੱਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ Deputy Commissioner ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਇਹ ਹੀ ਇਲਤਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਆਪ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕੇ Administration ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ Administration ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਊਬ ਨਾ ਕਰੋ।

श्री रलाराम (मुकेरियां): अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति इस राज्य की आज की स्थिति पर नज़र डालता है उसे स्वीकार करना पड़ता है कि एक बड़ी बात जिस के लिये हम अपनी मिनिस्टरी को सच्चे हृदय से बधाई दे सकते हैं वह यह है कि इस ने Administration की moral tone तथा इख़लाकी मेयार को ऊंचा करने की हर तरह से कोशिश की है। कोई व्यक्ति जो बाहर के जिलों से ताल्लुक रखता है और वहां काम होता हुआ देखता है, इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि यह मिनिस्टरी प्रान्त की तरक्की के काम कर रही है। Democracy प्रजातन्त्र, के साथ जो spoilt system का नाम जुड़ा हुआ है और जो हम प्राय: सभी देशों में देखते है, हमें यह कहने में बड़ी खुशी होती है कि हमारी सरकार यह प्रयत्न करती है कि यह spoil system का नाम भी हमारे Administration के साथ किसी तरह से जुड़ा न रहे। यह देख कर किस को खुशी न होती होगी कि favouritism, nepotism ,रियायत लिहाज और कुम्बापर्वरी की शिकायात को दूर करने के लिये हकूमत ने जो सब से बड़ा कदम उठाया है वह यह है कि उन्होंने छोटी मोटी नौकरियों की recruitment को भी अपने हाथ से निकाल कर Subordinate Services Selection Board के सुपुर्द कर दिया है। क्या हम यह बात गर्व के साथ नहीं कह सकते कि इस किस्म की मिसाल

[श्री रला राम]
हमें बाकी देशों में भी और अपने देश में भी कहीं नहीं मिलती । हरेक हकूमत कोशिश करती है कि patronage उस के हाथ में बनी रहे । यह तो हमारी मिनिस्टरी की नेकनियती है कि उन्होंने ऐसा किया है । They want to give the State a clear and an efficient administration उनकी यह खाहिश है कि सूबे को शुद्ध और बहुत ही कुशलतापूर्ण शासन मिले । इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उस का अपने हाथ से patronage को Sabordinate Services Selection Board के सुपुर्द कर देना, मैं समझता हूं इस बात का एक बड़ा प्रमाण है कि हमारी हुकूमत यह कोशिश कर रही है कि शासन का इखलाकी मेयार हर तरह से ऊंचा हो, और जो व्यक्ति इस बात से इन्कार करता है. वह इस कार्यवाही की अहमियत को समझने से कासिर है कि यह बड़ा कदम हमारी हकूमत ने Administration के इखलाकी मेयार को ऊंचा करने के लिये उठाया है और हम यह बात फ़खर से कह सकते हैं कि हमारे शासन में कुटुम्ब पालन रियायत और लिहाज़ की instances अर्थात मिसालें, निरन्तर कम होती चली जा रही हैं । यहां तक कि बाज़ लोग तो यह कहने लगे हैं कि अब आप की पार्टी के हाथ में रहा ही क्या है कि लोग आप की पार्टी की तरफ झुके रहें । लोग भले ही ऐसी बातें कहते रहें । यह तो प्रमाण है इस बात का कि हमारी हकूमत नेकनियती से Administration की morale को ऊंचा कर रही है और इस बात से इनकार करना, मैं समझता हूं, जान बूझकर सचाई से आंखें बन्द करना है ।

जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारे वज़ीर साहिब tours पर जाते हैं, पार्टी के मैम्बरों से मिलते हैं, इस बारे में मैं अर्ज़ करूंगा कि democracy को कामयाब करने के लिये यह एक निहायत ही अच्छा तरीका है । मिनिस्टर साहिबान प्रजा के Contact (सम्पर्क) में रह कर उस की तकलीफ़ों को जान सकते हैं । अगर मिनिस्टर दौरे पर न जायें तो विरोधी पक्ष के लोग कहेंगे कि प्रजातन्त्र राज्य के मिनिस्टर तो अपनी कोठियों से बाहर निकलने की तकलीफ गवारा नहीं करते और अगर tours पर जाते हैं तो भी उन्हें attack का target बनाया जाता है । मैं समझता हूं कि ऐसी आलोचना रचनात्मक आलोचना नहीं है । प्रजातन्त्र को कामयाब बनाने के लिये मिनिस्टरों को चाहिये कि वे tours करें और गांवों के निवासियों के कष्टों को अपनी आंखों से देखें ताकि उन्हें दूर किया जा सके । मुझे अपने ज़िले का अनुभव है । वहां जब भी मिनिस्टर जाते हैं तो वे कभी किसी मैम्बर को अफसरों से इस तरह introduce नहीं कराते कि यह हमारे खास प्रिय मैम्बर हैं, इन का ध्यान रखें । (तालियां) ऐसी बातें बेबुनियाद हैं कि मिनिस्टरों की वाकफियत को exploit करके अफसरों को influence किया जाता है । यह इलज़ाम निराधार है । महज़ इस बात के लिये मिनिस्टरज़ की आलोचना करना कि वह कभी २ गवर्नमेंट का थोड़ा सा पैट्रोल खर्च कर के प्रजा से contact जनता से सम्पर्क बनाये रखते हैं, democracy को कामयाब नहीं बल्कि फेल करने वाली बात है । इस लिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा शासन को बधाई देना चाहता हूं कि वह निरन्तर इस कोशिश में हैं कि Administration का moral tone

ऊंचा हो और मैं यह कहने में हकबजानब हूं और मैं यह बात सामने बैठे सज्जनों तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम मैम्बरान का यह feeling है कि मिनिस्टर साहिबान Administration में अनुचित मुदाखलत नहीं करते और हम दावे से कह सकते हैं कि हम जहां कहीं भी हों इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो काम अफसरान के करने का है वह उन्हीं के ज़रिये हो। हां अलबत्ता अगर यह सज्जन यह चाहें कि हम अपने हल्के के लोगों की शिकायात मुनासिब वक्त पर अफसरान तक न ले जायें तो हम अपने फर्ज से कोताही करेंगे। अगर यह सज्जन इस बिना पर किसी गल्तफहमी में मुबतला हो जायें तो हम मजबूर हैं। मैं निवेदन करता हूं कि यह हमारा कर्तव्य है और हम कांग्रेसी इस कर्तव्य पालन का प्रयत्न करते हैं। जब भी अपने लोगों की शिकायत को अफसरान तक ले जाने का अवसर होता है हम उससे चूकते नहीं। इसलिये मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मिनिस्टर साहिबान या कांग्रेस पार्टी के मैम्बर Administration में कभी भी बेजा मदाखलत नहीं करते और न कभी करेंगे क्योंकि वे अपने कर्तव्य को अच्छी तरह समझते हैं।

दो और बातें हैं जो मैं खास तौर से मिनिस्टरी तक आप के द्वारा पहुंचाना चाहता हूं। यह ठीक है कि corruption दूर करने का बड़ा भारी प्रयत्न किया गया है। जब हम जिला के अफसरान से मिलते है तो हमें यह अनुभव करके खुशी होती है कि अफसरान के higher तबका में रिश्वतस्तानी निरन्तर कम होती चली जा रही है। हां, अभी Subordinate staff में काफी हद तक corruption पाई जाती है और मैं यह बात मिनिस्टरी तक पहुंचाना चाहता हूं कि शासन को और शुद्ध करने के लिये इन को भी tone up करने की ज़रूरत है ताकि जनता महसूस करे कि corruption का अन्त हो गया है। अगर हम corruption को दूर करने में कामयाब हो गये तो हमारी Administration इस राज्य की ही नहीं बल्कि सारे भारत की बड़ी भारी सेवा कर सकेगी।

इस के सम्बन्ध में हमारे Prime Minister साहिब ने कहा था कि "A welfare State presupposes a clear and efficent Aminiistration" अगर हम लोकहित में काम करना चाहते हैं तो हमें Administration को पवित्र करना होगा जब तक एडमनिस्ट्रेशन को इस चीज़ से मुबर्रा नहीं किया जाता प्रशासन अच्छी तरह से नहीं चल सकता। मैं समझता हूं कि जब तक इस को दूर न किया जाएगा तब तक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी ही रहेगी। अतः इस बात पर ध्यान देने की बड़ी ज़रूरत है।

दूसरी बात जो आपके ज़रिये, अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मन्त्रिमण्डल तक पहुंचाना चाहता हूं वह लाल फीतेका साम्राज्य (Red tapism) है। माना कि Red Tapism कम हो गया है मगर इस हद तक कम नहीं हुआ जिस हद तक कि ज़रूरी था। लाल फीते का राज्य इस हद तक है कि लोग इस से तंग आ चुके हैं। वास्तव में यह जनता को बड़े कष्ट और तकलीफ़ में डालता है। इन को दूर करना चाहिये।

[श्री रला राम]

तीसरी बात जो अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा मुख्य मंत्री तक पहुचाना चाहता हूं और Administration से आशा रखता हूं कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा वह है बेरोज़गारी जो कि लिखे पढ़े नौजवानों के अन्दर खास कर बढ़ रही है। आशा है कि वह इसको दूर करने का प्रयत्न करेगी। क्योंकि एक ऐसा खतरा है जोकि देश को तबाही की तरफ ले जा सकता है। जैसा कि अकसर कहा जाता है—

"Unemployed man power is more dangerous than the atom bomb."

बेकार जनता ऐटम बम्ब से भी अधिक खतरनाक है। इस लिये बेरोज़गारी को दूर करना हमारे शासन की बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है। इस में संदेह नहीं कि जो कदम बेकारी को दूर करने के लिये उठाये गये हैं वह प्रशंसनीय है। लेकिन अगर हमने इस समस्या को बहुत तेज़ी से tackle करने का प्रयत्न न किया तो यह देश के लिए एक भारी खतरा साबत हो सकती है।

ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ (ਟਾਂਡਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਿਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ ਨੇ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਚ ਮੁਚ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜੋ Welfare State ਕੂਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਗੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਤਲਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ? ਜੇਕਰ Administration ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਮਹਜ਼ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਛਡਦੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਰਵੀਏ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟਸ (departments) ਵਿਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਵਈਆ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਵਡੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰ ਹਨ। ਜਦ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਕਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ (Finance Minister) ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਕਰੋੜ 30 ਲਖ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ 29 ਲਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ revised ਬਜਟ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਕਰੋੜ, 85 ਲਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ 92 ਲਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਦੀ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ 10 ਲਖ ਵਧ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪਲੀਮੈਂਟ੍ਰੀ ਬਜਟ (Supplemantry Budget) ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ Development State ਬਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਆਦਾਦੋ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ Development State ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ figures ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਖੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੇ। figures ਵਿਚ ਜੋ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ explain ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇਕ ਖਰਚ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲਗ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਚਮੁਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਠਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਫਾ 144 ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਕੀ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਇਜ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ crimes ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 54,000 ਮੁਕਦਮੇ ਦਫਾ 107 ਦੇ ਅਤੇ 11,000 ਮੁਕਦਮੇ ਦਫਾ 109 ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ? ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ?

[ਸਰਦਾਰ ਚਨੰਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ]

ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰਨ civil liberty ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਸ civil liberty ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੁਰਮ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਬਜਟ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਰਨਾਲ, ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ crime ਘਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਜੁਰਮ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਰਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ ਲਈ ਢਾਈ ਲਖ ਰੁਪੇ ਦੀ ਰਕਮ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਘਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਤਨੀ ਖਰਚ ਵਿਚ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ । ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਢੜਾ crude ਜਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਟੇਟ (State) ਦੀ development ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ development ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰ ਸਿਧੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। Development State ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ

refined ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ-ਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਸਾਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ development ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ motor transport ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਉਪਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਪੁਠੇ ਟੰਗੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਢੰਗ ਹਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Text Books ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਪੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਪੀਆਂ ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਢੰਗ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਛਪੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁਜਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਪੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜ ਕਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਨ ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ Character ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬ, 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ Labour Minister ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ 500 ਤੋਂ 1,000 ਰੁਪਿਏ ਤੀਕਰ ਦੇ checque ਮਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ donations ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ

[ਸਰਦਾਰ ਚਨੰਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ]

ਉਨ੍ਹਾਂ cheques ਦੇ ਨੰਬਰ ਤਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਲੁਧਿਆਨੇ ਦੇ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ donations ਲਏ ਗਏ। ਇਹ donations ਕਿਸ ਚੀਜ ਦੇ ਸੀ? ਆਖਰ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਪਹਿਲੋਂ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਓਹਨੂੰ anti-social ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ anti social ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ character ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ welfare ਵਜੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ decentralisation of power ਦੇ ਬੜੇ ਦਾਵ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। Decentralisation ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਖਤਿਆਰ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਏਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਨਾਈਆਂ, ਮਿਉਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਮਗਰ tax ਲਗਾਉਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ S.D.O. ਰੱਖਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Executive ਦਾ ਇਕ steel frame ਬਨਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ C.I.D. ਰਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ S.D.O. ਰਖ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਰਖਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ decentralisation ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ decentralisation ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਕ Deputy Commissioner ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਚਾਰ ਪੰਜ Deputy Commissioner ਹੋਰ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ decentralisation ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਲ ਵੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ District Boards ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ bodies ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ Motor Transport ਦੀ Nationalisation ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ refined ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ Development State ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ॥

श्रीमती शन्नो देवी: (अमृतसर शहर-दक्षणी हलका) स्पीकर साहिब, आज ऐवान में General Administration पर बहस हो रही है। मगर इस पर अपने ख्यालात ज़ाहिर करने से पहले मैं अपने साथी मैम्बरों से एक बात कहना चाहती हूं। यहां कई बार इस बात की तरफ ध्यान दिलाया गया है कि हाऊस की dignity का हर हालत में ख्याल रखना चाहिये। जब मैं आप की इजाज़त से खड़ी हुई तो मैं हाऊस के posses-sion में थी लेकिन एक मेम्बर साहिब उठ कर ऐवान को एक तसवीर दिखाने लगे। यह कुछ नामुनासिब सा मालूम होता था।

अब मैं असल मामले की तरफ आती हूं। हमें यह देखना चाहिये कि हमारा General Administration किधर जा रहा है। बेशक हमारे सूबे का करोड़ों का बजट है मगर मैं कहती हूं कि बजट करोड़ों नहीं अरबों का भी क्यों न हो जब तक इस की implementation ठीक तौर पर न हो उस वक्त तक हम बेशक अपने आप को मुबारिकबाद दे लें इस से क्या होता है? होना तो यह चाहिये कि सारा पंजाब मुबारिकबाद दे। इस का यही तरीका है कि हम सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। सब से पहले मैं मेम्बर साहिबान से कहती हूं कि बजट बना कर उसे implement करने के बारे में जहां services के फराइज़ हैं वहां हमारा भी कुछ फर्ज़ है। हमें चाहिये कि उन के काम में रुकावट न डालें और उन्हें अपना सहयोग दे कर इस को implement होने दें।

अब मैं Chief Minister साहिब का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहती हूं कि जो भी important मामला गवर्नमैण्ट के सामने पेश हो उस का फ़ैसला जल्दी हो जाना चाहिये। मैं पूछती हूं कि क्या वजह है कि एक important मामला जिस में उन्होंने personal interest भी लिया था दो ढाई साल से वैसे ही लटक रहा है? यह बात ठीक नहीं है और इस का अच्छा असर नहीं पड़ सकता।

स्पीकर साहिब, हमारे बजट में industries के लिये एक खास रकम रखी गई है। बाज़ मैम्बरों ने कहा है कि यह रकम थोड़ी है मगर मुझे इस बात से बहस नहीं। मैं तो यह कहना चाहती हूं कि अमृतसर हमारे पंजाब में एक ही business centre

[श्रीमती शन्नो देवी]

है। United Punjab में भी हमारा सब से बड़ा centre यही था। वहां labour और mill owners का झगड़ा चल रहा है । वह बात सरकार के कानों तक जरूर आई होगी। मैं Chief Minister साहिब से कहती हूं कि यह मामला बहुत लम्बा हो गया है। इस से सिर्फ अमृतसर का ही नहीं सारे पंजाब का नुकसान हो रहा है। मैं अपने साथी राम चन्द्र जी से जिन्होंने परसों इस बारे में रौशनी डाली थी सहमत नहीं हूं बल्कि उन से और चीफ मिनिस्टर साहिब से कहती हूं कि दो साल हुए Labour Minister और चीफ मिनिस्टर साहिबान वहां गये थे और अपना वक्त खर्च किया था। उन्होंने चार चार नुमाइंदों की एक कमेटी भी बना दी थी। अब वह अपनी file देखें उस से सब कुछ मालूम हो जायगा। फिर जिस की गलती हो उस को सज़ा दें और जो सचाई पर हो उस के साथ इनसाफ करें। मैं तो कहती हूं कि अपना बच्चा भी हो तो कसूरवार होने पर उस को सज़ा मिलनी चाहिये। अगर हम ऐसा न करेंगे तो इस का अच्छा असर नहीं पड़ेगा । तो मेरी प्रार्थना है कि झगड़े को अब ज़्यादा बढ़ने न दिया जाये। मैं अपने Chief Minister साहिब को याद दिलाना चाहती हूं कि उन के सामने जब Finance Minister, Labour Minister, Local Self Government के सैक्रेटरी और हलके के कई ज़िम्मेदार लोग मौजूद थे और जब पूरी बहस के बाद सब चीजें तै हो गई थीं तो नामालूम नौ बजे के बाद क्या हो गया था। लेकिन मैं कहती हूं कि यदि हमने सूबे को उठाना है तो हमें मज़बूत कदम उठाने होंगे और अपने किये हुए फैसलों को implement करना होगा। जो भी ग़लती पर हो चाहे X हो Y हो या Z उसको ग़लत करार दिया जाये। हमारा यह बजट जो एक development budget है तभी सफ़ल हो सकता है और हमारे दिलों में तभी खुशी हो सकती है यदि ग़रीब लोगों को कोई आमदनी का ज़रीया नज़र आये। हम जो Labour के हामी हैं सब यही चाहते हैं और खास कर मैं तो मज़दूरों, चपड़ासियों, क्लरकों और दूसरे छोटे भाइयों की तकलीफें दूर करने में हमेशा आगे आगे रहती हूं और किसी से पीछे नहीं होती। परन्तु यह बात तो Government level पर होनी है और सरकार को चाहिये कि अपने किये हुए फैसले को implement कराये।

स्पीकर साहिब, जब मैं बजट की किताब उठाती हूं तो मेरी नज़र demand No.10 पर पड़ती है। आप मेरे साथ सहमत होंगे कि औरतें चाहे मातायें हों, चाहे बहिनें, घर के बजट बनाने में बहुत हुशयार होती हैं। मेरे दिल में भी उमंग पैदा होती है कि मेरे सूबे का बजट इतना अच्छा हो कि सब लोग मुझे बधाइयां दें। लेकिन बजट तैयार करते समय तो मेरी सलाह नहीं ली गई। क्या अच्छा हो कि अब ही मेरी बात मान ली जाये। मैं देखती हूं कि Ministers की तनखाहों के लिये 2,69,000 रुपया रखा गया है। यह रकम पिछले साल की रकम से करीबन दुगनी है। मेरा विचार है कि इस को घटाया जाये। मैं politics में नहीं जाना चाहती कि 8 Minister हों या सात। मैं तो कई बार मांग कर चुकी हूं कि कुल ५ वज़ीर हो जायें तो अच्छा है। मैं तो यह बात खर्च घटाने के लिये कहती हूं। लेकिन अगले साल वज़ीरों की तनखाहों पर इस साल की निसबत खर्च दुगना होना है। शायद यह इस लिये हो रहा है कि कुछ और वज़ीर, Deputy Ministers और Parliamentary Secretaries बनाये जाने हों।

अध्यक्ष महोदय : आप के ५ मिंट और हैं ।

श्रीमती शन्नो देवी : स्पीकर साहिब, मैं चाहती हूं कि इस रकम को जो इस साल की निसबत दुगनी है, घटाया जाये ।

फिर इस सूबा की administration दरुस्त न होने की एक और वजह है । मैं ऐवान के मैम्बरों से कहती हूं कि हम लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा आदत है कि हम हर काम में दखल देते हैं । चाहे मैम्बर हों चाहे वज़ीर, हम सब ऐसा करते हैं । हमारे Chief Minister साहिब को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिये । हम सब लोग पारसा नहीं और services के सारे लोग गुनाहगार नहीं । यदि हम में से कोई भी किसी के नाम पर quota लेता है तो administration और services के नाम पर धब्बा आता है मगर कसूरवार हम होते हैं । हमें चाहिये कि जब भी हमारी नज़र में ऐसा आदमी आये जो कसूसरवार हो तो चाहे वह कोई ही क्यों न हो हम उसे सज़ा दें । ऐसा करने से हमारे प्रान्त की सारी administration चाहे यह police का महकमा हो या कोई और, वह बिल्कुल ठीक हो जायगी ।

मुझे चंडीगढ़ के बारे में भी कुछ कहना है । इस शहर का नक्शा बनाने के लिये कहीं कहों के लोगों की खिदमात हासिल की गई । लेकिन पिछले दिनों जब बारिश हुई तो घरों की जो हालत हुई बयान से बाहर है । सड़कों का तो यह हाल था कि नाओ की ज़रूरत पड़ती थी । इन दिनों सड़कों की यह हालत है कि बिचारे जूतों की कुछ न पूछिये । मेरा विचार है कि मेरे भाइयों को भी यही तकलीफ हो रही होगी जो मुझे हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : बहिन जी, यदि बेअदबी न हो तो अपनी बहस को Demand No. 10 तक महदूद रखिये ।

श्रीमती शन्नो देवी : स्पीकर साहिब क्योंकि चलने फिरने से भी वास्ता पड़ता है इस लिये यह बात भी कह दी गई । श्रीमान् जीं, मैं कहती हूं कि वह कौनसा पंजाबी है जो यह नहीं चाहता कि पंजाब बढ़े और फले फूले । कोई भी जिम्मेदार और समझदार आदमी यह नहीं चाहता कि नुक्ताचीनी केवल नुक्ताचीनी के लिये ही की जाये । इस लिये मैं समझती हूं कि सरकार को healthy criticism सुन कर हमेशा प्रसन्न होना चाहिये । हमारे Chief Minister साहिब बड़े बुद्धिमान पुरुष हैं । Administration को चलाना खूब जानते हैं । मैं उन से दरख्वास्त करूंगी कि जो वह उस दिन मौजूद न थे जब रोहतक का मामला बड़े serious ढंग से पेश किया गया था उन्हें तहकीकाती कमेटी बनानी चाहिये । मैं यह नहीं कहती कि यह कमेटी कैसी बनाई जाये । वह खुद बहुत बुद्धिमान है और इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं । परन्तु उन को एक कमेटी ज़रूर बनानी चाहिये जो इस मामले के बारे में तहकीकात करे । जो भी कसूर वार हो उसे सज़ा दी जाये । और यदि पोलीस बिल्कुल निर्दोष साबत हो तो उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाये जिन्होंने पुलिस पर इतने इलज़ाम लगाये हैं ।

[श्रीमती शन्नो देवी]

मुझे Chief Minister साहिब के सामने एक बहुत serious बात भी रखनी है। वह यह है कि सूबे में बहुत communalism आ रहा है। Communalism ने कभी pay नहीं किया। हम जानते हैं कि pre-partition दिनों में हमारी क्या हालत थी। मुझे समझ नहीं आती कि हिंदुस्तान की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेज़ी को कैसे replace कर रही है। हम न हिंदी को तरक्की दे रहे हैं और न पंजाबी को। हालांकि West Punjab के मुसलमान पंजाबी को अपनी ज़बान कहते हैं लेकिन हम ने इस की तरक्की के लिये कुछ नहीं किया। मुझे इस बात का गौरव है कि मेरी ज़बान पंजाबी है। परन्तु मैं कहती हूं कि मुझे पंजाब में ही नहीं रहना है। मेरा मुल्क हिंदुस्तान है। लेकिन मैं हर जगह मोटर में, गाड़ियों में ज़बानों का झगड़ा ही सुनती हूं। यह बिल्कुल ठीक है। यदि मेरी बात ग़लत साबत हो तो I am liable to punishment.

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्या को चाहिये कि वह अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती शन्नो देवी: श्रीमान् जी! मैं खुद महसूस कर रही हूं कि मुझे अपना भाषण खत्म कर देना चाहिये परन्तु मैं आप से दरख्वास्त करती हूं कि मुझे एक दो मिनट बोलने के लिये और दें। मैं आप की विसातत से माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहती हूं कि वह अपने साथियों की तरफ निगाह डालें। अगर वे सर्विसिज़ के कामों में नाजाइज़ तौर पर दखल देते हैं तो उन को मुनासिब सज़ा दें और अगर सर्विसिज़ कोई ग़लत काम करती हैं तो उन्हें भी मुनासिब सज़ा दी जाये। जिस राष्ट्र में सम्मान की अपमानता और अपमानता का सम्मान होता है तो चाहे बजट कितना ही अच्छा या खूबसूरत क्यों न हो वह नाकाम बजट होता है। मैं इन शब्दों के साथ आप का शुक्रिया अदा करती हूं।

ਸਰਦਾਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ-ਧਰਮ ਕੋਟ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠਨ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੈਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੇ workers ਨੂੰ ਤੰਬੀਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਨ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰੀ, ਸਨਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗਏ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ workers ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ convessing ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ worker ਸਰਦਾਰ ਖਮਣ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਰੁਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय मेम्बर को कहूंगा कि वह ऐसे व्यक्तियों का जिक्र न करें जो यहां नहीं हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (U. P.) ਵਿਚ ਮੁਕਦਮੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ ਜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨ ਹੋਏ।

मुख्य मंत्री: उस का नाम तो बता दीजिये ।

ਸਰਦਾਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਿਆਂ ਸੌਹਰਿਆ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ revert ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਇਹ ਗਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਲਈ ਦੌਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ-ਸਤਾਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ workers ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਆਵਾਜ਼ਾਂ: ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ) ਮੈਂ challenge ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਨਾ ਥਾਨੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ Superintendent Police ਕੋਲ ਰਿਪੋਟਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿ ਥਾਨੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਮਕੇ ਆਦਮੀ ਤੇ control ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਤੇ Control ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੀ ਚਿਠੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ੀ ਚਿਠੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਿਠੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਿਆ।

[ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ]

ਮਲਕੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਤਿੰਨ reminder ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ consolidation ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਢਿਲ Settlement Officer ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰੇਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੇ ਤੇ ਕਤਲ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣ ਲਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ,! ਕਲ ਮੇਰੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੰਧਾਂ ਪਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰੇਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਦੀਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਛਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਬਣੀਆਂ ਕੋਟ ਭਾਈ ਤੇ ਸਾਹਬ ਚੰਦ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਛਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰੇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ Motor Transport Companies ਸਾਰੀਆਂ Nationalise ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨ ਤੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖਣੀਆਂ ਪੈਣ ਗੀਆਂ।

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय मैम्बर से कहूंगा कि वह General Administration पर बहस करें।

ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ Malwa Bus Service ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰੇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ

route nationalise ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ! ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੰਤ੍ਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਰਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਣ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰਖ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਦੀ ਗਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ਕੀਤੀ। ਮੋਗਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ nationalise ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ nationalise ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਕਲ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨ ਹੀ ਕਮਯੂਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖਲਾਫ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਹਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰੇਸੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਜਨਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।

मुख्य मंत्री : क्या आप मेहरबानी करके उन कतल आदि के मुकदमों के नाम बता देंगे जिन में आपने कहा है कि approach की गई है ?

ਸਰਦਾਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਦਸਾਂਗਾ

राए रघुबीर सिंह (सैराज) : श्रीमान जी मौजूदा मिनिस्टरी जब से कायम हुई है यह इस का तीसरा बजट ऐवान के सामने आया है। जो भी Administration की detail में जायगा उसे पता लगेगा कि इस बजट में पहले और दूसरे बजट से कितना ज़्यादा फरक है। आज इस देश की जनता का यह नारा है कि हमने यहां पर एक Welfare State कायम करनी है। आप महसूस करेंगे कि किस तरह से इस बजट के द्वारा Welfare State की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। इस बात का गिला कुछ उन दोस्तों को ज़रूर होगा जो अपनी पार्टी के ज़ोर से देश पर छा जाना चाहते हैं। अगर वह देश पर छा जाना चाहते हैं तो उन्हें लोगों का confidence हासिल करना चाहिये और अगर वह election में नाकामयाब हो जायें तो उन्हें देखना चाहिये कि

[राए रघुवीर सिंह]

उन में क्या खराबी है। परन्तु मुशकिल यह है कि वह मेरे दोस्त जनता के पास नहीं जा सकते क्योंकि उन का असूल और है और democratic Government का असूल और। मैं स्पीकर साहिब आप के द्वारा इस हाऊस को बड़ी प्रसन्नता से बताना चाहता हूं कि Welfare State की तरफ हमारा कदम बढ़ता ही जायगा चाहे हमारे रास्ते में कितनी ही मुशकिलात क्यों न हों। असल में मुशकलात का नाम ही ज़िन्दगी है। जनता हमारे साथ है। वह धोका नहीं खा सकती। वह जानती है कि इस थोड़े से असरे में जो हमें काम करने के लिये मिला है हम क्या कुछ कर पाये हैं। इस में शक नहीं कि इनसान कहीं ग़लती भी कर देता है। Opposition के हम मशकूर हैं कि वे हमें कभी कभी सरकार की ग़लतियां बता देती है। एक मिनिस्टर साहिब के बारे में कहा गया है कि वह अमृतसर गये और उन्होंने लोगों से चंदा इकटठा किया। परन्तु यह बात ग़लत है. उन्होंने वहां से कोई donations हासिल नहीं किये थे। हमने administration को चलाना है। हमने यह देखना है कि यह लोगों की बेहबूदी के लिये काम करे। इस लिये हमारा सब का रुहझान तामीरी काम की तरफ होना चाहिये। हमें healthy नुक्ताचीनी करनी चाहिये। Democratic Government में यह ज़रूरी है कि हम लोगों के ideas Ministers तक पहुंचाएं। एक Opposition के भाई ने फरमाया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डज़ (District Boards) की election अभी तक नहीं की जा रही और इस को टाला जा रहा है शायद इस लिये कि इस से हमारी यह democratic सरकार कोई मकसद हासिल करना चाहती है। अगर आप बजट को देखें तो आप को पता लगेगा कि एक कमेटी कायम की जा रही है इस बात की जांच के लिये कि आयंदा हमारे सामने आने वालें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड किस तरह के हों। उस कमेटी ने यह देखना है कि डिट्रिस्क्ट बोर्ड मौजूदा शकल में रहें या इन को पंचायत राज के नमूने पर वाकई एक लोगों की चीज़ बनाया जाये। इस चीज़ के लिये कुछ सोच की ज़रूरत है और यह काम उस कमेटी ने करना है। अब अगर यह भाई यह कह दें कि यह Democratic Government इस तरह से कोई निकम्मा मकसद हासिल करना चाहती है तो इस का क्या हल है, यह तो इन का वहम है, होना तो यह चाहिये कि यह सामने बैठे भाई भी सरकार को बतायें कि क्या होना चाहिये क्योंकि वे भी पंजाबी हैं. न कि यह हो कि किसी कारखाने में हड़ताल हो जाये और हल्लागुल्ला हो जाये और इस तरह से देश में पैदा हो रही दौलत बन्द हो जाये। इस तरह के healthy criticism की मौजूदा हालात में जब दुनिया का political atmosphere बिगड़ता जा रहा है और भी ज़रूरत है। और फिर हम तो एक सरहद्दी सूबे के रहने वाले हैं, इस लिये हमें और भी एहत्यात से काम लेना होगा।

Opposition की तरफ से एक बात का ज़िक्र किया गया है और इस बारे में इस तरफ के मैम्बरों ने भी कुछ टीकाटिप्पणी की है। वह है red-tapism। इस में शक नहीं कि administration में red-tapism कुछ हद्द तक ज़रूर है। Common man को हमने काम करके दिखाना है। उस के सामने हम काम के बग़ैर कोई दलील नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर स्कूलों की किताबों का मामला

है । उन के छपने में और स्कूलों तक पहुंचने में देर हुई है । मैं जानता हूं कि सरकार को कुछ मजबूरियां दरपेश थीं लेकिन उन को हल किया जा सकता था ।

इस के इलावा में अर्ज़ करना चाहता हूं कि देश की दौलत को बढ़ाने के लिये forests को develop करना ज़रूरी है । हम देश की economy को बनाना चाहते हैं । मेरी suggestion इस सिलसिले में यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा plantation करें जिस के लिये बजट में उचित स्कीम नहीं रखी गई है ।

Principal Iqbal Singh : Is that, Sir, a part of the general administration ?

अध्यक्ष महोदय : अगर परिंसिपल साहिब जैसे आदमी information मांगें तो आम आदमियों का क्या बनेगा ? (*Laughter*).

राए रघुबीर सिंह : इस में कोई शक नहीं कि लाहौल के लिये 75 लाख रुपया केंद्रीय सरकार से मिला है और यह 5 वर्ष के लिये है । यह बहुत अच्छी बात है । परन्तु मैं चाहता हूं कि सरकार backward areas की तरक्की की ओर ध्यान दे क्योंकि लाहौल और स्पिती भी backward areas हैं ।

यह जो कांगड़े और गुड़गाओं का खाता खोला गया है यह नई बात है उस खाते में यह रुपया पंजाब सरकार द्वारा दिखाया जाना जनता के लिये धोखे का कारण बन सकता है । जो रकम दो तीन साल से पड़ी थी वह इस्तेमाल हो गई है । बहरहाल कांग्रेस सरकार की मिहरबानी है कि उस ने कांगड़े और कुल्लू की तरफ ध्यान दिया है । जो रकम कुल्लू में सड़क बनाने के लिये बजट में रक्खी गई है वह बहुत थोड़ी है । कुल्लू-शिमला की 122 मील सड़क पर केवल 55 से 58 मील के अन्दर 1,73,000 रु. खर्च हो रहा है । इस सड़क को केवल 2-3 मील ठीक करने से मकसद प्राप्त नहीं होगा । अन्त में प्रधान जी मैं आप का धन्यवाद करता हूं कि आप ने मुझे अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिये समय दिया है ।

श्री कन्हैया लाल बुटैल (पालमपुर) : स्पीकर साहिब, मैं उस दुःखी तथा बदकिस्मत इलाके का प्रतिनिधि हूं जिसे पालमपुर कहते हैं । जिस समय पंजाब के 29 ज़िले थे और रक्बा बहुत ज्यादा था । पंजाब के गवर्नर हेली साहिब ने इस की खूबसूरती और सेहत-अफ़ज़ा आबोहवा के देखते हुए 1927 में इसे सूबे की नई राजधानी बनाने के लिये चुना था । पालमपुर जिसे वह पदवी मिलनी थी जो आज चंडीगढ़ को मिली हुई है 11-12 तारीख को जल कर खाक में मिल चुका है और वहां पर राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं रहा । सब मकान और इमारतें तबाह हो गई हैं । आग ने 48 लाख रुपये का नुकसान किया है ।

अंग्रेज़ी हकूमत के वक्त से जो शहर एक सुन्दर सेहत-अफ़ज़ा मुकाम तस्सवर किया जाता है आज बिल्कुल बरबाद हो चुका है । डेढ़ हज़ार परिवार बेघर और बेदर हो चुके हैं । न इन के रहने के लिये कोई जगह रही है न कोई रोज़गार का वसीला रहा है । लोगों ने सोते वक्त जो कपड़े उतार कर रखे थे वे भी जल कर खाक हो गये हैं । अब तन ढांपने को उनके पास कोई कपड़ा नहीं । उनकी सब चीज़ें जल कर खाक हो गई हैं. currency note तक जल गये हैं ।

[श्री कन्हैया लाल बूटैल]

हम इस बात के लिये सरकार के शुकर-गुज़ार हैं कि वहां पर Deputy Commissioner साहिब, Superintendent of Police और छिब्बर साहिब, Inspector Police ३५ पुलिस के आदमी ले कर गये थे। Military के सरदार रघबीर सिंह ने और हिलाल और योल कैम्प के आदमियों ने भी आग को बुझाने के लिये बहुत यत्न किये। मगर पालमपुर को Punjab Government से शिकायत थी और गिला था क्योंकि इस ने उस की बेहतरी की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, इस लिये पालमपुर ने कहा, "मुझे जलने ही दो, मेरी ज़रूरत ही किसे है, मेरी परवाह ही कौन करता है, मेरी हक-तलफी तो एक अर्से से हो रही है"।

श्रीमान् जी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरे हलके की जिस की आबादी १७५,००० है, development के लिये बजट में एक पाई भी नहीं रखी गई। मैं Ministry का ध्यान पूरे जोर के साथ इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। पालमपुर इस वजह से जल कर राख हो गया है क्योंकि इस की हमेशा हक-तलफी होती रही है। आज जब कि यह जल चुका है। सारे भारत वर्ष का ध्यान इस की ओर चला गया है, मगर हमारी Ministry अभी तक सोई हुई है। इस ने वहां के लोगों को किसी किसम की सहूलियत मुहय्या नहीं की। मैं सरकार से फिर दर्खास्त करता हूं कि वह इन दुखी, तबाह हाल लोगों की सहायता के लिये मुनासिब relief measures इख्त्यार करे। उन्हें जल्द से जल्द grants और सस्ते कर्जों की शकल में माली इमदाद भी दे।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਤੁਸੀਂ Budget ਦੀ general discussion ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਓਦੋਂ ਵਕਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਗਰਾਓਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਤ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਾਂ General Administration ਦੇ head ਥਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

General Administration ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ Budget ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਪਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁੰਮਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਣ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ Budget ਦੀਆਂ figures ਵੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਹੜੀਆਂ ਹਨ।

General Administration ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ Finance Minister ਹੋਰਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫਿਕਰਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ :--

Decentralisation of Administration has been our guiding principal.

ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ figures quote ਕਰ ਕੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ policy ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11,000 ਰੁਪੈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਇਕ item discretionary grants ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ Governor ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ 6,000 ਰੁਪੈ ਦੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ 4,000 ਰੁਪੈ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ Commissioner ਅਤੇ Deputy Commissioner ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹ 1,020 ਰੁਪੈ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ powers ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਲਕਿ ਹੇਠੋਂ ਉਪਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ decentralization ਦਾ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ decentralization ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ Treasury Benches ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥਕਦੇ।

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ Administrative powers ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਬੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ, ਪਰਧਾਨ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਸਾਧਾਰਨ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਂ ਤਾਂ Administrative ability ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ level of intelligence ਇਤਨੀ ਉਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਪਰਸਪਰ ਝਗੜੇ ਇਨੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ helpless ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ Administrative unit ਬਨਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ training ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ training centres ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

[ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ]

ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਪਰ ਖਰਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2,54,000 ਰੁਪੈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ 2,12,880 ਰੁਪੈ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟ ਰੁਪਿਆ ਰਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। Opposition ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਤਿਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ, ਉਨੇ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ satisfied feel ਕਰੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਵਧ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਉਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਰਚ ਘਟਾਇਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਰਚ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਘਟਾਂਉਦੇ ਕਿ opposition ਦੇ ਬੈਂਚਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਚ ਮੁਚ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਕਿ ਖੁੰਜੜ ਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪਰ ਜਿਸ (ਡੇਰਕਾ) ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਨੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਰਚ

ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਤੀ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਠਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਾਇ ਕੋਟ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ Non-Congressmen ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਵਿਚ ਐਨਰੋਲ (enrol) ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, Consolidation of Holdings ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਤੇਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸਕਰ Cosolidation Officers ਅਤੇ Assistant Consolidation Officers ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਰੇ ਇਤਾਬਰ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਥੇ ਇਕ ਐਸਾ ਗਰੁਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

[ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ]

ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸੋ । ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੱਜਣ ਹਨ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ Ruler ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਚ ਮੁਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਹਬੱਤ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਯਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰੁਕਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ । ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜਲੂਸ ਕਢਣਾ ਚਾਹਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ, ਆਮ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ representative ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਦੋ ਗਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਸਪੀਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1,06,940 ਰੁਪੈ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ maintenance ਵਾਸਤੇ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੁਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ urgency ਦੇ ਵਕਤ ਕਈ ਦੂਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਖਰਚ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਵਰਨਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ Treasury Benches ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ Resolution ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਵ opposition ਵਲੋਂ move ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਈ ਮੁਫੀਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਸੁਝਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਜਿਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ attitude ਹਕੂਮਤ ਦਾ opposition ਵਲ ਹੋਵੇ ਉਥੇ united nation ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ mental outlook ਬਦਲਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਜੀਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਡ ਛਡ ਕੇ ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਸਜਣ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰਫ਼ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥਲਿਓਂ ਮਿਟੀ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। (*Interruptions*) ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ challenge ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਲ ਨਹੀਂ ਖਿਚ ਸਕਦੇ।

दीवान जगदीशचन्द्र (लुधियाना शहर, उत्तरी हलका) : स्पीकर साहिब, एक नुक्ताचीन किसी तेली के मकान पर जाकर पूछने लगा कि सरसों का तैल कैसे निकालते हो। उस ने जवाब दिया कि मेरा बैल कोल्हू को चलाता है और उस में सरसों पिसती है तो तेल निकलता है। फिर उस ने पूछा कि इस के गले में घंटी क्यों बांध रखी है। तेली ने जवाब दिया कि इस को काम पर लगा कर मैं अपने दूसरे कमरे में चला जाता हूं और दूसरा काम करता रहता हूं। घंटी की आवाज से मुझे पता लगता रहता है कि बैल अपना काम कर रहा है। फिर उस नुक्ताचीन ने कहा कि अगर बैल खड़ा हो कर ही सिर को हिला कर घंटी को बजाता रहे तो तुम को धोका दे सकता है। उस पर तेली ने कहा कि यह बैल नुक्ताचीनी नहीं है। यह बैल काम करने के लिये बना है। साहिब सदर, मेरे opposition के दोस्तों ने

[दिवान जगदीश चन्द्र]

नुक्ताचीनी की है। लेकिन, स्पीकर साहिब, आप के द्वारा में उन्हें बता देना चाहता हूं कि पंजाब के अवाम नुक्ताचीन नहीं, वे काम करना जानते हैं। उन्हों ने पिछले साढ़े छः सालों के अर्सा में गवर्नमैण्ट को पूरा तुआवन देकर अपनी अनथक मेहनत से इस सूबे को बनाया है और इस की administration को और नज़मोनसक को ऊंचा और मज़बूत किया है।

साहिबे सदर, आप को पता ही है कि आज से साढ़े छः साल पहले हमारे सूबा की क्या हालत थी। हिंदुस्तान की तकसीम हुई और यह सूबा ज़हूर में आया। उस वक्त हर तरफ फ़सादात का आलम था। लूटमार, आग लगाने की वारदातें हर तरफ हो रही थीं। हर किसम के जराईम हो रहे थे। कोई पूछने वाला नहीं था। ऐसा नज़र आता था कि यह सूबा हमेशा के लिये अपना भविष्य खो बैठेगा। यह पाकिस्तान और हिंदोस्तान के दरम्यान एक no-man's land बन कर रह जायगा। इन हालात में, स्पीकर साहिब, हमारी सरकार ने इस नए सूबे का नज़मोनसक अपने हाथ में लिया। आज हम क्या देखते हैं? सूबे में एक बेहतरीन किसम की administration कायम हो चुकी है जिस की तारीफ़ केवल पंजाब में नहीं बल्कि सारे हिंदोस्तान के दूसरे सूबों में भी की जा रही है।

स्पीकर साहिब, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि इस साढे छः साल के अर्सा में न केवल पुलिस के ज़रिये administration को, नज़मोनसक को कायम किया गया है, बल्कि बेहतरीन तरीकों से—जो कि एक सर्वोदय स्टेट के या welfare state के होते हैं—नज़मोनसक को मज़बूत और जराईम को कम किया गया है।

साहिबे सदर, आप जानते हैं कि किस कदर हमारे भाई अपने काम काज और घरों को पाकिस्तान में छोड़ कर यहां आये। बेघर और बेकार होने की वजह से यह मुमकिन था कि वे जराईम करने लग पड़ें, डाके मारने लग जायें, और चोरियां करने लग जायें। लेकिन बड़ी तेज़ी से और पूरी कोशिश से मर्कज़ी सरकार की मदद से उन्हें इस तरफ बसाया गया और उन के लिये रोजी के साधन जुटाये गये। इस वक्त हम बड़े फ़खर से कह सकते हैं कि वह हर बहिन और भाई जो पाकिस्तान को छोड़ कर इधर आये, अपने अपने कामों में लगे हैं और इज्ज़त के तरीके से अपनी रोज़ी कमा रहे हैं।

इसके इलावा, स्पीकर साहिब, आप जानते हैं कि इस अर्सा में पंजाब के अन्दर नहरों का, बिजली की तारों का और सड़कों का एक जाल सा बिछा दिया गया है, किस लिये? इस लिये कि सूबा में बसने वाले लोगों का मियार-ए-जिन्दगी ऊंचा हो, किसान फिर से अपने कामों में लगें, हमारे आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में सुधार हो और ज़राईम में कमी हो जिस के नतीजे के तौर पर मुकदमा बाज़ी में कमी हो। स्पीकर साहिब, आज हम कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारी गवर्नमैण्ट आज decentralisation और administration की reorganisation कर रही है उस से अवाम के घरों तक इन्साफ पहुंचाया जायेगा। इस वर्ष कुछ ज़िलों में तहसीलों को headquarters बनाया जा रहा है और इस तरह से इनसाफ को सस्ता बनाया जायगा। इस पर भी नुक्ताचीनी की गई है। कहा गया है कि यह चीज़ तो लोगों को फांसने के लिये की गई है। स्पीकर साहिब,

मैं जानता हूं कि किस तरह लोगों को ज़िलों के headquarters पर तकलीफें होती हैं। खास कर उन लोगों को जो कि टैक्स वगैरा देने और दूसरी दरखास्तें देने के लिये ज़िला के सदर मुकाम पर आते हैं। सो मैं तो बजा तौर पर अपनी गवर्नमैण्ट को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उसने जिलों की बजाये तहसीलों को headquarters बनाने का फैसला किया है।

इस के बाद, स्पीकर साहिब! अप्पोज़ीशन (opposition) की तरफ से इस बात की भी नुक्ताचीनी की गई है कि administration का खर्च कम नहीं हुआ। कुछ दोस्तों ने कहा कि केवल दिखावेबाज़ी के लिये कुछ आंकड़े रखे गये हैं। आप की विसातत से, स्पीकर साहिब! मैं यह कहना चाहता हूं कि लैजिस्लेचर पर जहां १९५३-५४ में ११ लाख ४१ हज़ार रुपया खर्च हुआ वहां सन् १९५४-५५ में यह खर्च ११ लाख और १८ हज़ार होगा। इसी तरह आप सैक्रेटेरियेट को लें, जहां पिछले साल २९ लाख ९६ हजार रुपया खर्च हुआ था वहां अगले साल केवल २७ लाख ६८ हजार का खर्च होगा। यही हिसाब कमिश्नरों पर किये जाने वाले खर्च का है। पिछले वर्ष २ लाख ४४ हज़ार के मुकाबिले में सन् १९५४-५५ में २ लाख १२ हज़ार रुपया खर्च होगा। इसके इलावा डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन पर पिछले साल ७२ लाख ४६ हज़ार रुपया खर्च हुआ था, वहां इस साल decentralisation की वजह से काम बढ़ जाने के बावजूद ६० लाख ३९ हज़ार रुपया खर्च होगा।

फिर यह कहा गया है कि इन वर्षों में सूबे की कोई तरक्की नहीं हुई, नज़मोनसक में बहुत खराबियां हैं जराईम में कमी नहीं हुई और यह कि पुलिस कुछ काम नहीं कर रही। मैं हैरान हूं कि ऐसा कहने वाले लोग कैसे हकीकत से आंख मूंद लेते हैं? उन की इत्तलाह के लिये मैं यह बताना चाहता हूं कि सन् १९५३-५४ में सन् १९५१-५२ के मुकाबले में आठ हज़ार और सन १९५२-५३ के मुकाबले में चार हज़ार जुर्म कम हुए हैं। क्या इसे बेहतरी की तरफ एक अच्छा खासा कदम नहीं कहा जा सकता?

इस के साथ ही, स्पीकर साहिब! आप जानते हैं कि हमारा एक सरहद्दी सूबा है। इस के इलावा अभी तक हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ताल्लुकात खुशगवार नहीं हुए। साथ ही अमरीका-पाक की arms aid संधि से भी बार्डर पर ज्यादा अहतयात रखने की ज़रूरत है। यह भी हो सकता है कि विदेशों के लोग इस मुल्क में चुपचाप काम कर रहे हों। हो सकता है कि वे लोग अवाम को नज़मोनसक में खराबियां पैदा करने के लिये उकसा भी रहे हों। इस लिये, मैं समझता हूं, स्पीकर साहिब, कि सूबे की हिफ़ाज़त करने और अन्दरूनी नज़मोनसक को बरकरार रखने के लिये Police और intelligence का काम पक्का और मजबूत हो। इस बात की जरूरत है कि हमारे पास ऐसी मज़बूत Police force हो जो हरेक गड़बड़ का सामना कर सके। जो force इस वक्त हमारी सरकार ने P.A.P. की शकल में बनाई है उस की हमें खास ज़रूरत थी। इस लिये कौन कह सकता है, स्पीकर साहिब, कि आज के हालात को सामने रखते हुए हमें पुलिस force की ज़रूरत नहीं? कौन कह सकता है कि इन हालात में आज हमें ज़्यादा ढोलों को बनाने की ज़रूरत

[दीवान जगदीश चन्द्र]

नहीं ? सरहदी सूबा होने के कारण आज हमारे ऊपर एक खास जिम्मेदारी आयद होती है । इस लिये हमारा फ़र्ज़ है कि सीमा की रक्षा करने के लिये और मज़बूत बनने के लिये पहले अपने अन्दरूनी नज़मोनसक को मज़बूत करें ।

इस के इलावा साहिबे सदर! कहा गया है कि यह जो पंचायतों का सिलसिला शुरु किया गया है, यह भी एक ढौंग है । यह भी कहा गया है कि हमारा अपने वोटरों पर विश्वास नहीं रहा, इस लिये गवर्नमैण्ट सख्त कानून लागू कर रही है । स्पीकर साहिब ! आप जानते हैं कि आज हमारे सूबा में पंचायतें किस अच्छे ढंग से काम कर रही हैं । आखिर वे पंचायतें कोई ऊपर से थोड़े ही ठौंसी गई हैं । जिस तरह हमें आम लोगों ने चुना है ,उसी प्रकार गांव में भी सभी बहिनों और भाइयों ने अपने वोटों से उन्हें मुन्तखिब किया है । उन्हें पूरे इख्तेयार हैं कि वे गांव के नज़मोनसक को चलाएं, इनसाफ करें और लोक भलाई के काम करें । स्पीकर साहिब, यह कहा जाता है कि सभी इख्तेयार हम पंचायतों को दे दें ऊपर से कोई कंट्रोल (Control) न हो । लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह एक तजुर्बा है जो कि आज हम कर कह रहे हैं । आज हज़ारों वर्षों के बाद यह तरीका दुबारा अपनाया जा रहा है । आज से हज़ारों वर्ष पहले हिंदुस्तान का सारा नज़मोनसक पंचायतों के सिर पर चलता था । आज जब कि हज़ारों वर्ष के बाद हम इस तजुर्बे को दोबारा राइज कर रहे हैं, यह ज़रूरी है कि हम बड़ी एहतयात से काम लें । हमारी गवर्नमैण्ट का तो खुद यह इरादा है कि पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा ताकत दी जाये । लेकिन इस चीज़ के लिये कुछ वक्त चाहिये । हमें आशा है कि आहिस्ता आहिस्ता जब वे शासन के तरीकों का तजुर्बा हासिल कर लेंगी तो उन्हें और इख्तियारात दिये जायेंगे ।

स्पीकर साहिब ! फ़िरकापरस्ती की तरफ भी ईशारा किया गया है । हमारे अकाली भाईयों की तरफ से यह कहा गया है कि आज की गवर्नमैण्ट फ़िरकापरस्ती के वातावरण को पनपा रही है । कहा गया है कि वह फ़िरकापरस्तों की हौसला अफ़ज़ाई करती है । स्पीकर साहिब ! मैं क्या कहूं उन भाइयों को जिन का नज़रिया ही शुरु से फ़िरकापरस्ती का रहा है । लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि क्या वे यह नहीं जानते कि हमारी Administration के दो बड़े Important पुर्ज़े चीफ़ सैक्रेट्री और होम सैक्रेटरी सिख हैं ? क्या उन्हें यह पता नहीं कि काफ़ी ज़िलों के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस के सुप्रिंटैण्डैण्ट और दूसरे बड़े अफ़सर सिख हैं ? मैं हैरान हूं कि प्रत्यक्ष प्रमाण होते हुए भी ये भाई ग़लत ब्यानियां करने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश क्यों करते हैं ? मुझे खुशी है कि आज हमारी कैबीनेट में फ़िरकापरस्ती की हवा भी नहीं आने पाती और किसी को इस लिये सज़ा नहीं दी जाती कि वह सिख है या हिन्दू । इस लिये स्पीकर साहिब ! मैं आप की इजाज़त से ऐसे भाई को कहना चाहता हूं कि आज के बदलते हुए जमाने में उन्हें ऐसे नज़रिये को बदलना होगा क्योंकि आज अवाम को पंथ के नाम पर गुमराह नहीं किया जा सकता ।

मेरे कम्युनिस्ट भाइयों ने भी बहुत सी बातें की हैं, खास तौर पर उन्होंने यह कहा है कि लोगों को स्यासी आज़ादी नहीं—उन्हें स्यासी ख्यालात को ज़ाहिर करने की आज़ादी

नहीं । वह खुलकर बात नहीं कर सकते । स्पीकर साहिब ! मैं उन्हें पूछना चाहता हूं कि वह बतायें कि आज कम्यूनिस्ट पार्टी को अपना स्यासी प्रचार करने जलसे करने और जलूस निकालने पर कौन सी पाबन्दी है ? मैं उन से कहना चाहता हूं कि पहले वह उस मुल्क की स्यासी आज़ादी से हमारा मुकाबला करें जिस की वे यहां नुमाईन्दगी करते हैं । रूस में तो आज किसी को वोट देने तक की आज़ादी नहीं । वहां पर तो rule of bullet है, ballot नहीं । हम इस सूबे में rule of ballot कायम करना चाहते हैं rule of bullet नहीं । और इसी लिये हम rule of bullet लाने वाली activities को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते । अगर वे यह चाहें कि minority में होते हुए भी उन के ख्यालात चलें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते ।

इस के इलावा, हमारे कुछ साथियों ने जो कि किन्हीं ज़ाती कारणों से कांग्रेस को छोड़ कर अपोज़ीशन में चले गये हैं कुछ ख्यालात का इज़हार किया है । उन्हें स्पीकर साहिब ! मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमैण्ट ने सारे हिन्दुस्तान में पहली दफा Subordinate Services Selection Board कायम करके एक मिसाल कायम की है ।

छोटी नौकरियों के लिये मुलाजम भरती करने के जो इख्त्यारात सरकार के अपने पास थे वे इस बोर्ड को सौंप दिये हैं । अब यह Services Selection Board सारे प्रान्त की छोटी नौकरियों की आसामियां पुर किया करेगा । गवर्नमैण्ट ऐसा करने के लिये हमारे मुबारिकबाद की मुस्तहिक है ।

फिर साहिबे सदर ! यह कहा गया है कि हमारे वज़ीर साहिबान अब कितनी शानदार कोठियों में रहते हैं जो कि चुनावों से पहले नरक के समान कोठियों में रहा करते थे । जिन भाइयों ने ऐसा कहा है वह वही हैं जो इलैकशन के बाद इन्हीं चीफ मनिस्टर साहिब की उस नरक की कोठड़ी का वज़ारत हासिल करने के लिये चक्र काटा करते थे और अब वह कैसे उन कोठियों को नरक की कोठियां कहते हैं ।

फिर मेरे एक दोस्त ने जो लुधियाना से अकाली मैम्बर हैं यह कहा है कि लुधियाना में Law and Order की यह हालत हो गई है कि कोई भी शख्स सूरज छिपने के बाद शहर से बाहर नहीं निकल सकता । मुझे उन की इस बात पर बड़ी हैरानी हुई है क्योंकि इसी माननीय मैम्बर ने लुधियाने में Public Relations Committee की मीटिंग में बैठ कर कहा था कि उस ज़िला में Law and Order बड़ा अच्छा चल रहा है और उन्होंने वहां के Deputy Commissioner और Superintendent of Police को इस के लिये बधाई भी दी थी । मगर अब यहां यह बात कहते हैं कि वहां Law and Order ठीक नहीं रहा । मैं हाऊस को बता देना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त में crimes में हर साल कमी होती चली जा रही है । जहां १९५२ में आम कराईमस (crimes) की तादाद १,३७६ थी तो १९५३ में १,२८७ रह गई थी । इस साल सूबे में तीन डकैतियों के वकूए हुए जिन में से एक डकैती जो लुधियाना शहर के अन्दर हुई थी उस का ज़िक्र इन की तरफ से किया गया है । यह दुरुस्त है कि वहां कुछ लोग रात के आठ बजे के करीब बन्दूकें ले कर आ गये थे और एक दूकान पर उस के मालक को डरा धमका कर उस से

[दीवान जगदीश चन्द्र]

कुछ रुपया छीन कर भाग गये थे। लेकिन मुझे यह बात हाऊस में कहते हुए फ़खर होता है कि वहां Administration ने पूरे जोर से इस केस की तफ़तीश की और उन डाकूओं को पकड़ लिया गया है यह लोग मलाया से आये हुए थे वहां के लोकल होते तो और बात थी और इस के साथ ही एक और बड़े खतरनाक गैंग (gang) को गिरफ्तार कर लिया गया है जिस की वजह से पंजाब में डकैतियां कम हुई हैं। इसी तरह Burglaries की तादाद में कमी हुई है। जहां १६५२ में इन की तादाद ३१६ थी १६५३ में वे २५७ हुई है।

फिर साहिबे सदर ! मेरे एक अकाली दोस्त ने कहा है कि हमारे सूबा में लोगों को मज़हबी मामलों में आज़ादी नहीं रही है और मज़हबी नारे लगाने पर भी पाबन्दियां लगाई जाती हैं। मैं हाऊस को बता देना चाहता हूं कि एक बार लुधियाने में अकालियों की तरफ से एक जलूस निकाला गया था और वहां ऐसे नारे लगाये गये जो दूसरों के दिलों को दुखाएं। उन्हें ऐसा न करने की दरखास्त की गई पर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो ऐसे नारों पर अगर हकूमत पाबन्दियां लगाती है तो इस में कोई बुरी बात नहीं है। यह कोई औरंगज़ेब का ज़माना तो है नहीं कि किसी को यह आम बाज़ार में कहने की जुरत पड़े कि खंडा खड़का देंगे। मैं अर्ज़ करता हूं कि जहां तक आम नज़मोनस्क का ताल्लुक है उन्हें तो अपने आप को हिंदुस्तानी समझना चाहिये और हिंदुस्तानी समझ कर चलना चाहिये और जहां तक आर्थिक सामाजिक और स्यासी ख्यालात हैं उन्हें हिंदुस्तानी बन कर सोचना चाहिये। पंजाब का नज़मोनस्क दूसरे सूबों से मज़बूत है। अभी तो पैप्सू के हाल ही के Elections में वहां यही तो कहा गया था कि पंजाब में कांग्रेस की वज़ारत है वहां कितना अच्छा नज़मोनस्क है। यहां कांग्रेस ने इतना अच्छा काम किया था कि इसे देख कर वहां के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिये हैं। उन्होंने यह महसूस किया कि आम फ़िरकापरस्ती का ज़माना गुज़र गया है और इसी लिये उन्होंने अपने वोट कांग्रेस को दिये हैं।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी (आदमपुर) : स्पीकर साहिब ! मैं आप का बहुत मशकूर हूं जो आप ने मुझे बोलने का मौका दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इस का यह मतलब हुआ कि पहले आप को बोलने का मौका कभी नहीं दिया गया हालांकि कल भी आपने तकरीर फरमाई थी।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : पहले भी आप जो मौका देते रहे हैं उस के लिये भी शुक्र गुज़ार हूं लेकिन आज इस शुक्रगुज़ारी में बहुत इज़ाफ़ा करूंगा अगर आज मुझे बोलने का काफी समय देंगे।

हमने आज़ादी के बाद अपनी हकूमत बनाई। हम इस वक्त चाहते हैं कि इस में एक नई चीज़ पैदा करें एक नई current पैदा करें कि लोग हकूमत को महसूस करने

लग जायें कि यह पुरानी हकूमत से अच्छी है । जब पबलिक में यह अहसास आ जायगा तो हम समझेंगे कि हमारी हकूमत इस तरह की बन गई है जिस का हमें पहिले दिन से ख्याल था और जिसका हम स्वप्न लेते थे वह अब पूरा हो गया है ।

General Administration की demand पर बोलते हुए मैं वज़ीर साहिब की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि किस तरह से हमारे Finance Minister साहिब ने कल अपनी speech में हाऊस की तवज्जुह एक sentence की तरफ दिलाई थी। उन्होंने कहा है और बड़ी खूबसूरती से कहा है:— 'Public Expenditure will be a sheer waste, if it were reduced to the level of inefficiency' मैं उन के इस फिकरे की तारीफ करता हूं। यह बहुत अच्छा है। खर्च बेशक ज़्यादा हो जाये लेकिन efficiency जो हो उसे कायम रखा जाये। इस लिये मैं उन की तवज्जुह इस बात की ओर दिलाता हूं कि वह अपनी पूरी ताकत और सिदकदिली से Administration की efficiency को ऊंचा ले जायें। हमारे चीफ मनिस्टर साहिब ने भी अपनी एक पब्लिक स्पीच में यह कहा था कि मैं उस दिन खुश हूंगा जब कि हमारे पंजाब की सारी Administration के मुलाज़मों की तनखाह कम से कम सौ रुपया माहवार होगी। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं चीफ़ मनिस्टर साहिब की ज़बानी यह सुनता हूं। लेकिन मेरी यह खुशी देरपा भी नहीं रहती जब मैं उन की अमली बातें देखता हूं कि किस तरह गरीब मुलाज़िमों को तीस और चालीस रुपये की कलील तनखाह में बड़ी तंगी के साथ गुज़ारा करना पड़ता है। मैं नहीं कह सकता कि वह इतनी थोड़ी तनखाह पर जिन्दा भी रह सकते हैं या नहीं। साढ़े चालीस रुपया से कम तनखाह पाने वाले मुलाज़मों को तरक्की दे कर उन की Pay में ढाई रुपये का इज़ाफा किया गया है लेकिन यह इज़ाफा रु 49-8-0 तक ही पहुंच कर रुक गया। पचास रुपये से लेकर एक सौ रुपये तक की तनखाह पाने वालों को कुछ नहीं दिया गया। हमारे फाईनांस मनिस्टर (Finance Minister) साहिब बड़े काबिल आदमी हैं। उन की काबलीयत का लोहा मैं पहले ही से मानता हूं क्योंकि मेरा उन से अकसर वास्ता पड़ता रहा है और मैं उन्हें ज़ाती तौर पर जानता हूं। इस लिये मैं कहूंगा कि हमारे Finance Minister साहिब यह देखें कि 50 और 100 रुपये के दरमियान तनखाह पाने वालों के साथ वह सलूक नहीं किया गया जो किया जाना चाहिये था। यह बात कहने में मेरा यह मकसद नहीं कि उन की तनखाह 50 से 60 या 60 से 70 रुपये कर दी जाये बल्कि यह है कि जो इन में Disparities हैं वह दूर कर दी जायें। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो रु 2-8-0 बढ़ाने से तारीफ़ हासिल करने का जो हक उन्हें हो जाता है वह नहीं रहेगा। इस लिये मैं उन से इलतिजा करता हूं कि वह ऐसी मशीनरी बनायें जिस से उन लोगों की इकतसादी हालत बेहतर हो।

हमें सूबा को industrialise करने के पेशेनज़र प्राईवेट इन्डस्ट्री को encourage करना चाहिये। मुझे अफसोस है कि हकूमत ने ऐसा करने के लिये कोई रक्म बजट में नहीं रखी सिवाए bamboo industry की, यानी बांस की

[प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी]

टोकरियां या और छोटे मोटे सामान की production के। अगर इस तरफ हमारी सरकार की यही रफतार रही तो मेरा ख्याल है कि वह नक्शा कायम नहीं होगा जो हम अपने मुल्क का दुनिया में कायम करना चाहते हैं। हमने वादे तो बहुत किये मगर न तो नेक नियती से अच्छी administration ही कायम की और न ही तालीम ज्यादा फैलाई है। मुल्क अभी तक undeveloped ही पड़ा है। हमारी Central Government के Commerce Minister श्री T. T. Krishanamchari ने कहा है कि nationalisation की अभी हिंदुस्तान में स्टेज (Stage) नहीं आई क्योंकि relatively यह मुल्क बहुत पिछड़ा हुआ है और पूरी तरह develop नहीं हुआ। इस लिये Nationalisation की बात करना गुनाह है। Industry की अगर rapid growth हो जैसी कि Russia में हुई है तो फिर किसी को शिकायत नहीं रहती। हमने सही तस्वीर खींचनी है। Industry की तरक्की करनी है। लेकिन यह बातें यहां हो नहीं पातीं मगर nationalisation पहले ही शुरू हो जाती हैं। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन इस ख्याल से कि parliamentary tone नीचा न हो सिर्फ इशारे ही करूंगा।

एक मनिस्टर साहिब ने जो nationalisation की स्कीम चलाई है, उस से पब्लिक की क्या हालत है। एक तब्के में agitation फैल रही है। फिर books की nationalisation क्यों की गई। जिस की मुज़म्मत पंडित नेहरू ने भी की। सरकार की इस पालिसी से एक तरफ publishers नालां हैं, और दूसरी तरफ Operators. Finance Minister साहिब ने कहा कि मुआवज़ा दिया जायगा, operators को जगह दी जायगी, लेकिन इस तबके के लोगों को तसल्ली कैसे हो, क्योंकि उन्होंने घर घाट बेच कर अपना सारा सरमाया लगा कर यह छोटी सी industry कायम की थी।

सब से पहले हकूमत को तवज्जुह agriculture की तरफ देनी चाहिये। Five-Year Plan में industrialisation के साथ ही इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये। पहले २ यह कहा गया है सड़कें बनेंगी, नहरें बनेंगी और रेलें अच्छी होंगी। यह वही चीज़ है जो हमें स्कूलों में अंग्रेज़ों की बरकतों के नाम से पढ़ाई जाती थीं। यही अब कहा जा रहा है कि सड़कें होंगी, नहरें चलेंगी और रेलें बनेंगी। यह तो बड़ी मामूली सी चीज़ है। मगर हमारी हकूमत इस के गीत गाये जा रही है। Five-Year Plan पर commentary हमारे मुल्क में भी हुई थी और foreign countries में भी हुई थी। सब ने इसे एक बड़ी ही modest सी plan बताया है। हमारे Finance Minister साहिब ने भी इसे एक modest सी स्कीम ही बताया है। मुझे खुशी है कि उन में भी सच बोलने वाले हैं।

अब दखिये कि लोगों की हालत क्या है। मैं सच कहता हूं कि लोग दुखी हैं। इस किस्म के सैंकड़ों केस देखने में आये है जिन में लोगों ने खास कर नौजवानों ने इस ज़िन्दगी से तंग आकर suicide कर लिया। जेब से कागज़ निकला तो लिखा था 'मेरे पास गुज़ारे का कोई साधन नहीं था। नौकरी के लिये सैंकड़ों दरखास्तें दीं लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। इस लिये तंग आकर रेल के नीचे सिर देकर इस दुनियां से चला जाता हूं।" हिंदुस्तान के अन्दर ऐसी सैंकड़ों मिसालें हमारे सामने आ चुकी हैं। जिस मुल्क के अन्दर यह हालत हो. बेवाओं की यह हालत हो उस का क्या बनेगा। उन वर्करज़ की families और widows का बजट में नामो निशां नहीं जिन को मुल्क के लिये फांसी मिली। हमारे Finance Minister साहिब ने बताया कि एक ऐसी बेवा का नाम दर्ज कर लिया है और एक ऐसा केस under consideration है और बाकी 10 हैं जिन के मुताल्लिक कुछ नहीं कहा गया। यहीं बस नहीं इस किसम की 800 applications पड़ी हुई है जिन के मुताल्लिक कुछ नहीं कहा गया। इन से पूछो तो next year, next year की आवाज़ सुनाई देती है। Political sufferers के बारे जो उन्हों ने कहा उस की हम दाद नहीं दे सकते ।

अध्यक्ष महोदय : आप के ५ मिनट और रह गये हैं।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : मैं unemployment के बारे बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन संकोच करता हूं। अभी तक मेरे मुल्क में बहुत बेकारी है, परेशानी है। हकूमत न कोई plan बनाती है और न सोचने की तजवीज़ ही करती है। यहां आजकल की education बिल्कुल ridiculous है। असली चीज़ तो basic education है जिस से Basic necessities of life पूरी हो सकती हैं। आज के स्कूल और कालिज़ तो मिट्टी के खिलौने हैं।

ऐडमनिस्ट्रेशन जो है वह universal basis पर national income को खर्च नहीं कर रही है। इस का फर्ज होता है कि वह अच्छे तरीके से मुल्क के पैसे को खर्च करे।

Education का जो तरीका है वह भी अजीब है। यह ठीक है कि लड़कों और लड़कियों के लिये बेसिक स्कूल खोले जा रहे हैं मगर जहां 50 लड़के या लड़कियां हैं वहां भी एक टीचर (teacher) और जहां 60-70 तक हैं वहां भी एक टीचर (1 teacher) नियत किया जाता है। हमें तो अब यह देखना है कि क्या तालीम इस तरह से दी जा सकेगी ? क्या इस ढंग से बच्चे समझ सकेंगे ?

यह कहा गया है कि गवर्नमैण्ट के अन्दर बड़ा इनसाफ है। महिकमों और अफसरों में से corruption दूर करने के लिये Public Service Commission और Subordinate Services Selection Board बना दिये गये हैं। मगर मैं समझता हूं कि यह बोर्ड आदि केवल इस लिये बनाये गये हैं कि पावर (power) को centralize किया जाये। ताकि सब चीज़ें वज़ीरों के हाथों में से गुज़रें। इन बोर्डों का यह फायदा है कि मनिस्टर अपने आदमी इस तरीके से लगा सकते हैं। इस

[प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी]

तरह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि सरविसों में कोई intellectual calibre आ सकता है। पावर को centralize करने से corruption बढ़ेगी। Public Services Commission और Subordinate Services Selection Board तो महज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को नौकरियां दिलाने की गर्ज़ से बनाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफैसर साहिब ! क्या आप कोई जिम्मेदारी भी महसूस करते हैं या नहीं। आपको पता होना चाहिये कि Public Service Commission और Subordinate Services Selection Board के मेम्बरों के character और integrity पर कोई हमला नहीं होना चाहिये। और इस को Challenge नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है आप इस बात का ख्याल रखेंगे।

प्रोफैसर मोता सिंह आनन्दपुरी : मेरे पास सबूत हैं। अगर वज़ीर साहबान चाहें तो मैं चिट्ठियां पेश कर सकता हूं। (*interruptions*) अब यह मुझे interrupt कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : Please do not take notice of their interruptions.

प्रोफैसर मोता सिंह : मैं मानता हूं कि हकूमत चलाने के लिये टैक्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। पर इस के लगाने के ढंग और होते हैं। इस का मतलब यह नहीं कि आप Revenue पर टैक्स लगा दें। आप estate पर टैक्स लगा सकते हैं। आप बेशक और चीज़ों पर टैक्स लगा दें मगर गरीब किसानों पर 18 लाख का टैक्स न बढ़ाओ। किसान तो पहले ही कई तरह के टैक्स दे रहा है अब Revenue पर टैक्स लगाना वाजिब नहीं।

दूसरी चीज़ Economic Situation की है। इस के बारे में मुझे यह कहना है कि high prices हैं और low earnings हैं। trade बेशक बढ़ रही है मगर low earnings को ऊपर उठाने की ज़रूरत है। Unemployment का ज़िकर किया गया है। एक लम्बी चौड़ी तफसील दी गई है कि किस तरह इस को दूर किया जायगा पर कोई चीज़ पूरी होती नज़र नहीं आती और बेरोज़गारी दिन बदिन बढ़ रही है।

आखरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह untouchability के बारे में है। कल Tribune के काबल एडीटर साहिब ने इस के बारे में कुछ बातें कही थीं। जिससे बहुत हद तक इस का हल निकल सकता है। मुझे पता चला है कि untouchability को दूर करने के लिये Constitution में एक धारा लाई जा रही है। और कानून बनने वाला है। आप अगर slums में जा कर देखें तो पता चलेगा कि उन के रहने की जगह कितनी गन्दी है और वहां पर लोग गौओं, भैंसों की तरह कई कई एक एक घर में रह रहे हैं। मैं अर्ज़ करूंगा कि फिनांस मनिस्टर (Finance Minister) साहिब इस की तरफ तवज्जुह दें। अगर ऐसी हालत को दूर न किया गया तो कांग्रेस राज्य बदनाम हो जायगा।

ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਨੂਰਮਹੱਲ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, General Administration ਤੇ ਜੋ ਅਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ! ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ opposition ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਬਜਟ ਤੇ general discussion ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਣ ਵਾਸਤੇ efficiency ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫੀਸ਼ਨਸੀ ਵਧਾਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੇਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜੋ ਨੁਕਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਫੀਸ਼ਨਸੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ crimes ਨੂੰ ਰੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਬਲਕ peace ਨੂੰ disturb ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

ਫਿਰ unemployment ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ revolt ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਠਾਏ ਹਨ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ Small Scale Industries ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Uncultivated Evacuee Land ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ੪,੦੭੫ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ]

ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੇਹਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ unemployment ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ Administration ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵਡੇ ਅਫਸਰ ਤਕ ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛਡੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਕਦੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ Copying Agency ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ document ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਈ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੇਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਕੇ ਨਕਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੀਘਰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪਵੇਗਾ।

ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਅਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ Sanctity ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਉਥੋਂ ਦਾ atmosphere ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ court ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ atmosphere ਵਿਚ ਮੁਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਚੀਜ਼ decentralization ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡ ਨੂੰ ਫਿਲੌਰ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Justice ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਕਸਦ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਲਵੰਡ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਇਕ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ੫੦ ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਸਕੇ। ਅਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨ ਕੇਵਲ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਜਲਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਜੇ ਫੇਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਲੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Decentralisation ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ inconvenience ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ Sub-Division ਬੇਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮਗਰ ਫਲੌਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਰਦਾਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਭਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਤੰਗੀ ਤੇ ਹਨੇਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੰਦ ਓਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦ ਓਹ ਸਨ ਜਿਨਾ ਨੇ

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ]

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨੈਹਰੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਧਮਾਚੌਕੜੀ ਮਚਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਜਹ ਨਾਲ ਹਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਅੱਗੇ ਨੇਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਜਦੋਂ no-confidence vote ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਨ੍ਹੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ PEPSU ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਲੂਮ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸਾਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤ ਲਈਆਂ (hear, hear)। ਇਹ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ communalism ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ A.C.O. ਅਤੇ C. Os. ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ efficient ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਲਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ communalism ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ communalism ਨੂੰ ਛਡ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਅਪਣ communalism ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ............

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਧੋਖਾ......

ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ : ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫਜ਼ withdraw ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਰੇ Communalism ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ Public Service

Commission ਅਤੇ Subordinate Services Selection Board ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਈ ਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਿਆਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਭੈੜੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤੇ Communalism ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਨ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।

ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ scientific approach ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ reformatory ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਖੋਲ੍ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਲ Scientific approach ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਦਾਂ ੨ ਪੰਦਰਾਂ ੨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਬਾਂ ਕਟਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਇਸ reformatory ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ।

Rehabilitation ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ dissatisfied ਹੋਣ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਅਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਸੀ। Non-permanent allotments ਨੂੰ Quasi-permanent ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ ਜਿਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ (Hear, hear)।

ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ demand ਇਕ ਤਰੱਕੀਯਾਫ਼ਤਾ ਬਜਟ ਦੀ demand ਹੈ। ਸਾਨੂੰ administration ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ]

Co-operation ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ opposition ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ destructive criticism ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਣਾ co-operation ਦੇਣ ।

श्री मनी राम (फतेहाबाद) : सभापति जी ! General Administration की बाबत आज कुछ Opposition वालों ने कहा और कुछ बरसरे इकतदार पार्टी वालों ने । इन में से बरसरेइकतदार पार्टी वालों ने पहले तो बजट पर सरकार को बधाई दी और फिर अपने अपने ज़िलों की तकलीफ़ों को रोना शुरु कर दिया । मेरा ख्याल है कि अगर कोई वज़ीर साहिब इस पर बोलते तो वह भी ऐसा ही करते ।

मुझ से पहले जो कांग्रेसी भाई बोले उन्होंने Administration की तारीफ की और साथ में जो उन्हें passports के बारे तकलीफ़ थी वह भी कह डाली है । उन्हें यही तकलीफ थी । उन्हें और तकलीफ हो ही क्या सकती थी । उन्हें कोई पुलिस का Inspector या Sub-Inspector तो तंग कर ही न सकता था ।

स्पीकर साहिब ! Administration एक साधन होता है जनता को सरकार के साथ मिलाने का । Administration खूबसूरत बिलडिंगों में नहीं देखी जाती । अगर Administration को देखना है तो गांवों और शहरों में देखिये । विचारे गरीब किसानों की क्या बुरी हालत हो रही है । गरीब किसानों को जो सारे देश का पेट भरता है ज़मीन से उखेड़ा जा रहा है । मैं कहता हूं क्या ऐसा करने से हमारी ज़मीन बेकार न हो जायेगी और क्या इस तरह हम अपनी State को Welfare State बना सकेंगे ? मुझे यकीन है कि अगर किसान के साथ यह सलूक हुआ तो सूबा आगे नहीं पीछे जायगा । सरकार जानती है और दूसरे सब लोग जानते हैं कि हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का violence अर्थात तशद्दद में विश्वास नहीं । कोई भी ऐसी report पेश नहीं की जा सकती जिससे ज़ाहिर हो कि हमारी पार्टी ने तशद्दद से काम लिया हो । लेकिन इस के बावजूद Administration की गलतबयानी पर जब हमारा पुरअमन जलूस हिसार में जा रहा था किसी सियासी भेद के मातेहत दफ़ा १४४ लग दी गई । जलूस क्या कर रहा था । कोई violence नहीं हो रही थी । "गांधी अमर रहें" के नारे लगाये गये थे और लोग अपनी पंचायत के सामने अपनी तकलीफ़ रखने के लिये जा रहे थे । इस मौका पर हिस्सार में इतनी पुलीस लगा दी गई कि शायद हमारे इतने आदमी भी न थे । दफ़ा १४४ लगा कर उन्हें अपनी पंचायत के पास जाने से रोका गया ताकि वे अपनी मांग मनवा न सकें । इन गरीब लोगों की पुरअमन शनवाई न होने दी । मैं पूछता हूं कि क्या इन हालात में ऐसा कानून लागू कर देना democracy के खिलाफ नहीं ? क्या इसी को Civil Liberties कहा जाता है ? यह तो Civil Liberties के साथ मज़ाक करना है । हो सकता है कोई ताकत के नशे में इस चीज़ को जायज़ साबत करदे, वरना इसे कोई ठीक न कहेगा । जब हमारा पुरअमन जलूस जा रहा था तो हमें पकड़ लिया गया और धक्के

दे कर जेल की तरफ ले जाया गया। मुझे हथकड़ी लगाई गई । श्री प्रेमऋषि जो हमारे All-India Executive के मैम्बर हैं उन्हें भी हथकड़ी लगाई गई। यह नहीं कि मुझे Police के D. S. P. साहिब और Magistrate साहिब जानते न थे। यह लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर भी यह हमें हथकड़ियां लगा कर झटके देते हुए जेल को ले गये और ६ तारीख तक हमें वहां रखा। यह है वह सलूक जो यह सरकार सियासी मुखाल्फों के साथ करती है। यहां पर मुझे दो Communist साथियों की, जो जेल में पड़े हैं बात याद आ गई है। हमारी सरकार और इस के हामी यह कहते हुए नहीं थकते कि रूस में एक पार्टी की हकूमत है और वहां पर किसी प्रकार की मुखालफ़त को बरदाश्त नहीं किया जाता। मुखालिफ़ों को गोली से उड़ा दिया जाता है। परन्तु मैं उन से कहता हूं कि आप तो महात्मा गांधी के असूलों पर चलने वाले लोग हैं। यदि आप यह समझते हैं जो यह मेरी अपनी राय न हो कि रूस में ऐसा किया जाता है मगर आप रूस के नक्शेकदम पर क्यों चलते हैं आप एक ग़लती को मिटाने के लिये दो ग़लतियां क्यों करते हैं। मैंने देखा है कि इन दो Communist detenus को चार महीने से C Class में रखा हुआ है। मुझे बहुत दु:ख है कि इन लोगों से यह सलूक हो रहा है। इन्हें Political class दी जानी चाहिये। यह बातें democracy और Civil Liberties के खिलाफ हैं। स्पीकर साहिब! General Administration में इतनी Corruption है कि जब तक यह नहीं मिटती, सूबा तरक्की नहीं कर सकता। Corruption का मतलब सिर्फ रुपया लेना, लिहाज़ या कुंनबा-परवरी ही नहीं होता। यदि अनजान होने के कारण बेइनसाफी कर देने को भी Corruption नहीं कहते। लेकिन जानते हुए कि इनसाफ यह है उसे न करना Corruption कहलाता है।

अध्यक्ष महोदय : आपके पांच मिनट और हैं!

श्री मनी राम : बहुत बेहतर, स्पीकर साहिब! मैं कहना चाहता हूं कि सुधार ऊपर से होना चाहिये नीचे से नहीं। मेरे एक साथी ने कहा था कि खराबी नीचे है। मैं इस बात को नहीं मानता। मेरे दोस्त केवल वही बातें कह देते हैं जो वज़ीर इन्हें कहने को कहते हैं। मैं देखता हूं कि बड़े अफ़सरों के तो यह लोग पुजारी हैं। जब किसी Executive Engineer का ज़िक्र आता है तो चौधरी लहरी सिंह भगवान की तरह अपने भगत को बचाने के लिये उठ खड़े होते हैं। परन्तु यह ठीक नहीं। Corruption गरीब चपड़ासियों और Constables में नहीं। यदि थोड़ी है भी तो उस का कारण उन की भूख है। Corruption तो असल में बड़े अफ़सरों में पाई जाती है जो अपने ऐशोइशरत के लिये गरीबों को लूटते हैं। यह बड़े लोग केवल रिश्वत लेते ही नहीं देते भी हैं। हैरानी की बात है पीछे जब चौधरी लहरी सिंह Election Tour पर भाकड़ा गये तो रिश्वत दे कर आये। वे भगीरथ का अवतार बन कर गये थे। फ़रीदपुर के लोगों ने कहा कि वे इस शर्त पर सहायता करेंगे अगर उन के गांव के लिये मोगा दिया जाये। चौधरी लहरी सिंह ने उसी समय Executive Engineer को बुला

[श्री मनी राम]

कर उन्हें मोगा दिला दिया। यह हैं बड़े लोगों के तरीके। जब बड़े लोग रिश्वत लेते और देते हों तो रिश्वत लेना एक धर्म बन जाता है और लोगों का रहजान खुदबखुद इस तरफ हो जाता है। लोग वह काम नहीं करते जिस की निन्दा हो। इस लिये मैं कहूंगा कि रिश्वत ऊपर है। बड़े अफ़सरों में है, नीचे नहीं। चपड़ासी बिचारे क्या रिश्वत लेंगे? उन से तो रिश्वत ली जाती है। दिन भर तो वे बिचारे office में काम करते हैं और उस के बाद उन्हें अफ़सरों के घरों में काम करना पड़ता है और उन के बच्चों को खिलाना पड़ता है। यह रिश्वत नहीं तो और क्या है।

स्पीकर साहिब, वक्त की तंगी के कारण मैं केवल एक और बात अर्ज़ करना चाहता हूं। मैं निहायत अदब के साथ appeal करूंगा कि रोहतक के ज़िला के अन्दर क्या हुआ; ज़िला रोहतक में क्या हुआ इस मामले पर बहिस में पड़ने से यह बात लम्बी हो जायेगी। अगर पचास आदमी एक ग़लत मांग पेश करते हैं या सौ आदमी एक ग़लत मांग पेश करते हैं तो बरसरेइक्तदार पार्टी का फर्ज़ हो जाता है कि वह उस में तहकीकात करवाये। अगर तहकीकात न हो तो इस का मतलब यह है कि बरसरे इक्तदार पार्टी एक ब्यान दे दे और ताकत के जोर से इस बात को दबा दे। यह अच्छी बात नहीं होती। इस लिये अध्यक्ष महोदय मैं आप के द्वारा मंत्रिमंडल से यह कहूंगा कि इस बात को सुलझाने का वाहिद तरीका यह है कि तहकीकात कराई जाये। अगर enquiry के बाद बात साबित हो गई तो गवर्नमैण्ट की नाअहिलियत साबत हो जायगी अगर ग़लत भी साबत हुई तो भी Administration की नाअहिलियत होगी जिस के खिलाफ इतनी ग़लत बात चली। इस लिये मैं समझता हूं कि इस मामला में enquiry करानी बहुत ज़रूरी है। मैं हाऊस का ज्यादा वक्त नहीं लेता और इन शब्दों के साथ अपने स्थान पर बैठता हूं—

सिंचाई मंत्री : श्रीमान जी, अगर आप की इजाज़त हो तो मोगा के बारे में कह दूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वे बैठ जायें।

ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁਨਾਸਿਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਚੰਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਗੜਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਨ ਵਡੀ ਵਜਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲਖ ਪੰਚੇ ਪਏ ਪਾਉ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ

ਨਾ ਰੁਪਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਪੜੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਟੈਲੀਫੂਨ ਖੜਕਾਏ ਕਿ ਇਥੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਟੁਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਘਾਬਰੇ ਹੋਏ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਤੇ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨ ਤੋੜੋ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਰੀਬ ਲੁਟੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਅੱਪਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਪਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ (memorandum) ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਏ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਪੇਚਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਨਾ ਟੁਟੇ।

सिचाई मंत्री : औचित्य प्रश्न । क्या General Administration पर बहिस करते हुए अप्पर हाऊस के सम्बन्ध में बहिस की जा सकती है (आवाजें : हाँ अप्पर हाऊस भी इस माँग में शामिल है ।

सिचाई मंत्री : मैं समझता हूं कि माननीय मैम्बर प्रसंग अनुकूल है बात नहीं कर रहे

अध्यक्ष महोदय माननीय मैम्बर को चाहिये कि वह अप्पर हाऊस पर इस समय बहिस न करें ।

ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ੩੦ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਖਰਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲੇਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਵਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ । ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ੫੦੦ ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲਗੇ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ । ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ੧,੫੦੦ ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਫਰ ਖਰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕੀਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਖਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 20, 30 ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਕ ਭਾਰੀ ਕੁਟੰਭ ਪਾਲਣ ਦਾ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੋ ਤਿਨ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਮੁਕਦੱਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀਓਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨ ਛਡੇਗਾ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਕੀਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਤੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਦਾਖ਼ਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ General Administration ਹੈ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟ ਕਰ ਦਿਉ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ੨,੦੦੦ ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ੧,੫੦੦ ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਲੈਣੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ੫੦੦ ਰੁਪਿਆ ਮਾਹਵਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਉਭਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਤੀਹ ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਡਿਆਂ ਵਡਿਆਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਕੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੇ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ

standard of living ਉਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਮਾਹਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰਖਦੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ S. O. ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਇਕ ਵਡਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ 70 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰੇ । ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਸੀਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪਿੰਡ ਲੱਗਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾੜਾਬਦੀ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ । ਪਹਿਲੇ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਕਿ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਅਫਸਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਆਈ । ਇਸ ਗੜਬੜ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੂਕ ਦਿਤੇ । ਕੀਹ ਉਤੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ?

ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜਦ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਹਰ ਇਕ ਥਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ । ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਡੁਬ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਨਾਲਾ ਕਢ ਕੇ ਚਾਰ ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਂ । ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਡੁਬ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ (ਰੋਪੜ) : ਪੂਜਯ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ Demand No. 10. General Administration ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ

[ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ]

ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਭੇਜਨ ਭਿਜਾਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਉੜਾਈਆਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਕ ਪੋਸਟ ਉੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ district administration ਨੂੰ reorganise ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਹ reorganisation ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ limitations ਭੀ ਹਨ। ਪਰ ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ reorganisation ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਲਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ arms ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕਵਾਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਦੀ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ।

ਅਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ General Administration ਦੀ demand ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ

ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਤੇ ਜਨਰਲ discussion ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ country ਦੀ ਆਮ ਹਾਲਤ ਤੇ discussion ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦੀ leniency ਬਹਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ irrelevancies ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ।

अध्यक्ष महोदय : यह जो आप कह रहे हैं यह भी irrelevant है।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ : I am very sorry, Sir. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ General Administration ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ Civil Secretariat ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਾ procedure ਬਹੁਤ ਲੰਮਾਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ, ਅੰਡਰ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ reorganisation ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Secretariat ਦੀ ਵੀ reorganisation ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ Gorowala Committee ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਕੇ Central Government ਨੇ Central Secretariat ਨੂੰ reorganise ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਇਥੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Secretariat ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ simplify ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ Senior Clerk ਦਾ ਕੰਮ junior clerk ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪ੍ਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਪਾਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਉਡਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ simplify ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਸ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਅਫ਼ਸਰ confidence ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ checking ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ checking ਜੇ junior ਕਲਰਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ

[ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ]

ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੁਝ officials ਅਤੇ ਕੁਝ non-officials ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

General Administration ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਕਮ Anti-Corruption Committee ਲਈ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ Anti Corruption Committee ਨੇ ਕਿੰਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ officials ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਚਲਾਇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 117 Officials ਨੂੰ dismiss ਕੀਤਾ ਗਿਆ 28 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ revert ਕੀਤਾ ਗਿਆ; 28 ਦੀ increment stop ਕੀਤੀ ਗਈ; 64 ਨੂੰ warn ਕੀਤਾ ਗਿਆ 28 ਨੂੰ retire ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 12 resign ਕਰ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ cases ਵਿਚ ਜੋ speedy action ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ Indian Penal Code ਅਤੇ Criminal Procedure Code amend ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ codes ਨੂੰ amend ਕਰਨਾ ਇਸ House ਦੇ scope ਤੋਂ ਬਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Parliament ਹੀ amend ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ Corrupt Officers ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। Legal procedure ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ criminal case ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Evidence ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾਂ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ witness medical certificate ਭੇਜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਫਸਰ 50,000 ਰੁਪੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪੰਜ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚ ਕੇ ਗਾਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ case ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ Ciriminal Procedure Code simple ਹੋ ਜਾਇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ suspend ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ

corruption ਦੇ cases ਉਪਰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ Central Government ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ corruption cases ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ procedure suspend ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ cases ਦਾ summary trial ਕਰ ਕੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ transporation for life ਦੀ ਦਿਤੀ ਜਾਇ। corruption ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ progressive countries ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਫਾਜ਼ਲ ਦੋਸਤ ਹੋਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਹਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ General administration ਉਪਰ ਖਰਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਰਚ ਨੂੰ ਏਨਾ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ efficiency ਘਟ ਜਾਵੇ advisible ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਰਚ ਉਸੇ ਹਦ ਤਾਈਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਾਈਂ administration ਦੇ ਠੀਕ ਚਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਂ ਪਵੇ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲ Chief Minister ਹੋਰਾਂ ਦੇ notice ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। District headquarters ਅਤੇ ਤੈਹਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ officials ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ litigants ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆਇ ਹੋਇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ copy ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜ ਜਾਣ ਤਾਂ copying agent ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਔਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਿਛੋਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, copy ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਭ offices ਵਿਚ corruption ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂ ਵੀ administration ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤਾਈਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ pursue ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਕ table ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ

[ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ]

ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤਿਆਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। public ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ confidence ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ disposal of receipts ਉਪਰ ਹਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ Check ਹੋਵੇ। ਮੈਂ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਇਕ campaign ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਬੜਾ healthy effect ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ efficiency ਵਧ ਗਈ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ Development Minister ਸਾਹਿਬ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ Ministry ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ corruption ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ campaign ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ "ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਦੀ spirit ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ development ਕਰੋ" ਇਸ ਤਲਕੀਨ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤਾਈਂ ਜ਼ਾਇਲ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹੀ spirit ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ (ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਹਾਵਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਗਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਡ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ-ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਰਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਗਠ-ਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੜੇ ਤਫਰਕੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਗ ਆਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਦੇ ਹਨ "ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਯੂਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਹਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂ ਜਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ"। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੇ ਚਲਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਚੁਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : ਇਹ ਚੰਗੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਹਦਾਪਨ ਹੈ।

Shrimati Sita Devi: Is this word parliamentary?

Mr. Speaker: Please withdraw this word.

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ: ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਯੂਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ war hysteria ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਝਟ ਦਫ਼ਾ ੧੪੪ ਹੇਠ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਯਾਦ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਿਛੋਂ ਢੰਡੋਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਚਿੱਆਂ ਤੇ ਬੁਢਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਪਰ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Minister for Development : I can go and explain things to the people at any time I like.

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ: ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 'ਜਾਣਾ ਮੁਬਾਰਕ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਚਿੱਆਂ ਜਾਂ ਬਢਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀ ਜਲਸਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਿਆਂ ਬੁਡਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁਟਣ ਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਰਖਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

[ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ]

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਗਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਸਾਡਾ ਲਗਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਰ ਮਹਾਤਮਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪਖਪਾਤੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਹੁਣ ਉਠਕੇ ਬਾਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗਲ ਕਢਕੇ ਬਾਹਿਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ 'ਮੈਂ ਕਬ ਕਾਂਗਰੀਸੀ ਹੂੰ, ਆਪ ਕੇ ਗਾਂਵ ਮੇਂ ਪੀਨੇ ਕਾ ਪਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ'। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਰਖੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਲੁਹੀਆਂ ਸਰਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਤੇਗ ਰਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇ ਚਲਿਆ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਭ ਉਸ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 1949-50 ਵਿਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜੋਗਾਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੱਝੀਂ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਕਾਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੋਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿਉ। ਹੋਰ ਦਿਤੀ ਲੇਕਿਨ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਲੂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਗੰਢ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਚੌਕੀ ਬਿਠਾ ਦਿਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਤਰਖਾਨ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਚੌਕੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੌਕੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਇਥੋਂ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਚੌਕੀ ਦਾ ਖਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ,ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 17 ਚੌਕੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਚੌਕੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਫ਼ਲਾਣੇ ਫੁਲਾਣੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਇਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੌਕੀਆਂ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਲਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। decentralise ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ powers ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਪੰਜਾਂ ਸਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਲ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੱਝੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਮੱਝ ਬੀਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੇ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸਾਂ ਮਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਉਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਸਲਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਹਿਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹਵਾ ਬਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਈ ਫੁਲਾਣਾ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਗਲ ਭਾਵੇਂ ਸਚੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ

[ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ]

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਹ ਭਾਂਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਨ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਓਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਓਥੋਂ ਹੀ ਓਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹਵਾ ਬਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲ਼ੇ ਬਲ਼ੇ। ਲੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਾਰ ਫੁਲਾਨਾ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਕ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਊਂਸਪਲਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਵਾਦ ਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੁਟੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗ੍ਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸੈਯਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ corruption ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ warder ਜੇਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅਗੇ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਭ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਨ ਉਹ Superintendent ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਰਬਾਨ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇ ਦਿਨ Superintendent ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਐਸੀ ਜਗਹ ਉਪਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਦਸਤੂਰ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਮੀਨੁ ਦੀਨ ਵਾਂਗੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਰਵਈਆ ਛਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਖਿਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਹ ਪੋਲੀਸ ਕਰੇਗੀ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ! ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੁਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਚਮੁਚ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਬਰ ਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੇ ਦੁਕੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਪੰਜ ਦਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੋ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਚੁਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਕੀਹ, ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬਚਿਆਂ ਅਤੇ ਟਬਰ ਟੋਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ ਖਰਚ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਗਾਇ। ਅਸਲੀ ਮਦਦ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਸਿਆਸੀ ਢੋਂਗ ਅਤ ਆਡੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬੜੇ ਸੁਚਜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੀਆਂ ਡੀਗਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਅਜ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਧਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਦਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਉਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਥੇ ਕਰਨ ਕੀਹ ਆਇਆ ਏਂ? ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ।

ਫਿਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਈ ਕੀ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਨਾਂ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ

[ਸ੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ]

ਗਰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਇਹ ਮਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਿਧੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ । ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਣਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿਕਣ ਦੋ ਚਾਰ ਰੁਪਈਏ ਦਿਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਨਕਲ ਵੀ ਲੈਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

श्री नानहू राम (गोहाना) : स्पीकर साहिब, आपने जो मुझे बोलने के लिये टाईम दिया है इस के लिये मैं आप का शुकरिया अदा करता हूं । मैं हाऊस की जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं कि मैं यहां ज़िला रोहतक के गोहाना हल्के की नुमाइन्दगी करता हूं । इस लिये जिन दो गांव—राबड़ा और जागसी—के मुतअल्लिक मेरे मुख्तलिफ भाइयों ने पुलिस के मुज़ालम की झूठी और फ़र्ज़ी कहानियां इस हाऊस के अन्दर सुनाई उन के बारे में कुछ हकीकत आप के रूबरू रखना चाहता हूं ।

पंडित श्री राम शर्मा जो कि हमारे ज़िला के मोहतरम और बुजुर्ग नेता हैं, ने भी अपनी तकरीर के दौरान में इस बात को माना था कि जब ज़िला के हालात बिगड़ गये थे, उसी वक्त पुलिस ने कार्यवाही शुरु की । इस के इलावा दूसरे भाइयों ने और चौधरी मामचंद जी वगैरा ने अपनी तकरीरों में जो कुछ भी क्यों न कहा हो मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्हों ने यह बखूबी तसलीम किया है कि इन गांव में डाकुओं के गिरोहों ने अंधेर गर्दी मचा रखी थी और हालात इतनी नाजुक सूरत इख्तयार कर चुके थे कि पुलिस को कार्यवाही करने पर मजबूर होना पड़ा ।

इन परेशानकुन हालात से हमारे कम्यूनिस्ट भाइयों ने फ़ायदा उठाया । वह वहां गांव में गये और कई किस्म की फ़र्जी कहानियां घड़ लीं । उन का तो यह असूल ही है कि 99 बार खूब झूठ बोला जाये क्योंकि उन का विश्वास है कि 100 वीं दफ़ा तो वह झूठ भी सच बन जायेगा । इस लिये अपने इस असूल पर काम करते हुए उन्हों ने कई प्रकार के झूठ घड़े, फ़र्ज़ी कहानियां तैयार कीं । मैं, स्पीकर साहिब, खुले तौर पर यह बताना चाहता हूं कि किसी असली औरत की बेइज्ज़ती तो वहां पर कोई नहीं हुई । हां अगर उन्हों ने कोई नकली औरतें बनाई हुई हों और उन की अस्मतदरी हुई हो, तो मैं कुछ नहीं कह सकता ।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस ने तभी अपनी कार्यवाही शुरु की जब हालात बहुत ही खराब हो चुके थे और पानी सिर के ऊपर से गुज़र चुका डाकुओं ने

ने दिन दिहाड़े अंधेर मचा रखा था और वहां के अमन और कानून को ताक पर रख दिया था। मैं इस सम्बन्ध में केवल एक मिसाल आप के सामने रखता हूं। रावड़ा गांव के अन्दर एक नाबालग लड़के को हेमराज डाकू ने गोद में लिया। यानी उसे मुतबन्ना बनाया। यह सारी चीज़ वहां सभी के सामने हुई, किसी को उस के खिलाफ कुछ कहने की जुरत न थी—इतनी दहशत फैला रखी थी उस ने वहां। खूब शराब के दौर चले, हलवे बने और खीरें पकाई गईं। उस function के दौरान हेमराज ने उस लड़के से वाईदा लिया और कहा कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया या मारा गया तो मेरे इस काम की जिम्मेदारी तुमने अपने सिर पर लेनी है और इसे आगे बढ़ाना है। सो हालात इतने खराब हो चुके थे कि किसान अपने खेतों में जाने से डरते थे। जब उन की बारी आती थी खेतों में पानी देने की तो वे डरते, यह भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा था। इलाके में इतना डर पैदा हो चुका था कि लोग दिन में भी अकेले सफ़र करते डरते थे। दिन दिहाड़े वहां पर कत्ल हो रहे थे। लोगों को जिन्दा जला दिया जाता था; दरख्तों से बांध कर गोली से उड़ाया जाता था। कई हज़ारों के मजमे में से चौधरी रिज़क राम के मुन्शी को पकड़ कर बाहर जाकर मारा गया। जब हालात इस कदर खराब हो गये तो क्या पुलिस कार्यवाही न करती? क्या पुलिस कम्यूनिस्टों की खड़ी की हुई इस conspiracy के सामने घुटने टेक देती? क्या गवर्नमैण्ट अपने सूबे के एक हिस्से में इस तरह के हालात को जारी रहने देती? हमारे कम्यूनिस्ट भाई तो फ़र्ज़ी कहानियां बना कर लोगों को गुमराह करना चाहते थे। वे तो चाहते थे कि रोहतक के इन हिस्सों में एक दूसरा तिलंगाना बनाया जाये और इस प्रकार हकूमत को बदनाम किया जाये। लेकिन मैं स्पीकर साहिब, आप के द्वारा इन भाइयों को वाजेया तौर पर यह बताना चाहता हूं कि जब तक यह हकूमत की बागडोर हमारी इस कांग्रेसी सरकार के हाथ में है, हम उन की इन चालों को कभी भी सफ़ल नहीं होने देंगे। हम कभी भी यह बरदाश्त नहीं कर सकते कि बलवाई लोग कानून को अपने हाथों में लेकर देश में बेचैनी पैदा करें और पंजाब में एक दूसरा तिलंगाना बना दें। (तालियां)।

स्पीकर साहिब, मैं आप के सामने इसी लिये कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं कि असली हालात पर रौशनी डालूं। स्पीकर साहिब, मेरे मोहतरिम भाई और बुज़ुर्ग नेता पंडित श्री राम शर्मा ने चैलेंज (challenge) किया है। मैं ने तो, प्रधान जी उन के चैंलिजं को सन् 1951-52 में ही कबूल कर लिया था। लेकिन अब मैं आप के द्वारा उन नेता को अपना यह चैलेंज पहुंचाना चाहता हूं कि मैंने तो उस वक्त उन का चैलेंज मंज़ूर किया था। अब वह मेरा चैलैंजं मंज़ूर करें कि अब जबकि मनिस्ट्री में न रहने के कारण वह अप्पोज़ीशन में चले गये हैं और कांग्रेस से भी निकल गये हैं, अपनी असैम्बली की सीट से भी अस्तीफा दे कर दोबारा इलैकशन के मैदान में आएं। मैं चैलैंजं करता हूं कि उन सारे के सारे आठों भाइयों को, जो कि कांग्रेस के नाम पर इस असैम्बली में चुने गये थे, कि वे अपनी सीटों से अस्तीफा दे कर दोबारा चुनाव लड़ें। मुझे यकीन है कि उन्हें अच्छी तरह से आटे दाल का भाव मालूम हो जायगा। (तालियां)।

स्पीकर साहिब, मैं आप को बताना चाहता हूं कि मैं खुद राबड़ा और जागसी गांव में गया। मेरे भाई श्री माम चन्द ने भी इस बात को कबूल किया था कि वहां पर हालात इतने

[श्री नानहू राम]
नाजुक हो गये थे--डाकुओं की कार्यवाहियों के कारण--कि वे खुद भी कई महीने उस गांव में नहीं गये क्योंकि उन्हें खुद अपनी जान का खतरा था। इसी तरह दूसरे भाइयों ने भी कहा। खैर, मैं आप को बता रहा था, स्पीकर साहिब, कि मैं खुद उस गांव में गया। सारे हालात मालूम किये। यह भी पता किया कि किस ढंग से वे लोग अपने कार्य में मसरूफ़ थे। स्पीकर साहिब, आप सुनकर हैरान होंगे कि इन भाइयों ने सच्चाई पर किस ढंग से पर्दा डाल कर गवर्नमैण्ट और पुलिस को जिस ने वहां अमन कायम करने के लिये हर मुमकिन कदम उठाये--बदनाम किया। स्पीकर साहिब, मुझे पता लगा कि किस चालाकी से हमारे कम्यूनिस्ट भाईयों ने वहां जाटों को भड़काया। उन्हों ने उन्हें कहा कि ऐ हमारे जाट भाईयो! इस कांग्रेस की हकूमत में तुम्हारी बहु-बेटियों की इज्जत महफ़ूज़ नहीं रह सकती। कांग्रेस के राज में तुम्हारी बहु-बेटियों की बेइज्जती की जाती है, इस लिये तुम पुलिस का मुकाबला करो। यही कारण था कि जागसी के अन्दर जाटों ने गुमराह किये जाने पर पुलिस का मुकाबला किया। यही वजह है कि कुछेक गिरफ्तारियां भी हुई।

पुलिस को बदनाम करने के लिये क्या क्या और किस प्रकार के ज़लील तरीके अपनाये गये, उन का भी मैं थोड़े लफ़ज़ों में ज़िक्र करना चाहता हूं। प्रधान जी, हमारे हां गांव में एक खास किस्म का पौदा होता है जिसे कौंच के नाम से पुकारते हैं। इन कम्यूनिस्ट भाईयों ने और मुखालिफ़ लोगों ने उस इलाके की कुछ औरतों से कहा कि तुम उस पौदे को अपने बदन पर रगड़ लो और जब तहकीकात हो रही हो तो कहना कि पुलिस ने तुम्हारे चुटकियां भरी थीं। और मारा था.............।

श्री बाबू दयाल : On a point of order, Sir. अर्ज़ यह है कि General Administration पर बहस हो रही है। इस लिये यह बिल्कुल irrelevant बात कर रहे हैं।..........(विघ्न)

Mr. Speaker : He is quite relevant. I am not to be guided by your Judgment. Please take your seat.

श्री नानहू राम : मैं बता रहा था कि यह बिल्कुल ग़लत बातें हैं कि पुलिस ने वहां पर औरतों के साथ ज्यादती की। पुलिस ने जो कार्यवाही वहां की है वह बिलकुल ठीक की है। वहां पर गुण्डे आदमी इतने पैदा हो गये थे कि लोगों का वहां रहना ही मुश्किल हो गया था। न उन की इज्ज़त safe थी न उन की पूंजी। मैं कहता हूं कि यह ग़लत बातें करते हुए इन्हें शरम नहीं आई कि पुलिस ने उन लोगों की बेइज्ज़ती की है। वहां वे लोग हेमराज डाकू को पनाह देते थे। उसे वहां खाने को हलवे और पूड़े मुहैया करते। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने पुलिस वालों से पूछा कि आप लोगों ने क्यों औरतों की बेइज्ज़ती की है तो उन्हों ने स्पीकर साहिब यह बताया कि हम ने उन की बेइज्ज़ती बिल्कुल नहीं की लेकिन हेमराज डाकू के बारे में तफ़तीश करते हुए उन से पूछताछ ज़रूर की थी। और वह भी बड़ी इज्ज़त के साथ। यह बेइज्ज़ती का मामला ऐसे ही मशहूर कर दिया गया है।

मैं हाऊस को यह भी बता दूं कि जब सच्चर साहिब जिला रोहतक में दौरे पर गये थे तो हम ने उन से कहा था कि वहां हालात इस कदर ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि आप जल्दी कोई कार्यवाही करें। उस वक्त वहां हकूमत डाकूओं की हो चुकी थी। हरेक गांव में किसी न किसी डाकू ने एक मतवाज़ी गवर्नमैण्ट कायम कर रखी थी। वहां के लोगों में इतना डर और दहशत फैल चुकी थी कि कोई भी मरद या औरत उन के बारे में कुछ बताने को तैयार न होता था। ऐसे हालात में जरूरी इकदाम करने के लिये हम सरकार और अपने चीफ़ मनिस्टर साहिब का शुकरिया अदा न करें तो क्या करें। हमें पहले अमन की ज़रूरत थी और वह अब मेरे हलके में कायम हो गया है। अब अमन के बाद वहां की आम तरक्की के सम्बन्ध में कदम उठाए जा सकते हैं। मैं यह फिर दोहराना चाहता हूं कि पुलिस के ज़ुल्म की कहानियां घड़ी गई हैं इन पर मैं ने रोशनी डालने की कोशिश की है।

श्री बाबू दयाल (सोहणा) : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय। मैं इस demand पर इस लिये बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि इस में 40 लाख 70 हज़ार रुपया की जो ग्रांट है उस की कोई justification नहीं है। इस demand में जो तीन लाख 21 हज़ार रुपये का खर्च है वह एक ऐसा खर्च है जिस पर हम discussion नहीं कर सकते। वह राज्यपाल के बारे में है। दूसरी grant इस में तीन लाख रुपया की है वह है Upper House के मुतअल्लिक। इस ग्रांट के बारे में अर्ज़ करता हूं कि जब यह असैम्बली बैठी थी तो पहिले ही Session में कोई 80 मैम्बरान ने दसखत कर के इस हाऊस को उड़ाने के लिये चीफ़ मनिस्टर साहिब को लिख कर दिया था। चीफ़ मनिस्टर साहिब जो पार्टी के लीडर हैं उन्हें पार्टी मीटिंग में यह कहा गया था, कि यह जो Upper House है इस का कोई फ़ायदा नहीं और इस पर खर्च बहुत हो रहा है। यह खर्च करना उचित नहीं इस लिये इसे तोड़ दिया जाये। लेकिन उन्हों ने कहा कि यह बात हाऊस पास कर सकता है पार्टी नहीं कर सकती। लेकिन यह नहीं किया गया। पहिले तो पंडित जवाहरलाल का हवाला दिया गया फिर यहां............

Chief Parliamentary Secretary : On a point of order, Sir. Can the hon. Members discuss here what happened in the meeting of the Congress Legislature Party ?

Mr. Speaker : Please let him say, what he wants to say.

श्री बाबू दयाल : श्रीमान् जी, इस हाऊस को कायम रखने की कोई justification नहीं है और इस के खर्च को General Administration की ग्रांट में नहीं रहने देना चाहिये। इस के बाद आता है मनिस्टर साहिबान का खर्च और इस असैम्बली का खर्च। स्पीकर साहिब ! मेरे ख्याल में जो सबूत इस असैम्बली ने दिया है वह शायद ही दुनिया की किसी असैम्बली ने दिया हो। (*Interruptions*) (विघ्न)।

Mr. Speaker : Order order.

श्री बाबू दयाल : मैं समझता हूं कि जो कुछ इस असैम्बली के मैम्बरों ने किया है और जो आज स्टेट में हो रहा है आज तक दुनिया की तवारीख में ऐसा काम नहीं किया गया। फिर जिन की बदौलत यह लोग हकूमत कर रहे हैं और जिन की बदौलत इन गदियों

[श्री बाबू दयाल]

पर बैठे हैं वह मैम्बर हैं हमारे सियाहपोश लीडर श्री किदार नाथ सहगल और प्रोफैसर मोता सिंह जिन्होंने अपनी उमरें ही जेलों में गाल दी हैं और पंडित श्री राम शर्मा जी जिन के मुतअल्लिक यह लोग उन की बुराइयां सुन कर खुश होते हैं। क्योंकि जो इस तरह की बातें यह लोग करते हैं वही असैम्बली करती है इस लिये इस की ग्रांट भी justified नहीं है। यह बड़ी भारी तादाद में इन लोगों को मलियामेट करने के लिये............

Mr. Speaker : The Legislative Assembly has not taken any action. Moreover your party is not under discussion.

श्री बाबू दयाल : जनाब स्पीकर साहिब, यह पंजाब कांग्रेस असैम्बली पार्टी के मैम्बर तो थे..

अध्यक्ष महोदय : जिस मामला पर आप तकरीर फर्मा रहे हैं वह हाऊस से बाहर का मामला है।

श्री बाबू दयाल : तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि दो लाख 70 हज़ार रुपया मनिस्टर और डिप्टी मनिस्टर की तनखाहों का रखा गया है और एक लाख सात हज़ार रुपया उन की कारों वगैरा के लिये रखा गया है और इन का पब्लिक के साथ यह रवैया है कि Irrigation Minister साहिब ने मुझ पर यह इलज़ाम लगाया था कि मैं उस केस की inquiry पर इस लिये नहीं पहुंचा था क्योंकि मेरी शिकायत गलत थी और मैं enquiry में आने से डरता था। जनाब स्पीकर साहिब ! मैं इस सिलसिले में यह अरज करना चाहता हूं कि मैंने यह शिकायत की थी कि एक Sub-Divisional Officer ने सरकारी काम पर रुपया नहीं लगाया बल्कि वह खुद हज़म कर गया था। जब मुझे उस की enquiry पर Superintending Engineers ने बुलाया तो मैं शिमले से भागा आया और वहां मौके पर पहुंच गया मगर उस Superintending Engineer ने मुझे चकमा दिया और कहा कि मैं खाना वगैरा खा आऊं। तो जब मैं खाना खाने चला गया तो उस ने बाद में उन चन्द गंवार लोगों से जो वहां बैठे थे. बयान वगैरा ले कर enquiry मुकम्मल कर ली और मेरी वापसी पर मुझे कहने लगा कि उस ने enquiry complete कर ली है। जब मैंने फिर सिंचाई मंत्री साहिब से मिल कर दरखास्त की वह मुझे enquiry की रिपोर्ट दिखायें और मैंने उस Superintending Engineer की शिकायत की तो उन्होंने कहा कि वह Superintending Engineer के खिलाफ शिकायत सुनने के लिये तैयार नहीं हैं और फिर मुझ पर हाऊस में उन्होंने उलटा इलज़ाम लगाया है..........

श्रीमती सीता देवी : On a point of order, Sir. यह इस समय General Administration पर बहस हो रही है। क्या माननीय मैम्बर अपने personal grievances निकाल रहे हैं या यह जो demand है इस पर बोल रहे हैं ?

Sardar Ajmer Singh : He is discussing the conduct of a Minister.

अध्यक्ष महोदय : मैं बहिन जी से दरखास्त करता हूं कि वह जरा अपना दिल वसीह करें और उन्हें बोलने दें। जब General Administration पर बहस हो रही हो तो जो Administration चलाने के जिम्मेदार होते हैं वे भी under discussion होते हैं। लेकिन यह बहुत सी बातें ऐसी कह रहे हैं मसलिन वे खाना खाने चले गये इत्यादि जो कि relevant नहीं हैं।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि अगर उस के खिलाफ कोई इलजाम तहकीकात में साबत हो जाये तो उस की सजा मुझे दी जाये। मगर उन्हें ऐसा करने की जुरअत न हुई। मैं ने कहा कि Superintending Engineer के खिलाफ enquiry करें। चीफ मनिस्टर साहिब से भी शिकायत की; मनिस्टर साहिब से भी कहा। उन्होंने फरमाया कि तहकीकात करेंगे। दो साल हो गये हैं लेकिन आज तक कोई तहकीकात नहीं हुई।

अब मैं मनिस्टर साहिबान का पब्लिक के साथ क्या व्यवहार है, वह बताता हूं। एक बार Development Minister साहिब गुड़गांव जिले में पहुंचे। वहां एक तहसीलदार था जिसने उमर भर में कभी रिश्वत न ली थी। आप उसे revert कर आये। तीन, चार M.L.A.s ने आप के पास representation किया। उन्होंने कहा कि तहकीकात की जाये और जुर्म साबत होने पर उसे सजा दी जाये। अगर यह जुर्म साबित हो जाये तो मुजरिम हम होंगे और सजा के हकदार होंगे। सरकार की इस कार्यवाही का नतीजा यह हुआ है कि वहां पर आज तक कोई ईमानदार आदमी नहीं आया। बाबर के नायब तहसीलदार के बारे में शिकायतें आईं कि वह शराब पीकर मदहोश रहता है। एक बहन जो वहां पर Health Visitor हैं, उस के साथ उस ने जो कुछ किया वह बयान नहीं किया जा सकता। डाकखाने पर पत्थर फेंके, गालियां दीं। वह नायब तहसीलदार से तहसीलदार हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप किस level पर चले गये हैं। Please wind up.

श्री बाबू दयाल : इस के बाद मैं Law and Order की तरफ आता हूं। तीन गांवों, अभयपुर, दमदमा और रीठों में कई आदमियों का कतल हुआ। मुलजमान पकड़े गये। तीनों गांवों में ताजीरी पुलिस बैठा दी गई, जिस की कोई justification न थी। मनिस्टर साहिब दौरे पर गये तो कई दफा आप की खिदमत में हाजर हुआ। दो दफा तो शिमला में भी गया। लोग बहुत फिरे। सरकार जिन हरिजनों के उद्धार का दावा करती है, उन्हीं हरिजनों को जबरदस्ती कोड़े लगाकर सोलह सोलह रुपये वसूल किये जाते हैं।

फिर एक बाबा चन्द्र दास हैं। उन का घर बार और सामान छीन लिया गया है। आप एक influential आदमी हैं और M.L.C. थे। उन का माल छीन कर उन्हें वहां से निकाल दिया गया और जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। उस के लिये कुछ किया जाये। मुझे ताअाज्जुब है कि इस गवर्नमैण्ट के राज्य में ऐसी चीजें होती हैं।

[श्री बाबू दयाल]

मनिस्टर साहिब तक पहुंच की गई उन्होंने लुध्याना से लिखा कि यह केस feasible है। यह कैसे हो सकता है ? उस को लूट लिया गया है, पुलिस ने चालान कर लिया है। वह जायदाद छोड़ कर दूसरी जगह मारा २ फिर रहा है।

अब मैं Public Service Commission के मुतािल्लक यह अर्ज करूंगा कि Assistant Registrar, Co-operative Societies की post के लिये interview पर बुलाया गया, इम्तिहान हुआ, लेकिन अभी तक result declare नहीं हुआ। मैंने स्वाल भी दर्याप्त किये। जवाब दिया गया कि एक Advisory Committee बैठी है। तो public के साथ ऐसा बर्ताव होता है। एक responsible अफसर ने मुझे बताया कि मेरा लड़का first division में आया है।

अध्यक्ष महोदय: अब बस कीजिये।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ) : ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। General Administration ਤੇ ਜੋ discussion ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਬੜਾ ਮੁਫੀਦ item ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ administration ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਨਜ਼ੱਲੀ। Administration ਦੇ ਦੋ ਹਿਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਕ public ਅਤੇ ਦੂਜਾ public servants। ਅਗਰ public ਦਾ administration ਵਿਚ confidence ਵਧੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ public servants ਵਿਚ confidence ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ administration ਦ tone ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ party label ਨੂੰ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ propagation ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ treat ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਨ।

ਕੁਝ ਮੈਂ political sufferers ਬਾਰੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ administration ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਕਾਰ ਵਧੇ। Congressmen ਦੀ help ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨੇਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਂਬਰ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਣ ਜੋ Congressmen ਹੋਣ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਦਾਦ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ figures ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਆਦਮੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਜਾਂ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।

ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਇਕ ਬਿਰਧ ਆਦਮੀ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੇ ਮੈਂਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਕੈਦ ਕਟ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ sufferers ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਲੀਫ (relief) ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ? ਇਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਤਾਂ ਰਖਿਆ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਇਕ ਹੋਰ ਗਜਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 33 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਦਸੋ। ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਚਲੋ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕੁਲੀ ਵਿਚ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕੁਲੀ ਵੇਖੀ। ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਸ ਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।

ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ Five-Year Plan ਹੈ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਪਾਸ request ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੀ success ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ level ਤੇ ਲੈ ਆਉਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨ ਰਖਣ। ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਨਾਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜੋ ਤਹਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ confidence ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ sufferers ਤਾਂ ਕਾਂਗ੍ਰਸ organisation ਤੋਂ confidence ਚੁਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਤੀਆ ਹੈ ਯਾਨੀ Gift ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਣ ਇਹ gift ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ fail ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।

ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ allegations ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ

ਕਰਾਂਦੇ, ਪਬਲਕ ਨੂੰ confidence ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ? ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਓ ।

ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ Anti-corruption ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜ ਆਦਮੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਨ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰਨ enquiry ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਥੇ ਐਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਉਥੇ enquiry ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ । ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ confidence ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ confidence ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ dispassionate enquiry ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਾਂ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਹਕੀਕਾਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ allegations ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਾਏ । ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਵਸਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ ।

ਫੇਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਤਕ incidents ਪਿਛੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ । ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ dacoits ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ । ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲਏ । ਡਕੈਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ । ਮੇਰੇ ਇਥੇ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਕੀਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ credit ਹੈ ? ਜੇਕਰ large scale ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਡਿਪਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, Superintendent Police ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ action ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ । ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਉਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ hold

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

loose ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਿਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਕੀਹ ਵਜਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਗੈਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ raid ਕੀਤੇ ਗਏ । ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਸਨ ਤਾਂ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਕ ਧੱਬਾ ਹੈ ਅਤੇ allegation ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਬਲਕ ਵਿਚ confidence ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ dispassionate enquiry ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹਾਲਾਤ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਖਰਾਬ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਹਕਬਜਾਨਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਥੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ?

ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਥ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ for ਜਾਂ against ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ dispassionate enquiry ਹੋਵੇ।

ਫੇਰ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਫਦਾਰੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਮੁਰੱਬਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਭਣੀ ਸੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ। Consolidation Officers ਅਤੇ Settlement Officer ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ

ਤੇ ਵੀ ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੱਬੇ ਬੰਦੀ ਤੋੜ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਰੱਬੇ ਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰੇਸੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ allegations ਨਹੀਂ facts ਹਨ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰੇਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੇ ਬੰਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰੇਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਰੱਬੇ ਬੰਦੀ ਤੋੜੀ ਗਈ।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਹੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰੇਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਸ ਦਿਓ। You will be given a reply.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਾਹਲੇਵਾਲ ਲਖਨ ਪੁਰ ਅਤੇ ਪੁਤਦੀ ਵਿਚ ਮੁਰੱਬੇ ਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀ ਗਈ। ਲਖਨਪੁਰ ਦੇ ਡਾਇਰੇਕਟਰ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਰੱਬੇ ਬੰਦੀ ਤੋੜ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੁਰੱਬੇ ਬੰਦੀ ਮੁਕਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਲੋਕ satisfy ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ ਕੇਵਲ ਤਿਨ ਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ?

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਨੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰੇਸੀ ਵਰਕਰ ਕਾਕਾ ਰਾਮ ਦੇ ਬਹਨੋਈ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਆਨੇ ਘਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚੀਖ਼ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਸੀ. ਓ. (Consolidation Officer) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਪਰੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਆਇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਬਣਿਆਂ। ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਐਸ. ਓ. (Settlement Officer) ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਰਖੀ ਅਤੇ ਭਾਂਵੇ ਲੋਕ ਮੁਰੱਬੇ ਬੰਦੀ ਤੇ ਮੁਤਮਈਅਨ ਸਨ ਫੇਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਹੇ ਹਕ ਹੋਣ। non-congressmen ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ confidence ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਏ ਗਾ।

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਖਤ ਰਵਈਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ democracy ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ [illegible]uest ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ [illegible]ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਛਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਘਸੀਟਿਆਂ ਤੇ ਮੁਛਾਂ ਪੁ[illegible]ਤਨੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ [illegible]ਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ [illegible]ਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਛਾਂ ਪੁਟੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ [illegible]ਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮ[illegible] ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਾਂ ਇਕ ਹੁਕਮ [illegible]ਨ ਤਾਂ ਇਕ circular ਕਿਉਂ ਨਹ[illegible] ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ[illegible]ੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ Sacriligious ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ inhuman [illegible]। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਲੀਲ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤਗਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪ[illegible] ਲੋਕ ਇਸਤ-ਗਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ result conviction ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ for and against ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 20, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰੀਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਵੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁਕ ਤੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤਕ ਤਾਂ entry ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ good, satisfactory ਅਤੇ very good ਅਤੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਦ remarks ਦਿਤੇ ਜਾਨ inefficient ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ life ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅੱਜ Presidents ਮੈਡਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲ ਉਸ ਨੂੰ censure ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਇਸ discrimination ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕੇਡਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੀ ਅਫਸਰ ਯਾ Superintendent Police ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਯਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੀ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬੁਰਾ ਰੀਮਾਰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰੂਲ ਬਣਾਉ ਕਿ ਇਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦਤ ਦੀ service ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੋਈ Board ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਰੀਮਾਰਕ ਠੀਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਹ

ਚੌਧਰੀ ਲੈਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ Chief Engineer ਯਾ Superintending Engineer ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਰੀਮਾਰਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਵੇ? ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਸਰੀਹ ਦਾ ਲਮਬਰਦਾਰ ਚਨੰਣ ਸਿੰਘ 25 ਯਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਮਬਰਦਾਰ ਚਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੁਦਤ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਅਸੈਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਭਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਕ ਮਮੂਲੀ Sub Inspector ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਓਹਦੀ ਲਮਬਰਦਾਰੀ ਤੋੜਨ ਤਕ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਰਿਮਾਰਕ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ Cancel ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ 25 ਯਾ 30 ਸਾਲ ਵਿਚ ਓਹਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਖਿਰ ਕੁਝ M.L.A., ਮੈਂ, ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰੇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿਚਾਰੇ ਦੀ ਲਮਬਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਫੇਰ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਓਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ restore ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ M.L.A. ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ confidence ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ too soon ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ rural ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ duty ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ।

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਆਪਣੀ duty ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਅਤੇ duty ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲ.........

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : But it was stopped.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : It was stopped when it had already done a great harm. ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਫੇਰ ਜਨਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਨਖਾਹ ਏਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Pepsu ਵਿਚ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਰਖੇ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ ਹੋ।

श्री माम राज (भिवानी) : प्रधान जी ! मैं आप का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस वक्त कुछ कहने का मौका दिया है। फिर मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि जो बजट पेश किया गया है वह प्रजा की भलाई का बजट है। हां, यह दूसरी बात है कि जिन गरीब इलाकों को ज्यादा तवज्जुह की जरूरत थी उन की कम परवाह की गई है। मैं वज़ीर साहिबान को अपनी आंखों देखी बातें बताता हूं। मेरे इलाके में सब से पहला मसला मुज़ारों का है। कुछ अरसा हुआ भिवानी के तहसीलदार ने मुज़ारों और मालगुज़ारों को बुलाया और मुज़ारों से कहा कि इन से मुआफ़ी मांगो और नम्बर बदलवाओ नहीं तो बेदखल कर दिये जायेंगे। बाज़ जगह मुज़ारों को लाठी के जोर से भी बेदखल किया गया है।

फिर प्रधान जी मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद हरीजनों के बारे में हालात में कोई तबदीली नहीं हुई। इन को कूओं से पानी तक नहीं भरने दिया जाता और इसी तरह की बहुत सी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। फिर जनाब हमारे हां भिवानी Municipal Committee में एक नौकरी थी। एक हरीजन ने उस के लिये दरखास्त दी मगर वह जगह एक कम पढ़े हुए उम्मीदवार को दे दी गई। हम ने बहुत शोर मचाया मगर किसी ने हमारी न सुनी।

इस के बाद मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि हमारे इलाके म पानी की बड़ी तंगी है। मवेशियों को पिलाने के लिये भी पानी नहीं मिलता। सब जगह नैहरों का इंतजाम है मगर हमारे इलाके में नहीं। मैं अर्ज़ करता हूं कि वहां भी नैहरों का बन्दोबस्त किया जाये नहीं तो लोग डांवा डोल हो जायेंगे। वहां अगर बरसात के पानी से कुछ पैदा हो जाये तो वे बिचारे कुछ खा लेते हैं नहीं तो उन्हें घर बार छोड़ कर मज़दूरी के लिये बाहिर निकल जाना पड़ता है।

मेरी गुज़ारिश है कि जब सारे पंजाब को सहूलतें मिल रही हैं तो हमें क्यों नहीं मिलतीं। क्या हम पंजाब की प्रजा नहीं हैं। हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। इस लिये मेरी प्रार्थना है कि हमारे इलाके में पानी का इन्तज़ाम जल्द किया जाये। हमारा इलाका बिलकुल पिछड़ा हुआ है और हर वक्त तंग रहता है।

स्पीकर साहिब ! हरीजनों के बच्चों की पढ़ाई के लिये नवीं जमात तक वज़ीफों का प्रबन्ध सरकार की ओर से किया गया है। परन्तु वज़ीफा बहुत देर के बाद दिया जाता है और आम तौर पर वक्त पर मिलता ही नहीं। मेरे विचार में अच्छा हो यदि वज़ीफा हर तीन महीने के बाद मिले और ठीक वक्त पर दिया जाये।

श्रीमान् जी ! आप की कृपा से मैं अपनी सरकार को यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे इलाके में जो गरीब लोग बसते हैं उन के साथ इतना भारी जुल्म होता है कि उन्हें बगैर किसी कानूनी कार्यवाही के बेदखल कर दिया जाता है और वे बिचारे हाथ मलते रह जाते हैं। मेरे इलाके में कई ऐसे गांव हैं जहां जितने चाहियें उसे से कहीं ज्यादा हरिजन रहते हैं, परन्तु उन में से किसी को पंच नहीं बनाया गया। भाबड़ा, नुहानी और दूसरे कई गांवों की मिसालें दी जा सकती हैं। मेरी गुज़ारिश है कि जिन लोगों का हक है उन्हें जरूर दिलाया जाये।

एक और बात भी मैं कहनी चाहता हूं। पूरभर के गांव में एक करम सिंह ठाकुर है। इस ने हरिजनों को पीसने का ठेका ले रखा है। वह हरिजनों को बहुत गालियां और धमकियां देता है। उन के मकानों के बाहिर बाड़ें लगा देता है। उस का कोई इन्तज़ाम किया जाये। बस यही बातें कहने के लिये मैं खड़ा हुआ था।

श्री मूल चंद जैन (सम्भालका) : माननीय स्पीकर साहिब ! सियासी आज़ादी के बाद हमारा जो काम है बह यह है कि इस देश में आर्थिक और सामाजिक आज़ादी को जल्द से जल्द लाया जाये। और इस मकसद को पूरा करने के लिये हमने अपने इस बजट को और इस Demand General Administration को परखना है। मैं समझता

[श्री मूल चन्द जैन]

हूं कि इस Demand पर या बजट पर यह नुक्ताचीनी करना कि इस आदर्श की तरफ़ जो आज हमारे सामने हैं कोई कदम नहीं बढ़ाया गया सख्त ग़लती है। यह बजा तौर पर कहा जा सकता है कि हमारी Government का ध्यान इस आदर्श की तरफ़ है जो कि सारे हिंदुस्तान के लिये विधान में रखा है। लेकिन मैं और ज्यादा हेरफेर में न जाता हुआ कहूंगा कि जिस रफ़्तार से यह काम होना चाहिये उस रफ़्तार से यह काम नहीं हो रहा। इस बात के बारे में कुछ मिसालें देना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर हमने मुज़ारों का कानून अर्थात Security of Land Tenures Act pass किया है। हमारा मकसद इस कानून के पास करने से यह था कि मुज़ारों का फ़ायदा हो। यह ठीक है कि हमारी सरकार और वजारत के दिल में और खास तौर पर सरदार प्रताप सिंह जी क दिल में मुज़ारों के लिये बहुत दर्द है। जब हज़ारों की तादाद में ejectment हुई और दावे हुए तो कोर्टफीस वगैरा और दूसरे खर्चे की मुआफ़ी दे दी गई। लेकिन मैं कहूंगा कि जो असली मसला है जूं का तूं है। PEPSU हमारी पड़ोसी State है। प्रधान के राज के दिनों में प्रधान की तरफ से श्री राओ ने मुज़ारों के लिये जो कानून मनजूर करवाया और जो आज PEPSU में लागू है हमारे कानून की निसबत वहीं अच्छा है। स्पीकर साहिब! मैं आप की विसातत से इस एवान को बताना चाहता हूं कि असल चीज़ क्या है। वह यह है कि हमारे देश में दो किस्म के लोग रहते हैं। एक तो वह लोग हैं जो आर्थिक तौर पर आज़ाद हैं और अपने पाओं पर खड़े हैं। दूसरे वह लोग हैं जिन का आधार आर्थिक तौर पर दूसरों पर है अर्थात् यह लोग आर्थिक तौर पर दूसरों के गुलाम हैं। हम चाहते हैं कि इस गुलामी को दूर किया जाये। यह हमारे काम को नापने का एक गज़ है। इस बात से इनकार नहीं हो सकता कि बहुत से लोग हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक गुलामी का शिकार हो रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि इस गुलामी को खत्म करने के लिये इस बजट ने क्या part अदा किया है।

स्पीकर साहिब! इस गज़ से जिस का मैं ने ज़िकर किया है इस बजट और Administration को परखने के लिये और इस की कसवटी पर पूरा उतरने के लिये मैं कई कदम गिनवा सकता हूं। Common Land Regulation Act पास हुआ, हरिजनों को लम्बरदार बनाने का कानून पास हुआ, और भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस तबका की तरक्की के लिये जिस में अब जागति हो चुकी है पूरी तरह कदम नहीं उठाये गये। हमारी सरकार उन की भलाई के लिये कुछ कदम तो उठाती है, परन्तु जब उन पर अमल करने का स्वाल आता है तो हमारे अफ़सरान उस हद तक अमल नहीं करते जितना कि करना चाहिये।

मैंने गवर्नर साहिब के अड्रैस पर बहिस करते हुए भी इस point पर ज़ोर दिया था और वज़ीर ख़ज़ाना ने इस point का जवाब देते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि मूलचन्द कौन सी चीज़ों को शामिल कर रहे हैं। आज कल वक्त ऐसा है जब कि

हजारों मिसालें दी जा सकती हैं जहां अमीर और गरीब लोगों के साथ अलहदा अलहदा सलूक किया जाता है। इस के इलावा मैं देहातों में वकील होने के नाते से देख रहा हूं कि 80 या 90 फीसदी अहिलकारों का रुख अमीर लोगों की तरफ होता है और गरीब लोगों को वह बिल्कुल नजरान्दाज करते हैं। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि यहां सब ऐसे अफसर हैं जो गरीबों से हमदर्दी नहीं रखते। मैं आप की विसातत से यह बात अफसरों तक पहुंचाना चाहता हूं कि वह देखें कि अफसरों का क्या मकसद होता है हमें चाहिये कि हम भी देखें कि हमारा मकसद क्या है। क्या यह आज अमनो अमान अर्थात् Law and Order की State नहीं है। हमारा मकसद आज महिज़ revenues इकट्ठा करने का नहीं। हमारा मकसद आज देश की भलाई और प्रान्त से गुरबत को दूर करना है। बढ़ी हुई बेरोजगारी को दूर करना है, ऊंच नीच को दूर करना है। मैं समझता हूं कि इन बातों में हमारे अफसर हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। हम उन की traditions को जानते हैं। वह उन तबकों से ताल्लुक रखते हैं जो Haves कहलाते हैं। मैं मंत्रिमंडल का ध्यान इन बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। हो सकता है कि वह मेरी बातों को न मानें क्योंकि ऐसी बातें कही जा रही हैं कि यह समझना कि जो हो रहा है ठीक है और complacent रहना दुरुस्त बात नहीं। इस context में मैं कांग्रेस की छः मार्च की कांग्रेस workers की जो meeting हुई जिस में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के मैम्बर और M.L.A.s शामिल थे और उन्होंने जो कुछ administration के बारे में हुआ उस की तरफ गवर्नमैण्ट का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की एक meeting होती है और वहां ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में राये का इज़हार किया जाता है तो उस बात की तह तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि हमारी ऐडमिनिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश, देहली और पैप्सू के मुकाबले में बदर्जहा अच्छी है। लेकिन अफसरों में वह हुब्बुलवतनी नहीं पाई जाती जिस की आज़ाद देश में ज़रूरत है। इन अफसरों का रवैया जो Police State की training से उन्होंने इख्तयार किया हुआ था उन traditions को हमने आज Welfare State के हालात के मुताबिक बदलना होगा। जब हम गांव में जाते हैं तो वहां कोई तबदीली नज़र नहीं आती जो कि Welfare State (लोक हितकारी राज) में होनी चाहिये ऊपर से ले कर नीचे तक एक लड़ी है। कहीं कहीं ऐसे अफसर हैं जिन्हें pro-poor कहा जा सकता है। अफसरान को परखने की यह कसौटी है कि बेरोज़गारों को रोज़ी देने का प्रबन्ध करें और मुज़ारों को रोज़ी के फिकर से निजात दिलायें। इस मामले में co-operative का महिकमा मुज़ारों की बहुत मदद कर सकता है लेकिन इस बात की तरफ कोई नज़र नहीं की जाती। तीन साल से मुज़ारों का मसला हमारी सरकार के सामने पेश है। जिस वक्त कोई मुज़ारों का कानून पास होता है तो जब implementation का वक्त आता है तो अफ़सरान दूसरी बाते बनाते हैं और कहते हैं कि गवर्नमैण्ट भंगियों और चमारों को हमारे सिर पर चढ़ा रही है। बम्बई में दो तीन साल हुए मुज़ारों की भलाई का कानून पास हुआ तो अखबार ने लिखा कि बम्बई की ऐडमिनिस्ट्रेशन मुज़ारों के कानून को implement करने के लिये मुज़ारों का साथ नहीं दे रही है. बल्कि landlords का साथ दे रही है। हरिजन अखबार

[श्री मूल चन्द]

ने लिखा कि अफ़सरों को परमात्मा के लिये अपना रवैया तबदील करना चाहिये। जनता को यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिये कि सरकार उन के हितों के खिलाफ काम कर रही है ताकि उन के दिल में dissatisfaction या नाराज़गी का जज़बा पैदा न हो। मैं अफसरों से कहना चाहता हूं और साथ ही मंत्रिमंडल से अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह अपने अपने महिकमों के अफसरों की पड़ताल करें। आप Consolidation Department को ले लीजिये। माननीय विकास मंत्री—सरदार प्रताप सिंह को हर मैम्बर ने बधाई दी है। Consolidation Department में रिश्वत की गुंजाइश थी। इसी रिश्वत को हम ने खत्म करना है। अमीरी और गरीबी को जहां भी हो उस को दूर करना है। अब Consolidation Department में कम से कम रिश्वत होगी। 90 फ़ीसदी से ज्यादा खत्म हो चुकी है। इसी तरह Co-operative Department में रिश्वत खत्म हो सकती है, P.W.D. में खत्म हो सकती है। दूसरे महिकमों में भी रिश्वत खत्म की जा सकती है। जहां रिश्वत खत्म नहीं हो सकती उस के लिये बड़े बड़े अफ़सर जिम्मेदार हैं। उन्हों ने वह steps नहीं लिये जो कि उन्हें लेने चाहियें थे। इस सिलसिले में मेरे एक दोस्त ने Labour Commissioner के बारे में कहा। उस के मुतअल्लिक शिकायतें मैंने भी सुनी थीं। Labour Commissioner मज़दूरों की भलाई के लिये होता है। यह कहा जाये कि अगर Labour Commissioner रहेगा तो मज़दूरों की भलाई नहीं हो सकती यह एक अजीब सी बात मालूम होती है।

अब मैं सरकार को तीन चार सुझाव पेश करता हूं। हमारे प्रान्त में जो चीज़ खास तौर पर तकलीफ़ का बाईस बनी हुई है वह सिट्टा बाज़ी है। इस के मुतअल्लिक मैं ने माननीय मुख्य मंत्री को लिखा कि सिट्टाबाजी से गरीब लोग बेहद exploit होते हैं। इस को रोकने के लिये Gambling Act में बड़ी खामियां हैं। पुलिस वाले मुलाजिम को दो चार रुपये जुर्माना कर के छोड़ देते हैं। बेरोज़गारी की वजह से गरीब आदमी सिट्टेबाज़ी में फंस जाते हैं और बाद में चीखो पुकार करते हैं। हर शहर में, हर कस्बे में सिट्टेबाज़ी की बीमारी फैली हुई है। मैं गवर्नमैण्ट से प्रार्थना करूंगा कि वह इस जुर्म को काबले दस्त-अन्दाज़ी पुलिस बनाये और इसे नाकाबिले ज़मानत बनाना चाहिये और इस जुर्म की सज़ा ज्यादा बढ़ा देनी चाहिये।

इस के इलावा मैं गवर्नमैण्ट का ध्यान खास तौर पर शहरों में बदकारी के अड्डों की तरफ दिलाना चाहता हूं। इन की तादाद आजकल ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री ने अखबारों में पढ़ा होगा। इस लिये मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस की तरफ खास तौर पर ध्यान दें।

अब मैं publicity की machinery का ज़िक्र करता हूं। कई माननीय मैम्बरों ने इस बारे में कहा है कि जो काम गवर्नमैण्ट करती है उन का अच्छी तरह से प्रचार नहीं किया जाता। इस लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहूंगा कि वह इस तरफ अपना खास ध्यान दें और publicity में जो कमी है उसे दूर करने का यत्न करें।

इस के बाद मैंने Arms Licence के सिलसिले में कुछ कहना है । पिछले दिनों एक meeting हुई कि असलाह् के लाईसेंस दिये जायेंगे तो उस पर नुक्ताचीनी हुई । मैं नहीं जानता कि इस बारे में क्या कदम उठाये गये । लाईसेंस देने के बारे में उसी पुराने तरीके की पैरवी की जा रही है जिस में बहुत सी खामियां हैं । बहुत कम तादाद में लाईसेंस दिये जाते हैं ।

अब मैं छोटे मुलाज़मों के सिलसिले में जो Have-nots हैं कुछ कहना चाहता हूं । यह बड़ी खुशी की बात है कि गवर्नमैण्ट ने 40/8/- रुपये माहवार तनखाह लेने वाले मुलाज़मों की तनखाह २ रुपये माहवार बढ़ा दी है । यह भी ठीक है कि जब से इस Ministry ने हकूमत की बाग डोर अपने हाथ में ली है उन्होंने दस बारह रुपये माहवार छोटे मुलाज़मों की तनखाहों में इज़ाफ़ा कर दिया है । लेकिन जैसा कि माननीय मैम्बरों ने कहा है यह तनखाह भी उन के लिये बहुत कम है । बेशक सरकार को सिनेमा वालों पर टैक्स लगा कर गुनाह-ए-बेलज्ज़त मिला है लेकिन फिर भी सरकार को कोई और ऐसा साधन ढूंढ कर उन की तनखाह को और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये । गो हमारे वज़ीर खज़ाना ने argument दी थी कि अगर हमारी स्टेट का मुकाबला दूसरी स्टेटों से किया जाये तो हमारी स्टेट में low-paid staff को उन के मुकाबले में बहुत ज्यादा तनखाहें मिलती हैं ।

स्पीकर साहिब ! मैं आप की मारफ़त सरकार से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारी State के मुकाबले में हमें दूसरी States के लोगों का Standard देखना चाहिये । हमें यहां के लोगों के रहने सहने के Standard का दूसरी States के लोगों के Standard से मुकाबला करना चाहिये । हमारा Standard दूसरी States के मुकाबले में बिहतर है । इस लिये यह कहना कि दूसरी States के मुकाबले में हम ज्यादा तनखाहें देते हैं, कोई argument नहीं है । अगर और तनखाह बढ़ाने की गुंजायिश नहीं है तो भी हमें छोटे मुलाज़मों की तनखाहें जितनी जल्दी हम बढ़ा सकें बढ़ानी चाहियें ।

इस के बाद मैं हरयाने के चार ज़िलों का ज़िक्र करना चाहता हूं । एक तरह से इस का General Administration से सम्बन्ध है । अगर इस बजट को गहरी नज़र से देखा जाये तो आप को मालूम होगा कि जितना इन हरयाने के चार ज़िलों पर खर्च होना चाहिये उतना हो नहीं रहा । जवाब में मैं जानता हूं कि यह कहा जायेगा कि भाखड़े पर जो खर्च किया जा रहा है उस से इन ज़िलों को फायदा पहुंचेगा । परन्तु फिर भी अगर बजट का गहरा मुताल्या किया जाये तो हम देखते हैं कि इन चार ज़िलों पर Irrigation के बारे में या Medical और तालीम के बारे में जितना खर्च होना चाहिये वह नहीं हो रहा । मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि मनिस्टरी को जो पिछड़े हुए इलाके हैं उन का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिये । हरयाने को Joint Punjab में अंग्रेज़ी राज्य के समय में भी नज़रान्दाज किया जाता था । इस लिये अब इन इलाकों की तरफ़ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये । यह शब्द कह कर मैं बैठ जाता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई और माननीय सदस्य तकरीर करना चाहें तो वे कर सकते हैं ।

सिंचाई मंत्री (चौधरी लहरी सिंह) : स्पीकर साहिब ! मैं ज्यादा details में आज नहीं जाना चाहता। मैं केवल उन दो तीन बातों का जवाब दूंगा जो श्री बाबू दयाल, कामरेड मनीराम और श्री मूल चन्द जी ने कहीं हैं। यह कहा गया है कि एक अफ़सर के खिलाफ़ शिकायत की गई मगर उस की enquiry नहीं की गई। यह कहा गया है कि एक Superintending Engineer ने उन से धोका किया और उन को enquiry में नहीं बुलाया था। यह कहा गया है कि वह माननीय सदस्य खाना खाने चले गये थे, Superintending Engineer वापसी पर रास्ते में उन्हें मिला और उस के बाद उन्हें enquiry में शामिल होने का कोई मौका नहीं दिया गया। असल बात यह है कि इन अफ़सरों ने उन सब लोगों को enquiry में शामिल होने का मौका दिया जिन की तरफ़ से शिकायत की गई थीं। मेरे दोस्त को एक registered notice भेजा गया था। वहां पर enquiry के लिये एक date मुकर्रर की गई थी। इस के बावजूद यह कहना कि धोका किया गया है, ठीक नहीं है। Superintending Engineer ने मुझे बताया और सब के ब्यान ले लिये गये हैं, मुतअल्लिका M.L.A. से भी दरखास्त की गई थी कि वह भी तारीख पर आयें मगर वह नहीं आये इस के बावजूद यह कहा जाता है, यहां पर कि हम इस मामले को दबाना चाहते हैं।

श्री बाबू दयाल : On a point of personal explanation.

अध्यक्ष महोदय : जब वे तकरीर खत्म कर लेंगे तो आप personal explanation दे सकते हैं।

सिंचाई मंत्री : फिर मैंने उस दोस्त से कहा कि हम यह केस enquiry के लिये Suprintending Engineer को दोबारा भेज देते हैं। अब इस बात से साफ़ इनकार किया जाता है। मैं आप फिर कहता हूं कि मेरे काबिल दोस्त अगर चाहें तो हम उन को फिर मौका देने के लिये तैयार हैं। (*Cheers*)। मैं चाहता हूं कि आप enquiry में जायें। हम अफ़सर को भेजने के लिये तैयार हैं। उस अफ़सर ने मुझे बताया कि उस दोस्त का कोई मकान का झगड़ा था और वह उस पर दबाओ डालना चाहते थे। इस से पंडित श्री राम को भी कुछ तक्लीफ हुई और मेरे दोस्त को भी तकलीफ हुई। मैं नहीं चाहता कि हमारी Cabinet के खिलाफ़ यह कहा जाये कि वह रिश्वत के cases को दबाते हैं। मैं इस मामले की सब details में जाने के लिये तैयार हूं। मैं खुल्लम खुल्ला House के सामने यह कहता हूं कि मेरे दोस्त जिस तरह भी enquiry कराना चाहें हम उस के लिये तैयार हैं। वे जितने चाहें गवाह पेश करें हम enquiry के लिये तैयार हैं।

मेरे एक और दोस्त ने कहा है कि मैंने कांग्रेस उम्मीदवार को वोटें दिलाने के लिये एक गाओं को नहिर का एक मोघा दे दिया। हकीकत यह है कि जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो रास्ते में एक हाई स्कूल पड़ता था। जब मैं उधर से गुज़रा तो स्कूल के उस्तादों और लड़कों ने मुझे पकड़ कर कहा कि स्कूल बिल्कुल बारानी इलाके में है और कुआं बहुत दूर है इस

लिये बच्चों को पानी की बहुत तकलीफ होती है। उस मोघे का पहले फैसला हो चुका था। लोगों ने मुझे बताया कि उस मोघे में देर हो रही है। वह मोघा पहले मनजूर हो चुका था। इस में यह कहना कि Cabinet रिश्वत देती है बिलकुल ग़लत है।

फिर लाला मूल चंद जैन ने यह कहा कि बजट में हरियाने को कुछ नहीं मिला है। वह अगर हिसाब करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। मैं कहता हूं कि अकेली झज्जर की तहसील में 30 लाख का काम करवाया गया है। इसी तरह अम्बाले और करनाल में सब ज़िलों में काम हुआ है। इस लिये ज़िलों की बातें करना ठीक नहीं है। अगर कोई शिकायत हो तो आप लीडर साहिब से मिल कर उन्हें कह सकते हैं। वह हरेक को accommodate करने के लिये तैयार हैं। लेकिन हरियाने के नाम पर एक नया ज़हिर पैदा करना ठीक नहीं। इस से कम्यूनिस्टों और दूसरे ऐसे अफ़सरों को जो ऐसी बातें चाहते हैं ज़हिर फैलाने का मौका मिलेगा।

The Assembly then adjourned till 2-0 *p. m., on Mondy, the* 22nd *March,* 1954

307 PSLA—283—21-2-55—CP&S. Pb., Chandigarh

Punjab Legislative Assembly Debates

22nd March, 1954

Vol. I—No. 10

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, 22nd March, 1954

CHANDIGARH :
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab.
1954

Price Re -/7/-

PUNJAB LEGISLATIVE ASSEMBLY

Monday, 22nd March, 1954

The Assembly met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh Capital, at* 2 *p. m. of the Clock. Mr. Speaker (Dr. Satyapal) in the Chair.*

QUESTION HOUR (DISPENSED WITH)

Chief Minister (Shri Bhim Sen Sachar) : Sir, I would suggest that if the number of the hon. Members desirous of speaking on the "General Administration" today is large, the Question Hour may be dispensed with. With your permission, I would start replying to the criticism levelled by various hon. Members in connection with Demand No. 10 at 4-30 p.m. The Development Minister also wants to speak.............

Mr. Speaker : How much time will the Development Minister take for making his speech ?

Chief Minister : Sir, he might require half an hour for this purpose.

Mr. Speaker: This means that if the Question Hour is not dispensed with the total time that will be left at the disposal of the hon. Members wishing to speak on the Demand now before the House will be one and a half hours.

Chief Minister : Sir, that is why I suggested that if the number of the hon. Members desirous of speaking on the "General Administration" is large, the Question Hour might be dispensed with.

अध्यक्ष महोदय : चीफ़ मनिस्टर साहिब ने फ़रमाया है कि आज बहस का आखिरी दिन होने की वजह से Development Minister साहिब आधे घंटे के लिये तकरीर करेंगे और खुद चीफ़ मनिस्टर साहिब अपनी तकरीर साढ़े चार बजे से लेकर ६ बजे तक करेंगे। तो आध घंटा Amendments के लिये चाहिये। इस लिये अगर Question hour चले तो hon. members के लिए बहस का वक्त सिर्फ एक घंटा रह जाता है। मेरी मुश्किल यह है कि Question जमा बहुत हो गये हैं। तो भी वक्त की तंगी के मद्देनज़र Question hour dispense with किया जाता है।

DEMAND FOR GRANT

GENERAL ADMINISTRATION

(Resumption of Discussion)

पंडित श्री राम शर्मा (सोनीपत) : स्पीकर साहिब ! General Administration पर शनिवार से बहस-हो रही है और आज भी इस ऐवान में इस बात पर मुबाहिसा

[पंडित श्री राम शर्मा]
हो रहा है कि हमारी State की administration किस तरह और कैसे चल रही है । General Administration में सभी बातें शामिल हैं और इस मुतालबाए ज़र के साथ हर उस बात को सामने लाया जा सकता है जिस के लिये हमारी Cabinet और ज़िले के अफ़सरान ज़िम्मेदार हैं ।

पहली बात जो मैं जनाब की खिदमत में कहना चाहता हूं, यह है कि चूंकि General Administration के अन्दर Legislature भी शामिल है, जहा तक बहस मुबाहसे का ताल्लुक है, आप भी इस बात को मैम्बरान से कई मर्तबा कह चुके हैं, और मैं भी यह महसूस करता हूं कि हमें अपने इस ऐवान में बहस की सतह काफ़ी हद तक बुलन्द और ऊंची रखनी चाहिये । बाज़ औकात इस बात की तरदीद होती है और लोग ज़ाती हमलों और छोटी २ बातों पर उतर आते हैं और नतीजा यह होता है कि हम सही बातों से हट कर ऐसी बातों में चले जाते हैं जिन से सूबे की कोई खिदमत नहीं होती और हम लोगों के सामने इस एवान के मुतल्लिक राय कायम करने के लिये वह बात पेश नहीं करते जो हमें करनी चाहिये । जहां तक Opposition के मैम्बरान का ताल्लुक है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम इस एवान में बहस के दौरान ज़ाती हमलों और छोटी २ बातों से बिलकुल परहेज़ किया चाहते हैं । हम जिस मकसद के लिये इकट्ठे होते हैं और पंजाब के अव्वाम जिस बात की हम से उम्मीद रखते हैं, हम उस मेय्यार पर पूरे उतरें । Opposition के मैंबर इस बात में पहल नहीं करेंगे कि बहस के अन्दर उन बातों को ऐसे तरीके से लाया जाए जो मुनासिब न हो और मैं उम्मीद करता हूं कि Leader of the House खास तौर पर इस बात का ख्याल रखेंगे ।

दूसरी बात मैं State की माली हालत के मुतल्लिक अर्ज़ करना चाहता हूं । यह ज़ाहिर है कि हम करीबन डेढ़ अरब रुपये के मकरुज़ हैं । इस साल तकरीबन 1 करोड़ का घाटा है । 4 करोड़ रुपये सालाना हमें सूद अदा करना पड़ता है । तो भी दिल बहलाने के लिये यह बात सोच सकते हैं कि इतनी भारी रकम कर्ज़ लेकर हम ऐसे कामों पर खर्च कर रहे हैं कि जिस से हमारे सूबे की आमदनी बढ़ेगी और हम तरक्की के रास्ते पर चलेंगे । मगर जहां तक Community Project Schemes और इसी तरह के दूसरे सुधारों का ताल्लुक है मैं गवर्नमैण्ट के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि जहां तक Self-help सेवा भाव और खिदमत का ताल्लुक है हम बहुत ही कम पैदा कर पाये हैं और अब तक जो काम होना चाहिये था नहीं हुआ । बाकी जो कुछ हुआ भी है तो जब खर्च होता है तो कुछ न कुछ होना ही हुआ, लेकिन जहां तक मैं ने देखा है हम लोगों के अन्दर वह स्पिरिट (spirit) पैदा नहीं कर सके हैं जो होनी चाहिये थी । चंद अफसरान ऐसे हैं जो खुद मेहनत करते हैं लेकिन हमने खुद देखा है कि बहुत हद तक काम फुसला कर और दबाव के तरीकों से लिया जा रहा है । इस लिये हमारे लोगों के अन्दर वह Self-help की spirit जिसकी एक आज़ाद मुल्क को अपनी हालत सुधारने के लिये ज़रूरत होती है अभी पैदा नहीं हुई । मैं कई मिसालें देकर तफ़सील में जाना नहीं चाहता लेकिन मैं देखता हूं कि लोगों से काम बेगार में लिया जाता है । हमारी गवर्नमैण्ट को कोशिश

करनी चाहिये कि वह इस काम के अन्दर ऐसी spirit पैदा करें कि लोग खुद महसूस करने लगें कि यह उनका अपना काम है। मगर जब तक यह चीज पैदा नहीं की जाती यह जो करोड़ों रुपये का खर्च Community Project के कामों पर हो रहा है, इस में तब तक पूरी कामयाबी नहीं हो सकती। यह ठीक है कि बाहर से लोग आते हैं और समझ लेते हैं कि काम हो रहा है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि वह चीज़ बिल्कुल पैदा नहीं हुई, जिस का कि हम स्वप्न देखते आ रहे हैं।

इस के इलावा, कैपीटल और भाखड़ा डैम Projects पर जो हम करोड़हा रुपया लगा रहे हैं, यह मेरा ही ख्याल नहीं बल्कि सब का ख्याल है कि इस रुपये का एक बड़ा भारी हिस्सा बरबाद होता है और इसे सरकारी व दूसरे लोग खा जाते हैं। जो काम हुआ है वह तो नज़र आता है मगर जो रुपया खर्च हुआ है उस का ख्याल कोई नहीं करता। यह तो ऐसी ही बात है जैसे कोई आदमी एक रुपया खर्च करके तीन आने के बर्तन खरीद ले और फिर बहस करे कि यह कैसी अच्छी चीज़ है। इस बात से इनकार नहीं हो सकता कि काम हुआ है, लेकिन इस बात की बड़ी भारी शिकायत है कि इस में रिश्वत, लूट और इसी किसम की दूसरी बेईमानियों का कोई हिसाब नहीं। मैं इस बात की तरफ गवर्नमैण्ट की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं..........

फिर हमारे वज़ीर खज़ाना ने जो कुछ कहा है वह मुझे अब तक याद है कि किसी मामले में भी हमारे वज़ीर दखल नहीं देते। किसी पार्टी का भी सरकारी इंतज़ाम और day-to-day administration अर्थात् आये दिन के सरकारी कामों में दख़ल नहीं। हकूमत के अन्दर किसी को भी मुदाख़लत करने का हक नहीं है और अफ़सर बगैर किसी दबाव के सही काम कर रहे हैं। मगर मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है और मैं महसूस करता हूं कि सूबे की हालत बिगड़ रही है। स्टेट में जो बड़े २ अफ़सर थे वह जा चुके हैं, ठीक है, मैं इस बारे में किसी की हिमायत नहीं करता और न ही नुक्ताचीनी करता हूं मगर यह सही है कि चीफ़ सैक्रेटरी के सिवाय ऊपर का कोई बड़ा अफ़सर सूबे में नहीं रहा। सब बड़े अफसरों को दूर कर दिया गया है। अफ़सरों में घबराहट और बेचैनी मौजूद है। जहां तक Administration का ताल्लुक है मैं समझता हूं और महसूस करता हूं कि अफ़सरों का यह ख्याल है कि उन्होंने नौकरी करनी है दिन गुज़ारने हैं। वह समझते हैं कि उन्हें वज़ीरों के इशारों पर चलना है। ऐम. ऐल. एज़. को खुश करना है। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अफ़सर कहते हैं कि उन्होंने "हां जी" "हां जी" करना है। मैं नहीं समझता कि यह ऐवान किस हद तक इस बात से वाकिफ़ है मगर वह सब लोग जानते हैं जिनका कि ऐडमनिस्ट्रेशन (Administration) से वास्ता पड़ता है। जो हालत आजकल General Administration की है मैं महसूस करता हूं कि यही हालत अंग्रेज़ों के राज्य के आखिरी दिनों में थी बल्कि अब उस से भी खराब है। यहां तो यह हालत है कि पार्टी और गरोहबन्दी को मज़बूत करने के लिये अफ़सरों का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार सर खिज़र हयात ने कहा था कि वह काम की जांच इस तरह की करेंगे कि उस अफ़सर का काम ज्यादा अच्छा समझा जायेगा जिस की इलैक्शनों में सब से ज्यादा शिकायतें आयेंगी। हो सकता है कि हम भी उसी हालत को पहुंच जायें।

[पंडित श्री राम शर्मा]

जब समाज की परवाह न की जाये और गवर्नमैण्ट को मज़बूत करने के लिये पार्टी और गरोहबन्दी को मज़बूत किया जाये और इस के इलावा किसी बात का ख्याल न रखा जाये और कहा जाये कि गवर्नमैण्ट बढ़िया तरीके से चल रही है तो मैं ज़ोर से कहूंगा कि यह एक पार्टी गवर्नमैण्ट के शीघ्र ही डूबने की आखिरी अलामत होती है।

चाहे गवर्नमैण्ट में अंग्रेज़ था, हिन्दुस्तानी था, मैं हूं या कोई दूसरा हो जिन लोगों ने गवर्नमैण्ट की मशीनरी को गरोहबन्दी से मज़बूत करने की कोशिश की उन का बेड़ा ग़र्क हो गया है। टर्की के अन्दर एक ही पार्टी थी। बड़े बड़े आदमी उन में काम करते थे। कोई Opposition नहीं थी। मगर फिर भी वह पार्टी खत्म हो गई और पिछले इलैक्शन में बुरी तरह हार गई। हमने अखबारों में पढ़ा है कि Opposition के न होते हुए भी ruling party को लोगों ने वोट नहीं दिये।

फिर आप East Bengal में देखें कि कैसे ruling party को लोगों ने वोट नहीं दिये और अब तक जो कुछ हुआ है आप सब जानते हैं। फिर यह कोई भी नहीं कह सकता कि अब पाकिस्तान के Frontier सूबे में क्या होगा। किसी को पता नहीं कि लोग किसे वोट देंगे। इन सब बातों से साफ़ ज़ाहिर है कि जहां हकूमत के ज़रिये पार्टी को मज़बूत करने की कोशिश की जायेगी वहां पर पार्टी गवर्नमैण्ट को खत्म करने की अलामत साफ़ होगी।

गरोहबन्दी को मज़बूत करने के लिये क्या किया जाता है और क्या नहीं किया जाता। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैम्बर जाते हैं और वज़ीर साहबान को कहते हैं कि अगर फ़लां आदमी को रात तक न पकड़ा गया और गरिफ्तार करके जेल में न भेजा गया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो मुझे पता है कि किस तरह किसी को छोड़ा जाता है और किस तरह पकड़ा जाता है, मैं उन के नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन इस तरह गरोहबन्दी को मज़बूत रखने की कोशिश की जाती है।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जब गवर्नमैण्ट इस हद तक आ जाये तो ज़ाहिरा नज़र आता है कि उनकी गवर्नमैण्ट कैसे चल रही है और ऐसी गवर्नमैण्ट का हशर वह होता है जो मुल्क में और बाहर हम देखते हैं। मैं ज़ोर से कहना चाहता हूं कि जहां ऐडमनिंस्ट्रेशन (Administration) की यह हालत हो वहां अफ़सर अपने आप को secure नहीं समझते। वज़ीर तो बहुत बड़े आदमी हैं और वज़ीरों को मिलने के लिये भी बड़े बड़े लोग आते हैं लेकिन 99 प्रतिशत नीचे से बड़े अफ़सर ने समझ लिया है कि उसे हर जायज़ वा नाजायज़ चीज़ बड़ों के इशारे पर करनी होगी।

हमारे वज़ीर खज़ाना ने फरमाया था कि day-to-day administration में कोई भी वज़ीर या ऐम. ऐल. एज़ मुदाखलत नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि उनका यह बयान बिल्कुल ग़लत है। अगर सूबे की हालत यहां तक बिगड़ चुकी है और अगर मेरे दोस्त इन तरीकों से हकूमत को मज़बूत करना चाहते हैं और गवर्नमैण्ट को चलाना चाहते हैं तो वे अच्छी तरह समझ लें कि लोगोंने भी तरीके अज़मा लिये हैं। वे उन तरीकों से गरोहबन्दी को खत्म कर देंगे।

एक बात इन्हों ने यह कही है कि Judiciary को Executive से अलग कर रहे हैं। यह इस Spirit से किया जा रहा है कि वज़ीर साहिबान हरेक पर dominate कर सकें। हकूमत में इस तरीके से काम हो कि मजिस्ट्रेसी (Magistracy) और जज (Judges) यह सोचें कि वह पार्टी एजन्ट (Party Agent) के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर यही Spirit है Judiciary को अलग करने की, तो इस से कुछ फ़ायदा न होगा।

वज़ीर साहिब का कहना है कि सूबे में Law and Order improve कर गया है। रोहतक की हालत के बारे में मैंने वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर सुनी है कि फलां जगह इतने अफसर भेजे गये। जब हालत कुछ ठीक हुई तो वह अफसर वापिस बुला लिये गये और काम बन गया। जब फिर हालत ज़रा बिगड़ी तो और अफसर और पुलिस भेज दी गई और हालात पर काबू पा लिया गया। लेकिन यह अमरेवाक्या है कि इतने ख़तरनाक, ख़ौफनाक और शर्मनाक डाकुओं के सरगुने को अभी तक नहीं पकड़ा गया। इस के बीच के आदमियों को पकड़ लिया गया है या मार दिया गया है। लेकिन गवर्नमैण्ट को पता होना चाहिये कि इस का क्या असर हुआ क्या नतीजा निकला। वहां की तमाम पोलीटीकल पार्टियों ने शिकायतें की हैं। रोहतक की Bar Association की तरफ से, आर्य समाज की तरफ से, Congress workers और कांग्रेसी देवियों की तरफ से, रोहतक में रूनुमा हुए हालात के बारे में शिकायत की गई है। यह शिकायत उन लोगों की तरफ से की गई जो वहां के मेम्बर हैं और दूसरे लोगों की तरफ से भी की गई। लेकिन गवर्नमैण्ट कहती है कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि औरतों पर बलात्कार और असमतदरी से लेकर सब कुछ वहां हुआ। लेकिन वज़ीर खज़ाना ने ही नहीं बल्कि वहां के तीन चार मेम्बर कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ।

सिंचाई मंत्री: तीन चार नहीं बल्कि सात आठ ऐसा कहते हैं। खैर 8-9 कहते हैं कि हालात ठीक थे। माना कि वहां हालात ठीक थे तो क्या जिस के मुतल्लिक Bar Association ने कहा है वह बात नहीं थी। अगर यह बात है तो मुझे अंग्रेज़ों का ज़माना याद आता है। जब अंग्रेज़ का राज्य था तो हिंदोस्तानियों पर ज़ुल्म ढाये जाते थे। जब लोग कहते हैं कि ज़ुल्म हुआ है तो गवर्नमैण्ट कहती है कि नहीं हुआ। Home Secretary कहता कि ऐसा नहीं हुआ। इस की एक खास वजह थी, वह यह कि जब वह देखते थे कि उन के कहने न कहने के बावजूद भी ज़ुल्म हो रहा है और उन के 'नहीं नहीं' कहने का असर लोगों पर नहीं होता तो वह इस बात को अपने मुफ़ाद में समझते थे कि एक Enquiry Committee मुकर्रर कर दें। इसी तरह वज़ीर खज़ाना और गवर्नमैण्ट की तरफ से "नहीं नहीं" कहने के बावजूद अगर लोग शिकायत कर रहे हैं तो यह गवर्नमैण्ट के मुफ़ाद में है कि वह यह मामला का किसी Judicial या बेज्युडीशियल कमेटी को enquiry के लिये दे दें। और यह ऐसी बाडी हो जिस को लोगों का एतमाद हासिल हो। "नहीं नहीं" कहने से कुछ नहीं बन सकता।

कांग्रेस गवर्नमैण्ट कहती है कुछ नहीं हुआ। वज़ीर खज़ाना कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं हुई। न औरतों की असम्मतदरी की गई न उन पर बलात्कार किया गया है

[पंडित श्री राम शर्मा]
तो क्या यह ठीक नहीं होगा कि जो कुछ Bar Association कहती है या आर्य समाज की देवियां कहती हैं या सवा सौ आदमी कहते हैं ? मैं कहता हूं कि उनको बेलाग Judiciary का verdict ले कर ग़लत बताया जाये। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उन लोगों के बताये हुए वाक्यात ठीक साबत होते हैं। लेकिन ऐसी कार्यवाही नहीं की जा रही क्योंकि गवर्नमैण्ट और वज़ीर साहिबान को डर है कि बेलाग Enquiry करने से उनके राज़ फ़ाश हो जायेंगे। Enquiry की रोशनी में सब चीज़ नुमायां हो जाएगी।

फिर ला ऐंड आडर (Law and order) के बारे में कहा गया है कि पुलिस और Magistracy आज़ाद हैं। मगर पुलिस देखती रहती है कि उनको ऊपर से क्या इशारा होता है। General Administration की यह हालत है और इस का नक्शा नहीं बदला गया। अगर इस नकशे को न बदला गया तो मैं कहता हूं कि इस से कोई profit नहीं होगा और मैं अपने सामने बैठे दोस्तों से कहूंगा कि जो कुछ East Bengal में हुआ है उन्हें उस को नहीं भूलना चाहिये।

श्री बाबू दयाल (सोहना) : स्पीकर साहिब! मैं एक personal explanation देना चाहता हूं। परसों Irrigation Minister साहिब ने मुझ पर तीन इलज़ाम लगाये थे। पहला यह कि मैं inquiry के मौके पर पहुंचा ही नहीं। यह इलज़ाम ग़लत है। मैं उस मौका पर पहुंचा था और लोगों ने मुझे बताया कि Superintending Engineer कहता है कि मैं inquiry के लिये नहीं आया और कोई ....

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ explanation दें तकरीर न करें।

श्री बाबू दयाल : बहुत अच्छा जनाब ! दूसरा इलज़ाम यह था कि मैं उस अफ़सर से मिल गया था। अगर मैं मिल गया होता तो आप के पास वह file ले कर क्यों आता जो आप ने उठा कर फैंक दी थी। तीसरा इलज़ाम था कि किसी कांग्रेसी कारकुन का मकान requisition कराया गया था उस को de-requisition कराने के लिये मैंने ऐसा किया। यह भी बिल्कुल ग़लत बात है।

श्री गोरख नाथ (नरोट जैमल सिंह) : स्पीकर साहिब ! 18 तारीख को General Administration के बारे में Opposition की तरफ से जो कुछ कहा गया और जो नुकताचीनी की गई उस का ताल्लुक इस बात से भी था कि वज़ीरों को बाहर बहुत कम जाना चाहिये और दफ़तर में बैठ कर काम करना चाहिये। इस का जवाब जो कि बहुत मुनासिब था प्रिंसिपल रला राम जी दे चुके हैं। मैं उस को दोहराना नहीं चाहता, मगर उस की ताईद करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ़ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम इस बात की ख़ाहिश रखते हैं कि हमारा Administration बेहतर हो और इस ख़ाहिश को अमली जामा पहनाने में हमें कुछ कामयाबी भी हुई है लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि जो चीज़ें इस में चल रही हैं और जो खतरात हैं उन से आंखें न मूंद लें। General Administration के सिलसिले में एक बात जो साधारण समझी

जाती है मैं उसे खतरनाक समझता हूं। वह यह है कि मेरे ज़िले में development का काम होता रहा। खुद मेरे इलाके में Community Project के काम होते रहे हैं। वहां एक बड़ा बंद भी बनाया गया जिस की काफ़ी publicity हुई। लोग हज़ारों की तादाद में वहां काम करने गये। इस के लिये 50,000 रुपये के खर्च का अंदाज़ा था और कहा गया था कि लोग खुद बाकी काम करें। मगर वह अंदाज़ा ग़लत साबित हुआ और 50,000 की donations हासिल करनी पड़ीं। वह donations हमारे Administration ने हासिल कीं। लेकिन अब अगर उन के बारे में सब बातों का analysis किया जाये तो मैं कहूंगा कि ऐसी donations हरगिज़ नहीं ली जानी चाहियें। हमारे Deputy Commissioner के इखलाक, ईमानदारी और मेहनत पर फख़र किया जा सकता है। लेकिन ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जब donations ली गई तो अफ़सरों ने donations देने वालों के कई नाजायज़ काम किये। यह कुदरती बात है कि जो अफ़सरों को रुपया देते हैं वे अपने काम पीछे मुख्य रख लेते हैं और गरीबों से बेइनसाफ़ी हो जाती है। मैं अर्ज़ करता हूं कि लाखों की donations हासिल करने में अगर एक गरीब को भी नुकसान पहुंचता है तो ऐसी donations नहीं ली जानी चाहियें। Administration का हर एक अफ़सर Deputy Commissioner जैसा नहीं हो सकता, इस लिये इस बारे में बहुत इहतियात करनी चाहिये।

फिर मैं सरकार का मशकूर हूं कि उसने हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत को महसूस किया है। यह हमारे इलाके में कालिज की ज़रूरत का सवाल था और अब के बजट में इस का ख्याल किया गया है। मगर इस के लिये भी कहा गया कि सवा लाख रुपये की donations हासिल कर ली जायें तो कोई हरज नहीं। मगर हमारे लोग गरीब हैं पैसा पैसा कर के तो जमा नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ दो मिनट और।

श्री गोरख नाथ : मगर स्पीकर साहिब मैं तो............

अध्यक्ष महोदय : मैं बेबस हूं, अभी और भी बहुत से मेम्बर साहिबान ने तकरीरें करनी हैं।

श्री गोरख नाथ : खैर वह सवा लाख रुपया जमा कर लिया गया मगर उसी तरह जैसे अंग्रेज़ के वक्त में होता था या Unionist सरकार किया करती थी। Sub-Inspector और दूसरे अफ़सरों की मारफ़त यह रुपया जमा कराया गया। कौन नहीं जानता कि जब Sub-Inspector रुपया जमा करते हैं तो क्या हुआ करता है। मेरी अर्ज़ यह है कि यह ज़रूरी खर्च था तो सरकार यह रुपया खुद देती। इस के लिये tax लगाया जा सकता था। अमीर लोग tax दे सकते हैं। अगर टैक्स देने के बाद इन के पास कुछ पैसा कम हो जाये तो कुछ न बिगड़ जायेगा।

एक और ज़रूरी बात मैं अपने लीडर साहिब से कहना चाहता हूं। अगरचे रिशवत अब पहले से कम हो गई है। इस की वजह खाह यह हो कि अफ़सर डरने लगे हैं या उन का अखलाक़ बुलन्द हो गया है। फिर भी एक और खतरनाक चीज़ पैदा हो रही है। इस बारे में मैं अपने ज़िले की बात कहता हूं। हर जगह हर चौक में ऐसे लोग नज़र आते हैं जिन्होंने खद्दर

[श्री गोरख नाथ]
पहन रखा होता है। और वे लोगों को धोके से लूट रहे हैं। कोई मेरा नाम ले देता है। कोई कह देता है कि मैं कैरों साहिब या सच्चर साहिब का आदमी हूं और उन से हर काम करा सकता हूं वह इस तरह से अफ़सरों पर दबाव डालते हैं। यह अलग बात है कि बड़े अफ़सर अब दबाव में नहीं आते लेकिन छोटे अफ़सर बहुत दफ़ा दबाव में आ जाते हैं और इस तरह गरीबों से बेइनसाफी हो जाती है। मैं अपने लीडर से अब कहूंगा कि वह C.I.D. की ओर से पता लगायें कि ऐसे कौन कौन आदमी हैं जो लगातार कई सालों से सवेरे सात बजे शहरों के चौकों और होटलों के सामने आ बैठते हैं और शाम के सात बजे घरों को जाते हैं कोई काम नहीं करते और उनका कोई ज़रिया गुज़ारे का नहीं लेकिन इन का रहन सहन काम करने वालों से अच्छा है यह साधारण लोगों से रुपया ठगते हैं। इसके बारे में बड़े छोटे अफ़सरों से भी पता लगाया जाना चाहिये कि वह कौन लोग हैं जो अफसरों के लिये रिश्वत से भी बढ़ कर खतरनाक हैं और गवर्नमैण्ट के लिये बदनामी का कारण है। इन दलालों के खिलाफ कार्यवाही से रिश्वत बहुत हद्द तक बन्द हो जायेगी।

ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ General Administration ਉਤੇ 1,45,51,800 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਸਹੀ ਮਹਿਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ 8 March ਵਾਲੇ address ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਸਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ 19 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੁਣ 21 ਫੀ ਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਤੇ industry ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੜਾ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 4 ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੇ cottage industries ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ apply ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 20 ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਤਾਂ ਦੇਖ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਰਪੋਰਟ ਪੁਰ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ apply ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ cases pending ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ approval ਦਿਤੀ ਜਾਏ।

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਸ ਇਸ ਖਰਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ Section 109 ਹੇਠ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਗਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵੇਰੀ ਲਿਖ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਖੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗੇ ਜਿਹੜੇ section 109 ਹੇਠ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਧਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਹੋਣੋ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ ।

ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਰੀਜਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ under section 376, 363, 498, 454, ਤੇ ਹੋਰ sections ਦੇ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਵਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਭੁਲ ਚੁਕ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਚਾਲਾਨ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੇਸ ਹਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੇਸ dismiss ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ minister in charge ਪਾਸ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ Ministry ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਿਹੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ । ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਪਿਛੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ 11 ਹਰੀਜਨ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਦੀਵਾਲੀ P.S. Kathu Nangal, Amritsar ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਸੀ ਉਸਦੀ ਹਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ friction ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਹਰੀਜਨ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੁਖਾਲਿਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਕ scheduled caste ਦਾ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਉਤੇ under Section 454 ਹੇਠ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿਲਾਕੇ ਉਸ ਉਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਕਰਾ ਦਿਤਾ । ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ । ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ dog ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਕ magistrate ਕੁਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ! appeal ਹੋਈ ਤਾਂ Sessions Judge ਨੇ magistrate ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹਾਲ ਰਖਿਆ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, Sessions Judge ਖੁਦ ਬਹਿਸ ਕਰਤਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਸੁਣੀ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ । ਪਿਛੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗਲ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ । ਮੈਂ

[ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ]

ਸਿਰਫ਼ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ policy declare ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਾਨ ਬਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ (ਜੱਟਾਂ) ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਆਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ co-operate ਕਰਨਗੇ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ੭ ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਜਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (General Administration) ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਚੀ ਮੁਚੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ? ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕ ਹਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਥੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤਦ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਬਲਕ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਤਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਇਹ ਤਾਲ ਮੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੁਖੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਕਠਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ 144, ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ (Public Safty Act) ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤਰ ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਗਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤਰ ਸਰਦਾਰ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਟਵਾਰੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਿਆਂ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ deputation ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਟ ਭੇਜੀ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟ (Council of State) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਰੀ ਗਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰਾਣ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਮ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨ ਆਇਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਰਦਾਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲ ਪਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਇਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹੱਤਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ Scheduled Caste Fedration ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Vtilization of Waste Lands Act ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਜਾਤੀਆਂ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਨਾਵਾਂ ਇਲਾਕੇ

[ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਵਿਚ ਭੋਵਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਦਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਨਾਈ ਤੇ lease ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ scheduled caste ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਪਗੜੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ—ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜਨਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਗੀ ।

श्री जगत राम भारद्वाज (होशियारपुर) : स्पीकर साहिब, पेश्तर इस के कि मैं कुछ और बात कहूं मेरा ख्याल था कि इस democratic set-up में जो मुखालिफ पार्टी है वह अपने आप को कतई तौर पर मुखालिफ पार्टी समझती है और उस का सिवाए गवर्नमेंट पार्टी की मुखालिफत करने के और कोई काम ही नहीं । इस लिये मैं समझता हूं कि वह अपने आप को एक गलत रास्ते पर ले जा रही है । यह Opposition Party महिज़ Opposition के लिये नहीं बल्कि यह एक Supplementary Party है जिस का काम यह है कि जो खराबी हकूमत में हो उसे उस को सामने रखे और अपना फर्ज यह न समझे कि उस ने कतई तौर पर गवर्नमेंट पार्टी की मुखालिफत करना है । स्पीकर साहिब ! मैं गुज़ारिश करूंगा कि इस हाउस में पुलिस के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । हम ५० वर्ष से आज़ादी कि जद्दो जहिद में पुलिस का मुकाबला करते आये हैं । हमारा कतई तौर पर जज़बा पुलिस अफ़सरों के खिलाफ रहा है क्योंकि वह हमें हथकड़ियां लगाते थे और तंग करते थे । ऐसा जज़बा होना कुदरती बात है । जिस तरह हम ने bureaucratic जज़बे को दूर करने की कोशिश की है इसी तरह हमें पुलिस के खिलाफ जो हमारे दिल में जज़बा है उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिये । पुलिस अफ़सरों के मन से भी यह भाव दूर हो जाने चाहियें कि वह हमारे हाकिम हैं बल्कि उन्हें अपने आप को लोगों का खादिम समझना चाहिये । इसी तरह हमने भी यही देखना है कि हम पुराने जज़बे के तहित तो काम नहीं कर रहे । पुलिस के या दूसरे जहां भी अफ़सर हैं उन के दिल में पुराना जज़बा कुदरती है । बदले हुए हालात में हमारे अन्दर ऐसा जज़बा उन के खिलाफ नहीं रहना चाहिये । इस लिये अगर हम लोग अच्छी तरह से देखें तो सही रास्ते पर आ सकते हैं और हम दोनों में कोई मतभेद नहीं हो सकता ।

दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि रिश्वतखोरी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि लोगों को सरकारी अफ़सरों के सलूक से शिकायत है । सलूक इस किस्म का मिलता है कि लोगों का दिल दुखी हो जाता है । इस सलूक की वजह से लोग यह समझने लग जाते हैं कि अफ़सर रिश्वत चाहते हैं । एक तरफ सलूक और दूसरी तरफ बाकी सारी खराबी है । सलूक अगर ठीक हो जाये तो सब कुछ ठीक हो सकता है । यह मेरी जाती राए है ।

दूसरी चीज़ मैं यह कहना चाहता हूं कि administration वज़ीरों के सामने ज़िम्मेदार है । वह आगे Legislature के सामने ज़िम्मेदार है और Legislature

Public के सामने जिम्मेदार है। मगर ultimately sovereignity लोगों के अपने हाथ में है। पब्लिक की राए को हमें सर पर रखना चाहिये। Administration हकूमत के ज़ेर है और वुज़रा Legislature के आगे जिम्मेदार हैं। इस तरह से एक दूसरे पर ज़िम्मेदारी आयद होती है।

फिर हम देखते हैं कि मुल्क के अंदर administration ने क्या किया है। अगर हम ४७ के बाद law and order को देखें तो हमें पता लगता है कि जरायिम कम हुए हैं। Irrigation के बारे में लाखों एकड़ ज़मीन को पानी दिया गया है, बिजली की पैदावार बढ़ाई गई है, ज़मीनों का इस्तेमाल जारी है। Co-operative Societies के बारे में हम देखते हैं कि उन का काम बढ़ गया है; Community Projects का बहुत ज्यादा काम हो रहा है। Industries का विकास हो रहा है और Labour की बेहतरी की स्कीमें बनाई जा रही हैं। सड़कें बन रही हैं पंचायतें बनाई गई हैं। मुलाज़मों की तनखाहें बढ़ाई गई हैं। ग़र्ज़ेकि मुल्क के अंदर सब कुछ हो रहा है।

यहां फरमाया गया है कि वुज़रा साहिबान दौरे करते हैं। मेरे जिले का एक हिस्सा कंडी का इलाका है। अगर वज़ीर वह इलाका देखते तो उन का जिगर फट जाता। एक वज़ीर साहिब पिछले दिनों वहां गए थे। उन्हें यह जान कर हैरानी हुई कि ७०० मुरब्बा मील के इलाके में काने ही काने है और जंगली जानवरों के डर से लोग जाग कर रातें काटते हैं। वह जंगली जानवर कोई फसल नहीं छोड़ते। परन्तु licences की यह हालत है कि कुछ शौकीन लोग पिस्तौल पहने फिरते हैं। यह वह केवल शौक पूरा करने की गर्ज़ से पहनते हैं। कुछ लोगों ने हिफाज़त के लिये बन्दूकें रखी हुई हैं। मगर शिकारी बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। इस की कुछ वजह यह है कि शिकार के licence की सालाना फ़ीस १५ या १८ रुपये है और गोलियों की कीमत ५०. रुपये सैंकड़ा है। शिकारियों के खत्म हो जाने की वजह से जानवर सब फसलें खाए जा रहे हैं। हम मशकूर हैं कि सरकार ने चोओं की तरफ ध्यान दिया है। मगर अब यह जंगली जानवरों का मसला हमारे लिये एक जटिल समस्या बन गई है। मैं चाहता हूं कि वहां पर फौज या पी. ए. पी. को भेज कर जंगली जानवरों का सफ़ाया कराया जाये। अगर ऐसा किया जाये तो मुल्क बस सकता है वरना नहीं।

खान अब्दुल ग़फ्फार खां (अम्बाला शहर) : जनाबे सद्र ! जिस वक्त मैं यहां मौजूद होता हूं, मैं दोनों तरफ की तकरीरें यानी इस तरफ वाले साहिबान की और Opposition वाले साहिबान की भी ग़ौर से सुनता हूं। मगर अफसोस यह है कि हम में जो खामियां हैं वह हम कहना नहीं चाहते और जो Opposition है उन्होंने कसम खा रखी है कि हमारी वज़ारत चाहे कितना अच्छा काम क्यों न करे उन्होंने भूले भटके से भी उस की तारीफ़ नहीं करनी है।

सरदार सरूप सिंह—ऐसा तो नहीं है, खां साहिब।

खान अब्दुल ग़फ्फार खां : उन की यह आदत है। लुध्याने के एक मैम्बर ने फरमाया कि अफसरों को काम करने नहीं दिया जाता और हमारे कांग्रेस के मैम्बर उन पर बेजा रोअब डालते हैं और उन को intimidate करते है। मुझ को और ज़िलों का पता नहीं। मैं अपने

[खान अब्दुल गफ्फार खां]
ज़िले अंबाले के बारे में दावे से कह सकता हूं कि वहां पर कोई कांग्रेसी डिप्टी कमिशनर या Superintendent of Police को मरऊब करने के लिये नहीं जाता है। मैं challenge करता हूं कि Opposition का कोई मैम्बर आए और मुझे दिखाये कि कब कोई कांग्रेसी अफ़सरों के पास गया है। लेकिन अगर यह बात है कि कहना ही है कि रोटी खाते हुए दाढ़ी हिलती है तो उस का हमारे पास कोई इलाज नहीं।

फिर मोगा के एक मैम्बर ने कहा कि कांग्रेस वरकर रिशवत लेते हैं। मैं समझता हूं कि चूंकि यह बात इस House के floor पर कही गई है इस लिये वह अपने आप को immune समझते हैं। लेकिन अगर यह बात बाहर कही जाती तो मैं समझता हूं कि वह immune न होते।

Mr. Speaker : Please do not say that.

श्री वधावा राम : जो लिखा है वह ज़रूर पढ़ेंगे।

खान अब्दुल गफ्फार खां : मैं बग़ैर लिखे के पढ़ सकता हूं। मैं कोई मौकूफ़ शुदा पटवारी नहीं हूं।

Mr. Speaker : Order, please.

खान अब्दुल गफ्फार खां : यह बात गलत है कि कांग्रेस का कोई मैम्बर ऐसा काम करता है। बल्कि मैं बता सकता हूं कि Opposition पार्टियों के कई मैम्बर ऐसा करते हैं। मैं उन के नाम भी बाहर जाकर बता सकता हूं। (*Cheers*)

फिर सामने बैठे दोस्तों ने यह भी कहा है कि वज़ीर साहिबान तन्खाहें तो पंजाब के खज़ाने से लेते रहे और काम Pepsu में electioneering का करते रहे। यह भी कहा गया है कि उन्होंने पार्टी की अग्राज़ के लिये सरकारी मोटरकारों और पैट्रोल का इस्तेमाल किया। मैं उन से पूछता हूं कि क्या कांग्रेसी होने के नाते यह उन का फर्ज़ नहीं था और अगर वह पेप्सू में न जाते तो अपने फर्ज़ से कोताही न करते। (तालियां)।

फिर उन्होंने यह कहा कि पैप्सू में कांग्रेस राजाओं और महाराजाओं की हो गई है। अपने तौर पर उन्हों ने यह कह कर एक बड़ा तीर मारा है। मैं उन से यह कहूंगा, "कल तक आप लोग जिन के दरबार में जाते थे, हम ने उन को ला कर आप के दरबार में खड़ा कर दिया है।" आप कहते हैं कि वे खतरनाक सांप हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप को किसी शख्स को सांप से तशबीह नहीं देनी चाहिये।

खान अब्दुल गफ्फार खां : जनाबे वाला ! उन्हों ने ही यह इर्शाद फरमाया है। मैं पूछता हूं कि अगर कोई ग़लती कर के, मुआफ़ी मांग ले और सीधे रास्ते पर आ जाये, तो इस में क्या हर्ज है ? दरे तोबाह तो किसी पर बन्द नहीं है ?

इस में शक नहीं कि इस हुकूमत के राज्य में बहुत कुछ हो रहा है लेकिन इतना नहीं जितना public चाहती है ? हम चाहते हैं और जितना हम और वज़ीर साहिबान खुद चाहते हैं। मिसाल के तौर पर पुलिस के कर्मचारियों को लीजिये। वज़ीरों के सामने तो कप्तान साहिब और दूसरे बड़े २ अफ़सरान आते हैं। लोगों को तो, Constables, Head Constables

और Sub-Inspectors से ही वास्ता पड़ता है। इसी तरह माल के महकमे में public का छोटे कर्मचारियों से वास्ता पड़ता है। वज़ीर साहिबान के सामने तो डिप्टी कमिश्नर और माल अफसरान वगैरा ही आते हैं। मगर छोटे कर्मचारियों में ईमानदारी नहीं है, तो लोग कुदरती तौर पर बड़े अफसरों और वज़ीर साहिबान की ईमानदारी पर भी शक करने लगते हैं। इस लिये मैं वज़ीर साहिबान की खिदमत में अर्ज़ करता हूं कि वे छोटे मुलाज़िमों की ईमानदारी की तरफ ज़्यादा ध्यान दें।

Mr. Speaker : Please finish your speech now.

खान अबदुल ग़फ्फार खां : बस जनाब, मैं एक बात और कह कर बैठ जाता हूं। जनाबे वाला, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर सूबा में, हर महकमा में अम्बाला डिवीज़न को कतअन ignore किया जा रहा है और फिर इस डिवीज़न में से जिला अम्बाला को सब से ज़्यादा नज़र अंदाज़ किया जा रहा है। मुझे बड़े दुःख के साथ अपने वज़ीर साहिबान से कहना पड़ता है कि उन में रहम करने की ताकत भी नहीं रही अम्बाला शहर में लोगों को पानी तक नहीं मिलता। रोज़ सर फुटव्वल होती है। पुलिस के पर्चे बढ़ जाते हैं और झगड़े में बर्तन फट जाते हैं। पानी की बड़ी किल्लत है। कई बार इस मामले की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया गया है मगर अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस तरह अंग्रेज़ों के वक्त में United Punjab की हकूमत के East Punjab को ignore करने की वजह से आज हम रो रहे हैं, इसी तरह अगर अम्बाला डिवीज़न को ignore किया जाता रहा, तो हमको एक न एक दिन फिर रोना पड़ेगा। "अगर इस डिवीज़न की हालत खराब ही रही तो यह प्रांत की तरक्की की स्कीमों और आप की नेक ख्वाहिशात की तकमील के रास्ते में रोड़ा बन जाएगा। हम तो कुछ डूबेंगे ही, साथ वालों को भी ले डूबेंगे।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲਫਜ਼ Rhetorically use ਕੀਤੇ ਹਨ। He never meant what he has said.

Sardar Sarup Singh : On a point of order, Sir. It is a reflection on the hon. Member concerned.

Mr Speaker : No. I would have no objection to being called a rhetorician.

Minister for Development : Sir, it was just a tribute to the hon. Member.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ Utilization of Waste Lands Act ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਖਾੜਦੇ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਟ ਕੇ ਖੇਤੀ

[ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ]

ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕਰਦੇ । ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਚੁਥਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ reclaim ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਨੂੰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ agreement ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾਂ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਉਪਰ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ reclamation ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਈਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਾਹੀ ਕਰ ਕੇ agreement ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ (ਤਾਲੀਆਂ) ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ lease ਉਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਦ ਦੇਣਗੇ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਮੁਰੱਬਾ ਬੰਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਰੱਬਾ ਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋ ਸੱਜਣ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ specific ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਜਵਾਬ complete ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਸਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ adjourn ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਨੀਆਂ ਕੁ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਲਖਣ ਪੁਰ, ਗਹਿਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਭੂਮਤੀ ਦੀ ਮੁਰੱਬੇ ਬੰਦੀ ਤੋੜ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੰਨੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਕ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ Opposition ਵਲੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਖਣਪੁਰ ਵਿਚ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਸਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਮੀਆਂ ਗਲਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਫਿਰਨੀ ਸਕੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰਨੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਹਰੀਜਨ ਆਬਾਦ ਹਨ ਉਥੇ ਫਿਰਨੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਹਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜ ੨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰਨੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਈ ਜਿਸ ਜਗਾਹ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਥੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਫੈਦਪੋਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ Settle-ment Officer ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਗਲਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁਰੱਬੇ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਭਲੇਵਾਂ ਹੈ, ਯਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਣਵੇਈਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਲਾ ਹੈ—ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਖ਼ਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆਇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਹਾਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਸਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁਰੱਬਾ ਬੰਦੀ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਲੈਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ argue ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁਰੱਬਾ ਬੰਦੀ ਟੁਟਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਫੁਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰ-ਖਲਾਫ petition ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁਰੱਬਾ ਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਲੀਡ (plead) ਕੀਤਾ। ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਨਾਂ ਤੋੜਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਉ ਹੇਠ ਆਕੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੋੜੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਫਿਰਨੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹਕ ਨਹੀਂ ਬਨਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁਰੱਬੇ ਬੰਦੀ ਤੋੜ ਦਿਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੋਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਟੁਟਣ ਦਿਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹੋ ਵਜਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ consolidation ਦੇ mutation ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੇ ਹੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰ ਲੋ ਉਹ ਅਪਣੇ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੰਦਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ (cases) ਨਾ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ legal binding ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ consolidation ਦੇ mutation ਦੇ cases ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿਤ੍ਰ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਲਗ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ,

[ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਅਗੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ consolidation ਦੇ mutation ਵਿਚ Assistant Consolidation Officer ਅਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ A. C. O. ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਛੋਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ opposition ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ degrade ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ degrade ਕਰਕੇ ਗਿਰਦਾਵਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ (ਤਾਲੀਆਂ)। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ meet ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਫੇਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਗਲ ਇਕੋ ਸਾਹ ਵਿਚ ਕਰ ਛੱਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ transfer ਬਹੁਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਤਕਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਦੂਸਰਾ ਫਿਕਰਾ quote ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ। ਦਰਅਸਲ ਲੜਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਣ ਅਫਸਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀਆਂ ੨ ਰਸੀਦਾਂ ਕਟੀਆਂ ਹਨ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੇਸ ਅਲੇਹਦਾ ਚਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਛਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰਖੋ। ਪਰ ਗਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸਿਉਂ (ਅੱਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ) ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਚਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ। ਯਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ। ਜਿਥੇ ਵੀ ਅਸੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਚੰਗਿਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ revert ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਉਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਸੇ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਏ0 ਸੀ0 ਓ. (Assistant Consolidation Officer) ਨੂੰ ਮੈਂ revert ਕੀਤਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਪੁਛੋਗੇ, ਕਿਉਂ ? ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਯਾ ਤਿੰਨ mutations ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਪੱਖ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀ ਕਿਤਾ । ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸੋ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਏ0 ਸੀ0 ਓ. ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੁਛਿਆ ਅਤੇ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਆਇਆਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੇ ਕਿਓਂ ਕੀਤੀ ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ revert ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ action ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ । ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ । ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਉ । ਪਰ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈ ਓਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ । ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇ । ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ । ਆਖਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਾਂ । ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਅਗੇ-ਪਿਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਮੁਤਅਲਕਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗਾ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਯਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਵੇ । ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਵਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਥੇ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਾਂਗਾ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤਿਕਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ੧੫,੧੫ ਯਾ ੨੦,੨੦ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਯਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਆਦ ਦਸਾਂਗਾਂ ।

ਕੁਝ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀ ਦੌਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਦੌਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਦੌਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਦਰਅਸਲ

[ਵਿਕਾਸ ਮੰਤੀ]

ਬਲਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਗਲ ਦੀ ਤੱਸਲੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਥੋਂ ਤਿਕਨ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਓ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਓਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਇਕ ਗਲ ਸੁਣਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨੀਵਿਆਂ ਨੀਵਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਦਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ (Opposition) ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਨਿਓਂ ਕੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਚਮੁਚ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਿਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਥੇ ਕੀਤੀ ਨ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇ ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੋਵੇ।

ਮੈਂ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਕਹਿਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਿਕਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਓਹ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ self-help ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਪੁਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਸੜਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ self-help ਨਾਲ ਬਨਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਨਯੋਗ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇ ਕਰਦੇਂ ? ਆਖਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਫ਼ਜ "ਵਰਗਲਾ" ਦਾ ਉਹੀ ਮੈਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ "persuasion" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ persuade ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ incentive ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ? ਕੀਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ competitions ਵਿਚ ਲਿਆਉਨ ਲਈ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗਲ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲਫਜਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਨ ਤੋਂ ਰੋਕਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੇਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ? ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਲੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ ?

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਕਲ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਲਾਵਜਾਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਹੁਣ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ constructive criticism ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਨਿੱਗਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਅਸਲੀ ਭਲਾਈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀਰ ਇਸ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ actions ਤੇ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਚਮੁਚ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ।

ਹਾਂ, ਪਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ self-help ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ facts and figures ਨਹੀ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਕਿ Community Projects ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ self-help ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ National Extension Scheme ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ facts and figures ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ (Finance Minister) ਨੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਤਾ ਹੈ (*cheers*) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗਲ ਸੁਣਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ 80 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁਖ ਨੰਗ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਾਗ਼ ਡੋਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਯਕੀਨਨ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਝ ਆਨਰੇਬਲ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਹਨ........।

ਸ਼੍ਰੀ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ : 'ਆਨਰੇਬਲ ਮਨਿਸਟਰ' ਨਾਲ ਰਲਕੇ ?

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ duty ਤੋਂ ਅਨਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ irregularity ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਏ।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਵਲ opposition ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ opposition ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਧਾਨ ਜੀ ਟੱਲੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ

[ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਯਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਯਨ ਵਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਅੰਬਾਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਉਲਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੂਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਗਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਰੋਸ ਹੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਫਿਰ, ਪਰਧਾਨ ਜੀ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਜ਼ਮੋਨਸਕ ਵਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਪੁਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ development ਪੁਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, law and order ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਬਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਘਟੋ ਘਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ law and order ਉਥੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ । ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਥਾਨੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਕ ਇਕ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਥਾਨੇਦਾਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾੜੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਮਾਲ ਕਰਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਉਪਰਾਂਤ ਜਿਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਦਫ਼ਾ 107 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਥੇ Special Magistrate ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ Executive ਤੇ Judiciary ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੋਵੇ । ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Security of Land Tenures Act ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ Executive ਤੇ Judiciary ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇਸ

ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ Deputy Commissioners ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਮਿਲਕੇ Law and Order ਦੀ ਮਿਟੀ ਪਲੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਕਿ Executive ਅਤੇ Judiciary ਨੂੰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਲਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ Additional District Magistrate ਦੇ ਥਲੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ Additional District Magistrate Deputy Commissioner ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ executive ਦਾ ਵੀ ਅੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ Posecuting Branch Deputy Commissioner ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਆਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Executive ਤੇ Judiciary ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਥੇ Executive ਨੂੰ Judiciary ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ proposal ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਮੋਨਸੱਕ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ Branches ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਜ਼ਮੋਨਸਕ ਦੀ ਮਿਟੀ ਪਲੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ Development State ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਮੋਨਸਕ state ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ State ਵਿਚ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਨਜ਼ਮੋਨਸਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ administration ਉਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੇ Deputy Commissioners ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਜਮਾਤ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰੁਟੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

श्रीमती सीता देवी (जालन्धर शहर, दक्षिण-पूर्वी हल्का) : श्रीमान् प्रधान जी ! General Administration पर दो दिन से गवर्नमैण्ट Benches की तरफ से और दूसरी तरफ से बहुत कुछ कहा जा रहा है। अब जब हम Opposition वालों की speeches सुनते हैं तो उन से यह मालूम होता है कि Opposition वालों ने खुद ही मान लिया है कि General Administration जो है वह पहले से बेहतर है क्योंकि करोड़ों रुपया इस पर खर्च हो रहा है। चाहिये तो यह था कि अगर General Administration पर नुक्ताचीनी करनी है तो कुछ Constructive Suggestions दिये जायें। लेकिन वे नहीं दिये गये। सिवाये तानाजनी, जातियात के झगड़ों या फिर्का प्रस्ती की किस्म की चीज़ों के Opposition की तरफ से और कुछ नहीं पेश किया गया। तकरीबन जितनी speeches जो यहां इस बहस के दौरान में हुई हैं, मैंने सब को अच्छी तरह सुना है। इन से यह मालूम होता है कि Opposition वालों की तरफ से यह माना गया है कि General Administration में आगे से काफी improvements हो रही हैं परन्तु वे अपने मन के मुताबिक कुछ कहना नहीं चाहते क्योंकि अगर वे कहें तो उन की लीडरी खतरे में पड़ जाती है। अगर वे General Administration की तारीफ़ करने लगें तो उन्हें डर है कि कहीं पंजाब के लोग यह न कहने लग जायें कि तमाम Oppos tion वाले सरकार की तारीफ़ करने लग पड़े हैं। सो अगर यह ऐसा कहें तो इन की बात कुछ नहीं बनती ।

एक बात स्पीकर साहिब जो मैं कहना चाहती हूं यह है, कि जैसा के पंजाब की सरकार इस प्रदेश की हालत को सुधार कर एक Welfare state बनाने के लिये पंचायतें, Cummunity Projects और Five-year Plan आदि बना रही है और हमारे Opposition वालों का सपीचिज़ (Speeches) करने का जो standard है उस से इन की लीडरी खत्म हो जायगी यानी यहां सारे मुल्क के अन्दर जितनी बीमारी और बेकारी है यह अगर दूर हो जाये तो इन लोगों का काम जो कि इसी बीमारी और बेकारी की दलदल से ही बना रह सकता है, किस तरह से चल सकेगा। इन को केवल इस बात की चिन्ता है कि यह दलदल बनी रहे। स्पीकर साहिब इस लिये यह Opposition वाले इस तरह की चीजें करते हैं। पहले यह कहते थे कि हमारे मिनिस्टर साहिबान शिमला की पहाड़ियों पर बैठे हैं इन को जनता के दुखसुख का क्या पता हो सकता है। अब जब कि हमारी गवर्नमैण्ट यहां आ गई है और हमारे वज़ीर साहिब लोगों से सम्पर्क बढ़ाने के लिये दूसरे जिलों में जाते हैं तो यह उन के दौरों पर एतराज़ करते हैं। स्पीकर साहिब, अगर यह प्रान्त में दौरे न करें तो अफसर अपनी मन मानी करने लग जायें। फिर जब चंडीगढ़ को जो Capital बनाया है, इस लिये कि जनता से contact हो सके और कि अफ़सर मन मानी न कर सकें और इस लिये भी कि वह लोग जो जनता को ग़लत रास्ते पर डालते हैं, ऐसा न कर सकें। इन बातों के पेशेनज़र हमारे मंत्री दौरा करते हैं। इस वक्त हमारा जो Administration है उस में आगे से बहुत improvement है।

वक्त बहुत थोड़ा है, इस लिये थोड़ी सी और बातें कहूंगी।

तहसीलों के जो सब-डवीजन बनने हैं, उन से ग्राम जनता, जो देहात में रहती है, उन की तकलीफों में कमी हो जायगी। फिर पी. ए. पी. के लिये ६४ लाख रुपये की रक्म रखी गई है और कहने वाले एतराज़ कर सकते हैं कि यह ज़्यादा है। मैं कहूंगी कि यह ज्यादा रक्म नहीं है। हमारा Border Province है। P. A. P. और इस की पुलिस की हमारी protection के लिये ज़रूरत है। इस के साथ मैं मनिस्टर साहिब से request करूंगी कि वह Central Government से कहें कि इसका share दे क्योंकि यह खर्च हमारे ज़िम्मे नहीं पड़ना चाहिये।

हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की यह बड़ी ख्वाहिश है कि हमारा प्रान्त एक Welfare State बने। जितनी यह feeling उन की है उतनी अफसरों की नहीं है उन के मन बदलने की ज़रूरत है। मैं यह नहीं कहती कि उन के पुराने ढंग हैं। पुराने ढंग बदल रहे हैं लेकिन नीचे के अफसरों के तरीके नहीं बदल रहे। मिनिस्टर साहिब आर्डर करते हैं मगर उन को implement तो नीचे के अफसरों ने ही करना हैं। नीचे के अफसरों, खास तौर पर P. W. D. के Overseers और S. D. O.s का व्यवहार पब्लिक और वर्करज़ के साथ ऐसा नहीं जैसा कि होना चाहिये, खास तौर पर जैसा कि एक Welfare State के लिये जरूरी है। चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा था कि सैक्रेटेरियेट (Secretariat) नया बन रहा है मैं कहती हूं कि मन भी नया होना चाहिये।

फिर भ्रष्टाचार, corruption को रोकने के लिये हमारी स्टेट में काफी प्रयत्न हो रहा है। भ्रष्टाचार नाशक कमेटी ने काफ़ी काम किया है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब keen हैं कि भ्रष्टाचार को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाये। मैं कहना चाहती हूं कि जो enquiries होती हैं वह departmental की बजाये High level के Non-officials के द्वारा होनी चाहियें। और जो फैसला हो जल्दी होना चाहिये। मैं समझती हूं कि जब कोई केस 2, 3 साल तक लटकता रहता है तो इस से फैसले की शान नहीं रहती।

जेलों के मुतअल्लिक बताया गया है कि हिसार और करनाल में जेलें बनाई जा रही हैं। जेलों में improvement की जरूरत है। जैसे prepartition दिनों में जेलों में बड़े २ प्रैस भी चलते थे ऐसे ही यहां भी कुछ होना चाहिये जिस से इन जेलों के लोग काम भी करें। और जनता और गवर्नमैण्ट का फायदा हो कहीं ऐसा न हो कि जब उन लोगों को हम जेलों से रिहा करें तो वे फिर डाके मारना शुरु कर दें। 6 साल हो गये हमें आज़ाद हुए हुए। Central जेल बन रही है, बड़ी अच्छी बात है लेकिन स्त्रियों के लिये कोई जेल नहीं बनी जैसी कि लाहौर में थी। जो political और Non-political औरतें कैदी होती हैं उन्हें काफी तकलीफ होती है। लुध्याना में मैं ने देखा कि औरतों को काफ़ी तकलीफ है।

फिर पासपोर्ट की बात है जो दूसरे देशों को जाने वालों को चाहिये। जालन्धर के लोग काफी तादाद में बाहर जाते हैं जिस के लिये पासपोर्ट लेने में काफी तकलीफ होती है। मैं गवर्नमैण्ट से प्रार्थना करना चाहती हूं कि वह ऐसा इंतज़ाम करे कि लोगों को महीना दो महीना

[श्रीमती सीता देवी]

में पासपोर्ट मिल जाये। इस के लिये लोग कभी जालन्धर कभी शिमला और कभी चंडीगढ़ मारे २ फिरते हैं। उन को खुद परेशानी होती है और वे हमें भी परेशान करते हैं।

फिर जालन्धर के लिये water works की बात है। जालन्धर एक semi-Capital है। इस के मुताल्लिक हमने और म्यूनिस्पेलिटी ने भी लिखा। मैं प्रार्थना करती हूं कि जालन्धर के लिये water-works ज़रूर होना चाहिये।

स्पीकर साहिब, मुझे अपनी बातें कहने की इजाज़त देने के लिये मैं आप का शुक्रिया अदा करती हूं।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੂਰਬੀ ਹਲਕਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ mutual compliments, party meetings ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ House ਦਾ ਸਮਾਂ debates ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇ।

ਸੱਚਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਭੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ administration ਵਿਚ interfere ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ੨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ subordinate staff ਅਪਨੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆਉਣ। ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ interfere ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ interference ਅਜਕਲ administration ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਭੀ ਮੈਂ ਇਕ concrete ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਤਨੇ ਕੇਸ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਤਨੀਆਂ convictions ਕਰੋ। (ਵਿਘਨ) ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸਟਰ ਲੇਮਿਅਰ ਸੀ। ਮਿਸਿਜ਼ ਲੇਮਿਅਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ 'you have killed my husband' ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਕੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਨ।

ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ administration ਨੂੰ second class ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਖੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ T. A. ਤੋ ਨਹੀਂ administration ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ I. C. S. ਦੇ 33 ਅਫਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ executive branch ਵਿਚ ਸਿਰਫ 11 serve ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ high percentage ਦਾ ਸੂਬੇ ਤੋ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪੂਰੀ encouragement ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ interference ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਂਹੀਦੀ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ interference ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਲੇਮ (claim) ਗ਼ਲਤ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Opposition ਵਾਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੌਰਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਕ omnibus ਦੇ ਅਡੇ ਦੀ opening ceremony ਕਰਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਦੌਰਾ ਹੈ ? ਬੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਭਾਲ ਕੇ ਦਸੇ ਕਿ ਜੋ ਦੌਰੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ misuse ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਦੌਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੌਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਫੇਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇਕ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਕਾਰਾਂ ਗਰਦ ਉਡੋਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ (speed) ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ । ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ (traffic) ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਦ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਮਿਹੀਨੇ ਫਰਵਰੀ 13 ਜਾਂ 12 ਨੂੰ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ (Grand Trunk Road) 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੀ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਗਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 10 ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ਖ਼ਰ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (transport) ਦੀ ਨੇਸ਼ਨੇਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ (nationalization) ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗਿਅਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਨ੍ਹਾਈ ਸੀ । ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ

[ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ]

ਨੈਸ਼ਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ corruption ਦੇ ਫੈਲਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਟ declare ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ by discussion ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਰੂਟ (routes) ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਰੂਟ declare ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ compensation ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ arbitration ਅਥਵਾ ਨਿਰਪਖ ਸਾਲਸ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਓਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਂਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੇਲੇ ਅਸਾਡੇ ਸਾਹਮਨੇ ਰਖਣ ਅਤੇ ਦਸੱਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਨੇਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਿਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਮੂ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਂਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਰਚ ਸੇਂਟਰ ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸੇਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੇਂਟ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿਸਾ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3-2 ਫੀ ਸਦੀ ਤਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਚਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਨਾਲ associate ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ totally disbelieve ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮੋਹਤਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਹਬੀ ਤੇ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ associate ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ disbelieve ਨਾ ਕਰਨ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ procedure ਵਲ ਆਉਂਦਾਂ ਹਾਂ। ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਨਾਕਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਡੇ ਤੋਂ ਵਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪਾਸ ਵੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਸ ਵੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਵਦਰਜਾ ਭੇਜੀ ੨ ਫਿਰਦੀ ਫਿਰਾਂਦੀ ਮੁੜ ਓਸੇ ਅਫਸਰ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਆਈ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਨਿਰਪਖ ਹੋ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ simple ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ procedure ਬਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਕਤਲਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।

श्री बिशना राम (नवां शहर): प्रधान जी, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 1946 से 1952 तक जो हालात पंजाब में रहे हैं और आज तक चले आ रहे हैं वह तकसीम के बाद कोई बदले नहीं। मेरे कुछ साथी जो तकसीम से पहले अंग्रेज अफसरों के साथ रह कर काम करते थे आज भी उसी तरह के लोगों से मिल कर नाजाइज़ कार्यवाही............

अध्यक्ष महोदय: चौधरी साहिब, आपने जो कुछ कहा है सुनाई नहीं दिया। आवाज़ बहुत कम है।

श्री बिशना राम: प्रधान जी, जिस समय पुराने साथी मिले हुए थे वह नाजाइज़ कार्यवाही करने पर मजबूर होते थे लेकिन अब गवर्नमैण्ट को चाहिये कि कोशिश करे कि कोई अफसर नजाइज़ कार्यवाई न करे।

चूंकि Opposition वाले कहते हैं कि एम. एल. एज़. सिफारशें करते हैं या वज़ीर साहिबान सिफारशें करते हैं इस लिये सरकार को चाहिये कि कानून के द्वारा ऐसी पाबन्दी लगा दे कि अदालतों में किसी को भी जाने की ज़रूरत न पड़े। (वकत की घंटी की आवाज़ सुनकर) श्रीमान् जी. मैं आगे तो कभी बोला ही नहीं और आज आपने मौका तो दिया है मगर आप बोलने नहीं देते।

अध्यक्ष महोदय: आप ने जो कुछ बोलना था। बोल लिया लेकिन सुनाई नहीं देता।

श्रम मंत्री: आप डट के बोलें।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, चौधरी सुन्दर सिंह आप की मदद करेंगे।

श्री बिशना राम: मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि अफसर बड़े आदमियों की बात सुनते हैं। आम तौर पर गरीब लोगों की सुनवाई नहीं होती। और अफसर भी गरीब लोगों की परवाह नहीं करते। इस खराबी को दूर करना चाहिये।

इस के बाद स्पीकर साहिब मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि Community Projects के अन्दर गवर्नमैण्ट ने बड़ी बड़ी स्कीमें रक्खी हैं। लेकिन इन स्कीमों में से हरिजन वैलफेयर फंडके लिये केवल $2\frac{1}{4}$ लाख रुपये की रकम रखी गई है। कम्यूनिटी प्राजैक्टों (Community Projects) का काम पौने दो साल से चल रहा है पर इन पौने दो सालों में पौने दो पैसे भी हरिजनों की भलाई के लिये नहीं खर्च किये गये।

फिर Industry वालों को उतनी रकम नहीं मिल रही है जितनी कि उन को मिलनी चाहिये।

एक बात और, प्रधान जी, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि गवर्नमैण्ट जो कर्ज़े दे रही है वे इतनी जल्दी और इस तरीके से तकसीम किये जायें कि दो महीने में ही कार्यवाही खत्म हो जाये। क्योंकि इन कर्ज़ों की रकम को सरकार ने अदा करना है। वज़ीर साहिबान ने अपनी जेबों में से नहीं देना है।

ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ (ਸਿਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ! ਇਸ demand ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ 64,00,000

[ਸਰਦਾਰ ਉਤਮ ਸਿੰਘ]

ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ Centre (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ) ਕੋਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਮੁਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਉਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਸੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ Opposition ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ Judiciary ਤੇ Executive ਨੂੰ ਅਲਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫੇਰ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ sub-division ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਨੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਫਤ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ।

ਫਿਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ crime ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੇਰ administration ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇ? ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ murder ਅਤੇ ਨਕਬਜ਼ਨੀ ਵਗ਼ੈਰਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਆਦਾਦੋਸ਼ੁਮਾਰ ਤੋਂ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾ ਸਾਧਾਰਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ administration ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਮਸਾਇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਮਵੇਸ਼ੀ ਵਗ਼ੈਰਾ ਚੁਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਹ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣਾ co-operation ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਬੰਦ ਬਨਾਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਵਡੇ ਬਚੇ, ਜਵਾਨ ਸਭ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਕ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤੀ।

ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ Budget Session ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਬਿਆਨਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਬਿਆਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਘਟਾਨਾਂ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲਿਆ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਈ items ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਖਿਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਵਲ opposition ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ, ਕਾਦੀਆਂ, ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ case ਚੂੰਕਿ

court ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ floor of the House ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਤਹਤ ਅਦਾਲਤ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡਾਰ (ਨੂਹ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ demand ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਰਾਯਾ $2\frac{1}{2}$ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ standard rent $12\frac{1}{2}$ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਉਤੇ ਜਿਤਨਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ Upper House ਦਾ ਖਰਚ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਹੈ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੇਰ ਜਨਾਬ, ਮੇਰਾ ਇਸ demand ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਤੇ ਓਸ ਬਾਰੇ inquiry ਕਰਾਉਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋਂ ਇਕ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ । ਬੀਬੀ ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਓਹਦੀ inquiry ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਇਸ demand ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਰਲੀਧਰ, ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਦੱਤ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕੀ ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਰਲੀਧਰ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ । ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ democratic ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ।

ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਸ demand ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੁਅਜ਼ਜ਼ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ 'C Class' ਵਿਚ ਰਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਇਸ demand ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ transport ਨੂੰ nationalise ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ route ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ nationalise ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਿਆ ਛਡ ਦਿਤਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ corruption ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ nationalisation ਵੀ ਇਸੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ corruption ਵਧੇਗੀ । ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ transport ਦੀ nationalisation ਨਾਲ 70 ਫੀ ਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ demand ਦੀ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

[ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲਗ਼ਨੀ ਡਾਰ]

ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅੰਬਾਲੇ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੁਪਿਆ ਕਿਤਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਲਿਓਂ ਇਸਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਿਆ ਵਰਤਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇ।

ਫੇਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ demand ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ administration ਵਿਚ redtapism ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ demand ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ technique ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Industrial Finance Corporation ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ Deputy Commissioners ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ Deputy Commissioner ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ Five-Year Plan ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨੀਆ ਕਮੇਟੀਆ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ group ਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਮਦੱਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨ ਦੇ compensation ਲਈ ਅਸੂਲ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਪਹਿਲੇ compensation ਬੁਢਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੂਲ ਬਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਕੀ ਕੈਦ ਕਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਟਬੰਦੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ (propaganda) ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Administration ਵਿਚ intervention ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਬੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ M.L.A. ਅਤੇ M.L.C. ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀਹ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਲ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਦੋ ਗਲਾਂ Personal explanation ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ Chief Minister ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨਹੀ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਨ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ Bombay Express ਦੇ ਡਬਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹਨ। (ਹਾਸਾ)

ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ Rape of Rawalpindi ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲੇ ਮਈ 1947 ਵਿਚ ਤੇ ਫੇਰ February 1948 ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਉ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਉਤੇ ਰਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੇਜ਼ ਉਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ reference ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਨਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਹਰ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਮੇਜ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ।

ਵਿਕਾਸ਼ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲਗਨੀ ਡਾਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ Chief Minister ਦੇ ਨਾਂ High Command ਵਲੋਂ ਚਿਠਿਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ Muslim Leaguers ਦੇ ਨਾਂ ਚਿਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾਂ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਰੱਬਾ ਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਤੋੜ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ।

ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ; ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ justify ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਰੱਬਾ-ਬੰਦੀ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਪਣੇ Professional ਕੰਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗਹਲੇਵਾਲ ਤੇ ਪੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀ। ਲੱਖਣਪੁਰ ਵਿਚ ਕਾਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਸਾਲਾ ਸੀ ਜਾ ਭੈਣੋਈ ਸੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ । ਮੈਂ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ । ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ (clients) ਦੀ ਇਹ request ਨਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਤੋੜ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ (appeal) ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇਹ ਵਖਰੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਰਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਮੁਰੱਬਾ-ਬੰਦੀ ਤੋੜ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਾਰੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ! ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ House ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਘਟੀਆਪਨ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

श्री सरूप सिंह (नरनौंद) : स्पीकर साहिब इस बहस में opposition के साथियों ने कई बातें कही हैं लेकिन एक भी constructive suggestion के तौर पर नहीं की। मैं कहूंगा कि अगर हमारी ministry और हकूमत के पिछले दो वर्षों के काम पर नज़र डाली जाये तो जहां तक General Administration का सम्बन्ध है कोई पंजाबी, हां Opposition के भाइयों को छोड़ कर यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि यहां बहुत improvement हुई है। मैं इस बारे में दो तीन मोटी २ मिसालें देनी चाहता हूं।

जहां तक decentralization of Administration यानी इनसाफ का सस्ता और जल्द मिलने का ताल्लुक है मेरे Opposition के भाई इस बारे में बहुत नुक्ताचीनी किया करते थे। जब यह असूल हमारी सरकार की तरफ से लागू किया गया तो पंजाब की जनता ने इसे बहुत सराहा क्योंकि इस से पंजाब की जनता को बहुत फायदा पहुंचता था। मैं इस सिलसिले में एक दो सुझाव मन्त्रिमंडल के सामने पेश करना चाहता हूं। जहां तक Administration की decentralization का ताल्लुक है इस सिलसिले में एक बड़ी मुश्किल हमारी पंचायतों को दरपेश है। स्पीकर साहिब, जितने इख्तियारात पंचों को दिये गये हैं उन के मुताबिक पंचों की तालीम बहुत थोड़ी है। इस लिये गवर्नमैण्ट को चाहिये कि सब से पहिले पंचों को तालीमयाफता बनाने का प्रबन्ध करे ताकि वह अपने अख़त्यारात का सही इसतेमाल कर सकें। Judiciary और Executive को अलहदा अलहदा करने के बारे में दस पन्दरह साल से पंजाब की जनता ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जनता मांग कर रही थी। पंजाब के लोगों की खुशकिस्मती है कि गवर्नमैण्ट ने इस असूल को पंजाब की administration में दाखिल कर दिया हैं। इस असूल को तजरुबे के तौर पर छ: जिलों में लागू कर दिया है। मैं चाहता हूं कि यह तरीका सारे पंजाब में लागू कर दिया जाये। इसी तरह पुलिस को Prosecution Branch से अलहदा कर देना चाहिये। जब तक पुलिस को Prosecution Branch से अलहदा नहीं किया जाता तब तक judiciary का Executive से अलहदा होने का फायदा पंजाब के लोगों को नहीं पहुंच सकता।

इसके इलावा हमारी सरकार के लिये यह बहुत ज़रूरी है कि administration को Overhaul किया जाये। Opposition के मैम्बरों की तरफ से कभी २ यह एतराज़ उठाया जाता है कि सरकार अमीर को ज्यादा अमीर और ग़रीब को ज्यादा ग़रीब बना रही है। इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूंगा कि अगर पिछले दो सालों के बजट पर निगाह डालें तो साफ तौर पर पता लगेगा कि हमारी सरकार इस फर्क को दूर करने के लिये काफी कोशिश कर रही है। सरकार इस मसले पर ग़ौर कर रही है कि किस तरह low-paid employees की तनखाहें बढ़ाई जायें और high-paid employees की तनखाहें कम की जायें। इस बारे में यह ठीक है कि जहां low-paid employees की तनखाहें बढ़ाने की तरफ सरकार ने अपनी तवज्जुह दी है वहां मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि जो

मुलाजिम अपनी Association बना कर सरकार पर दबाव डाल सकते हैं उन की आवाज सरकार तक आसानी से पहुंच सकती है और ऐसे मुलाजिमों की तनखाहें बढ़ाने की तरफ सरकार ने अपना ध्यान दिया है। लेकिन जहां तक पुलिस का ताल्लुक है सब-इन्स्पैक्टरों और इन्स्पैक्टरों की तनखाहें बहुत कम हैं। कानस्टेबल की तनखाह चालीस पचास रुपये माहवार और सब-इन्स्पैक्टर की तनखाह १२० रुपये माहवार है जो कि बहुत थोड़ी है। मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि वह अगले साल के बजट में इन मुलाजिमों का ख्याल रखेगी। जहां तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन (General Administration) का ताल्लुक है यह बात माननी पड़ेगी कि हमारी Administration एक top-heavy Administration है। इस बारे में मैं कहूंगा कि हमारी सरकार Administration को कम खर्च वाली administration नहीं बना सकी। District Headquarters और Secretariat में बहुत सा स्टाफ फालतू है। इस के इलावा महिकमा खेती बाड़ी में बहुत से इन्सपैक्टर काम कर रहे हैं और Co-operative Department में भी बहुत से इन्सपैक्टर ऐसे हैं जिन्हें बहुत कम काम करना पड़ता है। इस स्टाफ की काफी कमी की जा सकती है। मैं दो तीन बातें और कह कर बैठ जाता हूं।

Mr. Speaker : I would ask the hon. Member to wind up his Speech.

श्री सरूप सिंह : मैं इतना कह कर ही समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मुझे Irrigation Demand पर बोलने के लिये ज्यादा समय देंगे।

श्री चूनी लाल (रीवाड़ी) : स्पीकर साहिब! मैं आप की मेहरबानी का बहुत मश्कूर हूं कि आपने आज मुझे बोलने के लिये वक्त दिया है। मैं आप की विसातत से हाऊस के सामने एक दो सुझाव पेश करना जरूरी समझता हूं। स्पीकर साहिब मैं देखता हूं कि Opposition Benches पर जो मैम्बर बैठे हुए हैं वह हमेशा गवर्नमैण्ट की हर बात पर नुक्ताचीनी ही करते हैं। उन्होंने एक दस्तूर अपना लिया है कि गवर्नमैण्ट को criticise करना है। वे गवर्नमैण्ट बैंचों पर बैठे हुए मैम्बरों की न केवल किसी बुरी बात को बल्कि सभी अच्छी बातों को भी criticise करने लग जाते हैं। इस तरह से जनता यह समझने लग जाती है कि गवर्नमैण्ट को criticise करना इन लोगों की आदत में दाखिल हो गया है। आप को शायद दूसरी जमात की कहानी याद होगी जो कि एक गडरिया गांव वालों को शेर के आने की ग़लत बात कह कर बहकाया करता था एक दिन शेर के सचमुच आ जाने पर वह मारा गया और उसे बचाने के लिये कोई आदमी उस की मदद के लिये न गया। मैं समझता हूं कि इस किस्म की ग़लत बातें कह कर वह जनता का विश्वास खो रहे हैं। इस लिये यह जरूरी है कि वह अपना रवय्या तबदील करें ताकि State का फायदा हो और उन की बात में सच्चाई नज़र आने लगे।

स्पीकर साहिब! गवर्नमैण्ट की बड़ी खाहिश है कि Administration अच्छी हो और इस लिये उन्हों ने Executive को Judiciary से अलग कर दिया और सारे सूबे में पंचायतें फैला दी हैं। और सब-डिवीज़न बना दिये हैं। एक बात अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि जहां Sub-divisions बने हैं वह अभी तक महज़ कागजी कार्यवाई है। रीवाड़ी को भी Sub-division बनाया गया है। इस से पहिले इसे ज़िला

बनाने का ख्याल था क्योंकि यह जिले का सब से बड़ा शहर है जहां ५० हज़ार की आबादी है लेकिन पानी की कमी की वजह से इसे ज़िला नहीं बनाया जा सका। स्पीकर साहिब रीवाड़ी में भी पीने का पानी नहीं है। जैसा कि सब साहिबान ने कहा है कि यहां कई जगहों पर पीने का पानी नहीं मिल सकता। दूसरे ज़िलों में कालेज खोले जा रहे हैं, स्कूल खोले जा रहे हैं लेकिन रीवाड़ी शहर में लोग नमकीन पानी पीकर गुज़ारा कर रहे हैं। एक दफा माननीय मुख्य मंत्री वहां तशरीफ ले गये थे और जब उन्हें वहां एक गलास पानी का दिया गया तो वह एक घूंट भी न पी सके। मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे इलाके की तकलीफ को जरूर जल्दी दूर करने की कोशिश करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मैम्बर से कहूंगा कि वह अपना भाषण जल्दी समाप्त कर दें।

श्री चूनी लाल : स्पीकर साहिब ! दूसरे ज़िलों में सरकार कालेज खोल रही है, स्कूल खोल रही है सड़कें बना रही है लेकिन मेरे इलाके में पीने का पानी भी नहीं मिल सकता। हमारे सरकारी अस्पताल में मरीज़ों को पीने का पानी नसीब नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मैम्बर से फिर कहूंगा कि वह अपना भाषण जल्द समाप्त करें।

श्री चूनी लाल : अध्यक्ष महोदय ! मैं Backward District का रहने वाला हूं इस लिये मैं आप से गुज़ारिश करूंगा कि मुझे ज्यादा वक्त दिया जाये। इस के इलावा मैं गवर्नमैण्ट का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि दो साल से मेम्बरान इस बात की मांग कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव जल्दी कराये जायें। मेरी समझ में नहीं आता कि गवर्नमैण्ट ऐसा क्यों नहीं कर रही। पहली Election को हुए बहुत साल हो गये हैं और इस अर्सा में नौजवान मैम्बर बूढ़े हो गये हैं। इन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में Nepotism और favouritism चल रही है। मेरे जिले में तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के teachers को तीन तीन महीनों के बाद तनखाह मिलती है और वह भी एक महीने की।

इस के बाद वे बेचारे कई महीनों तक मारे मारे फिरते हैं। आज तक उन को पिछले महीनों की तनखाहें नहीं मिली हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह का ज़ुल्म सरकार कैसे बरदाश्त करती है।

(At this stage, the bell rang indicating that the time of the hon Member was over)

Shri Chuni Lal : One minute more, please.

Mr. Speaker : Please resume your seat.

श्री तेरा राम (खूइयां सरवर) : श्रीमान् प्रधान जी ! हमारे देश में एक पुरानी कहावत है, 'यथा राजा तथा प्रजा' प्राचीन काल में हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी ऐसा ही होता था। पुराने वक्तों में जैसा राजा होता था वैसी प्रजा होती थी। यदि राजा अच्छा होता था तो प्रजा अच्छी होती थी और यदि राजा में नुक्स होते थे तो प्रजा में भी बुराइयां ... आज कहावत है, "यथा प्रजा तथा राजा", क्योंकि ... आज कहावत इस के उलट है। ... राजा बनता था परन्तु आज कल

ballot box के पेट से निकलता है वह हुकूमत चलाता है। मेरा मतलब यह है कि असेम्बलियों तथा पार्लियामेंट के सदस्य जिन्हें बैलट बक्स में अपना वोट डाल कर लोग चुनते हैं आजकल हकूमत करते हैं। इस लिये जैसी प्रजा होगी वैसे राजे हकूमत चलाने वाले होंगे। आज यहां पर शासन पर बहस करते हुए विरोधी पक्ष के सदस्यों ने कहा है कि सरकार अच्छी नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बात हम सब पर लागू होती है। यदि हम हकूमत को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें अच्छे काम करने होंगे।

अध्यक्ष महोदय : Demand पर बात कीजिये। general व्याख्यान न कीजिये।

श्री तेरा राम : अगर हम चाहते हैं कि शासन में सुधार हो तो हमें एक आदर्श लोगों के सामने रखना चाहिये। हिंदुस्तान में सैंकड़ों सालों की अंग्रेज़ की गुलामी के कारण लोगों की आर्थिक, शारीरिक, नैतिक तथा सामाजिक हालत बहुत खराब हो गई थी हिंदुस्तान सब बातों में नीचे गिर गया है। सैकड़ों सालों का बिगड़ा हुआ खेल दो चार सालों में ठीक नहीं होगा। यह हम जानते हैं कि लोगों को बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु हमारा यह कर्तव्य है कि जो अच्छा काम सरकार ने किया है उस की सराहना करें और जो बाकी रह गया है उस के लिये सुझाव पेश करें और उस के बारे में मांग की जाये।

श्री रिज़क राम (राए) : साहिबे सदर, General Administration पर आज दो रोज़ से बहस हो रही है। इस के बारे में Opposition की तरफ से एक साथी ने यह ठीक तौर पर कहा था कि administration का रौशन पहलू यह है कि आम लोगों में हकूमत के बारे में विश्वास पैदा हो। अब देखना यह है कि आया इस साल के बजट में ऐसी बातें मिलती हैं जिन से यह सही तौर पर अंदाज़ा लग सके कि सरकार वाकई इस बात की खाहशमंद है कि लोगों में सरकार के बारे में और सरकार की machinery के बारे में एतमाद पैदा हो। इस सिलसिले में सब से पहले मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि देश में अमनो अमान की हालत अच्छी होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में Opposition की तरफ से कई बातें कही गई हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रोहतक ज़िले के हालात का बहस के दौरान में बहुत चर्चा हुआ है और वहां हालात अच्छे न थे। परन्तु सरकार की और इस की machinery की कोशिशों से अब वहां अमन कायम हो गया है। Opposition ने बताया है कि इन कोशिशों के कारण कुछ मफ़रूर आदमी मारे गये। हकीकत यह है कि उस ज़िले की ९० फी सदी आबादी सरकार की मशकूर है इस लिये कि इस ने ज़िले से गुंडागरदी को खत्म कर दिया है और आज ग़रीब लोग सुख का सांस लेते हैं। यह सरकार की बड़ी कामयाबी है।

इस बात पर काफी बहस हो चुकी है कि सरकार की तरफ से उस ज़िले में सख्ती हुई है। मैं इस सम्बन्ध में ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं जहां तक ज़िला रोहतक का सम्बन्ध है वहां के ऐसे हालात थे कि एक अरसे से वहां एक पार्टी बनी हुई थी जिस में बड़े बड़े आदमी शामिल थे जो कतल करते थे और डाके डालते थे। इस position की वजह से उन लोगों का देहात में रोब था और लोग उन से डर कर मफ़रूरों को पनाह देते थे। उन आदमियों की इज्ज़त होती थी लोग उन से डरते थे। जो उन को नाराज़ कर बैठते थे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता था। इस लिये देहात में उन

[श्री रिजक राम]
लोगों का दबदबा था जो खुल्लमखुल्ला कतल करते थे या कतल करने वालों को पनाह देते थे। मैं समझता हूं कि काफ़ी अरसा अंग्रेज़ का राज्य रहा और फिर यूनियनिस्ट (Unionist) सरकार का दौर रहा। मगर कोई सरकार या सरकार की machinery उन ताकतों से टक्कर न ले सकी। हम सच्चर साहिब की इस हकूमत को बधाई देते हैं कि इस ने इस गुंडागरदी का चैलिंज मनज़ूर करते हुए घबराहट महसूस नहीं की। वहां पर कोई मामूली हालात नहीं थे। हालात इस कदर ख़तरनाक थे कि किसी अफ़सर की क्या मजाल थी कि उस गरोह का मुकाबला करे। नौबत यहां तक पहुंच गई थी कि कुछ वकील या दूसरे आदमी भी जो पबलिक life में ममताज़ थे, गरोहबन्दी में हिस्सा लेते थे।

स्पीकर साहिब, जब पुलिस ने कुछ सर्गरमी दिखाई, तो ज़रूरी था कि उन लोगों में जिन्होंने अड्डे बनाये हुए थे और public life में महज़ इसी वजह से position हासिल की हुई थी बुखलाहट पैदा हो। चुनांचि उन्होंने शोर मचाया। यह एक स्वाभाविक बात थी आज फिर आप के सामने दो गांवों का ज़िक्र आया है और औरतों के सम्बन्ध में ऐसी वैसी बातें कही गई हैं। जो बहस House में इस वक्त तक हो चुकी है, मेरे ख्याल में उसे सुन कर आप को और बहुत सारे मैम्बर साहिबान को यकीन हो गया होगा कि यह बातें वैसे ही कही गई हैं। इन की सदाकत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पचास साठ गांवों में से जहां पुलिस की सरगर्मियां हुई हैं सिर्फ इन दो villages को ही single out किया गया है। मौज़ा राबड़ा में हेम राज और उस के साथियों ने एक रात सब घरों की तलाशी ली क्योंकि वे एक आदमी को कत्ल करना चाहते थे। इतफाक से वह आदमी उन को उस रात न मिला। इस के बाद एक आदमी ने हेम राज की गोद में अपने लड़के को दिया था और उस ने कसम खाई थी कि अगर हेम राज लाचार हो गया तो वह हेम राज के अधूरे काम को पूरा करेगा। वह लड़का एक कत्ल के case में गिरफ्तार हो चुका है। मुकद्दमा sub judice है और तफ्तीश हो रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन गांवों के लोगों की ओर से जिन के १०, १५ आदमियों की पंचायत ने एक लड़के को हेम राज का मुतबन्ना बनाया हो तो फिर हमें राज और उस के साथियों पर आपत्ति आ जाने की सूरत में क्या २ "अन-होई" बातें नहीं कही जा सकती।

जागसी के मुतल्लिक सब जानते हैं कि राम सिंह के मारे जाने से पहले वहां पर किसी किसम की चर्चा नहीं थी।

१९ जनवरी को राम सिंह और उस का एक साथी मारा गया. हेम राज बच निकला मगर दो तीन मफ़रूर पकड़ लिये गये। इस वाकिया के दो तीन दिन बाद जागसी के मुतल्लिक ज़िक्र आना शुरु हुआ कि वहां पर पुलिस ने ज्यादतियां की हैं। जागसी में हेम राज की दो बहनें बियाही हुई हैं और राम सिंह के कई रिशतेदार भी रहते हैं। अगर वहां के कुछ लोगों ने पुलिस पर इलजाम लगाये हैं तो यह कोई हैरानी की बात नहीं है। वहां के दस पन्दरह आदमी तो उन के रिशतेदार हैं। सरकार ने गुंडागरदी के challenge को meet करने में और कातिलों के gang को तोड़ने में जो हिम्मत दिखाई है, ज़िला रोहतक की तमाम आबादी उस के लिये इस की मशकूर है।

श्री रणजीत सिंह कैप्टन (हिसार सदर) : जनाब स्पीकर साहिब ! आज आप के सामने हमारी पार्टी के साथियों और मुखालिफ पार्टी के साथियों ने भी General Administration पर बहस की है। Governor के address पर भी आम तौर पर इसी विषय पर बहस होती रही। कौन नहीं जानता कि आज जनता में जो जागृति पाई जाती है वह कांग्रेस की वजह से है ? (तालियां) आज हर शख्स अपने ख्यालात का इज़हार कर सकता है। आज हमारे विकास मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वह यह कि हम इनसान हैं, गलती कर सकते हैं। उन का अपनी कमज़ोरियों का एतराफ करना एक काबिले तारीफ बात है।

यह रोहतक का सिलसिला पांच, सात रोज़ से चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि अपनी तकरीर में मुख्य मंत्री जी जरूर पूछेंगे कि Opposition वाले कैसी enquiry मांगते हैं। चाहे उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर भी बातें कही हैं, हम उस Government के नुमाईंदें हैं जिस की नीव महात्मा गांधी के राम राज्य के असूलों पर रखी गई है। श्री राम चन्द्र जी ने इनसाफ के सामने अपनी धर्म-पत्नी को भी मुआफ नहीं किया था और अपने राज्य की नेकनामी के लिये उन्हें जंगलों में भेज दिया था। जैसी कार्यवाहियां allege की गई हैं, ऐसी कार्यवाहियों की कोई superior police officer आज्ञा नहीं दे सकता। मैं भी अगर रोहतक का नहीं तो कम अज़ कम उस के आस पास के ज़िलों में से एक जिले का रहने वाला हूं। वहां पर इस तरह की पुलिस की ज्यादतियों की आम चर्चा हो रही है। हमारे साथी कहते हैं कि यह गलत है, मुखालिफ धड़े के आदमी कहते है कि ऐसी चीज़ें हुई हैं। उन को भी लोग interested कह सकते हैं और हम को भी। मैं इस बात को मानता हूं कि एक फोड़े को दूर करने के लिये चीर-फाड़ करनी ही पड़ती है, मवाद को दबा २ कर निकालना ही पड़ता है। जब तक ऐसा न किया जाये कोई फोड़ा अच्छा नहीं हो सकता। अगर किसी आदमी के साथ ज्यादती हो गई हो तो कोई खास बात नहीं है मगर इस case में तो कई देवियों का ज़िक्र आया है, हमारे सन्यासी स्वामी स्वतन्त्रानंद जी जैसों ने enquiry की है और ब्यानात दिये हैं। मैं समझता हूं कि इन हालात में मैं Government की यह duty है कि वह हाऊस को यकीन दिलाये कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। हमारे मुख्य मंत्री जी का word ही काफी है। अगर वह इतना ही कह दें कि 'मैं हाऊस को यकीन दिलाता हूं कि अगर किसी शख्स ने किसी बहिन के साथ कोई ज्यादती की है, तो वह इनसाफ के पंजे से बच कर नहीं जायेगा।' तो यह enquiry के बराबर होगा। अगर इस से भी लोगों की तसल्ली न हो तो मेरे ख्याल में हम उन के doubts का कोई इलाज नहीं कर सकते।

श्री लाल चंद प्रार्थी (कुल्लू) : स्पीकर साहिब, General Admnistration पर इस कदर बहस हो चुकी है कि मेरे लिये ज्यादा कहने की गुंजायश नहीं रही। Opposition के दोस्तों ने बड़े तुमतराक से जो बातें कही थीं, उन के जवाबात दिये जा चुके हैं। मैं इन दोस्तों को सुनाने के लिये एक दो verses पढ़ना चाहता हूं। इन verses में वह सब कुछ आ जाता है जो मैं उन से कहना चाहता हूं।

[श्री लाल चन्द प्रार्थी]

यह सुर्ख सूरज से कह दे कोई कि अपनी किरनों को गिन के रख ले।
मैं अपने सेहरा के ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं।
मेरा तखय्यल, मेरे इरादे करेंगे फितरत पे हुकमरानी,
जहां फरिश्तों के पर हैं लर्ज़ां, मैं उस बुलन्दी पे जा रहा हूं।

यह उस पंजाब का पैग़ाम है जो हमारी और उन की आंखों के सामने तामीर हो रहा है। अगर हमारे दोस्तों के suggestions तामीरी हों तो उन पर विचार किया जा सकता है वरना वे अपनी सुर्ख किरनों को गिन कर रख लें, हम अपने सेहरा के ज़रें २ को चमकना सिखा देंगे।

जहां तक General Administration का सम्बन्ध है, हमारा राज्य नुमायां तरक्की कर रहा है। हो सकता है कि कहीं २ कुछ कमजोरियां बाकी हों मगर न इनसान मुकम्मल पैदा हुआ है और न ही हर चीज़ की तकमील इस के अपने हाथ में है। इनसान से ग़लतियों का होना ऐन मुमकिन है। सरकार के पास अल्ला-दीन का चिराग नहीं है कि वह सब खामियों को एक दिन में दूर कर के नये पंजाब की इमारत को मुकम्मल कर सके।

स्पीकर साहिब, इस सिलसिले में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इन थोड़ी सी कमज़ोरियों के लिये सारे अफसरों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हां किसी, अफसर में कहीं खामी ज़रूर है। मिसाल के तौर पर वे कमजोरियां ये हैं: सरकार ने पब्लिक रिलेशन्ज़ कमेटियां (Public Relations Committees) बना रखी हैं, Grow-More-Food के सम्बन्ध में कमेटियां बनाई हुई हैं, और (Co-ordination Board) इन कमेटियों की कभी २ घंटा आधा घंटा मीटिंगें करती हैं लेकिन जो रचनात्मक काम इन को करना चाहिये वे नहीं कर रहीं, जनता और सरकार में जो तालमेल बढ़ना चाहिये वह नहीं बढ़ रहा है। इस लिये मैं यह बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि उसे इन चन्द बुराइयों को दूर करना चाहिये और जो लोग ज़िले में at the helm of affairs हैं उन्हें सरकार की पालिसी चलाने में ज्यादा हुश्यिार होना चाहिये। स्पीकर साहिब हमारा ज़िला एक पहाड़ी ज़िला है। बेशुमार जंगलात हैं और उन में जंगली जानवर जो फसलों को बरबाद कर देते हैं। पिछली बार सच्चर साहिब कांगड़े तशरीफ लाये तो उन के सामने भी लोगों की यह कठिनाई रखी गई कि किसानों को हिफाज़त, ज़रायत के लाईसेंस नहीं मिल रहे हैं। सच्चर साहिब ने इस सिलसिले में (डिप्टी कमिश्नर को सुविधाएं देने की आज्ञा दी लेकिन बावजूद इन की आज्ञा के आज तक उस पर अमल नहीं हुआ है) बल्कि लाईसेंस ज़ब्त किये गये हैं।

Administration के सिलसिले में मैं दूसरी अर्ज़ यह करूंगा कि जो रुपया हमीरपुर और देहरा तहसील के लोगों को Finance Relief Fund के रूप में देने के लिये स्वीकार हुआ था वह अभी तक अदा नहीं किया गया। लोगों को इस रुपये की इतनी ज़रूरत थी कि जो ब्यान नहीं की जा सकती लेकिन हैरानी की बात है Relief का रुपया जो उन लोगों को जिन्होंने पालमपुर थडिमार सड़क पर काम किया उस कष्ट के समय नहीं मिला जबकि वहां कहत पड़ा हुआ था और अभी कितने महीने गुज़र गये हैं। आज तक वह

रुपया लोगों को मिला नहीं जिस से उन को बहुत कठिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इन हालात में मैं अर्ज़ करूंगा कि सरकार को इस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिये और जिले की Administration को सुधारना चाहिये। अन्त में मैं आप के द्वारा Finance Minister साहिब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस लिये कि मेरे इलाके को विकास के लिये कोई रक्म इस बजट में नहीं रखी गई। केवल १०,००० रुपये की मामुली रक्म इस के लिये रक्खी गई है। यह रक्म लोगों की Horticulture Station के सिलसिले में acquire की गई ज़मीन की कीमत है। इस के इलावा जो ज़मींदारों को देनी है। और कोई पैसा उन गरीब लोगों की सहायता के लिये नहीं रखा गया यह बहुत निराशाजनक है।

हज़ार शुक्र कि मायूस कर दिया तूने,
यह और बात है तुझ से बड़ी उमीदें थीं।

श्री कसतूरी लाल गोयल (असन्ध) : स्पीकर साहिब, यह मेरा पहला मौका है कि मैं असैम्बली के २ साल के समय में मैं हाऊस में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। पेश्तर उस के कि मैं मौजूदा निज़ाम की कुछ तारीफ करूं मैं चाहता हूं कि सरकार जिस तरह से पिछड़ी हुई जातियों का ध्यान रखती है उसी तरह इसे पिछड़े हुए इलाकों का भी ध्यान रखना चाहिये यह आवश्यक है कि जिस प्रकार बजट में पिछड़ी हुई जातियों के लिये Provision किया जाता है उसी प्रकार पिछड़े हुए इलाकों के लिये भी कुछ होना चाहिये। लेकिन पंजाब सरकार के राज्य में यह चीज़ नहीं हो रही। इस सिलसिले में मैं कई एक मिसालें पेश कर सकता हूं। अमृतसर में बटाला-बयास सड़क पर खर्च करने के लिये ७ लाख रुपया मंज़ूर किया गया है जिस में से ३ लाख इसी साल खर्च किया जायगा। ज़िला जालन्धर में रानीताल-ज्वालामुखी सड़क के लिये २० लाख रुपया मंजूर किया जिस में से ५ लाख इसी साल खर्च होगा। एक और टांडा-श्रीगोविन्दपुर-उधो नंगल सड़क के लिये २५ लाख रुपया रखा गया है जिस में से १२ लाख इसी साल खर्च किया जायेगा। दूसरी तरफ हमारे ज़िला करनाल में देखिये एक सड़क पानीपत से असन्ध तक ऐसी ही सड़क बनाने के लिये १५ लाख रुपये तक रखे गए हैं जिन में से २॥ लाख रुपये इसी साल खर्च होने हैं। और २॥ लाख अगले साल खर्च होंगे, इस तरह यह सड़क छः साल में पूरी होगी पांच साल तक तो इसे अपने इलाके की सड़क नहीं कह सकते। लेकिन मेरी constituency की सड़कों पर वही मिसाल आती है कि जब बिमार खत्म हो जायगा तो फिर डाक्टर पहुंचेगा। अर्थात् जब कच्ची सड़क की हालत बहुत ही खराब हो जायगी तो सरकार का ध्यान उस तरफ जायेगा।

स्पीकर साहिब, इस के इलावा मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि वर्तमान निज़ाम अमीरों और बड़े २ जमींदारों का ही है इसे गरीबों का निज़ाम नहीं कह सकते। इस निज़ाम में गरीबों और मुज़ारों पर नाकाबिले ब्यान जुल्म हो रहे हैं खास कर थाना राजोंद के हरिजनों और मुज़ारों पर मसलन मौज़ा फटवाल और सतोकमाजरा के मुज़ारों पर अगर वे बिचारे तंग आ कर अफसरों के पास कभी जाते हैं तो अफसर उन की शक्ल तक देखना पसन्द नहीं करते। उन को कहते हैं कि तुम लोग आधी ज़मीन लेकर फैसला नहीं करते तो दफा हो जाओ। यहां तक कि उन को जगह २ पर धमकाया जाता है और नफ़रत की निगाह से देखा

[श्री कसतूरी लाल गोयल]

जाता है । यही हाल हरिजनों का है । गांव पोपड़ा, थाना राजोंद में १६ घर हरिजनों के पुलिस ने उजाड़ दिये हैं जो कि मैदान में पड़े हैं उन की झोंपड़ियां गिराई गई हैं जिन की यह तसवीरें मेरे पास हैं। उन के पास घर भी नहीं हैं और उन के बाल बच्चे बाहर रुलते फिरते हैं उन की बुरी हालत हो रही है। इस असैम्बली में और मौजूदा निज़ाम में तो यह हालत है—

न तड़पने की इजाज़त है न फर्याद की है,
घुट के मर जाऊं यह मर्ज़ी मेरे सैयाद की है ।

स्पीकर साहिब, मेरी समझ में नहीं आता कि हरयाना के ज़िलों को क्यों उपेक्षित किया जा रहा है ? एक बार एक पठान और एक शेख कहीं सफर को जा रहे थे। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ कर वे खाना खाने लगे । शेख के पास बाजरे की मोटी मोटी रोटियां थीं लेकिन फिर भी खाने के समय उस ने खुदा का शुक्र किया । पठान के पास कोर्मा और गंदम की रोटी थी लेकिन उस ने जब यह देखा कि शेख बाजरे की रोटियों पर खुदा का शुक्र कर रहा है तो वह बिगड़ कर बोला कि तुम लोगों ने खुदा का दिमाग खराब कर दिया है अगर तुम लोग बाजरे की रोटियों पर ही उस का शुक्र गुज़ारते हो तो हमें कोर्मा और पिलाओ कैसे मिलेंगे । तो स्पीकर साहिब मेरे कहने का मतलब यह है जो मैम्बर बगैर कुछ मिले ही वज़ीरों की तारीफ और शुक्र करते हैं उन्होंने वज़ीरों का दिमाग खराब कर दिया है (हरयाना को उन से कुछ मिलने वाला नहीं) कि जहां तक मेरे ज़िले का ताल्लुक है जो लोग यह बात कहते हैं कि मौजूदा निज़ाम के वक्त में उस ने तरक्की की है वे गल्त ब्यानी करते हैं और एक तरह से वज़ीरों के साथ दुश्मनी करते हैं वे उन को सही बात नहीं बताते । मैं अपने आप के वज़ीरों का सच्चा साथी समझता हूं जो कि सही बातें बता रहा हूं ताकि वह अंधेरे में न रहें । Finance Minister साहिब से यह भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि बतायें कि पंजाब के १२६ हलकों में अलहदा २ क्या २ खर्च हुआ है । अगर constituency में इसी प्रकार से रुपया खर्च होता रहा है तो मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि Haryana प्रान्त के मैम्बरों का हाल बंगाल के मुस्लिम लीग के मैम्बरों जैसा होगा लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि हरयाने के लोग अपने मेम्बरों से उन से यह ज़रूर पूछेंगे कि क्या तुमने कभी बजट के पोथों को खोल कर भी देखा है कि नहीं ? या आप लोग ३०० रुपये लेते रहें और मौजें करते रहें । तो मैं उन से यह अर्ज़ करना चाहता हूं के वज़ीर खजाना को Haryana प्रान्त के लोगों के लिये कुछ रकम रखवा कर अपने कर्तव्य परायणता का सबूत देना चाहिये ।

Mr. Speaker: Now the Chief Minister will reply to the criticism.

मुख्य मंत्री (श्री भीम सेन सच्चर) : स्पीकर साहिब, पेश्तर इस के कि मैं उन में से किसी एक प्वाएंट (point) का जो कि opposition की तरफ से या किसी और तरफ से उठाए गये हैं, जवाब दूं, मैं यह वाज़ह कर देनाचाहता हूं कि मैं अपनी तकरीर को एक वकील की तकरीरर नहीं बनाना चाहता । मैं जहां तक समझता हूं कि गवर्नमैण्ट को चलाने का सही रास्ता क्या है और उस के लिये क्या करने की ज़रूरत है सिर्फ इसी हद तक जाऊंगा ।

मैं मानता हूं, स्पीकर साहिब, इस बात को कि पंजाब आज के दिन वह नहीं है जो कि हम असल में देखना चाहते हैं। यह जाहिर है कि अगर आज का पंजाब वही पंजाब हो जाए जो कि हम चाहते हैं और जो कि चन्द सालों के बाद होगा, तो फिर शिकायत ही क्या है ? शिकायत हो ही नहीं सकती। ताहम्, स्पीकर साहिब, यह एक खुली बात है कि आज जो हालात हैं, उनमें बहुत कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है। हमारे सूबे में इस वक्त डाकू हैं, चोर हैं, रिश्वतखोर हैं--रिश्वत देने वाले हैं, रिश्वत लेने वाले हैं। कोई मुहज्ज़ब तरीके से रिश्वत लेता है और कोई किसी और ढंग से लेना चाहता है। यह सारी चीज़ एक सही चीज़ है और मैं इसे कबूल करता हूं। लेकिन, स्पीकर साहिब, जब मैं यह कहता हूं तो इस के साथ यह भी कह देना चाहता हूं कि इन चीज़ों का होना इस बात की कोई सफाई नहीं कि गवर्नमैंट इसको खत्म करने की कोशिश नहीं करती। इन चीज़ों को मौजूदा वजूद पंजाब में हमारे किसी फ़ेल या अमल की सफ़ाई में पेश किया जा सकता है। लेकिन, स्पीकर साहिब, अगर यह चीज़ें हमारी Administration में अब भी उस हद तक पाई जाती हों कि हमारे इस एवान के साथी महसूस करते हैं तो मैं खुले तौर पर अपने आप को आप के सामने पेश करता हूं और तैयार हूं इस बात के लिये कि इस हाऊस की एक कमेटी आफ़ प्रिविलेजिज़ (Committee of Privileges) उन तमाम कामों को देखे जो कि हम कर रहे हैं। क्यों ? स्पीकर साहिब, यह मैं इस लिये कह रहा हूं कि मेरा हर काम मेरा हर फेअल, मेरी हर बात जो है, वह मेरी ज़ाती बात नहीं रह जाती बल्कि वह इस हाऊस की शान और ताकत का इज़हार करती है। मैं Constitutional procedure में नहीं जाना चाहता कि आया मैं किसी ऐसी कमेटी के सामने पेश हो सकता हूं या नहीं। मगर स्पीकर साहिब, कुछ और बात कहने से पहले मैं यह पेशकश करता हूं और आप से दरखास्त करता हूं कि आप बेशक मेरी इस पेशकश को मानते हुए इस हाऊस की एक Committee of Privileges बना दें जो कि यह देखे कि Administration को चलाने के लिये जिन उसूलों को वहां सही समझती है या जिन उसूलों की सराहना इस हाऊस में की जाती है आया यह मनिस्ट्री उन को अमली जामा पहनाती है या नहीं।

आखिर, स्पीकर साहिब Administration हो कैसी ? सीधीसादी बात है। Administration का सीधा ताल्लुक है उस नीति से जो कि वज़ारत बनाती है। Administration का ताल्लुक है वज़ीरों के फेअलों से और उन के कामों से। Administration का ताल्लुक है उन अफ़सरों से जो कि वज़ारत की पालिसी को आगे चलाने के लिये होते हैं। इस लिये सवाल अब यह है कि वह नीति-वह पालिसी--हमारी क्या है ? वह यह कि हम अपने नज़मोनसक को किस तरह चलाते हैं ? आया हम सिफ़ारिशें सुनते हैं या नहीं ? आया हम अफ़सरों की राय से इत्तफ़ाक करते हैं या नहीं ? आया अफ़सरों से मिल कर अपना कोई ज़ाती काम करते हैं या नहीं ? आया कमिशनज़ के उन मैम्बरों पर, जिन की हम हर रोज़ दुहाई देते हैं और जिन्हें हम ने अपने हाथों से तमाम ताकत को छोड़ कर उन के हवाले कर दिया, influence exercise करते हैं या नहीं ? जब हम कदम कदम पर यह वाज़ेया करते हैं कि उन कमिशंज़ के मैम्बरों की independence और integrity unquestionable है तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि अगर इन कमिशंज़ और उन के ऐसे ईमानदार मैम्बर मुकरर करने के बाद भी मैं या मेरा

[मुख्य मंत्री]

कोई साथी किसी back door method से उन लोगों पर असर डालता है तो मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं, स्पीकर साहिब, कि हम इन बैंचों पर बैठने के लायक नहीं (*cheers*) मैं इस बात को ज़ोर से इस लिये कहता हूं कि रोज़ेरौशन की तरह दुनिया जानती है कि आज हमारी Public Service Commission और Subordinate Services Selection Board जिन ताकत और शान से पंजाब का सिर ऊंचा कर रहे हैं, वह पंजाब ही के credit में जाता है (*cheers*) स्पीकर साहिब, आप खुद ही अंदाज़ा लगायें, खुद ही ख्याल करें कि आया वह कौन सी बात थी जो कि मेरे इस रास्ते में रुकावट डालती थी कि मैं ऐसे बोर्ड को मुकर्रर न करूं ? कोई ऐसी रुकावट न थी। तो फिर कौनसी ऐसी चीज़ थी जो मुझे मजबूर कर सकती थी कि मैं सूबे में Subordinate Services Selection Board मुकरर करूं ? Constitution में ऐसा कोई provision नहीं। यहां तक कि इस किसम की Services के लिये, जिन के चुनने के लिये यह बोर्ड मुकरर किया गया है, सारे हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा बोर्ड नहीं। मुल्क भर में इस की कोई मिसाल नहीं मिलती। स्पीकर साहिब, ऐसा होता और हम उस को follow न करते और हमारे साथी यह दलीलें देते कि फुलां जगह में ऐसी body कायम है––क्यों नहीं इसे पंजाब में भी Constitute किया जाता––तो फिर तो वाक़ई हम पीछे रह जाते। लेकिन ऐसा कहीं और जगह पर नहीं है। तो फिर क्यों हमने यह सभी इख्तियारात भी अपने हाथों से खो कर एक Independent body के हाथों में सौंपे ? यह इस लिये कि हम ईमान्दारी के साथ यह चाहते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा Confidence लोगों का––आम जनता का–– Administration में हो सकता है वह हो। स्पीकर साहिब, मैं वाज़िया तौर पर यह बता देना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात में यकीन रखते हैं कि अगर हम सर्विसिज़ (Services) का Confidence हासिल नहीं करते तो सूबे की Administration चल ही नहीं सकती। इस लिये, इस हुकूमत की पालिसी ही यही है कि सर्विसिज़ को पूरी तरह Confidence में किया जाये। लेकिन सर्विसिज़ के Confidence में लेने का मतलब यह नहीं कि शायद बाज़ भाई यह समझे कि जो कुछ उन के दिल में आये वे करते जाएं। या दूसरे इलफ़ाज़ में यह कि उन को कोई पूछने वाला ही न हो। तो, जनाब स्पीकर साहिब, यह बात नहीं है। उन्हें Confidence में लेने का मतलब यह है और जो हरेक अच्छा पब्लिक सर्वेंट (public servant) चाहता है कि उन को अपनी राए का इज़हार करने की आज़ादी हो। उसे इजाज़त दी जाये कि वह बग़ैर किसी डर के अपने विचारों को ज़ाहिर कर सके। उस के इलावा वे खुद भी कुछ नहीं चाहते। स्पीकर साहिब, मैं बिला खौफ़े तरदीद यह कह सकता हूं कि हमारे अफ़सर खुद इतने अच्छे और responsible है कि उन की किसी मामले पर ज़ाती राए कुछ भी क्यों न हो, वे तब तक उसे ज़ाहिर नहीं करते जब तक कि उन्हें ऐसा करने की इजाज़त न दी जाए। स्पीकर साहिब, मुझे यह कहने में भी गुरेज़ नहीं कि पालिसी बना कर execute करने में हम खुद भूल कर दें तो कर दें लेकिन सर्विसिज़ उसे हमेशा strictly implement करती हैं। इस लिये उन को Confidence में लेना पड़ता है। लेकिन स्पीकर साहिब ! Confidence में लेने का मतलब यह

भी नहीं कि सर्विसिज़ के बारे में हम एक general policy बनालें : इस तरह तो हरेक आदमी आ कर यह पूछेगा कि साहिब आप ने यह क्या किया ? स्पीकर साहिब, अच्छा तो मालूम नहीं देता लेकिन अगर आप मुझे मुआफ करें तो मैं एक चीज़ मिसाल के तौर पर आप के सामने रखना चाहता हूं। गो ऐसी बात का ज़िक्र मेरा यहां करना ठीक नहीं, फिर भी चूंकि Administration का ताल्लुक है मैं आप को यह बता ही देना चाहता हूं। चंद ही दिन हुए---शायद दो चार दिन का मामला है---मेरे एक दोस्त हैं वह अपने एक लड़के को साथ लेकर मेरे पास आये। Civil Supplies Department में वह लडका काम करता था। मैंने पूछा क्या बात है ? क्या तुम retrench हो गये हो ? इस लिये कोई शिकायत है किसी के खिलाफ़ ? स्पीकर साहिब, मुझे बड़ी खुशी हुई यह बात सुनकर कि एक ऐसा आदमी जो कि retrenchment में आ गया है और जो Jobless है यह कहता है कि मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं कि मेरी छांटी क्यों हुई। उस ने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं क्योंकि मेरी retrenchment भी कायदे कानून, और उसूल के मुताबिक हुई है (*Hear, hear*)

फिर स्पीकर साहिब, आप जानते हैं और आप का तजरुबा भी वसीह है कि Promotions के बारे में रियायत का ख्याल चल रहा है कि कुछ आदमियों को नीचे से ऊपर कर दिया जाता है क्योंकि वह अच्छा काम करते हैं वह होता तो ठीक है लेकिन मैं इस से घबराता हूं कि कहीं किसी के साथ बेइनसाफी न हो जाये और इस इख्तियार का गलत इस्तेमाल न किया जाये। इस लिये हमने यह अखतिआर Public Services Commission और Subordinate Services Selection Board के हवाले कर दिया है। इस के लिये चाहे कोई कायदा नहीं या कोई कानून नहीं था जो गवर्नमेंट को ऐसा करने पर मजबूर करता लेकिन बावजूद इस बात के हमारी मनिस्ट्री ने यह कर दिया है कि अगर किसी अफसर को प्रोमोट (promote) किया जाता है उस से Senior अफ़सरों को supersede कर के तो उन सारी मिसलों के साथ उन सारे आदमियों की Personal Files भी भेजी जायें जिन को supersede किया गया है ताकि Public Service Commission देख सके कि किसी के साथ बेइनसाफी तो नहीं की गई। स्पीकर साहिब, इस तरह से मैंने और मेरे साथियों ने जितनी भी promotions देने की ताकतें हमारे हाथ थीं वे सारी की सारी Public Service Commission और Selection Board को सौंप दी गई हैं फिर स्पीकर साहिब मेरी मनिस्ट्री Public Service Commission और Subordinate Services Selection Board की सिफारशों को हर सूरत में मानती है और कभी भी एक केस नहीं हुआ जिस को गवर्नमैण्ट ने reject कर दिया हो (तालियां)।

यहां से स्पीकर साहिब आपको यह सुनकर खुशी होगी कि उस दिन इत्तफ़ाक से मुझे Chairman, Subordinate Services Commission मिल गये और मैं ने उन से पूछा कि यह जो इस हाऊस के अन्दर इस बात की नुक्ताचीनी चल रही है कि हमारे कुछ मैम्बर साहिबान और वज़ीर साहिबान आप के पास सिफारशें करते हैं क्या यह ठीक बात है।

[मुख्य मंत्री]
तो उन्हों ने कहा कि किसी वज़ीर या मैम्बर ने कभी हमारे पास पहुंचने की कोशिश नहीं की। यह बात आप दरयाफत कर सकते हैं।

फिर स्पीकर साहिब ! यह कहा गया है कि हमारी तरफ से अफसरों को दबाया जाता है और उन्हें दबा कर कुछ काम करने के लिये कहा जाता है। मैं इस सिलसिले में इतना ही अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि हमारे पुराने साथी जो Opposition में बैठते हैं वह हमें यह कहा करते थे कि हमने अपने हाथों में कोई ताकत नहीं रखी हुई है और हम ने तो उन को सिर चढ़ा रखा है और वह हमारी मानते ही नहीं। उन की बात से यह स्पष्ट होता है कि हमारे इशारे पर चलने वाले नहीं है। जब हालत यह हो तो फिर यह शिकायत किस तरह की हुई। इस लिये मैं आप की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि Services में सब से पहली चीज़ जो होनी चाहिये वह यह है कि Services की साख ऊंची हो और यह साख ऊंची रखने के लिये एक ही चीज़ की ज़रूरत है और वह है कि हम हर ईमानदार अफसर को इमानदारी और आज़ादी से काम करने दें। स्पीकर साहिब आप को खुशी होगी कि हम उन्हें यह आज़ादी दे रहे हैं। इस के साथ ही मैं हाऊस को इस बात की तसल्ली करा देना चाहता हूं कि मैंने अफसरों से कहा है और जो मेरे साथी हैं उन्होंने भी उन्हें यह हिदायत दे दी है कि देखिये इस लोक राज्य के समय में लोगों ने आप के पास आना है आप का यह फर्ज है कि आप हमदर्दी से उन की बातें सुने और उन का काम करने की कोशिश करें। और अगर आप के पास कोई ऐसी दरखास्त आती है जो नाजायज़ हो तो आप ऐसी बात करने से इनकार कर दें और ऐसा करने में अगर ज़रूरत समझें तो साफ़ कह दें कि हमारे चीफ़ मनिस्टर नहीं मानते। जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो यह कैसे कहते हैं कि हम अफसरों पर दबाव डाल कर काम लेते हैं। दूसरी चीज़ जो हम Services से हटाना चाहते हैं वह है Corruption हम चाहते हैं कि उन की Integrity कायम रहे क्योंकि मेरा विश्वास है कि यह Services ही हैं जो हिंदुस्तान के शासन को बना सकती हैं या बरबाद कर सकती हैं। यह देश को बचाने और बिगाड़ने की instrument हो सकती है। वह पंजाब को बनाना चाहें तो बना सकती हैं और बिगाड़ना चाहें तो बिगाड़ सकती हैं।

फिर स्पीकर साहिब अगर कोई अच्छा काम करता है तो उस की इज्ज़त होनी चाहिये, उस का पूरा मान किया जाना चाहिये और उस की सराहना करनी चाहिये। अगर यह बात हो तो झगड़ा किस बात का हो।

फिर स्पीकर साहिब ! यह कहते हैं कि हमारी गवर्नमैण्ट कितनी नालायक है कि चीफ़ सैक्रेटरी और कुछ थोड़े आदमियों को छोड़ कर बाकी तमाम के तमाम अच्छा काम करने वाले जो senior आदमी थे वे गवर्नमेंट आफ इंडिया में चले गए हैं। उन्हें केंद्रीय सरकार ने मांग लिया है। मेरे दोस्त यह बात महसूस नहीं करते कि इस में भी हमारे पंजाब का सैर ऊंचा होता है कि इस की सर्विसिज़ (Services) इतनी अच्छी हैं कि उनकी मांग बाहर भी बड़ी है।

वह हमारी सर्विसिज़ के आदमी ही हैं जो Government of India में Aircraft का General Manager का काम बड़ी खुश उसलूबी से कर रहे हैं। फिर स्पीकर साहिब आप को इल्म है कि हमारे एक Senior अफसर जिन का नाम है श्री B. R. Tandon उन को गवर्नमैण्ट आफ़ इंडिया में भेजने के लिये मैंने कोशिश की थी ताकि वह वहां किसी और जगह पर लग सकें क्योंकि हाउस ने यह खाहिश जाहिर की थी कि यहां दो Financial Commissioners नहीं होने चाहियें। यहां केवल एक Financial Commissioner होना चाहिये। मैं हाऊस को बता दूं कि जब Tandon Sahib पटियाले में थे तो यहां वापस आने से घबराते थे कि अगर वह यहां आ गये तो उन्हें नुक्सान पहुंचेगा। लेकिन फिर भी टंडन साहिब को बुला लिया गया था। सच्ची बात तो यह है कि उन्हें वहां से बुला कर फिर Financial Commissioner के ओहदे से हटाने में मुझे अपनी ज़बान से वापस जाना पड़ता था। लेकिन हाऊस की राये की कदर करते हुए उस के इस मुतालबे की कदर करते हुए कि जो बड़ी २ posts हैं उन को कम किया जाए, मैंने डाक्टर काटजू से कहा कि मैं चाहता हूं कि टंडन साहिब को कोई केंद्र में जगह दे कर लगा लिया जाये। स्पीकर साहिब, आप को यह बात जान कर खुशी होगी कि जब कि पास डायरैक्टर जनरल आफ़ सिविल सप्लाईज़ ऐंड परचेजिज़ की जगह खाली हुई तो मैंने अपने मित्र सरदार स्वर्ण सिंह जी से जो सैण्टर में मिनिस्टर हैं, मुतालबा किया कि कोई जगह हमारे पंजाब के आदमी को दे दें। तो उन्होंने हमारी यह बात मान ली। स्पीकर साहिब, मेरी और मेरे साथियों की यह policy रही है कि हम पंजाब से गवर्नमैण्ट आफ़ इंडिया या हिमाचल प्रदेश या पटियाला को अच्छे २ अफ़सर भेजें। हम यह चीजें किसी खास गर्ज़ या खास नीयत से नहीं कर रहे हैं।

फिर माननीय स्पीकर साहिब, हमारे लीडर आफ दी आपोज़ीशन ने फरमाया है कि minorities के साथ यहां सख़्ती होती है। तो क्या मैं उन से पूंछ सकता हूं कि minorities के साथ सखती होती है इस लिये कह रहे हैं कि उन के खेत लह लहा रहे हैं। क्या उनके साथ सख्ती इस लिये हुई वह कहते हैं कि उन के नौजवान हमारी फौज की शान को बढ़ाए हुए हैं या इस लिये हुई है कि उन के बच्चे खुले तौर से स्कूलों और कालिजों में पढ़ते हैं। वह कहते हैं कि माईनारिटीज़ (minorities) को हम Services के नज़दीक फटकने नहीं देते। मैं उन्हें यह बता दूं कि Recruitment to Services हम अपने पास नहीं रखते इसी तरह promotions भी हम ने अपने हाथों में नहीं रखीं। उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जिन से गलत फहमी पैदा हो सके लेकिन मैं इस गल्तफहमी को दूर करना चाहता हूं। मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि यहां पर minorities से कितनी ज्यादती हो रही है और यहां minorities को किस तरह निकाल बाहर फैंका गया है उन तक किसी की नज़र तक न पहुंच सके।

लीजिये मैं पुलिस के महिकमा के बारे में आंकड़े पेश करता हूं।

[मुख्य मंत्री]

		Majority	*Minority*
I.G. Police	..	1	..
D.I.G.	..	3	4
S.Ps.	..	25	15
A.S.Ps.	..	7	4

(एक Scheduled Caste का मैम्बर भी है)

D.S.P.	..	45	31

और मैं, स्पीकर साहिब, आप के ज़रिये Leader of the Opposition को बता दूं कि यह ६० और ४० फी सदी बनता है। इन आंकड़ों को झुटलाया नहीं जा सकता। आखिर हम करें तो क्या करें। स्पीकर साहिब मुशकिल यह है कि जो कुछ Leader of the Opposition कहें उस की कदरोकीमत होती है। अब यह figures देखिये:—

		Minority Community	*Majority Community*
D.C.	..	4	9
S.D.O.	..	4	4
A.D.M.	..	4	8
Magistrates	..	35	40
Settlement Officers	..	5	6
Revenue Assistants	..	6	9
Miscellaneous	..	21	33

Commissioners, Financial Commissioner, Secretaries, Chief Secretary, etc.

यह जो नक्शा मैं ने रखा है आप के सामने, यह बतलाने के लिये कि कितना ज़ुल्म हो रहा है minorities से। क्या minorities को दबाया जा रहा है इसलिये कि Director of Industries हैं minority के, Director of Land Records हैं minority के और फिर Development Secretary हैं minority के। ठीक बहुत दबाया जा रहा है। हमारे बाज़ दोस्त हैं जो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, पंजाब को किधर ले जा रहे हैं? मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं कि मुझे किसी public scrutiny के सामने खड़ा कर दिया जाये। अगर एक भी appointment ऐसी हो जो इनसाफ पर न की गई हो तो जो सज़ा देना चाहें हमें दें।

अगर Opposition वालों की तकरीरों को सुनें तो यूं समझ पड़ता है कि सूबे में राज्य दफा १४४ का है, detention का है। यह स्वाल चूंकि बड़ा ज़रूरी है, इस

लिये इस के मुतल्लिक कुछ कहना चाहता हूं। सूबे में दफा १४४ तीन दफा लगाई गई। यह उस वक्त लगाई गई जब कुछ लोग ने जो अपने तरीके को बेहतर समझते हों, लेकिन जिसे कोई समझदार आदमी ठीक नहीं समझ सकता, ऐसा काम करना चाहा जिस से काशमीर हिंदुस्तान से हमेशा के लिये अलग हो जाता। प्रजा परिषद की कोशिश यह थी कि पंजाब को Jumping ground बनाया जाये, पैसा खर्च करें, भर्ती करें, और जम्मू में मोर्चा लगाया जाये। पंजाब गवर्नमैण्ट इस की इजाज़त नहीं दे सकती थी। यह काम November 1952 में शुरु हुआ और हम ने मजबूर हो कर February 1953 में पाबन्दी आयद की; और यह कब तक आयद रही? यह उसी वक्त हटा दी गई जब उन्होंने agitation, call off कर ली। दूसरा मौका आया तब जब अकाली दोस्तों ने agitation कर के पंजाब में गड़बड़ डालने की कोशिश की। पहले तो हमने यह सोचा कि आदमी आये जाये या अपने ख्यालात का इज़हार करे तो हमें क्या एतराज हो सकता है। मगर बाद में जब हम ने देखा कि 'मतलबे साअ्दी दीगर अस्त' तो कानून का एहतराम करवाने के लिये पाबन्दी लगानी पड़ी और ज्योंही उन्होंने फरमाया कि मामला खत्म है, तो हम ने भी दफा १४४ खत्म कर दी। तीसरी बार दफा १४४ आयद करने का मौका फिर पैदा कर दिया। क्या कहूं स्पीकर साहिब, वक्त मेरे पास इतना नहीं कि सब चीज़ें पूरी तरह ब्यान करूं। एक पार्टी के बड़े मुअज़िज़ भाई ने कहा:—

"The trouble started when the tenants of the village made an effort to plough the land which they had been cultivating in the past and which was recently brought under cultivation by absentee landlord..........Before taking this step, the tenants also applied for the correction of Girdawari records but their applications were rejected.

As soon as it rained, the tenants attempted to plough the land which was about 3,000 bighas. The landlord in consultation with Shri Ram Dayal, General Secretary of the Punjab Congress Committee—now a Congress candidate for the by-election......lodged reports in the Police Station. The police proceeded to the village immediately, surrounded it and made, indiscriminate arrests." Further he said—
"I personally think that they did not violate the law and even if they did so from the point of social justice they had a right to do it."

स्पीकर साहिब! जब इन लोगों की यह ज़हनीयत हो जाए कि कानून हो या न हो वे तो जो उन की मरज़ी में आयगा वही करेंगे। और जिस तरह जी में आयगा कानून की खिलाफवर्ज़ी करेंगे, तो मैं आप के ज़रीए लेकिन बड़ी नम्रता के साथ साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि अगर कोई आदमी या पार्टी कानून का उलंघन करेगी तो उस को कानून की गिरफ्तारी में ले लिया जायगा चाहे वह आदमी कांग्रेसी हो, या मैम्बर असेम्बली, वज़ीर या कोई और। (तालियां)।

यह गवर्नमैण्ट, स्पीकर साहिब घबराये किस से? कानून को तोड़ने वालों से? अगर ऐसा हो तो कानून एक मज़ाक बन जायगा। हमें बताया गया है कि किसान आ रहे हैं कानून को तोड़ने के लिये। एक हज़ार आ रहे हैं दो हज़ार आ रहे हैं। २ हज़ार हों या पांच हज़ार हो हम इन नम्बरों से डरने वाले नहीं। हम तो इन्हीं numbers में से निकले हैं। इन्हीं demonstrations में से ऊपर उठे हैं फिर हम इन से क्यों घबराएं।

[मुख्य मंत्री]

हमें, स्पीकर साहिब बताया गया कि एक हज़ार किसान नहीं बल्कि दो हज़ार आ रहे हैं हम ने कहा कि आने दो ।

चश्मे रोशन दिले माशाद, इन के लिये दरियां बिछा दो । धूप में आये हैं इन को पानी वानी पिला दो । यह ज़रा आराम करें हम खुद इन में जायेंगे और इन की तकलीफों को सुनेंगे ।

हम घबराने वाले नहीं । घबराहट अगर है तो एक है, वह यह कि जब तक हमारे दोस्त तुशद्दद की हद तक नहीं जाते और लोगों को इस तरफ नहीं ले जाते, तब तक हमें इन पर कोई एतराज़ नहीं । वह जलसे करें, डरामे करें procession निकालें, जो मर्ज़ी है करें । उन को ख्याल की कैद नहीं होगी, क्योंकि हम कहते हैं कि Democracy है तो Democracy तब तक नहीं हो सकती जब तक ख्याल की कैद हो । (तालियां) ।

स्पीकर साहिब, हमें कहा गया है कि हम जुल्म करते हैं । हम क्या जुल्म करते हैं ? देखिये साहिब दफा १४४ लगा दी गई है । लोगों को पकड़ा जाता है। स्पीकर साहिब, हम उन लोगों को पकड़ते हैं जो मुकाबला में आते हैं और कहते हैं कि हम हकूमत का सर कुचल देंगे । उन लोगों को पकड़ते हैं जो यह कहते हैं कि हम फुलां फुलां की लाशों पर अपना घर बनायेंगे, जो तुशद्दद पर उतर आते हैं । मैं यह बातें अपने आप ही नहीं कह रहा । जब मैं बोलता हूं तो साथी मैम्बरों को ही नहीं बल्कि सारे पंजाब के लोगों को अपनी पुश्त पर समझता हूं । (तालियां) ।

फिर स्पीकर साहिब यह मुझे लाठियों की याद दिलाते हैं । हम लाठियां अपनी मर्ज़ी से नहीं चलाते हैं । कानून हमें ऐसा करने की इजाज़त देता है तो चलाते हैं । अगर लोगों ने तुशद्दद करने से गुरेज न किया तो लाठियां चलेंगी'। फिर अगर लाठियां चलाता हूं तो इस लिये कि हाऊस ने मुझे यह ताकत दी है । कानून भी ताकत देता है । मैं फिर स्पष्ट तौर पर कह दूं कि अगर कोई कानून की हदूद से तजावीज़ करता है तो लाठियां चलाई जाती हैं । (*Interruptions*) ।

Mr. Speaker: Order, please.

मुख्य मंत्री: स्पीकर साहिब, देखिये क्या साईंस के जमाना में भी मुझे याद दिलाने की ज़रूरत है कि—

'Prevention is better than cure' (Repeated interruptions).

अध्यक्ष महोदय : जब मेम्बर बोलते हैं तो मनिस्टर आराम से सुनते रहते हैं । इस लिये अब आप भी interrupt न करें और सुनें ।

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, एक और मामला है जो अब subjudice हो गया है कि रोहतक में लोगों को पकड़ लिया गया है । जो लोग रोहतक में पकड़ लिये गये हैं उनमें दो तीन एम. एल. एज. भी थे जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया था । तो स्पीकर साहिब इन लोगों को क्यों पकड़ा गया है ? इस लिये कि इन्होंने जगह जगह पर कारनामे किये हैं ।

श्री वधावा राम : जो कारनामे बताए जा रहे हैं वे ग़लत हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप interrupt न करें दूबारा (*interruptions*).

Mr. Speaker : You must keep quiet.

ਸਰਦਾਰ ਚਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਧੂਤ : ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਵਧਾਵਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਪ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮਨਿਸਟਰ ਅਸਾਨੂੰ unduly interrupt ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤੇ ਟੋਕੀਏ ਤਾਂ ਆਪ ਅਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਪ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ walk out ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।

Mr. Speaker: That is your job.

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके जब मनिस्टर बोल रहे हों तो interrupt न करें, कल फिर मौका मिलेगा आप जवाब दे सकते हैं।

श्री किदार नाथ सहगल : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि चौधरी लहरी सिंह तो हमें हमेशा interrupt करते हैं।

Mr. Speaker: Order, please.

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब ! मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमें १४४ दफा लगानी पड़ती है, Detention Act लागू करना पड़ता है। क्यों क्या हम इसे चाहते हैं ? नहीं। लेकिन हमारे भाई इसे चाहते हैं।

स्पीकर साहिब, फिरोज़पुर में क्या हुआ है ? लोगों ने कहा कि ज़मीन नहीं छोड़नी, जान देनी है।

फिर इस के बाद जगसी में क्या हुआ ? 8th February को आग बरसाने वाली तकरीरें की गई। अब अगर आग लगाई जाये और यह कहा जाये कि धूआं न उठे, आग लगाई जाए और कहा जाये कि शोले न उठें। यह कैसे हो सकता है। मेरे भाइयों ने आग लगाई और वह आग भड़क उठी। तीन दिन बाद पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस के आदमी ज़ख्मी हुए। एक नंबरदार को चोटें आईं। इस लिये जब आप कहते हैं कि Preventive Detention Act लागू न किया जाये, दफा १४४ न लगाई जाये तो क्या यह सब कुछ वाक्यात की बिना पर कहते हैं। अगर हालात आप ऐसे बना देंगे तो हमें उन हालात के मुताबिक कार्रवाई करनी होती है।

स्पीकर साहिब यह जो कहा गया है कि हम पर १४४ दफा की मदद से हकूमत कर रहे हैं बिल्कुल बेमानी बात है। हमें तो ऐसा करने पर मजबूर किया जाता है।

फिर स्पीकर साहिब ! जिस जगह पर यह कहा जाये कि यहां तो बड़े डाके पड़ते हैं, लूट मार हो रही है, यह हो रहा है वह हो रहा है तो मैं कहता हूं कि अगर कोई देखने की ताकत रखता हो और फिर न देखे तो उस की मर्ज़ी। Figures होते हुए भी वह अगर आंखें बन्द कर ले तो मैं क्या कर सकता हूं। डकैतियों के बारे में मैं figures देता हूं।

[मुख्य मंत्री]

Year	No. of dacoities committed
1950	85
1951	78
1952	49
1953	40

The monthly average number of dacoities during the year 1953 was 3.3 against an average of 8 per month during the pre-partition period of 1942 to 1946.

स्पीकर साहिब, आप यह कहेंगे कि मैं यह pre-partition days के figures क्यों दे रहा हूं। यह इस लिये कि मेरे बाज़ मोअज़िज़ दोस्त मुझे कहते हैं कि तुम्हारे राज्य से अंग्रेज़ का राज्य अच्छा था। ठीक है, उस वक्त हालात बहुत अच्छे थे और अब बिगड़ गये हैं क्योंकि उस वक्त जहां 8 per cent dacoity cases थे वहां अब 3.3 per cent रह गए हैं।

स्पीकर साहिब ! क्या मैं इस बात से खुश हूं कि झगड़े हों, क्या मैं इस बात से खुश हूं कि राम सिंह मारा गया या क्या मैं इस बात से खुश हूं कि चन्दर पकड़ा गया। या मैं इस बात से खुश हूं कि हथयार पकड़े गये, पिस्तौल पकड़े गये और आदमी पकड़े गये। नहीं, मैं इन वाक्यात से खुश नहीं। मुझे तो रंज है कि पंजाब के अन्दर इस तरह के लोग हैं जो गंदे और ग़लत रास्तों पर चलते हैं और पकड़े जाते हैं।

हमारा नज़रिया, हमारा मकसद, हमारी मनज़िल और है। मैं यह तो नहीं कहता कि मेरी और आप की मनज़िल में फ़रक है। हां बाज़ औकात मजबूरी और मसलिहत की वजह से दिल की बात कहने की जगह कई भाइयों को कुछ और कहना पड़ता है। ख़ैर स्पीकर साहिब ! जनवरी की crime report यह है। वक्त तंग है इस लिये मैं यही बता देना काफी समझता हूं कि जनवरी 1954 में crimes की तादाद 2,374 थी और जनवरी 1953 में 2,593 जिस का मतलब यह है कि एक साल में 219 की कमी हो गई। (*Hear, hear*)।

In all, 2,374 cases were registered during January, 1954 as against 2,593 cases registered in January, 1953.

लेकिन आप यह न समझें कि इस से मेरी तसल्ली हो गई है। मैं तो हैरान हूं बल्कि मुझे अफसोस है कि इतने जराइम भी क्यों हैं। मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि हम इन को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं। लेकिन वह सिर्फ पुलिस की मदद से कम नहीं हो सकते बल्कि यह आप के तआवुन और आप की मदद से ख़त्म होंगे।

फिर अर्ज़ यह है कि आप पुलिस को बेशक बुरा कहें और जितना चाहें कोसें लेकिन उस के जो काराए नुमायां हैं वे किसी से पोशीदा नहीं हैं। मैं सिर्फ फिरोज़पुर का ज़िक्र करता

हूं। वहां एक truck जाता था एक डाकू उस पर चढ़ गया और बनोलों की आठ दस बोरियां नीचे फेंक दीं। अब स्पीकर साहिब आप मुलाहज़ा फरमायें कि सुबह ३ बजे रिपोर्ट पहुंचती है और Superintendent of Police उसी वक्त चल देता है और २२ मील की मनजिल तय कर के माल जा पकड़ता है और उस को गिरफ्तार कर लेता है। इसी तरह गुड़गांव में एक Inter-provincial gang था वह भी पकड़ लिया गया। मेरे एक दोस्त ने कहा कि लुधियाने में दिन दिहाड़े डाका पड़ा। बेशक डाका पड़ा। हम शर्म महसूस करते हैं कि डाका पड़ा। असल में तो शर्म यह काम करने वालों को होनी चाहिये मगर हमें भी अफसोस है। ताहम हमारी पुलिस ने भी हाथ पर सरसों जमाकर दिखलाई। उसने उन सब को पकड़ लिया और दिन रात एक करके माल बरामद भी करा लिया। मेरे दोस्त कहते हैं कि हम पुलिस से बहुत दुखी हैं। स्पीकर साहिब, मैं आप की वसातत से उन को एक पेशकश करता हूं। वह जिस इलाके का चाहें इंतज़ाम सम्भाल लें। मैं वहां से पुलिस हटा लेता हूं। यह पुलिस striking farse के तोर पर तो कायम रहेगी लेकिन वह जहां चाहें इंतजाम संभाल लें (*Hear, hear*)। आईए यह आज़माइश करके देख लीजिये।

फिर कहा गया लोगों का उतसाह मर गया है और अफसर तआवुन नहीं करते। मैं अर्ज़ करता हूं कि हमारे Community Projects लोगों के उत्साह और इरादों की तरजमानी कर रहे हैं। सड़कें, बन्द, drain वगैरा बन रहे हैं। अगर लोगों में उत्साह नहीं है तो फिर क्या यह सब कुछ आप ने बनाया है ?

फिर अफसरों पर इलज़ाम लगाया गया है कि वह लोगों को तंग करते हैं। मैं अर्ज़ करता हूं कि मैं हर एक अफसर से तवक्को रखता हूं कि सूबे की भलाई के लिये दिन रात एक कर दे और इस के लिये अपना सारा influence इस्तेमाल करे। सिर्फ यह बात है कि वह influence किसी को नुकसान पहुंचाने वाला न हो।

एक साहिब ने कहा है कि वज़ीर चंदे लेते हैं। इस के मुतअल्लिक मैं खुले लफ्जों में कहना चाहता हूं कि हम सब से पहले public men हैं और मनिस्टर बाद में हैं। हम Public men होने के बाइस वज़ीर बने हैं। वज़ीर होने की वजह से public men नहीं बने। हमें यतीमखाने, स्कूल आदि खोलने और पब्लिक भलाई के बहुत से काम करने हैं। उन के लिये हम को पैसा दरकार है। अभी पिछले दिन गवर्नर साहिब के address में कहा गया है कि सरकार ने ३ लाख रुपया कौमी शहीदों के लिये रखा है मगर लोगों की तरफ से काफी response नहीं। बस हम ऐसे कामों के लिये ज़रूर चंदे लेंगे और लेते रहेंगे। देखना यह है कि वह चंदा मेरी जेब में न जाये। अगर मैं खराबी करूं तो एक पैसे की खराबी के लिये करोड़ लानत डालिये।

फिर कहा गया कि वज़ीर अपनी position का फायदा उठाते हैं। मैं अर्ज़ करता हूं कि जो लोग मेम्बर नहीं हैं वह आप के बारे में यही कहते हैं कि आप मेम्बरी का असर डालते हैं। मगर इस का सही test यह है कि वह असर लोगों की भलाई के लिये इस्तेमाल किया जाए।

[मुख्य मंत्री]

एक दोस्त ने कहा है की अगवा की वारदातों का जिक्र नहीं किया जाता क्योंकि इन को शर्म आती है। बात यह है कि इन की नज़र उसी चीज़ पर पड़ती है जो अखबारों में छपती है। एक बदकिसमती की बात है जिस पर मैं आप के जरिये Press की बड़े अदब से तवज्जुह दिलाना चाहता हूं। जहां जरायम का पता लगाना हो वहां छुप छुप के काम करना पड़ता है। मगर यहां वह बात आठ आठ दस दस बार पहले दूसरे पांचवे और आठवें सफे पर छाप कर उन लोगों को खबरदार कर देते हैं कि हुशियार रहो। मैं अर्ज़ करता हूं कि इस से जुरम करने वालों को फाइदा होता है और हमारे ज़िम्मेदार Press को जुर्म करने वालों की नहीं उन को पकड़ने वालों की मदद करनी चाहिये। खैर अगवा शुदा औरतों के बारे में यह अर्ज़ है कि १९५१ में १२० वारदातें हुई जिन मे से ११४ बरामद कर ली गई। १९५२ में ११४ में से १०५ और १९५३ में १०८ में से १०० औरतें आप के पंजाब की इस निकम्मी और नालायक पुलिस ने बरामद कीं (*Hear, hear*)।

जहां तक kidnapped children का सम्बन्ध है मुझे इस बात का दुःख है कि यहां पर बच्चों को kidnap किया जाता है लेकिन करें तो क्या करें। हमारे समाज की यह हालत है कि यहां कई ऐसे निरदई और बेरहम आदमी हैं जो छोटे छोटे बच्चों पर अपना हाथ साफ़ करते हैं। १९५१ में १२८ बच्चे kidnap हुए और इस निकम्मी पुलिस ने ११५ recover किये। १९५२ में १३३ kidnap हुए और ११६ recover किये गये। १९५३ में १७२ में से १४८ recover हुए। कुल ४३३ में से ३७९ बच्चों को recover किया गया। स्पीकर साहिब, मुझे उन बच्चों का बहुत दुःख है जो वापस नहीं लाये जा सके। लेकिन यह नहीं कि यह बच्चे इस लिये न मिल सके कि Police इन को recover न करना चाहती थी। यह इस लिये वापस न आ सके कि कई भाई जो उन के recover करने में मदद दे सकते थे उन्होंने सहायता नहीं दी। आखिर वह बच्चे उड़ कर आसमान पर तो नहीं चले गये।

स्पीकर साहिब ! मेरे दोस्त कहते हैं कि यह Police बहुत नालायक और निकम्मी है और इस पर बहुत ज्यादा खर्च आ रहा है। परन्तु एक तरफ तो यह कहा जाता है कि Scotland Yard बन जाये और दूसरी तरफ यह सुनने में आता है कि खर्च न हो। यह कैसे हो सकता है। लेकिन मैं अपने दोस्तों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम सब कुछ करेंगे मगर पैसा चाहिये। जगाधरी जिला अम्बाला के बच्चों के न मिलने का मुझे बहुत रंज है। लेकिन उन का न मिलना कोई बहुत अचम्भे की बात नहीं। स्पीकर साहिब आप को याद होगा शिमला में rail-motor पर हमला हुआ था। अंग्रेज़ का वक्त था और बहुत ज्यादा efficiency थी। परन्तु दो साल से ज्यादा अर्सा सुराग लगाने में लगा था। मैं यहां पर यह बता देना उचित समझता हूं कि मैं आम तौर पर किसी ऐसी दरखास्त को नहीं मानता जिस में यह कहा जाये कि फलां अफ़सर को फलां जगह पर लगाया जाये। परन्तु यहां जगाधरी वाले मामले में मैं भी ढीला पड़ गया। मेरे पास लड़कियों के बाप ने आ कर कहा कि अगर एक खास police officer को तफ़तीश पर न लगाया गया तो उस के दिल में एक हसरत

रह जायगी। मैंने उन से कहा कि अगर उस police officer के लगाने से उन की तसल्ली हो सकती है तो मैं उसे ही लगा देता हूं। यह मैंने इस लिये किया था कि लड़कियों के बाप के दिल में यह हसरत न रह जाये कि पूरी तफ़तीश नहीं की गई।

मेरे दोस्तों ने रोहतक ज़िले का हवाला देते हुए कहा है कि हम inquiry से घबराते क्यों हैं और inquiry क्यों नहीं करवाते। मुझे समझ नहीं आती उनका मतलब क्या है। यह मेरे पास रभडा के भाइयों की एक चिट्ठी है मैं इसे सभा में पढ़ कर सुनाता हूं।

बखिदमत जनाब वज़ीरे आज़म पंजाब गवर्नमैण्ट।

श्रीमान जी!

निवेदन हम बाशिन्दगान मौज़ा रभडा की यह है कि हमारे गांव की निसबत चंद खुदगर्ज़ अशख़ास ने गलत अफवाहें police के बारे फैलाई हुई हैं कि यहां पुलिस ने औरतों की बेइज्ज़ती की है। हम यह साफ़ तौर पर वाज़े कर देना चाहते हैं कि हमारे गांव में पुलिस ने किसी भी औरत की बेइज्ज़ती नहीं की और न ही इस किसम की कोई शिकायत हमारी तरफ से पुलिस के खिलाफ है। और बल्कि यह चंद खुदगर्ज़ आदमियों ने जिनका हमारे गांव से कोई भी वास्ता नहीं है अपना उल्लू सीधा करने के लिये यह गलत प्रापेगेंडा बनाया हुआ है। हम बिल्कुल अमन से रहते हैं। हम दोबारा आप का और आप की सरकार का शुकरिया अदा करते हैं।

इस चिट्ठी पर बहुत से आदमियों के दस्तखत हैं। इन में कोई सरपंच है कोई पंच हैं, कोई लम्बरदार हैं कोई हरिजन है और कोई जाट। कहने का मतलब यह है कि हर तरह के लोगों के इस पर दस्तखत हैं। यह चिट्ठी मैं सभा के सामने पेश करता हूं। बेशक कोई शखस इसे challenge करना चाहे तो करे। फिर मेरे दोस्त कहते हैं कि inquiry क्यों नहीं करवाते, डर की क्या बात है। मेरे दोस्त कप्तान साहिब ने कहा है कि सीता माता अगरचे बिल्कुल पाक थीं फिर भी राम ने उसे घर से निकाल दिया था। मैं उन को कहना चाहता हूं कि वह सत्युग का ज़माना था। उस समय लोग हमेशा सच कहते थे और कभी झूठ न बोलते थे। वे अपना उल्लू सीधा करने के लिये अपनी बहिनों और बच्चियों की इज्ज़त से न खेलते थे। मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि political purposes के लिये मेरी बहिनों और बच्चियों के नाम को पांवके नीचे रौंदा जा रहा है। उन लोगों को जो ऐसा कर रहे हैं शर्म आनी चाहिये। मैं इन से कहता हूं कि मैं खुद इस inquiry को अपने हाथ में लेता हूं और अगर कोई साहिब यह साबत करदे कि बहिनों और बच्चियों की बेइज्ज़ती हुई है तो मैं हर कसूरवार को कड़ी से कड़ी सज़ा देने को तैयार हूं। जहां तक judicial inquiry का सम्बन्ध है वह तो लोगों के हाथ में है। हमारे हाथ में तो Executive enquiry हुआ करती है और हम इस के लिये तैयार हैं।

स्पीकर साहिब! एक जगह Deputy Commissioner जाये, पुलिस कप्तान जाये, D.I.G. जाये। D.I.G. अंग्रेज के वक्त में तो बहुत बड़ा अफ़सर हुआ करता था और उस की बहुत कदर होती थी। मैजिस्ट्रेट वहां पर जाता है। यह चीज़ें जैसे मेरे दोस्त चौधरी रिजकराम ने कहा हमने शुरु की है। यह दिसम्बर के आखिर में या जनवरी के शुरु में होता

[मुख्य मंत्री]

है। कुछ पनाहगीर पकड़े जाते हैं और कुछ डाकू मारे जाते हैं। यहां तक तो कोई नहीं बोलता। सब खामोशी ही खामोशी होती है और हर कोई आनन्द में रहता है। परन्तु यकायक कुछ लोगों के दिलों में आता है कि ज़िला रोहतक में अमन क्यों है। उठ कर ऊंचे ऊंचे नारे क्यों न लगाये जायें और मौके का फायदा क्यों न उठाया जाये। असल में बात यह है, स्पीकर साहिब! मुझे अपनी बहिनों और बच्चियों का बहुत एहतराम है। परन्तु मैं उन से कहना चाहता हूं कि वे हमारे सामने आकर शहादत दें। यदि वे दूसरों के सामने शहादत दे सकती हैं तो हमारे अफसरों के सामने भी तो ऐसा कर सकती हैं। फिर वे शहादत न दें तो inquiry कैसे हो सकती है। Inquiry मेरे बारे नहीं और न ही आपके बारे है। inquiry तो इस बात की होनी है कि आया उन की बेइज्जती हुई है या नहीं। इस लिये उन्हें चाहिये कि वे शहादत देने से न घबरायें।

स्पीकर साहिब! मुझे तो criticise किया जाता है कि मैंने inquiry नहीं करवाई। परन्तु मैं कहता हूं कि Judicial inquiry करवाना तो मेरे दोस्तों के हाथ है। क्या उन्होंने इस बात के लिये कोई इस्तेगासा दायर किया है।

हाई कोर्ट खुली है आप जा सकते हैं और इस्तगासा दायर कर सकते हैं। मैं पूछता हूं कि आज तक क्यों कोई इस्तगासा या शिकायत वहां दायर नहीं की गई? स्पीकर साहिब! फिर Bar Association का तज़करा किया गया है। इस बार ऐसोसियेशन के १०० मैम्बर हैं। जो बार ऐसोसियेशन की meeting हुई उस में सिर्फ २८ मैम्बर हाज़िर हुए और २८ मैम्बरों में से ११ आदमियों ने vote दिया। बार ऐसोसियेशन की तरफ से enquiry की मांग की जाती है। मेरे पास इस बार ऐसोसियेशन की दर्खास्त आई कि उन्हें मिलने के लिये मौका दिया जाये क्योंकि वह इस वाकिया के मुतल्लिक हालात मेरे सामने रखना चाहते हैं। स्पीकर साहिब! मैं उस वक्त तो वहां नहीं था। मैंने कांगड़ा से जवाब दिया कि वह मुझ से फलां तारीख को मिल सकते हैं। आप शायद समझते होंगे कि शायद यह लोग वहां चार रोज़ पहले पहुंच गये होंगे। मैं आप को बता दूं कि वह आज तक मेरे पास तशरीफ नहीं लाये। बार ऐसोसियेशन के मैम्बरों ने जिन्होंने बड़े बड़े resolution पास किये उन्होंने लिखा कि मुआफ कीजिये हम नहीं आ सकते जब आना होगा तो लिखेंगे। हम इसी इंतजार में हैं कि वह आयें और हमें पता चले और समझ में आये कि कितने ज़रूरी और valuable arguments हैं जिस से उन के ख्याल के मुताबिक तखता पल्ट जायगा। स्पीकर साहिब, आप बहुत तजुरबाकार हैं. आप जब सुनते होंगे तो आप हैरान होते होंगे कि अगर रोहतक का वाकिया न होता तो फिर Opposition क्या कहती। वह हमें कहते हैं कि बड़े नालायक हो कि इस सूबे को अनाज में surplus बना दिया है। क्यों अम्बाला डिवीज़न का सत्यानास कर रहे हो और कर्ज़ा ले कर रेगिस्तान को नखलिस्तान बना रहे हो। बड़े नालायक हो कि Sundar Branch को perennial कर दिया है। बड़े नालायक हो कि गुड़गांव में boring करवा रहे हो और जगाधरी में ट्यूबवैल लगा रहे हो। बड़े नालायक हो कि Consolidation Department से रिश्वत इस तरह से भगा दी है जैसे गधे के सिर से सींग। बड़े नालायक हो कि हर पंचायत के area

में स्कूल खोलना चाहते हो। स्पीकर साहिब ! मैं फख्र से आप को कह सकता हूं कि आप के सूबे में जो पिछले साल १९५३ में normal था ८० फीसदी नार्मल crop थी। हमने गंदम पिछले साल १०.८० लाख टन पैदा की थी। आज ईश्वर की कृपा से और किसान भाइयों की मेहनत से और Consolidation महिकमा की कोशिशों से और बिजली और पानी देने वाले वज़ीर की मेहनत से आज ९५ फीसदी नार्मल crop है। हमने ११.८८ लाख टन अनाज पैदा करना है और हमारे सूबा की अपनी normal requirement १०.५५ लाख टन है यानी हमारा सूबा surplus हो जाता है। पंजाब ने जो अनाज export किया है वह ५०,००० टन हैं और पैप्सू का है ६७,००० टन। देहली की total consumption 11.80 लाख टन है, हिमाचल प्रदेश की consumption १० लाख टन है। पंजाब से estimated exportable surplus १.३० लाख टन है। फिर हमारे पास १.२० लाख टन होंगे। इसी तरह से पैप्सू के पास १.६९ लाख टन होंगे। स्पीकर साहिब, पंजाब और पैप्सू को मिला कर देहली और हिमाचल की ज़रूरियात को पूरा करते हुए हम १,९०,००० टन अनाज हिन्दुस्तान के बाकी इलाकों में भेज सकेंगे। हम बड़े नालायक इस लिये हैं कि हमारी गवर्नमैण्ट ने फैसला किया है कि पैप्सू, देहली, हिमाचल प्रदेश को खुराक के लिहाज़ से एक Zone बना दिया जायगा। हमने यह भी फैसला किया है कि पहली मई से अनाज को इधर से उधर ले जाने में कोई रुकावट नहीं होगी। बेशक पैप्सू का कोई ज़मींदार अपना गेहूं बिला रोक टोक हिमाचल प्रदेश या देहली में ले जा सकता है। जब चावल पर से control उठाया गया तो कई भाइयों ने चावल की कीमतें बढ़ा दीं। हमने हुक्म दिया कि हमारे गोदामों से लोगों को सस्ते दामों चावल दिये जायें। स्पीकर साहिब, आप की गवर्नमेंट के गोदामों में ३०,००० टन से ज्यादा गंदम पड़ी हुई है। चना भी पड़ा हुआ है। इस के इलावा स्पीकर साहिब ! बड़े अंदाज़ से कहा गया था कि फलां आदमी के in-laws का महिकमा है। अगर किसी आदमी का लड़का या किसी आदमी का दामाद या किसी आदमी का भाई जो कोई काम नार्मल तौर पर कर रहा हो और वह काम टैंडर के ज़रीये मिल रहा हो तो अगर इस मुअज़िज़ एवान की आवाज़ उस आदमी की गर्दन ज़दनी कर देती है सिर्फ इस लिये कि उस के बाप या सुसर ने सूबे की खिदमत का बीड़ा उठाया हुआ है तो मैं और मेरे साथी कभी ऐसे ख्याल की हिमायत नहीं कर सकते। कोई आदमी यह बताये कि फुलां आदमी के साथ हम नाजायज़ रियायत करते हैं या फलां आदमी को इस लिये फायदा पहुंचाते हैं कि उस का भाई या लड़का या दामाद बहुत बारसूख आदमी है लेकिन अगर खुले तौर पर कोई टैंडर होते हैं तो उस में रियायत का क्या स्वाल पैदा होता है। स्पीकर साहिब ! पंजाब गवर्नमैण्ट के हाथ में है क्या ? नौकरियां हमारे पास नहीं। ठेके देना हमारे बस की बात नहीं। लोगों की खिदमत करते हैं इतना तो किया है।

इस के अलावा, स्पीकर साहिब ! यह कहा गया है कि यह जो Nationalization की जा रही है इस का कोई फायदा नहीं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ६२-६३ लाख रुपये की investment कर के ११ लाख की आमदनी हो रही है। इस तरह से कई लाख रुपये की आमदनी बढ़ सकती है। जो लाखों रुपये की आमदनी होगी वह लोगों की

[मुख्य मंत्री]

सेहत, तालीम और सड़कों की तामीर पर खर्च की जायगी। स्पीकर साहिब, यह जो किताबों की Nationalization हुई तो मेरे दोस्त कहने लगे कि minority community को hit करते हैं। Nationalization किताबों की हुई और हमें communal गरदाना गया। अगर transport को Nationalisation करें तो भी हमें Communal कहा जाता है।

स्पीकर साहिब! मैं यह अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि जब तक यह सरकार बग़ैर किसी रू रियायत के काम करती है यह अपने प्रोग्राम से नहीं रुक सकती। (*cheers*) अब यह nationalization क्या है? इसमें जितने transport workers हैं उन्हें हम रखेंगे; vehicles हम खरीद लेंगे। अब अगर यह दोस्त, स्पीकर साहिब कुछ दो चार आदमियों के लिये सूबे की policy को यानी इस nationalisation के प्रोग्राम को बदलना चाहते हैं तो यह नहीं हो सकता। क्या आप चाहते हैं कि means of production लोगों के हाथों में न हों? फिर इस से बेरोजगारी किस तरह होगी जब कि हम सब आदमियों को रखेंगे। अब सुना है कि ट्रांस्पोर्ट वाले हड़ताल कर रहे हैं और यह सामने बैठे हुए दोस्त उन की मदद कर रहे हैं। हमने सुना है कि यह दोस्त कहते हैं कि अभी तो हम अपनी ताकत का जायिज़ा ही ले रहे हैं। मैं दलेरी से यह कह सकता हूं, इस लिये कह सकता हूं कि हमारी सरकार का प्रोग्राम जनता का प्रोग्राम है, कि जनता की ताकत को कोई नहीं रोक सकता (*cheers*)।

फिर tenants के बारे में कहा गया है। मगर हम से बढ़ कर tenants की बेहतरी के लिये किस ने काम किया है? यह दोस्त चाहते हैं कि लोगों की आपस में जूती चले। यह चाहते हैं कि tenants और ज़मींदारों की आपस में ठनी रहे और उन की चांदी हो। लेकिन हम यह कोशिश करेंगे कि लोगों में अमन कायम रहे। मैं मालिकों और tenants को कहना चाहता हूं कि हमारी निगाह में दोनों बराबर हैं। हमने यह देखना है कि किस का हक ज़्यादा है।

हरिजन भाइयों के बारे में कहा गया है कि उन के लिये कुछ नहीं हुआ। अगर आज कुछ नहीं हुआ तो मैं नहीं समझ सकता कि कभी कुछ हो भी सकेगा। ३१-१०-५२ को Class II में २१ हरिजन थे और ३१-१०-५३ को उन की गिनती २५ थी। Class III में ३१-१०-५२ को १,६०२ हरिजन थे और ३१-१०-५३ को २,०३८ थे। इसी तरह से Class IV में ३१-१०-५२ को १,३७० थे और ३१-१०-५३ को २,८८० थे। हमारी सरकार में अब २५ हरिजन Gazetted Officers हैं। हरीजन बच्चों की तालीम का प्रबन्ध किया जाता है, उन्हें वज़ीफ़े दिये जाते हैं और दीगर सहूलतें दी जाती हैं। यह सब चीजें की जा रही हैं। आज अगर कोई यह समझे कि हरीजन भाइयों को कोई ग़लत रास्ते पर लगा सकेगा तो यह ख्याल अस्तो मुहाल अस्तो जनूं। इन शब्दों के साथ मैं आप का धन्यवाद करता हूं (*Loud cheers*)

अध्यक्ष महोदय : Debate खत्म हुई। मुझे खुशी है कि इस debate में ४५ मैम्बर साहिबान ने हिस्सा लिया है। अब आप के सामने voting का मामला है। सब से पहले श्री दौलत राम शर्मा की cut motion है। फिर श्री वधावा राम की है। मैं बार बार आप को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। जब कोई मैम्बर अपनी cut motion withdraw करना चाहे तो मैं आप की मरजी से आप को पूछे बगैर उन्हें withdraw करने की आज्ञा दे दूंगा।

Mr. Speaker : Question is—

That item of Rs. 2,69,880 on account of h-1—Ministers be reduced by Rs. 100

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That item of Rs. 3,76,820 on account of h-1—Ministers and (h) 2—Purchase and maintenance of Cars of Ministers and Deputy Ministers be reduced by Rs. 1,50,000.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That item of Rs. 3,21,220 on account of (i) Legislative Council be omitted.

After ascertaining the votes of the House by voices. Mr. Speaker said "I think the Noes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon these Members who challenged the decision and supported the claim for a Division, to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 15 lakhs.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was by leave withdrawn

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 1.

The motion was by leave withdrawn

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1.

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 1.

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Re. 1

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by one per cent.

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by one per cent.

The motion was by leave withdrawn

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100,

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was by leave withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost

Mr. Speaker : Question is—

That the demand be reduced by Rs. 100.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That a sum not exceeding Rs. 1,45,51,800 be granted to the Governor to defray the charges that will come in course of payment for the year 1954-55 in respect of General Administration.

The motion was carried.

The Assembly then adjourned till 2 *p. m. on Tuesday the* 23*rd March*, 1954

261 PSLA—283—28-12-54—C P and S. Pb. Chandigarh.

Date Due

32474 PVS—15,000—Govt. Press, U. T., Chd.

32474 PVS—15,000—Govt. Pr...

PUNJAB VIDHAN SABHA

Library, Chandigarh

Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced by the borrower. In case of set of volumes, price for the whole set will be realised.

Help us to keep the books fresh and clean.